राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का चौंतीसवां दिवस संख्या: 15

बुधवार,
05 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः विराजें, विराजें। हो गयी राम-राम। सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। शुरू करें। प्रश्न काल। डॉ. दयाराम परमार।

तारांकित प्रश्नोत्तर

खैरवाड़ा के राजकीय कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण

281. डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कृषि महाविद्यालय, खैरवाड़ा के भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात किन कारणों से बन्द कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कार्य को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) जी हां। राजकीय कृषि महाविद्यालय, खैरवाडा के भवन निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। कार्यकारी एजेंसी द्वारा पूर्व में कार्यादेश जारी किया गया, किन्तु संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने एवं अनुबन्ध सम्पादित नहीं किये जाने के कारण अनुबन्धानुसार कार्यादेश को रद्द किया गया। पुनः निविदा आमंत्रित कर वित्तीय बिड खोलने के उपरान्त पूर्व संवेदक द्वारा विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी।

(2) जी हां। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त करने के उपरान्त कार्यकारी एजेंसी द्वारा निविदा कार्यवाही पूर्ण कर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में भवन निर्माण कार्य नींव भरकर डीपीसी भरने तक पूर्ण हो गया है। कार्यादेश अनुसार भवन निर्माण दिनांक 20.11.2025 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं है। मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मोतीराम।

रेवदर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

282. श्री मोतीराम (रेवदर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रेवदर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर स्थानीय निवासियों को रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): विधान सभा क्षेत्र रेवदर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु भूमि आवण्टन बाबत जिला कलक्टर को पत्र दिनांक 07.10.2024 लिखा गया है। भूमि आवण्टन के उपरान्त ही औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाना सम्भव है।

श्री मोतीराम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का जवाब मेरे पास आ गया है। मेरा पूरक प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय, जिला कलक्टर को दिनांक 07.10.2024 को भूमि आवण्टन हेतु लिखे गये पत्र का उल्लेख किया गया है। यह बताया जाये कि आवण्टन की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि रेवदर क्षेत्र में पांच औद्योगिक क्षेत्र पहले से मौजूद हैं। उसके बावजूद भी वहां जरूरत थी, इसी कारण हमारे विभाग ने कलक्टर को पत्र लिखा है। कलक्टर एक बार क्षेत्र चिह्नित करेगा, जमीन चिह्नित करेगा, उसके बाद उसकी कार्यवाही होगी और फिर उसे हम औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ पूछना है?

श्री मोतीराम (रेवदर): सर, पांच महीने हो गये। अभी तक क्या हुआ इसके बारे में?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि सदन के हर विधायक को यह जानने की जरूरत है। यह पहले भी मैंने बतलाया था। मैं आज इस बात को दोहराता हूं और उसका मैं उदाहरण देता हूं।

जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति कहीं पर कोई जमीन खरीदता है तो यह तय नहीं कर लेता कि उसी समय उस पर निर्माण कर लेगा। आगे का सोचकर भी जमीन ली जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीनों की कमी होती जा रही है। यह जरूरी है कि हमारा विभाग अभी से आगे का विजन रखकर जमीन चिह्नित करे और फिर आगे चलकर जरूरत पड़ने पर उसको औद्योगिक क्षेत्र में डवलप करे। रेवदर क्षेत्र में पहले ही पांच औद्योगिक क्षेत्र हैं। हमें और जमीन की जरूरत है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम उसे तुरन्त ही डवलप करें। जब जमीन मिलेगी, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे और फिर आगे जिस तरह से डिमांड आयेगी, उसे देखते हुए उसको डवलप किया जायेगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री सुरेश गुर्जर।

खानपुर में पेयजल योजना से वंचित ग्राम

283. श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत किन-किन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है तथा कितने गांव अभी तक वंचित है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से गांव फ्लोराइड की समस्या से ग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कुल 405 ग्राम अवस्थित हैं। इन सभी ग्रामों को जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर जल सम्बन्धों द्वारा लाभान्वित करने हेतु वृहद पेयजल परियोजना/अन्य पेयजल योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी हैं। योजना का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

स्वीकृत 4 वृहद पेयजल परियोजना में से वृहद पेयजल परियोजना छापी-झालावाड़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खानपुर हेतु स्वीकृत 140 ग्रामों में से 23 ग्रामों का कार्य पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, शेष का कार्य प्रगतिरत है। वृहद पेयजल परियोजना राजगढ़-झालरापाटन एवं छापी-विस्तार का कार्य प्रगतिरत है तथा वृहद पेयजल परियोजना परवन-अकावद के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। परियोजनावार स्वीकृत ग्रामों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

लघु पेयजल परियोजना के तहत विधान सभा क्षेत्र खानपुर के 64 ग्रामों को लाभान्वित किये जाने हेतु स्वीकृत 58 लघु योजनाओं में से 45 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर 50 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है, शेष का कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में एकीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस) की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार कोई भी ग्राम फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी का जवाब मिल गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर के 405 गांवों में 4 योजनाओं के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की स्वीकृति जारी की गयी है। इसमें 73 गांवों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 332 गांवों के लिए योजना प्रगतिरत है। इनमें से 143 गांवों के लिए अभी निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से पूरक प्रश्न है कि जिन गांवों को पूर्ण बताया

गया है, वहां ग्रामवासियों की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। आधे गांवों में पानी पहुंच रहा है और आधे गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे बहुत सारे, कई सारे गांव हैं।

क्या क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि के साथ एक कमेटी गठित कर इसकी जांच कराने का सरकार विचार रखती है, जिससे पता चल जाये कि वास्तव में नलों में पानी पहुंच रहा है या कागजों में पानी पहुंच रहा है? इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जायेगा।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किया, इनके क्षेत्र में वास्तव में 405 गांव जोड़े जाने थे, 73 कम्प्लीट बताये हैं। जो 73 गांव ओटीएमपी के द्वारा जल जीवन मिशन से जोड़े गये हैं, जिनमें पानी नहीं आ रहा है, जिनमें प्रेशर की कमी है, पिछले कार्यकाल में वास्तव में सही मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से यह दिक्कत आ रही है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे अधिकारियों की एक टीम बनाकर जहां-जहां पानी नहीं आ रहा, आपको साथ में लेकर उनकी जांच कर लेंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हर घर में जितने कनेक्शन दिये थे, उन सबमें प्रेशर से पानी आये। यह 100 परसेंट हम व्यवस्था करेंगे।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, सरकार ने खानपुर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी जैसे गम्भीर विषय पर आईएमआईएस की रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि गांवों में कोई फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से ग्रसित नहीं है, क्या खानपुर विधान सभा क्षेत्र के खानपुर कस्बे, जोलपा, पीपलाज, झागर, गोल्याखेड़ी, कंवलदा, गादरवाड़ा डूंडी, मेहंदड़ी, भगवानपुरा, सूमर में पानी के सैम्पल लिये गये हैं? यदि हां तो कब लिये गये और इसके क्या परिणाम आये? मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खानपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव कंवरपुरा मंडवाला में 13.05.2024 को सैम्पल लिये गये थे और उनके आधार पर वहां पर कोई फ्लोराइड नहीं था। माननीय सदस्य ने जो गांव अभी बताये हैं, उनमें वास्तव में फ्लोराइड है तो उनकी जांच करा लेंगे। वैसे जो योजनाओं के तहत चार योजनाएं इनके यहां सैंक्शन की हैं, उनमें जो भी पानी आयेगा, सतही जल से परवन से आयेगा। खानपुर में छापी, झालावाड़ से आयेगा। इनके बकानी के झालावाड़ जिले के छापी विस्तार से पानी आयेगा। जो भी पानी आयेगा, वह अंडरग्राउंड न होते हुए सतही जल आयेगा। वह पूरा फिल्टर होकर आयेगा। कोई फ्लोराइड का पानी नहीं देंगे। बाकी जिन गांवों का आप बता रहे हैं, उनकी दुबारा फ्लोराइड जांच करा लेंगे। यदि फ्लोराइड पाया जायेगा तो जो भी ट्रीटमेंट होगा, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

रावी व व्यास नदी से पानी लाने की योजना

284. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 में रावी व व्यास नदी से पानी देने के लिए राजस्थान व पंजाब सरकार के बीच समझौता हुआ था? यदि हां तो समझौते के तहत प्रदेश को कितना पानी मिलना था? वर्तमान में प्रदेश को कितना पानी मिल रहा है तथा शेष पानी के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने क्या प्रयास किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश के हिस्से का शेष पानी लाने के लिये क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) जी हां, रावी-व्यास नदियों के अधिशेष पानी के बंटवारे के बारे में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य 31.12.1981 को समझौता हुआ था, जिसके तहत राजस्थान को 8.60 एम.ए.एफ. पानी निर्धारित किया गया। वर्तमान में प्रदेश को रावी-व्यास नदियों के अधिशेष जल में से 8.00 एम.ए.एफ. पानी मिल रहा है।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शेष 0.60 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान को देने के लिए भारत सरकार, पंजाब सरकार तथा भाखडा ब्यास प्रबन्धन मण्डल से लगातार अनुरोध किया तथा उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में भी लगातार यह मुद्दा उठाया गया। राजस्थान द्वारा 0.60 एम.ए.एफ. रावी-व्यास पानी बहाली के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मूल सूट नं. 6/2020 दायर किया, जो कि दिनांक 26.07.2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ था । गत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ठ-अ पर संलग्न है।

(2) सरकार प्रदेश के हिस्से का शेष 0.60 एम.ए.एफ. पानी प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयासरत है। मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्टैंडिंग कमेटी की दिनांक 25.10.2024 को आहूत 21वीं बैठक में भी मुद्दा उठाया गया तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन, राजस्थान द्वारा दिनांक 27.02.2025 को इस बाबत सचिव जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भी लिखा गया है।

MKD/RTM/05.03.2025/11:10/1b

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पंजाब सरकार से जो 31.12.1981 को समझौता हुआ था। उसको निरस्त करने के लिए 2004 में पंजाब समझौता समिति अधिनियम, 2004 पारित करके उसको रद्द कर दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में यह कहा कि यह वैधानिक नहीं है, आपको इसको निरस्त नहीं कर सकते हो, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी अपना सबसे अनुकूल समय है।

डबल इंजन की सरकार है, हमने हरियाणा से यमुना जल समझौता किया, मध्य प्रदेश से ईआरसीपी का समझौता किया। मैं यह कहना चाहूंगा, इसके लिए एसीएस स्तर के उच्च अधिकारी को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो केवल यही काम करे। यह 0.60 एमएएफ

पानी जो हमको नहीं मिल रहा है, वह हमको मिल सके।

दूसरा, जो भाखड़ा ब्यास मंडल है, उसमें हमारे राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो प्रयास करके उसमें भी हमारा एक प्रतिनिधि हो, जो हमारा पक्ष रख सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यह चाहूंगा कि क्या आप कोई एसीएस स्तर के उच्च स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे? दूसरा प्रश्न है कि भाखड़ा ब्यास मंडल में हमारा प्रतिनिधि नियुक्त हो, इसके लिए क्या आप प्रयास करेंगे? दोनों बात का जवाब दे दीजिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय को कहना चाहता हूं कि हमने सर्वोच्च न्यायालय में दायर छूट में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी करने और अपना पक्ष रखने हेतु सीनियर अधिवक्ता श्री विक्रमजीत बनर्जी, अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया को पैनल में नियुक्त किया है।

जहां तक एसीएस स्तर के नोडल अधिकारी को नियुक्त करने की बात है तो माननीय विधायक महोदय का अच्छा सुझाव है। हम इसका अध्ययन कर विचार करेंगे। इसके अलावा आपने भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में अपना सदस्य नियुक्त करने की बात की है, इसका भी हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री उमेश मीणा।

जनजाति छात्रावास में कार्यरत कार्मिकों हेतु पृथक कैडर

285. श्री उमेश मीणा (आसपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितना बजट आवंटित किया गया? उक्त आवंटित बजट कहां-कहां व्यय किया गया? योजनावार, जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावास, आश्रम बालक-बालिका छात्रावास में कुल कितने कार्मिक कार्यरत हैं? उक्त में कितने अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग का अलग कैडर बनाने की प्रक्रिया कब से चल रही है तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है व उसमें क्या प्रावधान किये जा रहे हैं? प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में प्रावधित राशि एवं व्यय की गई राशि विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

योजनावार जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विभाग द्वारा कुल 437 आश्रम छात्रावासों में 511 कार्मिक, 23 आवासीय विद्यालयो में 261, 8 बहूद्देशीय छात्रावासो में 5, 13 खेल छात्रावासों में 33, 11 कॉलेज छात्रावासों में 9 कार्मिक कार्यरत हैं। उक्त समस्त कार्मिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

जिलेवार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभागीय मंत्रालयिक सेवा के 4 कार्मिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के 191 कार्मिक विभिन्न छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में कार्यरत हैं।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-II व छात्रावास अधीक्षक (पुरुष) ग्रेड-II के पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.01.2022 (परिशिष्ट-द) से जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001 मे शामिल कर दिया गया है।

विभागीय छात्रावास अधीक्षक कैडर के पदो को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 से राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में शामिल कर दिया गया है। वर्तमान में 470 वार्डन के पदों को सीधी भर्ती हेतु प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति हो तो पूरक प्रश्न..

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया, ठीक है। पूरक प्रश्न पूछो।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): उत्तर आ गया है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब आया है, उसमें आदिवासी समुदाय के उद्धार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य व केन्द्र की विभिन्न योजनाओं के 997 करोड़ रुपये का बजट, जिसमें 744 करोड़ रुपये खर्च किये गये, मतलब ढाई सौ करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। खर्च क्यों नहीं हुआ और बजट का आगे क्या किया गया?

इसमें भी विशेषकर केन्द्र की पीएमएएजीवाई योजना में राज्य के लिए आवंटन 100 करोड़ में से एक रुपया भी खर्च नहीं बताया तो क्या यह पैसा केन्द्र सरकार ने दिया या नहीं? यदि हां, तो उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया गया? और परिशिष्ट-ब में जो खर्च का ब्यौरा दिया गया है, उसके तीसरे नम्बर पेज पर स्विमिंग पूल पर 3 करोड़ के आसपास बजट खर्च किया गया है तो स्विमिंग पूल कहां बनाया? किसकी मांग पर बनाया? क्या स्विमिंग बनाकर आदिवासी बच्चों को विकास करोगे? या फिर स्विमिंग पुल और अन्य अनावश्यक जगहों पर टी ए डी का बजट का उपयोग किया जा रहा है? उसको रोकने का प्रयास रखते हो? उसकी जानकारी सदन को दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि केन्द्र सरकार का 1 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए।

यह केन्द्र सरकार का 2023-24 बजट है, वह बजट केन्द्र सरकार से आया नहीं। उस समय सरकार की कांग्रेस थी। आया नहीं तो खर्च करने का सवाल ही नहीं।

दूसरा, एक इन्होंने कहा कि एक खेल स्टेडियम बांसवाड़ा में तरणताल स्वीकृत है, 09.09.2021 का, सरकार इनकी थी। स्वीकृत राशि 5.77 लाख, 90 परसेंट कार्य पूर्ण हो गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीट पर जाइये। कल इतना कह दिया क्वश्चन ऑवर में कोई नहीं आएगा। यह क्या है?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): यह कार्य पूर्ण होने के बाद क्रीड़ा परिषद को हैंडओवर कर दिया जाएगा, काम पूरा कर लिया जाएगा।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने स्विमिंग पूल के बारे में पूछा, स्टेडियम के बारे में नहीं और सरकार के बारे में नहीं। यह जो अभी 2025-26 आपके कार्यकाल में चल रहा है। केन्द्र सरकार का कितना बजट आया? यह पूछना चाहूंगा।

आदिवासी के कल्याण के लिए इतना बड़ा विभाग है और सरकार ने 1 हजार 25 कार्मिक शिक्षा व अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ले रखे हैं। खुद टीएडी विभाग का एक भी कार्मिक नहीं है। यदि है, तो मंत्री जी बताएं। उनके टीएडी विभाग के खुद के कार्मिक कितने हैं?

छात्रावास अधीक्षक के 470 वार्डन के पदों पर भर्ती के लिए जो प्रक्रिया जारी है, मां-बाड़ी केन्द्र में हंडरेड परसेंट एस टी वर्ग के शिक्षा सहयोगी लगा रखे हैं। उसी तर्ज पर 470 वार्डन पदों पर एस टी वर्ग के अभ्यर्थी लगाने की मंशा रखते हैं। सदन की मेज पर अवगत कराएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। विराजो।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): प्रश्न तो गोलमोल है, प्रश्न तो कुछ है नहीं।

अध्यक्ष महोदय जी, आपने यह कहा कि 470 पद, जो हमारे हॉस्टल हैं, इनमें पहले कैडर नहीं था और कैडर नहीं था तो हम लोग शिक्षा विभाग से अध्यापक लेते थे और उनको वार्डन के तौर पर लगाते थे। अब हमारा कैडर बन गया और उनकी कार्मिक विभाग द्वारा प्रक्रिया चालू है। यह होने के बाद में हमारा कैडर बन जाएगा।

अध्यक्ष महोदय जी, हमारे छात्रावास अभी बढ़ गये हैं, 492 छात्रावास है और ये 470 पद हैं। यह जो अन्तर है, यह अन्तर इसलिए है, अभी जो हॉस्टल वगैरह खुले हैं, इसके कारण से यह अन्तर आ रहा है। ये पद भी फाइनेंस को भेजकर, स्वीकृत कराकर पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामकेश।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): सर, एस टी के जो वार्डन हैं...

श्री अध्यक्ष: आपके दो हो गये, विराजो। दो प्रश्न हो गये, दो में भी आपने लम्बा, ठीक है, बैठो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दो क्वेश्चन हैं। एक तो आपने कहा कि जो पीएमएएजीवाई की जो सड़कें हैं, इसके एक हजार करोड़ रुपये आए थे। वह एक भी खर्च नहीं किया। दूसरा, आप यह जो कैडर बनाने की बात कह रहे हो। यह कब तक आपका काम पूरा हो जाएगा और कब तक आप नियुक्ति दे दोगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। आपसे प्रश्न पूछा है। एक बार दुबारा पूछ लें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नैक्स्ट प्रश्न पुकार दिया था।

श्री अध्यक्ष: आप तो विराजो। प्रश्नकाल, मैं डील रहा हूं। आप एक बार दुबारा पूछ लो। आप विरोजो। आप दुबारा पूछ लो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा पूछ लेता हूं। आपने परिशिष्ट-अ पर जो लिखा है कि प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अन्दर राशि का प्रावधान किया था, उसमें से एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण रहे? एक नम्बर। दो नम्बर, यह है कि आपने जो प्रावधान किये हैं, अलग कैडर बनाने के ये नियुक्ति कब तक हो जायेगी? क्योंकि आपने जिस दिन जनजाति की डिमांड थी, उस दिन भी कहा था कि हम कैडर बना रहे हैं तो कब तक कैडर बनेगा? और कब तक नियुक्ति होगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जी नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल किया है, अपने परिशिष्ट-अ पर, ये पैसा 2023-24 का है, राज्य सरकार द्वारा 75 हजार 608.19 लाख रुपये, व्यय है 63.12, यह राशि आपके समय में खर्च हुई है, आई है।

Bhs/Rtm/05.03.25/11.20/1c

अध्यक्ष महोदय जी, संविधान की धारा 275, 11,020.80 इसमें 10,294.87 ये खर्च किया ये आपकी सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम में यह पैसा 10 हजार करोड़ है। यह पैसा खर्च इसलिए, जैसा हमने पहले भी बताया था कि यह पैसा आप लोग ले नहीं पाये, वहां से केंद्र से मिला नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ले नहीं पाये कि भारत सरकार ने दिये नहीं?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): केन्द्र से आया नहीं। केन्द्र से आया नहीं तो खर्च कहां से होगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय, उत्तर सुन लो। दूसरे किसी को अनुमति नहीं है, सबके लिए नहीं है आपको अकेले को है। नो। आप अलग प्रश्न लगा दो अगली बार।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): दूसरा आपने क्या पूछा था? कैडर का कब तक पूरा करोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैडर का इनके समय में हो गया था, लेकिन जो नियमों में है, अपने को अपने वित्त विभाग को दे करके उसको फाइनेंस में लेना

था वो आप ले नहीं पाये। हमने यह प्रक्रिया पूरी करके और अब हमारे कमिश्नर कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। ये आते ही बहुत जल्दी कार्मिक विभाग परीक्षा करायेगा और उसके बाद में ये...

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा इतना सा ही आग्रह है सर, इसमें हमारी सरकार या उसकी नहीं है, सीधा अगर पैसा जिन लोगों ने खर्च नहीं किया चाहे हमारी सरकार के अधिकारी हो, उस पर आप कार्यवाही करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? एक नंबर बात। दो नंबर बात, जो काम हमारे टाइम में ही हो गया साहब, वो कैडर का तो, आप डेढ़ साल से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और बार-बार यह कि हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः विराजो।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अभी कर दिया और ये प्रक्रियाधीन है जो हमारे कमिश्नर कार्यालय में आते ही हम इसको फाइनेन्स को भेज करके जल्दी परीक्षा करा करके करायेंगे।

श्री अध्यक्षः विराजो। अगला प्रश्न। श्री रामकेश।

गंगापुर में भू-प्रबन्धन

286. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग द्वारा भू-प्रबन्धन की कार्यवाही कब-कब की गई?

(2) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में अन्तिम भू-प्रबन्धन की कार्यवाही कब की गई? भू-प्रबन्धन में विभाग द्वारा विधि विरुद्ध जो कार्यवाहियां अंकित कर दी गई थी, को क्या सरकार अभियान चलाकर विधि अनुसार दुरुस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा भू-प्रबन्धन की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

वर्तमान में DILRMP योजना के तहत सर्वे/रिसर्वे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में जिला सवाई माधोपुर की 3 तहसील क्रमशः गंगापुरसिटी, तलावडा व वजीरपुर शामिल हैं जिनमें सम्वत 2039-2058 में अंतिम भू-प्रबन्ध की कार्यवाही की गयी हैं।

भू-प्रबंध संक्रियाएं पूर्ण हो जाने के पश्चात पूर्ण रिकॉर्ड संबंधित जिला कलक्टर को सुपुर्द करने व रिकॉर्ड लागू होने के उपरांत अशुद्धियों की दुरुस्ती हेतु संबंधित उपखण्ड न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व अन्य सुसंगत नियमों, अधिनियमों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती हैं। जिसके लिए सम्बन्धित काश्तकार सक्षम न्यायालय में चाराजोई हेतु स्वतंत्र हैं।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया आपकी इजाजत हो तो मैं प्रश्न पूछ लूं? अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, 1955 और

राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 दो पारित करके और काश्तकारों को अधिकार और सुविधाएं दी थी। उसके बाद में 1958 के लगभग सैटलमेंट चालू हुआ पूरे राजस्थान में और सैटलमेंट के नाम पर काश्तकारों का जो राजस्व रिकार्ड था, उस राजस्व रिकार्ड के विपरीत जो टिप्पणियां कर दी थीं, उन टिप्पणियों को सुधारने के लिए मैंने आपसे समय सीमा पूछी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा आप कहोगे कि ये प्रश्न नहीं।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): आप सुनिये, प्रश्न ही पूछ रहा हूं, लेकिन जो जवाब दिया है अधिकारियों ने, मैंने प्रश्न क्या पूछा और जवाब घुमाकर के मेरे को रास्ता बता दिया, रास्ता तो मैं पढ़ा-लिखा आदमी हूं, मैं जानता हूं कि कोर्टों में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जिन मतदाताओं ने आपको इस सदन में बैठाया, सरकार बनाई...

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, क्या आप, आपने मुझे जवाब दिया है कि काश्तकार सक्षम न्यायालय में चाराजोई हेतु स्वतंत्र हैं। गलती करे सरकार, गलती करे सरकार के अधिकारी और चाराजोई करने के लिए जनता राजस्व अदालतों में जाये।

श्री अध्यक्षः आप तो प्रश्न पूछें।

श्री रामकेश (गंगापुर): तो आप क्या चाहते हैं कि जिन मतदाताओं ने आपको यहां भेजा वो 25-25 साल तक, 30-30 साल तक राजस्व अदालतों में मुकदमा लड़े? आपका उत्तर अगर हां में है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूछो। नो। आप प्रश्न पूछो। मतदाताओं का यह मुद्दा नहीं है।

श्री रामकेश (गंगापुर): प्रश्न पूछ रहा हूं यह। नहीं, आप चाहते हैं क्या? मेरा प्रश्न इतना सा है ...(व्यवधान)... आपको आवेश में आने की जरूरत नहीं है, आपको जनता ने यहां चुनकर के भेजा है।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछें, नहीं तो मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। आप प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हो। पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं इतना सा पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सैटलमेंट के द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड में गलतियां कर दी हैं श्मशान, कब्रिस्तान, मंदिर, रास्ते के जो विपरीत टिप्पणियां कर दी और उनके राजस्व न्यायालयों में जो भयंकर 90% मुकदमे चल रहे हैं, क्या सरकार जनता को राहत दिलाने के लिए कोई अभियान चलाकर के उन अशुद्धियों को दूर करना चाहती है? अगर चाहती है तो, अगर आपका जवाब हां में है तो मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना।

श्री अध्यक्षः पूछिये आप।

श्री रामकेश (गंगापुर): अगर आपका जवाब ना में है तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दो। माननीय मंत्री जी। जवाब आने दो। केवल जवाब। प्रश्न तक सीमित रहो, भाषण नहीं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो कहा है, अभी तक जो इन्होंने कहा है वो केवल भाषणबाजी है।

श्री अध्यक्ष: आप तो उत्तर दो।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा भाषण मेरी तरफ से भी हो जाये, ये केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा परंतु ये जो छोटी-मोटी अशुद्धियां हुई हैं, उसमें नियम और कायदे के अनुसार काम है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 व अन्य सुसंगत नियमों, अधिनियमों के तहत... ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ये तो जाता है कागज जाता है।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो वो मंत्री जो देंगे वो सुनना पड़ेगा। जवाब मैं थोड़ी दिलवाऊंगा कि यह जवाब बोलो। गलत बोल रहे हैं तो आप नियमों में आ जाओ कार्यवाही करवा दूंगा।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): जिसके लिए सम्बन्धित काश्तकार सक्षम न्यायालय में चाराजोई हेतु स्वतंत्र है। कोई किसी से गलती हुई या त्रुटि हुई, उसकी एक प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी ना।

श्री अध्यक्ष: आप अपना उत्तर दे दीजिये। उत्तर दे दो। आप अपना जो उत्तर देना है वह उत्तर दे दीजिये।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): ठीक है। दे दिया साहब, उत्तर दे दिया।

श्री अध्यक्ष: दे दिया?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न और पूछ सकते हो। प्रश्न सीधा।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि इससे 90% जो मुकदमे हैं ये इन गलतियों की वजह से राजस्थान की जनता त्राहिमाम हो रही है राजस्व अदालतों में तो मैं सरकार से केवल, मैं कोई सरकार को दुविधा भी नहीं डालना चाह रहा हूं इसलिए नहीं लगाया मैंने यह प्रश्न। मैंने प्रश्न सिर्फ इसलिए लगाया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री रामकेश (गंगापुर): आप राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हो, राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बहादुर सिंह।

श्री रामकेश (गंगापुर): यह क्या तरीका है आपका? जवाब नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कांग्रेस के कार्यकाल की त्रुटियां है ये इसमें लिखा हुआ है जवाब।

श्री रामकेश (गंगापुर): जवाब दिलवाइये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: भाषण कर रहे हैं, भाषण की अनुमति नहीं है। मतदाताओं से, जीत कर आये हो, यह है, वो क्या जवाब देंगे। यह प्रश्न है क्या?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, इतना सा आपसे निवेदन है कि जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपको किसने कहा, मिस्टर सहारण?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्योंकि सारे जो रिकॉर्ड्स के अंदर सैटलमेंट या सर्वे-रिसर्वे के आधार पर काफी जगह खसरों के अंदर चेंज आ गया, यह बात आप लोग भी जान रहे है, हम भी जान रहे हैं। इसमें यह तरीका तो है ही कि वह व्यक्ति कोर्ट में चला जाये तो कोर्ट में हर व्यक्ति जाएगा? लम्बा प्रोसेस है, हर व्यक्ति का खर्चा आयेगा, परेशानी होगी। माननीय सदस्य का पूछने का इतना सा ही तात्पर्य है क्या सरकार खुद कोई अभियान चलाकर जो त्रुटि हुई उनको ठीक करना चाहती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: बस आ गया। माननीय मंत्री जी, कुछ कहेंगे?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश में भारत सरकार ने...।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, सरकार कोई अभियान चलायेगी या नहीं? आप वह उत्तर दे दो।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): इतनी सी बात, मैं पूरी डिटेल बता रहा था।

श्री अध्यक्ष: उत्तर दे दो।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): महत्वाकांक्षी योजना DILRMP के अंतर्गत सर्वे- रिसर्वे का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सर्वे-रिसर्वे का काम दो चरणों में किया जाना है, जिसमें प्रथम चरण में प्रदेश के 11 जिले जयपुर, जोधपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सुनिये। उत्तर तो सुनिये।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): चूरू, बाड़मेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा

श्री अध्यक्ष: आपका उत्तर आ रहा है।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): और अजमेर जिले की चार तहसीलें अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और पीसांगन को शामिल किया गया है व दूसरे चरण में 22 जिलों को शामिल किया गया है। यह DILRMP जो योजना है यह भारत सरकार की है और 100% इसमें भारत सरकार का पैसा लगा है और भविष्य में ...(व्यवधान)... 1 मिनट, 1 मिनट सुन लो। 1 मिनट सुन लो।

श्री अध्यक्ष: नो। अंकित नहीं। बिना अनुमति से बोले तो अंकित नहीं।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अगले राजस्व अभियान में इन अशुद्धियों को दूर करने का बिंदु भी शामिल किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बहादुर सिंह।

वैर व भुसावर में सीवरेज

287. श्री बहादुर सिंह (वैर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र वैर के वैर तथा भुसावर कस्बे में सीवरेज लाईन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र वैर की नगरपालिकाएं वैर तथा भुसावर में वर्तमान में सीवरेज प्लान बनाने के लिए CPHEEO द्वारा निर्धारित पेयजल आपूर्ति 135 LPCD से कम होने के कारण सीवरेज प्लान स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

इसके स्थान पर माननीय मुख्य मंत्री की बजट घोषणा के क्रम में दोनों ही नगरपालिका वैर एवं नगरपालिका भुसावर में 15-15 KLD क्षमता के FSTP पूर्ण हो कर कार्यरत-Operational हैं।

Kas/rtm/05.03.2025/11.30/1d

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर और भुसावर बहुत पुराने कस्बे हैं। वैर में बाबा मनोहर दास जी की जन्म स्थली है, किला है और भुसावर में आचार बनता है, जो कि पूरे भारत और पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है और पुरानी आबादी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो गाइड लाइन बनाई है, इस गाइड लाइन से हटकर क्या वहां सीवरेज लाइन बनाने का आप विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक बनाई जायेगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीवरेज प्लांट बनाने के लिये भारत सरकार के और राज्य सरकार के जो दिशा-निर्देश हैं, उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, अलग से कोई कार्यवाही नहीं होगी। यह सही है कि वो दोनों पुराने शहर हैं, विधान सभा क्षेत्र वैर की नगरपालिकाएं, वैर और भुसावर, दोनों में ही

तकनीकी कारणों से सीवरेज लाइन नहीं डाली जा सकती है। किसी भी क्षेत्र में सीवरेज लाइन डाले जाने के लिये आवश्यक पेयजल आपूर्ति के लिये सीपीएचईईओ द्वारा निर्धारित मापदंडों में 135 एलपीसीडी होनी चाहिये। यह निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं होने की स्थिति में सीवरेज लाइन के स्थान पर एफएसटीपी का निर्माण करवाया जाकर स्थानीय समस्या का निस्तारण किया जाता है। नगरपालिका वैर में पेयजल आपूर्ति 68 एलपीसीडी तथा नगरपालिका भुसावर में 62 एलपीसीडी है। इस प्रकार निर्धारित पेयजल आपूर्ति 135 एलपीसीडी से कम होने के कारण सीवरेज लाइन नहीं डाली जा सकती है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जहां नगरपालिका भुसावर की जनसंख्या 19,946 है तथा परिवारों की संख्या 3,280 है, वहीं नगरपालिका वैर की जनसंख्या 19,385 तथा परिवारों की संख्या 3,076 है। मुख्य मंत्री बजट घोषणा संख्या 267 2022-23 के अंतर्गत दोनों ही नगरपालिकाओं, वैर-भुसावर में एफएसटीपी निर्माण की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा अंतर्गत नगरपालिका वैर में 15 केएलडी क्षमता का एफएसटीपी दिनांक 10.4.2024 को पूर्ण किया जाकर वर्तमान में संचालित है, जिसमें 10 वर्ष का रख-रखाव भी सम्मिलित है। इसी प्रकार नगरपालिका भुसावर में भी 15 केएलडी क्षमता का एफएसटीपी दिनांक 20.2.2024 को पूर्ण किया जा कर वर्तमान में संचालित है, जिसमें 10 वर्ष का रख-रखाव भी सम्मिलित है।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण के गांवों का विद्युतीकरण

288. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के कितने गांव विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी 104 राजस्व ग्राम विद्युतीकृत हैं।

(2) वर्तमान में आवेदक द्वारा आवेदन करने पर टीसीओएस-2021 के अनुसार घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने का प्रावधान है तथा यह एक सतत् प्रकिया है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और जो आपने जवाब दिया, उससे मैं संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्षः विषय खतम।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने दीन दयाल

ज्योति योजना और सौभाग्य योजना से गांव को तो जोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी ऐरिया में मगरा-ढाणी, जो पहाड़ी पर रहने वाले हैं, पूर्व सरकार ने तो वहां केवल वोट लेने का काम किया, मगर अपने यहां की डबल इंजन सरकार से मुझे उम्मीद है कि उनको आप लाइट देंगे, तो आप किस योजना से उनको जोड़ने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के 31 गांवों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ऑन ग्रिड 1002 कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। धरती आभा योजना के अंतर्गत यह प्रस्ताव बनाकर हमने केन्द्र सरकार को भेजे हैं, जैसे ही वहां से स्वीकृति प्राप्त होगी, इन गांवों को जोड़ा जायेगा। इनको ऑन ग्रिड कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से इनको लाभान्वित किया जायेगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पूर्व सरकार में तो आये दिन कटौती होती थी, मगर इस सरकार के आने के बाद कटौती तो बंद हो गई ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः नो, नो, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 400 केवी सब स्टेशन घासा में बनने जा रहा है, वो घासा का सब स्टेशन बन जायेगा तो हमारे यहां जो गर्मी में कटौती होती है, वो भी बंद हो जायेगी, तो कब तक यह पूरा हो जायेगा?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिस धोलिया उदयपुर 400 केवी जीएसएस के बारे में आपने पूछा है, इसकी निविदा प्रक्रिया में है और निविदा खोल दी गई है। अभी यह नेगोसिएशन में है, शीघ्र ही निविदा के कार्यादेश जारी करके इसका काम प्रारम्भ किया जायेगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्रीमती गीता बरवड़।

परिवहन निगम में महिला कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव

289. श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग की महिला कार्मिक चाइल्ड केयर लीव प्रदान की जाती हैं? यदि हां, तो कितने दिवस की व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

परिवहन मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग की पात्र महिला कार्मिक को पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730

दिवस की चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देय है। इस हेतु निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक 213 दिनांक 25.07.2019 की प्रति परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि 25.7.2019 में यह लागू किया गया, लेकिन 2019 से पहले जो कार्मिक हैं, उनका क्या होगा? 2019 में जब यह लागू किया तो यह चालू कब होगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसका मैटर यह है कि इसमें जो कर्मचारी सेवा में है, उनको चाइल्ड केयर लीव दिया जा रहा है और जो निगम के श्रमिक और कार्यशाला कर्मचारी हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवा नियम 1965 से शासित कर्मचारियों को देय अवकाश लाभ एवं सेवा शर्त तथा श्रमिक एवं कार्यशाला कर्मचारियों का स्थाई आदेश 1965 से शासित कर्मचारियों को देय अवकाश का लाभ सेवा शर्त भिन्न-भिन्न हैं। अत: निगम के सेवा नियम, विनियम 1965 से शासित कर्मचारियों को राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप चाइल्ड केयर लीव देय है, परंतु आदेश 1965 से शासित कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देय नहीं है। इसलिए यह आदेश 1965 के शासित कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव दिये जाने बाबत प्रकरण विचाराधीन लिया गया है तथा दिनांक 9.7.2024 को वित्त विभाग से लौटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इसका हम पुन: परीक्षण करवायेंगे और इसके बारे में जो भी दिशा-निर्देश होगा, आपको बता देंगे।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगी कि यह काम कब तक हो जायेगा?

Msk/rtm/05.03.25/1140/1e

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इस काम को बहुत जल्दी, क्योंकि यह चिन्ता हमको भी है। जब आप कर्मचारियों को दे रहे हैं, हमने ही चिन्ता करके इन श्रमिक कर्मचारियों के लिए भी किया था और हमने फाइल चलाकर वित्त विभाग से पूछा भी है, लेकिन जो जवाब आया है, हम उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। हम दुबारा परीक्षण करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामबिलास।

लालसोट में खण्ड कार्यालय की स्थापना

290. श्री रामबिलास (लालसोट): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लालसोट में खण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र लालसोट की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से बनाये रखने का कार्य दौसा

मुख्यालय पर स्थित खण्ड द्वारा किया जा रहा है। खण्ड दौसा के अंतर्गत वर्तमान में 04 उपखण्ड कार्यालय (यथा- नगर उपखण्ड दौसा, ग्रामीण उपखण्ड-दौसा, लालसोट एवं रामगढ़ पचवारा) कार्यरत हैं।

खण्ड दौसा कार्यालय के वर्तमान कार्यक्षेत्र/कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए लालसोट मुख्यालय पर नवीन खण्ड कार्यालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामबिलास (लालसोट): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

गंग कैनाल में आ रहे कैमिकल युक्त पानी की रोकथाम

291. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंजाब की फैक्ट्रियों का अपशिष्ट, कैमिकल युक्त पानी व बूढा नाला का दूषित पानी गंग कैनाल में प्रवाहित किया जा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा गंग कैनाल में आ रहे दूषित पानी की नियमित रूप से जांच की जा रही है? यदि हां, तो अन्तिम बार पानी की जांच कब की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गंग कैनाल में आ रहे दूषित पानी को श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में पेयजल हेतु वितरण किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दूषित पेयजल की रोकथाम हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) पंजाब राज्य के लुधियाना शहर का प्रदूषित जल बूढा नाला के माध्यम से सतलुज नदी में प्रवाहित किया जाता है एवं जालन्धर, नाकोदर तथा फगवाड़ा शहरों का सीवरेज जल एवं औद्योगिक अपशिष्ट काली बेन में प्रवाहित किये जाते हैं, जो कि सतलुज नदी में मिल जाता है। सतलुज नदी का पानी हरिके बैराज से इन्दिरा गांधी नहर, सरहिन्द फीडर व बीकानेर कैनाल के माध्यम से राजस्थान में आ रहा है, जिसमें बीकानेर कैनाल का पानी गंग कैनाल में प्रवाहित होता है।

(2) जी हां। बीकानेर कैनाल की आर.डी. 368.50 (राजस्थान-पंजाब बॉर्डर) पर रीयल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम (RTWQMS) स्थापित किया गया है, इससे बीकानेर कैनाल के माध्यम से गंग कैनाल में आ रहे पानी की पी.एच., टरबीडिटी, कन्डक्टीविटी, वाटर टेम्परेचर, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, बॉयो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजोल्व्ड अमोनिया नाइट्रेट्स एवं क्लोराईडस पैरीमीटर्स की जांच हो रही है, जिसकी सूचना ऑनलाइन प्रत्येक घण्टे के अन्तराल पर राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड जयपुर एवं जल संसाधन कार्यालय हनुमानगढ़ में स्थापित कंट्रोल रूम में

प्रदर्शित हो रही है, माह जनवरी, 2025 की रिपोर्ट परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा श्रीगंगानगर जिले में विद्यमान गंगनहर प्रणाली से प्राप्त हो रहे जल के नमूनों में हैवी मेटल्स यथा आर्सेनिक, केडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, लैड, मर्करी, निकल, सिलेनियम, जिंक की जॉच प्रत्येक माह केन्द्रीय प्रयोगशाला जयपुर से करवायी जा रही है तथा सामान्य रासायनिक, जीवाणु, डीओ, बीओडी, सीओडी की जांच विभागीय जिला प्रयोगशाला श्रीगंगानगर स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है। इन जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार गंग कैनाल का पानी श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न 313 ग्रामीण पेयजल योजनाओं तथा 07 शहरी जल योजनाओं द्वारा पेयजल हेतु सेडीमेन्टेशन टैंक में जल निथार कर स्लौसैण्ड फिल्टर/रेपिड ग्रेविटी फिल्टर के माध्यम से जल को परिष्कृत किया जाता है तथा क्लोरिन गैस/ब्लीचिंग पाउडर द्वारा क्लोरीनेशन करने के पश्चात जीवाणु रहित कर वितरण प्रणालियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक पूछिये।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): एक बड़ा गंभीर विषय है, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। पंजाब के लुधियाना शहर की फैक्ट्रियों से निकलने वाला कैमिकल अपशिष्ट व सीवरेज का गंदा पानी बूढा नाला के माध्यम से सतलुज नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जो सरकार ने भी माना है। इसकी वजह से राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित 12 जिलों में कैंसर, किडनी जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। अध्यक्ष जी, हमारे पदमपुर के गुलाल सिंह ओलख, जो महात्मा गांधी हॉस्पीटल जयपुर में भर्ती हैं, इनकी लेफ्ट साइड की किडनी में गांठ बन गयी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): एक सैकण्ड साहब। डॉक्टर बोला कि किडनी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो यह कैंसर का रूप ले लेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि पंजाब के लुधियाना शहर से केमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल अपशिष्ट व सीवरेज का गंदा पानी बूढा नाला के माध्यम से सतलुज नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, उसको सरकार बन्द करने का विचार रखती है या नहीं? हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 के तहत राजस्थान ने पत्र दिनांक 25.05.2010 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण मण्डल को पिटीशन भेजकर कानून अनुसार कार्यवाही हेतु निवेदन किया है। इसके उपरांत केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की टीम ने वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2013 एवं वर्ष 2014 में क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, जल के नमूने एकत्रित किये। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इन नमूनों की जांच में दूषित पानी प्रवाहित किये जाने की पुष्टि हुई। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पत्र दिनांक 10.11.2014 द्वारा सर्वेक्षण में प्रदूषित पानी की पुष्टि होने पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रदूषण के मुख्य स्त्रोतों का विस्तृत विवरण देते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपिसिटी बढ़ाने, स्थापित ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने तथा अशोधित सीवरेज सतलुज नदी में प्रवाहित नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये, जिस पर पंजाब सरकार द्वारा कार्यवाही जारी है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। प्रश्न पूछो।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ी गंभीर समस्या है। क्या हमें इससे निजात मिल पायेगी, साहब अभी तक यह जवाब नहीं आया है। स्पष्ट जवाब दें, 12 जिलों के लोग हम 200 लोगों और इस सदन की तरफ देख रहे हैं। हमें इस बीमारी से निजात दिलायी जाये।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 2006 से 2014 के बीच में हमने पंजाब सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बोर्ड और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बोर्ड को लगभग 66 पत्र लिखे। इसके अलावा भी हम पंजाब सरकार द्वारा सतलुज नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में कुल 57 एसटीपी का निर्माण कर उसके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है तथा 10 नये एसटीपी, सीईटीपी का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इसके अलावा भी हम अपने बीकानेर कैनाल की आरडी 368.50, जो राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर है, पर रियल टाइम वॉटर क्वालिटी पैरामीटर उपलब्ध होते हैं, जो कि रॉ वॉटर होने से इन पैरामीटर के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ट्रीटमेंट हेतु सिस्टम समय समय पर अपग्रेड कर नॉर्म्स के अनुसार पैरामीटर प्राप्त होने पर ही हम पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण राम।

होम गार्ड जवानों को नियमित रोजगार

292. श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या गृह रक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार होमगार्ड जवानों को 365 दिन नियमित रोजगार देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार होमगार्ड अधिनियम, 1962-63 में संशोधन कर होमगार्ड सेवा नियम बनाए जाने व होमगार्ड को ईपीएफ सुविधा दिए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह रक्षा मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) जी नहीं। राजस्थान होम गाड्‌र्स अधिनियम, 1963 की धारा 2 के अनुसार होम गाड्‌र्स एक स्वयं सेवक निकाय है।

विभिन्न विभागों/एजेन्सियों को आवश्यकता होने पर, उनकी मांग अनुसार राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 4 एवं राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 के नियम 17 के तहत नामांकित होम गार्ड्स का नियोजन किया जाता है।

(2) जी नहीं। राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान होम गार्ड्स नियम, 1962 में संशोधन कर होम गार्ड्स सेवा नियम बनाए जाने व होमगार्डों को ईपीएफ सुविधा दिए जाने का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 की धारा 2 के अनुसार होम गार्ड्स एक स्वयं सेवक निकाय है। होमगार्ड स्थायी/अस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में नहीं होने के कारण इनको कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत ईपीएफ की सुविधा देय नहीं है।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्षः पूरक पूछो।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): क्या यह सही है कि जिन होम गार्डों की नियुक्ति विभिन्न विभागों में कर ली जाती है, उन्हें लगातार नियमित रोजगार मिल जाता है, जबकि कई होम गार्ड जवान लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं और उनकी नियुक्तियों में काफी अंतराल आ जाता है। ऐसे में उन्हें काफी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। मेरा मंत्री महोदय से सवाल है कि क्या सरकार होम गार्ड जवानों की नियुक्तियों में रोटेशन प्रणाली अपनाकर लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा में बैठे होम गार्ड के जवानों को भी विभिन्न विभागों में आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा रखती है। यदि हां तो कब तक? नहीं तो क्यों, विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह बात सही है कि होम गार्ड की नियुक्ति मांग के अनुसार सरकार के अन्य उपक्रमों में भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, होम गार्ड की ड्यूटी कितने समय लगे, कितने समय न लगे, वह वहां का अधिकारी तय करता है। यह बात सही है कि किसी होम गार्ड को तो लंबे समय तक ड्यूटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। यह पारदर्शिता रखने के लिए हमने एक सिस्टम डवलप किया है, इसका प्रयोग हम पांच जिलों में कर रहे हैं, उसके बाद सभी जगह लागू करेंगे। तो इससे यह पता लगेगा कि कितने होमगार्ड लगातार लग रहे हैं और कितने नहीं लग रहे हैं। यह हम उससे देख पायेंगे तो अब यह समस्या नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है कि क्या सरकार दो माह से अधिक रोजगार की प्रतीक्षा में बैठे होमगार्ड के जवानों को न्यूनतम मजदूरी भत्ता प्रदान करने का विचार रखती है, जिससे उन्हें आर्थिक संकटों से नहीं जूझना पड़े, यहि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्षः विराजें। माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, ये हमारे स्वयंसेवक हैं और जहां जरूरत होती है, वहां भेज रहे हैं। इसका कोई मापदण्ड तय नहीं है कि दो महीने नियमित ड्यूटी देंगे या नहीं देंगे। यह हम मांग के अनुसार भेजते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुखवंत सिंह।

बडौदामेव उप तहसील का गोविन्दगढ़ उपखण्ड में सम्मिलन

293. श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अलवर जिले में बडौदामेव उप तहसील क्षेत्र को गोविन्दगढ़ उपखण्ड में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): वर्तमान में उप- बडौदामेव को गोविन्दगढ़ उपखण्ड में सम्मिलित करने संबंधी कोई प्रस्ताव राजस्व विभाग में विचाराधीन नहीं है।

श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न है कि क्या सरकार में बड़ौदामेव उप तहसील क्षेत्र को गोविन्दगढ़ उप खण्ड में सम्मिलित करने का विचार रखती है? क्योंकि अभी बड़ौदामेव उप तहसील क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ उप खण्ड में सम्मिलित है, जो कि दूसरे विधान सभा क्षेत्र में आता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में उप तहसील बड़ौदामेव को गोविन्दगढ़ उप खण्ड में शामिल करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव राजस्व विभाग में विचाराधीन नहीं है, परन्तु माननीय विधायक महोदय ने जो चीज बतायी है, उसके बारे में आपसे मैं संपर्क कर लूं या आप मेरे से संपर्क कर लें। जो भी समस्या आपने बतायी है, उसका समाधान भविष्य में करने का प्रयास करेंगे।

श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी

प्रदेश में 'एक राज्य, एक चुनाव' हेतु समिति का गठन

294. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 'एक राज्य, एक चुनाव' की प्रक्रिया वर्तमान में किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है?

(2) उक्त प्रक्रिया को लागू करने के लिए क्या किसी समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो समिति की अब तक कितनी बैठकें आयोजित कर क्या-क्या निर्णय लिए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या 'एक राज्य, एक चुनाव' के लिए विधि में संशोधनों की अनुशंषा की गयी है?

राज्य मंत्री, नगरीय विकास (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) राज्य में नगरीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन हेतु स्वायत्त शासन विभाग में सीमावृद्धि एवं परिसीमन का

कार्य प्रक्रियाधीन है, इस संबंध में जारी चरणबद्ध कार्यक्रम परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

'एक राज्य, एक चुनाव' के संबंध में विधिक राय ली जा रही है, प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं परिसीमांकन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण एवं समीक्षा हेतु आदेश दिनांक 16.01.2025 से एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया है, आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त उप समिति की बैठक उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) वर्तमान में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधिक राय ली जा रही है, प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि राजस्थान के जो सभी नगर निकायों में एकीकृत चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है एवं इससे राजस्थान की जनता को क्या लाभ होंगे?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 'एक राज्य, एक चुनाव' का एक मूल उद्देश्य यह है कि आज की वर्तमान स्थिति में हमारे पास जितने नगर निकाय हैं, उनके चुनाव लगभग आठ चरणों सम्पन्न हुए थे। बार-बार चुनाव सम्पन्न होने से बार-बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए भारत सरकार के 'एक राष्ट्र, एक निर्वाचन' कार्यक्रम के परिपेक्ष में राज्य में भी 'एक राज्य, एक चुनाव' योजना पर राज्य सरकार वर्ष 2024-25 में बजट घोषणा संख्या 97.6 (01) की गयी थी।

mdp/rtm/05.03.25/11:50/1f

सभी नगर निकायों का चुनाव एक साथ हो और बार-बार लगने वाली आचार संहिता से विकास में जो व्यवधान पैदा होता है, वह समाप्त हो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। कोई है?

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जो ये नगर निकायों की चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या एकीकृत चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग होगा? अगर हां, तो सभी चुनाव एक साथ कराने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी और उनकी उपलब्धता के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर

निकायों के चुनाव करवाने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अभी नगर निकायों की सीमा वृद्धि, परिसीमन और वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है। ये पूर्ण होने के बाद पता चलेगा कि राज्य के नगर निकायों में कुल कितने वार्ड गठित होंगे। छोटी नगर पालिकाओं में सामान्यत: एक वार्ड में एक पोलिंग स्टेशन बनता है। लेकिन नगर परिषद और नगर निगम होंगे, उनमें एक-एक वार्ड में पांच से लेकर सात तक या दस तक भी पोलिंग स्टेशन बनेंगे, बूथ बनेंगे तो उसी के हिसाब से मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य निर्वाचन आयोग के पास जितनी मशीनें उपलब्ध होगी, इसके अलावा वह पड़ोसी राज्यों से, अब तक कि जिस प्रकार की प्रक्रिया है, पड़ोसी राज्यों से वोटिंग मशीन मंगवाकर इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पहले तो आप बता दीजिए चुनाव कब होंगे? क्योंकि सबको चिंता हो रही है कि चुनाव कब होंगे, इसकी तारीख नहीं आ रही है। पहला प्रश्न तो मेरा यह है। दूसरा, मेरा यह है कि जो सरपंच बने थे, सरपंचों का तो आप लोगों ने टाइम बढ़ा दिया, लेकिन वे ही सरपंच जहां थे और वहां नगरपालिका बन गयी, उनको चैयरमेन बना दिया। उनको जो आर्डर हुआ था, वह यह हुआ है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा, तब तक आप इसके चैयरमेन रहेंगे। ये दोहरी नीति सरकार क्यों अपना रही है कि सरपंचों का, उन्हीं सरपंचों का कार्यकाल तो बढ़ गया, लेकिन वे ही सरपंच जो चैयरमेन बन गये, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को और नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि अभी हमारा पुनर्सीमांकन और वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और मतदाता सूचियों का काम पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार का मानस ये है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव करा दिया जाए और ये अवधि लगभग-लगभग आपके नवम्बर के आसपास हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: श्री महेन्द्र पाल मीना।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): दूसरा, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष महोदय को बताना चाहूंगा कि पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग दो अलग-अलग विभाग है। पंचायती राज ने अपने स्तर पर निर्णय लिया है और स्वायत्त शासन विभाग ने अपने स्तर पर लिया है।

श्री अध्यक्ष: श्री महेन्द्र पाल मीना। अगला प्रश्न। हो गया। माननीय मंत्री जी, उत्तर आ गया। महेन्द्र पाल मीना।

जमवारामगढ़ में लंबित विद्युत कनेक्शन

295. श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में कृषि कनेक्शनों के कितने डिमांड नोटिस जमा है एवं कितने कृषकों को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये गये तथा कितने लम्बित हैं। विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित कनेक्शनों को कब तक जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र जमावरामगढ में विगत पांच वर्षों एवं इस वर्ष 31 जनवरी 2025 तक कृषि के जमा मांग पत्र, जारी कनेक्शन एवं लम्बित कनेक्शनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया। मैं संतुष्ट हूं। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय से...

श्री अध्यक्ष: संतुष्ट हैं तो अगला प्रश्न पुकारे।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बोलिए। मैं तो कह रहा हूं आप पूछो।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लंबित कनेक्शनों को कब तक जारी करेंगे?

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि लंबित कनेक्शनों को कब तक जारी करेंगे, माननीय सदस्य, जो 31/01/25 की सूचना है, उसके अनुसार जो लंबित कनेक्शन हैं, वह हमारे पास 28/02/25 तक जमवारामगढ़ में 245 कनेक्शन लंबित हैं, जिनमें से 234 कनेक्शन फसल के खड़ी होने से रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण या कहीं पर बोरिंग की उपलब्धता नहीं होना, अन्य कारणों से कनेक्शन जारी करने में जो बाधा आ रही है, उसकी वजह से कनेक्शन लंबित हैं। 11 कनेक्शनों का कार्य प्रगतिरत है। जैसे ही फसल की कटाई होगी, रास्ते उपलब्ध होंगे और वे कारण दूर होंगे तो वे कनेक्शन आने वाले इस मई-जून के पहले-पहले करने का हमारा प्रोग्राम है।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि आपने बजट में जमवारामगढ़ को तीन बड़े-बड़े कनेक्शन दिए, तीन बड़े जी.एस.एस. दिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 296

श्री अध्यक्ष: श्री अनिल कुमार कटारा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री आदू राम मेघवाल।

बाड़मेर के सैनिक आश्रित परिवारों को सहायता

297. श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर के सैनिक आश्रित परिवारों के नौकरी, सहायता, मुआवजा व अन्य लाभ के कितने प्रकरण वर्तमान में कौन-कौनसे कार्यालयों में किस स्तर पर कब से लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सैनिक आश्रित परिवार के सदस्यों को किन-किन नियम या प्रावधानों के आधार पर नौकरी व अन्य लाभ प्रदान किए जाते है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सैनिक कल्याण मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जिला बाड़मेर के बैटल कैजुअल्टी (फेटल) एवं ऑपरेशनल कैजुअल्टी (फेटल) तथा बैटल कैजुअल्टी (नॉन फेटल) एव फिजिकल कैजुअल्टी के आश्रितों के नियोजन एवं विद्यालय नामकरण से संबंधित प्रकरण विभिन्न कार्यालयों में लंबित हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार उक्त लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने का प्रयास कर रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है। लंबित प्रकरणों मे आ रही कमियों को संबंधित विभागों के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही कर, शीघ्र ही लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।

(3) सैनिक आश्रित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति एवं अन्य लाभ दिए जाने के नियम व प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट "ख" एवं "ग" पर संलग्न है।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौहटन के बाछड़ाऊ ग्राम निवासी अमर शहीद पीराराम की प्रतिमा मूर्ति बाछड़ाऊ ग्राम के मुख्य चौराहे पर स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो शहीद की प्रतिमा कब तक स्थापित की जायेगी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न सुनाई नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य एक बार फिर प्रश्न पूछें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक बार दोबारा पूछ लें।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौहटन के बाछड़ाऊ ग्राम निवासी अमर शहीद पीराराम की प्रतिमा मूर्ति बाछड़ाऊ ग्राम के मुख्य चौराहे पर स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो शहीद की प्रतिमा कब तक स्थापित की

जायेगी?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि सरकार की योजनाओं में अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो बैटल कैजुअल्टी हो या फिजिकल कैजुअल्टी हो या उनके आश्रितों को नियोजन हो या उनको पेंशन हो, ये सारी सुविधाएं हैं। जो आप मूर्ति की बात कर रहे हैं ये मूर्ति गांव स्थापित करता है, सरकार नहीं करती।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): दूसरा प्रश्न है कि क्या ये सही है कि संपूर्ण बाड़मेर जिले के शहीद विधान सभा क्षेत्र चौहटन में अमर शहीदों के नाम पर राजकीय विद्यालयों के नामकरण सम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव लम्बे समय से लंबित हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र चौहटन में शहीद मूलाराम के नाम राजकीय विद्यालय का नामकरण सम्बन्धी लंबित प्रस्ताव प्रकरण का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? साथ ही, बाड़मेर जिले में नामकरण सम्बन्धित अन्य प्रस्ताव प्रकरणों का निस्तारण कब तक किया जायेगा?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी बाड़मेर जिले के अन्दर विद्यालय नामकरण से सम्बन्धित केवल एक ही प्रकरण है, जो अभी लंबित है। उसका कारण ये था कि परिवार ने उच्च विद्यालय के नामकरण की अपेक्षा रखी थी, जो नियमों के अन्दर नहीं था। हमारे सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी ने परिवार को समझाया। उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त थी, वह माध्यमिक शिक्षा के लिए अब रखी है। वह प्रकरण लंबित है, इसको तुरंत जल्दी हम करवा देंगे। एक ही प्रकरण है, जो लंबित है।

प्रश्न संख्या 298

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 299

अगला प्रश्न। श्री शान्ती धारीवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री ललित मीना।

किशनगंज के मां-बाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण

300. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कितनी मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा कितनी मां बाड़ी किराये के भवनों में संचालित हैं?

(2) क्या सरकार उक्त मां-बाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में 15 मां-बाड़ी व 251 डे-केयर सहित कुल 266 केन्द्र स्वीकृत हैं। जिनमें से 15 मां-बाड़ी व 21 डे-केयर सहित कुल 36 केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मां-बाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जा सकेगा।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे मां-बाड़ी और डे-केयर जो सेंटर हैं, उनमें भवन नहीं है और वहां पर पट्टे भी नहीं है। आप कब तक उनको फंड जारी कर देंगे ताकि वे उनके भवन में चल सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य का चिंता करना वाजिब है।

Ans/rtm 12.00 1g 05.03.2025

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य की चिंता करना वाजिब है। अध्यक्ष महोदय, जी, मां-बाड़ी के भवन बनाने का काम पिछली सरकार के समय नहीं हुआ ...(व्यवधान)... यह आपने नहीं किया, अब हम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: उत्तर दीजिए, 12 बज रहे हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अब हम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इधर। माननीय मंत्री जी, इधर सम्बोधित करे।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सुनो ना ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। माननीय मंत्री जी, विराजिये।

अनुपस्थिति अनुमति

जयदीप बिहाणी, श्री, सदस्य को 04 मार्च, 2025 से 12 मार्च, 2025 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री जयदीप बिहाणी सदस्य विधान सभा ने अपनी अस्वस्थता के कारण दिनांक 04 मार्च, 2025 से 12 मार्च 2025 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह देखो, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप उठ तो गये थे। अब सब लोग जागरूक हो गए हैं।

सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

कटौती प्रस्तावों की अग्राह्यता से बचने के लिए माननीय सदस्य उनकी नियमानुसार प्रस्तुति सुनिश्चित करें

मुझे दो जानकारियां और देनी है। हम लोग डिमांड्स पर प्रतिदिन कटमोशन लगाते हैं। सबको पता है एक-एक डिमांड पर पांच कटमोशन अपन लगा सकते हैं। लेकिन रोजाना मेरे पास फ़ाइल आती है कि आप इनको निरस्त करें। या तो कटमोशन उस विषय के ही नहीं होते हैं या फिर पांच से ज्यादा होते हैं, या फिर समय सीमा के बाद देते हैं, ऐसी स्थिति ना आये। मेरा सभी से आग्रह है कि हम सही समय पर पांच से ज्यादा नहीं लगाये ओर विषय के अनुसार लगाये। जिस विषय का जिस दिन है, उसी विषय का लगाये तो सुविधा होगी।

प्रश्न काल में सदस्य की अनुपस्थिति में अधिकृति हेतु समय पर सूचना प्रस्तुत करें

दूसरा, कई बार प्रश्न में कोई एबसेंट रहता है, दूसरे को प्रश्न पूछने के लिए मेरे पास स्लिप आता है1 एक व्यवस्था है कि कोई सदस्य आज छुट्टी पर रहने वाला है, दूसरे को अधिकृत करके, समय से, 11 बजे से पहले मुझे पत्र देगा, मैं उसको अनुमति दे दूंगा। ...(व्यवधान)...

दो मिनट बाद आ जाते। विराजो। हो गया, यह काम मेरा है। माननीय, मेरा काम मुझे करने दे, आपका काम आप करें। सभी अगर मेरा काम करने लग जाएंगे तो कठिनाई होगी। ...(व्यवधान)... वह तो मुझे पता है कौन कितना सहन नहीं करता, इस बात को रहने दो। कोने की सीट पर बैठ जाओ, अपनी सीट पर नहीं। मैंने अनुमति दे दी, कोने की सीट पर बैठ जाओ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1.श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से डिग्गी अनुदान योजना में आवेदन की अवधि न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री भगवाना राम सैनी, सदस्य की ओर से उदयपुरवाटी स्थित ट्रोमा सेंटर प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से टोंक ज़िले के समरावता गांव में प्रशासनिक पुनर्गठन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना के खनन क्षेत्र में सड़क निर्माण नियम अनुरूप नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री डूँगरराम गेदर, सदस्य की ओर से प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री अशोक कुमार कोठारी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर से गुजरने वाली मेजा नहर की सुरक्षा दीवार न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से प्रदेश में संविदा कर्मियों के शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से रतनगढ़ कस्बे के मध्य से गुजरने वाली रेलवे लाईन से आवागमन में हो रही परेशानी के संबध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

10. श्री अमीन कागजी, सदस्य की ओर से जयपुर में एम.आई.रोड पर पेयजल लाईन डालने से क्षतिग्रस्त सड़क से हो रही परेशानी के संबंध में।

11. श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से रेलवे स्टेशन डाबला जिला सीकर निवासी श्री सुनील जांगिड़ की गुमशुदगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12.श्री मुकेश भाकर, सदस्य की ओर से ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का स्थायी रजिस्ट्रेशन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13.श्री पुष्कर लाल डांगी, सदस्य की ओर से ग्राम रूडेडा तहसील वल्लभनगर निवासी श्रीमती मीनाबाई मेनारिया की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमीन कागजी, श्री सुरेश मोदी, श्री मुकेश भाकर एवं श्री पुष्कर लाल डांगी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्य, हम लोग स्थगन लगाते हैं, विपक्ष लगाता है। आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन स्थगन ऐसे विषय पर लगाये जो तात्कालिक हो, जो असाधरणतया डिमांड्स में नहीं आने वाले हों। जिन विषयों पर आप डिमांड्स पर बोल सकते हों, उन पर स्थगन मोशन नहीं लगायें और उसको देने की अनुमति चाहे चार ना भी आयें, दो होंगे तो भी देंगे, लेकिन उसी पर होगा जो डिमांड्स पर नहीं हो और तात्कालिक हो। बिना उसके कि पहले का है, छोटी-मोटी बातों पर स्थगन सदन का नहीं होता। यह हम सब लोग सावधानी बरतेंगे तो सुविधा होगी

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के बाधों को राम जल सेतु लिंक परियोजना से जोड़े जाने के संबंध में।

2. श्री अरूण चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित औद्योगिक इकाईयों के सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग स्थानीय क्षेत्र में किये जाने के संबंध में।

3. श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में बालिका विद्यालय खोले जाने के संबंध में।

4. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में प्रगतिरत सीवरेज कार्य के गुणवत्ता विहीन होने के संबंध में।

5.श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंगल फेज कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के संबंध में।

6. श्री धर्मपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी स्थित रीको में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के संबंध में।

7. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से नगर पालिका राजगढ़ के वार्ड नं. 09 स्थित कच्चे जोहड़ की चारदीवारी के निर्माण के संबंध में।

8. श्री कंवरलाल, सदस्य की ओर से पुलिसकर्मियों की समय पर डीपीसी कराने तथा उन्हें साप्ताहिक अवकाश दिये जाने के संबंध में।

9. श्री राजेन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महवा में फ़सलों की खरीद समर्थन मूल्य पर किये जाने के संबंध में।

10. श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवाली के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

11. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के संबंध में।

12. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से पुलिस थाना केसरीसिंहपुर में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 14/2025 की निष्पक्ष जांच के संबंध में।

13.श्री राधेश्याम बैरवा, सदस्य की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने के संबंध में।

14. श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में जल जीवन मिशन से वंचित क्षेत्रों को जोड़े जाने के संबंध में।

15. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सड़कों तथा पुलियाओं का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 05/03/2025 को शून्यकाल में बोलने हेतु 37 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	मा. सदस्य का नाम	विषय
1.	श्री हरलाल सहारण	चूरू विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या के संबंध में।

2.	श्री संदीप शर्मा	मंदिर माफी की ज़मीनों एवं पुजारियों को राजकीय संरक्षण प्रदान करने के संबंध में।
3.	डॉ. सुभाष गर्ग	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहनेरा के टैण्डर एवं कार्यादेश होने के उपरांत भी भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
4.	श्री आदूराम मेघवाल	चौहटन विधानसभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण बाड़मेर ज़िले में जंगली सूअरों (भंड्रो) द्वारा किसानों की फ़सलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचाने तथा आतंक से उत्पन्न विकट स्थिति के संबंध में।

माननीय श्री अमीन कागजी। अब आप अपनी सीट पर आ सकते हैं।

VPS-RTM-05.03.2025-12.10-1h

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जयपुर में एम.आई. रोड पर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि एम.आई. रोड जो जयपुर की एक मुख्य सड़क है, पिछले काफी महीनों से यह टूटी हुई है। तकरीबन दो साल पहले ही इस सड़क को नया बनाया गया था और उसके बाद अभी इसके अन्दर एक पानी की लाइन एम.आई.रोड पर अजमेरी गेट से लेकर पांच बत्ती होते हुए गवर्नमेंट हॉस्टल तक डाली गयी है। मैं इसमें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरी सड़क जर्जर हो गयी, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब मैंने अधिकारियों से इसके बारे में बात की तो मुझे यह बताया गया कि इसके रोड कट के पैसे पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट द्वारा जे.डी.ए. को जमा करवाये काफी समय हो गया।

श्री अध्यक्ष: आप बैठकर बात करें। माननीय सदस्य, बैठकर बात करें।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): जे.डी.ए. के अधिकारियों से जब मेरी इस बारे में बात हुई तो यह अवगत करवाया गया कि अभी इसको रिपेयर करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो कल जब मेरी अधिकारियों से बात हुई तो मैंने उनसे यह कहा कि जब आपके पास पिछले काफी दिनों से इस रोड कट का पैसा पी.एच.ई.डी. ने जमा करवा दिया तो यह सड़क रिपेयर क्यों नहीं हो रही है? इसी तरीके से जवाहर नगर की काफी कॉलोनियों में भी सड़कें तोड़ी गयीं। इसी तरीके से जौहरी बाजार जो कि एक मुख्य बाजार है, उसमें भी पी.एच.ई.डी. की लाइन डली और उसमें भी आज यही हालात हैं। जैसा कि आप सब लोगों को ध्यान है कि जयपुर में इस टाइम ट्यूरिस्टों का बोलबाला है और जयपुर की ये जो मुख्य सड़कें हैं, चाहे

एम.आई.रोड हो या जौहरी बाजार की सड़क हो या चाहे परकोटे की अन्य सड़कें हों, ये सारी जल जीवन मिशन के तहत और अमृत योजना के तहत तोड़ दी गयीं और इसमें पानी की जो लाइनें डाली गयीं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया धीरे बोलें। यहां तक आवाज नहीं आये।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): पानी की जो लाइनें डाली गयीं, जब अधिकारियों से मेरी इस बारे में बात हुई तो काफी जगह का पैसा, कुछ नगर निगम में और कुछ जे.डी.ए. में पैसा जमा हो चुका है। मेरा आपसे यह आग्रह है कि सरकार के जितने भी अधिकारी यहां पर बैठे हैं और मंत्री बैठे हैं यह जे.डी.ए. और एल.एस.जी. डिपार्टमेंट, दो जगह के ये काम हैं, तुरंत प्रभाव से इस सड़क को रिपेयर किया जाये, ताकि जयपुर की जनता को और बाहर से आने वाले ट्यूरिस्टों को एक अच्छा मैसेज हमारे जयपुर शहर गुलाबी नगरी का जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश मोदी।

डाबला (सीकर) निवासी श्री सुनील जांगिड़ की गुमशुदगी

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का 42 साल का युवक सुनील जांगिड़ जो डाबला रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान चलाता है, वह दुकान का सामान खरीदने के लिए 01 मार्च को अपनी कार से जयपुर आया था। उसके पास पुरानी देनदारी चुकाने के लिए और नई खरीददारी के लिए काफी रुपये भी थे। वह घर पर अपनी पत्नी को यह कहकर आया था कि मैं शाम तक काम पूरा करके वापस डाबला आ जाऊंगा। 01 मार्च को रात को करीब साढ़े नौ बजे उसकी पत्नी से बातचीत हुई और उसने पत्नी को यह कहा कि मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह गया है अगर यह अभी पूरा हो गया तो मैं रात को ही घर आ जाऊंगा वरना सवेरे जल्दी घर आ जाऊंगा और रात को किसी होटल में ठहर जाऊंगा, पर अभी तक भी वह व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंचा है, डाबला नहीं पहुंचा। उसका मोबाइल बंद आ रहा है। उसके परिवारजनों ने एक तारीख तक, दो तारीख तक इंतजार करके, जब वह नहीं पहुंचा तो वे जयपुर आये, उन लोगों ने दुकानदारों से, जिनसे वह माल खरीदता था, उनके पास तलाश किया, आसपास के होटलों में तलाश किया, टोल टैक्स के नाके पर भी उन्होंने यह तलाश की कि उस कार के नम्बर की कोई एंट्री उनको मिले, लेकिन उनके जो प्रयास हैं, वे सफल नहीं हुए और अंततः उन्होंने 02 तारीख को डाबला पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज करवाई।

सभी दुकानदारों और आसपास के जो जानकार थे, उन लोगों का यह कहना है कि 01 तारीख को दिन में उसको उन लोगों ने देखा है, उन लोगों से सम्पर्क हुआ है लेकिन 01 तारीख की शाम के बाद उसका सम्पर्क किसी से नहीं हुआ। वह व्यक्ति अकेला परिवार में प्रमुख कमाने वाला था और सारा परिवार आज दहशत में है। डाबला के व्यापारियों ने पूरा व्यापार बंद कर रखा है, जाम लगा रखा है। नीम का थाना क्षेत्र की अधिकतर पुलिस खाटू श्यामजी के मेले में गयी हुई है, वह हमेशा लगती है खाटू श्यामजी के मेले में इसलिए उस

पर पुलिस की तरफ से कोई उचित कार्यवाही नहीं हो पा रही है तो गृह राज्य मंत्री यहां पर विराज रहे हैं, उनसे आपके माध्यम से निवेदन है कि पुलिस विभाग को निर्देशित करके गुमशुदा व्यक्ति की तलाश कराएं और उसके परिवार को सम्बल प्रदान करें। एक स्पेशल टीम बनाकर उस पर लगायें। जयपुर का मामला है, घटना जयपुर में हुई है, इसलिए जयपुर की कोई टीम लगायें।

श्री अध्यक्ष: आपका विषय संज्ञान में आ गया। आप विराजें।

श्री मुकेश भाकर।

ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन का स्थाई रजिस्ट्रेशन

श्री मुकेश भाकर (लाडनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRT) की ओर से आवश्यकता महसूस की गयी कि भारी वाहनों की फिटनेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के जरिए कराई जाये, ताकि फिटनेस सही हो सके एवं परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं कम हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नियम बनाकर ए.टी.एस. लगाने हेतु लोगों को आमंत्रित किया एवं आवेदन पत्र मांग कर पात्र लोगों को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर लगाने के निर्देश दिये। राजस्थान में कई लोगों ने जमीन लेकर, इस प्रकार की मशीनें आयातित कर ए.टी.एस. लगा लिये एवं आवश्यक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाकर, यह सर्टिफिकेट भी साथ पेश कर कार्यवाही पूर्ण कर परिवहन विभाग को फाइनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विभाग से यह पूछना चाहता हूं कि आज लगभग छह माह व्यतीत होने के बावजूद भी इन लोगों को फाइनल रजिस्ट्रेशन कर ए.टी.एस. शुरू करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है एवं सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाएं रोकने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाये जा रहे हैं? ये लोग बैंकों से कर्ज लेकर कर्मचारी नियुक्त कर बैठे हुए हैं और ऐसे में आगे ए.टी.एस. लगाने का रास्ता बंद हो जायेगा तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इन लोगों को फाइनल रजिस्ट्रेशन करके राहत दी जाये ताकि आगे और भी ए.टी.एस. राजस्थान में लग सके। पुराने फिटनेस सेंटर्स को नये नियमों के तहत दी गयी अंतिम तारीख को बारबार इस कारण से बढ़ाया जा रहा है कि ए.टी.एस. नहीं लगे जबकि वास्तविकता यह है कि ए.टी.एस. को शुरू में लगाने वालों को भी चालू नहीं करवाया जा रहा है तो नये कैसे लगेंगे? सरकार प्राथमिकता के तौर पर इसको ले और ए.टी.एस. लगाने वालों को राहत दें।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्कर लाल डाँगी।

रूडेडा ग्राम (वल्लभनगर) निवासी श्रीमती मीनाबाई मेनारिया की हत्या

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। रूडेडा निवासी मीनाबाई मेनारिया घर से गाय खरीदने के लिए निकली थीं। रास्ते में एक व्यापारी मिला। उसने यह कहा कि मैं आपको गाय दिलाता हूं। मीनाबाई को साथ में ले जाकर उसकी रास्ते में हत्या कर दी, उसके जेवर ले लिये, उसके पास पैसे थे, वह सब भी ले लिये। ऐसा

गरीब परिवार है, पीछे कुछ नहीं है, छोटे-छोटे बच्चे हैं और परिवार को चलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हत्या करने वाले को मंगलवाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिस आदमी ने हत्या की थी..., पर मेरा सरकार से यह निवेदन है कि उस परिवार को कुछ सहायता दी जाये और उसके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाये, जिससे उसका परिवार चल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन के माध्यम से, मेरे मावली विधान सभा क्षेत्र के सरपंच संघ के अध्यक्ष देवी लाल डांगी जो सरपंच हैं वर्तमान नांदेल ग्राम पंचायत का, रात को साढ़े नौ बजे घर जा रहा था, रास्ते में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपको केवल इसी विषय पर बोलना है।

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): यह अलग से मांग की है, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन के जरिए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अलग से नहीं। दो मिनट की परमिशन इसी पर है। हां, इसी पर बोलें आप।

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): हां, इसी पर बोल रहा हूं मैं। देवीलाल डांगी जो सरपंच संघ का अध्यक्ष था और वर्तमान में सरपंच है, वह घर जा रहा था, रास्ते में मोटर साइकिल से दो लड़के जिन्होंने फायरिंग किया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह अलग विषय है, इस पर नहीं। आपको केवल एक की हत्या पर ही बोलना था। आप मोटर साइकिल और इस पर बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में मेरे सरपंच पर गोली मार दी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उस पर अलग से आओ।

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): गोली लग गयी, उस पर बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: 295, श्री मनीष यादव।

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए समय दें।

श्री अध्यक्ष: हत्या पर बोल लिये आप। हत्या पर और कुछ बोलना है तो बोलिये। यह दूसरा विषय है। यह कानून-व्यवस्था पर बहस नहीं है।

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): हत्या पर ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप उसी की हत्या पर, एक की, जिसका आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है। ...(व्यवधान)... केवल उसी हत्या पर बोलें जिसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। श्री मनीष यादव। यह क्या है? आप थोड़े ही कहोगे कि बोलो।

श्री पुष्कर लाल डाँगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर अपराध इतना हो रहा है, कोई अंकुश नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आप विराजिये। अलग से पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन आप देना। मना नहीं है। आप अलग से आओ।

श्री मनीष यादव।

ssy/rtm/05.03.2025/12.20/1j

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

शाहपुरा के बाधों का राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ाव

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के अन्तर्गत आने वाले निकाय शाहपुरा व मनोहरपुर तथा समस्त राजस्व गांवों में सिंचाई व पेयजल के पानी की विकट समस्या है। सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र भू जल की दृष्टि से डार्क जोन एरिया में सम्मिलित है।

विधान सभा क्षेत्र में मामटोरी-मनोहरपुर, शिखरगट्टा-देवन, दांतोडी-शिवसिंहपुरा व जमदेई-धवली सहित कुल चार बांध हैं। उक्त बांधो को PKC-ERCP में जोड़ने के लिए मैने 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 362 लगाया कि शाहपुरा के बांधो को ERCP में जोडने व क्षेत्र में सिंचाई के पानी की भी उपलब्धता के सन्दर्भ में सरकार क्या विचार रखती है? इसमें बताया गया कि वर्षा कम होने व भूजल स्तर गहरा होने के कारण क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल प्रवाह नही हो रहा है और बांधों को संशोधित DPR में जल उपलब्धता, तकनीकी व वित्तीय उपादेयता पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित बताया।

मैने पुनः द्वितीय सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 655 व अन्तः सत्र में प्रश्न संख्या 1831 के माध्यम से क्षेत्र के बांधो को जोडने की सरकार की मंशा पूछी, जिसमें बताया गया कि PKC-ERCP की DPR अंतिम चरण में है। DPR तैयार होने के बाद ही उक्त संदर्भ में जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

इसके उपरान्त मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तीनों सत्रों में प्रश्न व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी आग्रह किया गया है। सरकार का ध्यान पुनः आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करते हुए हमारे चारों बांधो को PKC-ERCP में जोड़ें जिससे क्षेत्र में पेयजल व सिचाई की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष श्री अरुण चौधरी।

औद्योगिक इकाईयों के सी.एस.आर. फंड

का स्थानीय क्षेत्र में उपयोग

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प की ओर प्रदेश अग्रसर है।

प्रदेश के प्रत्येक जिले में विभिन्न तरह के औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की

कंपनियां अपना कार्य कर रही है। उन कंपनियों से विभिन्न तरह के प्रदूषण भी फैल रहे हैं। साथ ही उस क्षेत्र में भारी औद्योगिकी के कारण जिले को आर्थिक रूप से किसी तरह का फायदा नहीं हो रहा है। प्रदेश में भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर शहर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, प्रदेश में विभिन्न सीमेंट कंपनियां, चित्तौडगढ़ की हिन्दुस्तान जिंक कम्पनी, बाड़मेर जिले की गिरल एवं कपूरडी तथा वेदान्ता ग्रुप के केयर्न कंपनी जोधपुर स्थित बोरावाडा औद्योगिक क्षेत्र आदि विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र संचालित है। साथ ही बालोतरा जिले की रिफाइनरी औद्योगिक क्षेत्र से भी आस-पास के इलाकों में पर्यावरण एवं अन्य रूप से कई तरह के आम जन को नुकसान भी होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के तहत सरकार से आपके मार्फत मांग करता हूँ कि प्रदेश में समस्त जिलों में जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, उन औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त राजस्व का हिस्सा एवं सीएसआर का फंड उस क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र में ही खर्च किया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे उस क्षेत्र विशेष में उन औद्योगिक इकाइयों से जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई हो सके और विशेष तौर से उस बजट की राशि को पर्यावरण संरक्षण में खर्च किया जाता है तो हमारी सरकार से जिस प्रकार प्रदेश को हरित बजट प्रथम बार दिया है, तो उसी अनुरूप प्रदेश में पर्यावरण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकेंगे।

साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय क्षेत्र के लोगों को भी उस औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने का आरक्षण अर्थात उस क्षेत्र विशेष के लोगों का कोटा निर्धारित होना चाहिए। जिससे उस क्षेत्र विशेष के लोग उस औद्योगिक इकाई में कार्य कर सकें एवं उस क्षेत्र का आर्थिक रूप से वहां रह रहे आमजन को फायदा प्राप्त हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द के विभिन्न क्षेत्रों में बालिका विद्यालय की स्थापना

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में निम्न स्थानों पर लम्बे समय से बालिका विद्यालय संचालित नही होने से बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रही हैं। बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये नवीन बालिका उच्च माध्यमिक विधालय ग्राम पंचायत बरसनी, कालियास, जिन्द्रास, तिलोली, मोड का निम्बाहेड़ा, पाटन (बदनोर), बढाढरों की सरेरी (हुरडा) में खोले जावें। इन सभी ग्राम पंचायत की विद्यालयों में बेटियों की संख्या अधिक है।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बेटियों के भविष्य के साथ कुठाराघात करते हुए बालिका विद्यालयों को महात्मा गांधी विद्यालयों में मर्ज कर दिया था। उन सभी को जैसे कि आसीन्द, बदनोर, शम्भुगढ, गुलाबपुरा में महात्मा गांधी विद्यालयों को हटाकर पुनः बालिका विद्यालयों में डी मर्ज कराकर संचालन करवाया जावे, जिससे हमारी बेटियां निडर होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

ग्राम पंचायत ईरास के हीरा खेड़ी, मोतीपुर के गांव नापाजी का खेड़ा, भोजरास में दोलतपुरा की ढाणी के विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया है, जिससे उक्त गांवों में शिक्षा का स्तर गिर गया है तथा मर्ज किये गये विद्यालयों की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक होने से पुनः उक्त स्थानों पर मर्ज विद्यालयों को डी मर्ज कर संचालन प्रारम्भ करवाया जावे, जिससे वहां के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिल सके।

अतः मेरा निवेदन है कि यह आदेश कराकर मेरे क्षेत्र की जनता को राहत दिलाएँ।

श्री अध्यक्षः श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा में प्रगतिरत गुणवत्ता विहीन सीवरेज कार्य

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में नगरपालिका बिलाड़ा शहर एवं पीपाड़ शहर में वर्तमान में रुडसीको के माध्यम से सीवरेज कार्य प्रगतिरत है। उक्त दोनों नगरपालिकाओं में कार्य की स्वीकृत डीपीआर में क्रमशः 7 एवं 5 स्थानो पर एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट) का निर्धारण किया हुआ है। लेकिन स्थानीय नगर पालिकाओं द्वारा बिना भौतिक सत्यापन किये और बिना ट्रोपोग्राफिक्स सर्वे किए चार-चार स्थानों पर एसटीपी का निर्धारण कर दिया गया है, जिससे एसटीपी शहर के बड़े एवं पेयजल युक्त राजोलाव तालाब एवं लूणी नदी के अन्दर ही निर्माण करने का मानस बना रखा है, जबकि विभाग द्वारा राजालाव तालाब के सौन्दर्यकरण एवं विकास के लिए 3.58 करोड रूपयों की राशि के कार्य की निविदा आमंत्रित कर दी गई। शेष अन्य एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट) को भी सड़क सीमा, आबादी क्षेत्र में भूमि अवाप्त किये बिना, मनमाने ढंग से बनवाये जा रहे हैं तथा उनमें न तो लेवल चैक किया गया एवं न ही गुणवता युक्त कार्य करवाये जा रहे हैं।

इसके अलावा शहर के चारों जोन के कार्य एक साथ प्रारम्भ कर जगह-जगह शहर के अंदर की सड़कें अंडर ग्राउण्ड केबलिंग, जल पाइप लाइनों की टूट-फूट, सीसी रोड तोड़ने से शहर का आमजन परेशान हो रहा है।

अतः आपके माध्यम से नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन है कि संबंधित कंपनी को निर्देशित करावें कि जब तक जिस जोन को खोदकर तोडफोड की उनकी जब तक पुनः नई सडक बनाने, नई पाइप लाइन बिछाने, नई अंडर ग्राउण्ड केबलिंग डालने के पश्चात एक जोन का कार्य सम्पूर्ण नहीं हो, इसके पहले दूसरे जोन में कार्य प्रारम्भ नहीं करें एवं किये गये कार्य की गुणवत्ता की जांच करवाकर, भौतिक सत्यापन कर उचित स्थान पर एसटीपी का निर्धारण किया जावे और तब तक खुदाई कार्य को रोका जावे।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री हमीर सिंह भायल।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंगल फेज कृषि कनेक्शन

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि प्रदेश में भूमिगत जल

स्तर की कमी हुई है। जलदाय विभाग से जो भी जलकूप की स्वीकृति मिलती है उसमे विद्युत विभाग से थ्री फेज कनेक्शन जारी किया जाता है, जबकि किसी भी स्थान पर थ्री फेज मोटर का पानी नहीं है। रेगिस्तानी जिलो में पेयजल को लेकर समस्या है। जल विभाग द्वारा जो भी नलकूप तैयार करवाया जाता है, उसमे बड़े पंप लगाकर पीने का पानी दिया जाता है।, जबकि पानी कम होने से वो मोटर बार-बार जलती है। विभाग में नुक्सान के साथ ही आमजन को भी पानी नहीं मिलता।, हमारे जिले में पानी की कमी को देखते हुए जलदाय विभाग को विद्युत विभाग से सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना चाहिए।

किसानो को भी अपने खेतो में पानी देने के लिए विद्युत विभाग से सिंगल फेज कनेक्शन की ही मांग आ रही है। पानी की कमी, अधिक गहराई में पानी होने से सिंगल फेज की मोटर पानी आराम से निकाल सकती है, साथ ही किसानो को लाभ के साथ विद्युत विभाग को भी लाभ होगा, विद्युत भार भी कम होगा और किसानो को अधिक बिजली आपूर्ति भी होगी। जलदाय विभाग को मात्र 6 घंटे बिजली आपूर्ति ही होती है तो सिंगल फेज कनेक्शन से 20 घंटे से अधिक बिजली मिलने पर पेयजल भी जनता को पूरा उपलब्ध हो सकेगा।

मेरा सदन के माध्यम से विशेष निवेदन है कि जलदाय विभाग और किसानो की मांग के आधार पर रेगिस्तानी जिलों में विद्युत विभाग से सिंगल फेज कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने के आदेश करवाकर राहत प्रदान करावें।

spp/rtm/05.03.2025/12.30/1k

श्री अध्यक्षः श्री धर्मपाल।

खेतड़ी स्थित रीको में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख निवेदन है कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम अशोकनगर में रीको स्थापित है, परन्तु रीको के नाम सिर्फ जमीन आंवटन के अलावा वहां अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि उक्त रीको क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाकर विकसित किया जावे और राइजिंग राजस्थान के तहत औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जायें, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले और क्षेत्र का विकास हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि खेतड़ी में तांबे के भण्डार प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसके खनन कार्य से लेकर शुद्ध तांबा निर्माण हेतु हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रोजेक्ट स्थापित है। जहां किसी समय 10 हजार से ज्यादा कार्मिक नौकरी करते थे तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 25 से 30 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ था, परन्तु आज वहां पर 500 से भी कम संख्या में कार्मिक रह गये हैं, जबकि आज भी तांबे के साथ-साथ अन्य खनिज पदार्थों के भण्डार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट का पुनरुद्धार किया जावे ताकि

क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके।

श्री अध्यक्षः श्री मनोज कुमार सादुलपुर। (अनुपस्थित)

श्री कंवरलाल।

पुलिसकर्मियों की समयबद्ध डी.पी.सी. व साप्ताहिक अवकाश

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत पुलिस डीपीसी व साप्ताहिक अवकाश एवं वेतन पे ग्रेड के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रदेश में सुरक्षा एव कानून व्यवस्था हेतु पुलिस बल निरन्तर कार्य कर रहा है पुलिस विभाग की सबसे निचली व सबसे मजबूत कड़ी पुलिस कांस्टेबल है, जो एक किसान का बेटा है जो दिन रात किसी भी परिस्थिति में सर्दी, गर्मी और बरसात में चौराहे पर खड़ा रह कर अपनी ड्यूटी करता है।

सभी राज्य कर्मचारियों के सगंठन बने हुए हैं जो अपने-अपने विभाग की जायज मांग को लेकर विरोध हड़ताल कर सकते हैं। पुलिस विभाग का कोई सगंठन भी नहीं है, ना पुलिस हड़ताल कर सकती है। पुलिस अपनी मांग को केवल सोशल मीडिया के माध्यम से सामने ला पाती है। जैसा की मैने विगत दिनों में देखा कि पुलिस विभाग ने ट्विटर के माध्यम से कई बार पे ग्रेड तथा डीपीसी प्रमोशन तथा साप्ताहिक अवकाश हेतु ट्रेंड चलाया जो काफी सफल भी रहा है। उनकी जायज मांगों पर सरकार को विचार करना चहिये।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध व विनम्र आग्रह है कि पुलिस विभाग की सबसे मजबूत कड़ी कांस्टेबल को मानसिक रूप से मजबूत व स्वस्थ रखने हेतु पुलिस कांस्टेबल की सोशल मीडिया पर उठायी जा रही मांगें पदोन्नति डी.पी.सी. प्रकिया, वेतन पे-ग्रेड तथा साप्ताहिक अवकाश पर संज्ञान लेकर पूरी की जावें।

श्री अध्यक्षः श्री राजेन्द्र।

महवा में फसलों की खरीद समर्थन मूल्य पर किया जाना

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत महवा में समर्थन मूल्य पर गेहूँ, सरसों और चना की खरीद करवाने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र महवा और आसपास के गावों में प्रमुखता से किसान कृषि कार्य करते हैं। गेहूं और सरसों की फसल का प्रमुखता से उत्पादन करते हैं, लेकिन उनको अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिल पाने के कारण उनको काफी पीड़ा होती है। किसान पहले ही मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कभी सूखे, अकाल से तो कभी ज्यादा बारिश के कारण के चलते तो कभी आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने में चिंतित रहता है। अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो खेती के लिए अच्छी खाद व कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता नहीं होने के कारण बहुत परेशानी में रहता है। वो अन्नदाता खुद भूखे पेट रह कर हम सब के पेट भरता है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी विशेष उल्लेख

प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि हमारे अन्नदाताओं की इस समस्या को देखते हुए महवा में ही समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल को खरीदने हेतु समुचित व्यवस्था करवाने की कृपा करें जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल की उचित कीमत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवाली (उदयपुर ग्रामीण) के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पूर्व सरकार, जिन स्कूलों में जैसे 3-4 कमरों में 12वीं तक स्कूल चल रही है। देवाली ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय को जमीन कक्षा-कक्षों के लिए पांच वर्षों में नहीं दी गई। इस वजह से आदिवासी छात्र-छात्रा की संख्या पहले जो 250 छात्र-छात्रा थी, मगर पढ़ाई प्रभावित होने की वजह से छात्र-छात्राओं का पढ़ाई छोड़-छोड कर जाने का क्रम जारी है। आज दिनांक तक 180 छात्र-छात्रा ही बचे हैं। अगर अगले वर्ष तक स्कूल को जमीन नहीं मिली तो इस विद्यालय में प्राइमरी स्कूल जितने भी विद्यार्थी नहीं रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जमीन आवंटन करवाकर जनजाति बालकों को सुचारु शिक्षा उपलब्ध हो सके और जून-जुलाई में और छात्र स्कूल छोडकर जाने वाले हैं, वो रुकेगे और जो छोड़कर गये वे छात्र-छात्राएं वापिस नाम जुडवायेंगे।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 295 के माध्यम से तुरन्त प्रभाव से जमीन उपलब्ध करवाकर जनजाति छात्र-छात्राओं को अध्ययन करके आगे बढ़ने का मौका जरूर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री पूसाराम गोदारा।

रतनगढ़ में विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि रतनगढ़ मुख्यालय पर मात्र एक ही 132 केवी जीएसएस है। रतनगढ़ शहर सहित इसके आस पास के गांवो में विद्युत भार अधिक होने के कारण वॉल्टेज की समस्या रहती है। रतनगढ़ मुख्यालय पर जमीन भी उपलब्ध है। अतः नया जीएसएस स्वीकृत किया जावें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के 220 केवी जीएसएस रतनगढ़ में 100 एमवीए का ट्रांसफार्मर वर्ष 2019 में जल गया था, जो कि अभी तक बदला नहीं गया है एवं 132 केवी जीएसएस रतनगढ पर 20/25 एमवीए का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, किन्तु दोनों ही पावर ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं करने से दोनों जीएसएस पर भंयकर लोड है, जिसके कारण बार बार ट्रिपिंग आना, और मेंटीनेंस के नाम से छह-छह

घंटे प्रतिदिन बिजली कटौती रतनगढ़ और राजलदेसर क्षेत्र में होती है। बिजली का बहुत भारी संकट है।

रतनगढ़ के सहायक अभिंयता कार्यालय, रतनगढ़ ग्रामीण एवं सहायक अभियंता कार्यालय राजलदेसर के अधीनस्थ बहुत से 33/11 केवी जीएसएस पर 3.15 एमवीए के अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। दोनों ही कार्यालयों के अधीनस्थ 33/11 केवी जीएसएस के अन्तर्गत एरिया सिंचित है, लोड अत्यधिक रहता है। एलडी के अलावा 6 से 8 घन्टे की अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। इसलिए सहायक अभियंता कार्यालय रतनगढ़ ग्रामीण एवं कार्यालय राजलदेसर को 33/11 केवी जीएसएस के लिए 3.15 एमवीए के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर दिए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

अतः मेरा निवेदन है कि रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करके विद्युत सम्बन्धित परेशानियों से राहत देने का श्रम करावें। धन्यवाद।

jyg/rtm/05.03.25/12.40/1l

श्री अध्यक्षः श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

केसरीसिंहपुर पुलिस थाने में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 14/2025 की निष्पक्ष जांच

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 295 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनाक 03.12.2024 को रात के समय संगम अध्यक्ष, जल उपयोक्ता संगम 4 एफएफए, जिला श्रीगंगानगर एवं गंग कैनाल की एफ नहर के टेल क्षेत्र के किसानों ने एफ नहर के 36 एफ मोघे के पास 10 इंची पाइप से नहर से पानी चोरी कर रहे व्यक्तियों की विडियोग्राफी की और विभाग को सूचना दी। विडियोग्राफी करते समय पानी चोरी कर रहे व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट की और ट्रैक्टर से उनको मारने की कोशिश को। पानी चोरी की सूचना पर विभाग ने पानी चोरी के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना केसरीसिंहपुर मे एफआईआर संख्या 282/2024 दर्ज करवायी और संगम अध्यक्ष, जल उपयोक्ता संगम, बंडिगा (श्रीगंगानगर) को दोषी व्यक्तियों की पानी की बारी काटने और 20 गुणा तवान कायम करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु संगम अध्यक्ष, जल उपयोक्ता संगम, बंडिगा द्वारा विभाग के आदेशों की पालना नही की एवं प्रकरण में दोषियों के बचाव हेतु हर सम्भव प्रयास किया। पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा भी उक्त प्रकरण की विडियोग्राफी को नजरअंदाज कर उक्त प्रकरण मे पानी चोरी की घटना की सूचना प्रशासन को देने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर संख्या 14/2025 दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि पानी चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये और उक्त प्रकरण में पानी चोरी की सूचना देने वाले

किसानों के खिलाफ पुलिस थाना केसरीसिंहपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 14/2025 की निष्पक्ष जांच कर उसे वापस लिया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम बैरवा।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद प्रक्रिया का सरलीकरण

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 295 पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया सम्बन्धित नियम 295 के तहत आगामी रबी के मौसम में किसानों के गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु विशेष उल्लेख।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत प्रदेश में आगामी मार्च माह से गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारम्भ हो जायेगी। समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने के बाद से ही हम देख रहे हैं कि कभी किसी, तो कभी किसी कारण किसान की पूरी उपज की तुलाई नहीं हो पाती और किसान हित में बनायी गयी अति लाभकारी व उपयोगी योजना प्रदेश में महज खानापूर्ति बनकर रह जाती है। योजना का वास्तविक लाभ किसानों को दिलवाने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण एवं निम्न सुधार करवाने की महती आवश्यकता है:-

1. ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन में टोकन की तारीख की बाध्यता समाप्त की जाये और किसान को कहीं भी, कभी भी अपनी उपज बेचने की सहुलियत मिले।

2. किसान जितना भी गेहूं विक्रय के लिए मण्डी में लाये, उसकी सम्पूर्ण उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाये।

3. मुनाफा काश्त करने वाले काश्तकार को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाये, क्योंकि जिसके पास जमीन नहीं है वह भी किसान है और खेती कर रहा है, इसलिए उसे भी योजना का लाभ मिलना चाहिए।

4. शामिलाती खाता होने पर किसान जिसके नाम चाहे भुगतान करवाये, किसानों से सहमति पत्र लेकर ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

5. कई बार देखने में आता है कि दलाल सक्रिय होकर किसानों के गेहूं की गुणवत्ता को कम दिखाकर तुलाई नहीं होने देते और बाद में पैसे लेकर उसकी गेहूं को तुलवा देते हैं। इस पर प्रभावी रोक होनी चाहिए, गुणवत्ता के नाम पर किसान का शोषण नहीं हो और उसका गेहूं समर्थन मूल्य पर तौला जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में उक्त सुधारों को लागू करवाकर किसानों को राहत प्रदान की जाये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कालूराम।

डग में जल जीवन मिशन से वंचित क्षेत्र

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी

नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर घर नल योजना से पानी पहुंचाया जाये। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी JJM जल जीवन मिशन योजना है जो राज्य के प्रत्येक गांव और ढाणियों में शुद्ध जल की आपूर्ति करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार शुद्ध जल की आपूर्ति हेतु पानी की टंकी लगवायेगी जिससे जल संकट से उस क्षेत्र में पानी की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा किंतु योजना का क्रियान्वयन समितियां द्वारा प्रभावी रूप से संचालन न किए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां जहां पाइप लाइन बिछायी गयी वहां की सड़कों की मरम्मत भी नहीं की गयी है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं आमजन परेशान है तथा अधिकांश टंकियां का निर्माण कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे पानी की किल्लत जस की तस बनी हुई है। जहां-जहां पाइप लाइन बिछायी गयी है वह निर्धारित मापदंड भी पूरा नहीं करती है, उसकी गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच करवायी जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना से वंचित लोगों को लाभ दिलाने हेतु अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करवाया जायें। इस योजना का संचालन समितियों के स्थान पर जन स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को दिया जाये, अनुभवी अभियंताओं से इसका लाभ मिल सकता है और कार्य समय पर पूरा किया जा सकता है। विधान सभा क्षेत्र डग जिला झालावाड़ में जल जीवन मिशन योजना के तहत काफी गांव आज भी वंचित हैं1 भीषण गर्मी शुरू होने से पहले कार्य जल्द से जल्द पूरे किये जायें ताकि जल जीवन मिशन योजना के तहत जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उनका अनुमोदन होकर कार्यदेश जारी किये जा सके और योजना को धरातल पर लाने में समय की बचत होगी और जनता की पीने के पानी जैसी विकट समस्या का समाधान हो पायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री सुरेश गुर्जर।

माननीय सदस्य आपने यह जो 295 सब्मिट किया है, इसमें 12 जगह तो कटौती है और आपके इनिशियल हैं। यह 295 सब्मिट करने का प्रोविजन नहीं है। आप फ्रेश लिखकर पूरा देंगे, कोई भी इसको देख लो, क्या यह 295 सब्मिट करने का कोई तरीका है क्या? जो लिखना चाहे, आपको स्वतंत्रता है, 250 शब्दों में, लेकिन मैंने गिन लिये, 12 या 13 करेक्शन होकर आपके इनिशियल हैं, यह कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं है कि अपने इनिशियल कर दें। यह सदन की प्रोपर्टी है, भविष्य में इसको ध्यान रखें। पढ़िये।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक कम्प्यूटर ऑपरेटर और लगा दो, हमारे कम पड़ रहे हैं। हमने लिखकर भी दिया था। लिखाने वाले ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्षः घर पर भी हैं सबके। और यह तो चार दिन पहले सब्मिट करते हैं।

खानपुर में सड़कों तथा पुलियाओं का निर्माण

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र खानपुर की जनता से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

विधानसभा खानपुर में सड़को की हालत बहुत ही खराब है, क्षेत्र की नोन पेचेबल सडकों में दहिखेडा से बांगडसी, लिंक रोड वाता खेडी खोलूखी मोहनपुर सीमाहा मुलखेडी, गोताना से वाया साखाडी बडकी लिम्मी, बाधेर की घाटी से बांसघट्टी-कुआभाऊ-दयाभाउ, मंडावर रोड से गोरधनपुरा- पृथ्वी पुरा, आकोदिया से हरिपुरा, अक्तासा से पनवासा, रटलाई से बरखेडी, खेरिया से पिपलिया नग्गा-सूरजपुरा-राजपुरा, थोबडिया से मंडीखोह, मेगा हाईवे खानपुर से डोबडा-भगवानपुरा- रामपुरा- सिंगोला, सीधनी से फदानिया, तारज से अंबाला, सारोला-से-ईस्ली महुआखेडा, खानपुर अदरू रोड से नया गांव ठाकरान, हरिगढ पनवाड रोड से ब्राहम खेडी, सिंबलखेडी से सोजपुर-भरतपुर की सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाना अत्यावश्यक है।

इसी तरह मिसिंग लिंक में लिम्मी से खडीखेडी, खडीखेडी से काकरदा, खडीखेडी से सुनारिया, भरतपुर से ईस्लामपुरा, बाधेर से उम्मेदपुरा, करनवास से अंबाला, पद्मया से डोबडा, खमाबदा से ओदपुर, हालीहेडा से जरगा, पिपलिया तालाब से रटलाई रोड लक्ष्मीपुरा से सूरी, बस्सा बन, नानोर से माचलपुर, देवरी रोड से मेलकी, ईरली चंदालिया-भूसरी शिव नगर दाणी, मोल्क्या खुर्द से मोलक्या तथा देवनगर रोड से शिवपुरा, खटकड से कोटडा कुंज, मोडी से लोडाखेडा, कुशलपुरा से गणेशपुरा वाया बाडिया मझरा, की संपर्क सड़कें बनाया जाना बहुत ही जरूरी है।

संपर्क सडक खेरिया से पिपल्या नग्गा के बीच में, भीमसागर नदी पर पर बराना की पुलिया, गुण्डला से मरायता के बीच, मोहनपुर से कोलूखेडी के बीच दरबड पुलिया तथा उजाड नदी पर भीमखेडा से कंवरपुरा के बीच, गणेशपुरा से मंडीखोह के बीच उजाड़ नदी पर तथा गरवाडा की पुलियाएं बरसात में डूब जाती है, जिससे इन गांवो का संपर्क टूट जाता है, आवागमन बंद होने से आपातकालीन स्थिति में कोई मदद नहीं पहुंच पाती है, यहां पर उच्चस्तरीय पुलियाओं के निर्माण की आवश्यकता है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उक्त पुलियाओ और सडको का निर्माण अविलंब कराया जाये। धन्यवाद।

MLS/RTM/05.03.2025/12:50/1m

श्री अध्यक्षः पर्ची। श्री हरलाल सहारण।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चूरू में बिजली की समस्या

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली

के उपभोग और महत्त्व को हम सभी जानते हैं। हमारे घरों में रोशनी करने, तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए इस आधुनिक दुनिया में बिजली विशेष स्थान रखती है। इसके बिना आज जीवन की कल्पना करना सम्भव नहीं है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं- रोटी, कपड़ा और मकान, ये भी आज के अधुनिक युग में बिजली के इर्द-गिर्द घूमती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था में बिजली के महत्त्व को कम नहीं आंका जा सकता है। एक विकासशील देश को विकसित बनाने के लिए बिजली अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका रखती है। आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में बिजली अधिक सुरक्षित जीवन जीने में अपना योगदान देती है। यह व्यवसायों का उत्पादन बढ़ाने, वस्तुओं की लागत कम करने तथा समय की बचत करने में सक्षम बनाती है।

हमारा प्रदेश कृषि पर निर्भर है तथा किसान और किसानी बिजली पर निर्भर हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेशवासियों को सुचारू रूप से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बजट के पैरा संख्या 10 में 20 हजार 700 मेगावाट बिजली सप्लाई करने की घोषणा की है। यह किसान हितैषी सरकार होने का एक प्रमाण है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन से बहुत सी ढाणियां वंचित हैं। 2019 से 2023 में पिछली कांग्रेस सरकार ने एक ढाणी में कनेक्शन नहीं किया और गरीब और किसान की बात करने वाले कांग्रेसी मित्रों से मैं कहना चाहूंगा कि आप गरीब और किसान की बातें करते हैं, पांच साल में आपने एक ढाणी में कनेक्शन नहीं किया। हमारी भजन लाल सरकार ने आते ही यहां विधान सभा में 2019 से चिह्नित ढाणियों को कनेक्शन दिये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही, हमारे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 8 हजार ढाणियों का सर्वे कराकर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास भी है...। सर, एक सैकंड।

श्री अध्यक्षः एक सैकंड हो गया।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत तंत्र मजबूत करने के लिए नाकरासर और ढाढरिया में 33/11 केवी जीएसएस बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री संदीप शर्मा।

मन्दिर माफी की जमीनों एवं पुजारियों को राजकीय संरक्षण

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। मन्दिर माफी की जमीनों पर 1963 में राजपत्र की घोषणा के अनुसार पुजारियों को उनकी खातेदारी दे दी गयी थी। इनका लगान भी वसूल कर लिया गया। 1991 में राजस्व विभाग के सर्कुलर के अनुसार समस्त पुजारियों की जमीनों को खातेदारी से हटा दिया गया। 2010, 2007 और 2018 के राजस्व परिपत्रों में सरकार ने इसे भूल माना। यह खातेदारी गलत तरीके से हटायी

गयी। यह आज भी रीस्टोर नहीं हुई है। इसकी वजह से पुजारियों को कृषि जमीनों में उनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।

जागीर अधिनियम की धारा 9 तथा टीनेंसी एक्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत भी वंशानुगत तरीके से पुजारियों को मन्दिर की जमीनों का खातेदार माना गया, जो 13.12.1991 के राजस्व विभाग के परिपत्र का उल्लंघन कर रहा है, जबकि जो खातेदारी पुजारी के नाम नहीं खुल पा रही, वहां भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर ये खाते खुलवा लिये जाते हैं। इन मन्दिर माफी जमीनों पर कई भू-माफियाओं के ऊपर हत्या, धमकाने और मार-पीट के मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें दौसा के महवा के शम्भू पुजारी की हत्या हुई।

मन्दिर हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। माननीय अध्यक्ष जी, टीनेंसी एक्ट को यदि माना जाये तो इन मन्दिर माफी की जमीनों को पिटीशन नहीं खुलना चाहिये। यह जमीन भू-माफियाओं के खाते तो बन्ध जाती है, परन्तु वह पुजारी, उसके खाते ही नहीं खुल पाती। वहां कॉलोनियां कट जाती हैं। यही पुजारियों का, इनके वंशानुगत रूप से खाते, जो चली आ रही है, उसके खाते नहीं खुल पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसमें कलक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिये और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसमें पूरे तरीके से जिम्मेदार मानना चाहिये कि वह इन भूमियों का प्रोटेक्शन कर सके।

मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, जिन्होंने जो काम 70 सालों में नहीं हो पाया था, उस मन्दिर संस्कृति, जो हमारी पोषक तत्व है, उस संस्कृति की धरोहर की रक्षा के लिए 2 साल के अन्दर राजस्थान प्रदेश के मन्दिरों को बजट में बहुत स्थान दिया है। साथ ही साथ, 3 हजार रुपये मन्दिर में भोग के लिए और 7500 रुपये पुजारियों का मानदेय किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मेरा आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि मन्दिर माफी की जमीन पर जो कब्जे हों, पुजारियों पर हमलों पर तुरन्त सख्त कार्यवाही की जाये। मन्दिर माफी की जमीनों पर पुजारियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। साथ ही, मन्दिर की सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ ही जो जमीन मन्दिर में सेवा हेतु इनके खाते बन्ध गयी थी, इनका वंशानुगत अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी गठित हो जाये तथा पुजारियों का हक संरक्षित हो, जिससे वे भी सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें। धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, इसमें मेरा भी आग्रह है। चूंकि भू-माफियाओं ने मन्दिर माफी की जमीनों पर जिस प्रकार से कब्जा किया है और एक पूरा रैकेट चला रखा है, मैं चाहूंगा कि आप इसमें जरूरत पड़े तो सदन में और भी चर्चा कराएं और इस पर आप डायरेक्शन जारी करें।

श्री अध्यक्ष: मेरा भी इसमें सरकार से आग्रह है, अजमेर में भी भू-माफियाओं ने कब्जा

करके कॉलोनी काटकर मकान बना लिये हैं। ऐसी स्थिति, जो सुप्रीम कोर्ट का है, मन्दिर माफी जमीन बेची नहीं जा सकती। सरकार कठोरतम कार्यवाही ऐसे लोगों के खिलाफ करे। जहां भी है, सब जगह आप लोग करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका फरमाना सही है और यह विषय किसी एक गांव या एक तहसील या एक जिले का नहीं, पूरे राजस्थान का विषय है। रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स एक्ट 1952 में आया था। उसकी धारा 8 के अनुसार तत्कालीन समय में जो खातेदार दर्ज थे, उनको खातेदारी अधिकार मिल गये, लेकिन सैक्शन 9 के अनुसार या अन्य प्रावधानों के अनुसार जिन्होंने अपना डिक्लेयरेशन दे दिया खुद काश्त के लिए, अपनी खुद की काश्त के लिए, वो खुद काश्त हो गयी।

श्री अध्यक्ष: आगे से नहीं, माननीय, पीछे से जाओ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा आपसे अनुरोध यह है कि अन्तिम रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को डैटी को परपेचुअल माइनर मान लिया है, इसीलिए डैटी की जमीन न तो किसी को ट्रांसफर हो सकती है और न किसी के नाम चढ़ सकती है। वह डैटी के नाम ही रहेगी। It is a perpetual minor. जो विषय कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, जो विषय नेता प्रतिपक्ष ने रखा और जो आपने व्यवस्था दी, उस सम्बन्ध में सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। डैटी की जमीन पर, मन्दिर माफी की जमीन पर कब्जा नहीं हो और इस सम्बन्ध में पुजारियों का जो विषय है, उसको भी सरकार गम्भीरता से देख रही है। इस पर कोई न कोई सख्त कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: यह विषय राजस्व विभाग का है तो राजस्व मंत्री भी इस पर गम्भीरता से ध्यान दें।

श्री सुभाष गर्ग।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहनेरा के टैंडर एवं कार्यादेश होने के उपरान्त भी भवन निर्माण प्रक्रिया के प्रारम्भ में विलम्ब

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहनेरा के टैंडर एवं कार्यादेश जारी होने के बावजूद भी मैं बताना चाहूंगा कि 06.10.2023 को कार्यादेश जारी हो गये। 05.07.2024 को इस कार्य को कम्प्लीट होना था और इसके लिए करीब 4 करोड़ 91 लाख की टैक्निकल सैंक्शन निकली थी। इसके बाद टैंडर राशि जो निकलकर आयी, वह 3 करोड़ 95 लाख समथिंग आयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, लगभग डेढ़ साल से अधिक हो गया है। अभी तक इसमें निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कई बार आपसे मिल चुका हूं। जिला प्रशासन से भी मैं काफी बार फोन पर बात कर चुका हूं। एनएचएम और उनमें काफी दिक्कत है। पीडब्ल्यूडी ने इस भवन को डिस्मैंटल करके नया भवन कराने की इजाजत दी थी। नये भवन के अनुसार टैंडर प्रक्रिया हुई थी,

लेकिन जिला प्रशासन पता नहीं किस कारण से कोई डिसिजन नहीं ले पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, जैसे भी बनवाना है, उसको डिस्मैंटल कराना है, नहीं कराना है, उसी भवन का उपयोग करते हुए उसका एक्स्टेंशन किया जाना है, उस पर आज निर्णय कराएं, जिला कलक्टर को निर्देश दें। ऐसी हठधर्मिता मचा रखी है कि डेढ़ साल से लगातार मैं लग रहा हूं और कम से कम सैकड़ों बार कॉल किये हैं। पांच-सात बार मैं आपसे भी अनुरोध कर चुका हूं। आप जिला कलक्टर से बात कर लें। इसके बावजूद भी कोई जूं नहीं रेंग रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार एक तरफ बड़ी ट्रांसपैरेंसी के साथ शीघ्र काम करना चाह रही है, लेकिन जिन अधिकारियों की वजह से ये काम नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री आदू राम मेघवाल।

चौहटन सहित सम्पूर्ण बाड़मेर में जंगली सूअरों (भंडूरों)
द्वारा किसानों की फसलों व सब्जियों को नुकसान

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में पर्ची के माध्यम से बोलने का सुअवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि एवं पंचायती राज मंत्री जी का ध्यान चौहटन विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण बाड़मेर जिले में जंगली सूअरों द्वारा किसानों की फसलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचाने तथा उनके आतंक से उत्पन्न विकट स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

MKD/RTM/05.03.2025/13:00/1n

राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण यहां की अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर आधारित है। चौहटन विधान सभा क्षेत्र सहित बाड़मेर जिले में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनकी आजीविका का मूल स्रोत कृषि है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में सम्पूर्ण बाड़मेर जिले में किसानों व आमजन को जंगली सूअरों के भयंकर आतंक से जूझना पड़ रहा है। जंगली सूअर झुंड में आकर किसानों की खड़ी फसलों एवं सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेष परिस्थिति के कारण किसान फसलों, सब्जियों की रखवाली करने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं।

मौजूदा हालात यह हैं कि किसानों के द्वारा बनाई गई कवच के रूप में चारदीवारी, तारबन्दी, मेड़ के नीचे से होकर जंगली सूअर हरे-भरे खेतों के अन्दर प्रवेश कर जाते हैं और फसल और सब्जियां नष्ट कर देते हैं। इन जंगली सूअरों को अप्रत्यक्ष संख्या ने किसानों के होश उड़ा रखे हैं।

अत: लोकहित के अति महत्वपूर्ण विषय पर मेरा निवेदन रहेगा कि चौहटन विधान सभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण बाड़मेर जिले में जंगली सूअरों की भयंकर आतंकी समस्या से किसानों

और आमजन को राहत दिलाने के लिए विभाग द्वारा कोई ठोस तथा प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: दोनों पक्ष तैयार हों तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पक्ष तय कर लें, स्थगित करें। पहले खाना खाओगे, तभी तो पानी पिओगे।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): सुरक्षा एवं सावधानी के साथ पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, ताकि किसानों को जंगली सूअरों के आतंक की गम्भीर समस्या से राहत मिल सके। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आज पानी की मांग पर चर्चा पर है, बहुत अधिक लोग बोलना चाह रहे हैं। वह तो ध्यान में है। तो आज का भी भोजन अवकाश निरस्त किया जाता है। हालांकि, मेरा था कि भोजन के बाद ही पानी पिया जाता है, लेकिन यहां भोजन से पहले पानी पीना चाह रहे हैं तो पी लीजिये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री श्रीचन्द्र कृपलानी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रदेश के गांवों की सीमा से लगी चरागाह भूमि का
आवश्यकतानुसार आबादी भूमि में परिवर्तन

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत प्रदेश के गांवों की सीमा से लगी चरागाह भूमि को आवश्यकतानुसार आबादी भूमि में परिवर्तित कराने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप तो ध्यान आकर्षित करके विराज जाओ। उसके बाद आपको बोलने की अनुमति होगी।

श्री श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जोगाराम जी ने कहा है।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों की दोस्ती अधिक है।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): प्रदेश में गांवों की चरागाह भूमि को आवश्यकतानुसार आबादी भूमि में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

1. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2(379)राज-3/81 दिनांक 01.06.1983 से आबादी विस्तार के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार 5 सदस्यों का प्रति परिवार मानते हुए तथा उसकी साधारण आवश्यकता-बाड़, जानवरों के लिये छप्पर, खल्याण, खुला स्थान आदि को सम्मिलित करते हुए, करीबन 700 वर्गगज या 1/7 एकड़ भूमि को आधार मानकर आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षण किये जाने का प्रावधान है। प्रति 200 परिवार या 1000 की जनसंख्या को आधार मानकर 10 एकड़ भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण जिसमें स्कूल, पंचायत घर, पटवार घर व खुला स्थान आदि भी शामिल है, किया गया है। इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक प्रति हजार की जनसंख्या पर 5 एकड़ भूमि का इस प्रयोजनार्थ आरक्षण किये जाने का प्रावधान है।

2. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 व 102क के तहत आबादी

विस्तार हेतु भूमि आरक्षित/आवंटन किये जाने का प्रावधान है। ऐसी भूमियों पर बसी आबादी को नियमित करने के संबंध में राजस्व विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र दिनांक 07.09.2017, 03.10.2017 एवं 30.11.2017 जारी किये गये हैं।

3. जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 के द्वारा कॉमन लैंड भूमियों पर अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के निर्देश हैं। केवल असाधारण/विशिष्ट परिस्थितियों में ही नियमन किया जाना अनुमत है। इसी प्रकार गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 द्वारा चरागाह भूमियों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश हैं। आबादी हेतु आरक्षित भूमियों पर बसी बस्तियों को प्रकरण विशेष के गुण व अवगुण के आधार पर नियमों के अनुसार नियमित किया जा सकता है। इस हेतु राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश जारी करती है व अभियान भी संचालित करती है।

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण हेतु विभाग द्वारा पॉलिसी 27.12.2021 जारी की गई है। उक्त पॉलिसी के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के अध्यधीन 35 वर्षों से निवासरत भूमिहीन परिवारों को अधिकतम 100 वर्ग मीटर तक के पट्टे प्रदान किये जाने के निर्देश हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। अभी आपने कहा कि जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य प्रकरणों एवं गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान के प्रकरणों की वजह से हमने यह फैसला किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि 2003 और 2004 में हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में तत्कालीन कलेक्टर रणजीत सिंह जी कठाला, जिन्होंने एक ही फैसले से चित्तौड़ जिले की हजारों बीघा बिलानाम भूमि...। जूली जी, थोड़ा सुन लो। आप भी नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा।

अध्यक्ष महोदय, 2003 और 2004 में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिला, जो रेवेन्यू मंत्री जी का भी जिला भी है। वह पहले चित्तौड़ जिले में ही था, एक आदेश से हजारों बीघा जमीन को बिलानाम से चारागाह में उन्होंने कंवर्ट कर दिया, एक आदेश से।

अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा पॉइंट यह है कि एक तो उसको वापस बिलानाम किया जाए। दूसरा, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे आवासीय, चाहे गैर आवासीय हो, जो कब्जे आदिवासी क्षेत्रों पर हैं। अभी आपने कहा कि 35 साल से जो कब्जे हैं एवं उससे पहले के कब्जे हैं, उनको पट्टे दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता, राजस्थान के कितने लोग यहां बैठे हैं, पूरे राजस्थान में कहीं पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि लाखों लोग जो पिछले 100 साल से, कोई 80

साल से, 90 साल से मकान बनाकर वहां पर बैठा है, न तो उसको कोई लाभ मिल रहा है, न प्रधान मंत्री आवास में कोई पैसा उसको मिलता है, न कोई लोन मिलता है, न बिजली का कनेक्शन होता है, न कोई उसको दूसरी सुविधा मिलती है, इस वजह से और फिर अतिक्रमण के नाम पर जब चाहे आदेश निकल जाते हैं, उनके अतिक्रमण तोड़ने चले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि उन सबको नियमित करने के लिए सरकार को कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। इसके अलावा, चरणोट में कई खेतों एवं कई गांवों के रास्ते निकल रहे हैं, उनको भी नियमित करना चाहिए। उन रास्तों को भी बन्द कर देते हैं, जिससे गांवों वालों को बहुत बार दिक्कतें आती हैं। जहां गांव बसे हैं, गांवों के बीच में चरागाह भूमि है, तो उसके बदले में दूसरी भूमि देकर उसको हटाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ मेरा मैटर नहीं है, पूरे राजस्थान के लाखों उन गरीबों का है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जो वर्षों से, जो हजार रुपये, दो हजार रुपये, पांच हजार रुपये, दस हजार रुपये भी महीने के नहीं कमाते हैं और उन्होंने छोटे-छोटे मकान बना रखे हैं और अतिक्रमण के नाम पर उन मकानों को हटाया जाता है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन है, अगर आपको कोर्ट का कोई लग रहा है कि कोई राइडर है, कोई दिक्कत आ रही है तो राज्य सरकार चाहे विधान सभा हो, चाहे लोक सभा हो, उसमें कानून बना सकती है। हमको कोई न कोई नियम तय करना चाहिए। आज से इतने साल पहले से जिनका कब्जा है, उनको नियमित करके, कम से कम उस गरीब आदमी को सुविधा तो दो।

उसके साथ आप फोरेस्ट की भी, आज राजस्थान में फोरेस्ट में हजारों गांव ऐसे हैं जो आपके क्षेत्र में, हमारे पूरे मेवाड़ में, जहां पर न तो उसको बिजली की सुविधा है, न मकान बनाने की सुविधा है, न पानी की व्यवस्था है, तो वे बिलकुल ऐसी जिन्दगी गुजार रहे हैं और उनका भला अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

Bhs/Rtm/05.03.25/13.10/1o

मैं आप के माध्यम से, अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय को यह कहूंगा कि इस बात का आप जवाब दें कि हम कितने समय में इसका फैसला करेंगे? विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले की जिन जमीनों को हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय ने एक साथ चरणोट का आदेश करके ...(व्यवधान)... खड़े होकर बोलो न पूरे प्रदेश का मामला है।

श्री अध्यक्ष: सदस्य को बोलने दो। आप गाइड मत करो। समझदार हैं, बहुत पुराने हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): तो मैं, मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि इसका कोई कानून बनायें ताकि लाखों लोगों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। इसमें दूसरे का नहीं। आप भी कर लेना ध्यानाकर्षण, आपका हो तो करवा दूंगा।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो

मामला उठाया है इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आने वाले समय में जो भी सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन के अनुसार जो भी काम होगा वो हम सरकार के माध्यम से करेंगे क्योंकि चरनोट एक बहुत महत्वपूर्ण और आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक भूमि की श्रेणी में आ रही है इसलिए और सुप्रीम कोर्ट के जो डाइरेक्शन हैं उसके अनुसार ही भविष्य में सरकार कार्य करेगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है कि एक कलेक्टर एक आदेश से हजारों बीघा जमीन बिलानाम को चरनोट कर देता है तो उसका हमारे पास कोई आधार ही नहीं है। लाखों लोग उसको भुगत रहे हैं और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर, मंत्री जी, थोड़ा संवेदनशील होकर इसके बारे में विचार करो। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम को मानना चाहिए, लेकिन अब कोई सीमेंट फैक्टरी लगती है तो अब वहीं लीज के नाम पर चरनोट देते हो कि नहीं देते हो आप जमीन हैं? दूसरी इंडस्ट्रीज लगती हैं, उसको देते हो, इन गरीबों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो इन गरीबों को आप भला करना है।

श्री अध्यक्ष: ध्यान में आ गया सरकार के। सरकार गंभीरता से इस पर विचार करे। श्री मनीष यादव।

शाहपुरा (जयपुर) के बाहर से बाईपास की स्वीकृति

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा कस्बा शाहपुरा (जयपुर) के बाहर से बाईपास स्वीकृत कराये जाने के संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-48) और शाहपुरा-अजीतगढ़ नीम का थाना राज्य राजमार्ग (एसएच-13) शाहपुरा कस्बे को दो भागों में विभाजित करते हैं, जिससे कस्बे में ट्रैफिक जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। बाईपास सड़क निर्माण के लिए 20.00 किमी लम्बाई लागत 152.00 करोड़ (भूमि आवाप्ति सहित) की आवश्यकता होगी। वर्तमान में शाहपुरा कस्बे के बाईपास निर्माण की स्वीकृति नहीं है। इस बाईपास सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी करना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय, जयपुर दिल्ली जो हाईवे है एन.एच. 48 और जो हमारा शाहपुरा-अजीतगढ़ नीमकाथाना राजमार्ग 13 है, उसकी वजह से जो भी हमारे शाहपुरा में औद्योगिक क्षेत्र है हमारे अजीतगढ़ में जो पास में नजदीक औद्योगिक क्षेत्र है, हमारे अजमेर में औद्योगिक क्षेत्र है वो आवागमन का रास्ता मुख्य

रास्ता शाहपुरा कस्बा ही है, उस वजह से जो भारी मालवाहक वाहन हैं वो वहां से आते-जाते रहते हैं।

माननीय, दूसरा एक बहुत बड़ा जो हमारे दिल्ली, हरियाणा में दौसा हाईवे से आने वाले जो लोग जो रींगस स्थित प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर और हमारे प्रसिद्ध त्रिवेणी धाम मंदिर को आते हैं वो भी उसी रास्ते से आते हैं, यह रास्ता सीकर व नीमकाथाना को पूरा जोड़ने वाला रास्ता है। साथ में, मोटे तौर पर इस रास्ते पर जो जयपुर दिल्ली राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर जो हमारा उप जिला अस्पताल है शाहपुरा वो सबसे बड़ा अस्पताल भी कस्बे में स्थित है, जिसकी लगभग ओ.पी.डी. औसतन प्रतिदिन 600 पेशेन्ट रहती है। अस्पताल में गायनिक सेंटर में औसतन 250 महिलाओं की ओ.पी.डी. रहती है और 5000 लोगों का आवागमन अस्पताल में प्रतिदिन रहता है और एन.एच. पर जो भी दुर्घटनाएं रहती हैं वो भी सारे लोग उसी उप जिला अस्पताल में आते हैं, जिनको जाम की स्थिति की वजह से, माननीय, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको अस्पताल पहुंचने में देरी होती है। कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं और जो जीवनयापन वहां पर लोग-बाग कर रहे हैं जो चारपहिया वाहन हैं, दोपहिया वाहन हैं, उनके भारी आवागमन की वजह से उनका जीवन बाधित हो रहा है। शोरगुल की वजह से है, जो प्रदूषण है उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कस्बे में बहुत अशांत वातावरण रहता है, जो हमारे दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, थड़ी वाले हैं, उनका पूर्णतः व्यापार ठप है और हमारे इस मार्ग पर सिविल न्यायालय, उप खण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना, पंचायत समिति कार्यालय और अन्य ब्लॉक लेवल के कार्यालय भी इस पर स्थित है और इस वजह से जाम की भारी स्थिति रहती है। माननीय, ऐसी परिस्थिति में कस्बे के बाहर से बाईपास का निर्माण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि बाईपास की डी.पी.आर. कब तक बनाकर बाईपास की राशि स्वीकृत कर दी जावेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि यह सही है कि शाहपुरा कस्बे में यातायात जाम की स्थिति रहती है। अतः मैं शाहपुरा कस्बे में बाईपास बनाने की फिजिबिलिटी की जांच करवा लेती हूं यद्यपि बाईपास बनाना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। अगर ऐसा लगता है, मैं भी अभी इस रोड पर वैसे गयी थी कुछ ही दिनों पहले और वहां जम की स्थिति रहती है अध्यक्ष महोदय, तो बिलकुल उसकी फिजिबिलिटी दिखवा लेंगे और फिर जो भी होगा बिल्कुल मुझे लगता है की जो माननीय सदस्य बात बता रहे हैं जो ये समस्या है, ये जेन्यूइन समस्या है और इस पर फिजिबिलिटी के बाद और सभी मापदंड वगैरह सब देखने के बाद बिल्कुल डी.पी.आर. बनाकर इसका काम शुरू करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): धन्यवाद, उप मुख्यमंत्री महोदया। मैं एक बात और इसमें

हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो जयपुर तिराहे की पुलिया और दिल्ली तिराहे की पुलिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत वर्षों से पिछले 10-15 वर्षों से अधूरी पड़ी है, उसका कार्य कभी रुक जाता है, कभी चल जाता है, उस पर भी आग्रह आपसे करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): और घासीपुरा कट जो हमारे भांकरोटा में घटना हुई, उसकी वजह से हमारे कई कट हाईवे पर बन्द कर दिये, वहां पर पुलिया बने ऐसा भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप केन्द्र को लिखें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया। विराजिये। ध्यान आकर्षित हो गया।

मेरा दोनों सचेतकों से और माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जो बोलने वालों की जितनी डिमांड है, बोलने वालों की सूची है, वह 11:00 बजे से पहले अपने सचेतकों को लिखा दें और मेरे पास 12:00 बजे से पहले आ जाये। जब बहस शुरू हो जाती है, उसके बाद तक आती रहती है तो सदन को यह व्यवस्था मेरे को भी देने में कठिनाई होती है अत: पहला नाम श्री नरेंद्र बुडानियां।

सॉरी। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री संदीप शर्मा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

याचिका

कर्मचारी बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को आर.जी.एच.एस. की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रदेश के कर्मचारी बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को राज्य के अन्य कर्मचारी और पैंशनर्स के अनुरूप ही आर.जी.एच.एस. की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री लादू लाल पितलिया।

रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपखण्ड मुख्यालय रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान मांगों पर विचार। श्री कन्हैयालाल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की प्रस्तुति

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के संबंध में 31 मार्च,

2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 118,66,49,47,000/- (एक सौ अठारह अरब छियासठ करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्ष: जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री, श्री सुरेश सिंह रावत।

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रस्तुति

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,82,72,73,000/- (तिहत्तर अरब बयासी करोड़ बहत्तर लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री नरेंद्र बुडानिया।

मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर विचार

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने एक महत्वपूर्ण विभाग पर इसमें डिमांड में चर्चा में लिया है, बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज यदि राजस्थान के अंदर सबसे ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वह पानी का है।

Kas/rtm/05.03.2025/13.20/1p

चाहे वह सिंचाई का पानी हो, चाहे वह पीने का पानी हो। आज मैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर के नीचे जितना भी सिंचित ऐरिया आता है, वहां पानी की कमी के कारण सारी की सारी पकी हुई फसल बरबाद हो गई। वहां का किसान बरबाद हो गया। फरवरी में पानी बंद कर दिया गया। आप मुझे यह बताइए कि एक तरफ हम किसान-किसान की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, एक तरफ किसान का निवाला छीनने का काम करते हैं, तो क्या हम किसान के शुभचिंतक हैं? आज आप जाकर बीकानेर डिविजन के हालात देखिए, आप हालात देखिए वेस्टर्न राजस्थान के, आज किसान आंदोलित हैं, किसान सड़कों पर हैं, उसकी आखों के आगे उसका निवाला छीना जा रहा है, उसकी फसल बरबाद हो रही है और सरकार कह रही है कि पानी नहीं है। किसानों के प्रति इतना तो असंवेदनशील मत रहो। हमारे मुख्य मंत्री जी जब बोल रहे थे, तो उन्होंने 20 बार कहा कि मैं किसान का बेटा हूं। हमें गर्व हुआ इस बात का कि वो किसान के बेटे हैं,

लेकिन आज किसान की आंखों में आंसू है। आप विधान सभा की कमेटी बनाकर भेज दीजिए कि किस तरह किसान की फसल बरबाद हो रही है। ऐसी बात नहीं है, पहले भी दिक्कतें आई हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के राज में, मैं पिछले 5 साल विधान सभा में था, कई बार दिक्कतें आई हैं, लेकिन सरकार ने संवदेनशील कदम उठाकर अपने स्तर पर पंजाब सरकार के साथ मुख्य मंत्री स्तर की वार्ता करके पानी लेकर आये हैं और किसान की फसल बचाई है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं सितम्बर, 2021 को पोंग बांध का लेवल 1300.15 फीट था और हमारा पानी 9,39,584 क्यूसेक्स दिवस था और सितम्बर, 2024 में पोंग बांध का लेवल 2021 से ज्यादा था, 1318.51 फीट और पानी भी ज्यादा था 9,65,830 क्यूसेक्स दिवस। पानी ज्यादा था, फिर भी पानी फरवरी में बंद कर दिया। मंत्री जी, आप जवाब दें तब बता दीजिए कि फसल बचाने के लिये आपने क्या प्रयास किये? पंजाब सरकार के पास कौन गया? किस प्रकार की प्रभावी कार्यवाही हुई? मेरा दावा है, मेरा मानना है कि सरकार संवेदनशील होती और पंजाब सरकार को कहती कि आपका किसानों का प्रदेश है, हमारे किसान की फसल जल रही है, तो निश्चित रूप से पानी देते, लेकिन आपको किसान की चिंता कहां है? आप तो चुनावों के समय ही किसान को याद करते हो, उसके बाद किसान याद नहीं आता।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से और राजस्थान की सरकार से, आप पंजाब सरकार से बात कीजिए। मुख्य मंत्री स्तर पर बात कीजिए और तुरंत पानी की व्यवस्था कीजिए, ताकि राजस्थान का किसान उजड़ने से बच सके, बरबाद होने से बच सके, उनके बच्चों का निवाला नहीं छीना जाये।

सभापति महोदय, एक नई बात और हो रही है, हर साल बंदी आती है, आपने फिर बंदी मांग ली। आप मुझे बताइए कि फरवरी से पानी नहीं, मार्च में पानी नहीं, अप्रैल में बंदी मांग ली, तीन महीने की बंदी। गांव में झोंपडियों में, ढाणियों में किसान रहता है, उसका पशुधन कहां जायेगा? मर जायेंगे किसान, मर जायेंगे गरीब लोग। इनको बचाने के लिये आपको प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये। सभापति महोदय, अभी वर्तमान में जो मुख्य नहर है, उसमें 3000-3500 क्यूसेक्स पानी चल रहा है। इस पानी को सभी नहरों में बांट कर गांव-ढाणियों में पशुधन को बचाने का काम किया जाना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, एक नई बात और कहना चाहता हूं कि मैं तारानगर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और मेरा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से जुड़ा हुआ है और वहां पर किसान बरबाद हो रहे हैं, किसान की फसल सूख रही है। जैसे और किसानों की सूख रही है, वैसे ही हमारी भी सूख रही है, लेकिन अत्याचार तो मत करो। राजनीतिक बदले की भावना से तो काम मत करो। किसान सबको वोट देता है, किसान किसी जाति का नहीं होता है, किसान सबका होता है। यहां राजनीतिक द्वेषता से काम हो रहे हैं। किसानों के साइफन काटे जा रहे हैं और

गिनगिन के काटे जा हैं और वह सिर्फ गरीब आदमी होता है, बड़ा किसान काबू में नहीं आता है, सिर्फ छोटा किसान ही है जिस पर यह ज्यादती होती है, यह जुर्म बंद करो। मैंने पांच साल के कांग्रेस राज में एक साइफन नहीं कटने दिया और एक भी अदालत में मुकदमा नहीं हुआ। आज जा कर देखिए, किसान का लाखों का नुकसान हो गया।

सभापति महोदय, एक तरफ राजस्थान पानी की कमी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ राजस्थान का बरसात का पानी व्यर्थ में बह रहा है। कन्हैयालाल जी, पानी समुद्र में जा रहा है। जा रहा है या नहीं जा रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? आजादी के इतने साल बाद भी हम बरसात के पानी को रोक नहीं पाये। हमारा लगभग 50-70 टीएमसी बरसात का पानी अरब सागर में जा रहा है। इसको रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिये। लोक सभा चुनाव में जालोर में मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी की मौजूदगी में कहा कि माही नदी का पानी जालोर में लाने के लिये हम संकल्पित हैं, यह भाषण मैंने सुना है। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन वह खुशी कहां गई, खतम। चुनाव के बाद भूल गये, अब इस नदी का नाम ही नहीं ले रहे। अब मुख्य मंत्री जी जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। डरो मत, यह गुजरात खा नहीं जायेगा हमको, इस लॉबी से डरो मत। हम जीत कर आते हैं, उनकी वजह से नहीं आते हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जालोर जिले में यह पानी कडाना बांध से आयेगा। यह पानी गेल की फ्लो से लाया जायेगा, जिसकी फिजिबिलिटी होने की तकनीकी स्वीकृति भी जारी हो चुकी है।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय सदस्य, उस पर काम चल रहा है।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): अच्छी बात है काम चल रहा है तो, लेकिन धरातल पर दिखाओ तो सही। आप जवाब में बता देना मेरे को कि क्या काम हुआ है। मंत्री जी, जब आप जवाब दो तो आप कहलवा देना कि कितना काम हुआ है।

श्री सभापति: कोई भी बीच में नहीं बोलें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): पिछली बजट घोषणा को आप चैक करें, उसमें सब कुछ स्पष्ट दिया हुआ है। 7 हजार करोड़ का प्रावधान लिया हुआ है।

श्री सभापति: बीच में ना बोलें। माननीय सदस्य, आप अपनी बात को जारी रखें, आप भी इनसे बात ना करें, आप तो अपनी बात कहें।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): सभापति महोदय, ईआरसीपी का नाम बहुत जोरों से लिया जा रहा है, ईआरसीपी, ईआरसीपी। कभी आप इसका नाम बदल कर केपीसी कर देते हैं, फिर कभी राम सेतु कर देते हैं, इससे पेट भरने वाला नहीं है।

Msk/rtm/05.03.25/1330/1q

नाम बदलने से पेट भरने वाला नहीं है। धरातल पर क्या है? धरातल पर बताइये। जनता है, ये सुनती भी है और फैसला भी करती है। आप तो मुझे इतना बता दीजिये कि आपने

इसके बारे में क्या किया? इसके बार में स्पष्ट रूप से बता तो दीजिये। जनता अंधरे में हैं, आप तो अपने जवाब में यही बता दीजिये कि जल संसाधन में कितना पैसा आवंटित था, उसमें कितना खर्च हुआ, यह तो बता दीजिये। ईआरसीपी का काम करिये, हमें खुशी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मुख्य मंत्री जी, जब मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने पहला काम, कहा कि मैं पानी लेकर आऊंगा, समझौते की ओर अग्रसर हुए। हमें बहुत खुशी हुई। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन प्रयास प्रयास ही रह गये। वास्तविकता से दूर हो गये। आज वास्तविकता क्या है? इस वास्तविकता पर आने की जरूरत है। आप ईस्टर्न की बात करते हैं, आप हमारे पश्चिम की तो बात ही नहीं करते। हम कितने लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं, आप उसके बारे में भी तो सोचिये। आप उसके बारे में भी कोई योजना बनाइये। आज हमारी नहरें टूटी हुई पड़ी हैं, मरम्मत नहीं हो रही है। मरम्मत के नाम पर असत्य बिल बनाये जा रहे हैं, सफाई के नाम पर बिल बनाये जा रहे हैं। कोई काम धरातल पर नहीं हो रहा है, यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यमुना जल समझौते की बात की और उन्होंने जोर-शोर से कहा कि मैं हरियाणा से समझौता करके आया हूं और चूरू जिले को, झुझुनूं को, सीकर को सिंचाई और पीने के लिए पानी भी देंगे। आपकी डीपीआर कहां है? एक साल हो गया है, कुछ तो बताइये। आपने पिछले वर्ष इसके लिए इतना हल्ला मचाया, श्रीचन्द जी इस बजट में क्या स्थिति है? आज बजट में यमुना जल का नाम तक नहीं लिया। यह है, आपकी घोषणा की स्थिति है। ...(व्यवधान)... जो प्रयास हो रहे हैं, मैंने उनके लिए धन्यवाद दिया है।

मैं 1993 में राजस्थान की विधान सभा का सदस्य था, भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने 1994 के अन्दर समझौता किया। मैंने उस डिबेट में भाग लिया है, मुझे 1994 की बात भी याद आती है और 1994 से लेकर आज तक क्या हुआ, देख लीजिये। प्रयास तो और मुख्य मंत्रियों ने भी किये, वसुन्धरा जी ने भी किये, मैं स्वीकार करता हूं। अशोक गहलोत जी ने भी इसके ऊपर खूब काम किया। अब भजन लाल जी की सरकार कर रही है, भजन लाल जी कर रहे हैं। आप बताइये कि हम खड़े कहां हैं? आप कहते हैं कि हम पाइपलाइन से पानी लेकर आयेंगे। आपको पाइपलाइन कौन डालने देगा? पाइपलाइन डाल भी दी तो हरियाणा के मुख्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। पानी आयेगा कहां से? यह पानी कैसे आ रहा है? फ्लड का पानी हमें मिलेगा। आप बताइये, फ्लड कब आता है और कितने समय आता है? इस पर जब इतना खर्चा करने की बात कर रहे हैं तो फ्लड का पानी क्या किसी से रुकेगा? किसी की हिम्मत है फ्लड का पानी रोकने की? जब पानी अधिक होगा तो मिलेगा, फ्लड का पानी तो ऐसे ही मिलता है। इसके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज डीपीआर के लिए आपने पैसा अलॉट किया, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। डीपीआर बनी नहीं। चुनाव के अन्दर जोर-शोर से कहा कि हम इन तीन जिलों को पानी देंगे। कितना पानी

देंगे, यह तो बतायें। कहां-कहां देंगे, यह तो बतायें। चूरू में कितना देंगे, झुंझुनूं में कितना देंगे, सीकर में कितना देंगे, हमको यह बताओ तो सही। यह सब सपना का सपना रह जायेगा, हरियाणा हमको एक बूंद पानी नहीं देगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिये। हरियाणा के मुख्य मंत्री यह दिखा रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी इस बजट के अन्दर सरकार ने एक असत्य सपना दिखाने की कोशिश की है। इस बजट में बताया गया है कि साहवा लिफ्ट कैनाल के अन्तर्गत तारानगर, चूरू में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि किये जाने हेतु डीपीआर बनायी जायेगी। यह साहवा लिफ्ट कैनाल कहां है? इसका तो नाम ही बदल दिया। साहवा लिफ्ट कैनाल पहले थी, फिर सरकार ने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल कर दी। आपको अधिकारी यह भी नहीं बता रहे हैं कि इस लिफ्ट कैनाल का नाम क्या है? या तो बताना नहीं चाह रहे, या आप उस महान नेता का नाम नहीं लेना चाहते। उस किसान के मसीहा का नाम नहीं लेना चाहते। आप जनता के सामने सही बात तो करें। मैं कहना चाहता हूं कि आपको डीपीआर बनाने की आवश्यकता कहां से आ गयी? डीपीआर की आवश्यकता ही नहीं है। घोषणा होती है तो काम करके दिखायें। हमने पहले ही बजट में तारानगर के अन्दर 20 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचित करने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और 10 हजार पर काम पूर्ण हो गया और 10 हजार पर ही काम चालू है। इसको काम कहते हैं। कोई डीपीआर नहीं बनी। बनाने की जरूरत ही नहीं है। सीडब्ल्यूसी से तो पास है। रिवाइज तकमीना भी पास है। जब इन्दिरा गांधी कैनाल में योजनाएं बनती है तो सीडब्ल्यूसी से भी अनुमति मिलती है, वह मिली हुई है। आपको डीपीआर बनाने की जरूरत नहीं है। आप भ्रमित मत करो। यह डीपीआर, डीपीआर करके भ्रमित मत करो, विधान सभा में असत्य बात मत बोलो। जनता को गुमराह मत करो। आपकी मंशा है तो आप घोषणा करो कि तारानगर क्षेत्र की इतनी हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित करेंगे, मैं खुद आपको माला पहनाने आऊंगा। करिये घोषणा। हिम्मत नहीं है। आपकी हिम्मत नहीं है।

सभापति महोदय, तारानगर, जहां से मैं चुनकर आता हूं। यह सही बात है कि पहले इसका नाम साहवा लिफ्ट कैनाल था, लेकिन जो साहवा कस्बा है, उसके नीचे किसान की जो जमीन है और आसपास का जो क्षेत्र है, वह सिंचाई से वंचित है। आज किसान आन्दोलित हैं। उनकी मांग वाजिब है कि हमें भी नहर से जोड़िये। मैं, मुख्य मंत्री जी, मांग करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि साहवा को और साहवा के आसपास की जमीन को सिंचित घोषित करिये। जब 12 तारीख को बोलें तो आप इसकी घोषणा करें, मैं उम्मीद करता हूं। सभापति महोदय, किसानों के साथ अन्याय मत होने दो। आज हमारे तारानगर में 20 हजार हेक्टेयर जमीन पर नहर बनी है। किसानों की जमीन अवाप्त हुई है। छोटे-छोटे किसान हैं, उनके पास छोटी-छोटी जमीनों के टुकड़े हैं, उनकी जमीन चली गयी।

mdp/rtm/05.03.25/13:40/2a

उनको मुआवजा तो सही मिलना चाहिए। मुआवजे का कायदा है, मंत्री महोदय कि आपकी जो रेट है, उससे चार गुना अधिक होती है। इसलिए अन्याय मत करना। वहां यह चल रहा है कि हम तीन प्रतिशत बढ़ाकर देंगे, तीन गुना। ये तीन गुना नहीं चार गुना बढ़ाना उनका हक है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात को आप हल्के में मत लेना। यह बात बहुत बड़ी बात होगी, किसान सड़क पर आ जाएगा, आंदोलित हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी।

सभापति महोदय, मैं सिंचाई की बात कर रहा था। अब पीने के पानी की बात करना चाहता हूं। आपकी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा संकट कोई रहा है तो पीने के पानी का रहा है। आप सब इस बात को जानते हैं। ये कब तक करेंगे, आपने किया, आपने किया, हमने नहीं किया तो हम यहां पर बैठे हैं। अब तो आप बैठे हो तो कुछ करो तो सही, कुछ करके तो दिखाओ। करके दिखाएंगे तो जनता देखेगी। देखिए, अभी गर्मी है, गर्मी गयी पीछे, सर्दी गयी, अब सर्दी में भी पानी का भयंकर संकट हो रह है। एक-एक महीने तक पानी नहीं आता है। सभापति महोदय, एक महीने पानी गांव में नहीं आयेगा तो वहां के लोग कैसे जिंदा रहेंगे? इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग के ऊपर टैंकर माफिया हावी है, आप उनको कंट्रोल कीजिए। वे अधिकारियों से मिले हुए हैं। गांवों में पानी जाने नहीं देते। एक-एक हजार रुपये में टैंकर बेचते हैं। किसान को, गरीब को लूट लिया उन्होंने। एक बात और कहना चाहता हूं कि गांव के अन्दर गरीब की बस्ती में पानी नहीं जाता। हकीकत बता रहा हूं कि गांव की गरीब बस्ती में पानी नहीं जाता। रसूखदारों ने इल्लीगल कनेक्शन कर लिए और मोटरें लगा रखी हैं। आप अभियान चलाइए, मैंने पिछली विधान सभा में भी कहा था कि उन पर कंट्रोल कीजिए। एक बात और कहना चाहता हूं कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं। हमारे एरिये में नहर का पानी इतना जहरीला आता है कि कैंसर के केस दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। गाडियों की गाडियां फूल जाती हैं। कैंसर के नाम से गाडियां चल रही हैं, और बीमारियां हो रही हैं। किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, लोगों को पीलिया हो रहा है। जहरीला पानी पी रहे हैं। इसके ऊपर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, दो-तीन मिनट और लूंगा। जे.जे.एम., जल मिशन एक शानदार योजना है और उसको 2028 तक बढ़ाई है सरकार ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप कर लीजिए, मैं आपके लिए ही कह रहा हूं।

श्री सभापतिः आप बोलिए। पक्ष-विपक्ष में न रहे।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): इस योजना को राजनीति का शिकार मत बनाइए। भ्रष्टाचारियों को दंड दीजिए, चाहे वह कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसको माफ मत कीजिए। हम आपके साथ है। लेकिन करो तो सही। एक सुझाव देना चाहता हूं, कन्हैयालाल जी, एक मोनिटरींग कमेटी बनाइए। एक विधान सभा स्तर पर बनाओ, विधान सभा के अन्दर। इतनी कमेटियां बनी हुई हैं, एक कमेटी और बना दो। जिले के अन्दर कमेटी बनाओ, उसमें वहां के विधायक को शामिल करो। मॉनिटरींग अच्छी होगी तो इसके परिणाम अच्छे आएंगे। यह

कहना चाहता हूं। तारानगर की जो 650 करोड़ की योजना है, उसके 2021 से 2022, 2023, 2024 में टेंडर हुए। अभी एक तारानगर पांडूसर 133 करोड़ की योजना के वर्क आर्डर हुए, उसको चालू तो कराइए। 6 महीने हो गये।

श्री सभापतिः विराजिए।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): धर्मशाला फीडर, धरमासर, चूरू, बिसाऊ ये सारी चीजें हैं। एक बात मैं....

श्री सभापतिः श्री गुरवीर सिंह।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (तारानगर): एक मिनट के लिए। मैंने, मंत्री जी, 5 टंकियां विधायक कोटे से बनायी हैं। 37-37 लाख रुपये दिए मैंने एक टंकी के, वह टंकी सवा साल से पानी का इंतजार कर रही है। आप पानी से जोड़ दीजिए। पानी से जोड़ दीजिए, जनता को कम से कम लाभ तो होगा। मेरा जो पैसा किया हुआ है विधायक कोष का, आज मुझे परेशानी होती है कि मेरा पैसा खर्च किया हुआ, वहां पर काम नहीं आया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री गुरवीर सिंह।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 व 42 के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी बात शुरू करूं उससे पहले मैं कबीर के एक दोहे से अपना वाक्य शुरू करूंगा-

'जल बिन मीन प्यासी रे, बिन पानी सब सून,

पानी गए न उबरे, मोती मानस चून।'

आज राजस्थान हमारा ऐसा प्रदेश है, जो पूरे देश की भौगोलिक स्थितियों से हमारे लिए चुनौतियां पूरे देश से अलग हैं, हमारे लिए कठोर हैं और हम पानी के बहुत से अलग-अलग स्रोतों पर निर्भर हैं। मैं देश की बात करूं तो आज दुनिया की जनसंख्या का भारत 18 परसेंट पापुलेशन इस देश में है, परंतु हमारे जो वॉटर रिर्सोसेज हैं वे मात्र 4 परसेंट हैं। इसके अलावा भारत का जो पर-कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर है, वह 1947 में जहां 6042 क्यूबिक मीटर था, 2021 में 1486 है, जिसमें 75 परसेंट हमारा डिक्लाइन हुआ है।

यह चुनौती और बढ़ जाती है जब हमारे सरकार के जो आकलन है, 2031 में जो आकलन है वह 1366 पर-केपिटा पर चले जाते हैं। सरकार केन्द्र की हो, राज्य की हो, किसी भी दल की हो, हमारी चुनौतियां और बढ़ जाती है। जहां रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की बात करूं तो जितनी बारिश पूरे देश में हर साल होती है, मात्र उसका 8 प्रतिशत पानी हम रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से संजो पाते हैं, हम संचय कर पाते हैं। हमारे को इस पर काम करने की आवश्यकता है।

जहां पानी की महत्ता को बताते हुए एच.आर्डर ने लिखा है - "thousands have lived without love, not one without water" कि हजारों लोग प्यार के बिना जिंदा रह सकते हैं, एक व्यक्ति पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये जो आज की महत्ता है, जो पानी की आवश्यकता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जब से जन्म लिया है तब से यह

स्लोगन इस देश में चलते आ रहे हैं। वह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप सबने भी पढ़ें होंगे। जिसमें लिखा है कि 'जल ही जीवन है', 'जल है तो कल है', 'जल से तो संसार है, पानी हर जीव का अधिकार है', पानी की बरबादी को रोकिए, बिना पानी क्या होगा जरा सोचिए'। ये सदन सोचे, सारे राजनीतिक दल के लोग सोचें, ये समाजसेवी सोचें, ये अधिकारी सोचें कि भारत के आने वाले भविष्य के लिए हमें क्या करना है? हमें लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है। ये मात्र स्लोगन बनकर नहीं रह जाए, यह मेरा सदन से आग्रह है। आज जहां सब तरह के अलग-अलग रक्षक बने, जहां जिस अभियान को देश ने छेड़ा उसको कामयाब किया है, आज जल रक्षक भी हमें बनना चाहिए। यह मैं मेरे देशवासियों से आग्रह करता हूं। हमें इसको जन-आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। इसके लिए मैं देश के हर नागरिक से आग्रह करता हूं।

प्रधान मंत्री मोदी जी ने पिछले 11 साल के कार्यकाल में बहुत-सी योजनाएं शुरू की हैं। चाहे प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, जिसमें तकरीबन 100 प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया। जिसके माध्यम से तकरीबन 24.35 लाख हैक्टेयर हमारा एडिशनल एग्रीकल्चर लैंड क्रियेट हुआ और जिससे पानी की बचत करके, उसकी क्वालिटी पर और काम कर सकें, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री जी ने इसको एक्सटेंशन देते हुए पी.एम.के.एस.वाई का तकरीबन 94 हजार करोड़ रुपया आज भारत की सरकार ने सेंक्शन किया है।

इर्रिगेशन की एफिशिएंसी पर एम.एस. स्वामिनाथन जी की रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो कम से कम तीस साल पहले उन्होंने हमें आगाह किया और ज्यादातर सरकारें उस पर काम नहीं कर पायी। हमारे लिए एफिशिएंसी बढ़ाने में आज ओवर ऑल इर्रिगेशन एफिशिएंसी जो मात्र 38 परसेंट है, इसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। नये खाले हों, नयी लाइनिंग हों, नहरों का, खालों का सुधार हो ताकि हम बचत कर सके। आज यदि हम इस पर पैसा खर्च करते हैं तो हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो पानी से जुड़े हैं, कम से कम उसका साढ़े बाईस परसेंट पानी हम बचा सकेंगे। इसके साथ ही राजस्थान सरकार के इस नवगठन के बाद माननीय भजन लाल शर्मा जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद पिछले साल की बजट घोषणा हुई, उसमें मुझे खुशी है कि राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड में 50 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया।

Ans/rtm 13.50 2b 05.03.2025

यह मात्र पूर्ववर्ती सरकारों की तरह घोषणा नहीं रही। तमाम राजस्थान के सेक्टर्स को इसमें जोड़ते हुए, चाहे वह उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम जहां भी जरूरत थी, उसके लिए बजट ही आवंटन नहीं किया वहां काम जारी हो गए, कामों के कार्यादेश जारी हो गये, आज काम प्रगति पर है। इस सरकार के रहते-रहते, पांच साल के लिए जनता ने चुना है, उस पांच साल में यह धरातल पर उतरेंगे मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अभी माननीय वरिष्ठ विधायक बोल रहे थे। आपने लगातार तीन साल तक ईआरसीपी का नाम लिया। पूरे देश के मीडिया ने जब भी आपसे दिल्ली में जाकर कोई इंटरव्यू लिया, केन्द्र सरकार पर जवाब मांगा, राजस्थान सरकार पर जवाब मांगा, तो मुख्य मंत्री जी के मुंह से एक शब्द निकलता था कि केन्द्र सरकार से पैसा नहीं आया। किसने रोका था आपको ईआरसीपी पर काम करने के लिए? आप एक पैसा पांच साल में नहीं लगा सके और आज की सरकार पर दोषारोपण करते हैं। आज सरकार ने ईआरसीपी को राम जल सेतु के नाम पर, हमारा एमओयू ही नहीं हुआ पांच साल में हम धरातल पर उतार कर दिखाएंगे। इससे एक तिहाई आबादी को पेयजल मिलेगा और हमारे 17 ज़िलों के चार लाख हैक्टेयर के किसानों को पानी मिलेगा। आप सब लोग इन्हीं पांच साल में देखेंगे, जो धरातल पर उतरेगी।

यमुना की बात हो रही थी। माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ है, 1993-94 की बातें कर रहे थे। भैरोंसिंह जी शेखावत ने 1994 में समझौता किया। आपने 15 साल राज किया, केन्द्र में भी आपकी सरकार थी, तब आप सो रहे थे? आज भजन लाल जी शर्मा ने इस पर काम किया है तो क्यों आपके पेट में दर्द है। आप 15 साल कहां गये थे, फुल मेजोरिटी की आपको सरकार मिली थी, एक बूंद पानी नहीं लाये। कभी इनके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, कभी इनके नेता बोलते हैं, कभी विधायक बोलते हैं, एक बूंद पानी नहीं आयेगा। आप जो मर्जी नकारात्मक सोच रख लीजिए पानी राजस्थान के शेखावाटी का अगर कोई लेकर आयेगा तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी लेकर आएंगे। चाहे सीकर हो, झुन्झुनूं हो, चूरू हो उसके लिए जो पानी समझौता किया है वह मिलेगा।

अभी हमारे साथी ने पेयजल पर बड़ी चिंता जाहिर की। तारानगर विधायक ने बात रखी कि पानी का संकट है, रसूखदार ले गये, कैंसर ट्रेन चल रही है। तो आप कहां गये थे, आपने पांच सालों में क्या प्रयास किये? आपको राजस्थान में 50 साल तक सरकार बनाने का मौका मिला, आप अब तक कहां गये थे? उन्होंने माना है कि जे.जे.एम. योजना शानदार है। जे.जे.एम. योजना में भ्रष्टाचार हुआ, यह भी माना है। क्योंकि हम तो इस सदन में नहीं थे, पुराना कुछ डाटा खंगालना पड़ता है, हम जब पिछले प्रतिवेदन पढ़ते हैं, बजट भी पढ़े हैं। इनके पांच साल के सारे गवर्नर के अभिभाषण, सारे बजट की घोषणाएं और इनकी अचीवमेंट हमने प्रतिवेदनों में पढ़ी है। मैं जे.जे.एम. की बात करूं तो 2019-20 में इन्होंने जो टारगेट लिया वह 17 लाख 92 हजार परिवारों का था और अचीवमेंट 01 लाख 2 हजार यानी मात्र 13 परसेंट है। उसके अगले साल पर आईये, 2020-21 में जे.जे.एम. के अन्दर टारगेट 20 लाख 71 हजार है और अचीवमेंट 19 परसेंट है। 2021-2022 टारगेट 30 लाख का और अचीवमेंट 5.38 है, यानी 18 परसेंट है। अगर 2022-2023 की बात करें और 2023-24 की बात करें तो पहली बार 40 के ऊपर ग्राफ़ गया है। जहां केन्द्र की सरकार ने इनको 93 हजार करोड़ रुपये राजस्थान में आवंटित किये, पांच सालों में सिर्फ 32 हजार करोड़ ले पाए। माननीय, वह 32 हजार करोड़ रूपये कहां लगे, यह जांच निश्चित तौर पर होगी, मॉनीटरिंग टीम बनी है, एक-एक काम की जांच होगी। हमारे मंत्री जी ने एक-एक विधायक से डिमांड

मांगी है और हमने सूचना दी है। बी.एस.आर. में इनके पाइप के रेट्स थे वह ज्यादा थे और मार्केट रेट से तीन गुणा थे। लाइन के साइड की पेमेंट्स उठाई है, पुरानी पाइपों को नाप कर पेमेंट उठाई है, जब इनके काले चिट्ठे सामने आएंगे तो सदन की पटल रखेंगे। इनके साथ, जब बाड़ ही खेत को खाने लगी थी उसके पर्दे फाश होंगे।

माननीय, जल जीवन मिशन को फेल करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसका टारगेट बढ़ाकर 2028 तक किया। हमारे बजट में हमने जो योजना रखी है, हमारे पिछले साल की अचीवमेंट है 6 हजार 91 करोड़ रुपये लगाकर 11 लाख 36 हजार परिवारों को हम घर में जल दे चुके हैं। आज इस साल में जहां अमृत-2 योजना में 183 नगर निकायों में 5123 करोड़ रूपये लगाकर हम काम कर चुके हैं। जल जीवन मिशन के ग्रामीण क्षेत्र में जहां 2024-25 में 1301 के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं और 2025-26 में हमारे 41 हजार 621 के टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, यह काम इसी पांच साल में करके हम धरातल पर उतारेंगे और आप सबके सामने हमारे लास्ट साल में हम रिजल्ट रखेंगे।

माननीय, मैं आई.जी.एन.पी. की बात करूं। हमारे से वरिष्ठ सदस्य अभी बात कर रहे थे। मैं आई.जी.एन.पी. की हिस्ट्री को सदन के सामने रखना चाहता हूं। बहुत से लोगों को जानकारी होगी, 1984 में हिमालय की नदियों का पानी हमारे बीकानेर रियासत में लाने के लिए तत्कालीन महाराजा डूंगरसिंह जी ने जो प्रयास किये। उस समय की पंजाब की रियासत हो, भावलपुर की रियासत हो, उनके विरोध के बावूद महाराजा गंगासिंह जी ने प्रयास शुरू किये और 1921 में उसकी शुरुआत करके 1927 में शिवपुर हेड पर उद्घाटन हुआ, मेरा सौभाग्य है वह सादुलशहर विधान सभा में आता है। हिमालय का पानी राजस्थान के मरुस्थल में लेकर आये तो महाराजा गंगासिंह जी लेकर आये। आई.जी.एन.पी. की परिकल्पना, आई.जी.एन.पी. की सोच और इसके लिए किसी ने रखा तो महाराजा सर्दुल सिंह जी ने रखा, जिन्होंने 1946 में राय बहादुर कंवर सेन जी को इसमें नियुक्त किया। आज हरिके बैराज है, वह उन्हीं की परिकल्पना थी, जिससे हम राजस्थान फीडर और फिरोजपुर फीडर से पानी ले रहे हैं। हरिके बैराज और आई.जी.एन.पी. की, उनकी सोच से उस समय 18 हजार 500 क्यूसेक्स पानी निर्धारित हुआ, आज उसकी क्षमता मात्र 11 हजार रह चुकी है। 18 हजार 500 की डिजाइन की हुई नहर आज की स्थिति में 11 हजार पानी ले रही है। आज तक का रिकार्ड खंगाला जाए तो पिछले 75 सालों के रिकार्ड में मात्र भैंरोसिंह जी शेखावत की ऐसी सरकार थी जिसमें 14 हजार क्यूसेक्स पानी 1993 से 1998 के बीच चला। ना कभी उससे पहले चला, ना उसके बाद चला, क्योंकि हमारी नहर जर्जर हो चुकी थी। इनकी कभी सोच नहीं रही कि इस नहर को दोबारा काम करने की जरूरत है, इन्होंने कभी प्रयास नहीं किये कि आई.जी.एन.पी. के द्वारा बनाया जाए।

हमारे तारानगर से आने वाले विधायक अभी बात कर रहे थे, जो आरोप उन्होंने लगाये कि किसान बरबाद हो रहा है, फरवरी में पानी नहीं मिला, पंजाब से वार्ता नहीं की। मैं बताना

चाहता हूं, आपके 2013 से 2018 के कार्यकाल में आपका मंत्री पंजाब में एक बार गया। पांच साल में मात्र एक बार इनका मंत्री पंजाब गया, उसको एक बूंद पानी नहीं मिला और आई.जी.एन.पी. के साथ चिपटी जमीन बेचकर आया और हमने वहां गंगानगर की सड़कों पर धरना दिया, यह है आपकी पांच साल की अचीवमेंट।

आज हम पोंग डैम की बात करें। जिसकी यह बात कर रहे हैं, आपका कांग्रेस का एक भी मंत्री व विधायक कभी भटिंडा क्रोस नहीं किया, आपको डैम की हालत पता नहीं कि पानी कैसे आएगा। पोंग डेम का जहां हमारा 49 परसेंट शेयर है, जिसमें उसकी केपेसिटी 1400 फीट भरने की है। पोंग डैम के लोगों को हमने घडसाना, अनूपगढ़ से लेकर जैसलमेर, मोहनगढ तक ज़मीनें दी है। हमारी जमीन देकर पानी लेकर पानी लेकर आए हैं, वह राजस्थान का हिस्सा है। आप बता दे, आज तक एक भी कोई मंत्री पोंग डैम की शक्ल देखकर आया है? वह भैरोंसिंह जी थे या वसुन्धरा जी थी और आज अगर किसी ने चिंता की है तो भजन लाल शर्मा जी ने की है। आप कभी नहीं बढ़ा पाए। पहली बार 1400 क्यूसेक्स, हमारे मुख्य मंत्री जी ने यहां से केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी, हमारी तीन बैठकें केन्द्र में हुई है, आज सीडब्ल्यूसी ने उसकी स्वीकृति जारी कर दी है, हम अगले साल से 1400 क्यूसेक्स पानी उस डैम में भरेंगे, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

पोंग डैम की बात करूं। 21 सितम्बर की बात कर रहे थे जब रेगुलेशन तय होता है, आप कभी रेगुलेशन की मीटिंग में नहीं गये। पांच साल इनकी सरकार रही, अखबार गवाह है, कांग्रेस का कोई एमएलए रेगुलेशन की मीटिंग में जाकर नहीं बैठा, यह ज्ञान बांट रहे हैं। मैं आज की हकीकत बताता हूं, पोंग डैम में मात्र 60 परसेंट पानी है, कभी जाकर देखिये, आंकड़े चेक करिये, उसके बावजूद हम आज 5-5 बारियां गंगानगर से लेकर जैसलमेर तक किसानों को देने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने बात की है, मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी से बात की है, हमारे सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी बात हुई है। मैं खुद जाकर इर्रिगेशन मिनिस्टर से मिलकर आया हूं, कैसे पानी लाए हैं, वह आप सपने में भी नहीं सोच सकते। यह पहली बार नहीं है। आज से पहले जब अकाली दल की सरकार हुआ करती थी, वसुन्धरा जी ने एक डेलीगेशन गंगानगर के हारे व जीते सभी एमएलएज का बनाकर भेजा।

VPS-RTM-05.03.2025-14.00-2c

तब भी हम प्रकाश सिंहजी बादल से पानी लेकर आये थे। कैप्टन अमरिंदर सिंहजी से भी पानी लेकर आये थे पर आपकी सरकार में आज तक एक विधायक, एक मंत्री दिखा दें, कोई रिकार्ड आपके पास हो तो दिखा दें, यह सदन के टेबल कर देना चाहिए। भाखड़ा डैम की बात करूं तो जब वॉटर इन-फ्लो से हमारा डिसाइड होता है, जब पानी का रेगुलेशन तय होता है तो आज मात्र 19 परसेंट पानी ही वॉटर इनफ्लो में आया है, उसके बावजूद राजस्थान में हम पानी लेकर आये हैं। हमारा शेयर निल है, आप आकड़े उठाकर देख लीजिए निल शेयर होने के बावजूद भी गंगानगर की गंगनहर हो, भाखड़ा हो और चाहे जैसलमेर-बाड़मेर तक पीने का

पानी पहुंचाने की बात हो तो आज हमारी सरकार ने पानी पहुंचाया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा आज रावी-व्यास की बात करे तो रावी-व्यास की बात हो तो यह मानसून पर निर्भर है। आप स्टडी कीजिए, केन्द्र सरकार ने इस पर स्टडी की है और पानी के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है। डैम के पिछले केचमेंट एरिया में बारिश नहीं है, वहां पर जिस अनुपात में बारिश की उम्मीद लगाकर पंजाब-हरियाणा बैठे हैं, हम उसके आखिरी छोर में बैठे हैं और मुझे यह कथन याद है, एम.एस. स्वामीनाथन जी ने जो मानसून पर लिखा है - "farming is the riskiest profession in the World since the fate of the crop is closely linked with the behaviour of the monsoon.", हम मानसून पर निर्भर हैं। आप उसकी स्थिति को जानिये और फिर अगली बात हम जब नहरों की करें और जो हमारे इन सालों में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है और एक बार बी.जे.पी. की सरकार आती है और मैं दोनों की सरकारों के चिट्ठे आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जिस बात की इन्होंने बात की, आज वसुन्धराजी की सरकार थी और ऊपर मोदीजी की सरकार थी, इस डबल इंजन की सरकार में 2,462 करोड़ रुपये आई.जी.एन.पी. के लिए मंजूर हुआ और काम शुरू हुआ। यह बातों में नहीं रहा, आज आर.डी. नम्बर 179 से लेकर आर.डी. नम्बर 496 जो पंजाब का हिस्सा है, लोहगढ़ हेड तक आने का, सी.सी. लाइनिंग का ऐसा शानदार क्वालिटी का काम हुआ है कि एक बूंद का रिसाव भी उसमें से नहीं हो सकता। 500 माइक्रोन पॉलिथीन फिल्म उसमें लगी है और पूरे अधिकारी, एस.डी.ओ. से लेकर चीफ इंजीनियर तक, वे हमारे मंत्री और मुख्य मंत्री के आदेश से सारी-सारी रात वहां बैठकर काम कराते रहे और आज उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है, जीरो आर.डी. से आर.डी. नम्बर 179 जो हरिके बैराज से लेकर पंजाब के हिस्से में है, उसकी डी.पी.आर. बनाने के लिए भी राजस्थान की सरकार ने आदेश कर दिया है। उसके बाद अगर लोहागढ़ हेड से मसितावाली हेड 671 आर.डी. तक, हमारा मात्र 12 किलोमीटर काम शेष बचा है बाकी सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ है। आज जीरो आर.डी. मसितावाली से लेकर 200 आर.डी. तक अगर काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने क्या किया जनाब? आपके जादूगर मुख्य मंत्रीजी 2008 से 2013 में आये तो ज्यादातर विधायकों को यह पता ही नहीं होगा, आप चाहे तो आर.टी.आई. लगा लेना, चाहे तो रिकार्ड खँगाल लेना, लोहगढ़ हेड पर तीन नहरें हरियाणा को दी क्योंकि आपके सिंचाई मंत्री के रिश्तेदारों की जमीनें पड़ती थीं, आपके चीफ इंजीनियर की डबवाली में जमीनें पड़ती थीं। तीन नहरें दी हैं। मैं तब तो छोटा था, दादाजी के साथ जाता था। 2013 की सरकार में जब इनका कार्यकाल खतम हुआ तो मुख्य मंत्रीजी से वे मिले और कहा कि जनाब, तीन नहरें दे दीं, उन तीन नहरों का पानी कहां गया? उसका जवाब कांग्रेसियों बताओ। सदन में पता चले लोगों को, आपकी हकीकत पता चले और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती है, डीडवाना से आने वाले माननीय विधायक ने भी एक दिन प्रश्न लगाया, तारानगर वालों ने भी प्रश्न लगाया, शिव वालों ने भी

प्रश्न लगाया कि हमारा पानी सीमित क्यों कर दिया गया? हमारा जो रकबा वहां लोहागढ़ से लेकर जो पानी घड़ला तक जाना था, उसका पानी कहां गया? जब यह नहर की, सार्दुलसिंहजी ने जिस नहर की परिकल्पना की थी वह 18500 क्यूसेक की थी, उस 18500 क्यूसेक में मात्र 1200 क्यूसेक पानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखा था और आपने क्या किया? वह कितना पानी था? वह पानी मात्र 6.48 प्रतिशत ही औद्योगिक क्षेत्रों का था और श्रीमान् जी, जब आप लोगों की सरकार थी तो 1574 क्यूसेक पानी दे दिया तो वह किसानों का गला काटकर पानी आपने दिया है। वह किसान का पानी था, वह पीने का पानी था। जिन्होंने आपकी जेब गर्म कर दी, जिन अधिकारियों की जेब गर्म कर दी, वह पानी किसानों का काटकर उद्योगों को दे दिया, किसान आपकी मुंह की तरफ देखते रहे और यह सरकार ने दिया है।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं हमारे भाखड़ा की बात करूं, ...(व्यवधान)... सार्दुल शहर में 92 करोड़ रुपये की नहरें देने का काम किया हो, भाखड़ा में 85 करोड़ का काम किया हो, और आज आई.जी.एन.पी. की और फिरोजपुर फीडर, फिरोजपुर फीडर का आपका 200 करोड़ का बजट उठाना कांग्रेसियों, वह आपका बजट में लगातार तीन साल तक दो सौ, दो सौ करोड़ की घोषणा की है पर एक रुपया भी नहीं लगा। आज हमारी सरकार में डी.पी.आर. मंजूर हो गयी है, तीन बार हम पंजाब में जाकर डी.पी.आर. मंजूर करवाकर लाये हैं और अगले साल से हमारा काम शुरू होगा, इसी कार्यकाल में फिरोजपुर फीडर बनेगी। अब हमारे बालेवाला जीरो हैड से लेकर खक्खा हैड तक 300 करोड़ रुपये अगर किसी ने दिया है तो माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्माजी ने दिया है।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रहे हैं, यह पचास साल तक काम आयेगा। इसके अलावा मैं यह मांग करता हूं कि आज जो हमारे 368 आर.डी. तक आपने खक्खा हेड तक पैसा दिया है, शिवपुर हेड, जहां उद्घाटन 1927 में महाराजा गंगासिंहजी ने किया था, उसको आर.डी. नम्बर 423 तक लाकर उसको जोड़ दीजिए, पचास साल तक दुबारा उस नहर की तरफ देखना नहीं पड़ेगा।

श्री सभापतिः विराजये। विराजिये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): अब एक टॉपिक रह गया, साहब। पक्के खालों का। पक्के खालों का आपने क्या किया? आपके गवर्नर अभिभाषण में आप चेक करना। समय नहीं है, यह तीन पन्ने तो सिर्फ आपके ही लाया था, वह बोलने का समय नहीं है, माननीय सभापति महोदय, घंटी बजा रहे हैं।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): पक्के खालों का ही बता देता हूं। 153 करोड़ रुपया एक साल में खर्च किया है और 590 करोड़ रुपया जहां पर हमारा विधायक नहीं है, संगरिया, रावतसर, टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा में 590 करोड़ रुपया, 200 करोड़ जहां पर हमारा

विधायक नहीं है रायसिंहनगर, अनूपगढ़, रावला-घड़साना में और 250 करोड़ रुपये के खाले कोलायत में, 230 के खाजूवाला में और 150 के बीकानेर में ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री श्रवण कुमार। आप विराजये।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): 573 के तो सिर्फ खाले ही बनेंगे, जनाब, हम यह आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और जनता को भी यह पता चले कि किसने क्या किया और बी.जे.पी. ने क्या किया।

श्री सभापतिः आप विराजिये। प्लीज।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन में मर्यादित एवं संयमित भाषा के प्रयोग की अपेक्षा

श्री सभापतिः श्रवण कुमारजी, आप बोलें उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख से निकले शब्द, हमारे व्यक्तित्व का और हमारे संस्कारों के परिचायक होते हैं। यह लोकतंत्र का मन्दिर है, सदन को हम मन्दिर की तरह मानते हैं तो निश्चित रूप से यहां बड़े मर्यादित और संयमित रूप से अपने शब्दों का हमें उच्चारण करना चाहिए। इसकी छवि, हमारा व्यक्तित्व बनता है इससे और सम्पूर्ण क्षेत्र में हमारी छवि यहां के हमारे शब्दों के उच्चारण से जाती है। तो मेरा दोनों ही पक्षों के सदस्यों से यह निवेदन है कि हम जिस तरीके का शब्द कई बार जाने-अनजाने में बोल जाते हैं तो उसमें बड़ा अपने आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पूरा राजस्थान अपेक्षाभरी नजरों से देखता है और कहीं ऐसा न हो कि क्षेत्र में हमें गालीबाज नेता के रूप में जाने जाना लग जाये तो यह हमारे लिए गलत होगा। श्री श्रवण कुमार।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर विचार

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 41 और 42 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार करता हूं।

किनारे पर खड़ा हूं बेशक मगर बखूबी जानता हूं कि कौन कितने पानी में है।

हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता,

दुनिया जीतने का हौसला रखा करो, एक बार जीतने से सिकंदर नहीं बनता।

माननीय सभापति महोदय, हमारे हिंदुस्तान में पानी की बहुत ही महती आवश्यकता है। पृथ्वी पर कुल 71 प्रतिशत भाग पानी से ढका हुआ है और इतना बड़े भाग का, 97 प्रतिशत भाग का खारा पानी है। 3 प्रतिशत पानी है जिसमें ढाई प्रतिशत पानी पहाड़ों की सतह में बर्फ के रूप में जमा हुआ है और पाइंट तीन प्रतिशत ही पानी पीने के काम आता है जो शुद्ध जल है। मोटे रूप में यदि एक लाख लीटर पानी की कल्पना करे तो केवल 7 लीटर पानी ही पीने योग्य है। यह कितनी बड़ी मजबूरी है? केवल 7 लीटर पानी ही पीने योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, प्रकृति भारत में जल संसाधन उपलब्ध करवाने में कंजूसी करती है। भारत दुनिया का कुल आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा है जबकि जल संसाधनों की उपलब्धता में यह 4 प्रतिशत ही है। पूरी दुनिया की 24 प्रतिशत जमीन भारत के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी भूमि का भाग भारत के पास है। इस तरह भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है।

महोदय, संसाधनों की दृष्टि से राज्यों की तुलना करें तो हमारे राजस्थान की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का दसवां हिस्सा है। हमारे भारत का राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है।

ssy/rtm/05.03.2025/14.10/2d

कुल क्षेत्रफल का दसवां हिस्सा और देश का सबसे बड़ा राज्य है। इतना बड़ा राज्य है पर पानी का अभाव है, क्योंकि बरसात कम होती है। जो हमारे बुजुर्गों का संसाधन था बावड़ी, तालाब, यह सब हमने बंद कर दिये और नये साधन कोई अपनाये नहीं, इसलिए हम बहुत बड़े पीड़ित हैं।

सभापति महोदय, देश की कुल आबादी का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। पशु देश का 11 प्रतिशत है। कृषि योग्य भूमि केवल 14 प्रतिशत है। आबादी, पशुधन, कृषि की तुलना में हमारे राज्य के पास जल की 1.18 प्रतिशत हिस्सा ही उपलब्ध है। भूमिगत जल 1.7 प्रतिशत हिस्सा है, जो बहुत ही कम है।

सभापति महोदय, आंकड़ों की बात करें तो राज्य का वार्षिक औसत रेन फ्लो 580 है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। राज्य की कुल सीमा में 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है पाकिस्तान वगैरह। राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 61 प्रतिशत क्षेत्रफल मरू स्थलीय है। कृषि योग्य क्षेत्रफल लगभग 183 लाख हैक्टेयर है। 75 प्रतिशत भाग वर्षा पर आधारित है। केवल 25 प्रतिशत भाग पर ही सिंचाई का साधन उपलब्ध है।

श्री सभापति: एक सैकण्ड माननीय सदस्य। यह मोबाइल को अपन सदन में लेकर आयें तो मेरा निवेदन है कि इसको स्विच ऑफ कर लें। अभी घंटियां बज रही थी। बोलने वाले को भी डिस्टर्बेंस होता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान देश में सबसे अधिक जल की गुणवत्ता से प्रभावित प्रदेश है। राज्य के 51 प्रतिशत जल में फ्लोराइड है और 42 प्रतिशत जल खारा है। राजस्थान की प्रमुख समस्या की बात करुं तो राजस्थान में जल संकट ही है। अन्य समस्याओं में जैसे बेरोजगारी, किसानों की समस्या, किसान को असमान वितरण, पर मुख्य समस्या जल संकट ही है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जो बने उन्होंने अपने क्षेत्रों का ही विकास किया। झुंझुनूं जिले के लोग कैसे पानी के अभाव में रहे, क्योंकि हमारे क्षेत्र का कोई मुख्य मंत्री नहीं बना। सुखाड़िया जी बने तो उदयपुर की तरफ तोप का मुंह कर दिया, अशोक जी बने तो जोधपुर

की तरफ कर दिया, वसुंधरा जी बनी तो झालावाड़ की तरफ मुंह कर दिया, शिवचरण जी माथुर बने तो भीलवाड़ा की तरफ कर दिया, जोशी जी बने तो बांसवाड़ा में कर दिया। झुंझुनूं जिले के लोगों को तो केवल शहीद होना ही पांति आया। जिन वीरांगनाओं के पतियों की फोटो सड़कों पर लगी हुई हैं और उनके बच्चे पानी की ट्राली लेकर के घूम रहे हैं। कम से कम सदन वालो शर्म करो। हमारी इज्जत भी करो कि शहीदों के बच्चे, विधवाएं आज पानी-पानी करते फिर रहे हैं। जो देश की शान शौकत को कायम रखते हैं। वहां का कोई मंत्री बना तो अपना काम निकाला, गंडा पाड़ा खेत के बाहर, लेकिन हमारा मुख्य मंत्री बना नहीं, मुख्य मंत्री नहीं बनेगा तो विकास के कार्य अधूरे रहेंगे।

अब जल मंत्री जी बने हैं, ऐसी जगह से बने हैं जब उठते हैं तो पानी की गंगा दिखती है और सोते हैं तो पानी की गंगा दिखती है। आपका क्षेत्र पानी से भरपूर है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): विभाग बदला जाये इनका। इनका विभाग बदला जाना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ना, ना, बदला नहीं जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप मांग करो इस बात की।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झुंझुनूं को पानी देना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि बदला जाना चाहिए। मैं क्यों कहूंगा? अगर इनको थोड़ी बहुत भी हम पर दया आती है तो शहीदों के बच्चों को पानी देना चाहिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप तो श्रवण जी घोषणा करो ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरी घोषणा कौन करेगा, मुख्य मंत्री जी ने भाषण में यह कहा था कि श्रवण, आपको पानी नहीं जल पिलाऊंगा। आज तक तो मैं जल, जल करता पागल हो गया। मुझे तो मिला नहीं। कौन पिलायेगा, आपको कब दया आयेगी, कब दया के पात्र बनोगे, कब पानी आयेगा। पूरा सदन इस बात पर विचार करे कि झुंझुनूं, सीकर और चूरू, जिसमें नंबर वन पर झुंझुनूं है शहीदों में, शिक्षा में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, चिकित्सा में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है पर पानी में सबसे पीछे वाले लाइन में खड़ा है।

माननीय मंत्री महोदय, 12 हजार करोड़ रुपये के माननीय अशोक जी गहलोत ने टेंडर कर दिये थे। कंपनी को ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद जब आपकी सरकार आई।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): करना पडा आपको।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर के पास ले चलूंगा, बैठ जाओ।

आपको मालूम है 12 हजार करोड़ रुपये का ठंडे बस्ते में डाल रखा है। पहले उन्होंने कहा एक-आध टेंडर भारी हो गया, 40 प्रतिशत अबॅव हो गया, नेगोशिएशन किया, अब 8 प्रतिशत पर रूका हुआ है, अब कितना नीचा और करोगे? अगर आप जितना लंबा खींचोगे, उतनी ही यह योजना महंगी होती चली जायेगी। जब आपकी सी एस ही नहीं मानता है तो किस बात के मंत्री, किस बात के मुख्य मंत्री और किस बात का आपका राज,? ऑर्डर निकालिये, कल

ही मंगाइये फाइल और कहिये कि ऑर्डर निकालें, वर्क ऑर्डर करो, कर दो, तब मैं जानू कि कोई हिम्मत वाला चौधरी है, नहीं तो ऐसे कोई भी बैठा रहेगा। बहुत आये, बहुत चले गये, करोगे हिम्मत? नहीं करोगे, नहीं करोगे। जब सुबह फोटो दिखाई देती है ना सी एस की तो सो जाओगे। मैं कह रहा हूं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, पत्थर के भी हाथ लगाये तो पानी क्या बन नहीं सकता, पर पानी बनाने की हिम्मत ही नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करुंगा हमारे माननीय मंत्री महोदय से कि 12 हजार करोड़ की जो स्कीम ठंडे बस्ते में पड़ी है, उसका वर्क ऑर्डर करवाया जाये। आज तो आप बोलो ही मत आपने कह दिया था।

श्री रामकेश (गंगापुर): कल आपने 5 मिनट खराब कर दिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कह रहा था कि मेरा गृह जिला झुंझुनूं है। उसमें पानी की जितनी कमी है, पिलानी जहां से मैं 3 बार जीता था, अब आदरणीय पितराम जी वहां से जीतकर आये हैं, वहां क्या हालत है? मंत्री जी स्वयं जाकर आये थे और लोगों ने इनसे गुहार भी की थी। दो कर्मचारियों को सस्पैंड भी करके आये। जब किसी भी आदमी का ऊपर से तार नहीं जुड़ता है तो नीचे वाले का तार काट देते हैं। एक तो जे ईएन था गरीब मेघवाल और दूसरा भी मेघवाल था, दोनों को सस्पैंड कर दिया और आज 12 महीने हो गये, वह सस्पैंड पड़े हैं और पानी है नहीं, वह क्या करेंगे? पिलानी में पानी है ही नहीं, सूरजगढ़ में पानी है ही नहीं, बुरी हालत है, पर करें क्या? रोयें तो रोयें कहां, कोई सुनने वाला नहीं है।

आपको मालूम है 244 पंचायत समितियां हैं, जिनमें से 239 तो पानी से ड्राई हो चुकी केवल 39 बची हैं, 205 तो खत्म हो गई। यही हालात रहे और आपने पानी का बहुत मजबूत काम नहीं किया, आपको जल बोर्ड बनाकर, मिनी सचिवालय बनाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

आप तो उस जगह से आती हो जहां सुबह उठते हो तो गंगा बहती है। मालपुरा वाले हमारे मंत्री जी उठते हैं तो गंगा सामने से बह रही है, लेकिन जहां से मैं आता हूं वहां तो केवल टीले ही टीले दिखाई देते हैं, जाऊं तो जाऊं कहां। लोग कहते हैं कि पानी लेकर आओ, हां भरकर गये थे, माननीय मंत्री जी, मैं ईमानदारी से सदन में खड़ा होकर कह रहा हूं कि अगर आपने पानी नहीं दिया तो श्रवण कुमार जनता के लिए शहीद हो जायेगा, विधान सभा में नहीं आयेगा। मुझे जनता ने 44 साल तक मेंडेट दिया है, मैं क्या जवाब दूंगा उनको, उन्होंने बड़े प्यार से जीरो से हीरो बनाया है। अगर पानी नहीं पिला सकता तो ऐसी राजनीति करने से क्या फायदा है? हम कोई लकीर के फकीर हैं क्या?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): मूर्ति लगवा देंगे आपकी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको मालूम है बुजुर्गों ने जो सरोवर, बावड़ी, तालाब, छोटे-छोटे खेतों के पास जोहड़ चालू किये थे, बरसात का पानी पीते थे, वह सारे के सारे स्रोत तो डुबो दिये। नई-नई बातें करके सारे सिस्टम को खराब कर दिया।

सभापति महोदय, यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम को खराब किसने किया?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कांग्रेस ने।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह इसलिए हुआ कि राज्य में पानी की कमी को दूर करना है तो सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि निम्न उपाय अपनाकर राजस्थान की पेयजल समस्या का समाधान कर सकते हैं:-

एक तो वर्षा जल संचयन, वर्षा का पानी इकट्ठा करिये। व्यर्थ मत जाने दो। बुड़ानिया जी कह रहे थे कि सारा बरसात का पानी समुद्रों में जा रहा है। समुद्र में जाते ही खारा हो जाता है। क्या काम आता है? हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सोच था कि नदियों को जोड़कर पानी पिलायें। वह चले गये, आशीर्वाद छोड़कर गये थे, आपने लागू नहीं किया।

spp/rtm/05.03.2025/14.20/2e

आप उनको लागू करिये कि नदियों को जोड़कर पानी पिलायें और सिंचाई के भाग को बढ़ायें। दूसरा, जल का पुन:चक्रण कर पुन: उपयोग में लेना चाहिये। हमारा जो वेस्ट पानी है उसकी रिसाइक्लिंग करके उसके बाद कुल्ला-दांतुन करने के लिये दूसरा पानी भेजिये और पीने का पानी अलग होना चाहिये। मीठे पानी से ही हम कुल्ला-दांतुन करते हैं और उसी से फर्श साफ करते हैं और उसी पानी से हम बर्तन साफ करते हैं और वही पानी हम पी रहे हैं। इसमें आपको दो नीति बनानी पड़ेगी। पानी का संचयन करके रिसाइक्लिंग करके उसकी मशीनें लगाकर पानी का बचाव करना पड़ेगा।

जल प्रबन्धन की ठोस नीतियां बनानी पड़ेगी। जल प्रबन्धन की कोई ठोस नीतियां आज तक सरकार ने नहीं बनायी है। केवल बात करते हैं। पांच साल के बाद कुर्सी बदल जाती है, पर विचार नहीं बदलते हैं। इसलिये आपको ठोस कदम उठाकर जल के अनुरूप खेती करनी चाहिये। उद्योगों में जल का सही इस्तेमाल हो। नदियों का संरक्षण करना चाहिये। जलापूर्ति के नेटवर्क का विस्तार करे। जल संचयन, बांध, तालाब, एनीकट्स का निर्माण करना चाहिये। जल संसाधन की पारम्परिक विधियों का संरक्षण, वनों का संरक्षण, गांवों की मिट्टी को जोड़कर एनीकटों का निर्माण और राजनीतिक सुधार। पानी पर राजनीति मत करो। पानी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिये। कोई भी सरकार आये उसका एक ही मानस होना चाहिये कि जनता को पानी पिलाना है। और बहुत सारी बातें हैं, उन पर राजनीति करो न, पर पानी पर मत करो। हम लोग पानी पर राजनीति करते हैं यह बहुत बुरी बात है।

उद्योग नीति बनायी जानी चाहिये। आधुनिक तकनीक से खेती की जाये। आज भी धोरों से खेती कर रहे हैं। फव्वारे और ड्रिप सिस्टम काम में लेना चाहिये ताकि पानी कम यूज होगा। आज भी धोरों से पानी चला रहे हैं। इसका यूज करने का तरीका बदलना पड़ेगा और प्रत्येक आदमी को यह सोचना चाहिये। मंत्रीजी, आप तो मंत्री हो ही, बुडानियां जी ने एक बात और कही थी कि आप एक सुदृढ़ कमेटी बनाकर, अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे इसमें कोई छोटा नहीं बनता है, दस अच्छे अधिकारी छांटकर कमेटी

बना दो। दो चार आदमी हममें से विधान सभा के ले लो। पानी की जो सुचारू रूप से कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सकता है, वह कार्यवाही करवाओ जिससे-

'मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है
हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है।
डरने वालों को कुछ नहीं मिलता
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।।

भाग मत जाना, पानी पिलाना है। कन्हैयालाल जी, कन्हैया का नाम बहुत बड़ा था। कृष्ण कन्हैया हो। पानी के लिये कन्हैया बन जाओ और पानी कन्हैया बन जाओगे तो लोग याद करेंगे। मंत्री कोई रहे या न रहे, कितने लोग तो मेरे देखते देखते 40 साल में कितने आये, कितने चले गये, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अगला कदम रखकर उसको पानी पिलाया हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह कविताएं स्वरचित हैं या कहीं से ली गयी हैं? अच्छी कविताएं हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कौनसी?

श्री सभापति: यह कविताएं स्वरचित हैं या कहीं से ली हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं, साहब, स्वरचित हैं।

श्री सभापति: खुद बनाते हो?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): और बना दूं, आप कहो तो आपकी बना दूं।

'आप तो कुछ भी मत करो,
बेहतर से बेहतर की तलाश करो।
मिल जाये नदी तो समुद्र की तलाश करो।
टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से,
टूट जाये पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो।।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आप तो बीजेपी में आ जाओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो बीजेपी में आ रहे हैं वो तो रोवण लाग रह्या हैं। बीजेपी में आ रहे हैं वो ही रो रहे हैं। हम क्या करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, गांवों के लिये जल जीवन मिशन बनाया। जल जीवन मिशन की योजना बनाने वाले केवल होटलों में बैठकर आनन-फानन में और कोई इसका आइडिया नहीं लिया तो यह योजना सफल कैसे होगी? बड़े-बड़े आई ए एस अधिकारी लोग और इंजीनियर्स होटलों में बैठ गये, लेकिन उनका प्लान केवल पांच साल का प्लान था। आपको मालूम है मंत्रीजी, पांच साल का प्लान इतना बड़ा हिन्दुस्तान में लागू नहीं हो सकता। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग भू-भाग है। अपने राजस्थान में बहुत सारा इलाका है जो ड्राई है। एक साथ लागू कर दिया और एक ही ठेकेदार को काम दे दिया। ठेकेदार का नाम है पदमचन्द जैन, जिसके लिये मंत्रीजी को मालूम होना चाहिये था, इंजीनियरों को मालूम होना

चाहिये था। यह सारी फाइल इंजीनियर से एफ.ए. के पास जाती है, एफ.ए. से मंत्री के पास जाती है और मंत्री ने केवल आनन-फानन में उसको काम दे दिया, जिसने कभी काम किया ही नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार बनाकर उसको काम दे दिया। उसने छोटे-छोटे टुकड़ों में दे दिया दूसरे को, इतना भारी एजेंडा तैयार किया कि नीचे वाले धाप गये, मंत्री भी धाप गये, संतरी भी धाप गये और फिर भी लास्ट में जेल के शिंकजे खोलने पड़े। ऐसे काम क्यों करते हैं? जब जनता का पैसा था, जनता में लागू करते। दुनिया में जाकर जनता आवाज उठाती है पानी के लिये, वहां पानी का सारा एजेंडा ठण्डे बस्ते में चला गया। वह पदम भी पागल हो गया। माननीय सभापति महोदय, पदम भी पागल हो गया। उसके सारे पैसे ले लिये, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज वह पदम हमारी राजस्थान की और पूरे हिन्दुस्तान के जल जीवन मिशन को फेल करके चला गया।

माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि कोई भी आदमी दोषी होगा तो वह बच नहीं पायेगा। मैंने उस पूरे दिन कुर्ते के बटन बंद ही नहीं किये कि कोई एक जाट तो आये जो बच नहीं पायेगा। 15 दिन बाद कौनसा टेलीफोन आया, कहां से आया। बटन मैंने भी बंद कर लिये, इन्होंने भी बंद कर लिये। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। कहां गये वो कैदी, कहां गये वो अपराधी? जो पहले-पहले पकड़े थे, वह चले गये और सारे ठंडे बस्ते में कागज डाल दिये। आप पकड़ो न उनको, कोई हिम्मत करो न। जो हिम्मत करेगा वो ही तो बादशाह कहलायेगा। सारे का सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। भगवान ने आपको मौका दिया है, बहुत कम मौका मिलता है। अब मौका दे ही दिया और जन्म ले ही लिया और काम करने की सोच ही ली और जलेबी की तरह घूम ही गये तो रस में डूबकर मजा लो। मतलब काम करके दिखाओ। रस में डूबने का मजा यह नहीं है कि आप उससे पैसे कमा लो। यह कह रहा हूं मैं।

श्री सभापति: अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अपने हिन्दुस्तान में, हमारे राजस्थान की और हिन्दुस्तान में पानी की अलग अलग मात्रा में बरसात होती है। अरूणाचल प्रदेश है, मेघालय है, कश्मीर है, उधर पानी खूब बरसता है इसलिये वहां पानी की दिक्कत नहीं आती है। अब उनकी तर्ज पर हम जल जीवन मिशन चालू करें या कुछ भी करें तो हमारे यहां वह सूट नहीं करता है। इसलिये मैं कहूंगा कि राज्यों की तुलना आपस में नहीं करके और उनके अलग अलग क्षेत्रों का ब्यौरा लेकर इस मिशन को चालू करना चाहिये था। अगर आप चालू करते तो तीन-चार में ..(व्यवधान)..

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

प्लीज, आप देखो उस दिन पांच मिनट खा गये थे मेरी।

श्री सभापति: आप एक मिनट में शीघ्र समाप्त करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अभी कर देता हूं। दो-तीन पन्ने और हैं।

श्री सभापति: दो-तीन पन्ने नहीं, जल्दी करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है इसलिये सारा सिस्टम खराब हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि मॉनिटरिंग के लिये अगर आपने किसी व्यक्ति को डेप्यूट कर दिया, चीफ इंजीनियर को आप ड्यूटी दे दो कि यह काम आप करोगे, वह अपने जे.ईएन., एक्स.ईएन. को किसी को भी देगा तो वह करेगा। जब तक लायबिलिटी तय नहीं होगी तब तक कोई आदमी जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा। जो लायबिलिटी दे देंगे उसको इस बात का भय रहेगा कि मेरा मंत्री मुझे चार्जशीट दे देगा, मेरा चीफ इंजीनियर मुझे चार्जशीट दे देगा और उस पर एक्शन भी होगा। तब तक यह पानी की जो दयनीय स्थिति है, यह ठीक नहीं हो सकती है। आप नोट कर लीजिये, मंत्रीजी, लायबिलिटी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है और लायबिलिटी नहीं दी है तो कोई जिम्मेदार नहीं बनेगा। वह दूसरे पर सरका देगा, वह आगे सरका देगा।

श्री सभापति: बिराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं-नहीं अभी नहीं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा ..(व्यवधान).. मंजिलों के आगे मंजिलें और भी हैं। प्लीज दो मिनट माननीय सभापति महोदय, आपको निवेदन करूंगा तीन मिनट दे दो।

श्री सभापति: नहीं, नहीं इतना समय नहीं है। आप 10 सैकण्ड में अपनी बात समाप्त करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 10 सैकण्ड में तो मेरे से बोला ही नहीं जायेगा। मैं घबरा और जाऊंगा।

श्री सभापति: बिराजो फिर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं ऐसे ही बूढ़ा आदमी हूं घबरा जाऊंगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा -

'मंजिलों के आगे मंजिलें और भी हैं,
यह दौर नहीं आखिरी दौर और भी है।
मत जाना जीतकर फूल और हारों के कांटों में
आपके वास्ते जिंदगी के रास्ते और भी हैं।

jyg/rtm/05.03.25/14.30/2f

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान। माननीय सदस्य, आपको धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुझाव, सुझाव।

श्री सभापति: टेबल कर दो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, जनसंख्या के अनुसार प्लान बनाना चाहिए। निविदाएं छोटी-छोटी निकालनी चाहिए थी। बड़ी निविदाएं निकाल दी, इससे पूरा राजस्थान घोच-पोच हो गया। बड़े ठेकेदार ने छोटे ठेकेदार को काम दे दिया और वो काम कर नहीं पाया। इसलिए छोटी-छोटी निविदाएं लगाकर आप काम कराते तो आज जल

जीवन मिशन का कार्य पूरा हो जाता।

श्री सभापति: आप मंत्री महोदय से मिल लेना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मिल लूंगा लेकिन...

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आमजन को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा जल जीवन मिशन योजना प्रारम्भ की गयी, ताकि देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंच सके, लेकिन हमारे राजस्थान प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता के कारण इस योजना को गति नहीं मिल सकी और लाखों घरों में आज भी इस योजना से पानी मिलने का इंतजार है। जहां काम हुआ वहां पाइप लाइनें बिछायी जाने के नाम पर गांव की सी सी सड़कें तोड़ दी गयीं, लेकिन आज तक वो ठीक नहीं करायी गयी, इस कारण ग्रामीणजनों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर संवेदकों द्वारा नल कनेक्शन का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। अनेक स्थानों पर मुख्य पाइप लाइनों को उच्च जलाशय से नहीं जोड़ा गया। पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी ग्रामीण जनों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और माननीय मुख्य मंत्रीजी, भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर अग्रसर होने लगा। जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना को 2028 तक बढ़ाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी एवं माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में आदरणीय दिया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में 20 लाख घरों में नये पेयजल कनेक्शन दिये जाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराये जाने का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु मुख्य मंत्री जल जीवन मिशन योजना प्रारम्भ करने की इस बजट में घोषणा की गयी। इस घोषणा में अमृत 2.0 योजना के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में सोजत रोड और नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल समस्या निस्तारण हेतु 2.8 एमएलडी का जल संशोधन संयत्र, स्वच्छ जलाशय एवं राइजिंग पाइप लाइन का निर्माण कर कंटालिया बांध से सोजत रोड पेयजल आपूर्ति हेतु 15 करोड़ 76 लाख रुपये के कार्य करने की घोषणा की गयी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं उप मुख्य मंत्रीजी एवं जलदाय मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि इसी तरह सोजत सिटी नगरपालिका क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपयों के कार्य कराने का भी प्रस्ताव है।

माननीय सभापति महोदय, जल ही जीवन की मूल आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में रायपुर के 189 गांवों को लूणी बांध से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। सोजत तहसील के देवली हूला एवं चण्डावल नगर स्थित वाटर प्लांट से सोजत तहसील की गुढा बछराज, केलवाद, पीपलाद, देवली हूला, बगड़ी नगर, पाचूंदा कलां, साण्डिया, रूपनगर, कर्मावास पट्टा, चण्डावल स्टेशन, चण्डावल नगर बासना, छितरिया, रूंदिया, अटपड़ा सहित 18 गांवों और ढाणियों में पानी की सप्लाई गजनेर बांध से की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र की 10 से अधिक ग्राम पंचायतों का स्थानीय भू-गर्भीय जल पेयजल योग्य नहीं है। बोरवेल या हैण्डपम्प खोदे जाने पर पानी अत्यधिक फ्लोराइडयुक्त और खारा मिलता है। 10 ग्राम पंचायतें, राजोला कलां, चौपड़ा, झूंपेलाव, रूपवास, चाड़वास, मेव और सरदार समंद, सूपड़ा एवं खारिया नींव के 34 गांवों में पेयजल योजना हेतु दातीवाड़ा योजना से जोड़ा गया है। लेकिन विगत एक माह से इन ग्राम पंचायतों हेतु पेयजल सप्लाई नहीं किया जा रहा है। इस कारण क्षेत्र में पेयजल की किल्लत बढ़ती जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय जलदाय मंत्रीजी, आदरणीय कन्हैया लाल जी चौधरी साहब का कि इस समस्या को मैंने आपको अवगत करवाया। मंत्रीजी ने तुरंत प्रभाव से सम्बन्धित अधिकारी से बात कर इस क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने बाबत निर्देशित किया।

माननीय सभापति महोदय, आगामी गर्मी का समय निकल जाने पर इस योजना का पानी सोजत शहर को मिलने वाला था, लेकिन मंत्रीजी द्वारा राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल थर्ड फेज का कार्य पूरा होने तक सप्ताह में एक बार पेयजल सप्लाई प्रारम्भ करने हेतु सख्ती से निर्देशित किया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र की शेष ग्राम पंचायतों को जवाई पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस और अकाल का संयोग रहता है, लेकिन राजस्थान में भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही सम्पूर्ण राजस्थान सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। क्षेत्र के सभी तालाब और बांध लबालब भरे हुए हैं। क्षेत्रवासियों को सिंचाई के साथ आगामी बारह महीनों तक पेयजल हेतु पर्याप्त पानी भी मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि सोजत उप खण्ड के यूडब्ल्यूएसएस सोजत सिटी के फिल्टर प्लांट के लिए इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन से मौजूद पाइप लाइन तक, मुख्य पाइप लाइन बढ़ाने और सोजत सिटी के अन्दर व सोजत शहर में शहरी जल आपूर्ति योजना के लिए मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन हेतु विभाग को भिजवायी गयी 2 करोड़ रुपये की राशि की कार्य योजना के प्रस्ताव स्वीकृत करायें ताकि शहर को पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे।

माननीय सभापति महोदय, रायपुर ग्राम पंचायत है, लेकिन यहां सहायक अभियंता कार्यालय शहरी क्षेत्र में दर्ज है। ग्राम पंचायत होने के कारण इस गांव में न तो जल जीवन मिशन योजना का लाभ मिल सका और न कार्यालय शहर क्षेत्र में दर्ज होने से अमृत 2.0 का

लाभ मिल पाया। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि रायपुर में नये पम्प हाउस की स्थापना, अधिक पेयजल क्षमता, ईएसआर और सीडब्ल्यूआर के लिए प्रावधान, नये ओपन वेल का निर्माण कार्य, नई पाइप लाइन बिछाने, उच्च जलाशय बनाने हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित बजट आवंटन कराने की अनुकम्पा करावें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 25 गांव सहित पाली जिले के 99 गांवों में उच्च जलाशय, टंकी निर्माण हेतु लगभग दो वर्ष पूर्व टेंडर किये गये थे, दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी आज तक ये कार्य नहीं हो पाया है। सोजत क्षेत्र में 25 गांवों में बनने वाली टंकियों में मात्र कुछ ही स्थानों पर यह कार्य किया जा रहा है। कई स्थानों पर बड़े-बड़े खड्डे खोदकर खुले छोड़ दिये गये हैं। जहां आये दिन बेसहारा पशु गिरकर हादसे के शिकार हो जाते हैं। टंकी निर्माण नहीं होने से ग्रामीण जनों में पेयजल की काफी परेशानी हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे ठेकेदार को हटाकर शीघ्र ही नये टेंडर करवाकर कार्य प्रारम्भ किये जायें ताकि आम जन को पेयजल की समस्या से राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से हमारी सरकार जल पर काम करने जा रही है, चाहे वो ईआरसीपी हो चाहे यमुना जल समझौता हो, मैं चार लाइन कहकर मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगी,

नवीन लहरों के बीच माधव कीर्ति गाथा गा रहे हैं हम,
राजस्थान की धरा पर अमृत ला रहे हैं हम,
समृद्धि का पथ प्रशस्त करते जा रहे हैं हम,

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामकेश।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 41 और 42 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभारी हूं।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, पानी की जो समस्या है, पानी पर जो चर्चा है, मैं समझता हूं कि जितनी भी अनुदान की मांगें हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आज हो रही है। इस चर्चा का कोई सार्थक परिणाम निकलेगा ऐसी मुझे आशा है। हम लगातार कहते हैं कि जल ही जीवन है। पानी बचाओ, ये नारे दीवारों तक पर लिखे हुए हैं। बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, जिस तरीके के नारे ये दीवारों पर लिखे हुए हैं उसी तरीके से यह जो नारा है पानी बचाओ का, उसको हम लोगों ने बहुत हल्के में लिया और पानी का जिस तरीके से दोहन हो रहा है, पानी का उपयोग बढ़ रहा है, उसके अनुपात में हम लोगों ने जल का संरक्षण करना था वो जल का संरक्षण नहीं हुआ, नतीजा यह हुआ कि पूरे राजस्थान में पानी की किल्लत है, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, शुक्रिया ईश्वर का कि इस बार बरसात ठीक हो गयी, नहीं तो

राजस्थान में बहुत ज्यादा बिगड़ जाते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज के इस अनुदान मांग की चर्चा के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा, माननीय हमारे जल संसाधन मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को जल का संरक्षण करना चाहिए था, जो हमारे सोर्स थे उन सोर्सों को हमने किस तरह से डेस्ट्रॉय किया।

MLS/RTM/05.03.2025/14:40/2g

कहां उनमें हमारी कमी रही, किस तरीके से वे क्षतिग्रस्त हुए, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे सामने बिलकुल स्पष्ट उदाहरण है। रामगढ़ बांध में एशियाड गेम्स की नौकायन प्रतियोगिता हुई थी और उस रामगढ़ बांध से आधा जयपुर पानी पीता था। आज स्थिति यह है कि एक बून्द भी रामगढ़ में नहीं है। जो कैचमेंट एरिया था, उसमें जमीन अलॉट हो गयी। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमारे परम्परागत स्रोत खत्म होते चले गये और पानी की किल्लत बढ़ती गयी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के पास खेती योग्य भूमि केवल 13.68 परसेंट है और जनसंख्या 6 परसेंट। पशु धन भी 11 प्रतिशत है और हमारे पास सरफेस वॉटर केवल 1.16 प्रतिशत है। ग्राउंड वॉटर में हमारी स्थिति बहुत कमजोर है 1.70 प्रतिशत और टोटल अगर हम आकलन करें तो 10 परसेंट भूमि और 1 प्रतिशत पानी। ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा कि पानी का संरक्षण किस तरह किया जाये। अगर हमने अभी नहीं सोचा तो हमें पछताना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा बढ़कर अगर कोई बात की जाये तो लगातार दम तोड़ती हुई हमारी पेयजल की योजनाएं हैं।

पेयजल की योजनाएं जो हमने बनाईं, हमने शुरुआत कुओं से की। कुओं पर हमने डोरी डालकर पानी निकालने का काम किया। हैंडपम्प लगाये और उसके बाद में वहां पर प्लांट लगाये, अरबों खर्च होते चले गये और सारी व्यवस्थाएं समय के साथ दम तोड़ती चली गईं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 302 ब्लॉक्स में से 214 ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, 27 क्रिटिकल और 21 सेमी क्रिटिकल हैं। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि भू-जल के मामले में राजस्थान की स्थिति बहुत कमजोर है।

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमने प्रयास भी किये। 2010 में राजस्थान सरकार वॉटर पॉलिसी लेकर आयी, लेकिन उसका क्या हाल हुआ? वॉटर रिसोर्स विजन 2045 का दिया और हमारी जो पूर्व मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा जी राजे, उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन कार्यक्रम राजस्थान में लागू किया कि जिस तरीके से फोर वॉटर्स कॉन्सेप्ट लेकर के वे आईं और जिस आधार पर ये योजनाएं बनीं, डिजाइन की गईं, खसरा नम्बर कहीं का और भुगतान कहीं का हो गया। आज मैं माननीय मंत्री महोदय, आपको कहना चाहता हूं, 2017 के बाद में एक भी स्ट्रक्चर आप बता दीजिये, अरबों रुपया खर्च हुआ राजस्थान सरकार का, एक भी स्ट्रक्चर आप बताएं, आप खुद जाकर देखिये, एक भी स्ट्रक्चर आज की

तारीख में जिन्दा नहीं है।

इस तरीके की हमारी जो योजनाएं बन रही हैं, बिना सोचे-समझे योजनाएं बन रही हैं, पैसा बरबाद हो रहा है, उसका फायदा राजस्थान की जनता को नहीं मिल रहा है। अगर हमने पानी के संरक्षण में इसी तरीके से चूक की तो भारी संकट हमारे सामने आने वाला है। माननीय सभापति महोदय, इंटर-स्टेट एग्रीमेंट जो हमने किये, गंग कैनाल का किया, भाखड़ा का किया, रावी और यमुना का किया, लेकिन प्रभावी कार्यवाही हम उसमें भी नहीं कर पा रहे हैं।

यमुना जल आवंटन समझौता, 25 साल बाद भी ताजेवाला हेड से खुद के हिस्से का पानी हम नहीं ले पा रहे हैं और नाथूराम जी मिर्धा साहब के समय नर्मदा के पानी का जो समझौता हुआ, उसके अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में जो पानी पहुंच जाये, उसके बाद में माही और ब्यास का पानी सिरोही, जालोर और बाड़मेर को मिलेगा। आज तक उसमें कोई प्रयास नहीं हुआ। हम वहीं के वहीं खड़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कावेरी जल विवाद के समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ था कि देश की सारी नदियां राष्ट्रीय सम्पदा हैं और उसके अनुसार जो नदी जल समझौते हैं, उनमें जो राज्य जितनी तरफदारी करेगा, जितनी पैरवी करेगा, उसको उतना फायदा मिलेगा। राजस्थान इस स्तर पर भी पिछड़ गया, जिसके कारण इंडस बेसिन में ट्रीटी हुई, वह प्रदेश अगर कोई था तो वह राजस्थान था, जिसके कारण हमको सतलुज, रावी और ब्यास नदी का पानी मिला। हम लोगों को हमारे हितों की पैरवी करनी चाहिये थी। वह पैरवी हम नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, ईआरसीपी का ही मुद्दा देख लीजिये, बहुत पहले से सुन रहे हैं ईआरसीपी की बात। ईआरसीपी के लिए माननीया वसुन्धरा जी ने सबसे पहले प्रयास किया, 2005 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री बाबूलाल जी गौर साहब के साथ में समझौता किया था। उस समझौते की पालना नहीं हो पायी, समझौता आगे नहीं बढ़ पाया। 2017 में पुनः उन्हें मौका मिला। 2017 में वापकोस कम्पनी के माध्यम से डीपीआर बनवायी थी और उस डीपीआर के आधार पर समझौता किया था। उस समझौते को हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने आगे बढ़ाने की बात की थी। उस समझौते के तहत राजस्थान को करीब 4 हजार एमसीएम पानी मिलना था। वह 4 हजार एमसीएम पानी जो मिलने की बात थी, वह डीपीआर के आधार पर थी। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनायी, वह तकनीकी विशेषज्ञों ने बनायी। उसके आधार पर राजस्थान को पानी मिलता।

अब जब ईआरसीपी की बात चली, सरकार बदलते ही हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने मध्य प्रदेश के साथ में, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ में एक नया समझौता किया है और उस समझौते की डिटेल अगर आपको बताऊं तो यह 2022 में जो समझौता हुआ, उसमें केन्द्र सरकार के हमारे जो तत्कालीन मंत्री गजेन्द्र सिंह जी के साथ में 1775 एमसीएम पानी ''available at 75 per cent dependability'', तो 75 परसेंट

डिपेंडेबिलिटी पर अगर हम लोग यह समझौता करते हैं तो केवल 1775 एमसीएम पानी मिलता है। अब मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट किया है, नया एग्रीमेंट किया है और उसके आधार पर करीब 4 हजार एमसीएम पानी मिलेगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं।

हम लोगों ने पिछले सत्र में यह मांग की थी कि आपने जो समझौता किया है, जो एमओयू किया है, उसकी कॉपी आप सदन में रखें, लेकिन एमओयू की कॉपी आज तक नहीं दी। एमओए जो किया है, उस एग्रीमेंट की कॉपी भी आप लोग नहीं बता रहे हैं। आप 4 हजार बता दीजिये, 4,500 बता दीजिये, हमारे पास जब तक यह रिकॉर्ड नहीं आयेगा, राजस्थान की जनता भरोसा नहीं कर सकती। हम तो यह चाहते हैं कि जो वसुन्धरा जी की डीपीआर थी, उस डीपीआर से ज्यादा अगर राजस्थान में आप पानी लाते हैं, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर आप उस डीपीआर से कम पानी लेकर आये तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी।

इसी के साथ, मेरा दूसरा निवेदन यह है, हमारे माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब बैठे हुए हैं। उनके सामने मैंने रखा था कि चम्बल, गंगापुर, नादौती पेयजल योजना, जो एक महत्वपूर्ण पेयजल योजना थी, आप ही के समय 2005 में वह स्टार्ट हुई और एसपीएमएल कम्पनी को उसका ठेका दिया था। 148 एमएलडी पानी का प्रोडक्शन करके गंगापुर, सवाई माधोपुर और नादौती के क्षेत्र को पानी मिलना था।

मुझे आज इस बात का दुःख है कि 2005 की स्कीम 2025 में भी पूरी नहीं हुई। बार-बार विधान सभा में प्रश्न लगाने के बाद में, बार-बार आपके सामने अनुरोध करने के बाद में, आपकी कार्यवाही के बाद में भी एक ऐसी कम्पनी, जिसने कांग्रेस सरकार के रहते हुए और बीजेपी की सरकार के रहते हुए, यह सबको धोखा देकर, चकमा देकर हमारे गंगापुर, सवाई माधोपुर और नादौती के लोगों को धोखा देने का काम किया है।

MKD/RTM/05.03.2025/14:50/2h

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसी कम्पनी के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। आपने मुझे आश्वस्त किया था कि इसमें एक महीने के अन्दर-अन्दर हम कार्यवाही करेंगे। आज एक महीना छोड़कर आठ महीने निकल गये, माननीय मंत्री जी। उसमें कार्यवाही नहीं हुई। गंगापुर को केवल 3 एमएलडी पानी मिल रहा है।

उसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा पांचना बांध है। माननीय सभापति महोदय, पांचना बांध 2150 एमसीएफटी का है। पूर्वी राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, लेकिन आपकी ही सरकार में, तत्कालीन वसुन्धरा जी की सरकार 2006 में, आपने इस तरह का उसमें ताला लगाया है, लगातार बांध भरा हुआ है और 40 हजार बीघा के जो किसान हैं, वे किसान लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उस बांध का ताला नहीं खुल रहा है। क्या वजह है कि बांध की तरफ आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

जो कमांड एरिया है, कमांड एरिया के किसान द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी उनको

पानी नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में लगाया, हाई कोर्ट में लगाया, उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। हाई कोर्ट से भी आपको निर्देश हैं, माननीय मंत्री महोदय।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पांचना बांध, ये जो झगड़े की जड़ आपने खड़ी की है, तत्कालीन भाजपा सरकार ने की है, उस समय जो मुख्य मंत्री जी थी वसुन्धरा जी, उन्होंने की है। यह किस तरह का ताला लगाया है। इस ताले की चाबी मिल नहीं रही है। इस ताले की चाबी ढूंढो और पांचना बांध को जल्दी से जल्दी खुलवाओ।

अगर पांचना बांध नहीं खुला तो वहां की जनता, वहां का किसान, जो बर्बाद हो गया है। अपनी फसल की, अपनी खेती की, अपनी जमीन के मुआवजे के लिए हाई कोर्ट में जा रहा है, अनुरोध कर रहा है और आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए, आपको पांचना का पेंच सुलझाना चाहिए।

अगर पांचना पेंच आपने सुलझाया तो निश्चित रूप से वहां की जनता को 40 हजार बीघा में जो पानी आना था, वह पानी आएगा। पूर्वी राजस्थान में यह पानी वहां किसानों को बहुत मदद करेगा। हमारे पीने के लिए और सिंचाई के लिए ईआरसीपी का जो मुद्दा है। उस ईआरसीपी के मुद्दे पर हम पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को वहां की परिस्थिति, वहां की भौगोलिक स्थिति अच्छी तरह से पता है।

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामकेश (गंगापुर): वहां राजस्थान में विशेष रूप से गंगापुर, सवाई माधोपुर में उनके लगातार दौरे होते थे। उनको अच्छी तरह पता है कि उस क्षेत्र में पानी की जबरदस्त कमी है। वह कमी ईआरसीपी के माध्यम से पूरी होगी। हमारे किसानों को पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा। मैं यही आपसे अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। नमस्कार।

श्री सभापतिः श्री ललित मीणा जी।

श्री ललित मीना (किशनगंज): सभापति महोदय, आप आपने मुझे मांग संख्या 41 - पेयजल और मांग संख्या 42 - जल संसाधन पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

मैं आपके माध्यम से सबसे पहले इस देश के प्रधान मंत्री और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारी बहुत अपेक्षित और पुरानी परियोजना ईआरसीपी, जिसकी आधारशिला इस राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने रखी, उसका शिलान्यास 17 दिसम्बर को हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जयपुर आकर किया और करने के साथ-साथ उसको धरातल पर उतारने का काम हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने किया।

वहां जिन दो डैमों की आधारशिला प्रधान मंत्री जी ने रखी। उन्होंने रामगढ़ और महलपुर बैराज, दोनों किशनगंज की हमारी पार्वती, परवन व कालीसिंध की नदियों पर रखने का काम

किया। उनके बनने से इस हाड़ौती के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान, आने वाले समय में जिस प्रकार इंदिरा गांधी कैनाल वर्षों पहले बनी, आज ईआरसीपी के माध्यम से पूर्वी राजस्थान संतृप्त होगा।

इसके साथ-साथ यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में ईआरसीपी का जो डैम बन रहा है, उसको जोड़ने के लिए, पेयजल और सिंचाई के लिए 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट देकर सर्वे के लिए पैसा दिया। मेरे केलवारिया, समरानिया, जहां पेयजल की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वह बहुत पिछड़ा हुआ और आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है। पेयजल की अभी से बड़ी समस्या आ रही है। कृषि कार्य के लिए चार-चार सौ, पांच-पांच सौ फीट नीचे तक पानी चला गया है। हमारे किसान भाई आज भी बांट जोह रहे हैं। सरकारें आईं और गईं, लेकिन उस हाड़ौती की धरा पर हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने और भगीरथ के रूप में हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने 250 करोड़ रुपये देकर सर्वे के लिए डीपीआर बनाने के लिए, मेरे विधान सभा क्षेत्र को सिंचित करने के लिए जो पैसा दिया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

मैं यह चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो मध्यम सिंचाई परियोजना है। मेरी बिलासी मध्यम सिंचाई परियोजना, मेरी रातई सिंचाई परियोजना, मेरी खटका सिंचाई परियोजना, हमारा सैमली फाटक, नारायण खेड़ा सिंचाई परियोजना, जो छोटे-छोटे तालाब हैं, सिंचाई के लिए उसको ईआरसीपी से जोड़ा जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आवाज न करो तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि जो बोलता है, वह डिस्टर्ब होता है। बात करो, मगर (..व्यवधान..)।

श्री ललित मीना (किशनगंज): ताकि आने वाले समय में किसान को उस क्षेत्र में पानी मिले, पेयजल की व्यवस्था हो सके। इससे केलवाड़ा, समरानिया की 7 हजार हैक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी। इसे साथ-साथ मुख्य मंत्री जी ने, हमारे विपक्ष के सभी भाई, सब लोग यह कहते हैं कि आप एमओयू बता दो। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम है। आप ऑनलाइन जाकर देखेंगे तो ईआरसीपी का एमओयू भी आपको उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा।

हमारे मुख्य मंत्री जी, हमारे प्रधान मंत्री जी जो कहते हैं, वह करते हैं। शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन भी करेंगे। सभापतिमहोदय, मैं इस सदन के माध्यम से हमारे ईआरसीपी में, इस बजट में और पिछले बजट में मुझे जो 410 करोड़ रुपये दिये हैं, केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए, कुनू नदी पर छोटे-छोटे एनिकट बनाने के लिए स्प्रिंकलर से, उसके लिए धन्यवाद दूंगा।

इसके साथ-साथ पुराणी, होरडापुरा, काकड़दा में नवीन एनिकट के लिए विशेष बजट इस बजट में दिया है। इसके साथ-साथ ईआरसीपी में 9 हजार 416 करोड़ के कार्यादेश जारी हो चुके हैं, धरातल पर लाने का काम हमारी वर्तमान सरकार, हमारे भजन लाल जी कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ 12 हजार 64 करोड़ रुपये की निविदाएं जारी कर दीं। मौके पर, धरातल पर जहां रामगढ़ और महलपुर बैराज बनेगा, उसका कार्यादेश जारी होकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में काम चालू हो गया है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हाड़ौती की, ये तीन बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी नदियां हैं, कालीसिंध, परवन और हमारी पार्वती। इनके माध्यम से आने वाले समय में इन 13 जिलों को, इंन्दिरा गांधी कैनाल की तरह, इस क्षेत्र के आम किसानों को पानी मिलेगा। इसके साथ-साथ, कुजाए, सैमरा, भवनगवा, जो हमारे एनिकट हैं, पूर्ववर्ती सरकार के समय, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने उस तलहटी क्षेत्र, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पथरीला है, आज भी कुओं से मोटर डालकर पानी पिलाने का काम किसान करते हैं। सिंचाई के लिए ईआरसीपी मील का पत्थर साबित होगा, उसमें मुझे बजट दिया है। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी को, मुख्य मंत्री जी को, सिंचाई मंत्री जी को जितना भी धन्यवाद दूं, वह कम है।

इसके साथ-साथ मेरे तिलगवा, मानपुर कस्बा, नूदेड़ा, संदोकड़ा, ढूडावर, भोयल के आसपास के गांवों में पेयजल की बड़ी समस्या आती थी। वहां पर पहले जो एनिकट बने, उनको ऊंचा करने का काम इस बजट में दिया। इसके साथ-साथ देवरी का झीरना तालाब, जिसकी वर्षों से मांग थी, उसको 25 करोड़ देकर, अभी निविदा जारी हो गई, टेंडर लग गये हैं। इसके लिए मैं हमारे मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा। इसके साथ-साथ 450 करोड़ रुपये, जो पिछले 15 महीनों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में धरातल पर दिये, आज उसका काम नीचे देखने को मिल रहा है। नाहरगढ़ में 50 लाख रुपये स्टॉक डैम बनाने के लिए दिये। नैपकॉन कम्पनी को कार्य आदेश जारी हो गया है। वर्तमान में नाहरगढ़ में सर्वे चल रहा है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा।

इसके साथ-साथ मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हाड़ौती की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना अकावत-परवन सिंचाई परियोजना, जिसके ऊपर मेरे विपक्ष के भाईयों ने बहुत राजनीति की। मैं कहना चाहूंगा कि 2011 में एक विपक्ष के, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएं और वहां परवन पर, वहां पर 2012 में पत्थर गाड़ कर चले गये, कोई बजट नहीं दिया, वहां मौके पर कोई कार्य चालू नहीं हुआ।

उस परवन की स्थिति वर्तमान में, मैं आपसे कहूं कि जब 2013 से 2018 तक बीजेपी की, मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी सरकार थी, उन्होंने 750 करोड़ रुपये देने का काम किया। उसकी डीपीआर बनाकर वर्तमान में 3 कम्पनियों ने उसका काम किया। उसका काम करने के साथ-साथ, आज डैम लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ-साथ वहां पर कैनाल और कैनाल के साथ-साथ पाइप, वर्तमान में पिछले 5 साल से बजट की बांट जोह रहे थे, वे आज तक नहीं बन पाये हैं।

Bhs/Rtm/05.03.25/15.00/2j

इसके साथ-साथ जो उस परियोजना में पाइपलाइन स्प्रिंक्लर से पानी दिया जाना था 1,10,000 हेक्टेयर की जो हमारे भूमि थी, उसको सिंचित करना था, उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ। पिछले 5 साल में जो डी.आई. के पाइप थे वो पाइप बदलकर उसमें एच.डी.आई. के पाइप स्थानांतरित करने का काम किया और उसमें उस समय जो जिंदल कंपनी जिसको टेंडर दिया गया, उसमें उसको 2 साल बाद टेंडर दिया, उसने अपना काम लगभग 80% पूरा कर दिया और 20% बिलों में। इसके साथ-साथ जो दूसरी कंपनी जी.वी.पी.आर. वर्तमान में जहां काम नहीं कर रही है उसको काम दिया, उसने आज अपना काम छोड़कर उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि वो महत्वाकांक्षी योजना जिससे हमारे झालावाड़, हमारे सांगोद, अंता, बारां को पानी मिलना था, वो आज सफर कर रही है। मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी पूरी तरह जांच करायें। आज उस जी.वी.पी.आर कंपनी ने अपना काम किया, उसने डिले किया, डिले करने के बाद भी उसकी जो सिक्योरिटी मनी थी, वो वापस उसको लौटा दी गई। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस परवन में हुआ और तात्कालिक उस समय के एस.ई, चीफ इंजीनियर, एक्स.इएन. को उसी सरकार ने हटाया। यह माना, लेकिन उनके खिलाफ़ आज वर्तमान में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मेरा आज सदन के माध्यम से निवेदन है कि 2018 में 2170 करोड़ रुपये का कार्यादेश हुआ था और 2022 तक इस परवन का काम पूरा करना था, वो नहीं हो पाया इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराकर इसको बजट भी दिया जाए और इस काम को आगे बढ़ा कर आमजन किसानों को उस हाड़ौती के बारां, झालावाड़ और कोटा के लोगों को इसका फायदा मिले। इसके लिये राहत प्रदान करें। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का दिलोद एनिकट, एक अरनिया एनिकट, 2021-22 में आपने 23 करोड़ रुपये दिया दिलोद के लिए, अरनिया के लिए 22 करोड़ रुपया दिया। आज वर्तमान में 4 साल होने के बाद आपने अभी तक वर्तमान में वहां पर काम नहीं हुआ और उसके तीन बार टेंडर हो गये, लेकिन हमारा दिलोद एनिकट के आज भी उस काम के लिए किसान बाट जोह रहे हैं। बार-बार टेंडरिंग के लिए कहते हैं।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि पुराना बजट है और उस सरकार ने तो नहीं किया पर इसको दिखवाकर धरातल पर ले के आने का काम करें। इसके साथ-साथ मेरे जखाका मझोला का तालाब, जिसकी डी.पी.आर. 2018 में बनी। 2018 में बनने के बाद हमारी सरकार ने पैसा दिया। आज 5 साल बाद भी वो वर्तमान में बजट की बाट जोह रहा है। 757 लाख रुपये उसको उस समय दिये। आज भी किसान उसके मुआवज़े के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मेरे कालीसोध तालाब जिसको 5 करोड़ रुपया दिया लेकिन वर्तमान में 2 साल भी नहीं चला और वह पहली बारिश में बह गया। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि कालीसोध तालाब की जांच कराकर और उसको ऊंचा करने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाए। इसके साथ-साथ मेरी 2018 की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना

हत्यादह मध्यम सिंचाई परियोजना जिसके लिये 600 करोड़ रुपया हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बजट में घोषणा की। आज उसकी मैं कह रहा हूं हमारे जो काश्तकार थे उसमें मोहिदा और करवरीकलां वहां के लोगों को विस्थापित करके दूसरी जगह बसाना था उनको मुआवजा, पुनर्वास का पूरा मुआवजा नहीं मिला। लगभग 652 लोगों को मुआवजा मिला और एक्सग्रेसिया के 242 लोग आज भी मुआवज़े के लिए किसान लोग आज भी वहां बाट जोह रहे हैं। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि उनको एक्सग्रेसिया के माध्यम से बजट दिलाने का काम करें।

साथ ही, मैं एक और आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारे विपक्ष के भाइयों को कि 2021 में भीम सागर डेम के गेट खोल दिये और गेट खोलने के बाद रात में ही पानी हमारे सांगोद, जहां से वर्तमान हमारे ऊर्जा मंत्री जी आते हैं वहां पर पूरे कस्बे में हालात खराब हो गये, पानी भर गया, उसकी जांच भी कराई। उस समय के तात्कालिक एम.एल.ए. हमारे पूर्व मंत्री भरत सिंह जी ने भी उस बात को इस सदन में रखा, लेकिन आज दिन तक भी उसको गोलमाल कर दिया गया। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आमदी सिंचाई परियोजना जो पिछली बार 2006 में उसकी आधारशिला रखी, उसके बाद 2014 में जब दोबारा सरकार आयी तो उसको बजट देने का काम किया और बजरंगगढ़ की हमारी जो नहर वर्तमान में बनकर तैयार हो गई, लेकिन आज ख्यावदा की जो नहर 2014 की डी.पी.आर. से...।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री ललित मीना (किशनगंज): सभापति महोदय, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। इसके साथ-साथ 2014 की, उसकी रिवाइज़ इस्टीमेट बनाकर उसको अतिरिक्त बजट देने का काम करें। इसके साथ-साथ मैं जो 2003 में पंचायती राज़ के तालाब, हमारे पंचायती राज को स्थानांतरित किये थे सिंचाई विभाग से उनको पुनः वापस आप इसमें जोड़ने का काम करें। इसके साथ-साथ मैं अपनी बात 2 मिनट में पूरी करूँगा।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री ललित मीना (किशनगंज): एक मिनट में।

हमारे जे.जे.एम. के जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के काम थे, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, उनके लिये, मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी कुओं से पानी पिलाया जा रहा है ट्यूबवैल से तो जे.जे.एम. का लगभग 45 गांवों में काम चल रहा है। 45 गांवों में से 23 में पूरा हो गया और 23 में भी स्थिति है यह है कि कई जगह पाइप लाइन अधूरी पड़ी हुई है।

श्री सभापतिः श्री अमित जी चाचाण।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मैं सभापति महोदय, 1 मिनट के बात पूरी करूंगा।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री ललित मीना (किशनगंज): इसके साथ-साथ मेरे जे.जे.एम. के लिए अतिरिक्त बजट देने का काम करें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल संसाधन, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान में जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तब-तब इतिहास गवाह है कि किसानों ने लगातार आंदोलन किये और सिर्फ इसलिये किये कि उन्हें उनके हिस्से का, उन्हें उनके हक का सिंचाई का पानी चाहिए था, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? जब-जब भी सरकार आई और जब-जब प्रदर्शन हुआ, पानी तो उनको नहीं मिला बदले में उन्हें गोलियां मिलीं, बदले में उन्हें लाठियां मिली, बदले में उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ी, बदले में उनके मुकदमे हुए, बदले में उन किसान नेताओं को जेल में जाना पड़ा। यह इतिहास राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पिछले 35 वर्षों में 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, 15 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, लेकिन यह किसान विरोधी सरकार, यह दलित विरोधी सरकार, यह तानाशाही सरकार हर बार किसानों को लाठियां देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है।

माननीय सभापति महोदय मेरे नोहर, भादरा और तारानगर के 29 गांवों को मैं सिंचित करने की बात करूंगा, जिनके चारों तरफ पानी लग रहा है उनके पड़ोसी के पानी लग रहा है, लेकिन 29 गांवों में पानी नहीं पहुँच रहा। 2013 से 2018 तक लगातार धरने प्रदर्शन हुए। हमारे जिले के ही सिंचाई मंत्री थे। दिये के तले अंधेरा था। किसान 200 फुट ऊपर उच्च जलाशय पर 7-7 दिन टंकी पर चढ़े रहे, कोई भी सरकार का नेता या उच्च अधिकारियों ने वार्ता नहीं की। कोई भी उस पर काम नहीं हुआ। जब हम सत्ता में आये, क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक चुना, हमने बार-बार मांग इस सदन में उठायी। एक बजट में तो मुख्यमंत्री जी ने डी.पी.आर. बनाने की घोषणा की, दूसरे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की घोषणा की और तीसरे बजट में 100 करोड़ रुपये से सिंचित करने का घोषणा की लेकिन मैं कहना चाहूंगा मुझे खेद है अधिकारियों की नकारात्मक सोच की वजह से वो काम आज भी शुरू नहीं हो पाया है और 30 गांवों के किसान आज भी राहत देख रहे हैं कि हमें क्या कभी सिंचाई का पानी मिलेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि किसान के प्रति सकारात्मक सोच को रखते हुए 29 गांवों को सिंचित करने का आप काम करें।

मैं बात करूं मेरे नोहर फीडर नहर की, नोहर फीडर नहर पिछले 1 साल में 6 बार हरियाणा में टूट गई है। चलती बारी में किसानों की बारियां पिट रही थी लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे थे। किसानों की मांग है कि इसका पुनर्निर्माण करवाया जाये। इस सरकार से पहले आप कई भाजपा के नेता जो हमारे दिल्ली में जाकर फोटो खिंचवाते थे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान के थे और उन्होंने कहा आप तो राजस्थान से अपने हिस्से की घोषणा करवाइये। कहा, मैं करवाऊंगा, तुरंत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 करोड़ रुपये हमारे बनते थे 20 करोड़ रुपये की घोषणा की, लेकिन हरियाणा सरकार ने एन.ओ.सी. नहीं दी, डी.पी.आर. नहीं बनने दी। आज 2 साल से काम अटका हुआ है। कई इंजनों की आपकी

सरकार है, आप उस पर संज्ञान लें? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में आपकी सरकार है। नोहर फीडर नहर का रीलाइनिंग का काम करवायें जिससे कि हमारे पूरे हिस्से का उसमें पानी मिल सके और किसानों के खेत तक पानी पहुंच सके। नोहर फीडर, अमर सिंह और सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के लिये 58 करोड़ रुपये के खालों की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां भी निकल चुकी थी, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार सरकार बनने के साथ ही उस वित्तीय स्वीकृति पर रोक लगा दी, जबकि उसकी निविदा भी आमंत्रित हो चुकी थी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे साथी तो कहते हैं, इन्होंने घोषणा की, हमने तो काम करके दिखाया है, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा आपने मात्र 13 करोड़ रुपये की उसमें स्वीकृति जारी करवाई है शेष 45 करोड़ रुपये के खालों की भी स्वीकृति करायें और उसके अलावा भी हमें 60 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है, जिससे कि खालों का पुनर्निर्माण होगा तो किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा। मैं बात करूँगा अमर सिंह ब्रांच की एक मेरी नहर की, क्योंकि मेरे नोहर विधानसभा क्षेत्र के काश्तकार टेल पर निवास करते हैं और टेल पर सबसे ज्यादा मार उन पर पड़ती है। आज उस अमर सिंह ब्रांच के मोगे साइज से बड़े लगे हुए हैं, उनकी भी निविदा आमंत्रित कर दी गई थी, लेकिन आज तक मौगे सही नहीं हुए जिसकी वजह से मूढ में और जो प्रथम में है वो किसान दो बार तीन बार पानी ले रहा है और मेरे किसान को अंतिम छोर पर पानी नहीं मिल रहा है।

मैं बात करूंगा सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना की, जो हरियाणा वाया भादरा होकर नोहर में पानी पहुंचता है। माननीय सभापति महोदय, हमने तो बजरी माफिया, शराब माफिया देखे, लेकिन मैंने उस क्षेत्र में पानी माफिया भी देखा जो हजार-हजार रुपये घंटे में पानी बेचने का काम कर रहा है। मैंने स्वयं ने विधायक रहते 7-7 रात, सर्द रातों में जनवरी के महीने में वहां नहर के किनारे तम्बू लगाकर उस पानी की चोरी रोकने का प्रयास किया था, जिसमें पूरे राजस्थान का एकमात्र पुलिस थाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नोहर में खोला, जो सिंचाई के पानी की चोरी रोकने का काम करेगा।

Kas/rtm/05.03.2025/15.10/2k

लेकिन आज भी हमारे प्रयास उसमें पूर्ण नहीं हुए, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से पानी टेल पर नहीं पहुंच रहा है।

माननीय सभापति महोदय, बीजेपी के नेता बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा 2004-2005 का रावला-घडसाना का आंदोलन, जिसमें किसानों को गोलियां मिली थीं और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का काम होना था, जिसमें 19.5 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी, उसमें 3 लाख 47 हजार हैक्टेयर भूमि को असिंचित करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और उस नहर से जो 6 लिफ्टें निकलती थीं, समान हिस्सा कट रहा था, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से सबसे

ज्यादा नुकसान सावा लिफ्ट, कुंभाराम आर्य लिफ्ट योजना को हुआ, जिसमें 1 लाख 40 हजार हैक्टेयर भूमि को असिंचित कर दिया। उसमें 19 सब माइनर बनने थे, मात्र 4 माइनरों का निर्माण हुआ, 15 माइनरों का निर्माण आज भी अधूरा है। उसमें नोहर की भी है, तारानगर, लूणकरणसर की भी हैं। माननीय सभापति महोदय, आज ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने राजस्थान की जनता को दिखा रहे हैं। यमुना जल समझौते से दिखा रहे हैं कि हम पानी लेकर आयेंगे, लेकिन जो हमारा मौजूदा सिंचाई का तंत्र है, उसे तो मजबूत कीजिए। यह सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की नकारात्मक सोच है, क्योंकि हम और आप तो बदलते रहते हैं, लेकिन दीर्घा में बैठे हुए लोग स्थाई होते हैं, वो नहीं चाहते कि किसानों को पानी मिले। पिछले 20 वर्षों में देखिए कितने नेशनल हाई-वे बने, कितने स्टेट हाई-वे बने, कितने उद्योगधंधे लगे, कितनी कॉलोनियों की आबादी बसी है, सिंचित भूमि कम होती जा रही है, फिर भी किसानों को पानी क्यों नहीं मिल रहा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधिकारियों को किसान के प्रति सकारात्मक सोच रखनी होगी, जिससे कि हम उनके हिस्से का पानी उसके खेत तक पहुंचा सके, उनके हाथ मजबूत कर सकें, क्योंकि हमारा राजस्थान कृषि प्रदान देश है। जब तक हम किसान के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारे क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से संभव नहीं है।

सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत बूंद-बूंद सिंचाई परियोजना के तहत अलग-अलग फेज में 317 डिग्गियों का निर्माण होना था, वर्तमान में 157 डिग्गियों का निर्माण कार्य चालू है, जिसमें भी कुछ अधूरी हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगर उन डिग्गियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा तो बूंद-बूंदी प्रणाली से सिंचाई का पानी प्रत्येक किसान को मिलेगा और किसान के पानी की बचत भी होगी।

माननीय सभापति महोदय, नोहर का विधान सभा क्षेत्र टेल पर स्थित है, इसलिए सभी नहरों में किसानों की बारियां पिट रही हैं। हरियाणा से जो हमारा 0.47 एमएफ पानी का समझौता हुआ था, आज भी हरियाणा हमें हमारे हिस्से का 0.17 एमएफ पानी नहीं दे रहा और उसके बाद भी जो पानी निर्धारित है, उसमें भी हमें कटौती मिल रही है। चाहे मैं अमर सिंह बैराज की बात करूं, चाहे सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना की बात करूं, चाहे नोहर फीडर नहर की बात करूं, आपकी तो कई इंजनों की सरकार है, दिल्ली तक आपकी सरकार है, फिर आप अपना पानी क्यों नहीं ले रहे? क्यों आपको पड़ोसी राज्य आंखें दिखा रहे हैं? क्यों पड़ोसी राज्य हमारे हिस्से का पानी बरत रहे हैं, यह आपको सोचना होगा, सामूहिक रूप से सोचना होगा, जिससे हम हमारे हिस्से का पानी लेकर आएं और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, ऐटासिंहासन माइनर का निर्माण भी लंबे समय से चल रहा है। धरना-प्रदर्शन और आंदोलन भी बहुत हुए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सबसे समीप का क्षेत्र होने के बावजूद भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। आप एक सकारात्मक सोच के साथ उसकी भी डीपीआर बनाएं और उसको भी पानी देने का काम करें।

सभापति महोदय, पेयजल की मैं बात करूं, मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र के 30 गांव आज भी वंचित हैं, जल जीवन मिशन में घर-घर पेयजल योजना के अंतर्गत उनके कनेक्शन नहीं हुए हैं। 230 करोड़ रुपये पूर्ववर्ती सरकार ने हमें स्वीकृत किये। मेरे लगभग सभी गांव उस योजना से जुड़ चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय, उन 30 गांवों की निविदा भी लग चुकी है। जल्द ही अगर वह निविदा स्वीकृत हो जाती है, तो उन 30 गांवों को पानी मिल जायेगा। ये गांव हैं, ढाणी बिजारिणीयां, ढाणी लेधा, प्रेमपुरा, लाखेरा, माहेला, ढाणी माहेला, रतना देसर, दूधजली, नैयासर, लाडम, घनीयासर, मालासर, कुल्चासर, स्वरूप देसर, कल्लासर, बिंजासर, केलनियां, चेलासरी, देवासर, कानसर, भोगराना, जोरावरपुरा, सुरपुरा, चक देईदासपुरा, असरजाना, सांगठिया, खरसंडी, ललानियां, नगरासरी व मुंसरी। इसके अलावा हजारों ढाणियां भी वंचित हैं, जहां आज भी पेयजल नहीं पहुंचा है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम प्रत्येक घर तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो यह हमारी नाकामी है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के लिये आप प्रयास करें और इस सर्दी के मौसम में पानी नहीं पहुंच रहा, इसकी वजह है कि हमारे डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी हो गई है। आज न तो लीकेज निकालने वाले कर्मचारी हैं, न वॉल खोलने वाले कर्मचारी हैं, न उच्च जलाशयों, टंकियों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कि प्रेशर से पानी नहीं पहुंचता और जो टेल पर हैं, ऊँचाई पर जो हैं, वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हमें इसमें तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी, मॉनिटरिंग करनी होगी और जहां-जहां भी कमियां रही हैं, आप जांच करवा करके, उनको भी दुरुस्त करें, जिससे कि हम हर घर तक पानी पहुंचा सकें। आज मैं यही कहूंगा

पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिये,
आग मेरे सीने में नहीं,
तेरे सीने में हो, यह आग जलनी चाहिये।
हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
अब तो यह सूरत बदलनी चाहिये।

धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापतिः श्री कुलदीप सिंह जी।

श्री कुलदीप (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं मांग संख्या 42 - जल संसाधन पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं दो लाइनों से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा,

हमने देखो नदियों के रुख को मोड़ दिया,
जो भी थीं बाधाएं, सबको तोड़ दिया।
आप बातें करते रहे बस पांच बरस तक,
भाजपा ने आते ही नदियों को जोड़ दिया।

माननीय सभापति महोदय, पानी जैसे गंभीर विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है,

सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और मुझे देख कर बहुत आश्चर्य हो रहा है, जिस प्रकार से विपक्ष की संख्या मुझे दिख रही है, मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष राजस्थान की जनता के लिये कितना संवेदनशील है। अभी नोहर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत जगह पेयजल की समस्या है। सभापति महोदय, मैं कुछ आंकड़े भी देख रहा था, अगर राजस्थान में 2018-23 के बीच में अशोक गहलोत जी की सरकार पानी पर और सिंचाई पर काम कर रही होती, तो राजस्थान में आज पेयजल की समस्या इतनी विकट नहीं होती। आप पांच साल तक केवल भाषण ठोकते रहे। कभी ईआरसीपी पर भाषण ठोकते रहे, कभी अन्य विषयों पर भाषण चलते रहे। राजस्थान में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी आपस में मुख्य मंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ते रहे और पांच साल में विकास के काम को भूल गये, इस कारण से राजस्थान में ये समस्याएं पैदा हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं विपक्ष को कुछ याद दिलाना चाहता हूं, इनके बजट में बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने करीं। अमृत योजना के अंतर्गत 5 हजार करोड़ रुपये की लागत के कार्य, कई जिले आपने इसमें शामिल किये, लेकिन ये एक रुपये का काम भी नहीं करवा पाये, एक रुपये का वर्क आर्डर भी जारी नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बाड़मेर, झुंझुनूं, उदयपुरवाटी, सूरजगढ़ में आपने घोषणा की, बहुत सारी योजनाएं आपने बजट में लीं, लेकिन पांच साल के कार्यकाल में इन्होंने एक रुपये का काम प्रारंभ नहीं किया, इसके कारण से पेयजल संकट पैदा हुआ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ईआरसीपी को लेकर बार-बार विपक्ष के साथी चर्चा करते रहते हैं। पांच साल तक आपका शासन रहा, आप हमें धन्यवाद भी दे रहे हैं, वसुन्धरा जी ने हमारी यह योजना प्रस्तावित की थी, लेकिन आप सदन को कम से कम इतना तो बताओ कि पांच साल में आपकी कांग्रेस सरकार ने क्या काम किया? एक रुपये का काम नहीं किया, केवल आप भाषण देते रहे, उसका जिक्र करते रहे, पॉलेटिकल फायदा लेते रहे, लेकिन एक रुपये का काम भी आपने प्रारंभ नहीं किया। आज भागीरथ के रूप में निकल कर राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा जी आये, जिन्होंने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सान्निध्य में हरियाणा सरकार व मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री जी से बात की और इसको जमीन पर पहुंचाने के लिये एमओयू करने काम किया है। आपको तो अधिकार ही नहीं है, आप इतना क्यों पूछते हो कि एमओयू में क्या हुआ? पांच साल तक तो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे, एक रुपये का काम आप कर नहीं पाये और हमसे सारी जानकारी चाहते हो। आप चिंता मत कीजिए, हमारे मुख्य मंत्री महोदय सदन के बीच में जो एमओयू हुआ है, उसकी पूरी कार्ययोजना के बारे में बतायेंगे भी और राजस्थान की जनता को पानी पहुंचाने का काम भी करेंगे।

Msk/rtm/05.03.25/1520/2l

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ईआरसीपी, मैं तो प्रदेश की सरकार और

माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामगढ़ तक पानी लाने की बात हमारी पूर्ववर्ती सरकार में थी, वसुन्धरा जी की सरकार में थी, मैंने मांग की थी कि रामगढ़ बांध का पानी त्रिवेणी धाम तक की नदी में जाये, जो धाभाई के बांध तक जोड़ा जाये, बुचारा का बांध भरे, छितौली का बांध भरे, हमारे कई विधान सभा क्षेत्रों में इसका लाभ होगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने 4100 करोड़ रुपये हमारी विधान सभा विराटनगर में इस योजना में शामिल करके जोड़ने का काम किया है। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। विगत सरकार के द्वारा पेयजल के लिए नौनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा, लिंक की घोषणा की गयी। पेयजल जैसे महत्वपूर्ण योजना पर कोई ठोस काम नहीं किया। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिला रहा हूं कि मात्र इतना कहना, सरकार पर आक्षेप लगाना, इससे राजस्थान का विकास संभव नहीं है। विकास तब संभव होता है, जब आपका राज आता है तब तो आप भूल ही जाते हैं कि आपको करना क्या है? हमारी सरकार ने कितना सारा काम किया है, लगभग 9 हजार 400 करोड़ के कार्यों के कार्यादेश जारी किये हैं। इसके अतिरिक्त 12 हजार 64 करोड़ की निविदाएं भी हमारी सरकार ने आमंत्रित की हैं। साथ ही, 12 हजार 807 करोड़ रुपये की स्वीकृति राशि भी जारी की है। बहुत सारा ईआरसीपी में काम होने वाला है। आप चिन्ता न करिये, आने वाले समय में, मैंने कहा था, मैं किसान का बेटा हूं, खेत और खलिहान से निकलकर आता हूं। हमेशा इस बात को राजस्थान के इतिहास में याद किया जायेगा कि राजस्थान के इतिहास में 2023 में राजस्थान में भजन लाल शर्मा मुख्य मंत्री बने थे और हमारा खेत और खलिहान हरा-भरा होगा।

आज वास्तव में राजस्थान में पानी की समस्या है। पानी पर हमें काम करने की आवश्यकता है। राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर राजस्थान को आगे बढ़ाना है, सब लोगों को मिलकर इस पानी की समस्या के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जिनका जिक्र भी मैं करना चाहता हूं, जेजेएम में भ्रष्टाचार किसने किया? हमारी सरकार ने तो किया नहीं। हमने तो जांचें प्रारंभ करने का काम किया है। अगर जेजेएम में भ्रष्टाचार हुआ तो कांग्रेस के शासन में हुआ। मैं जिक्र करता हूं, ऐसे बहुत सारे कामों का, जिसमें मेरा स्वयं का जिला कोटपुतली-बहरोड़ भी शामिल है, जयपुर-ग्रामीण भी शामिल है, दौसा व अलवर भी शामिल है, नीम का थाना जिला भी शामिल है, जिनमें जेजेएम में बड़ा करप्शन हुआ। हमारी सरकार ने जांच भी करवायी है। कुछ अधिकारियों और कुछ ठेकेदारों को जेल भी भेजने का काम भी किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेजेएम में मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में ऐसी बहुत सारी योजनाएं थीं, जो अभी तक पैंडिंग हैं, जिनका अभी तक कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में, मैं मंत्री महोदय आपसे भी आग्रह करता हूं कि बहुत बड़ी समस्या है। एक

हजार फीट तक पानी नहीं आता और हम जितने बोरिंग-ट्यूबवैल करवाते हैं, सूखे चले जाते हैं। मैं हमेशा एक बात का जिक्र सदन में करता रहता हूं, सदन के बाहर भी जिक्र करता रहता हूं कि मेरे विराटनगर में पेयजल की समस्या को ध्यान में रखकर, मैं शुरुआत करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में जो नगरपालिका पावटा, प्रयागपुरा है, अमृत-2 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसको इसमें जोड़ा जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापतिः दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री कुलदीप (विराटनगर)ः सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय लेना चाहता हूं।

साथ ही, मैं निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 40 ट्यूबवैल की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि ट्यूबवैल स्वीकृत करके सरकार इस काम को पूरा करेगी। साथ ही, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भी काम हैं, लगभग 33 गांव में 26 रिवाइज स्कीम्स हैं, जिनका आज तक का टेण्डरिंग का काम भी पूरा नहीं हुआ है। वर्क ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ है। मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो पुराने काम स्वीकृत हैं, उनको शीघ्र करने का काम करेंगे। साथ ही, मैं डब्ल्यूआरडी विभाग से भी मांग करता हूं कि हमारे आंतेला गांव है, जहां पर एक बरसाती नाला निकलता है, वहां पर जब पानी आता है तो गांव में बड़ा संकट पैदा होता है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर एक अच्छे नाले का निर्माण हो, पक्के नाले का निर्माण हो जाये, दीवार बनकर तैयार हो जाये। इसमें आबादी को लाभ मिल सके। साथ ही, मेरे विराटनगर में बड़े बांध हैं, छितौली के बांध से विराटनगर से निकलने वाले विभिन्न स्ट्रीम्स के चैनलाइजेशन और प्रोटेक्शन के कार्य, बैराठ बांध का जीर्णोद्धार, इसके विभिन्न स्ट्रीम्स के चैनलाइजेशन के कार्य। विराटनगर क्षेत्र कालराई ढाणी का बांध है, बीजक पहाड़ी का बांध हैं और बहुत सारे एनिकट हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पावटा क्षेत्र के खार वाले नाले से चैनलाइजेशन के प्रोटेक्शन का कार्य भी सरकार पूरा करेगी।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री कुलदीप (विराटनगर)ः साथ ही, मैं निवेदन करना चाहिए। माननीय महोदय, एक बहुत गंभीर विषय है। मेरे रामपुरा गांव में, जाझा गांव में, छापड़ा कलां में, छापड़ा खुर्द में, चिमनपुरा में, साहीबाड़ में, दातावाड़ा में, अमरपुरा में, मेड़ में, पाचूंडाला में, भांकरी में, बडवे में, प्रागपुरा में, पावटा में, कुकड़ेला में, भांभोद में, इन सब गांवों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये, श्री सुरेश मोदी।

श्री कुलदीप (विराटनगर)ः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन सब कामों की जांच कराकर यहां स्वीकृति प्रदान करेंगे।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री कुलदीप (विराटनगर)ः 000

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। बहुत समय पहले से इसे डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। पानी 1200 फीट से पहले नहीं आता है, बहुत सारे बोर सूखे निकलते हैं और जो पानी आता है, वह पीने के योग्य नहीं होता, उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उसे मजबूरी में जनता को पीना पड़ता है। अधिकांश हैंडपम्प पूरी तरह से नकारा हो चुके हैं। जल जीवन मिशन का काम शुरू हुआ तो लोगों को एक आस बंधी कि शायद अब पीने के पानी की कमी से छुटकारा मिलेगा, परन्तु जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों को देखकर वह भी टूटने लगी है। मंत्री महोदय, एक भी पंचायत ऐसी नहीं है, जिसमें जल जीवन मिशन का काम पूरा हो गया है। कहीं पाइपलाइन डल गयी है, कहीं टंकी बन गयी है, कहीं पर बोर खुद गया है, लेकिन पूरा काम किसी भी पंचायत में नहीं हुआ है। एक काम सब पंचायतों में जरूर हो गया है कि जो सड़कें बनी हुई थीं, जो ब्लॉक लगे हुए थे, उनको जरूर जल जीवन मिशन की काम करने वाली एजेंसी ने तोड़ दिया और उनकी वापस मरम्मत नहीं की।

जो बोर सूखे निकल गये हैं, ड्राई चले गये हैं, उनकी एवज में योजना में कोई प्रावधान नहीं है कि उनकी जगह दूसरे बोर लगाये जायें। अभी तक हमारे इलाके में दूसरे बोर नहीं लगे हैं। इसमें एक बड़ी समस्या रखरखाव की है। लगाये गये पाइप टूट रहे हैं, मोटरें जल रही हैं, स्टार्टर तो बहुत ही खराब क्वालिटी के लगाये जा रहे हैं, जो रोज खराब हो रहे हैं। आगे जाकर यह योजना भगवान भरोसे ही चलेगी, इन कर्मचारियों के भरोसे नहीं चलेगी। आज पीने के पानी की यही स्थिति है कि शहर में व गांव में लोग बहुत परेशान हैं। महिलाएं दूर-दूर से सिर पर पीने का पानी लेकर आती हैं। चालू बोरिंग व हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हो रही है। न तो सामान हैं, न कर्मचारी हैं। लोग परेशान होकर टैंकर से पानी डलवाते हैं। घरों में पानी कई-कई दिनों से आता है। एक योजना सौलर ट्यूबवैल की ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। पिछली बार सरकार ने दस-दस सौलर के ट्यूबवैल दिये थे, वे बहुत उपयोगी रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी विधान सभा क्षेत्र में, जहां पानी की कमी है, ग्रामीण क्षेत्र में सौलर के दस-दस ट्यूबवैल जरूर दें। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना बनी, जिसका नाम बदलकर। सीकर, नीम का थाना व झुझुनूं जिले के शेष रहे गांव व कस्बों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा गांधी नहर आधारित प्रस्तावित बृहद पेयजल योजना किया गया। इस योजना के तहत 6 विधान सभा क्षेत्रों के 1161 ढाणियों और 18 कस्बों को पानी देने की योजना बनी। आरडी 103 से यह पानी लाकर सीकर और झुझुनूं में देना था। ऐसी महत्वपूर्ण समस्या का इस बजट में कहीं जिक्र भी नहीं किया गया है। कोई एक रुपया भी इस योजना के लिए नहीं दिया गया, जिस योजना का काम बड़े स्तर पर पूरा हो चुका है। सारी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति की 37वीं बैठक में इसका अप्रूवल हो चुका है। आपके पिछले बजट में भी आपने 7 हजार 583 करोड़ रुपये की इस योजना पर मुहर लगाकर यह स्वीकृति दे दी थी, लोगों को आस बंधी थी कि आपके कार्यकाल में यह योजना जरूर पूरी

होगी।

mdp/rtm/05.03.25/15:30/2m

RWSSC को कार्यकारी एजेंसी भी नामित किया जा चुका है। स्टेट का और सेंटर का कितना शेयर रहेगा, यह सब भी तय हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद इस योजना का नाम बजट में नहीं लिए जाने से लोगों में यह आशंका पैदा हो रही है कि आप इस योजना के लिए गंभीर है या नहीं है। कृपया मंत्री जी जब जवाब दें, तब ये बताएं सदन को कि इस योजना की क्या स्थिति है? कब तक ये पूरा होगा, कब तक धरातल पर आयेगा और कब तक इन क्षेत्रों से लाभान्वित होने वाली जनता को इसका पानी मिलेगा?

मुझे डर है कि जो 521 एम.एल.डी. पानी प्रस्तावित है, वह कहीं जैसे पिछली बार यमुना के पानी के लिए वहां के मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि कोई पानी-वानी नहीं दिया जाने वाला है, वैसे ही कोई कहानी इसके साथ नहीं हो जाए और हमारा जो ये पानी का हिस्सा है, हमारी लापरवाही, हमारी देरी की वजह से कहीं वह हिस्सा पानी का, हमसे नहीं छूट जाए। आपने लोक सभा चुनाव से पहले यमुना जल का एक झुनझुना जनता को फेंका। 17 फरवरी को आपने हरियाणा के मुख्य मंत्री खट्टर जी और भजन लाल जी और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी के बीच में एक समझौता किया और आपने घोषणा की कि चार महीने में डी.पी.आर. तैयार होकर इसका काम शुरू हो जायेगा। अब हुआ क्या कि इस समझौते की जो असलियत थी, वह खट्टर साहब ने दस दिन में ही अपनी विधान सभा हरियाणा में जाहिर कर दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम कोई पानी-वानी राजस्थान को नहीं देंगे। जो अतिवृष्टि का पानी है, जो बाढ़ का पानी है, वह 15-20 दिन तक अतिरिक्त रहेगा हमारे पास, जो हमारे काबू में नहीं रहेगा, वह पानी हम राजस्थान को देंगे। उसमें से भी हम 25 परसेंट पानी स्वयं रखेंगे, बाकी का पानी देंगे और अंडरग्राउण्ड पाइप लाइन के जरिये ये पानी राजस्थान को दिया जायेगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि 17 फरवरी को आज मार्च शुरू हो गयी है 2024 की जगह 2025, एक साल से ऊपर हो गया। इस योजना का क्या हो रहा है? इसकी डी.पी.आर. बन रही है या नहीं बन रही है? अगर बन रही है तो कौनसी एजेंसी है जो इस डी.पी.आर. को बना रही है, कृपया सदन के पटल पर रखें। आपने समझौता तो आज तक सदन में नहीं रखा कि आपने क्या समझौता किया यमुना का, लेकिन कम से कम मेहरबानी करके इतना तो बता दीजिए कि फलां एजेंसी इसकी डी.पी.आर. तैयार कर रही है और इतने दिन में इसकी डी.पी.आर. तैयार हो जायेगी और इतने दिन में जो भी कुछ पानी मिलने वाला है, भले ही वह 1 क्यूसेक है या 1 हजार क्यूसेक है, वह पानी कब तक राजस्थान की जनता कोमिलेगा?

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दस बांध ऐसे हैं, जो आज तक नीम का थाना की जनता को पानी पिलाने का काम करते आए हैं। बने हुए

बांध हैं। अगर इन बांधों में आप पाइप के जरिये पानी लाने की बात कर रहे हैं तो इन बांधों में डाल दिया जाए, जिससे कि जो भी बाढ़ का पानी है, वह इन बांधों में आ जाएगा तो इससे हमारे यहां का जलस्तर बढ़ेगा और सिंचाई के लिए अगर उपलब्धता होगी, जितना पानी आयेगा, उसके भी काम में लिया जा सकेगा। मैं मंत्री जी आपको इन बांधों के नाम रिकॉर्ड में देना चाहता हूं। रायपुर पाटन बांध, पीथमपुरी का सर, बिहार बांध, माकड़ी बांध, रायला बांध, भूदोली बांध, झालाना बांध, गावड़ी बांध, झीलो बांध। इन बांधों में आप यमुना का पानी लाते हैं तो इनमें पाइप के जरिये डलवाइए, जिससे आपका खर्चा भी कम लगेगा और जनता को सुविधा भी मिलेगी।

सभापति जी, आज दुनिया चाँद पर जा रही है और हम अपने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उनके घरों पर नहीं दे सकते। महिलाएं दूर-दूर से सिर पर ढोकर पानी लाती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मेरे बगल में मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगता हुआ गांव है हरियाणा का बेटण्डी, वहां तक खुली नहर के जरिये पानी आ रहा है। अगर संभव हो तो उस खुली नहर को थोड़ा-सा चार-पांच किलोमीटर आगे और बढ़वा दीजिए तो वह पानी मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहुंच जाएगा। कम खर्चे में ये काम हो सकता है। नरेगा की लेबर को भी आप इस काम में लगा सकते हैं। हम लोग भी मशीनें देने में सहयोग कर सकते हैं। दानदाताओं का सहयोग ले सकते हैं। अगर ये संभव है तो इस पर आप काम कीजिए। इस बजट में आपने दोनों जो योजनाएं हैं, कुम्भाराम लिफ्ट योजना और यमुना जल, इन दोनों का नाम भी, जिक्र भी बजट में नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, कोई प्रावधान क्यों नहीं किया है? इससे इन दोनों योजनाओं के भविष्य पर संशय नजर आ रहा है। आप नीम का थाना को कोई बजट नहीं दे रहे। आपने उसे जिला निरस्त कर दिया। कृपया पीने का पानी तो जनता को उपलब्ध कराएं। आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है।

श्री सभापतिः प्लीज, बात समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): मेरे क्षेत्र में पीने का पानी कब तक आयेगा, ये सदन के पटल पर स्पष्ट करें। आप राइजिंग राजस्थान जैसे आयोजन कर रहे हैं। लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आप किसान को नहर का पानी दे दें, आपको रोजगार की समस्या अपने आप खतम हो जायेगी। किसानी को फायदे का सौदा कर दें। बहुत-सी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जायेगा। मेरा निवेदन है मंत्री जी, आप इन दोनों योजनाओं के बारे में जब जवाब में अपने जरूर स्पष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय। 'जल ही जीवन है', 'जल है तो कल है'। सभापति महोदय, कहते हैं कि पृथ्वी पर पहला जीव जल से आया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कर्नल अल्बर्ट आइंस्टाइन एवं कर्नल टॉड ने पानी की चिंता करते हुए कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। उनकी भी चिंता थी और 600 वर्ष पहले गुरु जम्भेश्वर भगवान ने ये चेतावनी दी थी कि यदि पानी को नहीं बचाया गया, प्रकृति के साथ

छेड़छाड़ की, पौधों को काटा गया, जीव-जंतुओं की रक्षा नहीं की गयी तो मुझे आज ओजोन परत में छेद नजर आता है, ये छेद आगे बढ़ेगा और धरती पर प्रलय आयेगा। उन्होंने भी चिंता की और मैं कह सकता हूं कि वीर शिरोमणि अमृता देवी ने प्रकृति की और पानी की रक्षा करने के लिए, उन्होंने कहा कि सिर साठे और पेड़ बचे, तो भी सस्तो जान और उनके नेतृत्व में पेड़ को बचाने के लिए 300 लोग एक ही दिन में शहीद हो गये और पेड़ों को बचाया। ये प्रकृति के साथ बहुत बड़े उदाहरण हैं।

मैं कह सकता हूं कि आज राजस्थान का क्षेत्रफल देश 10.41 प्रतिशत है। राजस्थान में जल की उपलब्धता 1.16 प्रतिशत रही है। अधिकतर ब्लॉक डार्क जोन घोषित हो गये। आम जनता फ्लोराइड पानी पीने को मजबूर है, नाइट्रेट पानी पीने को मजबूर है। जब ये पानी पीते हैं तो बीमारियां होती हैं, कूबड़े और हो रहे हैं। ये हालात हैं, ऐसे हालत में जो हमारा मारवाड़ है, पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में सात वर्षों में, दो वर्षों में अकाल, दो वर्षों में जमारा होता था और पांच वर्ष अकाल पड़ता था। पानी की महत्ता कोई समझता था तो हमारा ये राजस्थान समझता है। हमारे इलाके में तो हम दो टांके रखते थे। दो टांकों में एक में खारा पानी और मीठा पानी। कभी नहीं भूलते थे कि हाथ धोना है तो खारा पानी से और पीना है तो मीठा पानी। पानी का तीन-तीन बार हम उपयोग करते थे। वास्तव में घी सस्ता था और पानी महंगा था। इस प्रकार पानी का सदुपयोग हमेशा किया। उसका संरक्षण किया।

आज मैं कह सकता हूं उस समय के राजतंत्र में जो राजा-महाराजा थे, जैसा अभी सभी सदस्य कह रहे थे, उस समय क्या सोच थी, गंगासिंह जी गंग नहर लेकर आए और हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर का उन्होंने कायाकल्प किया। हमारे यहां भी मारवाड़ में महाराजा उम्मेद सिंह जी ने जवाई बांध बनाया। जवाई बांध से जवाई नहर बनाकर जोधपुर पानी लाए। साथ ही, ऐसे कई बांध बनाएं जिससे पूरे मारवाड़ की पानी की समस्या का समाधान हुआ और आज भी जनता लाभान्वित हो रही है। जैसे सुरपुरा बांध है, पिच्याक बांध है, सरदार सरोवर बांध, तख्त सागर बांध, कायलाना, उम्मेद सागर, मारवाड़ के गांवों में तालाब, कुएं, बावड़ियां, पोखर, नहरें बनाकर पेयजल और सिंचाई के लिए व्यवस्था की थी, जिससे आज जनता लाभान्वित हो रही है।

मैं कह सकता हूं कि आज हम आभारी है और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने पहली बार ये घोषणा की है कि गांव में जितने भी तालाब हैं, जिनका संचालन, संधारण और रख-रखाव पंचायतें करती थीं, अब वहां से बदलकर, हस्तांतरण करके जल संसाधन मंत्रालय में दिया है, जिससे इनकी डी.पी.आर. बनेगी, इनका एक पूरा मास्टर प्लान तैयार होगा। वे तालाब मॉडल के रूप में विकसित होंगे, जिससे जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्स थे, उनका काम इसमें होगा। मैं उनका बहुत-बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही, भारत के आधुनिक निर्माता हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने दो योजनाएं बहुत बड़ी चलायीं। एक तो हर घर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से हर घर में बिजली कनेक्शन और दूसरा

जल से नल और नल से जल, जल जीवन मिशन अभियान चलाकर उनकी मंशा थी कि प्रत्येक घर के अन्दर पानी पहुंचे, इसलिए ये योजना चली।

Ans/rtm 15.40 2n 05.03.2025

मैं दुर्भाग्य के साथ व अफसोस के साथ कह रहा हूं कि जब यह योजना चालू हुई तब काँग्रेस सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय आनन-फानन में काम हुआ। होना यह था कि पूरे विधान सभा क्षेत्र का सर्वे होता, डीपीआर बनती और उस आधार पर योजना स्वीकृत होती, लेकिन अधिकारियों ने कमरे में बैठकर, गूगल सर्च करके योजना तैयार कर दी और योजना ऐसी करी कि सतही जल की योजना तो नहीं बनाई, उन्होंने ओटीएमपी की योजना बनाई, गांव की योजना। गांव में टयूबवैल खोदकर उच्च जलाशय बनेगा, उसमें भरेंगे, उससे ढाणियों में पानी जाएगा, लेकिन वह पानी भी फ्लोराइड था, खारा पानी था, उसकी योजना बना दी। पाइप लाइन गूगल से सर्च करके ले ली। जब डिजाइन हुई, टेंडर हुआ तो जो उच्च जलाशय बना उसकी चारदीवारी बनी, पम्पिंग स्टेशन बना उसमें ज्यादा बजट लग गया तो पाइप लाइन में कटौती कर दी। पाइप लाइन में कटौती करने से वह लाइन वहां गांव में नहीं जुड़ी, जिससे वह वहां भी कम पड़ गया, तो ऐसे हालत कर लिये।

इसके अलावा उन्होंने जानबूझकर राजनीतिक द्वेष भावना से हमारी कई ढाणियों को, राजस्व गांवों को छोड़ दे दिया कि यह गांव हमें वोट नहीं देता, इसलिए इस योजना में शामिल मत करो। पानी में कैसी राजनीति? पानी में भी राजनीति हुई। यही नहीं, उच्च जलाशय जो डिजाइन में स्वीकृत किये थे, सैंक्शन था, स्वीकृत था गांव का और बना दिये वहां से आठ किलोमीटर दूर एक ढाणी में। जहां सैंक्शन था वहां तक की पाइप लाइन ली थी, अब आठ किलोमीटर दूर वह पाइप कम पडी, ऐसे हालात इस योजना में किये। इसलिए, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, कमाई का जरिया बन गया था, कांग्रेस शासन में भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र, घटिया सामग्री के माध्यम से खूब भ्रष्टाचार हुआ है। वास्तव में ऐसे में जांच होनी चाहिए। पानी के मामले में जो जनता की यह हालत करती है..., पानी पीते हैं तो अन्दर से लोग आशीष देते हैं कि भगवान आपका भला करे, उनके पैसे को खाने का काम किया है, आपको उन्हें जेल के सीख़ों के पीछे भेजना चाहिए, आपको यह सख्ताई से काम करना चाहिए।

जल जीवन मिशन पूरे हिन्दुस्तान में चला, लेकिन राजस्थान की हालत यह हुई कि हमारा राजस्थान 33वें पायदान पर था। इसलिए मैं खासतौर से आपको कहना चाहूंगा कि ओटीएमपी की पहली योजना थी, उनको फिर से सतही योजना बनायें। जो भी पाइप लाइन कम पड़ गई, चाहे ओटीएमपी में पड़ी है, चाहे अलग-अलग संख्या बना दी वहां कम पड़ी है, उसके लिए हमने फिर से स्टेटमेंट, पत्रावली बनाकर भेजी है कि अगर आप हमें यह पाइप देंगे तो योजना सुचारु रूप से हो जाएगी लेकिन आज हालत यह है कि कहीं पाइप लाइन लगी है तो एसआर तक नहीं पहुंची, एसआर बन गई तो पाइप लाइन नहीं है। जितना पैसा

लगा है आज जनता को एक परसेंट भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि ऐसी एक कमेटी विधान सभा क्षेत्र में बनानी चाहिए और ढंग से सर्वे करके वापिस सर्वे हो फिर डीपीआर बने। डीपीआर बनकर 2028 तक जो समय बढ़ाया है उस समय के अन्दर हमें पूरे क्षेत्र में, हर घर, हर ढाणी में पानी पहुंचाने का काम इस योजना में करना चाहिए, जिससे जनता आपकी प्रशंसा करें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारी सरकर 2013 से 2018 तक थी। उस समय आदरणीय वसुन्धरा जी के समय ऐसा सिस्टम था कि सब जगह पानी पहुंचता था और हमारे विधान सभा क्षेत्र में तो टैंकर ट्रांसपोर्ट था ही नहीं। कांग्रेस की सरकार पांच साल रही, जगह-जगह, बड़े-बड़े अवैध कनेक्शन हुए और पानी का व्यवसाय हुआ। उस गांव का पानी जाता था, उनके हक का पानी बीच में रोकते और वह ही पानी भरते और उसको 1000-1500 रुपये में बेचने का काम शुरू हो गया, यह उद्योग हो गया। इसलिए मैं खासतौर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हर साल पांच करोड़ का पानी, टैंकर ट्रांसपोर्ट चल रहा है।

मंत्री महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे यहां खूडियाला से आगोले की योजना है, उसमें 25 करोड़ की पाइप लाइन लानी थी, अगर 25 करोड़ की पाइप लाइन आ जाती तो वहां टैंकर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता और हर साल पांच करोड़ खर्च होना बंद हो जाता। यह स्कीम बनकर आ गई, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन यह फाइनेंस में अटकी हुई है, इसकी वित्तीय स्वीकृति बाकी है, आप इसको कराए, मेरा आपसे यह खास निवेदन रहेगा।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ वर्षों से, भैंरोसिंह शेखावत जी के समय से जनता जल योजना चलती थी। पहले पंचायत उसका संचालन करती थी।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): फिर कांग्रेस सरकार में यह जलदाय विभाग के पास आ गई, तो इसमें 436 योजनाएं तो ले लीं, लेकिन उन योजनाओं में पक्षपात हुआ कि यह जनता जल योजना बीजेपी वाले चला रहे हैं, उनको छोड़ दिया, उनका क्या कसूर है, इन योजनाओं को भी आप शामिल करें।

मेरा विशेष निवेदन यह रहेगा कि अवैध कनेक्शन हो रहे हैं, उनके लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा। जैसे डिस्कॉम में विजिलेंस थाना बनाया है, उसी थाने में आप संख्या बढ़ाकर यही थाना विजिलेंस में भी काम लें। मुक़दमे वह दर्ज करें, साथ जाए और उसके साथ-साथ अवैध कनेक्शन काटने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सिस्टम है, पाइप लाइन पर चलेगा, उससे पता लग जाएगा कि कहां पर अवैध कनेक्शन है, आपका विजिलेंस थाना जाएगा, मुकदमे दर्ज करेगा और उस पर कार्यवाही होगी। अगर यह काम नहीं होगा तो अवैध कनेक्शन काटेंगे फिर वापिस होंगे। इसके लिए आपको सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इस पर आप विशेष तौर से ध्यान दे, मेरा खासतौर से निवेदन है।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने और गांव के लोगों ने ओपन वेल बनाये थे, बरसों से उन्हीं से पानी पीते थे, आंधी आने से उसमें कचरा आ गया, मिटटी आ

गई, तो गांव में जितने ओपन वेल बने हुए हैं उनमें सफाई करें। उसका होरिजेंटल व वर्टिकल बोरिंग कराकर, मरम्मत कराकर, सफाई कराकर अगर सोलर पम्प लगा देंगे तो हमारे गांव के ट्रेडिशनल सोर्स थे, वे फिर से चालू हो जाएंगे, जैसे गांव के लोग पहले पानी पीते थे। उससे हमारी समस्या का समाधान होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले पांच साल में यह हालात हो गये कि हमारे हैण्डपम्प खराब हुए, टयूबवेल खराब हुए, ना तो वहां सामान मिलता था और आज भी हालात यही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा 2013-2018 हमारी सरकार थी, उस समय अधिकारियों को कुछ पॉवर दे रखे थे।

श्री सभापतिः अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): एक मिनट। चीफ इंजीनियर को आठ लाख का, एसई को पांच लाख का, एक्सईएन को दो लाख, तो छोटे-छोटे काम उनके स्तर पर हो जाते थे, अगर ऐसा अधिकार दे देंगे तो जो छोटी-छोटी समस्या है, उनका समाधान होगा।

श्री सभापतिः श्री हरीश जी चौधरी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): लास्ट। मंत्री महोदय आपसे हमारा निवेदन है कि जो ई.आर.सी.पी.बनी है, उसी तर्ज पर हमारे मारवाड पश्चिमी राजस्थान के लिए डब्ल्यूआरसीपी की योजना बनाये। मारवाड़ की नहरें, तालाब हैं वे उससे जोड़े। माही का समझौता है उसका पानी..

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए। श्री हरीश जी चौधरी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मारवाड़ को सौभाग्य देने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, धन्यवाद। पानी, जल के संदर्भ में बात करने के लिए मुझे अवसर दिया तो मेरे जहन में आया कि मैं किससे बात करूँ, किस आधार पर बात करूँ। सभापति महोदय, हमारी पीढ़ियों का, पूर्वजों का दर्द इस पानी से जुडा हुआ है, अगर उसको हम लोग अहसास करें तो इससे बड़ा दर्द और तकलीफ हम लोगों के लिए और कुछ नहीं है जो पानी के संदर्भ में हैं। विशेषकर थार में रहने वाले हम लोगों के लिए।

पानी के संदर्भ में इतिहास भी बहुत बोला गया। इस सन्दर्भ में घोषणाएं, नियम, दोषारोपण, प्रक्रिया, आयोजन, सर्वे, डीपीआर, मेरी सरकार, उसकी सरकार, ये तमाम बातें कीं। परन्तु अंत में इस पेयजल के सन्दर्भ के लिए हम लोगों के लिए लक्ष्य क्या रहना चाहिए, लक्ष्य यह हो कि हर घर के अंदर पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, शुद्ध पानी पहुंच रहा या नहीं, हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। अगर हम लोग ईमानदारी से विश्लेषण करें तो हर किसी को पता है, जो राजस्थान को जानता है उसको अच्छी तरह से पता है, सरकार में बैठे लोगों को पता है, हमें पता है, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स को पता है। जल के सन्दर्भ में मेरा मानना है कि हम लोगों का दृष्टिकोण अलग रहना चाहिए, क्योंकि इस समस्या का समाधान हम लोगों के लिए प्राथमिकता के लिए पीढ़ियों से है।

हां, श्रेय आपको जिसको चाहे दें। गंगनहर का श्रेय देने के लिए कह रहे हो, जिसको चाहो दें। हर किसी ने गंगनहर के सन्दर्भ में कुछ ना कुछ योगदान किया है। उस समय इस व्यवस्था के अन्दर जो लोग थे उनको आप श्रेय देना चाहो तो दें, मुझे व्यक्तिगत तौर से इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है, पर वे संसाधन आए कहां से। मेरे मित्र, विधायक ने बात करी, 90 प्रतिशत वह किसानों के खून पसीने की कमाई का हिस्सा, जो भी उस समय की व्यवस्था थी उसमें देकर, 90 प्रतिशत के अंश से वह गंगनहर बनी। लाखों मजदूर हम लोगों के पूर्वज, मजदूरी के माध्यम से वह गंगनहर बनाई।

VPS-RTM-05.03.2025-15.50-2o

अब आप जिसको श्रेय देना चाहो आप दें पर एक शब्द तो अपने पूर्वजों के बारे में अगर बोलते तो शायद मुझे और हमारे पूर्वजों को अच्छा लगता। यह बात सुनते-सुनते मुझे, एक जॉर्ज ऑरवेल ने एक किताब लिखी थी, 1984, क्या हम लोग पूरी की पूरी व्यवस्था उस दिशा में लेकर नहीं जा रहे हैं? जिसको जो इच्छा हो, क्योंकि अगर बात पूरी करेंगे, तार्किक करेंगे तो अंत में इनके पास कुछ नहीं रहेगा, यह जाति और धर्म से उसको जोड़ेंगे तो कम से कम जल के सन्दर्भ में वह मैं कोई मौका, अवसर इनको नहीं देना चाहता हूं वरना मैं उस सन्दर्भ में भी पूरी की पूरी बात करता। हमारे पूर्वज और तमाम इस थार के अन्दर रहने वाले लोग, सिर्फ इस जल के लिए, पानी के कारण अपना घर, अपना परिवार, अपना क्षेत्र छोड़ा। बाड़मेर जिला जिसका मैं निवासी हूं, कोई भी परिवार बाड़मेर का मूल निवासी नहीं है। सब हम लोग बाहर से आये हुए हैं। हर जाति, धर्म के लोग बाहर से आये हुए हैं। सिर्फ पीने के पानी, न्यूनतम पीने का पानी, जिससे हम जिंदा रह सके उसकी खोज में हम लोग संघर्ष करते-करते आज जहां है, वहां पर बैठे हैं। आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरा गांव बायतू है, मेरा विधान सभा क्षेत्र बायतू है पर बायतू हम लोग कैसे पहुंचे? वह सफर आज हम लोग याद नहीं कर रहे हैं। मेरे बायतू का ही नहीं, हर कोई जो थार में रह रहा है, उनकी यही कहानी है। हम प्यासे मरते हुए, हमारे पूर्वज प्यासे मरते हुए, न्यूनतम जिंदा रहने के लिए इस थार को छोड़कर मध्यप्रदेश के उस मालवा इलाके के अन्दर गये, कुछ पाने के लिए नहीं, आज मैं राजनीतिक तौर पर गया हूं तो उस मायने से नहीं, कोई नौकरी के लिए व्यापार के लिए नहीं, अपने आप को जिंदा कैसे रख पाये, उस प्यास को मिटाने के लिए मालवा जाते थे और अपने साथ-साथ उस पशुधन को भी लेकर जाते थे। क्या आज इस पीढ़ी के अन्दर हम लोगों के पास जो सब कुछ पहले से बेहतर हुआ है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वहां तक आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं?

सबसे पहला सवाल यह आता है कि जो एग्जिस्टिंग हम लोगों के पास जो ढांचा है, उस ढांचे को हम लोग कैसे जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, पेयजल के सन्दर्भ में उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हजारों करोड़ रुपये उन स्कीम्स के सन्दर्भ में हम लोगों ने खर्च किये। सरकार, आपकी सरकार, मेरी सरकार, उसकी सरकार, इस देश के अन्दर किसी की सरकार

को, किसी को यह अधिकार नहीं दे रखा है। संविधान के अन्दर मतदाताओं को विधायक और लोक सभा का सदस्य बनाने का अधिकार दे रखा है और जो विधायक बहुमत में हैं, उनको सरकार के अन्दर जो भी सरकार है, वह कैबिनेट है। पांच साल तक जो यहां पर बैठे हुए थे, वे नारे अलग लगा रहे थे। आज पांच साल में आप लोगों की यह मजबूरी है। मैं आपकी मजबूरी जानता हूं। मैं भी आपकी जमात का हूं कि आपको राजस्थान में कोई लाल नहीं दिखेगा, एक ही लाल दिखेगा। हम लोगों को भी राजस्थान में कोई गांधी नहीं दिखता था तो यह मजबूरी भी है इसलिए यह सरकार के सन्दर्भ में बात करते रहते हो, पर यह सरकार, यह जो अपन लोग यहां पर बैठे हैं, अपन लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि उस अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को हम लोग पेयजल पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उसका उत्तर है- नहीं। आप ईमानदारी से देख लें।

आज इस प्रदेश के अन्दर सबसे बड़ा पद किसका है? हमारे यहां इस प्रदेश में, राजस्थान में सबसे बड़ा पद राज्यपाल महोदय का है, हम लोग उनके आगे महामहिम लगाते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदय को भी आप अर्द्ध-सत्य अधूरी जानकारी देकर उनके मुख से, क्योंकि इस पद से बड़ा आज की इस व्यवस्था में कोई पद नहीं है, राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त में उनसे आपने एक उदाहरण दिलवा दिया। आपने उदाहरण दिलवा दिया कि राज्यपालजी अपने विजिट में गये, वे तामलोर गये, बाड़मेर जिले में उस तामलोर के अन्दर जिस व्यक्ति गोविंद सिंह पुत्र झब्बर सिंहजी की ढाणी में गये, तो वहां पर पीने का पानी नल के माध्यम से पानी आ रहा था।

माननीय सभापति महोदय, जब हम लोग यह बात कर रहे थे इस सदन के अन्दर तो उस पड़ोस के अन्दर रहने वाला बिलकुल जिनके पड़ोस के अन्दर ढाणियां हैं, रेशमाराम मेघवाल और हरकाराम मेघवाल, उसके दर्द, तकलीफ का अहसास हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनके जहन के अन्दर, मन में ये बातें हैं। यह बिलकुल पड़ोस की ढाणी है उनकी, बिलकुल पड़ोस की ढाणी, उसमें अभी आज तक, अभी मैं यहां खड़ा हूं जब तक उनके वहां पर पीने का पानी नहीं है। और तो और छोड़ो, जो ग्राम पंचायत तामलोर है, उस ग्राम पंचायत तामलोर के अन्दर भी, माननीय सभापति महोदय, उस तामलोर के अन्दर भी देवलगढ़ और हीरपुरा के अन्दर आज तक पानी नहीं हुआ, उस राजस्व गांव के अन्दर भी। सिर्फ हम लोग बोलने के लिए और सिर्फ दिखाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

हां, सब गलत हम ही हैं। कोई भी इस जल के सन्दर्भ में, बरसात नहीं हो रही है, उसका भी दोष आप देते हो, वह भी लेने के लिए हम तैयार हैं। हर योजना के सन्दर्भ में जो कमी है, गलती है, वह सब हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, पूरा दोषी हम लोगों को बता दो, बना दो, पर जिसको कम से कम न्यूनतम पीने का पानी की जरूरत है, उनको तो वह पानी पिलवा दो। उसका दर्द तो समझ लो, पीने का पानी तो छोड़ो। उसकी हंसी-ठिठोली तो आप लोग नहीं उड़ायें। उस दर्द को समझकर अगर आप अपनी मन मंशा में, माननीय सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं, मैं यह जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इंटेंशन के तौर के ऊपर, मैं इन

दोनों मंत्रियों के इंटेंशन के ऊपर, मेरे जहन के अन्दर बिलकुल कोई भी सवाल नहीं है। चाहे पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर हों या चाहे इर्रिगेशन मिनिस्टर हों, जितना थोड़ा मैं इनको जानता हूं, सैक्रेटरी के तौर पर भी मैं इन दोनों सैक्रेटरीज को जानता हूं, मेरे मन के अन्दर बिलकुल भी जीरो प्रतिशत संशय भी नहीं है, बाकी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की गारंटी नहीं ले रहा हूं कि उनके इंटेंशन सही है या गलत है पर इन चार व्यक्तियों के सन्दर्भ में जो प्रशासनिक तौर के ऊपर और सरकार के तौर पर इन विभागों का नेतृत्व कर रहे हैं, इनके इंटेंशन में कहीं भी कमी नहीं है पर क्या सामूहिक तौर पर हमारी यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम लोग वह जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, चाहे वह हैंडपम्प हैं, ट्यूबवैल हैं, अंडर ग्राउंड वॉटर से बनायी हुई है, सरफेस वॉटर से जो स्कीम्स बनी हुई हैं, सबसे पहले उनकी स्थिति क्या है? क्या वह सब ठीक चल रही हैं? अगर अपन यह आकलन करें कि वह सब ठीक नहीं चल रही है तो हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उनका हम लोग ठीक से कैसे संचालन करें? हमारे पास संसाधन कम है। चाहे आर्थिक संसाधन है, वे भी सीमित हैं, हमारे पास मानव संसाधन भी सीमित है। स्टाफ के सन्दर्भ के अन्दर जो स्थिति है, वह भी पता है कि पहले जो पी.एच.ई.डी. का स्टाफ था, इर्रिगेशन का स्टाफ था, उसमें बहुत बड़ी कटौती हो गयी और उसका सौ प्रतिशत दोष हमें दे दो पर उसमें सुधार हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सवाल का उत्तर तो हमको ढूंढना पड़ेगा और तो कोई नहीं ढूंढेगा। इस लोकतंत्र में वह जिम्मेदारी हम लोगों की क्या है? हम लोगों की, इस सदन की यह जिम्मेदारी है कि उसका हम उत्तर ढूंढें। उसमें संसाधन की कमी नहीं आनी चाहिए, उसमें रिपेयर, मेंटिनेंस अगर करवानी हो तो रिपेयर, मेंटिनेंस करवाइये। अगर कोई बिलकुल भी ठीक नहीं हो सकती तो उसको रिप्लेस करवा कर, पाइप लाइन हो या अन्य हो, उसको हम लोगों को प्राथमिकता से देखना चाहिए।

उसके बाद में जो सबसे ज्यादा चर्चा देश, दुनिया और इस सदन में हो रही है जे.जे.एम. स्कीम की। उस जे.जे.एम. स्कीम के बारे में सबसे ज्यादा मुबारकबाद आपको। पहले बनाने वाले जो इस स्कीम के समय मंत्रीजी थे, मेरे छात्र जीवन में बाबूसिंहजी को पता है, आमने सामने हमने चुनाव लड़ा है, उनको मुबारकबाद। अभी जो मंत्री हैं, जब मैं एम.पी. था, पांच साल बिलकुल बगल में वे नोर्थ एवेन्यू में रहते हैं, उनको मुबारकबाद। जिसको देना है मुबारकबाद दे दो, और कमियां हैं, वे सब हमको दे दो, पर उस जे.जे.एम. जो स्कीम है, उसको समझने की आवश्यकता है। जो जे.जे.एम. स्कीम बनी, कोई भी स्कीम, कोई भी रणनीति शत-प्रतिशत सही नहीं हो सकती, यह भी हमको मानना पड़ेगा। जे.जे.एम. स्कीम को जितना अपन ने समझकर जो पहला कदम अपन ने उठाया सर्वे के सन्दर्भ में, आज सबसे बड़ी त्रुटि उस सर्वे में ही है। आप दोषारोपण दे दो कि भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हैं तो 15 महीने में आप लोगों ने क्या किया? मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा। भ्रष्टाचार का जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वे आप लोगों के पास में ही बैठे हैं, उन्हीं पोजिशन में बैठे हैं, वे ही ठेकेदार हैं, वे सब चीजें अलग हैं क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

माननीय सभापति महोदय, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है L-1, जो L-1 के आधार के ऊपर आपको टेंडर उसी को देना पड़ेगा। या तो इस प्रक्रिया के सन्दर्भ में अपन चर्चा करें जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन L-1 है, इससे निजात कैसे पायें? वह उसके अन्दर बिडिंग के अन्दर कम भी आ जाता है, यह सबको पता है, उसके अन्दर ही उसको यह काम करना पड़ता है और इसके सन्दर्भ में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। कम से कम पेयजल के सन्दर्भ में यह L-1 का जो भी हम लोगों की यह समस्या है, इसके बारे में हम लोगों को समझना चाहिए और हो सकता है, यह ताकत हमारे पास है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। कोरोना के वक्त में जो ताकत हम लोगों के पास थी, लोकतंत्र में उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने परचेज भी की, फैसले भी किये। वह ताकत अन-कांस्टीट्यूशनल ताकत नहीं थी तो यह जो L-1 के सन्दर्भ में मेरा यह निवेदन है कि इसको भी आप लोग देखो।

अब सवाल यह है कि सर्वे में यह कमियां रह गयीं तो सर्वे का सुधार हम कैसे करें? सर्वे और नीचे धरातल के अन्दर बहुत बड़ा गैप है, उसको हम लोग कैसे मेटें? डिविएशन के सन्दर्भ में विभाग पहले ही यह फैसला ले चुका है। विभाग ले चुका है। मंत्रीजी, आप विभाग के मंत्री हो, यह जो भ्रम-भ्रांति फैला रहे हैं कि आप 15 महीने के मंत्री हैं, यह ऑनरशिप लो आप और पीढ़ियों में आगे भी आपको मंत्री के तौर पर ही याद रखेंगे, यह ऑनरशिप लो क्योंकि यह भ्रांति फैलायी जाती है कि, साहब, छोड़ो-छोड़ो, पहले वाले की जिम्मेदारी मत लो। हर उत्तर के अन्दर, हर बात में तो जो डिविएशन का प्रावधान है, उस डिविएशन के प्रावधान से हम लोग जो सर्वे में त्रुटियां हैं, कमी है, उसको हम लोग दूर कैसे करें?

ssy/rtm/05.03.2025/16.00/2p

दूसरा यह कि जो पंपिंग स्टेशन हैं, क्योंकि पहले हम लोगो ने जो इकाई मानी थी वह राजस्व गांवों को इकाई मानी थी, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्व गांव को बनाया, राजस्व गांव बहुत बड़े थे, एक-एक ग्राम पंचायत भी 80 किलोमीटर की थी, उसके संदर्भ में भी मेरा निवेदन है कि वह डेविएसन के बाद में जो यह पंपिंग स्टेशन एडिशनल कहीं करने हैं तो करें।

दूसरा, गाय के संदर्भ में भी हम लोग बहुत बोलते हैं, जय गो माता, पालना छोड़ दिया है पर पूजन और नारों के अंदर तो हम लोगो ने गायों को छोड़ा नहीं। जो प्रावधान था, 40 लीटर इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर इंसान के लिए और 30 लीटर पशुधन के लिए, मेरा दोषारोपण नहीं है, क्योंकि सच्चाई के अंदर आएंगे तो और आपको तेरी-मेरी लगेगी, जिसने भी किया इस रेगिस्तानी इलाके के अन्दर, वह प्रावधान केंद्र सरकार ने तबदील नहीं करके अब सिर्फ 55 लीटर कर दिया है। 55 लीटर हम इंसानों को तो मिल रहा है, जिस गाय को अपन पूजते हैं, उसका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके बारे में भी, मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि आप केंद्र सरकार के अंदर, विशेषकर जो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहां इंसान से ज्यादा पशुधन हमारे यहां हैं, उसके संदर्भ में सैद्धांतिक वहाँ से प्रावधानों में परिवर्तन नहीं

करोगे तब तक यह बढ़ेगी नहीं।

पीने के पानी के अलावा जो आज की स्थिति है, मोहनगढ़ में जो इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पानी आ रहा है, वहां पंपिंग स्टेशन नहीं चल रहे हैं। मैंने कई दफ़ा बोला कि वहां पंपिंग स्टेशन 10 हैं, बिजली के कारण वहां पंपिंग स्टेशन एक, दो चल रहे हैं, जो भी व्यवस्था कर रखी है।

सभापति महोदय, शहर के लिए अलग, गांव के लिए अलग व्यवस्था, क्या यह सही है? अगर सही है तो हम लोग सर्वसम्मति से इसकी स्वीकार्यता कर दें। जयपुर में मैं रह रहा हूं, बाड़मेर में मैं रह रहा हूं, जोधपुर में मैं रहा हूं, पीने के पानी के लिए हमारे कोई भी हक और अधिकारों में कटौती नहीं है। अगर मैं ढाणी में रह रहा हूँ तो सभापति महोदय, 3-3, 4-4 महीने से हम लोगों को पानी नहीं मिला।

श्री सभापतिः बात समाप्त कीजिये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अभी जो एमएलए महोदय, जैसलमेर एमएलए साहब कह रहे थे आईजीएनपी से, आप फैसला कर लो कि 5 साल के अंदर जो पानी के प्रबंधन की व्यवस्था थी, 2 वर्षों के अंदर थी।

श्री सभापतिः श्री रामबिलास जी। श्री रामबिलास जी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): अगर किसानों को सही मिल रहा है, सब कुछ सही है तो बाड़मेर, जैसलमेर के किसान इनसे ज्यादा विश्वास किसी का नहीं करना। महादेव जी का भी नहीं करना।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये। समाप्त कीजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): 000

श्री सभापतिः श्री रामबिलास जी।

श्री रामबिलास (लालसोट): सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 41, 42 पेयजल और सिंचाई की मांग पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, जैसा कि सदन को विदित है कि आदरणीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी के भागीरथ प्रयासों से हमारे राजस्थान में एक जीवन दायनी योजना ईआरसीपी, पीकेसी आई, उसमें गति प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में इस योजना के लिए 9300 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों की घोषणा की। ईआरसीपी कॉरपोरेशन उन्नयन कर राजस्थान का वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन स्थापित किया जाकर, इसके माध्यम से लगभग 4 हजार करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणाएं साफ दर्शाती है कि सरकार इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र धरातल पर लाकर पूर्वी राजस्थान की जनता को लाभान्वित करने के लिए कितनी गंभीर है?

इसी बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र लालसोट में 2 एनिकट की घोषणा सरकार ने की है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री और हमारी वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उदयपुरा में 7 करोड़ और नालावास के लिए 8 करोड़ रुपये के पक्के

डैम बनाने की घोषणा की।

महोदय, इस साल अच्छी बरसात हुई और उसके कारण से मेरे लालसोट विधान सभा क्षेत्र में मोरेल डैम है, जो भरा। उस मोरेल डैम की क्षमता 2707 मिलियन घन फीट है और भरने के बाद ओवर फ्लो में 5363 मिलियन घन फीट पानी बह गया। इस पानी को हमारे लालसोट में दक्षिण बिनोरी सागर, सिंथौली, सूरतपुरा, जो इस डैम से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अगर इस पानी को लिफ्ट परियोजना द्वारा इन डेमों में पहुंचा दिया जाये तो ये दोनों डैम भरें और इनके भरने के बाद में दिवाचली डैम भरे। इसके भरने के साथ-साथ हमारे इस इलाके में 60 से 70 गांवों को पेयजल का फायदा मिले, वहां के जल स्तर में फर्क पड़े और उन गांवों के लिए ये डैम वरदान साबित हों।

माननीय सभापति जी, इस साल हमारे क्षेत्र में पानी के लिए जन आंदोलन हुआ। बारिश के दिनों में जब नदी बह रही थी और यह पानी मोरेल डैम से ओवरफ्लो होकर वेस्ट जा रहा था तो हमारे लोगों में एक जागृति आई और बहती हुई नदी को पांच जगह लोगों ने कच्चे डैम बना के रोका। मैं समझता हूँ, 25 किलोमीटर हमारे लालसोट क्षेत्र में मोरेल नदी और ढूंढ नदी को रोका। जिससे हमारे इलाके में आज की स्थिति यह है कि जहां बिलकुल सूखे कुएं पड़े थे, जो बोरिंग सालों से बंद पड़े थे वह आज सुचारु रूप से चल रहे हैं, वहां पर आज खेती हो रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में राउवास डैम, खारली डैम, सूरतपुरा डैम को ईआरसीपी से जोड़ा जाये। ईआरसीपी के जरिये इनमें पानी पहुंचाया जाये ताकि हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उस समस्या का हमें एक बड़ा समाधान मिले।

जेजेएम की बात करें तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में ईसरदा प्रोजेक्ट के जरिए पाइप लाइन का काम चल रहा है, पर वह इतनी धीमी गति से चल रहा है, मैं समझता हूं आने वाले 7-8 साल तक भी वो काम पूरा नहीं होने वाला। अगर यही हालत रही तो ये पूरा हमारा जेजेएम वाला सिस्टम फेल हो जायेगा। आज उनको आस पास के, पड़ोस के गांवों में बोरिंग करके ट्यूबवेल करके उससे पानी दिया जा रहा है और वो भी सूखते जा रहे हैं। अगर वह पानी सूखता जा रहा है तो वह जेजेएम का सिस्टम भी बंद होता जा रहा है।

दूसरी चीज़, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इसमें कुछ नई योजनाएं हमें लानी चाहिए। एक तो पाइप लाइन हो गयी उसके मेंटिनेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पीएचईडी कहती हैं ग्राम पंचायत इसकी रिपेयरिंग कराएगी, ग्राम पंचायत इन बोरिंगों का बिल जमा करायेगी, हैंडओवर करने के बाद ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत कहती है, हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है। ग्राम पंचायत में पैसा नहीं है। किस मद से उस पाइप लाइन को ठीक कराया जाये? कहाँ से बिजली का बिल दिया जाए? इसके बारे में भी सरकार को विचार किया करना चाहिए।

साथ में, जो इस पाइप लाइन को पीछे डिस्टर्ब करते हैं, लोग बड़े होल करके कनेक्शन ले लेते हैं, उनमें राड, सरिये देकर पाइपों को तोड़ दिया जाता है और उस पानी को सिंचाई के काम में लिया जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ़ भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे तक पानी यह पहुंचना चाहिए। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी कमी है तो पानी की है और हमारे लालसोट के साथ-साथ मैं समझता हूं पूरे राजस्थान में सब जगह पानी की समस्याएं आती जा रही हैं। मैं आज इस मौके पर सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि चाहे हमारे सारे विकास रोक दो।

spp/rtm/05.03.2025/16.10/2q

हमें नहीं चाहिए सड़क, हमें नहीं चाहिए फैसिलिटी लेकिन हमें पानी चाहिए। एक साल सारे विकास कार्यों को ड्रॉप कर देना चाहिए, सारी योजनाओं को बन्द कर देना चाहिए और सरकार को सारा ध्यान केवल पानी पर देना चाहिए। अगर पानी होगा तो हमारा किसान सम्पन्न होगा, पानी होगा तो हमारा इलाका सम्पन्न होगा, पानी होगा तो आने वाली पीढियां सम्पन्न होंगी, पानी होगा तो गांवों में से पलायन होना बन्द होगा, पानी होगा तो पशु सुरक्षित रहेंगे, पानी होगा तो मैं समझता हूं कि हरा-भरा राजस्थान होगा। इसके लिये सरकार को विशेष कदम उठाना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो पानी की योजना है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, इसके लिये पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर तय करना चाहिए कि हमें और सारी मांग बन्द कर दो, सारी छोड़ दो। सारा विकास का पैसा और किसी में नहीं लगाये, हमें कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले अगर राजस्थान को जीने के लिये अगर जरूरत है तो पानी की जरूरत है। इसी के साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 41-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं 42-जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बोलने का मौका दिया, आपका और हमारे लीडर टीकाराम जी जूली साहब का और रफीक साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी बात शुरू करने से पहले एक दोहा सुनाना चाहता हूं-

'रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून
पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून।।'

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मकराना शहर व ग्रामीण इलाके के अन्दर पेयजल का मुख्य स्रोत इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 2010-11 के अन्दर 3 हजार करोड़ की एक योजना बनी थी और उस योजना

के तहत नागौर जिला और अभी हमारा नया जिला बना है डीडवाना-कुचामन, उसके अन्दर पानी का काम हुआ। अभी हाल ही में मकराना के अन्दर सी.डी.एस.-2 के तहत एक हजार करोड़ की योजना और बनी। इसके अन्दर इतनी अनियमितता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह योजना में क्या-क्या अनियमितता है, इस पर बाद में आऊंगा, लेकिन आज गांव और ढाणी के अन्दर 4 हजार करोड़ रुपये मकराना शहर और ग्रामीण में खर्च होने के बाद भी वहां पर पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है और गांव के अन्दर अगर सुबह से शाम तक 20 फोन आते हैं तो उनमें से 18 फोन तो खाली पानी को लेकर आते हैं। इस योजना के तहत हमारे कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। इस योजना के तहत पाइप लाइन नहीं डाली जा रही है। यह योजना बिना मापदण्ड के या नक्शे के विरुद्ध और कहीं ढाणियों में जोड़ी जा रही है तो इस तरह से पानी की बहुत भारी जिले के अन्दर समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत साढ़े 400 MLD पानी की हमारे दोनों जिलों की डिमांड है, वहां पर हमें केवल 250 MLD पानी ही मिल रहा है और मकराना शहर के अन्दर 1900 MLD पानी के स्थान पर मात्र 1200-1300 MLD पानी ही मकराना शहर को मिल रहा है। मकाराना ग्रामीण के अन्दर 22-23 MLD के स्थान पर 14-15 MLD पानी ही मिल रहा है। गर्मियों के दिनों में पानी की मांग सभी जगह पर ज्यादा रहती है, जबकि इस वक्त दो महीने तक नहरबंदी भी रहती है। इस स्थिति में सरकार को विशेष पानी की आपूर्ति के लिये ध्यान रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे PHED मंत्री हैं, यह हमारे नागौर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। हमारे मकराना शहर के अन्दर 8-10 दिन से पानी की सप्लाई होती है और पानी की सप्लाई जब होती है, जब वहां पर रास्ते रोके जाते हैं, जाम होते हैं तब प्रशासन वहां पर काम करने की स्थिति में आता है। कई जगह तो मकराना के अन्दर एक पानी का बिल हजारों रुपये का आया है, जिसमें कई गरीबों के बिल पानी के 20 हजार के बिल आये हैं। मेरे पास बहुत लम्बी सूची है। मैंने मंत्री महोदय से एक बार टेलीफोन पर बात की थी और इन्होंने एक्स.ईएन. को बोला भी था कि इसकी जांच की जाये। 80 रुपये का बिल महीने का आता है, वह 20-22 हजार रुपये के मकराना में काफी जगह घरों के अन्दर बिल आ रहे हैं। जिसके कनेक्शन हैं, नहीं है, डोर टू डोर नाम पूछ लिया और एवरेज बिल के हिसाब से पानी के बिल आ रहे हैं। लाखों लीटर पानी लीकेज के नाम पर बह रहा है। विभाग को शिकायत करते हैं पर सुनाई नहीं देता। बोरावड़ शहर की व्यवस्था शहर के अधिकारियों को दे देनी चाहिये। मकराना के अन्दर बोरावड़ नगरपालिका है। वहां पर पानी की व्यवस्था के लिये रेगुलर विंग को संचालन के लिये दे देना चाहिये क्योंकि बोजड के हिसाब से तो वह लोग इसका काम नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने मकराना शहर के लिये 3 साल पहले 21 करोड़ रुपये की अमृत योजना-2 की एक पॉलिसी बनायी थी। यह योजना अभी तक प्रक्रियाधीन है और स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी यह योजना चालू नहीं हुई है। इसके

अन्दर 110 किलोमीटर पाइप लाइन और तीन पानी की टंकियां बनेंगी। इससे पानी की आपूर्ति होगी। माननीय मंत्रीजी जल्दी से इसका टेंडर या जो इसकी रुकी हुई प्रक्रिया है, उसको आप शुरू कराने की कृपा करें।

पूर्ववर्ती सरकार हमारी थी, मैं 2008 से 2013 में एम.एल.ए. था, कम से कम 350 ट्यूबवैल हमने खुदवाये थे। वह सिंगल फेज के ट्यूबवैल थे और उन ट्यूबवैलों को ग्राम पंचायत के पास रख-रखाव के लिये रख दिया गया। ग्राम पंचायत न तो उसका बिजली का बिल भरती है, ना मोटरें जलती हैं तो उसका काम कराती है और पानी की त्राहि-त्राहि मची रहती है। इसके लिये एक स्कीम बनाकर इन ट्यूबवैलों को आप PHED के अन्दर लेलो। यह खाली मकराना की बात नहीं, पूरे राजस्थान का इश्यू है यह। इससे आप लोगों को पानी का सोर्स मिलेगा। सिंगल फेज सरकार की तरफ से बंद हो गये। टू और थ्री फेज की लागत 19-20 लाख रुपये आती है और यह तीन-चार लाख रुपये के अन्दर खुदे हुए ट्यूबवैल हैं, तो पानी ढाणियों के घर के सामने है लेकिन उसका पानी नहीं पी पा रहे हैं। मंत्री महोदय, इसके लिये आप विशेष तौर से योजना बनाइये।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर RO प्लांट के रख-रखाव की सीमा पूर्ण हो गयी है। यह भी पूरे राजस्थान की समस्या है और मेरे मकराना में 45 RO प्लांट पिछले साल से बंद पड़े हैं और मात्र 18 RO प्लांट ही चालू हैं। इसको भी टेंडर करके RO प्लांट जो चलाने वाला है, उसको आप चालू करवायें।

जल जीवन मिशन के संचालित VWSC/VTC द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इसका कारण समितियों के पास बजट एवं संसाधन नहीं है इसलिए इसका संचालन विभाग द्वारा किया जाये। अभी इसका संचालन ग्राम पंचायत द्वारा कमेटी बनाकर किया जाता है लेकिन उससे बराबर होता नहीं है, तो इसका संचालन आप विभाग को देंगे तो इसका भी अच्छा परिणाम निकलेगा। जे.जे.वाई. व जे.जे.एम. का संचालन विभाग द्वारा कराने का विचार करना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इधर से एक पेपर भेज दूं।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): नहीं-नहीं, पेपर नहीं लिस्ट है। एक मिनट, मुझे और टाइम देना।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य, बाद में मिल जाये तो भेज देना।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): कई ढाणियों और गांवों के अन्दर जो पानी ..(व्यवधान).. (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दो मिनट, आप पेपर ढूंढ लो।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): यह नीचे अन्दर घुस गया शायद। मैं आपको कहना चाहता हूं देवली के अन्दर, जो देवली ग्राम पंचायत है, उसमें पानी की टंकी बनी हुई है, उसको जाखली होते हुए साढ़े छह किलोमीटर की तरफ पानी घुमा-घुमाकर पाइप लाइन डाली जा रही है। अगर बूडसू से सीधा देवली के अन्दर पाइप लाइन डालेंगे तो चार किलोमीटर की

दूरी बनेगी। ..(व्यवधान).. मुझे प्लीज तीन-चार मिनट देना। सॉरी।

jyg/rtm/05.03.25/16.20/3a

श्री सभापति: ...(व्यवधान)... आपस में बात न करें।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): यह सीडीएस टू प्रोजेक्ट में अनियमितता है, बरसेल में पेरेलल डाली गयी पाइप लाइन एक-डेढ़ फुट पर डाली गयी है जो रोज डैमेज होती है। बेसुनी सेवाजी नोजों की ढाणी, घूसो की ढाणी पाइप लाइन 90 एमएम के स्थान पर 50 एमएम की डाली गयी है। ग्राम चाण्डी में एयरटेल टावर से गोशाला तक 90 एमएम के स्थान पर 50 एमएम की पाइप लाइन डाली गयी है, ग्राम खेली शिला और रतनाम वीटीसी में 190 एमएम के स्थान पर 125 एमएम पाइप लाइन डाली गयी है। जहां कहीं भी पाइप लाइन डाली गयी है वहां पर जो सड़कें तोड़ी गयी हैं वो सड़कें भी अभी तक नहीं बनी है। ग्राम मोडी चारणा व रेलियो की ढाणी में एल एण्ड टी कम्पनी द्वारा 90 एमएम की पाइप लाइन डालनी चाहिए थी जिसमें जुबेरी कम्पनी ने 75 एमएम की पाइप लाइन डाल दी है, जिससे जुबेरी कम्पनी का काम सक्सेस नहीं होगा। ग्राम सपेट में रामदेवजी मन्दिर के पास हाईवे नजदीक पाइप लाइन खुले में पड़े हैं। ग्राम दावड़िया में टंकी के पास पाइप लाइन 180 एमएम के स्थान पर 160 एमएम डाली गयी है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, ग्राम वीटीसी के पास 140 एमएम के स्थान पर 125 एमएम की पाइप लाइन ही डाली गयी है। एल एण्ड टी कम्पनी द्वारा टंकियों का पूरा काम, जीपीएस सिस्टम, सीढ़ियां एवं सफाई आज दिनांक तक नहीं हुई है। एल एण्ड टी कम्पनी ने चोयल एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी को ठेका दे रखा है।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह जी भायल।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): कम्पनी में मात्र 40-50 कर्मचारी ही कार्यरत हैं व भुगतान 89 कर्मचारी उठा रहे हैं, ...(व्यवधान)... माननीय मंत्रीजी, इन सबकी जांच कराइये। मैं कई बार कलेक्टर साहब को बोल भी चुका हूं। धन्यवाद।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 व 42 पेयजल व नहरी पानी पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ की धरती में अभी हमारे मारवाड़ से ही शेरगढ़ से और बायतु से आने वाले माननीय सदस्य पानी के बारे में सारी चीजें बता रहे थे। वास्तव में वहां पानी की दिक्कत है, पानी की कमी है। पानी के लिए वो क्षेत्र एक दूसरे के, जनता के लिए मजबूर आदमी, कोसों दूर से पानी लाया जाता है। बरसाती जल को पूरे साल तक संयोये रखने में, मीठा पानी मात्र बरसात का ही है, जनता एक दूसरे का सहयोग भी करती है। मारवड़ की धरती में थोड़ा पानी होने पर भी बराबर उपयोग करते हैं। एक कहावत है, थोड़ा पानी देखकर, एक दूसरे को पीने की मनुहार करके प्राण तक त्याग दिया जाता है, यह

घटना रेगिस्तानी क्षेत्र की है। वहां पर पानी को सोने से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। वहां कहा जाता है,

जल थोड़ो, नेह घणो, लाग्यो प्रीत तो भाण,

तू पी, तू पी कैवता, दोनों तज्या प्राण।

यह मारवाड़ में और रेगिस्तान में पानी की महती आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, जो भी स्कीम जनता के लिए बनती है पर समय पर उसकी क्रियान्विति नहीं होने, डीपीआर समय पर नहीं बनकर, जैसे जल जीवन मिशन की बात चल रही थी, इसमें जल जीवन मिशन में कई ढाणियां, कई मजरे, कई घर, कई मोहल्ले वंचित रह गये। जीएलआर बन गयी, पानी अभी तक नहीं पहुंचा। जैसे मेरे बाड़मेर जिले में, अभी बालोतरा जिले में सिवाना तीन स्कीम से जुड़ा हुआ है। पोकरण-फलसूण्ड, बिलिया-संतरा भाखरी वाली लाइन और उम्मेद सागर-धवा और नर्मदा से, नर्मदा वाला पानी आज तक 20 गांव जो जुड़े हुए हैं उनका ऑफिस, जायका का ऑफिस नागौर में है, 400 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो डीपीआर ओनली पेपर में बनी है, आज दिन तक कोई पानी पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पोकरण-फलसूण्ड वाली योजना अभी बायतू से आने वाले विधायक महोदय बता रहे थे और यह हकीकत है कि बिलिया से संतरा भाखरी लाइन के लिए वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से पानी की पम्पिंग नहीं होती है, दो-दो, तीन-तीन महीने तक पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी की चोरी तो हो रही है, इनके साथ में उम्मेद सागर-धवा की लाइन की भी यही की यही हालत है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा, माननीय मंत्रीजी, कि अच्छा बजट देकर सरकार ने पेयजल के लिए जो कोशिश करने की जो महती आवश्यकता पर जोर दिया है लेकिन इन क्षेत्रों में व्यवस्था किस तरीके से अपन कर सकते हैं कि एक ढाणी और मजरे तक, गांव तक पानी पहुंचे। जैसे आपने योजना में 755 करोड़ रुपयों से भी अधिक का प्रावधान कर जनता को राहत प्रदान की है। राजस्थान के इतिहास में पेयजल के लिए सबसे बड़ा बजट साथ ही शहरी क्षेत्र में भी 5 हजार करोड़ से अधिक का बजट निर्धारित करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल के लिए प्रावधान किया है। भिन्न-भिन्न स्थानीय निकायों में अमृत 2.0 योजना में कई शहरों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए भी बजट निर्धारित किया है। इसमें मेरे सिवाना में भी अमृत 2.0 में 15 करोड़ रुपये दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, नव सृजित नगरपालिका सिणधरी में भी शहरी क्षेत्र में जोड़ते हुए इसमें भी अमृत 2.0 का बजट प्रावधान करके वहां भी पीने के पानी की आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। एक बड़ी आवश्यकता पीने के पानी की योजना पोकरण-फलसूण्ड-बायतू, इस योजना का अभी तक गांवों तक इतने साल से एसआर तो बन गयी, पाइप लाइनें गांवों तक कई जगह डल गयी, एसआर बनी हुई पड़ी हुई है वो भी सात साल, आठ साल हो गये, उसमें आज दिन तक एक बूंद भी पानी गया नहीं है, इसको हम किस तरीके से 2004 से 2010 में पूरा होना था आज 2025 चल रहा है, मेन पावर निर्धारित

करके इसको जल्दी से जल्दी करवाने के लिए अपन कोशिश करेंगे तो जनता को पानी मिल सकेगा, वरना बड़ी मुश्किल है।

अभी मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, माननीय मंत्रीजी को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को और वित्त मंत्रीजी को कि 20 हजार का मूण्डली के पास में एक हैण्डल पोइंट बनाने के लिए आपने बजट में प्रावधान किया है। इसके साथ ही सिणधरी की तरफ जो लाइन जा रही है वो कालूडी, भूगा भगतसिंह और शोभावास में एक हैण्डल पोइंट वन डे स्टोरेज बनाकर अपन उस लाइन के लिए पीने के पानी की योजना को थोड़ा-बहुत अमली जामा पहना सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ये योजना जैसलमेर जिला बिलिया से बहुत लम्बी लाइन होने की वजह से इसमें मेरे सिवाना लाइन को अगर जैसे रिफाइनरी को अलग लाइन दी है उसी की तर्ज पर सिवाना के लिए नई डीपीआर बनाकर अगर लाइन का प्रावधान अपन नहीं करेंगे तब तक, माननीय मंत्रीजी, सिवाना की जनता को मीठा जल पीने के लिए नहीं मिल सकता। बिजली वॉल्टेज के कारण, अभी दो महीने हुए हैं, पूरा बालोतरा क्षेत्र, सिवाना क्षेत्र जहां पोकरण-फलसूण्ड से पानी आ रहा है, वो वॉल्टेज नहीं मिलने की वजह से पानी पम्पिंग नहीं हो रहा है। तो आज भी बंद पडा है। विभाग में कर्मचारियों की कमी है, रिटायरमेंट होते गये, नये कर्मचारी अपन भर्ती नहीं कर पाये इसलिए उनकी भर्ती करने की भी अपन व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि ओ एण्ड एम स्कीम स्वीकृत करवा कर खण्डवार कार्य कराया जा सके तो सुपरवीजन में छोटा-मोटा काम हो सकेगा। हैण्डपम्प है, पुराने कुएं हैं, जल स्रोत हैं, पानी बरसात कम होने की वजह से एक समय था कि सिवाना बाड़मेर का कश्मीर था, हजारों-लाखों बीघा में खेती होती थी, अब पीने के लिए भी पानी कमी हो गयी है। समदड़ी मुख्यालय पर सहायक अभियंता, जलदाय विभाग का पद सृजित कराने की कृपा करावें और उम्मेद सागर-धवा के लिए भी जैसे जोधपुर में एक स्टोरेज बनाकर जो किया है, उम्मेद सागर-धवा-समदड़ी के लिए भी एक स्टोरेज बनाकर वहां पर पानी की व्यवस्था कराने की कृपा करावें।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, सिवाना सिणधरी खण्ड को नलकूप और हैंडपम्प के लिए वहां एक क्षेत्र ऐसा है कि कई जगह पानी है तो वहां पर ज्यादा हैंडपम्प दे देते हैं, नलकूप स्वीकृत कर देते हैं तो भी गर्मी में सहारा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि खराब पड़े सोलर नलकूप, आरओ प्लांट को सही करवाकर राहत दी जा सकती है। सिणधरी क्षेत्र में खराब पड़े हैंडपम्प, प्लांट और सोलर नलकूपों के लिए विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। सिवाना, सिणधरी खण्ड के लिए सबसे अहम जो स्कीम नर्मदा है, नर्मदा से जो 20 गांव तो अभी जायका के माध्यम से जुड़े हुए पड़े हैं पर नजदीक वो ही एक पीने के लिए पानी है तो

बालोतरा और सिणधरी और सिवाना के गांवों को पीने के लिए नर्मदा से स्कीम बनाकर, डीपीआर बनाकर उसका पानी सिणधरी होते हुए लेते हैं तो ही ये कागजों में सिर्फ ड्राइंग बनी हुई है, अपन इसको धरातल पर उतार कर करेंगे तो आने वाले समय में सिवाना को पेयजल उपलब्ध हो सकता है।

MLS/RTM/05.03.2025/16:30/3b

एक जो बाड़मेर लिफ्ट के नजदीक गांव हैं, अगर 15-20 गांव नजदीक लग रहे हैं, वह बिलकुल 2 किलोमीटर पर पानी आया हुआ है तो उन गांवों को पीने के लिए पानी अपन वहां से भी दे सकते हैं। सिवाना पेयजल स्कीम उम्मेद सागर-धवा का मैंने आपको निवेदन कर ही दिया। स्टोरेज बना दिया जाये तो इसमें थोड़ा बैनिफिट हो सकता है।

केन्द्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय से प्रदेश सरकार द्वारा मेरे क्षेत्र में स्पेशल सर्वे करवाकर बरसाती जल के संरक्षण को लेकर एक डीपीआर बनायी जाये तो भविष्य में मेरा क्षेत्र पानी के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो सकता है। वन भूमि ज्यादा होने की वजह से कैम्पा फंड में अगर वन विभाग को पैसे देकर चैकडैम बनाया जाये, जो अरावली श्रृंखला से पानी नीचे उतर रहा है, उसको रोका जाये तो पीने के पानी की समस्या दूर की जा सकती है।

पंचायत समिति के गांव कर्मावास, सेवाली, सिंयाली, कर्मों का बाड़ा, रातड़ी, अरथंडी, खंडप, सरवड़ी, गोलिया, राखी तथा पूर्व में पाली जिले के बांध हेमावास अन्य गांवों से सिंचाई के लिए पानी देने को लेकर योजना प्रस्तावित थी। आज भी पाली और जालोर जिले के गांवों को नहरी पानी देने के बाद जो शेष पानी बचता है, वह वेस्ट हो रहा है, आज भी बेकार पडा है। वह पानी उपरोक्त गांवों के हिस्से में दिया जाये तो सिवाना क्षेत्र में भी पीने के पानी और खेती करने के लिए पानी, दोनों का समाधान निकल सकता है। जल संसाधन विभाग को दिशा-निर्देश जारी कर मेरे क्षेत्र के गांवों में सिंचाई हेतु पानी दिया जाना प्रस्तावित किया जाये।

प्रदेश में राम सेतु योजना, जो ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान में बनी है, इसके आधार पर पश्चिमी राजस्थान में अगर डब्ल्यूआरसीपी बन जाती है तो रेगिस्तान के गांवों को पीने का पानी मिल जाये, खेती बरसात में भी कर लेंगे, पर पीने का पानी जब तक नहीं मिलेगा तो गर्मी में बड़ी विसंगति रहेगी, बड़ी तकलीफ रहेगी। जैसे वन्य क्षेत्र भाखरड़ा बैल्ट, हल्देश्वर महादेव से लगाकर कैम्पा फंड में एक बार स्कीम में सैंक्शन भी हुई थी, इसकी डीपीआर बनाकर छोटे-छोटे बांध, एनिकट अगर बन जाएं तो लोगों को काफी राहत मिल सकती है। पीने के पानी की राहत मिलेगी तो सब होगा। ये छोटे बांध हैं, तटबन्दी, जिसमें मवड़ी, सिनेर, अन्नपूर्णा नगर, भाखरपुरा, नालगुढा, फूलन, धारना, सेला, धीरा, डंडाली, कांकी, मूठली, महनी, तेलवाड़ा, भागवा, जिनपुर, मुबारी, देवंदी, गोड़णा, इंद्राना, हरजियाना, कुसीप, थापन, तो इनमें छोटे चैकडैम बन जाएंगे तो पीने के पानी की समस्या भी हल होगी और पानी रुकेगा तो बरसात में कुछ सहारा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, उम्मेद सागर-धवा-खंडप योजना के लिए जो जोधपुर से सीडब्ल्यूआर बनी थी, वह सिर्फ जोधपुर के लिए ही बनी, जिसमें कई लाइन और जुड़ गयी हैं। इससे पानी स्टोरेज की कमी, पानी की साफ-सफाई और पानी की शुद्धता में भी समस्या आ रही है। जोधपुर में उम्मेद सागर-धवा-समदड़ी-खंडप योजना के लिए अलग से एक नयी सीडब्ल्यूआर निर्माण की आवश्यकता है, जिससे समदड़ी क्षेत्र को पीने के लिए पूरा पानी मिल सके।

श्री सभापतिः विराजें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री यूनुस खान।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आय-व्यय अनुमान वर्ष 2025-26 की सेकंड स्टेज में अनुदान मांग संख्या 41 और 42 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से सबसे पहले छप्पनिया अकाल को याद करते हुए महाराजा गंगासिंह जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने इस राजस्थान के लिए क्रान्ति की शुरुआत की और आज वे हम सबके लिए पूजनीय हैं। उनके साथ-साथ में, जो उस समय के हमारे इंजीनियर थे कंवर सेन गुप्ता जी, उन्हें भी श्रद्धांजलि के साथ धन्यवाद दूंगा कि ऐसे व्यक्ति ने एक प्लान बनाया, जिसके माध्यम से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बनकर आयी। इससे पहले जो गंगासिंह जी थे, उन्होंने गंग नहर निकाली और जो प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जो आज लगभग 649 किलोमीटर लम्बी परियोजना है।

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, एक हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री हैं माननीय चौधरी साहब, दूसरे मंत्री जल संसाधन मंत्री हैं, दोनों सक्षम मंत्री हैं, दोनों के पास बहुत अच्छी टीम है। उम्मीद है कि अगले चार वर्षों में ये अपनी टीम के साथ राजस्थान की पीने के पानी की समस्या का समाधान करेंगे।

सभापति जी, हमारे राजस्थान की बहुत सारी सन्धियां हुईं, जिनमें विशेष रूप से राजस्थान और पंजाब की हमारी जो सन्धियां हुईं, मैं उनकी ज्यादा लम्बी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि 1920 में जो सबसे पहली सन्धि की महाराजा गंगासिंह जी ने, उसके बाद में सतलुज और रावी-ब्यास का जो पानी हमारे राजस्थान में हरिके बैराज के माध्यम से पहले गंग नहर में गया और उसके बाद में इन्दिरा गांधी नहर में आया।

सभापति महोदय, इस इन्दिरा गांधी नहर में, जो हमारे वर्तमान में लगभग 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और चूरू, इनमें तो सिंचाई और पेयजल दोनों जाते हैं, लेकिन मात्र पेयजल जो है हमारे जोधपुर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा तथा बाड़मेर में है। ये 13 जिले हैं। हम जहां आते हैं,

अभी हमारे से पूर्व वक्ताओं ने बात कही, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पीने के पानी की बात कही, मैं सिर्फ पीने के पानी की बात कहूंगा।

मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धरा जी को कि उन्होंने 4 हजार करोड़ की परियोजना बनाकर दो स्टेज में जो हमारा अखण्ड नागौर था, उसको पीने का पानी दिया, जिसमें मकराना, डीडवाना भी आता है। उसमें डीडवाना क्षेत्र के अन्दर लगभग हमारे को पानी मिलना था 40 एमएलडी, जो माननीय मंत्री जी के नोटिस में है। मैं माननीय मंत्री जी का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वे हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, शायद हमीर सिंह जी भायल साहब, हमीर सिंह जी भायल साहब, थोड़ा निवेदन कर रहे हैं, सर, मेरा आपसे निवेदन है, वे हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं। हमें उनके अलावा, एक तो पीएचईडी के मिनिस्टर हैं, एक हमारे प्रभारी मंत्री हैं, उसका हमें लाभ मिलना चाहिये और जो हमारे हिस्से का पानी है, वह बारूपाल कैनाल से जो हमारे जोधियासी, जायल, नोखा, डीडवाना तक आता है, वह पानी हमें मिलना चाहिये।

मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक तो उसमें दो-तीन छोटी-छोटी समस्याएं हैं, जिनके बारे में मैं आपके माध्यम से कहूंगा। एक तो उसमें जायका का जो प्रोजेक्ट है, जो एल एंड टी ने किया, उसमें ग्राम पेयजल स्वच्छता समितियां बनी हुई हैं। वे समितियां मौलासर और डीडवाना, दो पंचायत समितियां हैं, उन दोनों में से सिर्फ मतलब आप देखिये एक ग्राम पंचायत में वह समिति बनी हुई है। इस पर आप पुनर्विचार करके आगे बढ़ें। दूसरा, एक हमारा रेट्रोस्पेक्ट फिटिंग वर्क का लगभग 34 नये गांव और 240 ढाणियों का एक प्रोजेक्ट 2022-23 के बजट का पडा है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान कर लें।

तीसरा, हमारे हिस्से का पानी दे दें। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर का पानी जो हमें मिलना चाहिये था हरिके बैराज में, पंजाब से सतलुज, रावी और ब्यास का, वह पानी हमारा हिस्सा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि भैरोंसिंह जी के समय से लेकर आज माननीय भजन लाल जी के समय तक लगातार राज्य सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन वह हमारा 0.60 एमएएफ पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा जो मूल समझौता था, वह 8.60 एमएएफ का था, जिसमें से 0.60 एमएएफ पानी आज भी हमें नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि उस समझौते को लागू करवाने की कोशिश करे।

जो 204 किलोमीटर का फीडर है हमारा, जो आज क्षतिग्रस्त हो गया, उस क्षतिग्रस्त फीडर को भी रेनोवेट कराने का काम करें, क्योंकि उसका केन्द्र सरकार का भी पैसा पड़ा है, राज्य सरकार का भी पैसा पडा है, लेकिन पंजाब उसमें काम नहीं करने दे रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कितनी सच्चाई है, जब भी हम बात करते हैं तो अधिकारी लोग यह कहते हैं कि, साहब, वहां दिक्कत आ रही है तो मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि वह 204 किलोमीटर का हमारा फीडर है, उसका भी सुधार करें और जो हमारी मुख्य नहर है, जिसमें हमारा नोखा दरिया में पानी आता है, वहां तक जो ड्रिंकिंग के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको उनका

हिस्सा मिल जाये। यह मेरा आपके माध्यम से कहना है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इंटर-स्टेट के जितने समझौते हुए हैं, उनमें आज एक भी समझौता ऐसा नहीं है जो हमारा राज्य लागू करवा सका हो। 1920 से अगर हम शुरू हों और लास्ट में अभी ईआरसीपी की चर्चा चलती है, हमारे यहां पर यमुना की भी चर्चा चलती है, ये तो बाद के विषय हैं, अगर हम उनका भी जिक्र करें तो 12 जुलाई 1994 से यमुना की बात चल रही है, क्योंकि मेरा जिला सीकर यमुना से प्रभावित क्षेत्र में आता है और मैं जहां से चुनाव लड़ता हूं, वह आता है इन्दिरा गांधी नहर के सतलुज, रावी औ ब्यास के उसमें।

MKD/RTM/05.03.2025/16:40/3c

रावी, ब्यास, भाखड़ा का जो मैनेजमेंट बोर्ड है। केन्द्र में सरकार है, माननीय मंत्री आप उनसे बात करके कम से कम अपना एक स्थायी मैम्बर हो, उसकी तो नियुक्ति करवायें जिससे हमें हमारी बात कहने का तो मौका मिला। जबकि हमारे इसी राज्य से एक व्यक्ति केन्द्र में जल संसाधन विभाग का मंत्री रहा, लोग उनसे उम्मीद करते थे, जोधपुर के लोग भी उम्मीद करते थे, बाड़मेर के लोग भी उम्मीद करते थे, जैसलमेर के लोग भी उम्मीद करते थे और राजस्थान की जनता भी उम्मीद करती थी कि आज हमारा मंत्री बना तो कम से कम राजस्थान के हितों की रक्षा करके मैनेजमेंट बोर्ड में हमारा मैम्बर लगा दे। न हमारा कोई मैम्बर लगा, न हमारे हितों का पानी मिला।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है, माननीय दोनों मंत्रीगण बैठे हैं, तालमेल बिठाकर सरकार काम करना चाहती है, हम भजन लाल जी सरकार पर कोई शंका व्यक्त नहीं कर रहे हैं, काम करना चाहती है, लेकिन काम की गति जो है, इनके 14 महीने तो खत्म हो गये, जो शेष टाइम बचा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि डीपीआर बनते-बनते टाइम लगेगा, फिर टेंडर होंगे, टेंडर में वर्क ऑर्डर होगा, फिर लोग कोर्ट चले जाएंगे, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा तो समय बहुत सीमित है। इसको गतिशील बनाकर तेज गति से काम करने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि 1981 में जो रावी, ब्यास का समझौता हुआ था, उसमें जो हमारा हिस्सा मरा, अभी भी हमें उस हिस्से का तो पानी नहीं मिल रहा है, वह तो अलग है, लेकिन 7.59 एमएएफ पानी जो मिल रहा था, वह भी आज की तारीख में, मैंने कल ही वहां आंकड़े देखे हैं, वह पानी भी हमें नहीं मिल रहा है।

राजस्थान के जितने इंटर-स्टेट समझौते हैं, चाहे वो समझौता हमारा मध्य प्रदेश के साथ हुआ हो, जवाहर सागर डैम का हो, राणा प्रताप सागर डैम का हो, कोटा बैराज, चम्बल का हो या फिर राजस्थान पंजाब के बीच में भाखड़ा, पौंग, हरिके बैराज, गंग कैनाल, आईजीएनपी और उसके अलावा गुजरात से जो माही डैम का पानी आना था।

माननीय सभापति महोदय, उसमें भी आप सबको पता है, आज क्या स्थिति है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हुआ नहीं और वह सारा पानी गुजरात में रह गया। आज हम गुजरात

से वह पानी लेने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, जो समझौते हमारे हुए, उन समझौतों को लागू करवाने के लिए विशेष रूप से टास्क फोर्स बनाकर राज्य सरकार को काम करना चाहिए।

मैं आपको कहूंगा राजस्थान और हरियाणा का जो समझौता हुआ, जिसमें आपका हथिनी कुंड बैराज का, ओखला हैड वर्क्स और नोहर सिद्धमुख की बात चलती है, मेरे से पहले आने वाले बहुत सारे सदस्यों ने भी यह बोला, माननीय सभापति महोदय, वे समझौते भी लागू नहीं हो रहे हैं। इसलिए, जो इंटर स्टेट रिवर एग्रीमेंट्स हैं, उन एग्रीमेंट्स पर राज्य सरकार गम्भीरता से ध्यान दे।

विशेष रूप से, जिस तरह से बार-बार ईआरसीपी की बात करते हैं, उसी तरह से ईआरसीपी से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यह पश्चिमी राजस्थान के 13 जिलों का, जिसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार आने वाले समय में अन्तरराज्यीय समझौतो को लागू करवाने के लिए अथक प्रयास करेगी।

अभी मैं मिनिट्स देख रहा था। माननीय सभापति महोदय, मिनिट्स में बहुत सारी जगह तो हमारी मीटिंग्स भी नहीं हो रहीं हैं और राज्य हमें तवज्जो ही नहीं देते हैं, क्योंकि वे अपर स्ट्रीम में हैं, अपन लोअर स्ट्रीम में हैं। लोअर स्ट्रीम का स्टेट होने के नाते हम हमेशा घाटे में जाते हैं। हमारे इस घाटे की पूर्ति, क्योंकि इंटर स्टेट एग्रीमेंट्स हैं और उनके माध्यम से भारत सरकार का संरक्षण है, अपन कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो इस डबल इंजन की सरकार से राजस्थान को उसका हक मिलना चाहिए, खाली भाषण तक डबल इंजन नहीं रहना चाहिए। भाषण से बाहर आकर राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा के लिए यह सरकार काम करे। यही उम्मीद करते हुए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अंशुमान सिंह भाटी।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं मांग संख्या 42- जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

भारत की एक तिहाई आबादी के पास स्वच्छ पेयजल नहीं है। हर साल तकरीबन 15 लाख बच्चों की मृत्यु गन्दे पानी के कारण होती है और हिन्दुस्तान की 42 प्रतिशत नदियां आज खतरे के स्तर से ज्यादा दूषित हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत हिन्दुस्तान में निवास करता है व उनके पास कुल विश्व के पेयजल का मात्र 4 प्रतिशत है। जबकि हमारे बराबर जनसंख्या वाले चीन के पास यही आंकड़ा 6 प्रतिशत का है।

हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान की 8 करोड़ की जनसंख्या के लिए यह पेयजल संकट और भी गहरा है। हमारे यहां पर विश्व का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान मौजूद है, जो कि पूरे विश्व का सबसे घनत्व वाला रेगिस्तान है, जहां पर राजस्थान की तकरीबन 40 प्रतिशत आबादी निवास करती है।

2022 में आए नेशनल कमीशन फॉर वूमन की एक रिपोर्ट के आधार पर इस थार रेगिस्तान में पानी संचय करने हेतु कुएं एवं बावड़ियों के पास से हमारी महिलाएं जल लेकर आती हैं, उनको साल में औसतन 14 हजार किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ता है। अब आप कल्पना करिये, प्रतिदिन दस से बीस लीटर का सिर पर घड़ा लेकर चलना और वह भी 40-40 किलोमीटर तक के लिए। अगर वह तीन साल लगातार यह सफर करे तो वह निश्चित रूप से पूरी धरती की एक पूरी परिक्रमा कर लेगी।

पिछले 70 सालों में हमारे राजस्थान के अन्दर 40 से अधिक सूखे पड़े। पिछली सदी में राजस्थान के थार की जनसंख्या 500 प्रतिशत से बढ़ी है और साथ ही जितना हमारा पशुधन है, 130 प्रतिशत बढ़ा है। निश्चित रूप से जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे जल हो, चाहे कुछ और हो, उस पर भारी दबाव पड़ रहा है। जिस प्रकार से हम सतही जल और भूजल का दोहन कर रहे हैं, उससे हमारे भूजल का स्तर नीचे जा रहा है और नलकूप भी लगातार सूखते जा रहे हैं और कहीं न कहीं हम हमारे जितने भी पारम्परिक जल स्रोत हैं, उनकी तरफ भी उदासीन है और निश्चित रूप से यह संकट और भी गहराता जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान साउथ अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन की तरफ ले जाना चाहूंगा, जिसकी जनसंख्या पूरे जयपुर की जनसंख्या के बराबर है। यहां पर पुराने टाइम में 6 बांधों से पेयजल की आपूर्ति हुआ करती थी, परन्तु वहां मानव के कुप्रबन्धन, लालच व प्रकृत्ति का सम्मान नहीं करने के कारण से आज यह हाल है कि वह विश्व का पहला जलविहीन शहर कहलाया गया है। वहां पर आज भी इमरजेंसी जैसे हालात हैं। जिस शहर को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 235 लीटर पानी वहां मिलता था, आज की तारीख में कतारों में लग-लगकर एक आदमी को एक दिन में मात्र 25 लीटर। माननीय, एक बाल्टी जितना पानी उनको मिलता है, तो निश्चित रूप से यह स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। हिन्दुस्तान के बैंगलोर में भी यही हाल है और कहीं न कहीं जिसको अपन हॉलीवुड कहते हैं, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य के अन्दर भी 2 हजार फीट तक भूजल है, वहां खत्म हो चुका है और सूखे के कारण वहां आये दिन आगजनी की घटनाएं और जंगल में आग देखने को मिलती है।

किसी समय में हमारा यह थार रेगिस्तान भी हरा-भरा हुआ करता था। यहां पर आपकी सतलुज की शाखाएं, इंडस, घग्घर, सरस्वती नदियां बहा करती थीं और आठ हजार साल पहले यही क्षेत्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जैसी सभ्यताओं का केन्द्र बना। परन्तु समय बदलता गया, भौगोलिक परिस्थितियां बदलीं और नदियों ने खुद की दिशा बदली, उसी के साथ यह क्षेत्र फिर से सूखने लगा। रेगिस्तान का विस्तार हुआ और आज यहां पर थार रेगिस्तान है, परन्तु इसके बावजूद जो भी हमारे पूर्वज थे, वे लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने खुद का कभी स्थान नहीं छोड़ा और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पुराने ज्ञान, अनुभवों को आगे बढ़ाते हुए, स्थानांतरित करते हुए एक सुव्यवस्थित अत्यधिक प्रभावी प्रणाली स्थापित की। जल संचय एवं संरक्षण हेतु आजमाई एवं प्राकृतिक व मानव निर्मित पारम्परिक प्रणाली व

संरचनाएं जैसे कुएं, जोड़, पायतन, बावड़ी, बैरी, टोबा, तालाब आदि से हमने हमारे सीमित प्राकृतिक संसधानों का उत्कृष्ट प्रबन्धन व संरक्षण किया, जिससे यह थार रेगिस्तान दुनिया का एक मात्र जीवित रेगिस्तान कहलाया गया है।

हम लगातार हजारों वर्षों से इस रेगिस्तानी इलाके में न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि हमारा जल प्रबन्धन दुनिया में सराहा गया है। यह थार रेगिस्तान कोई आम रेगिस्तान नहीं है, यह संघर्ष साहस का प्रतीक है। थार ने हमें यह भी सिखाया कि कैसे मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प, इच्छाशक्ति के साथ समाज और प्रकृति को एक दूसरे का पूरक बना सकता है।

हमारा राजस्थान का काल से एक बहुत पुराना नाता रहता है। जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने बात रखी, छपनिया अकाल संवत् 1996, मतलब सन 1899 के अन्दर हमारे यहां छपनिया अकाल पड़ा, इस त्रिकाल के अन्दर हमने अन्न काल भी देखा, जन काल भी देखा, तिन काल भी देखा। उससे ज्यादा भयानक शायद ही राजस्थान के इतिहास में कोई काल आया हो। राजस्थान के थार की तकरीबन एक चौथाई जनसंख्या काल को प्राप्त हुई और इन तीन सालों के अन्दर जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने यातनाएं सहन की होंगी, अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।

उदाहरण के तौर पर, जो हमारी खेजड़ी होती है, उसकी छाल को, छोडे को उतारकर, उसको पानी के अन्दर उबालकर उसका रोटी की तरह हमने सेवन किया। जो हमारे कांटेदार भूरट होते हैं, उसको हाथों से साफ करके घट्टी में पीसकर आटा बनाकर उसकी रोटी हमने खाई। इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि किस विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे पूर्वजों ने इस थार रेगिस्तान में जीवन को स्थापित रखा और संरक्षित भी रखा।

Bhs/Rtm/05.03.25/16.50/3d

मैं मोटी बात यह कहना चाहूंगा कि 8000 साल से जो चलती आ रही फूलप्रूफ व्यवस्था थी उसको कहीं न कहीं जो पूरी दुनिया में मिसाल बनी उसको छोड़ कर हम आज कहां पहुंच चुके हैं। मैं आज भी दावे से कह सकता हूं कि इस रेगिस्तान के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर राजस्थान के अंदर अंतिम छोर पर बैठे हुए किसी भी किसान को किसी भी ग्रामीण को पूरे उसके हिस्से का पानी नहीं पहुंच पा रहा है और हम गोदी वाले को छोड़कर आज पेट वाले की आस कर रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हुए उन देशों को फॉलो कर रहे हैं जिनका खुद का सिस्टम भी फेल हो चुका है। हमारे समाज को उनके आचरण और व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है क्योंकि अपन को कहीं न कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आज से 100 वर्ष पूर्व महाराजा गंगा सिंह जी इस रेगिस्तान के सीने को चीरते हुए लिमिटेड संसाधनों के बावजूद भी इस मरू भूमि के अंदर अगर ले कर आ सकते हैं तो आज अपने पास इतने संसाधन होने के बावजूद अपन को मात्र पांच से दस किलोमीटर पानी अगर पहुंचाना है तो उसमें अपन को क्या दिक्कत आ रही है।? अगर अपन इसी प्रकार से चलते रहे तो आगे संकट और गहरायेगा।

हम पहले एक बरसात के ऊपर पूरा हमारा 1 साल निकाल लिया करते थे, अब भगवान की मेहर भी हमारे ऊपर है जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर है तकरीबन 40% से अधिक औसतन बरसात बढ़ी है और जैसलमेर जैसे सूखे जिले के अंदर भी 10 साल में 30 से 150% बरसात में इजाफा हुआ है। यह जितना भी एक्सेस वॉटर है इसका हमें संचय करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं देना चाहिए और इसी से एक नये राजस्थान का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही साथ रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पर भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे जिस प्रकार से पश्चिमी भूभाग में और पहाड़ी क्षेत्रों में जितनी भी लंबी-लंबी राइजिंग लाइन होती है, मैन लाइन के अंदर लोग-बाग पानी चोरी करने हेतु उसको पंक्चर कर लेते हैं और जो भी हमारे नहरी तंत्र है, उसके मुढ के अंदर जहां हमारे शुरुआती नहर की संरचना के अंदर अवैध मोगे और साइफन लगा लिये जाते हैं, इससे अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान को उनके हिस्से का पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो सरकार करोड़ों रुपये व्यय करने के बावजूद भी खुद के जो भी लक्ष्य है उस तक नहीं पहुंच पाती और पात्र लोग आदि वंचित रह रहे हैं। इसलिए इसी क्रम के अंदर आज से कुछ माह पूर्व जुलाई, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। यह निर्देशित किया कि जांच एजेंसियों को सात वर्ष तक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए पहले आरोपियों को उपस्थित होने का नोटिस जारी किए बगैर और फिर इसे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किये बिना आरोपियों को गिरफ्तार करने से बचना चाहिये। हिंदुस्तान के अंदर अपराधियों को मात्र गिरफ्तारी का भय होता है मुकदमों का कोई भय नहीं होता। अगर इसी प्रकार से हिंदुस्तान चलता रहा, यह राजस्थान चलता रहा तो यह हमारा सारा तंत्र कैसे चलेगा? तो जैसे अगर अपन कनेक्शन काटेंगे, कनेक्शन काटते ही थोड़े दिनों बाद वापस से वहां पर अवैध कनेक्शन जुड़ जायेंगे तो इससे गंभीर मुद्दे को देखते हुए हमें राजस्थान ईर्रिगेशन एंड ड्रेनेज एक्ट, 1990 की धारा 55...।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बस 1 मिनट। ...व पी.एच.ई.डी. एक्ट के अंदर संशोधन करके आदतन अपराधियों के खिलाफ़ 1 लाख रुपये का जुर्माना व सात वर्ष से अधिक कारावास करा जावे क्योंकि ये सभी जब तक अपराध गैर जमानती नहीं बनाये जायेंगे, तब तक हम जो हमारा लक्ष्य चाहते हैं कि अपराधियों में भय व्याप्त हो, वहां तक हम नहीं पहुंच पायेंगे। इसी प्रकार से जो पोंग बांध के अंदर ऊपर वाला 10 फीट का पानी है वो पानी भी हम इन्सर्जेन्सी के टाइम से, पंजाब की इन्सर्जेन्सी 1980-90 के दशक के बाद से, तो वो भी हमारा पूरा नहीं भर पा रहे हैं तो हमें बरसात के समय पाकिस्तान के अंदर हमारा जो खुद का हिस्से का पानी है वो छोड़ना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बाड़मेर और जैसलमेर का हक भी मारा जा रहा है, टेल एंड का भी हक मारा जा रहा है, तो हमें बी.बी.एम.बी. के माध्यम से यह बात उठानी चाहिये। और जो हमारा फील्ड स्टाफ है, जैसे बेलदार, मेट, जिलेदार, गेज रीडर जिनके आई.जी.एन.पी. में

97% पद खाली हैं, जो 3% पद बचे हैं वो भी आगे आने वाले 2026 तक रिक्त अधिक हो जायेंगे, उनको भी तुरंत प्रभाव से भरना चाहिये और साथ ही साथ आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में जो दूषित पानी जो आई.जी.एन.पी. हमको दे रही है, जो पेयजल में हम उपयोग ले रहे हैं और यह फ्लोराइड युक्त हैंडपम्प और ट्यूबवेल का पानी है इससे भी हमारे जीवन से खिलवाड़ हो रहा है तो हमें पश्चिमी राजस्थान के खासकर सेकंड फेज में इस थार रेगिस्तान में बरसाती टांके कैचमेंट के सही देने चाहिए।

और साथ ही साथ लास्ट मेरा अनुरोध है कि जितनी भी हमारी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है उसमें हम मॉडल के तौर पर एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना को लें क्योंकि गर्मी के समय में विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण से पूरे पेयजल की आपूर्ति हम हमारे गांव तक नहीं पहुंचा पाते। तो हमें एक मॉडल के तौर पर एक प्रोजेक्ट को हमको लेना चाहिए, जहां पर पूरा का पूरा तंत्र सोलर पर आधारित हो, जो नेट मीटरिंग के माध्यम से जो भी अतिरिक्त बिजली हो, उसको फीडर में डाले। इससे सरकार को राजस्व की आय भी होगी और जनता को पूरा हक का पानी मिलेगा। जय हिंद। जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 41 - जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं मांग संख्या 42 - जल संसाधन विभाग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बैठे हैं, उनका ध्यान मैं सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर ही दिलाना चाहूंगा कि जब पिछली बार पानी पर चर्चा हुई थी, हम पक्ष और विपक्ष के सब साथियों ने बहुत ही सार्थक चर्चा की थी लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि माननीय मंत्री जी ने सदन से घोषणा की थी कि जो ट्यूबवेल खराब है, जो ओपनवेल कुएं हैं ओपन वेल कुओं की हालत यह है कि आज ओपनवेल में, मैं उस टाइम पर भी यही बात बोला था, माननीय मंत्री जी, कि ओपनवेल में आज कोई मिस्त्री नहीं मिलता है। अगर ओपनवेल कुएं की मोटर खराब हो जाये तो 15 दिन तक उस मिस्त्री को ढूंढने में लगते हैं और वो मिस्त्री मन की मर्ज़ी का पैसा लेते हैं, जे.जे.वाई. के अंदर जो कुएं हैं गांव वाले पैसे देकर ठीक कराते हैं तो उसकी जगह पर आप ट्यूबवेल करवा दो तो ट्यूबवेल की मशीन है, आजकल मशीन से मोटर निकाल लेते है, वापस डाल देते हैं। एक भी ओपनवेल की जगह, आपने आश्वासन दिया था कि हम आने वाले दिनों में जितने भी ओपनवेल है, उनके स्थान पर ट्यूबवेल बनायेंगे और जो ट्यूबवेल खराब हैं उनकी जांच करवा करके और मोटर पाइप वही काम ले करके, जरूरत पड़ी तो दूसरा ट्यूबवेल खुदवा करके और वहां पानी की व्यवस्था करेंगे लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक एक भी ट्यूबवेल ठीक नहीं हुआ है, एक भी ओपनवेल की जगह कोई ट्यूबवेल नहीं खुदा है तो, माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिये, अधिकारियों को पाबंद कीजिये।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक वाकया बताता हूं एक गांव में दो ही सोर्स थे और दोनों में एक पहले एक खराब हो गया तो हमने उस ट्यूबवेल से दोनों पूरे गांव को पानी की व्यवस्था कर दी और भगवान ना करे के संयोग से वो भी खराब हो गया तो फिर कहां जायेंगे गांव वाले? जो खेत में किसान कृषि के ट्यूबवेल चलाते हैं उससे ट्रेक्टरों से पानी अपने घरों में ला-ला कर लोगों को पानी पीना पड़ा। फिर मैं आपके चीफ के पास आया, आपसे बात की तब जाकर के एक ट्यूबवेल की सैंक्शन निकली, वह ट्यूबवेल भी अभी तक खुदा नहीं है, तो क्या हाल है पानी का।

सबसे पहले आदमी को पानी की जरूरत रहती है माननीय मंत्री जी, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पानी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाये और जो आपने पिछली बार आश्वासन दिया था उस पर अमल किया जाये। एक जो पानी के पहले टंकियां थी, अभी जे.जे.एम. की पाइप लाइन डालनी शुरू कर दी, चाहे हमारी वाली सरकार हो उन्होंने भी एक आदेश निकाल दिया अधिकारियों ने बैठे ही कि जिस गांव में जिस ब्लॉक में जहां जे.जे.एम. की पाइप लाइन डाली जा रही है वहां न कोई एम.एल.ए. कोटे से पाइपलाइन की सैंक्शन निकाल सकते हैं, न कोई पंचायत से, न कोई पंचायत समिति से, न कोई जिला परिषद से और न वहां कोई वाटरवर्क्स लाइन डाल सकता, न कोई पानी की टंकी बना सकता, तो जे.जे.एम. का पानी तो 2028 तक आयेगा। 2028 तक गांव वाले क्या करेंगे? क्या इंतज़ार करेंगे 2028 तक का कि हम 2028 में टंकी बनायेंगे, पाइप लाइन डलवायेंगे? अब की बार आपने जो प्रावधान किया है हैंडपम्पों का और ट्यूबवैलों का आपसे बराए मेहरबानी है कि आप जो हमारे ग्रामीण इलाकों में ओपनवेल हैं उनकी जगह पर आप सर्वे करा करके चाहे कोई आप अपने अधिकारियों से सर्वे करा लो कि कौन-कौन से गांव में ओपनवेल है, उस ओपनवेल को बंद करो और उसकी जगह ट्यूबवेल खुदवा करके और उसका कनेक्शन बिजली का वो ही काम आ जायेगा तो गांव वालों की समस्या का समाधान हो जाएगा। जी.एल.आर. बनाने की आप परमीशन दीजिये कि पी.एच.ई.डी. जी.एल.आर. बनाये। जिस गांव में आज से 20 साल 30 साल पहले जी.एल.आर. बनी थी वो लीकेज हो गयी उससे आधा पानी उसका व्यर्थ जा रहा है। गांव की गलियों में कीचड़ हो रहा है, सार्वजनिक चौक में कीचड़ हो रहा है, लेकिन वो पानी व्यर्थ जा रहा है और नयी जी.एल.आर. बना नहीं सकते इसलिए वो आप उसमें प्रावधान कीजिये कि पानी की दूसरी जी.एल.आर. बनायी जाये।

सभापति महोदय, एक पाइप लाइन लीकेज की बहुत बड़ी समस्या है कि गांव हो चाहे शहर हो, लीकेज इतने हैं कि ठीक करने वाला कोई है नहीं क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कर्मचारी नहीं हैं। आपने ठेके पर दे रखा है ठीक है लेकिन ठेकेदार भी ठीक करता नहीं है। ठेकेदार को फ़ोन करते हैं और ब्लॉक के ए.ईएन., जे.ईएन. को फ़ोन करते हैं तो वो ऑफ द रिकार्ड बात करते हैं कि, साहब, बजट नहीं है, क्या करें? बजट के बगैर ठेकेदार काम कैसे करेगा? ठेकेदार बोलते हैं, हमारे को पैसे नहीं मिलते हैं तो हम कहां से ठीक करेंगे? और जब अधिकारियों को कहते हैं तो कहते हैं कि, साहब, बजट ऊपर से नहीं आता है तो ऊपर से

कहां से आयेगा? कोई भगवान थोड़ी देगा बजट। बजट तो सरकार को ही देना पड़ेगा। आप वहां बजट का प्रावधान करो, लीकेज से पानी व्यर्थ जा रहा है, कीचड़ हो रहा है और वही पानी वापस पाइप लाइन के अंदर आता है तो बीमारियां फैलती हैं इसलिये मेरी आपसे अपील है कि आप जो पाइपलाइन है, उसकी लीकेज की भी व्यवस्था करायें।

एक कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है। पिछले 5 साल हम लोग रहे शायद मेरे ख्याल से बहुत कम भर्ती की थी, लेकिन अब भी आप हो, आपको डेढ़ साल हो गये और भी आगे आपके पास तीन 3.5 साल हैं तो कर्मचारियों की भर्ती करो इस डिपार्टमेंट के अंदर और कर्मचारियों की भर्ती करके और गांव और शहर के अंदर पानी की व्यवस्था कराओ। जब कर्मचारी होंगे तो व्यवस्था करेंगे, कर्मचारी नहीं हैं तो किसको कहेंगे?

Kas/rtm/05.03.2025/17.00/3e

मेरे ब्लॉक में पिछले दिनों 3 जे ईएन, 2 ए ईएन थे, आपने एक ए ईएन के भरोसे सिटी और ग्रामीण, दो ब्लॉक छोड़ दिये, एक ए ईएन क्या करेगा? दो शहर हैं, 130 गांव हैं, इनको एक आदमी कैसे देखेगा? आप वहां भी खाली पड़े पदों को भरो और व्यवस्था करो।

आपने जो हैंडपम्पों की व्यवस्था की है, बहुत अच्छी बात है हैंडपम्प होने चाहिये, लेकिन हैंडपम्प वहां होने चाहिये, जहां जरूरत है। हम लोग सिफारिश से हैंडपम्प खुदा देते हैं और आज की तारीख में वो 80 परसेंट खराब पड़े हैं। पंचायती राज वाले बोलते हैं कि पीएचईडी के हैं। पीएचईडी वालों के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि पंचायती राज के पास हैंडपम्प रिपेयर करने का टेंडर है, हमारे पास प्रावधान नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। इन दोनों विभागों में आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से वो 80 परसेंट हैंडपम्प खराब पड़े हैं। हैंडपम्प यूज करने वाला,कोई मोहल्ले वाला या कोई ढाणी वाला अपने पैसे से ठीक करा लेता है तो ठीक है, नहीं तो हैंडपम्प खराब होने के बाद ठीक ही नहीं होता है, इसलिए आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए।

जे जे एम की बात करूं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बैठे-बैठे हंस रहे हैं। मंत्री जी, थोड़ा जे जे एम पर ध्यान दो। आप एक बात कह कर पीछा नहीं छुटा सकते कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया। पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया, तो जांच क्यों नहीं कराते?

श्री सभापतिः आप अच्छा भाषण दे रहे हो, इसलिए उनको खुशी हो रही है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): जांच कराओ, जांच करा कर जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसको पकड़ो और पकड़ कर जेल में डालो, वसूली करो, कौन मना कर रहा है? आपको डेढ साल हो गये, भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार करके पांच साल निकाल दोगे और जनता त्राहि-त्राहि करके मरती रहेगी। जे जे एम की यह हालत है कि एक गांव में पाइप लाइन डाले हुए एक साल से ऊपर हो गया, वह पूरी पाइप लाइन चोक हो गई, टूट गई। पाइप लाइन में पानी तो दूर की बात है, मेरा ख्याल है कि आप 2028 तक भी उसमें पानी नहीं चला सकोगे, क्योंकि ठेकेदार पाइप लाइन डालकर चला जायेगा, दो-तीन साल में उसका गारंटी पीरियड खतम हो जायेगा

और फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए जे जे एम योजना को सही ढंग से धरातल पर लाओ, जनता को उसका लाभ मिले। उसमें राजस्थान सरकार, भारत सरकार का जो पैसा लग रहा है, उस पैसे का सदुपयोग हो।

दूसरी बात यह है कि जे जे एम की जो पाइप लाइन डाली है, उस पाइप लाइन के डालने के वक्त जो सड़कें तोडी गई थीं, जो खरंजे तोड़े गये थे, जहां पाइप लाइन डाली है, वहां आप गांवों में जाओगे, तो गांव वाले यही कहेंगे कि हमारा गांव इससे पहले अच्छा था, क्योंकि न तो उन्होंने सड़क को रिपेयर किया है, न खरंजे को रिपेयर किया है। पाइप लाइन डालकर निकल गये और लोगों को आज वहां खड्डों से परेशानी हो रही है। आपने पूरे राजस्थान का यहां से एक कंपनी को टेंडर दे दिया और उस कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको सबलेट कर दिया और डिस्ट्रिक्ट वाले ने ब्लॉक वाइज सबलेट कर दिया और उस ब्लॉक वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी तो उसकी है, जिसने आपसे टेंडर लिया, उस तक बात पहुंचती नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अपील है कि आप उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। मैंने देखा था कि एमओयू में 20 दिन में रिपेयरिंग करने का प्रावधान है। 20 दिन तो क्या, डेढ़-डेढ साल तक रिपेयरिंग नहीं हुई है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप यह भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार कर रहे हो ना, कल हम वापस उधर आकर आपको भ्रष्टाचारी कहने लग जायेंगे कि आपने भ्रष्टाचार किया, इससे जनता को क्या मिला? जनता तो वैसे के वैसे ठगी कि ठगी ही रह गई ना। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप जे जे एम की तरफ ध्यान दें।

सभापति महोदय, जे जे एम में जो टंकियां बनाई गई हैं, वो तो भगवान भरोसे हैं। ठेकेदार ने जो टंकियां बनाई थीं, उसका गारंटी पीरियड तो खतम हो गया, उसमें आप पानी डाल नहीं सके और अब सूखी टंकियां लीकेज होंगी तो आप ठेकेदार को कहोगे कि रिपेयरिंग करो, तो वह कहेगा कि मेरा तो गारंटी पीरियड खतम हो गया। इसलिए मेरा आपसे मेरी अपील है कि इसकी मॉनिटरिंग करें। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सुबह उठते ही आदमी को पानी चाहिये, इसलिए पानी की व्यवस्था की जाये। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दीजिए। डेढ़ साल में कम से कम एक ट्यूबवैल तो खुदवा देते, एक हैंडपम्प खुदवा देते। ....(व्यवधान).... पांच ट्यूबवैल की सैंक्शन केवल कागजों में निकली है, अभी तक धरातल पर नहीं आये हैं। धरातल पर अगर ट्यूबवैल आये हो, तो आप जो कहोगे, वो करने के लिये मैं तैयार हूं। सरकार बने हुए डेढ़ साल हो गये, धरातल पर नहीं है। आपके अधिकारी कह रहे हैं 2011 की आबादी के अनुसार बहुत पानी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: विश्वनाथ जी।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 - पेयजल और 42 - जल संसाधन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

अभी फतेहपुर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य जे जे एम के बारे में बोल रहे थे। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की हर गांव तक नल से जल पहुंचाने की जो यह स्कीम थी, यह बहुत ही ऐतिहासिक स्कीम थी। बहुत ही अच्छा कार्य माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के लिये, राजस्थान के लिये किया। अभी आप जो कुछ कमियां गिना रहे थे, ये सब कुछ आपके समय में ही हुई थीं। आपको तीन साल का निर्धारित समय दिया गया, उस निर्धारित समय में आपने काम पूरा नहीं किया। अभी आप टंकी की बात कर रहे थे, पाइप लाइन की बात कर रहे थे, पूरा का पूरा कार्य आपके समय में हुआ और घटिया कार्य हुआ। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी आपके समय में हुआ। तीन साल में आप केवल 40 परसेंट ही काम कर पाये। इतना बजट केन्द्र सरकार से मिला, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। यह बात सही है कि जगह-जगह से पाइप टूट रहे हैं, ठेकेदारों की भी रिकवरी निकाली जा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जिन ठेकेदारों ने काम किया, माननीय मंत्री महोदय उसकी जांच करवा रहे हैं और उसकी रिकवरी भी निकाली गई है।

सभापति महोदय, मैं इस योजना के बारे में बताना चाहूंगा कि देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस चीज को गंभीरता से लिया और राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने इसके समय को 2028 तक बढ़ाकर राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। आपने जो कमियां गिनाई हैं और जो कमियां आपके समय में हुई थीं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय उनको हम दुरुस्त करेंगे। 20 लाख घरों को पेयजल से जोड़ने की बात कही है, यह बहुत ही बड़ा काम होगा। अमृत-2 योजना के तहत भी नगर पालिका क्षेत्र और नगर निकाय क्षेत्र में जो काम होगा, वह शहरों के लिये भी अच्छा होगा। 1000 ट्यूबवैल और डेढ़ हजार हैंडपम्प की जो बात कही है, मैं समझता हूं कि दूरस्थ क्षेत्र, जहां पानी की किल्लत रहती है, वहां पर इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी माननीय मंत्री महोदय ने, मुख्य मंत्री जी ने वर्तमान में एक ए ईएन ऑफिस पूगल में खोलकर और माहदेवाली को एक पेयजल की स्कीम देकर बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी एक मांग है कि हमारी ग्राम पंचायत भानीपुरा, छतरगढ और मोतीगढ़ ग्राम पंचायतों में एक पेयजल योजना बनाकर वहां की पेयजल समस्या का समाधान किया जाये, यह मैं मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर बताना चाहूंगा हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सपना था कि देश को नदियों से जोड़ा जाये और अंतिम छोर पर बैठे किसान तक पानी पहुंचाया जाये। एक तरफ अकाल पड़ता है, एक तरफ बाढ़ आती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद 2004 से 2014 तक आपकी कांग्रेस की सरकार थी और आपके द्वारा उस योजना को बंद कर दिया गया, यह कह कर कि इससे प्रदूषण फैलेगा। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ईआरसीपी

योजना, संशोधित राम जल सेतु परियोजना के नाम से एक बहुत बड़ी सौगात इस राजस्थान के लिये लेकर आये। इसमें 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिये पानी मिलेगा। 3 करोड़ जनसंख्या, करीब 1/3 जनसंख्या को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह कार्य प्रगति पर है। 9,416 करोड़ के कार्यादेश दिये जा चुके हैं और 12,064 करोड़ की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं और 12,807 करोड़ की स्वीकृतियां भी जारी की जा चुकी हैं। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर आपको बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी फीडर और मुख्य नहर परियोजना के प्रथम चरण के वितरण प्रणाली की नहरों के जीर्णोद्धार हेतु हमारी पिछली सरकार, माननीय वसुंधरा जी के समय में आरडब्ल्यूएसआरपीडी के अंतर्गत राशि 3,291.63 करोड़ की परियोजना तैयार की गई थी।

Msk/rtm/05.03.25/1710/3f

जिसके लिए वर्ष 2018 में न्यू डवलपमेंट बैंक से ऋण अनुबंध किया था। परियोजना के कार्य फरवरी, 2023 तक पूरे किये जाने चाहिए थे, लेकिन वह काम भी आपके समय में पूरा नहीं हुआ। इसके लिए भी मैं पूर्ववर्ती सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। 1960 के दशक से नहर बनी, लेकिन आज तक भी वहां किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। सभी नहर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। 3200 करोड़ रुपये पास कराकर यह काम किया गया है, उसमें भी आप लोगों ने पूरा काम नहीं किया। करीब 179 किलोमीटर के विरुद्ध 176 किलोमीटर रि-लाइनिंग हुई। 179 से 620 आरडी तक नहरों का जीर्णोद्धार हुआ है। मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारी सरकार के द्वारा योजनान्तर्गत वितरण प्रणाली नहरों के लिए 808 किलोमीटर लंबाई में जीर्णोद्धार कर लगभग समस्त कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं और इसकी भी समयावधि 12.02.2025 तक बढ़ायी गयी है, यह भी बहुत ही अच्छी बात है कि आने वाले समय में जो भी नहरें हैं, चाहे वह फिरोजपुर फीडर हो, सरहिन्द फीडर हो, चाहे वह इंदिरा गांधी की मुख्य नहर हो, जो भी वंचित काम हैं, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी।

मैं समझता हूं कि नहर की कैपिसिटी 18 हजार 500 क्यूसेक है, उसको वापस रेस्टोर करने का काम हमारी सरकार करेगी और पानी की समस्या रहती है, वह समस्या भी आने वाले समय में नहीं होगी। साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि 22 हजार 816 सेम ग्रस्त क्षेत्र है, उसके लिए भी 10 सुधार कार्य 200 करोड़ रुपये के करवाये जाने हैं, जिसके विरुद्ध 5 कार्यों में 108 करोड़ के कार्यादेश भी जारी कर दिये गये हैं।

मैं पक्के खालों की बात करूं। मेरे क्षेत्र में पिछले बजट में 100 करोड़ रुपये दिये और इस बजट में भी 230 करोड़ रुपये हमारी धोधा वितरिका और दंतौर वितरिका के लिए दिये गये हैं। अनूपगढ़ ब्रांच के अधीन आने वाले जितने भी समस्त खाले हैं, उनको भी दुरुस्त करने

का काम हमारी सरकार करेगी। मैं समझता हूं कि इसमें भी हमारे किसानों को लाभ मिलेगा और मुख्य नहर के जो दोनों पटड़े हैं, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 620 से लेकर 1458 तक के, नहर के दोनों पटड़ों के सुदृढ़ीकरण का कार्य के लिए राशि 75 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। वर्षाकाल में पटड़ों पर बालू मिट्टी होने के कारण मिट्टी का बहुत ज्यादा कटाव होता है, जिससे मुख्य नहर की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो जाता है। मुख्य नहर की सुरक्षा हेतु दोनों तरफ के पटड़ों पर मिट्टी का कार्य व जेएसबी कार्य करवाया जाना भी अति आवश्यक है। इसके लिए भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि डिजिटलीकरण और ऊर्जा बचत की दिशा में भी हमारी सरकार ने काम किया है, जिसके तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना (द्वितीय चरण) की आरडी 620 से लेकर 1458 के मध्य कमांड क्षेत्र के विभिन्न चक प्लान, बाड़ाबंदी, खतौनी एवं सरकारी भूमि खातों के डिजिटलीकरण के कार्य हेतु डीपीआर के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

सभी लिफ्ट नहरों के पंप हाउस में बिजली उपयोग को कम करने हेतु सौर ऊर्जा पार्क बनाने की डीपीआर भी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे बिजली की खपत कम आयेगी और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ेगा, यह भी हमारी नहरों के लिए किया जा रहा है। जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं, उनको भी सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर की बात मैं करूं, 1960 के दशक के प्रारंभ में हमारी 18 हजार 500 क्यूसेक क्षमता की जो नहर थी, लेकिन लगातार पानी चलने से समय-समय के साथ नहर की लाइनिंग की जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गयी, जिससे नहर की क्षमता घटकर 11 हजार 500 क्यूसेक रह गयी। अत: फीडर की मूल क्षमता को रेस्टोर करना अत्यंत आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त भांखड़ा सिंचाई परियोजना के लिए..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट के लिए। इंदिरा गांधी फीडर, जो 0 से 179 की लाइन क्षतिग्रस्त है, जर्जर है, जिसके लिए इंदिरा गांधी फीडर की आरडी 179 से आरडी 496 तक करवाये गये कार्य का समुचित लाभ नहीं मिल पायेगा। बजट 2025-26 में इंदिरा गांधी फीडर की आरडी 0 से 179 तक की रि-लाइनिंग कार्य करवाये जाने हेतु डीपीआर बनाने की राशि 5 करोड़ दी गयी है, वह बहुत ही अच्छा काम होगा। मैं समझता हूं कि इससे भी नहर सुदृढ़ होगी।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के पानी की उपलब्धता। हम जो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि किसानों को हर वक्त अपनी फसल बचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हमारे अनूपगढ़ के माननीय सदस्य भी यहां बैठे हैं, सूरतगढ़ के सदस्य भी बैठे हैं, जब भी रेगुलेशन हुआ, हम सब उस रेगुलेशन में थे, कांग्रेस के सदस्य भी थे, एमपी भी थे और वहां के किसान भी थे। रेगुलेशन में डैम का लेवल 1365 फीट था, इस बार पौंग डेम में पानी कम था। तो उससे चार बार ही पानी की उपलब्धता बतायी गयी, लेकिन

हमने वहां की चीफ इंजीनियर को कहा कि हमें पांच बारी की आवश्यकता है, उस समय पांच बारी के लिए हमारे किसानों ने कहा, विभिन्न संगठनों ने कहा, उसके आधार पर पानी दिया गया। मैं मानता हूं कि किसानों की मांग को देखते हुए अभी पानी की आवश्यकता है तो हमारे पास जो भी पानी है, उस पानी से किसानों को फसल पकाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। मैं इस मौके पर एक चीज और कहूंगा कि 0.6 एमएएफ की बात जो हम करते हैं। स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने वर्ष 1994 में भारत सरकार को पत्र लिखकर 0.6 एमएएफ पानी राजस्थान को देने की मांग की गयी थी। वर्ष 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑरिजिनल सूट दायर की, परन्तु इसकी पैरवी सही ढंग से नहीं हो रही है। पंजाब में लीगल एक्सपर्ट का पूरा पैनल बना हुआ है। हमारी सरकार ने अभी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विक्रम जीत बनर्जी को नियुक्त किया है। परन्तु इस केस की गंभीरता को देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि लीगल व टैक्निकल एक्सपर्ट का पैनल बनाये जाने की आवश्यकता है। इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगा बीबीएमबी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए और सतलुज के माध्यम से जो दूषित पानी आ रहा है, उसको भी रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरी एक डिमांड है कि पूंगल ब्रांच के अधीन आने वाली जितनी भी क्षतिग्रस्त नहरें हैं, उनके सुदृढ़ीकरण का बजट भी हमें आवंटित किया जाये और आरडी 414 से आरडी 620 के मध्य आने वाले छतरगढ़ तहसील की समस्त नहरों के क्षतिग्रस्त खालों को सुदृढ़ करने के लिए भी बजट दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अनिल कुमार शर्मा।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 व 42 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील भानीपुरा में शुक्रवार 28 फरवरी को हुई भयंकर ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को जो भारी नुकसान हुआ है, खेतों में फसलें पूरी तरह बिछ गयी हैं, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गयी हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसका सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाकर राहत देने का कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं पक्ष-विपक्ष की बातें सुन रहा था। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने एक साल की उपलब्धियों के बारे में बहुत ही बढ़ चढ़कर अपना वक्तव्य दिया। एक साल के कार्यकाल का एक छोटा-सा तुलनात्मक बताना चाहूंगा। माननीय सभापति जी, मैं दिसंबर, 2022 में उप चुनाव में चुनकर इस सदन में आया था और नवंबर, 2023 में आम चुनाव हो गये। मुझे लगभग आठ-नौ महीने ही काम करने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस थोड़े से समय में हमारे जन नायक लोकप्रिय अशोक गहलोत जी की सरकार में लगभग पांच दर्जन 60 ट्यूबवैल मैंने इतने कार्यकाल में स्वीकृत कराये और लगभग 50 ट्यूबवैल शुरू भी हो गये। चुनाव की घोषणा हो गयी, सरकार बदल गयी और एक दर्जन के लगभग जो ट्यूबवैल अधूरे रहे, सरकार ने समीक्षा के नाम पर उन पर रोक लगा दी और वे

आज भी लंबित हैं। पिछले बजट में सरकार ने घोषणा की कि हर विधान सभा क्षेत्र में डिपार्टमेंट से 10-10 ट्यूबवैल के प्रस्ताव मांगे गये और पांच-पांच ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये। यह सही है। मेरे यहां शुरू हो गये, एक-दो जगह उन्होंने चिह्नित कर ली, एक-दो शुरू भी हो गये। ...(व्यवधान)... जो हुआ है, वह तो हकीकत है। इस दरमियान विभाग ने आपके यहां against failure ट्यूबवैल के प्रस्ताव यहां भिजवाये हैं। जनता को भारी परेशानी हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पातलीसर छोटा, पातलीसरा बड़ा, राजासर बीकान, सोनपालसर, बंधनाऊ दिखणादा, सिकराली, हामूसर, बरजांगसर, हुडेरा, मेलूसर में एक-एक और पाबूसर व बलरामपुरा में दो-दो ट्यूबवैल के against failure के प्रस्ताव आपके पास आये हैं, कृपा करके आप इनको स्वीकृत कराकर जनता को राहत देने का काम करें, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

mdp/rtm/05.03.25/17:20/3g

माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में जे.जे.एम. योजनान्तर्गत हर घर तक पेयजल पहुंचाना था, जिसकी प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर काफी अच्छी बताई जा रही है एवं विभाग द्वारा घरों में नल लगाए जाकर कार्य पूर्ण मान लिया गया है। लेकिन धरातल पर कार्य किसी भी तरह पूर्ण नहीं हुआ है। आज भी जनता पेयजल हेतु त्राहि-त्राहि कर रही है। जिन गांवों में नल लगाये जा चुके हैं, वहां आज तक पानी नहीं पहुंचा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 23 ओ.एस.आर. बनाए जाने प्रस्तावित थे। जिनकी अनुमानित लागत 1 हजार 86 लाख रुपये हैं, लेकिन उक्त 23 ओ.एस.आर. का आज तक टेंडर भी नहीं हो पाया है, जबकि नियमानुसार उक्त कार्य 2024 में पूर्ण हो जाना चाहिए था। दूसरी तरफ, सरकार जल जीवन मिशन की सफलता का ढिंढोरा पीटती जा रही है। इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत धरातल पर तुरंत प्रभाव से कार्य कर गांव में पेयजल पहुंचाय जाए।

माननीय सभापति जी, इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिकराली, बलरामपुरा, नैणासर सुमेरिया, बुकनसर बड़ा, भोजरासर, रंगाईसर, दुलरासर, रूपलीसर, भानीपुरा, सारसर, गिडगिचिया में भी ओ.एस.आर. की सख्त आवश्यकता है। ग्रामवासियों द्वारा बार-बार पेयजल हेतु ओ.एस.आर. बनाए जाने की मांग की जा रही है। इसलिए इन गांवों में नये ओ.एस.आर. हेतु स्वीकृति जारी करवाई जाकर बजट आवंटन किया जाए। चूरू जिले को मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर भी सम्मिलित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल और पशुओं के पानी की भयंकर समस्या है। इस क्षेत्र में भूजल के अतिरिक्त पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं है। गर्मियों में पानी की समस्या रहती है। इस हेतु मेरे विधान सभा क्षेत्र के तहसील सरदारशहर के गांव भोजरासर, कानड़वास, राजास, खेजड़ा उत्तरादा, नैयासर, फोगां, रोही दुलरासर, भादासर दिखणादा और सरदारशहर के शहरी

क्षेत्र में वार्ड 2 नंबर, 15 नंबर, 17, 25, 43 व 52 नंबर वार्ड व रतनगढ़ तहसील जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं, बीनादेसर, पाबूसर व मेलूसर, इनमें नयी ट्यूबवैल की नितांत आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि यहां भी ट्यूबवैल स्वीकृत करें।

दूसरा, अभी हाकिम जी ने भी कहा और जाकिर जी, माननीय विधायक जी ने भी कहा, माननीय मंत्री जी ये जो हैंडपंप आपने बजट में घोषणा की है, मेरे यहां पानी काफी गहरा है, वहां हैंडपंप सक्सेस नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हैंडपंप की जगह सिंगल फेस ट्यूबवैल, चूंकि डिपार्टमेंट ने ये बंद कर दिए हैं और सिंगल फेस ट्यूबवेल की सबसे बड़ी समस्या है कि पी.एच.ई.डी. ने तो इसको मना कर दिया, न तो पंचायतें, न नगर पालिकाएं उनका बिल भरती हैं, न रख-रखाव करती हैं। इसमें कोई आप रास्ता निकालिए। जहां जरूरत हो हम विधायक कोटे से भी सिंगल फेस ट्यूबवैल दे सकते हैं। इसका रख-रखाव और जहां बिल की बात आती है, वहां मेन समस्या आती है, इसलिए ये भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर आप गंभीरता से गौर करें।

माननीय सभापति जी, धन्नासर से सरदारशहर की सप्लाई के लिए मुख्य पाइप लाइन, जो 1100 एम.एम. डाया, जो 25 साल पहले बिछाई गयी थी। इसका डिजाइन पीरियड भी पूरा हो चुका है। पाइप लाइन जगह-जगह से लीकेज हो चुकी है। कुछ जगह हाइवे जाने के कारण रिपेयर नहीं हो रही है। सरदारशहर की पेयजल सप्लाई की लाइफ लाइन कही जाने वाली पाइप लाइन, इस कार्य को आगामी बजट में शामिल कर स्वीकृति दिलाने का श्रम करें।

माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में गत सरकार द्वारा सिंचाई हेतु नहरी क्षेत्र में 58 गांवों के रकबे को सिंचित क्षेत्र में शामिल किया गया था। बस आधे मिनट में, सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में विस्तृत कृषि भू-भाग है, सिंचित क्षेत्र होने से कृषि आय में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। कृषि उत्पाद के निर्यात में राज्य सरकार की जी.डी.पी. में आशातीत बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। न तो उक्त नहरी रकबे को बढ़ाने हेतु डी.पी.आर. तैयार हुई और न ही खाला व नहर निर्माण हेतु विभाग द्वारा आज तक कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित सिंचित रकबे के अनुसार डी.पी.आर. तैयार करने, नहर व खाले निर्माण करने हेतु स्वीकृति जारी व बजट आवंटन करने की मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 व 42 पर बोलने का मौका दिया।

कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में,

फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है।

माननीय सभापति महोदय, ई.आर.सी.पी., जब वसुन्धरा जी की सरकार थी, भारतीय

जनता पार्टी की सरकार थी, प्रपोजल बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद में पांच साल सरकार बदल गयी। पांच साल सरकार बदलने के कारण उस ई.आर.सी.पी. को इन्होंने लटका कर पटक दिया। कोई काम ही नहीं किया और बहाने बनाते रहे। हमारी सरकार आयी। सरकार बनने के बाद में माननीय भजन लाल शर्मा जी मुख्य मंत्री बनें। उनके प्रयासों से केन्द्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन की सरकार आगे से भी जोर लगाया और पीछे से भी जोर लगाया और ई.आर.सी.पी. आ गयी। ई.आर.सी.पी. घोषित हो गयी। डबल था इंजन। शिलान्यास भी हो गया और पानी आयेगा। आप तो नहीं ला पाए, परंतु पानी आयेगा। आप तो जे.जे.एम. को ही पी गये। अब हल्ला मचा रहे हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और जो भरतपुर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी रूपारेल में भी पानी आयेगा, बाणगंगा में भी पानी आयेगा और गंभीर नदी में भी पानी आयेगा, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे संभाग में मीटिंग हो रही थी, उसमें मुख्य मंत्री जी गये थे। जो हमारे भरतपुर का नक्शा है, वह इस प्रकार से कमालपुरा का बार्डर पड़ता है, पथरेना गांव पड़ता है, वह सारा नक्शा बता रहे थे। हर गांव पर एक डेम होता था, हर पंचायत पर एक बांध हुआ करता था। वह सारे बांध भरते थे। जो बाणगंगा में पानी आयेगा, रूपारेल में पानी आयेगा, दंभी में पानी आयेगा, वह बांध सारे भरा करेंगे। एक बात और कह रहे थे, जब हम छोटे-छोटे थे, वह भी छोटे थे, हर बांध में कमल का फूल खिलता था और ई.आर.सी.पी. आने से, बाणगंगा में पानी आने से हर डैम भरेगा और कमल का फूल हमेशा खिलता रहेगा।

ई.आर.सी.पी. पर हमारे मित्र कह रहे थे कि अब सरकार आपकी आ गयी। साल हो गया, सवा साल हो गया, पांच साल तक आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, मजे मारते रहे, लड़ते रहे, मगर घोटाला इतना कर दिया। आपकी टंकी बनी, चूंचा रही हैं और जहां टंकी बनानी थी, वहां टंकी बनी नहीं। ये देखा कि मेरा आदमी कहां है, मेरा वोट कहां हैं, वहां टंकी बना दी। वह पानी जहां जाना चाहिए था, पूरे गांव को जाना चाहिए था, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है।

Ans/rtm 17.30 3h 05.03.2025

खराब पाइप लाइन डाल दी। जे.जे.एम. में जो घोटाला हुआ उस घोटाले के लिए तो कुछ कह नहीं रहे हैं। एक कांग्रेस के आपके साथी थे, हमारे भरतपुर में विधायक थे, ठेकेदार से कह रहे थे। ठेकेदार कह रहा था कि साहब मेरा बिल पास करवा दो, तो कह रहे थे आप मेरा काम कर दो, मैं आपका काम कर दूंगा। कोड वर्ड में बोला।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, इन्होंने बोला कि भरतपुर के विधायक है ...(व्यवधान)...

श्री बहादुर सिंह (वैर): भरतपुर के नहीं बोला। भरतपुर में थे। भरतपुर में थे, भरतपुर का

नहीं।

श्री सभापति: भरतपुर की भाषा ही ऐसी है का, के की हो जाता है।

श्री बहादुर सिंह (वैर): भरतपुर में तो सात थे, तो उन्हीं सातों विधायकों में से एक विधायक थे ...(व्यवधान)... ठेकेदार से बोले कि आप मेरा काम कर दो और मैं आपका काम कर दूंगा। उसके बाद उसने कोड वर्ड में अपने आदमी से कहा कि वहां पचास कुर्ते पाजामा रखे हैं। मैं आऊँगा आप शॉर्टकट आ जाना। वह थैले को लेकर चल दिया। वहीं एक शादी थी, शादी में ढोल बजाने के बाद ढोल वाला शॉर्टकट चल दिया। शॉर्टकट चल दिया तो ढोल बजने लग गया, क्योंकि अरहर के खेत में होकर जा रहा था, तुअर की दाल होती है अरहर। अरहर के खेत में से जा रहा था वहां चोर छुपे हुए थे, चोर ढोल वाले पर आ गये कि ढोल क्यों बजा रहा है, यह किसी पुलिस वाले को बुला रहा है। इतने में ही जो कुर्ते पाजामा का थैला लेकर आ रहा था, वह भागा, उन चोरों ने ढोल वाले को तो छोड़ दिया और कुर्ते पाजामा वाले को पकड़ लिया। वह बोला कि इसमें तो कुर्ते पाजामा है। बैग खोला तो उसमें कुर्ते पाजामा नहीं, माल था। बैग लेकर चले गये। उसके बाद ढोल वाले को पीटने लग गये। इस प्रकार से जे.जे.एम में घटना घटी। यह हकीकत है कोई कहावत नहीं है। गर्ग साहब हंस रहे हैं। आपको पता है कि कुर्ता पाजामा कौन कहता था।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): आप जब भी बोलते हो तो हंसी आ ही जाती है। ...(व्यवधान)...

श्री बहादुर सिंह (वैर): आपको पता है कुर्ता पाजामा कौन कहता था। जल संसाधन मंत्री जी बैठे हैं। मेरा वैर विधान सभा में सीता बंध है उसकी क्षमता बढ़ाई जाए। एक नाला बना हुआ था, वैर के अन्दर एक किला है, नहर चारों तरफ उस नाले से भरती थी। जो क़िले के चारों तरफ नहर है उसके लिए माननीय माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा कर दी, उसका पैसा भी पहुंच चुका है। वह गहरी हो जाएगी, उसकी सफाई हो जाएगी। वहां से पानी आने की आवश्यकता है। वैर शहर के अन्दर पहले हर घर में कुआं था, कुओं में पानी रहता था। नल की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी पाइप की जरूरत नहीं पड़ती थी। पानी उन कुओं में रहता था, वह कुएं अब सूखे पड़े हैं। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि सीता बंध की गहराई बढ़ाई जाए, नाला साफ किया जाए जो पानी आता था।

माननीय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी साहब बैठे हुए हैं। एक हमारे सांवरमल जाट भी थे, उनका बड़ा दिल था। जो कोई भी जाता था, हम भी जाते थे, हम एमपी थे, एमएल थे, तो जो मांगते थे उससे दस गुणा दे देते थे। तो मैं कन्हैयालाल चौधरी जी से कहना चाहता हूं कि आप भी बड़ा दिल बनाये माननीय चौधरी साहब। वह जाट लगाते थे, आप चौधरी लगाते हैं, तो जाट-जाट एक। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बड़े दिल के बन जाए।

मेरी विधान सभा के अन्दर जो जे.जे.एम. के कार्य हुए, पानी की टंकी है कुछ जगह तो चू चा रही है, यानी लीकेज। पहले छप्पर हुआ करते थे उसको यह कहते थे कि टपक पड़ रहा है या चू रहा है।

श्री सभापतिः माननीय सुभाष गर्ग।

श्री बहादुर सिंह (वैर): माननीय सभापति जी, अभी तो मैंने बोला ही नहीं, वैसे ही टाइम निकाल दिया। ...(व्यवधान)... अभी तो बोलना स्टार्ट हुआ हूं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापति महोदय, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। मैं जाति का कोरिया हूं और जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो कहते हैं गरपत करता गोरिया फिर जीतेगो कोरिया। तो साहब बोलने दो। ...(व्यवधान)...

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): जल संसाधन एवं पीचएईडी की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

श्री बहादुर सिंह (वैर): गर्ग साहब, रुक जाओ ना।

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): मेरा टाइम हो रहा है, सभापति महोदय मुझे बिठा देंगे।

श्री बहादुर सिंह (वैर): 000

श्री सभापतिः बहादुर सिंह जी, आप टेबल कर देना।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति जी, आप प्लीज दुबारा शुरू कर देना।

श्री बहादुर सिंह (वैर):000

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा है। पानी से सम्बन्धित चर्चा है चाहे वह पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो। मैं एक चिंताजनक विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2012 के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक व सामाजिक मामलों के विभाग, 2012 के अनुसार 2030 तक विश्व की लगभग आधी आबादी जल तनाव क्षेत्र में रह रही होगी। आप इस बात का अंदाजा लगाये। भारत का जहां तक उल्लेख करना चाहूंगा। भारत में आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि 70 परसेंट पानी तो पीने लायक ही नहीं है। पीने लायक नहीं होने की वजह से कितने हेल्थहजार्ड होते हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की जड़ पानी है, इस बात के बहुत सारे रिसर्च आ चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, दोनों मंत्री यहां बैठे हुए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि दोनों ही मंत्री बड़े सीधे है और सजग भी है। दोनों का व्यवहार भी बड़ा शालीन है। जैसा अभी वैर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने कहा था कि उदार दिल दिखाएंगे, निश्चित रूप से उदार है मैं यह कहना चाहूंगा।

सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि जल संकट का मामला है यह किसी पार्टी का या किसी सरकार का नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति का है, प्रत्येक जनप्रतिनिधि का है, तो इस पर हमें दलीय राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करनी चाहिए। वह क्या ऐसे लोंग प्रोस्पेक्टिव प्लान हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति का पानी सिंचाई के लिए मिले और पीने के लिए मिले। उस रूप में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। हम 4-5 चीजों को देखें कि क्लाइमेंट चेंज हो

रहे हैं, दुनिया कह रही है। क्लाइमेंट एक्सपट्र्स चिंता कर रहे हैं, क्लाइमेंट चेंज हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, भारत के सन्दर्भ में तो अपन सभी जानते हैं।

VPS-RTM-05.03.2025-17.40-3j

तीसरा, इतना ओवर यूज एंड वेस्टेज हो रहा है, यह सब हम गवाह हैं। आप गांव में कहते हैं कई बार कि पानी नहीं है, वहां मैं भी जाता हूं और आप भी जाते हैं, लोग भैंसों को, जानवरों को चम्बल के पानी से नहला रहे होते हैं। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। चौथा है पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन की वजह से पानी कितना दूषित हो रहा है। बहुत सारे सदस्यों ने यह बात उठायी थी, चाहे वह सिंचाई का पानी हो और चाहे वह पीने का पानी हो और मैं भरतपुर का उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां पिछले दस वर्ष से पता नहीं क्या हुआ है, कैंसर के मरीजों की, जैसे कि खबर आती है, डाक्टर्स बताते हैं कि कैंसर के मरीज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उसके पीछे एक प्रमुख कारण वे यह बताते हैं पानी की उपलब्धता और एक सबसे बड़ा एक और कारण है कि पानी है, बरसात आती है, बाढ़ भी आती है और हमारा इतने वर्षों के बावजूद भी, इसमें मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूं, उसके लिए सभी जिम्मेदार है। अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पूअर है। जो प्रवाह तंत्र है, विभिन्न नदियों का, मैं स्वर्गीय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने नदियों को जोड़ने की जो परियोजना लेकर आये थे, वह बड़ी अच्छी परियोजनाएं हैं। सबसे फोकस देना चाहिए सिंचाई के पानी के ऊपर। जो नाले हैं, कैनाल है, नदिया हैं, जब तक आप उनको नहीं जोड़ोगे उनको तो पीने का पानी कहां से मिलेगा, यह बता दीजिए मुझे तो हमारा फोकस पहले सिंचाई पर होना चाहिए कि जो अतिरिक्त पानी, लाखों गैलन पानी चला जाता है, समुद्र में जाकर मिल जाता है तो उसका यूज कैसे करे? तो प्रत्येक सरकार को उस प्रवाह तंत्र को मजबूत करे।

मैं भरतपुर के सन्दर्भ में यह उदाहरण देना चाहूंगा, सिंचाई मंत्रीजी बैठे हुए हैं और जल मंत्रीजी बैठे हुए हैं। भरतपुर के बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे भिजवाये गये हैं और निश्चित रूप से सिंचाई संसाधन मंत्री उनका ध्यान रखेंगे। जल जीवन की हम बहुत सारे लोग बात करते हैं। भ्रष्टाचार की भी बात करते हैं तो मुझे यह बता दीजिए कि किस योजना में भ्रष्टाचार नहीं है, यह बता दीजिए आप। कहां भ्रष्टाचार नहीं पनपता? चाहे कोई सी भी योजना है लेकिन उसको सुधारने की जरूरत है। उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन जो योजना बनाई गयी थी, मेरे को ध्यान है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, वर्ष 2016-17 में इसके सर्वे हुए थे। योजना कब की है? 2016-17 की है, उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं है। जहां पर ग्राउंड वॉटर नहीं है वहां पर ट्यूबवैल का प्रोविजन कर दिया, वहां पर टंकियां बना दी गयीं, टंकियां सूख रही हैं तो इस चीज को भी देखना चाहिए, इस चीज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा, दोनों माननीय मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं कि जल संरक्षण, जब तक हम नदियों को नहीं जोड़ेंगे, रिचार्जिंग

सिस्टम को डवलप नहीं करेंगे और जो कुशल सिंचाई सिस्टम है, वह भी आप जानते हैं, रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम है, डिसेलिनेशन अब बड़ा नया चल रहा है, समुद्र का खारा पानी या जहां पर भी खारा पानी है, उसके लिए मीठे पानी के प्लांट लगने लग गये हैं, उसको भी करें और इसी तरह से सबसे मजबूत काम अगर आप करेंगे तो प्रवाह तंत्र को मजबूत करिये और इसके लिए मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा, भरतपुर की एक घटना है, यह आप भी जानते हैं, मैं आपके संज्ञान में भी लाया था और यह सबके संज्ञान में है कि वर्षों से और जब भी बरसात आती है तो हरियाणा पानी जब अतिरिक्त छोड़ देता है, जब बाढ़ आती है तो वह हमें गुडगांव कैनाल से पानी देता है, जिसकी वजह से हमारी हजारों हैक्टेयर भूमि बरबाद हो जाती है और कुछ गांव हैं जिनका मैं बताना चाहूंगा, जिनका प्रवाह तंत्र मजबूत करने के लिए आपको भेजा है। जघीना, हथैनी, जाटोली, गांवड़ी, मडरपुर, फुलवारा, इकरन, रूंध इकरन, बछामदी, इसी तरह से तहसील डीग, कुम्हेर का पूरा एरिया है जहां पर छोटे-छोटे बांध हैं और वह पानी जो, यमुना जल समझौता का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि आपको सबको यह मालूम है, माननीय मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं कि यमुना जल समझौता हुआ था 1994 में, पांच राज्यों के बीच में यह हुआ था और 2005 में एक सहमति बनी थी कि केन्द्रीय जल आयोग ने यह कहा था कि हरियाणा से सहमति ली जाये। वह अभी केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन है। अब केन्द्र में भी आपकी सरकार है और यहां पर भी आप सरकार में है तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि 481 क्यूसेक पानी है, वह अभी नहीं मिल पा रहा है। 800 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है क्योंकि हमारा प्रवाह तंत्र मजबूत नहीं है तो इसके लिए हमने प्रस्ताव भिजवाया है, वह प्रस्ताव मैं टेबल कर रहा हूं। यह पूरे जिले के प्रस्ताव हैं, यह केवल भरतपुर विधान सभा क्षेत्र के नहीं हैं। यह पूरे भरतपुर जिले के सारे लोगों के प्रस्ताव हैं।

दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा बाण गंगा और एक गम्भीरी नंदी। मेरे से पूर्व साथियों ने भी चर्चा की थी, रामकेश मीणजी ने भी चर्चा की थी, पांचना का पानी, पूरे पूर्वी राजस्थान की जान है। जिस तरह से ई.आर.सी.पी. और चम्बल परियोजना है, उसी तरह से पांचना का बांध का पानी मिलना चाहिए और हाईकोर्ट का निर्णय हो चुका है तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस पांचना के बांध के पानी के ऊपर भी ध्यान दें।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ मेरे क्षेत्र की मांगें हैं, उनको मैं यहां पर रखना चाह रहा हूं माननीय मंत्रीजी, आपके सामने। एक मुरबारा बांध है, चिकसाना बांध को ई.आर.सी.पी. जो राम जल सेतु योजना है, उससे जोड़ा जाये। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि एम.एम. कैनाल और होम कैनाल एवं अजान कैनाल के प्रवाह तंत्र को मजबूत किया जाये जिसके प्रपोजल आपके सामने विचाराधीन है, हम भेज चुके हैं और चम्बल पेयजल परियोजना को अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है। यह दुर्भाग्य है, माननीय सभापति महोदय, 2010-11 की यह योजना थी, अभी तक वह पूरी नहीं हो पायी है जिसकी वजह से भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को पानी नहीं मिल पा रहा है।

एक बात और कहना चाहूंगा जो पेयजल से सम्बन्धित है। माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं। भरतपुर शहर की गैर अनुमोदित कॉलोनियों में चम्बल पेयजल की व्यवस्था की जाये और इसी तरह से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो अवैध कनेक्शन है, यह सबकी प्राब्लम है, सहारण साहब ने भी अभी यह मुद्दा उठाया था, यह अवैध कनेक्शन रोकने के लिए वास्तव में विजिलेंस की जरूरत है। आधे लोगों को ही पानी मिल रहा है और आधे लोगों को नहीं मिल रहा है और जो पावरफुल लोग हैं जो बाहुबली हैं, वे पानी को खोल लेते हैं, अवैध कनेक्शन कर लेते हैं और एक बात और कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन को अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं तो इस जल जीवन मिशन को पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट के अधीन लिया जाये, ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतों का मामला है, अन्यथा कितनी भी कोशिश कर लेना आप और कोई भी मतलब, जिसकी भी जो सरकार होती है, जिम्मेदारी उसकी होती है तो यह स्कीम सफल नहीं हो पायेगी।

इसी के साथ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि दो योजनाएं हैं, माननीय पेयजल मंत्रीजी को मालूम है, उसके लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा। 710 करोड़ रुपये की जो चम्बल से एक पाइप लाइन डलनी थी, उसके टेंडर हो चुके हैं, शायद कार्यादेश जारी कर देंगे। एक और, 1288 करोड़ रुपये की परियोजना और है, यह भी आपको मालूम है, उसके जल्दी से टेंडर जारी कर दीजिए तो घना को पानी मिलेगा जो हमारा अंतरराष्ट्रीय हेरिटेज है और वह एक पहचान है, पूरे इंडिया की पहचान है घना बर्ड सेंक्चुअरी, उसके लिए भी पानी मिलेगा और पूरे भरतपुर, अलवर दोनों जिले की वह योजना है, अब तो डीग भी है उसमें, तीसरा जिला डीग भी है, जिसमें वैर, बयाना, भरतपुर के वह भी गांव उस 1288 करोड़ रुपये की योजना में हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं दोनों माननीय मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ा पानी का संकट है। सिंचाई का पानी दे दीजिए और पीने का पानी दे दीजिए, वहां पर जमीन बहुत उपजाऊ है, किसानों की आय वैसे ही तिगनी हो जायेगी जो आप दुगनी, तिगनी करना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(माननीय सदस्य डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर) द्वारा कागज टेबल किये गये।)

श्री सभापतिः श्री कंवरलाल।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 एवं 42 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरे सदन के सब माननीय सदस्यों ने पानी पर बहुत गम्भीरता से चर्चा की है और राजस्थान, रेगिस्तान पानी की कमी के बारे में चर्चित है और उसकी यह पहचान है लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं खुश किस्मत हूं कि अंता विधान सभा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि आपके बीच में आकर मुझे बात करने का मौका दिया है। अंता विधान सभा क्षेत्र पूरा तीनों नदियों की तरफ से घिरा हुआ है। पहले राजस्थान की माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने परवन वृहद

सिंचाई परियोजना का जो शुभारंभ किया है उसका 85 परसेंट काम पूरा हो चुका है। मेरा 30 परसेंट विधान सभा क्षेत्र इस परियोजना से सिंचित हो जायेगा और दूसरा बीच में से जो अंता विधान सभा क्षेत्र में, चम्बल का आशीर्वाद जो मिला है, वह दायीं मुख्य नहर, मैं माननीय भजन लालजी को और आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं कि दायीं मुख्य नहर का जीर्णोद्धार करने के लिए 413 करोड़ रुपये और माइनरों, सब माइनरों को अच्छा करने के लिए, पक्का बनाने के लिए 471 करोड़ रुपये की जो स्वीकृत दी है, उसके लिए उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(समय: 17.48 बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

मैं यह कहता हूं कि अगर यह सब काम समय पर पूरा हो जाता है, माननीय मंत्री महोदय, तो अंता की जनता आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगी क्योंकि पूरा क्षेत्र में इर्रिगेशन होने वाला है। पूरा समतल क्षेत्र है और पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन पानी का मैनेजमेंट करने की कमी है, बस मात्र। मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं करते हुए यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार के अशोकजी गहलोत के समय, मेरे साथी पूर्व कैबिनेट मंत्री, गोपालन मंत्री के समय जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी बात मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। वहां पर गणेशगंज लिफ्ट परियोजना है, उस समय उसका टेंडर हुआ, टेंडर में 150 किलोवॉट की पांच मोटरें लगने का टेंडर हुआ था लेकिन उन्होंने बदनीयती से उसमें गड़बड़ी और घोटाला करके उनकी कम्पनी को एक टेंडर दिया और टेंडर में 130 की ही मोटरें लगायीं। पूरे दो साल तक अंता के किसान चिल्लाते रहे, चीखते रहे लेकिन सरकार के कान तक जूं नहीं रेंगी और किसान की खेती असिंचित रही।

ssy/rtm/05.03.2025/17.50/3k

उनका नुकसान हुआ। जैसे ही जनता का आशीर्वाद मिला, हमारे माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने और हमारे सिंचाई मंत्री जी ने 3 मोटरों की उस समय स्वीकृति दे दी और 2 मोटरों की अभी स्वीकृति दे दी, जब 5 मोटरें चलेंगी तो किसानों की जो बची हुई जमीन है, वह अच्छी तरह से सिंचित होगी। यह भ्रष्टाचार का एक सैंपल है।

दूसरा, चंबल से निकलने वाली जो दाईं नहर है, बहुत बड़ी कैनाल है, वह अंता को सिंचित करती हुई मध्य प्रदेश को जाती है। उसमें दो ऑफिस हैं, अंता नगर में भी ऑफिस है और मांगरोल में भी ऑफिस है। 32 बीघा जमीन में बहुत शानदार ऑफिस बने हुए थे, लेकिन उस समय के मंत्री जी ने बदनीयत से उन ऑफिसों को तोड़ दिया, तहस-नहस कर दिया और अन्य डिपार्टमेंट को दे दिया गया। यानी की सीएडी के इतने बड़े नहरी तंत्र को मैनेज करने के लिए आज एनटीपीसी के किराए के भवन में हमारा डिपार्टमेंट चलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इतने बड़े डिपार्टमेंट को, इतने बड़े नहरी तंत्र को और पानी जैसे काम को करने के लिए मांगरोल में ऑफिस बनाया जाये।

श्री सभापतिः प्लीज, आवाज कम करें।

श्री कंवरलाल (अंता): ईआरसीपी योजना के अंदर मेरी अंता विधान सभा क्षेत्र में एक तरफ ईआरसीपी का डैम है और दूसरा नोदेड़ा डैम है। मैं कहता हूं पूरे अंता क्षेत्र में बीच में से कैनाल निकलती है, दोनों तरफ से ईआरसीपी योजना में जुड़ेगा, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय के प्रसंज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में बीच में तालाब है और जो किसी धार्मिक नाम से, कोई गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है, कोई हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है, कोई किस नाम से प्रसिद्ध है, वह किशनपुरा तेजाजी का तालाब, बोरदा का तालाब, राउल जावल का तालाब, इन सब का रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन का काम अगर आपके माध्यम से होता है, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो नहरें निकलती है और उसके बाद जो टैल माइनर है उनका पानी अगर इन तालाबों में डाला जाए तो मैं कहता हूं पूरे तालाब भरे रहेंगे, जानवरों का पानी होगा, पीने को पानी होगा और जो महंगा पानी व्यर्थ बहकर नदी में चला जाता है वह रुकेगा और जनता को, किसानों को, लोगों को बहुत फायदा मिलेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मेरी एक बात और रखना चाहता हूं, बाण गंगा नदी है, इस नदी का कार्य मेरे क्षेत्र में स्वीकृत किया गया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इसकी बारिश के पानी में शीघ्र निकासी हो जाती थी, किसान फसल को भी नहीं ले सकते थे, पहले जल भराव के कारण संभव नहीं था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार मेरी इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी, आने वाले समय में इस दिशा में आवश्यक कदम उठायेगी। अगर हौसला बुलंद है तो हर काम, सपना सच होता है, सरकार की नीयत अच्छी हो तो हर खेत हरा-भरा हो सकता है।

मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह किसान हितैषी हमारी सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है, जल्दी ही बारां में स्थित कृषि उपज मंडी के विस्तार की आवश्यकता पड़ेगी।

अंत में, एक बार फिर मैं क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मेरी बात को रखने का मौका दिया। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

(स्वीकृति)

श्री सभापतिः सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

श्री मनोज कुमार।

अनुदान की मांग
मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर विचार

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 41 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

पानी का महत्वपूर्ण विषय है, पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले एक साल से जिस तरह से पानी की समस्या मेरे क्षेत्र में हुई है, पहले कभी इतनी गंभीर लोगों ने नहीं देखी। सर्दियां निकली हैं, सर्दियों में भी पानी सप्लाई जो 4 से 6 दिन हमारे वहां थी, उसका चक्र बढ़कर अब 10 से 15 और 15 से 20 दिन से पार कर गया है। गर्मियां अभी शुरू हुई नहीं हैं। क्या हालात होंगे यह आप समझ सकते हैं।

कुछ ही दिनों में नहरबंदी भी होने वाली है और उसके बाद कैसे इन हालात में पार पड़ेगी, अपन कह नहीं सकते। एल एंड टी कंपनी जिसको नहर के पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी है, वह भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रही है। उसके पास 10 साल का ओएंडएम है, पर ना तो वह पूरे कर्मचारी रखती है और ना ही पूरा मेंटेनेंस कर पा रही है। लीकेज हो गए तो महीने-महीने लीकेज ठीक नहीं होते। वाल्व जो लगे हुए हैं उनको बराबर ऑपरेट नहीं कर रहे क्योंकि उनके लिए आदमी रखना पड़ता है और बिना वाल्व के पानी की सप्लाई पूरे गांव में हो नहीं पाती। गांव आप जानते हैं ऊंचाई निचाई पर बसे होते हैं। टंकी खोल दी तो जो वाल्व खोल दिया वह खोल दिया। ढलान में पानी चला जाता है, उसको बंद नहीं करते तो ऊंचाई वाले एरिया में जा नहीं पाता। कर्मचारी इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनको पैसा देना पड़ता है। पैसा सरकार देती है फिर भी वह नहीं दे रहे। कारण यह है कि उन्होंने आगे सबलेट कर रखे हैं, जिनको जिम्मेदारी है, वह कहीं ना कहीं पैसा बचाना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं और जनता प्यासी मरती जा रही है।

सभापति महोदय, जे जे एम की बात है, अभी हाल ही में एक दो टंकियां पूरी हुई हैं। 20 टंकियों का निर्माण जे जे एम के तहत मेरी दोनों तहसीलों में हुआ। अभी प्रश्न भी लगाया था सब के सब निर्माणाधीन बतायी हैं। एक तरफ आप सारी टंकियां निर्माणाधीन बता रहे हो और दूसरी तरफ पोर्टल पर जे जे एम में लाखों कनेक्शन दिला रहे हो कि हमने लाखों कनेक्शन कर दिये। पानी सप्लाई दे दिया। जब टंकिया बनी नहीं, उनसे सप्लाई चालू नहीं हुई, घरों में पानी पहुंचा नहीं तो किस तरह से आपने उन घरों में पानी की सप्लाई दे दी और कैसे पोर्टल पर भ्रामक आंकड़े आप दे रहे हो?

हकीकत देखिये कि सिर्फ कनेक्शन जोड़ दिए, बाकी जो पाइप लाइन है वह जो जॉइंट है, वहां यों खड़े पड़े हैं, पानी की एक भी टंकी चालू नहीं है। आपने जवाब में भी लिखा है और वह लगभग अधूरी पड़ी है। दो-तीन पूरी हुई है उनको चालू करने की कोशिश की पर उनमें पानी रुका नहीं। जब पानी की टंकियों में पानी दिया ही नहीं तो उनको पोर्टल पर जो सिर्फ कनेक्शन घरों में नल लगा दिए और उनके मार्फत आप कह रहे हो कि हमने जेजेएम की

घरों में सप्लाई कर दी। कम से कम यह भ्रामक आंकड़े बंद करो, इसका सिस्टम सुधारो। उसी घर को आप पोर्टल पर जोड़ो जिसको वास्तव में पानी सप्लाई दे दिया। उसको आपको देना चाहिए। वरना आपके टारगेट पूरे हो जाएंगे और पानी कहीं पहुंचेगा ही नहीं।

अभी मेरे साथी बता रहे थे कि किस तरह से पिछले राज में ट्यूबवैल खोदे गए थे, इस बार नाम मात्र के आपने 10 दिए, जब सैंक्शन की बात आई तो आपने 5-5 सैंक्शन किये। कोई बात नहीं, पर समस्या उन ट्यूबवैलों की है कि जो ट्यूब वेल फेल हो रहे हैं। उन फेल ट्यूबेवैल के अगेंस्ट तो आपके ट्यूबवैल बनाने पड़ेगे। अगर उनके अगेंस्ट में ट्यूब वेल नहीं बनाएंगे तो पूरा जो ढांचा गांव का ट्यूबवैलों है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आधा हिस्सा जहां ट्यूबवैल सक्सेस नहीं हैं, पानी कम है, पर आधा हिस्सा वह है बीदासर साइड में सुजानगढ़ के जहां पर पानी अवलेबल है और पूरा एरिया पीने के पानी के लिए ट्यूब वेलों पर निर्भर है, ट्यूबवैल फेल हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा खुदता नहीं है। दूसरा सोर्स है नहीं। पानी की सप्लाई नहर की कैसी है, वह मैंने आपको बता दी, तो कम से कम जो फेल ट्यूब वेल है उनकी सैंक्शन जो प्रस्ताव आपके पास वहां आते हैं उनको तुरंत करना चाहिए। नये तो करो या नहीं करो, पर फेल का तो जरूर करो।

दूसरा, मेंटेनेंस की हालत यह है कि उनके पास केबल नहीं है। पानी से पाइप लाइन गल जाती है, उसको बदलने के लिए नहीं है। बहुत बड़ी समस्या मेंटेनेंस की है। आधे टाइम तो ट्यूबवैल सिर्फ इसलिए खराब पड़े रहते हैं कि मेंटेनेंस के सामान का टेंडर नहीं हुआ। सामान विभाग के पास नहीं है और उस वजह से सफर कौन कर रहा है, ग्रामवासी कर रहे हैं।

spp/rtm/05.03.2025/18.00/3l

पिछली बार मंत्री जी ने बहुत अच्छा रिबोर का प्रोजेक्ट्स लिया था कि हम जो ट्यूबवैल फैल गया, अगर वो रिबोर हो सकते हैं, तो हम रिबोर करायेंगे। मंत्रीजी ये बताएं की कहाँ तक उसकी आपको सफलता मिली? मैंने अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने कहा हमें अभी दो-दो ट्यूबवैल की परमिशन मिली है रिबोर की। एक बहुत अच्छा विभाग का अगर ये होगा कि बहुत से ऐसे ट्यूबवैल हैं, वह सिर्फ इसलिए फैल हो गए कि पानी थोड़ा नीचे चला गया। अगर उनको हमने 100 फुट और खोद दिया तो वहां पानी निकल सकता है। हमारे यहाँ जो ट्यूबवैल बन रहा है, कम से कम 25 लाख में बनते हैं। 25 से 30 लाख में विभाग वो ट्यूबवैल खोदता है। कितना महंगा है, अपन समझ सकते हैं। अगर वो ही फैल ट्यूबवैल रिबोर अगर 100-150 फुट हो गया और पानी अगर आ रहा है तो कम से कम उस समय तक जब तक वो ट्यूबवैल चलेगा, एक बहुत बड़ी समस्या का निदान होगा और बहुत बड़ा पैसा बचेगा। जहां विभाग अनुशंसा करेगा यह ट्यूबवेल रिबोर हो सकते हैं तो उनको रिबोर कराकर चालू अगर कर दें अपन तो एक बहुत बड़ी पानी की समस्या है, वो भी बचेगी।

माननीय सभापति महोदय, फैल ट्यूबवैलों की बात हुई। बहुत से मेरे ऐसे गांव हैं सांडवा, काकर छोटी, काकर बड़ी, मूंदडा, लिखमनसर, नोडिया, मारोठिया, रेडा, भासीणा, लुहारा,

ऊंटाला, लालगढ़, साजनसर, गिरवरसर, कोडासर, ढाणी पोटणिया, घंटियाल यहां के ट्यूबवैल् या तो फैल हो गए या सामान के अभाव में खराब पड़े हैं। अगर ये चालू हो जाएं तो ये जो 15-20 गांव हैं, कम से कम इन गांवों में पानी का जो लोकल सोर्स है वो आपका चालू हो जाएगा और कम से कम पीने का पानी कुछ मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, नहर के पानी की अपनी एक सीमा है क्योंकि जितना पानी मिलना था उससे कम आ रहा है। ये भी आप दिखाएं कि पानी जा कहाँ रहा है? 45 एमएलडी पानी सुजानगढ़ के लिए स्वीकृत है। पानी पूरा आता नहीं है। धन्नासर से सरदारशाहर आता है, सरदारशहर से रतनगढ़, रतनगढ़ से सुजानगढ़ अलग अलग वहाँ से रतनगढ़ से लक्ष्मणगढ़-सीकर अलग लाइन जाती है फतेहपुर की, सरदारशहर से अलग पानी फट जाता है और पाइप लाइन अभी हमारे पूर्व सदस्य बता रहे थे कि बार बार वो लीकेज होती है और एक बार जो पाइप लाइन में लीकेज होती है तो पांच-सात दिन का शिड्यूल पूरा बिगड़ जाता है?

दूसरा जो पानी की चोरी हो रही है, यह भी बहुत बड़ी एक समस्या है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जो चोरी है, मुक़दमे सबसे ज्यादा इसी के शुरू हो जाएंगे। जहाँ से पाइपलाइन गुजरती हैं या तो खेत वाले चोरी कर लेते हैं। गांव में जहाँ पानी आता है जो सक्षम हैं, वो मोटर लगाकर पूरा पानी खींच लेते है फर्स्ट पॉइंट पर ही। इससे पूरे गांव में पानी सप्लाई नहीं होता। इस पानी की चोरी को रोकने का प्रयास करने का विभाग में कोई शिकायत जाती है चोरी की, तो बड़ी विडंबना है कि विभाग कहता है कि आप लोग मुकदमा इसका दर्ज कराओ, आप लोग एफआइआर कराओ, तब हम लोग आगे कोई बात करेंगे। पानी विभाग का, लाइनें विभाग कीं तो विभाग क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराता? गांव वाला गांव के दूसरे अपने साथी से, अपने भाई से बैर नहीं ले सकता। सरपंच मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता, उसको आगे चुनाव लड़ना है और उनसे जीत कर आता है वो मुकदमा दर्ज नहीं कराता। कहीं ना कहीं वो दबाव में रहता है, इसलिए आप विभाग को आदेश दें कि विभाग, जो चोरी की जहाँ भी सूचना मिलती है, एफआइआर दर्ज करे, उनके विरूद्ध कार्रवाई करे।

माननीय सभापति महोदय, तीसरा ये जो जेजेएम में कुछ गांव फर्स्ट फेज में हमारे हुए थे, उनमें तीन गांव ऐसे हैं जिनका कोई धणी-धोरी नहीं हैं। PHED कहती है हमारे अंडर में नहीं हैं, पीएमसी कहती है, हमारे अंडर में नहीं है, पंचायत कहती है हमारे को परमिशन नहीं है। कोई भी उनकी मेंटिनेंस, कोई भी उनकी सार संभाल नहीं कर रहा है। ये फर्स्ट फेज में बने थे 2020-2021 से पहले। पंचायतों ने उस समय 10% राशि कलेक्ट की थी। वो बजट पंचायत में एक फंड में पड़ा है, पर न तो उनको स्वीकृति दे रहे हैं कि उस फंड से वो कनेक्शन चालू कर सकें, उसको खर्च करके, न उस फंड को वो मेंटिनेंस में उपयोग में ले रहे हैं। उसके बाद तो सरकार ने कह दिया था कि कोई फंड कलेक्ट नहीं करेंगे। पर उन तीन गांवों में वो फंड पड़ा है। ऐसे और भी बहुत सी जगह राजस्थान में होंगी। आप कृपा करके स्पष्ट निर्देश दें कि इस फंड को वह मेंटिनेंस में काम ले सकें, क्योंकि मेंटिनेंस आ रहा है ये

मानकर चलिए। पाइप लाइनें ऐसी हैं कहीं भी टूट जाती है सरपंच उनको ठीक कराता नहीं है। विभाग भी नहीं करता और तीनों गांव बंद पड़े हैं। सप्लाई इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कहीं पाइपलाइन फट गई, कहीं पाइप लाइन लीकेज है इसलिए ये हो नहीं रहा है। इसलिए मेरी यही मांग है कि पानी बहुत बड़ी एक समस्या आने वाले समय में हो जाएगी, इसलिए अपन इसको सुधार करें। पानी सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापतिः डॉ. ऋतु जी बनावत।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का समय दिया।

"जलं हि प्राणिनः प्राणाः जलं शस्यस्य जीवनम्।
न जलेन विना लोके शस्यबीजं प्रजायते।।"

अर्थात् जल जीवित प्राणियों की जीवनधारा है। जल ही फसल का जीवन है। पानी के बिना दुनिया में कहीं भी जीवन के बीज पैदा नहीं हो सकते। माननीय सभापति महोदय, ये तो सर्वविदित है कि जल के बिना जीवन निराधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती और जैसे कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग हर सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो आम जनता को पेयजल व सिंचाई के हेतु जल उपलब्धता को पूर्ण करने के सहयोग प्रदान करते हुए आवश्यक कदम उठाएं। किंतु हमने देखा कि पिछली सरकार द्वारा इस हेतु किए गए निरर्थक प्रयासों और केवल केंद्र सरकार पर आरोप की परिणति बखूबी से हम सबने देखी है, जिसके माध्यम से हम यह कहें कि जल जीवन मिशन, जिसके माध्यम से आम राजस्थानी के घर का सूखा मिट सकता था, ईआरसीपी के माध्यम से तब के 13 जिलों को सिंचाई का पेयजल मिल सकता था, सिंचाई हेतु पानी मिल सकता था, लेकिन हमने यह भी देखा कि जल जीवन मिशन को जल घोटाला मिशन बनाकर पिछली सरकार ने रख दिया और भ्रष्टाचार इतना हुआ कि अखबार की सुर्खियों में, हर दिन अखबार की सुर्खियाँ जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को बयां करती थीं। फिर राजस्थान में जनता ने राज़ बदला, सोच को बदला, आइडियोलॉजी को बदला और आम राजस्थान का नागरिक सोचने लगा कि हममें से कोई राजस्थान की सत्ता पर आये और आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के प्रयास से किसान का बेटा, हम सब के दर्द को समझने वाला व्यक्ति राजस्थान के मुखिया बने आदरणीय भजन लाल जी, और राजस्थान के दर्द को समझते हुए राज्य में जल आपूर्ति और संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये। उनके भागीरथी प्रयासों का ही परिणाम था कि राम जलसेतु लिंक परियोजना, जिससे 17 जिलों में सवा तीन करोड़ लोगों को पेयजल की उपलब्धता हुई। मुख्य मंत्री जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यमुना जल समझौता, जिससे कि शेखावाटी की पेयजल समस्या का स्थायी निदान होगा। इन सब प्रयासों के माध्यम से हमारे मुख्य मंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। प्रयास अगर पहले से शुरू होते तो आज काम धरातल पर होते। आज प्रयास शुरू हो चुके हैं और काम भी धीरे

धीरे धरातल पर दिखाई देने लगे हैं।

अब हम बात करें मंत्रीजी की, आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी मंत्री जी ने जल जीवन मिशन में हो रहे घोटालों के लिए, मैंने जब भी बताया मेरे क्षेत्र में दो-तीन पंचायतों की शिकायतें मैंने जब भी बताईं, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ़ जांच बिठाई तो यह कहना निरर्थक है कि प्रयास नहीं किए जा रहे। जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार सरकारों में हुए, उन को खत्म करने का प्रयास यह सरकार कर रही है और इसलिए यह साधुवाद की पात्र है।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन की समीक्षा की जरूरत है और इसके लिए मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहती हूँ मंत्री जी। इसमें मैं यह कहना चाहती हूँ कि अमृत-2 योजना में भरतपुर जिले में दो बार निविदा हुई हैं और दो बार निविदा होने के बाद एक ही फर्म आयी है। मेरा कहना यह है कि आप भरतपुर जिले की प्रोपर, भरतपुर जिले की एक साथ न करके, अगर अलग अलग करेंगे क्योंकि हमारे पास जो टाइम लिमिट बढ़ा है, जल जीवन मिशन का, वो 2028 तक का है। मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर हम जल्दी काम पूरा करना चाहते हैं तो इस निविदा का जो टाइम है, जो विधान सभा क्षेत्रवाइज कर लें या ब्लॉकवाइज कर लें, जिससे क्वालिटी भी बढ़े और आपका टाइम स्पीडली यह काम हो सके?

साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि जे.जे.एम. मे ढाणियों और नगलों को, जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं, इस जे.जे.मिशन स्कीम के तहत उनको भी जोड़ा जाए, जिससे ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाएं।

एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जे.जे.एम. में पंचायतों में आपका डिबोर हो गया, टंकियां बन गई, पानी भी शुरू हो गया। ठेकेदार ने हैंड ओवर की जब बात की तो हैंड ओवर न तो पंचायत का सरपंच लेना चाहता है और ले भी लेता है तो वो थोड़े दिन बाद मेंटिनेंस के अभाव में वो योजना गौण हो जाती है तो मेरा मंत्रीजी को यह सुझाव है कि पीएचईडी इसको हाथ में ले, ताकि इसका प्रोपर वाटर सप्लाई का काम हो सके हर गांव में, पंचायतों में जो-जो जे.जे.एम. स्कीम में आ रहे हैं।

jyg/rtm/05.03.25/18.10/3m

साथ ही मैं कहूंगी कि प्रोपर वाटर सप्लाई के लिए हमें लोगों की भी आवश्यकता होती है, मेन पावर की भी आवश्यकता होती है और हमारी इस जेजेएम में भी है कि नल जल मित्र योजना के माध्यम से हर पंचायत पर लोगों को लगाया जाये तो जो दो लोग आप लगायें हर पंचायत पर उनको जल्दी नियुक्त करें ताकि जहां पर टंकियां बन चुकी है वहां पर प्रोपर वाटर सप्लाई शुरू हो।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि आज भरतपुर के दैनिक भास्कर में एक खबर छपी कि 2013 में जो पूर्व में हमारी योजना थी, हमारी बीजेपी सरकार

की योजना थी उसमे आरओ प्लांट्स लगाये गये थे। भरतपुर-डीग जिले में 288 में से 294 आरओ प्लांट अभी बंद हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि एक कहावत भी है इंग्लिश में, “Water means life; clean water means healthy life” तो मैं यह कहूंगी इन आरओ प्लांट्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकती है। मेरा यह निवेदन रहेगा कि इन आरओ प्लांट्स का ओ एण्ड एम नहीं होने के कारण से ये शुरू नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए पॉलिसी बनायी जाये और इनको शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जलदाय विभाग में जेईएन पद, बयाना, रूपवास में रिक्त हैं उन्हें शीघ्र भरा जाये, जिससे कि जमीनी स्तर पर फील्ड में लोगों को अधिकारी जाये और स्कीम की मॉनिटरिंग कर सके। मैं यह भी कहूंगी कि सोलर ट्यूबवैल, सभी जगह ओ एण्ड एम के कारण से बंद है। ओ एण्ड एम पॉलिसी आप डिसाइड करें जो भी सोलर ट्यूबवैल्स हैं, उनके लिए, जिससे लोग लाभांवित हो पाये। मेरे क्षेत्र में पहाड़ी और पठारी इलाका ज्यादा है, जो जेजेएम में पाइप लाइन डल रही है वो वहां पर सक्सेसफुल नहीं है तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप माइनिंग एरिया, डांग क्षेत्र में डीआई पाइप लाइन डालें, उसको रिवाइज करके सर्वे करायें, जिससे कि वो लौंग टाइम के लिए सक्सेसफुल हो सके और आपने यह किया भी है। महलपुर चूरा की मैंने शिकायत की थी उसमें आपने डीआई पाइप लाइन के लिए प्रपोजल मांगा है। मेरा निवेदन रहेगा कि पठारी और पहाड़ी इलाकों में आप इसका रिवाइज सर्वे करवाकर डीआई पाइप लाइन की बात करें।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में चम्बल परियोजना के 72 गांव जुड़े हुए हैं रूपवास में और आज की तारीख में हर गांव में 4-5 पोइंट होते हैं, अगर हम हर गांव की मोनिटरिंग करें तो हम देखेंगे कि फस्ट टू लास्ट जो पोइंट है वहां पर पानी की सप्लाई नहीं होती पाती है। या तो पहले और दूसरे पोइंट पर ही पानी आ जाता है, सब जगह पानी नहीं पहुंच पाता है। हम आज बात कर रहे हैं हर घर जल हर घर नल की तो चम्बल परियोजना के माध्यम से हम जिन जगहों पर जेजेएम परियोजना संचालित कर रहे हैं वहां पर ऐसे प्रयास करें कि ज्यादा पोइंट्स हों, ज्यादा चम्बल के पोइंट्स लगें, जिससे पूरे गांव में वाटर सप्लाई प्रोपर हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभांवित हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि चम्बल परियोजना से जुड़े हुए गांवों में यह भी होता है कि जलदाय विभाग और चम्बल वाले जो अधिकारी हैं उनमें आपस में कॉर्डिनेशन नहीं होता है और इससे क्या होता है कि आम लोग प्रभावित होते हैं। मेरा यह कहना है कि कम से कम गर्मियों में तो आपस में कॉर्डिनेशन बने और वो प्रोपर जल सप्लाई का काम हो सके जहां पर चम्बल का पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर टैंकर से उनको पानी की सप्लाई हो जाये तो लोग ज्यादा से ज्यादा लाभांवित हो पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि ईआरसीपी राम जल सेतु लिंक परियोजना, यह परियोजना हमारे जिलों के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए जीवन दायिनी

है, सबको मालूम है। जब से इसका नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना पडा है तो वाकई में मैं यह कहूं कि राम के आने से जो राम को लाये हैं, हम राम को लाये हैं, वो पानी भी लायेंगे, तो निश्चित तौर पर यह बहुत साधुवाद वाली योजना है। माननीय सभापति महोदय, इस योजना के माध्यम से डूंगरी बांध से बंध बारेठा और बंध बारेठा से चैनल के माध्यम से पानी भरतपुर तक ले जाने की योजना है। मेरा निवेदन है कि गम्भीरी नदी का नैचुरल वाटर फ्लो सेवला हैड से रूपवास की ओर है और गम्भीरी नदी व कूकू नदी का प्रवाह सुनिश्चित करते हुए उसको आप भरतपुर तो ले जायें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मालापुरा, कंजोली, दाहना, बाकोली, दोरदा, सिंघावली, चेकोरा, शकरपुर, पाण्डी, नयागांव तक यह पानी पहुंचे इसकी योजना भी साथ-साथ रहे, ताकि नैचुरल फ्लो वाले जो गांव हैं वो उस पानी के न होने से प्रभावित न हों।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि राम जल सेतु योजना में खानवा बंध को भी जोड़ा जाये और इसकी ऊँचाई भी बढ़ायी जाये।

श्री सभापति: अपनी बात समाप्त कीजिये।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय सभापति महोदय, जिससे रूपवास की ढहर तक पानी उपलब्ध हो सके। साथ ही मिलसुआ, मेरथा, इब्राहिमपुर, शकरपुर, नया गांव, चेकोरा ग्राम पंचायत का वाटर लेवल बढ़ सके। रूपवास के ढहर में डैम या एनिकट बनाया जाये, जिससे जल स्तर बढ़े।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिये।

श्री डूंगरराम गेदर।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और।

माननीय सभापति महोदय, पहाड़ी माइनर, धोरेया माइनर, खैयठाकुर माइनर, रूदावल माइनर इनकी भी लम्बाई बढ़ाई जाये। खण्ड कार्यालय खोला जाये, एक्सईएन कार्यालय रूपवास में खोला जाये, इर्रिगेशन का और रूपवास में खण्ड स्तरीय एईएन कार्यालय खोला जाये। बंध बारेठा की ऊँचाई बढ़ाने और जमा सिल्ट को भी हटाने की आवश्यकता यहां पर है। मैं यही कहूंगी कि गम्भीरी नदी और कूकू नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो भी अवरोधक चीजें आ रही हैं, उनको हटाकर इसका प्रवाह सुनिश्चित किया जाये। मैं यही कहूंगी कि बहुत काम पानी के क्षेत्र में हो रहा है, सरकार का बहुत साधुवाद है। मैं यही कहूंगी कि इसी तरह से काम करते रहें और हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): 000

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

पानी है कितनी अनमोल,

जान लो तुम इसका मोल,

बिना पानी है धरती सूनी,
बिन पानी जीवन का नहीं मोल।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मोल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के लोग सबसे ज्यादा इस महत्व को समझते हैं। यहां के लोग इसके महत्व को समझते हैं तो आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अन्दर किसान अपनी फसल बचाने के लिए धरना दे रहे हैं, हाइवे जाम किये हुए है और रात को धरने पर सोते हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट।

आज वक्ताओं की संख्या ज्यादा है, दोनों ही दलों ने बात कर ली है, आठ मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है, छह मिनट पर मैं घण्टी बजाऊंगा, दो मिनट में जो आपकी इम्पोर्टेण्ट बात है वो रख दें। कृपया समय का ध्यान रखते हुए, नहीं तो आज की रात एक बजेगी, इसलिए समय पर जाने के लिए दो-दो मिनट सभी का कम किया गया है। ...(व्यवधान)... प्लीज सदस्य।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, ठीक है। आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पानी का जो महत्व है वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के लोग समझते हैं और वहां किसानों की पकी हुई फसल है जहां लोग धरना दे रहे हैं पानी के लिए रात को वहीं सोते हैं, रात को वहीं खाते हैं और पानी की मांग के लिए धरना दे रहे हैं। एक तरफ तो गंगानगर, हनुमानगढ़ का किसान पानी के लिए धरना दे रहा है और दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है। आज से काफी साल पहले हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने कहा था कि पाकिस्तान के अन्दर एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ने भी कहा था कि पाकिस्तान को एक-एक बूंद पानी के लिए तरसा देंगे, लेकिन हालात ये हैं कि आज जहां हम पानी के लिए तरस रहे हैं वहां 600-700 क्यूसेक से लेकर 1800 क्यूसेक तक पानी पाकिस्तान जा रहा है। दूसरी तरफ सरहिंद फीडर की मरम्मत का काम पंजाब सरकार ने और राजस्थान सरकार ने जो पैसा दिया, उसके लिए उन्होंने जनवरी में काम शुरू कर दिया और जनवरी में काम शुरू होने की वजह से 5 फरवरी से आईजीएनपी का जो सिंचाई का पानी है वो बंद कर दिया, एक-दो पानी सिंचाई के उधर के किसानों को मिलने चाहिए थे, ये हालात खराब करने का काम पंजाब की सरकार ने और राजस्थान सरकार ने, दोनों ने मिलकर इसको खराब करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के अन्दर लगभग 12 लाख एकड़ में गेहूं की बिजाई हुई, लेकिन किसान पानी के लिए पूरी तरह से तरस रहा है, इसके लिए राजस्थान सरकार को पूरी तरह से इस बात के लिए संज्ञान लेने की जरूरत है। सूरतगढ़ के अन्दर 365.5 आरडी पर क्रोस रेगुलेटर बने हुए एक साल हो गया, लेकिन उस क्रोस रेगुलेटर को चालू नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिरदवाल से लेकर 335 आरडी तक जो नहरें हैं या जो आउटलेट हैं, नहर के अन्दर, उन सारे के सारे किसानों को पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, भारी दिक्कत हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अन्दर खाळे जो 20 से 25 साल पुराने बने हुए हैं, उन खाळों की मरम्मत की जरूरत है, उन खाळों के लिए बजट देने की जरूरत है। नहीं तो किसानों का जो पानी है वो खराब आज भी हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 2025 तक जेजेएम के तहत सभी घरों तक हम पानी पहुंचा देंगे।

MLS/RTM/05.03.2025/18:20/3n

लेकिन इन्होंने अभी खुद ने ही उस जेजेएम योजना को 2028 तक बढ़ाने का काम किया है तो क्या यह संकल्प पत्र, जो इन्होंने पहले वादा किया था, उस वादे को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं? पिछली बार जो 2024-25 का बजट था, उसमें आपने जेजेएम योजना में 25 लाख परिवारों को नल से स्वच्छ पानी देने का वादा किया, लेकिन पिछले एक साल में पूरे राजस्थान में कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। इस योजना के तहत ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला और पीएचईडी विभाग के पास पैसा नहीं है। पैसे की वजह से हालात यहां तक बने हुए हैं कि यदि एक मोटर जल जाती है तो उसे भी ठीक कराने के लिए एक-एक महीना लगता है। जो लीकेजेज हैं, उन्हें ठीक कराने के लिए भी इनके पास सॉकेट नहीं मिलते हैं।

सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तीन-तीन नहर परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी वहां के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। इसके साथ-साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी के लिए आपने जनसंख्या के अनुपात में योजनाएं बनायी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो पशु पालक हैं, वे पशु पालते हैं और जो पशु पालते हैं, उन्हें भी पानी की जरूरत है। उन पशुओं को पालने के लिए जो पानी की जरूरत है, उसकी गणना आपने नहीं की है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पानी की किल्लत पूरे क्षेत्र में हो रही है। सूरतगढ़ उप खण्ड में एक एक्सईएन ऑफिस है, एक एईएन ऑफिस है और आज के हालात ये हैं कि अभी पीछे जब ट्रांसफर हुए तो आपने जेईएन के ट्रांसफर वहां से कर दिये, इसलिए एक ही एक्सईएन है, एक ही एईएन है और एक ही जेईएन है। इस वजह से भी बड़ी भारी दिक्कत वहां हो रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ क्षेत्र में जो जेईएन के चार पद हैं, वे पूरे किये जाएं और एईएन का एक और ऑफिस खोला जाये, ताकि वहां की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती 1992 के बाद राजस्थान में नहीं हुई। जेजेवाई योजना के कर्मचारी, लेबर कॉम्पोनेंट के कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारी मिलकर इस सारी योजना को चला रहे हैं। जो 1994 में जेजेवाई योजना के कर्मचारी आपने लगाये, आज 30-30 साल हो गये उन्हें इस विभाग में काम करते हुए, पूरी जिन्दगी उन्होंने इस विभाग में लगा दी, मात्र 7400 रुपये एक महीने का मानदेय मिलता है। उनका मानदेय बढ़ाया जाये और उन्हें

सहायक पम्प चालक का दर्जा दिया जाये, ताकि कम से कम जब उनकी उम्र 40, 50, 60 साल हो, तब वे यह तो कहें कि हम इस विभाग में इस तरह से काम करते थे, यह हमारा ओहदा था।

इसके साथ-साथ, मेरा यह भी कहना है कि लुधियाना शहर का जो बूढा नाला है, जालन्धर, नकोदर और फगवाड़ा का सीवरेज का जो कैमिकल युक्त पानी नहर के माध्यम से आ रहा है, उसे जब तक हम नहीं रोकेंगे, तब तक पूरे गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में टीबी, दमा, किडनी फेल्योर और कैंसर के पेशंट्स की भरमार रहेगी। बार-बार इस सदन के माध्यम से भी आवाज उठायी जा रही है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं है। सूरतगढ़ के चक और ढाणियों में जेजेएम योजना के तहत नल के द्वारा साफ व मीठा पानी पहुंचाया जाये और नयी जल योजना ठुकराना व 6 डीबीएन के अन्दर बनायी जाये।

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि जो जेजेएम योजना है, उसको अभी 2028 तक आपने रख दिया है, उस 2028 तक भी आप लोग उसे सही तरीके से पूरा करेंगे तो ढाणी-ढाणी पहुंचाने का काम करें और उसके लिए वहां कमेटी बनाकर काम किया जाये। बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इस योजना का बंटाढार हुआ जा रहा है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री रेवन्तराम डांगा।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): राम-राम सा। सभापति जी, थोड़ी दो मिंट दीजो मनै बत्ती। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पानी जैसे गम्भीर और बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर आज यह सदन चर्चा कर रहा है। इंसान के जीने के लिए हवा और पानी बहुत ही जरूरी हैं। रहीम जी ने अपने दोहों में भी पानी का महत्त्व बताया और कहा

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,

पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून।।

अर्थात पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और हमारे राजस्थान में तो पानी की क्या कीमत है, यह पश्चिमी राजस्थान के लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है? हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है, जहां पीने के पानी की एक-एक बून्द बहुत कीमती है। आजादी के बाद देश और प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर सभी सरकारों ने प्रयास किये, लेकिन आज भी हमारे प्रदेश के सैकड़ों गांव और ढाणियां स्वच्छ पेयजल का इन्तजार कर रहे हैं।

(समय : बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

मैं खुद गांव में रहने वाला किसान पुत्र हूं। मैंने पीने के पानी के लिए मशक्कत करती हुई हमारी माताओं-बहनों को देखा है, जोहड़ और तालाबों से पानी लाते देखा है, जो पीने योग्य नहीं होता था, लेकिन मजबूरी थी, पीना पड़ता था।

मैं नागौर जिले से आता हूं, जहां भू-जल खारा है और पीने योग्य नहीं है, लेकिन हमारे लोग मजबूरी में वह खारा पानी पीते हैं। उसमें फ्लोराइड की मात्रा भी ज्यादा है। इन सब समस्याओं को अगर किसी ने समझा और जाना तो वे हैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधान मंत्री जी को, जिन्होंने गांवों में बसने वाले भारत के लोगों की मूलभूत जरूरत को समझा और जल जीवन मिशन के नाम से एक ऐसी योजना की शुरूआत की, जो देश के हर परिवार को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए एक ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी योजना बन गयी।

2019 तक जल जीवन मिशन योजना शुरू होने से पहले देश के ग्रामीण इलाकों के केवल 3.23 करोड़ परिवारों को ही नल से जल मिल रहा था। प्रधान मंत्री जी ने 2024 तक इस योजना से देश के 19.34 करोड़ परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 अक्तूबर, 2024 तक 15.20 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन योजना के तहत नल से जल मिलने लगा है। अर्थात ग्रामीण इलाके के कुल भाग के 78.62 फीसदी हिस्से में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

कई राज्य तो ऐसे हैं, जहां 100 प्रतिशत परिवारों को नल से जल मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश राजस्थान का दुर्भाग्य है कि 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसने जल जीवन मिशन को ''लूट खाओ मिशन'' बनाकर छोड़ दिया। राजस्थान में 2023 में भाजपा की सरकार बनने से पहले हमारा प्रदेश जल जीवन मिशन में देश के अन्य राज्यों में सबसे पिछड़ा हुआ था, क्योंकि यहां जो सरकार थी, उसने जल जीवन मिशन में इतने घोटाले किये, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन्होंने राजस्थान की जनता के पानी के हक पर डाका डालने का काम किया। पाइप की क्वॉलिटी देखो, चाहे जो टंकियां बनी हैं, उनकी क्वॉलिटी देख लो, इन्होंने हर चीज में घोटाला किया।

इन्होंने घटिया पाइप लाइन डालने का काम किया। टोंटियां लगवा दीं, लेकिन आज तक पानी नहीं। उनको दुबारा से ठीक कराना पड़ेगा, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और तो और, इन्होंने पानी देने में भी भेदभाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छांट-छांटकर भाजपा विचारधारा के परिवारों को जल जीवन मिशन के सर्वे से वंचित किया और जब डीपीआर बनी तो उसमें अधिकांश गांव-ढाणियों को वंचित रख दिया। हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेश को आदरणीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के रूप में एक ऐसा कर्मयोगी, जमीन से जुड़ा हुआ किसान पुत्र मुख्य मंत्री मिला, जो जनता के दुःख-दर्द और तकलीफ को जानता है, समझता है।

चूंकि मुख्य मंत्री जी ने गांव का जीवन जीया है, उन्होंने अभावों को देखा है और दूसरों की पीड़ा वही व्यक्ति समझ सकता है, जिसने खुद पीड़ा भोगी हो, इसलिए कहा जाता है-

जांके पांव ना फटी बिवाई,
वो क्या जाने पीर पराई।।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान की जनता की पीड़ा को समझा और आदरणीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया कि जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाया जाये, क्योंकि कांग्रेस के कुकर्मों का फल राजस्थान की जनता क्यों भुगते? काम की गति धीमी रखी कांग्रेस की सरकार ने और भुगते राजस्थान की जनता, एक संवेदनशील मुख्य मंत्री ऐसा कैसे होने देते? हमारे प्रदेश का और राजस्थान की जनता का सौभाग्य है कि हमको डबल इंजन की सरकार होने का फायदा मिला और मुख्य मंत्री जी के आग्रह को आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार करते हुए जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया। अवधि बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं।

हमारे जलदाय मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब ने पिछले एक वर्ष में रात-दिन जल जीवन मिशन के कामों की मॉनिटरिंग करके काम की गति को तेज करवाया और जल्दी से जल्दी हर घर को नल से जल मिले, इसकी चिन्ता की।

MKD/RTM/05.03.2025/18:30/3o

परिणाम आपके सबके सामने नजर आने लगा, राजस्थान में जल जीवन मिशन का काम गति पकड़ने लगा। वंचित गांव-ढाणियों का दुबारा सर्वे करवाकर डीपीआर तैयार करवाई गई। डिविएशन स्वीकृत किए जा रहे हैं। सामान की आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर सहित नागौर के 180 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना और 74 एमएलडी पानी बढ़ाने की योजना, जिसे कांग्रेस सरकार ने कई वर्षों से लटका कर, अटका कर रखा, उन योजनाओं को हमारी सरकार ने आते ही स्वीकृति दे दी।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा को, हमारे जलदाय मंत्री माननीय श्री कन्हैयालाल जी चौधरी को, जिन्होंने 180 गांवों की जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त किया।

उनकी स्वीकृति जारी होने के बाद टेण्डर भी हो चुके हैं और जल्दी ही वर्क ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। इन 180 गांवों के लोग, वहां की जनता और मैं खुद इस नेक और पुण्य के काम की स्वीकृति जारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जलदाय मंत्री जी का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ।

यह फर्क है कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार में, हमारी सरकार काम करने में विश्वास रखती है, जबकि कांग्रेस की सरकार काम को अटकाने और लटकाने में विश्वास रखती है।

यही नहीं, जनता को पेयजल के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ट्यूबवैल और हैण्डपम्पों की स्वीकृतियां भी जारी की गईं और अभी बजट में दोबारा से घोषणाएं की गई हैं।

दूसरा, इस बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 ट्यूबवैल देने की घोषणा की गई है, लेकिन खींवसर का विशेष ध्यान रखते हुए, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे खींवसर का आप पूरा-पूरा ध्यान रखोगे।

अभी गांवों में चल रही पाइप्ड पेयजल योजनाओं की अधिकांश लाइनें पुरानी हो चुकी हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। कई जगह सामान की भी नहीं है। पम्प सेट, मोटर, केबल, पैनल बोर्ड आदि जिससे पेयजल आपूर्ति में बाधा आती है। कृपया गर्मियों से पहले सामान उपलब्ध करवा दिया जाए तो समस्या से निजात मिलेगी।

(समय : बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

हमारे कुचेरा, शंखवास और पांचौड़ी में जलदाय विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाएं। इससे क्षेत्र में योजनाओं की क्रियान्विति, संचालन और प्रबन्धन बेहतर हो सकेगा।

जल जीवन मिशन के काम को गति दी जाए। जो गांव-ढाणी पुराने सर्वे में वंचित रहे गये थे, उनको भी जोड़ा जाए। एक निवेदन यह भी है कि जल जीवन मिशन में सहभागिता राशि के नाम पर 1200 से लेकर 1500 रुपये प्रति नल कनेक्शन ग्राम पंचायत द्वारा राशि ली गई थी।

श्री सभापतिः विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): जलदाय विभाग में अभियन्ताओं और तकनीकी कर्मचारियों से चल रहे हैं। जिससे पेयजल की योजनाओं...। दो मिनट, सभापति जी। सिर्फ, दो मिनट, एक मिनट।

श्री सभापतिः प्लीज, माननीय सदस्य, विराजिये। डॉ. शिखा मील। विराजिये सदस्य विरोजिये। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): 000

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 41 और 42 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। जल ही जीवन है, यह सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा, हमें राजस्थान में जो अभी गम्भीर स्थितियां हैं, उनसे भी वाकिफ होना पड़ेगा।

हमारा राजस्थान रेगिस्तान का प्रदेश है, संस्कृति का प्रदेश है। पूरे देश के ज्योग्रोफिकल एरिया में साढ़े दस परसेंट करीबन राजस्थान के पास है। पूरी जनसंख्या से साढ़े पांच परसेंट राजस्थान के पास है, पर पूरे देश का टोटल सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी सिर्फ 1.16 परसेंट राजस्थान में है। पिछले दो दशक से भूजल का दोहन तेजी से बढ़ा है। 1984 में जो सिर्फ 35 परसेंट था, वर्तमान में 149 परसेंट है और जयपुर में तो यह ढाई सौ परसेंट तक है, जो बहुत ही चिन्तनीय स्थिति है। जीरो डे की हम सिर्फ कल्पना करते हैं, पर हो सकता है वह दिन भी जल्द आ जाए।

अगर सरकारों का रुख इस समस्या को लेकर ऐसे ही उदासीन रहा तो वह दिन दूर नहीं,

जब सुबह लोग दूध की थैली की तरह पानी की थैलियां भी लाया करेंगे। अगर हम बजट घोषणाओं की बात करें तो बहुत ही सतही और अगम्भीर नजर आती है। सीमान्त प्रदेशों के हालात का तो मुझे फिलहाल पता नहीं, पर राजस्थान के ह्दय राजधानी जयपुर से मात्र तीस किलोमीटर दूर मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जल संकट बेहद ही गम्भीर है। खेती पर आधारित हमारे क्षेत्र में लोग पानी की एक-एक बिन्दु के लिए मोहताज हैं।

सदन में स्थितियां ये हैं कि जब भी जनहित के गम्भीर मुद्दों पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष समाधान की बजाय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को बार बार याद करने लगता है। वे अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि वे सत्ता में हैं और वे सक्षम हैं। इस पर निदा फाजली की कुछ लाइनें मैं अर्ज करना चाहूंगी-

तुम से छूटकर भी, तुम्हें भुलाना आसान न था,
तुम से छूटकर भी, तुम्हें भुलाना आसान न था,
तुमको ही याद किया, तुमको भुलाने के लिए,

जनता यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोषारोपण देखने नहीं बैठी है। जनता की अपेक्षा है कि उसके जल संकट का समाधान हो।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र चौमूं की बात करूं तो पिछले एक वर्ष से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि नगर परिषद क्षेत्र और आसपास के गांव गम्भीर जल संकट से जूझ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि हमें बीसलपुर योजना की पानी सप्लाई से जोड़ा जाए, जो अभी हरमाड़ा तक पहुंच चुका है। क्यों नहीं सरकार इस पर विचार करती कि चौमूं की डिमांड को कैलकुलेट कर उसे भी स्वीकृत किया जाए। हमें हमारी जरूरत का सिर्फ एक तिहाई पानी नगर परिषद एरिया में मिल रहा है।

बजट में अमृत 2 योजना की बात करें तो सिर्फ पन्ने सजाए गये हैं। पिछले एक साल में कागजों को काले करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। एक वर्ष में चौमूं को एक बिन्दु पानी भी अमृत 2 योजना से नहीं मिला है। इससे कहीं ज्यादा पानी तो हमारी जनता अपनी आंखों से बहा चुकी है। ऐसा न हो कि अगर प्रजा की, आप यह जो अनदेखी कर रहे हैं, इससे अगले चुनाव में आपको भी खून के आंसू रोने पड़ें।

कागजों में कार्य प्रगति देखिये, 2024-25 के बजट में बिन्दु संख्या 7, 183 शहरी निकायों में 5 हजार 180 करोड़ के कार्य दो वर्षों में होंगे। 2025-26, बिन्दु संख्या 6, अमृत 2 योजना में 183 नगरीय निकायों में 5 हजार 123 करोड़ के काम होंगे। पैसा भले ही दोनों बजटों में 57 करोड़ का काम हो गया, पर शायद धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। आंकड़ों का एक भुलावा, पिछले बजट में दो साल में विधान सभा वार 10 ट्यूबवैल और 20 हैंडपम्प दिये गये। इस बार उन्हीं को घुमा फिराकर लिख दिया गया कि पूरे प्रदेश में हजार ट्यूबवैल दिये जाएंगे।

ट्यूबवैल की जब बात आई तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षितकरना चाहूंगी कि पिछले साल के सैंक्शन 5 ट्यूबवैल में से हमें एक बिन्दु भी पानी नहीं मिला है, पर इसका

राजनीतिकरण जरूर हो गया। सत्ता पक्ष के माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने धनखड़ जी और राठौड़ जी ने कहा था कि जल का राजनीतिकरण न हो।

मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप जरूर संज्ञान लें। इस लिस्ट को देखें, जो पांच ट्यूबवैल्स हमारे एरिया में सैंक्शन किये गये हैं। इस लिस्ट को देखें तो आपको लगेगा कि पानी का तो यहां जातिकरण तक हो गया। यह इस पूरे सदन के सदस्यों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। मंत्री कोई पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, वे यहां 200 सदस्यों के होते हैं और उनके पीछे 8 करोड़ जनता खड़ी है।

विभाग यह जरूर बताए कि किसकी अनुशंसा से ये 5 ट्यूबवैल्स किये गये और अगर यह कहा जाए कि अधिकारियों की रिक्मंडेशन थी तो 200 विधान सभा क्षेत्रों का ब्यौरा निकाला जाए और बताया जाए कि वही रूल्स सभी विधान सभा क्षेत्रों में फॉलो हुए हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह जनादेश का अपमान है। इन आंकड़ों के मायाजाल से सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है। साल भर से हम इस सदन में चीख-चीखकर अपनी जनता की वेदना को बयान कर रहे हैं, पर सरकार का दिल बिलकुल नहीं पसीजता। दिहाड़ी मजदूर, खेती करने वाले लोग, 5-7 हजार रुपये महीने के कमाने वाले लोगों को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। भरी गर्मी में एक टैंकर आठ सौ, नौ सौ, हजार रुपये तक आता है, वह भी दो-तीन दिन की वेटिंग पर आता है, बहुत सारी गलियां और गांव तो ऐसे हैं, जहां टैंकर तक नहीं पहुंचता। सरकार के पास ऐसी स्थितियों के लिए कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है।

हमारे चौमूं क्षेत्र के लिए कुछ टैंकर्स का टेंडर किया जाता है, पर वह काफी नहीं है। उनकी भी प्रोपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है।

मैं जल जीवन मिशन की बात करूं तो राजस्थान का न्यूनतम कवरेज जो है, वह हमारे चौमूं विधान सभा क्षेत्र में है, 37 परसेंट। केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन की अवधि 31 मार्च, 2024 को पूरी हो गई और अब कहा जाता है कि 2025 के बजट में केन्द्र सरकार ने इस समय सीमा को 2028 तक बढ़ाकर संजीवनी दी। अगर डबल इंजन सरकार ही है तो क्यों नहीं यह घोषणा पिछले बजट में की गई। संजीवनी का काम भी वक्त पर किया जाता है। अभी तो पानी की स्थितियां वेंटीलेटर पर आ चुकी हैं। हमारी स्थितियां ये हैं कि 18 गांव में तो वर्क आर्डर तक नहीं हुए हैं और 4 गांवों में वर्क ऑर्डर के बाद एग्रीमेंट नहीं हुए हैं।

मंत्री महोदय, मैं दो मामलों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वर्तमान में प्लानिंग की दुर्दशा यह है कि हाड़ौता बिजली की ढाणी, वहां एक पानी की टंकी का काम चालू हुआ, परिसर की दीवार तोड़ दी गई, वहां गड्ढा खोद दिया गया, वहां बजरी सामान आ गया, पर अचानक 5-7 दिन बाद उसका काम रोक दिया गया और उसकी लोकेशन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। क्या यह जनता के संसाधनों की, सिस्टम के संसाधनों की, पैसों की बर्बादी नहीं है? सिंगोद खुर्द में नाड़िया ग्राम में पानी की टंकी की गुणवत्ता की जांच आप जरूर कराये, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी अभी दरारें आ गई हैं।

Bhs/Rtm/05.03.25/18.40/3p

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने दो बार कहा कि पत्थर से पानी निकलेगा, कुछ चौमूं की तरफ भी इस पानी को भेज दें अगर पत्थर से पानी निकले तो वैसे भी हम तो हमारे इलाके में पत्थर का पानी खारा पानी फ्लोराइड रिच पानी ही पी रहे हैं। क्षेत्र में 15-16 आर.ओ. प्लांट्स हैं जो करीबन सभी एज ऑन ऑपरेश्नल हैं, 7 साल का पूरा उनका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड पूरा हो गया है। किसी के ट्यूबवेल का पानी भी खत्म हो गया है, पर कोई सुध नहीं ली जा रही, जो ओ. एंड एम. प्रपोज़ल्स हैं वो भी अभी तक तैयार नहीं हो पाये। सरकार इस पर भी अपना रुख स्पष्ट करे, जो पिछले एक-सवा साल में नहीं कर पाये हैं कि ये जो जे.जे.एम. के ट्यूबवेल्स हैं उनकी बिजली का बिल कौन भरेगा? पंचायत भरेगी, जनता भरेगी, पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेन्ट भरेगा या बिजली विभाग करेगा, क्योंकि आये दिन इनके कनेक्शनों को काटने, जोड़ने का खेल चलता रहता है।

मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि जिन भी गांवों में अभी तक जल जीवन मिशन वर्क ऑर्डर्स नहीं हुए हैं या कार्य अधूरे हैं, आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए उनमें नलकूप स्वीकृत कराये जायें। शहर में बहुत सारी जरूरत वाली जगह हैं जहां ट्यूबवेल की अनुशंसा मेरे द्वारा आपके विभाग में भेज दी गयी है पर वो पेंडिंग है। कृपया उस पर भी ध्यान दें।

श्री सभापतिः समाप्त करें, माननीय सदस्या।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): गोविंदगढ़ में कनिष्ठ अभियंता के दो पद स्वीकृत हैं, एक रिक्त है। वहां पर आप एक और पदस्थापन करायें और वहां पर जे.इएन., ए.इएन. जो है उन्हें आदेशित करें कि आमजन को सुविधा को देखते हुए गोविंदगढ़ कार्यालय में ही रहें। चौमूं के गवाल्डी और बलीखंड में नलकूपों को...(व्यवधान)... सिर्फ मैं 1 मिनट लूंगी, सर। गवाल्डी और बलीखंड में नलकूपों को गहरा कराने का कार्य अतिशीघ्र पूरा कराया जाये। कुछ दिन पहले केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो भारत उसमें भाग नहीं लेगा अगर, पानी की वजह से हुआ, तो, पर शायद वो राजस्थान की स्थितियों से अवगत नहीं हैं। समय रहते अगर हम लोग नहीं चेतते हैं और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं करते तो हो सकता है पानी की वजह से गृह युद्ध की स्थितियां बनें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द। जय संविधान।

श्री सभापतिः श्री अरुण चौधरी।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 41 एवं 42 पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज सर्वप्रथम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब को बहुत-बहुत तहेदिल से धन्यवाद देता हूं कि इस बजट के अंदर जन स्वास्थ्य एवं जल संसाधन विभाग में अपार बजट की राशि स्वीकृति की घोषणा की। जिस प्रकार हमारे विपक्षी भाई यह कहा करते थे कि ई.आर.सी.पी. कहां है, और ई.आर.सी.पी. की जो घोषणा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने की, आज विपक्ष उस बात को लेकर के दांतों तले

अंगुली चबा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किस प्रकार घोषणा की, लेकिन अब यह इस तरह से सोच रहे हैं कि ई.आर.सी.सी. धरातल पर कैसे आयेगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ई.आर.सी.पी. इस धरती पर आयेगी, इस राजस्थान को खुशहाल करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी अमृत टू योजना के तहत बालोतरा शहर में मीठे पानी की पाइप लाइन हेतु लगभग 180 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की थी। मैं हमारे प्रमुख विपक्षी भाइयों को एक बात अपनी दो लाइनें कह करके बताना चाहूंगा कि,

'नहीं बचा धरती पर पानी, बहा व्यर्थ बेमानी में,
खूब मिटाया तुमने पानी, यूं नादानी में,
इतना घाटा उठा चुके हैं, हम आप की मनमानी में,
नहीं आया इस धरती पर पानी, पूरी आपकी जवानी में।'

आज विपक्ष ने 75 साल जो राज़ किया और उसके उपरांत भी वो आज ये कहते हैं कि गांव-गांव के अंदर पानी की समस्या है। मैं कहता हूं अगर इसका कोई दोषी है तो हमारे सामने बैठे विपक्षी भाइयों की सरकार जो थी, उसके लिये वो संपूर्ण रूप से दोषी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगें माननीय मंत्री महोदय को रखना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा का पानी पचपदरा और सिवाना में लाया जाये। अगर ये पानी आता है तो इस क्षेत्र के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद जो उन्होंने पोकरण फलसूंड योजना को इस क्षेत्र के अंदर लागू करके और आज इस क्षेत्र के अंदर ये संपूर्ण रूप से पूरी तो नहीं हो पाई है लेकिन आमजन को इसका मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में उम्मेद सागर दवा परियोजना भी वसुन्धरा जी की देन हैं और मैं ये कहता हूं कि ये विपक्षी जो हैं वो दिन-रात एक ही बात करते थे जब इनकी सरकारें थी कि हमारे पानी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि वसुन्धरा जी की सरकार थी उस वक्त मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये पीने के पानी की जो व्यवस्था हुई उसके लिए मैं उनकी पूरी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, हमारे मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, आदरणीय भजन लाल जी को जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी हाल ही के बजट के अंदर लगभग 20 करोड़ की लागत से स्टोरेज जो पानी के लिये है उसकी घोषणा की, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यकता थी बालोतरा एवं आसपास के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसके अंदर 10 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी हो जाये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र के पचपदरा तहसील पर पानी के लिए बागुंडी से एक नई पेयजल लाइन बिछाये जाने की घोषणा कराने का निवेदन करता हूं। इसके अलावा पिंडारण से उमरलाई गोल अथवा खट्टू से चंदेसरा और कल्याणपुर से अराबा डोली, माजीवाला से असाड़ा, बुडीवाड़ा, जागसा, टापरा भी एक कोई नई लाइन पेयजल लाइन मंजूरी कराने की मदद करावें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुड़ी, सरूपरा, बोको की ढाणी, पारलू, रणिया देसीपुरा एवं बालोतरा शहर में साकरणा तथा नया बस स्टैंड, खेड़ रोड पर भी एक एस.आर. पानी की टंकी की स्वीकृति दिलाने का कष्ट करावें। इसके अलावा मैं हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा की मेरे विधानसभा क्षेत्र के तरसिंगड़ी गांव का मोलब तालाब, कूड़ी रवाड़ा, पारलू सराड़ा, जास्ती, कोरणा, डोली, अराबा, कल्याणपुर इन तालाबों का रखरखाव हेतु इस बजट के अंदर जरूर आप बजट दिलाने का श्रम करावें और इसके अलावा हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से पानी का स्रोत गांव के अंदर तालाबों का भी रहता है जो अन्य तालाब हैं उनके भी जीर्णोद्धार के लिये बजट जरूर दिलावें। इसके अलावा लूनी नदी की साफ-सफाई एवं इसकी तटबंदी कराने के लिये भी और बालोतरा शहर में इसको घाटनुमा बनाकर बालोतरा के अंदर इस लूनी नदी का सौंदर्य किस तरह से किया जाये, इसके लिये भी बजट दिलाने का कष्ट करायें। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र के कनाना, सराणा, कीटलोद, बिठूजा, कूपावास और सीलोर जेठंतरी जो हमारे सिवाना विधानसभा क्षेत्र के भी हैं, इसमें ज़ीरो चेकडैम तथा रपट बनाकर यह लूनी नदी जो प्रवाहित होती है, इसको जल स्तर बढ़ाने के लिये जरूर बजट दिलावें। जोजरी नदी के बहाव के लिए अभी हाल ही में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा में घोषणा की है तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय से, कि डोली अराबा से जो गंदा पानी आता है उसको जोजरी नदी के बहाव क्षेत्र के तहत इसका गंदा पानी जो है वो कहीं दूर निस्तारण किया जाये। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें पानी की अति प्रमुख समस्या है उसमें बागुंडी आकड़ली, दुधवा, खट्टू, चांदेसरा, गोल, तिलवाड़ा, बोराबास, कटवारी, कीटपाला, वरिया, मेवा नगर, कालूड़ी, असाड़ा, टापरा, जागसा, बूड़ीवाड़ा, सूरसिंह का ढाणा, माझीवाला, बंदनावास, आसोतरा, कीटनोद, जानियाणा, मूल जी की ढाणी, रणियादेसी पुरा, रावली ढाणी, रणिया, कनाना, पारलू, उमरला, एकखारवा, काकराला, सरूपरा सरवड़ी पटाऊ, भांडियावास, कुड़ी भूंगड़ा, रामसिन, जेरला, केड़, आकड़ली, पचपदरा, रेवाड़ा, नेवाई, चारलाई, तिरसिंगड़ी, थोब, नेवरी, गढोई, नागाणा, देरिया, कपूरड़ी, थूमली, मंडली, गंगावास, कोरणा, रोड़वा, जास्ती, बलऊ, कलावतसर, मूल की ढाणी, चांदराई, ग्वालनाड़ा, गोदावास, डोली, शिवनगरी, अराबा, कल्याणपुर और जसोल, इन सब ग्राम पंचायतों के अंदर पानी की अति समस्या है तो मैं आप की मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि इन ग्राम पंचायतों के अंदर भी पानी की किस प्रकार सुचारु रूप से आपूर्ति हो सके उसके लिये आप निर्देश दिलावें। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे विपक्ष की सरकार के जो पूर्व मंत्री महोदय थे उनके लिये इन्हीं के एक सदस्य कहा करते थे, Minister is a rubber stamp. मैं यह कहता हूं ...

Kas/rtm/05.03.2025/18.50/3q

कि अगर वक्त पर कार्य किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती, लेकिन हमारी सरकार

ने जिस प्रकार से यह घोषणा की है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में हमारा प्रदेश जरूर विकसित राज्य बनेगा, धन्यवाद।

श्री सभापतिः समाप्त करें। श्री नाना लाल नीनामा।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा घाटोल विधान सभा क्षेत्र दो जिलो में आता है। प्रतापगढ़ जिले में हमारी पंचायत समिति पीपलखूंट की तीन पंचायतें नोन कमांड क्षेत्र में आती हैं। वहां से पाइप डालकर जाखम बांध में 3.72 सीएमटी पानी जाखम में डालकर चित्तोड़ व उदयपुर को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि पीपलखूंट पंचायत समिति की जो पंचायतें हैं, वो माही बांध से बिलकुल लगी हुई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की 30 पंचायतें असिंचित हैं। मैं सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जाखम में डालकर चित्तौड़ ले जाएं, उदयपुर ले जाएं, राजसमन्द ले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माही बांध में हमारे क्षेत्र की पंचायतों के काश्तकारों को पहले फायदा दिया जाये। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के चोखी टामडिया से केनाल निकल रही है। केलामेला, घंटाली, बखतोड़, पीपलखूंट, शोभनिया, जेथलिया होते हुए प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद क्षेत्र में जाखम बांध में डाल रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की 7 पंचायतों में 5 हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है और 23 पंचायतों की 14185 हैक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार से कहना चाहूंगा कि मेरी 23 पंचायतों की 14185 हैक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित है, उसको पहले दिया जाये। मंत्री महोदय, उसका सर्वे करवा कर डीपीआर बनाकर इस क्षेत्र के लिये पानी उपलब्ध कराये। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, चोखी टामटिया, डेम के पास टामटिया है। इसके बाद चौकी, चाकबाड़ी, केलामेला, कूपडा, कालीघाटी, बखतोड़, घंटाली आदि पंचायतें हमारे क्षेत्र की हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये थोड़ी ऊँचाई पर है, तो आप डिग्गी बनाकर उसमें मोटर लगाकर उस क्षेत्र में पानी डालेंगे तो ये चार-पांच पंचायतें फिर सिंचित हो सकती हैं।

दूसरी बात यह करना चाहूंगा, प्रतापगढ़ से एक बहुत बड़ी ऐराव नदी निकलती है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र समलिया, कुशलपुरा, छोडलपुर, चरी, घंटाली, बावड़ी से बहती हुई माही बांध में उसका पानी चला जाता है। इस मौके पर माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में बाकी पंचायतें हैं, उस ऐराव नदी पर जगह-जगह एनिकट बना कर, जैसे समलिया, कुशलपुरा, छोडलपुर, घंटाली, बावड़ी, नायन, महुवाल, ठेसला, पर छोटे-छोटे एनिकट बनाकर उस पानी को रोका जाये तो उस क्षेत्र की जनता का भला हो सकता है। सिंचाई भी हो सकती है और पीने के काम भी आ सकता है। इससे उस क्षेत्र की जनता को फायदा होगा और उसकी आर्थिक उन्नति होगी। उस क्षेत्र में 100 परसेंट लोग जनजाति के रहते हैं और वो गरीब लोग हैं। मैं

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में छोटे-छोटे एनिकट बनाकर उस क्षेत्र की जनता को राहत देंगे।

इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे घाटोल विधान सभा क्षेत्र में सभी जगह पानी घूम गया, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पानी नहीं घूमा। नहर से 2934 किलोमीटर नरवाली वितरिका से निकलती है, उसके बाद बावनपल्ला से कंटाम माइनर निकलती है। वह काफी बड़ी नहर है, बावनपल्ला से बछियाडा वाया दुखवाड़ा, उसका सर्वे करवा कर डीपीआर बनाकर सरकार अगर उसको मंजूर करती है तो वहां की पंचायतें, कनकुरा, दुखवाड़ा, बछियाड़ा, दौलतसिंह गढ़ा, बढ़ाना, बावनपल्ला, जो पंचायतें बाकी हैं, वहां बड़ी नहर जा रही है, इन पंचायतों में पानी नहीं जा रहा है, अगर वह पानी वहां जाये तो उस क्षेत्र की जनता का भला हो सकता है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इसकी डीपीआर बनाकर इस क्षेत्र को सिंचित करेंगे।

इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दुखवाड़ा में 420 हैक्टेयर, बछियाड़ा, बूढाबच्छी में 24 हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है, अभी सिंचित नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां भी डिग्गी निर्माण करके पंपिंग स्टेशन बनाकर सौर ऊर्जा आधारित परियोजना को स्वीकृत कर जनजाति समुदाय के 2 हजार परिवारों को लाभान्वित करेंगे, यह मैं कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं पीएचईडी मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि घाटोल विधान सभा क्षेत्र में 12 गांव, जैसे कांजीगढा, मूंदडीपाडा, धनोड़ा, नरवाली, भबटिया, समनिया, उदाजीगढ़ा, चंदोजीगढ़ा, मियासा, डूंगरिया और बछियाडा, इनमें 2012 में जल जीवन मिशन के माध्यम से योजना स्वीकृत हुई थी। उसके टेंडर हो गये, वर्क आर्डर हो गये, इसके बाद काम किया। अभी कुछ दिन पहले, 31 तारीख से विधान सभा चालू हुई, इसके बाद में इन क्षेत्रों में मैं गया, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वहां बिलकुल पानी नहीं है, न टंकी है, कुछ भी नहीं है। क्षेत्र की जनता को जो करोडों रुपये का बजट मिला, वहां किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच करके दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करें। वहां अधूरे कार्य पड़े हैं। वहां के अधिकारियों ने एस्टीमेट बनाकर सरकार को दिया है। उसकी निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उसका जल्दी कार्यादेश देकर 231 गांवों को हर घर नल योजना से जोड़े जाने के लिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापतिः समाप्त करें। श्री धर्मपाल।

श्री नाना लाल निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, मेरे पीपलखूंट पंचायत समिति में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत...। धन्यवाद।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41, 42 पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले आग्रह करना चाहता हूं कि सुबह से इस विषय पर चर्चा सुनी जा रही है, सिर्फ एक दूसरे पर

दोषारोपण करना ही अगर हमारा उद्देश्य है तो मैं समझता हूं कि हम इस सदन का समय भी खराब कर रहे हैं और किसी स्थाई समाधान की तरफ हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी पर राजनीति होना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। स्थाई समाधान का अगर मैं जिक्र करूं तो मैं इतना बुद्धिमान तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक हम हमारे परम्परागत स्रोतों का संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई स्थाई समाधान हो नहीं सकता, क्योंकि यह आर्टिफिशियल चीज नहीं है, यह प्राकृतिक चीज है, इसका संरक्षण ही समाधान है। जल मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं पूरे सदन के सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक हम इस प्राकृतिक चीज को सहज कर नहीं रखेंगे, तब तक इसका स्थाई समाधान नहीं हो सकता। मैं एक बार जल पर रिसर्च करने वाले व्यक्ति के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे यही बात कही कि अगर इस जल को रखना है और आगे पीढ़ियों को जीवित रखना है, तो दौड़ते हुए जल को चलना सिखाओ, चलते हुए जल को रेंगना सिखाओ और रेंगते हुए जल को रुकना सिखाओ, तब तक इस धरती का क्षरण नहीं होगा।

Msk/rtm/05.03.25/1900/4a

इसलिए आग्रह करना चाहता हूं कि हम ऐसे स्रोत पैदा करें, छोटे-छोटे एनिकट पैदा करें जो कि हमारे परंपरागत स्रोत थे, उनको पैदा करें। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप से अगर पानी पैदा होता है तो हम अपना समय खराब कर लें, तालियां बजवा लें और अपना वीडियो क्षेत्र में छोड़कर यह कहें कि, नेता जी, आप बहुत अच्छा बोले। अगर इसी चीज से समाधान हो सकता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं किसी भी देश का आकलन होता है तो किसी के भाषणों से नहीं होता है। उस देश की स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, उस देश के हवाई अड्डे कैसे हैं, वहां का रेलवे प्लेटफॉर्म कैसा है, वहां की आबोहवा कैसी है, वहां जनता को पानी शुद्ध मिलता है या नहीं, जनता को कितना पानी शुद्ध मिलता है, वहां की रोड कैसी हैं, इन चीजों का आकलन होता है, तब जाकर ये चीजें हमारे देश को विकसित श्रेणी में लाने का काम करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 2019 को लालकिले से घोषणा की कि हम लोग 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत इस देश के हर ग्रामीण को, हर नागरिक को, सुदूर क्षेत्र में रहने वाले हर ढाणी के व्यक्ति को शुद्ध पानी मुहैया करायेंगे और नल से जल मुहैया करायेंगे। लेकिन उसमें भी राजनीति पर राजनीति। मैं कहना चाहता हूं कि सवा चार साल में सिर्फ सरकार बचाने वाली यह कांग्रेस सरकार, 27 हजार का एलोकेशन जल मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया, उसमें सवा चार साल में आप मात्र 6 हजार करोड़ रुपये खर्च करते हैं और आप सरकार बचाने के लिए होटलों में बैठे रहते हो। बुराई करने को क्या-क्या शेर नहीं पढ़े गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं:-

नजर नहीं, नजारों की बात करते हैं,

जमीं पर सितारों की बात करते हैं,
हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जो भी बात है, अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिए। मुझे बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं कहनी है। मुझे अपने क्षेत्र की भी एक-दो मांगें कहनी हैं, क्योंकि आप लोगों ने समय भी कम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जल जीवन मिशन को कबाड़ के खाने में डालने का काम इसलिए किया गया कि यह श्रेय नरेन्द्र मोदी को न मिल जाये। इतनी महत्वाकांक्षी योजना का श्रेय केन्द्र में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को न मिले, इसीलिए इसको कबाड़ में डाल दिया और यहां तक कि हम प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं और इस बात का हम सबूत भी दे सकते हैं कि इस जल जीवन मिशन के अन्दर पुराने पाइप खरीदकर, कबाड़ के भाव में पाइप खरीदकर उनको थोड़ा मेंटेन करके, रंग-रौगन करके रातों-रात उनको दबा दिया गया, जो आज पंचर हो रहे हैं, जंग खा रहे हैं, वह पूरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है।

मैं कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र का निवेदन करना चाहता हूं। हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी चीज, कोई भी जो योजना होती है, एक मिनट में धरातल पर नहीं आती है। यमुना जल समझौता, जिसमें झुंझुनूं, चूरू और सीकर आते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 30 वर्ष पहले स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन बीच में 20-20 साल तक कांग्रेस के सांसद इसके नाम पर राजनीति करते आये और चुनाव जीतते आये, लेकिन इस काम को 1 परसेंट भी आगे नहीं बढ़ाया। आज जो बड़ी-बड़ी बातों की सिर्फ घोषणा हुई, डीपीआर हुई, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यमुना जल समझौते का, जो हमारे शेखावाटी के लिए एक वरदान होगा, जीवनदायिनी होगा, उसके लिए हमारी डीपीआर बन रही है। उसमें हमारा पूरा शेखावाटी क्षेत्र आयेगा। मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि जब डीपीआर बने तो मेरे क्षेत्र की बात करूं। मेरे क्षेत्र खेतड़ी के अन्दर, मैं यह नहीं कह सकता है, पूरा खेतड़ी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें नहर संभव नहीं है। मैं जलदाय मंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन भी हमारी डीपीआर बने तो मेरा यह निवेदन है कि खेतड़ी क्षेत्र के जो बड़े परम्परागत बांध हैं, जो राजा अजीत सिंह ने उस टाइम बनाये थे, जो कालाभुजा बांध है, अजीत सागर बांध है, तिजोवाला बांध है, रवा बांध है, मोड़ीलाखर बांध है, सिर्फ और सिर्फ उनको भरने की आप लोग कृपा कर देंगे तो मैं समझता हूं कि खेतड़ी का उद्धार हो जायेगा और खेतड़ी में आप भागीरथ के रूप में शामिल होंगे।

इस आग्रह के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2024 से 2028 तक जल जीवन मिशन योजना को बढ़ाना, उसके लिए मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग मुझे बैठने के लिए कहें, उससे पहले ही कह देता हूं कि जब तक परंपरागत स्रोतों का संरक्षण नहीं होगा, इस चीज का स्थायी समाधान नहीं होगा, इतना ही आग्रह मुझे आज के दिन करना

था। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद।

श्री सभापति: श्री सोहन लाल नायक।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 41 व 42 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि 2024-25 के बजट में इंदिरा गांधी नहर के सेकण्ड फेज के लिए 1430 करोड़ रुपये खालों एवं नहरों की मरम्मत के लिए तथा खाले बनाने के लिए दिये थे, परन्तु क्या वे 1430 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं? दूसरी बात, 2024-25 के अन्दर फर्स्ट फेज को एक रुपया भी नहीं दिया गया, आईजीएनपी के फर्स्ट को एक रुपया भी नहीं दिया गया, यह भेदभाव फर्स्ट फेज वालों के साथ क्योंकिया गया? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज, सेकण्ड फेज से 10-15 साल पहले बना है, जो चीज पहले बनेगी वह क्षतिग्रस्त पहले होगी। जबकि आपने 2024-25 के बजट में सेकण्ड फेज को पैसे दिये और फर्स्ट फेज को एक पैसा नहीं दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार फर्स्ट फेज के लिए 200 करोड़ रुपये दिये, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछली बार भी मैंने आपसे मांग की थी। इस बार 200 करोड़ रुपये खालों, नहरों की मरम्मत के लिए दिये हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। परन्तु फर्स्ट फेज और सेकण्ड फेज में जो भेदभाव किया गया था, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा सेकण्ड फेज के अन्दर उच्च अधिकारियों, बड़े-बड़े नेताओं की हजारों मुरबा जमीन है, इसीलिए हमारे साथ यह भेदभाव किया गया। फर्स्ट फेज के अन्दर हमारे छोटे-छोटे किसानों की जमीन है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फर्स्ट फेज के अन्दर 5 लाख हेक्टेयर जमीन कमांड है, जबकि सेकण्ड फेज के अन्दर 414 लाख हेक्टेयर कमांड है, परंतु उसमें अलोटेड 2.98 करोड़ हेक्टेयर ही है। आप बताइये जो 5 लाख हेक्टेयर जमीन है, उसकी पैदावार ज्यादा होती है या 2.98 वाले की? फर्स्ट फेज वाले पैदावार करते हैं। ज्यादा अन्न हम उगाते हैं, हम मेहनत करते हैं और बजट सैकिण्ड फेज को दिया जाता है। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप इस बार सेकण्ड फेज का ध्यान रखें।

दूसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर घग्घर नदी का पानी आता है और 90 जीबी बॉर्डर एरिया है। वहां जब भी पानी आता है तो 8-10 गांवों का शहर और स्कूलों से नाता टूट जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि घग्घर नदी के दो पुल 90 जीबी, 11 जोइयां को बनवाया जाये। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पीने का पानी और उद्योगों के लिए पानी के लिए, आप जो कटौती कर रहे हैं, किसानों के लिए पानी की कटौती कर किसानों के साथ अन्याय किया, उसको दुरुस्त किया जाये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पंजाब पोर्शन के मुख्य नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है, फिर भी हर साल मार्च से लेकर जून तक हमारी बंदी ली जाती है, उससे हमारी अप्रेल-मई में बिजाई नहीं हो पाती। मेरा आपसे निवेदन है कि जब नहर पक्की हो चुकी है तो

बंदी लेने का क्या औचित्य है?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि गंग कैनाल सिस्टम के अन्दर पिछले दो सालों सीएडी द्वारा कोई खाला नहीं बनाया गया, जबकि हमारे क्षेत्र के गंग कैनाल सिस्टम में खालों की बहुत बुरी हालत है, उससे किसानों के खेतों में पानी पूरा नहीं पहुंच रहा, उन्हें उनके हक का पानी नहीं मिल रहा, तो सीएडी से उनके खालों का निर्माण करवाया जाये। सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मेरे अजीज, सादुलशहर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो कुछ किया हमारी भाजपा सरकार ने किया, जो कुछ किया, हमने किया। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जब आईजीएनपी बनी थी, उस वक्त भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था। जब आईजीएनपी का सर्वे हुआ था, उस वक्त भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था। कांग्रेस की सरकारें थीं। आज वे कह रहे हैं कि हम लोगों ने किया है। वर्ष 2004, 2005 और 2006 में भाजपा की सरकार के टाइम में घड़साना और रावला के अन्दर किसानों का आन्दोलन हुआ और 8 किसान शहीद हुए, आप सब जानते हैं। आज किसान फिर पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

mdp/rtm/05.03.25/19:10/4b

सीसी हेड पर उस वक्त भाजपा के तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा जी के टाइम पर किसानों पर लाठीचार्ज किया और आज भी वे मुकदमे भुगत रहे हैं। वर्ष 2002 में, वे कह रहे थे कांग्रेस ने क्या किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभापति महोदय, 2002 में आप भी उस वक्त मंत्री थे, पूरी कैबिनेट गंगानगर जाकर 474 करोड़ रुपये की गंग केनाल सिस्टम को पक्का किया, जो 70 सालों से कच्ची थी। पूरी कैबिनेट गंगानगर में गयी और 474 करोड़ रुपये सेंक्शन करके नहरों को और खालों को पक्का किया गया। उसी सत्र के अन्दर 11 हजार करोड़ रुपये अशोक जी की सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के फर्स्ट और सेकण्ड फेज के लिए नहरों की लाइनिंग के लिए दिए, जिसमें सूरतगढ़ ब्रांच, अनूपगढ़ शाखा और सेकण्ड फेज की नहरें थीं। ये कह रहे हैं कि आपके टाइम पर क्या हुआ? कांग्रेस का राज जब भी आया किसानों ने, आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड है, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का राज जब भी आया किसानों ने कोई आंदोलन नहीं किया और भाजपा की जब-जब सरकार आयी है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में आंदोलन हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से जलदाय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के विजय नगर के अन्दर 1975 की एक स्कीम है। उस वक्त सिर्फ 12 हजार की जनसंख्या थी, आज 40 हजार की जनसंख्या है। लेकिन स्कीम वही है, जिसमें 10 ऐसे वार्ड हैं, जहां आज तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गयी। इसका प्रपोजल 31/12 को विभाग द्वारा आपको भेजा गया है। मेरा निवेदन है कि वह स्कीम मंजूर कर लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था करें। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जो जेजेएम

स्कीम है, इसमें कुछ ढाणियां, गांव वंचित रहे हैं, उनको भी जोड़े ताकि उन लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। जो गांव ऊंची आबादी में बसे हुए हैं, उनमें ओवरहेड टैंक लगाकर पानी की व्यवस्था की जए।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर पीएस नहर जो है, उसका टेल पोर्शन रायसिंह विधान सभा में है और हैड पोर्शन करणपुर विधान सभा में है। टेल के किसान का पानी चोरी होता है तो वह जाकर मुकदमे दर्ज करवाते हैं। मुकदमे करणपुर विधान सभा क्षेत्र में होते हैं। उलटे हमारे जो टेल के किसान हैं, जिनके यहां पानी नहीं पहुंच रहा, उनके खिलाफ असत्य मुकदमे करवा कर उनको मारा जाता है। इस तरह की जो व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ किया जाए। ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः सभापति महोदय, आपके माध्यम से बहुत-से मेरे सीनियर सदस्य हैं, मंत्री महोदय, मेरे साथी...

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, दो लाइन। सत्ता वाले जो हैं, उनमें कुछ मद आता है तो उसके लिए दो लाइनें हैं-

ऊपर चढ़कर इतराने वाले,
त यह समझता है कि पहले से सुन्दर और सलोना लगता है,
अरे, जरा नीचे वाले से पूछ पहले से कितना बौना लगता है।
धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री हरलाल सहारण।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 41 व 42 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। विपक्ष के कई साथियों ने हमारे दोनो मंत्रियों को और ब्यूरोक्रेसी को सराहा इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम कुछ कर रहे हैं।

सभापति महोदय, रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, का एक वाक्य कहकर मैं अपनी आगे बात कहता हूं कि पानी एक अनमोल उपहार है जो सभी के जीवन केलिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। पेयजल समस्या हर क्षेत्र में व्याप्त है। इसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया था, जिसको हाल में केन्द्रीय बजट 2025-26 में 2028 किया है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने राज्य के बजट 2025-26 के पैरा संख्या 6 पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अमृत 2.0 योजना में 183 नगर निकायों को पेयजल आपूर्ति हेतु 5123 करोड़ रुपये के कार्यो की बजट घोषणा करते हुए शहरी क्षेत्रों की पेयजल समस्या के लिए कार्य प्रारंभ किये। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुख्य मंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) अंतर्गत 51 शहरों को जोड़ने का काम

किया। इसमें चूरू को शामिल किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 1200 करोड़ के बजट की घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 41 के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं, पिछली सरकार का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मेरे साथी उठकर कहने लग जाएंगे, एक गलत काम करने के कारण आज पानी के लिए तरस रहे हैं। खीवासर, जोड़ी, छलकोई, मैं इसीलिए आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं। समाधान ही कर रहा हूं और समाधान के लिए ही कह रहा हूं। आपने कुकर्म किये हैं, उसको भुलाने का काम कर रहा हूं। छलकोई, इन्द्रपुरा ऐसे गांव हैं, जहां ऐसी पाइप लाइनें डाल दी, एक-एक फुट, दो-दो फीट पर कि पानी लीकेज हो रहा है, पानी गांव में जा नहीं रहा है और गांव का किसान तरस रहा है। इसलिए मैं मांग करूंगा मंत्री महोदय से कि नई लाइनें डलवाकर उन गांवों को पानी पिलाया जावे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि पाइप लाइन डाली जाए। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी आज नहीं, पहले भी कभी नहीं गया था, पांच साल में, आज भी कम जा रहा है, इसलिए मैं आपसे मांग करूंगा कि छलकोई, मठोड़ी, नरसिंहपुरा, भैरूसर, जोड़ी, खीवासर आदि गांवों में पानी जाने का काम करने की कृपा करें। अभी मेरे कुछ साथियों ने, मेरे यहां भी आर.ओ. प्लांट लगाये हुए हैं। ठेकेदारों का काम पूरा होने के कारण वह आर.ओ. प्लांट खराब है। सूरजपुरा, जाजासर, रामसरा, देपाल, श्योपुरा, उठवालियां और अन्य गांव में, मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि वह आर.ओ. प्लांट चालू कराए जाएं।

मैं नहर मंत्री से मांग करूंगा कि अगर कुम्भाराम नहर रकबा बढ़ाया जावे तो मेरे चूरू तहसील में भी जोड़ी, छलकोई, कोटवा, खीवासर, ये तारानगर से चिपटी हुई पंचायतें हैं, इनको भी सम्मिलित किया जाए। यहां मैं उस शख्स का नाम लिए बगैर नहीं रहूंगा, पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको एक आदर्श के नाम से पहचाना जा सकता है, जिनको पक्ष और विपक्ष के दोनों के साथी याद करते हैं। जो नदियों से नदियों को जोड़ने का एक प्रस्ताव लाए थे, अगर वह आ जाता तो किसान खुशहाल हो जाता। ये अपनी धरती से सोने उगलने वाला काम हो जाता।

सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि अगर नहर का रकबा बढ़ाया जाता है तो और आगे बढ़ाया जावे। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पेयजल के साथ ही मेरी विधान सभा चूरू क्षेत्र में राणासर, लोचना, धांधू, घांघू, सुलतानपुरा, बालरासर, इन गांवों में मलसी से पानी जाता है, टंकियां बन गयीं, मगर एक ठेकेदार के कारण काम रुका हुआ है। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि इसका भी काम पूर्ण किया जावे।

सभापति महोयद, मैं माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री से मांग करता हूं कि पिछली सरकार में मेरी ग्राम पंचायत खासोली है, मेरा गांव भी है, उसमें एक बार आप यहां से टीम भेजकर जांच करवा लीजिए कि उन्होंने पैसा कब उठाया, काम कितना किया, कितना गलत, कितना सही किया, सारी रोड तोड़कर चला गया, सारे खुर्रे तोड़कर चला गया। आज भी वैसे ही पडा

है और मैं ठीक करवा रहा हूं। इसकी भी जांच करायी जावे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्री जी को, नहर मंत्री जी को कि एक अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहें कि विपक्ष भी आपको सराह रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शिमला।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): सभापति महोदय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मांग संख्या 41 व 42 पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज सुबह से आई.जी.एन.पी. नहर और पेयजल पर चर्चा चल रही है। बहुत-से सम्माननीय साथियों के अच्छे विचार भी आए हैं। सबसे अच्छा मुझे लगा कोलायत से आने वाले मेरे साथी ने कि हम आरोप-प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि इसका स्थायी समाधान कैसे किया जाए? किस तरह से किसान को बचाया जाए? किस तरह से किसान की खेती को बचाया जाए? हमारा मुद्दा ये होना चाहिए। सरकारें भाजपा की भी आयी हैं, कांग्रेस की भी आयी हैं, लेकिन आज भी हमारा किसान सड़क पर है, चाहे पानी को लेकर, चाहे फसल की मांग को लेकर। मेरी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि आई.जी.एन.पी., जो हमारे एशिया की सबसे बड़ी नहर है, यह 18,500 क्यूसेक्स पानी की सबसे बड़ी नहर है, लेकिन दिनों दिन जो बांधों की भराव क्षमता कम होती जा रही है तो इस नहर को किस तरह से भरा जाएगा? इस नहर में किस तरह से पानी लाया जाएगा? इसके लिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं।

Ans/rtm 19.20 4c 05.03.2025

मैं सदन से, मंत्री जी से, सरकार से मांग करती हूं कि सर्वप्रथम हमारा जो पोंग बांध है, भाखडा बांध है, रंजीत सागर बांध है, इनकी भराव क्षमता बढ़ाई जाए। 1390 जब 1385 के आस पास हम डेम को रखते हैं, जिसके कारण आये दिन आईजीएनपी के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर इस डैम को 1410 फीट तक भरा जाता है तो किसानों को अतिरिक्त पानी मिल सकता है, किसानों की फसल को बचाया जा सकता है।

सभापति महोदय, मेरे से पहले डीडवाना से आने वाले विधायक महोदय ने भी बात रखी थी। 1981 के समझौते के अनुसार पोंग बांध में हमारे राजस्थान का हिस्सा 8.60 था, आज भी पंजाब के पास है, वह हमें नहीं दे रहे, अगर यह पानी मिल जाए, देखने में आंकड़ा बहुत छोटा है लेकिन इसके अन्दर भी 3 लाख बैज क्यूसिक्स पानी आ रहा है, तो पूरे आईजीएनपी में डेढ़ बारी किसानों को पानी मिल सकता है, किसानों की फसल को बचाया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार है, इस पर क्या करेगी, हमें बताये।

दूसरा, जो बांध बने हुए हैं इस पर नियंत्रण पंजाब का है, मैं चाहती हूं और सदन से भी मांग करती हूं कि इन बांधों पर बीबीएम बोर्ड का नियंत्रण हो, जिससे पंजाब की मनमानी नहीं हो, राजस्थान के किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़े। हरिके बैराज से राजस्थान फीडर को पक्का किया जाए, इनके गेट को पक्का किया जाए, ताकि पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी उसको रोका जाये।

सभापति महोदय, अभी 10 फरवरी से पूरे बीकानेर संभाग के अन्दर, लूणकरणसर, घड़साना, अनूपगढ, जयसर, नोहर, भादरा किसानों ने एक सिंचाई पानी के लिए लगातार आंदोलन किया। उसके अन्दर हमारे बीकानेर के संभागीय आयुक्त ने हमारे सिंचाई विभाग के साथ हनुमानगढ, गंगानगर, बीकानेर के 25 किसानों का एक शिष्ट मण्डल हमारे पंजाब के अन्दर है, उसकी समीक्षा करने के लिये भेजा। हरिके बैराज है, पोंग बांध है इनको वहां जाकर देखा जाए कि किस तरह की वहां पानी की स्थिति है। जब हमारे किसान वहां गये सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ, वहां के संभागीय आयुक्त ने भेजा, हनुमानगढ़ के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि राजस्थान कैनाल के अन्दर हम ज्यादा पानी नहीं दे सकते क्योंकि सरहिंद फीडर का काम चल रहा है, वहां का पटड़ा टूट सकता है, इसका खतरा बना हुआ है। किसानों ने जब वास्तविक स्थिति देखी तो पाया गया कि राजस्थान कैनाल है इसमें 4 हजार 95 क्यूसेक्स पानी चल रहा था, उस पानी का लेवल सरहिंद फीडर के बेड लेवल से करीब दो फीट ऊपर था और दोनों नहरों के बीच जो पटड़ा था उसमें 100 फीट चौडा था, बेड से करीब 35 फीट ऊपर है। इस जगह नहर के टूटने, क्षतिग्रस्त होने का कहीं कोई खतरा नहीं था। फिरोजपुर के अधिशासी अभियंता ने भी कहा था कि अगर हजार से 1200 क्यूसेक्स पानी यदि नहर में दिया जाता है तो किसी तरह की सीपेज या पटड़ा टूटने की संभावना नहीं है। राजस्थान सरकार की उदासीनता रही। अगर किसानों को पानी मिल जाता तो गेहूं, चना, सरसों की रबी फसल है जो एक पानी के बारी के अभाव में खतम हुई। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि पीछे भी 6 बार डैम के लेवल को डाउन करके किसानों को पानी दिया गया था। 2021-22 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमारे डैम के लेवल को डाउन करके किसानों को पानी दिया गया था और फ़सलों को बचाया गया था1

सभापति महोदय, सबसे बड़ी विड़म्बना, जब किसानों ने हरिके बैराज में जाकर देखा तो पाकिस्तान की तरफ 400-500 क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान जा रहा था। मेरे पास 03 मार्च की पेपर की कटिंग है, सेनीवाली हेड से पानी पाकिस्तान जाता देख गंग कैनाल के प्राजेक्ट के चेयरमेन रो पड़े थे, उसमें 600 से 1800 क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी ने भटिण्डा के अन्दर एक सभा में कहा था कि मैं एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं जाने दूंगा। 19 अक्टूबर, 2019 को अरनड़ा बांध में, नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस की गलत नीतियों व राजनीति का खामियाजा हमारे हरियाणा व देश के जवानों ने भुगता है और मेरा किसान भी भुगत रहा है, हमारे हक का पानी हमारे काम आ सके इसके लिए पिछले 70 सालों में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया, हमारी नदियों का पानी, हमारे हिस्से का होते हुए भी पाकिस्तान जाता रहा है और हमारी सरकारें देखती रही, पानी जाता रहा, पानी जाता रहा। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हमारा पानी पाकिस्तान जाना चाहिए या फिर हमें हमारा हक मिलना चाहिए? यहां का किसान परेशान है और पाकिस्तान के खेत हरे भरे हैं, क्या यह मंजूर है? यह पानी आपका हक है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं जाने

दूंगा। मैं केन्द्र सरकार से और यहां की सरकार से पूछना चाहती हूं कि जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसके लिए आपने क्या कार्ययोजना बनाई? आज भी जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसको आप रोक रहे हो क्या?

मेरे से पहले मेरे एक साथी कह रहे थे कि जो उझ नदी है जो रावी नदी की ही उप नदी है, उसके ऊपर शाहपुर में जो डैम बना है, किस तरह से केन्द्र सरकार ने वहां अनुमति दी? केन्द्र में उस समय जल संसाधन मंत्री अर्जुनराम जी मेघवाल थे। 08 सितम्बर, 2018 को वह एमओयू हुआ था कश्मीर व पंजाब के बीच में। जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके अनुसार रावी व व्यास में 52 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान की थी और ईआरएलडी आयोग के अनुसार भी, यह बात लिखित में है, तथ्यों के साथ मेरे सामने हैं, तो किस तरह से आपने राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया। आपने शाहपुर कंडी डैम के अन्दर राजस्थान का हिस्सा तय नहीं किया। आज भी वहां राजस्थान का शेयर जीरो है।

सभापति महोदय, आईजीएनपी का रेगुलेशन बना वह 5 फरवरी तक था, 3 फरवरी को इन्होंने सिंचाई पानी बंद कर दिया, तो आपने दो दिन पहले पानी क्यों बंद किया, जबकि 05 फरवरी तक हमारा रेगुलेशन चल रहा था। 14 नवम्बर को हनुमानगढ़ हमारी को हमारी जल परामर्शदात्री की बैठक हुई थी, जिसके अन्दर जनवरी में समीक्षा बैठकर रखनी थी। उस वक्त हमने वहां के चीफ को कहा था कि पंजाब में फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के लिए तब तक अनुमति नहीं देनी, आपने अनुमति देनी है तो तभी देनी है जब राजस्थान में मार्च-अप्रैल में हम पानी की बंदी लेंगे, तो आपने किससे पूछकर ली, जनप्रतिनिधियों की कोई बात नहीं रखी। हमारा रेगुलेशन होता है वह 21 सितम्बर से 20 मई तक होता है। जल परामर्शदात्री की बैठक होती है वह 21 से 30 के बीच में ही होनी चाहिए जो 30 नवम्बर को हुई थी और 01 अक्टूबर को हमारा रबी का रेगुलेशन जारी होना था और संभागीय आयुक्त 3 तारीख को उस पर साइन करते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि यह अधिकारी हमारी सरकारों को सही राय देते होंगे। मंत्री जी से, सरकार से मेरा निवेदन है कि हमारा गंगानगर व पूरा बीकानेर संभाग इस वक्त सिंचाई पाने के लिए आंदोलनरत है। सिंचाई विभाग जो आपको गलत राय देता है इस पर ध्यान दीजिए और हमारी खेती, हमारे किसान को बचाइये।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि पिछले 4-5 दिनों से डैम में अच्छी आवक आ रही है, तो केन्द्र सरकार बीबीएम बोर्ड है, इसमें हस्तक्षेप करके पानी जो आईजीएनपी गंगनहर के किसानों को, भाखड़ा के किसानों को देकर हमारी फसल को बचाया जाए। बीबीएम बोर्ड में राजस्थान को स्थायी मेम्बर बनाया जाए। जब तक राजस्थान बीबीएमबी में स्थायी मैम्बर नहीं होगा पंजाब की मनमानी रहेगी। इसी तरह से हमारे किसान रोते रहेंगे।

सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं जलदाय मंत्री जी से मांग करती हूं कि जनता जल योजना के जो कर्मचारी हैं इनका स्थायीकरण किया जाए, इनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, 7410 रुपये इस महंगाई के अन्दर बहुत ही कम है। अमृत-2 योजना के अंतर्गत,

शहरी जल योजना जो अनूपगढ़ के विस्तार के लिये, जनता जल योजना के स्टोरेज टेंक का निर्माण किया जाना है, वह भूमि पशुपालन विभाग के पास है, तो मैं मांग करती हूं कि वह भूमि जलदाय विभाग को हस्तान्तरित की जाए, ताकि अमृत-2 योजना का उचित रूप से वहां इम्प्लीमेंट हो सके।

सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि हमारी कई प्राइवेट कॉलोनियां हैं, कोलोनाइजर है वह या तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है या मिला नहीं है, तो जो नियम है उनमें शिथिलता प्रदान की जाए और उनको पेयजल की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्राइवेट कालोनियों में लोग रह रहे हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सके।

इसके साथ-साथ मेरा उपखण्ड घडसाना, जल योजनाएं चल रही है, इनका एक भी काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक। नहरबंदी के अन्दर पूरा का पूरा जल संकट, कहीं तो फीडर खराब है, कहीं नहरों से डिग्गियों तक चेनल का निर्माण नहीं हुआ, कहीं विद्युत कनेक्शन नहीं है, कहीं इंजन के सहारे पानी लिया जा रहा है, कहीं वाटर वक्स नाकारा है, पम्पहाउस निर्माण का कार्य अधूरा पडा है, तो 05 फरवरी से आईजीएनपी में नहरबंदी शुरू हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल भंडारण के लिए अभी भी निर्माणाधीन है, तो किस तरह से हम गर्मी में आम पब्लिक को पानी देंगे?

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जेजेएम के अन्दर कार्य चल रहे हैं, कौन-कौनसी कम्पनियां काम कर रही हैं, इनकी गुणवत्ता की जांच की जाए, जो गलत पाई जाती है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय भीम।

श्री सभापति: श्री छोटूसिंह।

VPS-RTM-05.03.2025-19.30-4d

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 और 42 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। पानी की उपयोगिता इस सीमांत क्षेत्र और थार रेगिस्तान, बाड़मेर और जोधपुर जितना जानता है, बाकी लोगों को इसकी इतनी उपयोगिता का पता नहीं है। हमारे पूर्वजों ने वहां कैसे जल से किस प्रकार से जीवन जिया? वहां परंपरागत स्रोत थे, अच्छे-अच्छे स्रोत थे। चाहे वह तालाब के रूप में हो, चाहे वह खड़ीन के रूप में हो, चाहे वह रेंगते हुए पानी को छोटे-छोटे स्तर पर इकट्ठा किया हो, उससे उनका जीवन यापन चलता था और पानी की इतनी वैल्यू समझते थे कि एक बार उस पानी से स्नान करने के बाद फिर वह बचे हुए पानी को भी कैसे उपयोग में लेना है, यह जैसलमेर की जनता जानती है। वर्तमान समय में बहुत सारे विपक्ष ने आरोप लगाये और यह

कहा कि 14 महीने हो गये हैं, काम नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य था कि देश में 2024 तक आम घर तक हम पानी पहुंचाएंगे लेकिन यह विडंबना है कि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्वालिटी का भी ध्यान नहीं रखा, गुणवत्ता नहीं देखी और यह सोचकर बजट नहीं दिया कि इसका यश दूसरे लोग, दूसरी पार्टी ले जाएगी। जल एक ऐसी चीज है जिसको हर आदमी को इसकी जरूरत रहती है, हर इंसान और पशु को जरूरत रहती है। अपन सब यह चाहते हैं कि जल से बहुत बड़ा धर्म कहीं नहीं है, लोग प्याऊ लगवाते हैं, तालाब खुदवाते हैं, बावड़ी खुदवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, वे इसलिए खुदवाते हैं कि आमजन को जल मिले। उसमें तो किसी यश का काम नहीं है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया ने इस तरफ का कोई ध्यान नहीं रखा।

बहुत सारी शिकायतें भी मिलीं, कामों में अनियमितताएं हुईं और उसका लाभ पूरे राजस्थान की जनता को नहीं मिल पाया। जे.जे.एम. के अन्दर आबादी के हिसाब से लाभान्वित होना चाहिए, वह नहीं हुआ लेकिन वर्तमान सरकार आदरणीय भजन लालजी की सरकार को मैं यह धन्यवाद देता हूं कि जे.जे.एम. के अन्दर वृहद एवं एकल जलप्रदाय परियोजना में दिनांक 15.12.2023 से 31.03.2024 तक लगभग तीन लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया। यह भी, साथ ही इन योजनाओं में लगभग 2018 करोड़ रुपये का भी व्यय किया।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं 2024-25 में 8.36 लाख ग्रामीण परिवारों को नल उपलब्ध करवाकर लगभग 4559 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी है। 15.02.2025 तक 2066 नये नलकूप भी खुदवाये और इसके साथ में 2891 नये हैंडपम्प भी लगवाये। यही नहीं पूर्ववर्ती सरकार के ऐसे कई हैंडपम्प थे जो क्षतिग्रस्त थे, क्रियाशील नहीं थे, उनमें से 2 लाख 87 हजार 744 खराब हैंडपम्पों को भी पुनः चालू करवाया इसलिए मैं और आम जन, पूरी जनता जैसलमेर की राजस्थान की वर्तमान सरकार के मुखिया आदरणीय भजन लालजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

(समय: 19.34 बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, उस क्षेत्र के हिसाब से हमारे माननीय जलदाय मंत्री ने हकीकत में भी देखा है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जो पाइप लाइन लगी थी, वह किसी कारण से दीमक से या ज्यादा जंग लगने से जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गयी थी तो आप पधारे और आपने वैकल्पिक व्यवस्था की, उसकी रिपेयरिंग करके मेरे शहर को पानी पिलाया लेकिन वह अस्थायी व्यवस्था थी। मैं यह चाहता हूं कि इस योजना में विभाग द्वारा, बड़ी योजना के रूप में इसको विकसित करके मेरे जैसलमेर को, एक तरफ से तो गजरूप सागर तालाब आता है, उसमें उस पानी का कलेक्शन किया जाये, रोका जाये और उसके पास में फिल्टर प्लांट लगाकर मेरे शहर को पानी पिलाया

जाये। यह व्यवस्था, पूर्व में भी इसका एस्टीमेट बना था, आदरणीय, वह सक्सेस नहीं हुई। मैं आदरणीय मंत्रीजी से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्कीम को, इस योजना को आप जल्दी सेंक्शन करें तो आने वाली गर्मी के सीजन में मेरे जैसलमेर शहर के लोगों को पेयजल की व्यवस्था होगी।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप एक परमिशन दें कि जिन माननीय सदस्यों के पास अपनी बात लिखी हुई है और कोई टेबल करना चाहे तो आप इजाजत दे दें तो उन सदस्यों की बात रिकार्ड पर भी आ जायेगी और समय भी बच जायेगा।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आदरणीय, मेरा तो एक मिनट का काम है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य। आज सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं मगर समय के अभाव की वजह से किसी के पास लिखा हुआ है तो आप टेबल कर दीजिए, पूरा रिकार्ड में आ जायेगा। नहीं तो पांच मिनट, सात मिनट में आपकी पूरी बात कह नहीं पाएंगे। मुख्य-मुख्य बात आप कह दो और बाकी टेबल कर दो।

हां, छोटूसिंहजी।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, हमारे लोग तो कोई बोले ही नहीं। हमारे लोग पहले बजट पर भी नहीं बोल पाये, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी नहीं बोल पाये तो आठ मिनट से नीचे नहीं। आपके लोग तो बोले हुए हैं, आपके लोग तो आप कम कर लो भले ही लेकिन आठ-आठ मिनट से कम नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैंने नेता, प्रतिपक्ष से सहमति ले ली है और जो टेबल करना चाहे उनकी मर्जी से, मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। बोलना चाहे तो वे बोलें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): रखना चाहे तो रख सकते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह तो अपनी च्वाइस पर है न।

श्री सभापति: च्वाइस के ऊपर कहा है, स्वेच्छा से।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पिछली बार हमें तो चार मिनट से ज्यादा नहीं बुलवाया जाता था। हमें तो चार मिनट में ही टोक दिया करते थे पिछली बार।

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है जहां आखिरी छोर तक नहर से पानी आया, उस नहर की, आई.जी.एन.पी. नहर की शाखाएं 105 आर.डी. से अंतिम छोर म्याजलार तक पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने आदरणीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में एक स्कीम बनाई थी और उस स्कीम का सर्वे भी हो गया, सेंक्शन भी उनकी हो गयी थी लेकिन बीच में सरकार कांग्रेस

की आयी और उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्कीम को जो हमारे अंतिम छोर पर पेयजल का ट्यूबवैल पानी जा रहा है उससे उसी नल से पानी दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री विराजे हुए हैं, उस योजना को पुनः चालू किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जैसे परंपरागत हमारे जल के जो स्रोत थे, पुराने जल के स्रोत थे, जैसे कुएं थे, जैसे हमारे तालाब थे, जैसे हमारे कम से कम 800-900 खड़ीन थे, जिसमें पानी भरता था और भरने के बाद में जब सिंचाई होती थी और उसके बाद में उस जल का रिसाव उन कुओं में जाता था तो पुराने अपने जो स्रोत हैं, उनको अब भी आपको विकसित करना होगा जिससे कि जल की उपयोगिता का पता पड़ेगा और आमजन तक वह पानी पहुंचेगा। उन कुओं के लिए भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत से कि उन कुओं के अन्दर भी बिजली के कनेक्शन कराएं, मोटरें लगाएं ताकि गांव और ढाणी तक वह पानी पहुंच सके।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, अब मांग संख्या 42 आती है जो नहर विभाग से सम्बन्ध रखती है।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): मैं, आदरणीय, यह निवेदन करना चाहता हूं, एक मिनट, केवल एक मिनट। आदरणीय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भरोसे रखा, वॉटर रेगुलेशन की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अन्दर सभी जन-प्रतिनिधि आये और चार बारी का बोला था कि कृषि के अन्दर हम आपको चार बारी देंगे लेकिन, आदरणीय, यह किसानों के साथ धोखा हुआ है। केवल तीन बारी ही मिली इसलिए उन किसानों का बीज उनकी खेती में ही रह गया।

आदरणीय, आधा मिनट दे दीजिए। ...(व्यवधान)...

ssy/rtm/05.03.2025/19.40/4e

हमारे आईजीएनपी की 1365 आरडी से बहुत बड़ी डिग्गी पेयजल के लिए, इमरजेंसी के लिए तैयार कर रहे हैं। उसकी गुणवत्ता में जब हम गये तो बड़ा फर्क लगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके अन्दर अलग से ऑडिट करवाकर उस डिग्गी की गुणवत्ता को सुधार जाये ताकि वहां पूरे जिले को पानी मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री सुरेश गुर्जर।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 41 और 42, पेयजल और जल संसाधन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पूरे दिन से पानी पर चर्चा हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं, मैं राजस्थान के उस जिले से आता हूं जहां पर राजस्थान की सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा नदियां बहकर निकलती हैं। सबसे ज्यादा डैम, सबसे ज्यादा तालाब हैं, तो मेरे जिले झालावाड़ में हैं।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे जिले में बहने वाली परवन नदी, काली सिंध नदी, आहू नदी, छापी नदी और उजाड़ नदियों का जो पानी बहकर जाता है, उस बहते हुए पानी से 17 जिलों की जो ईआरसीपी योजना सरकार ने बनाई है, उससे 17 जिलों के लोगों को पानी मिलेगा।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे जिले में सबसे ज्यादा नदियां हैं, सबसे ज्यादा तालाब हैं, सबसे ज्यादा पानी है, इसके बावजूद भी नदियों के पास बसे हुए गांव के लोग खेती के लिए और पीने के पानी के लिए आज भी प्यासे हैं। मैं मेरी विधान सभा खानपुर के असावर तहसील में आने वाले 6 पंचायतों के 40 गांवों की बात करूं तो वहां के लोगों के लिए ना तो खेती का पानी है और ना पीने का पानी है जबकि एक किनारे भीमसागर डैम बना हुआ है और दूसरी तरफ काली सिंध डैम बना हुआ है फिर भी वहां के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। लंबे समय से वहां पर लिफ्ट परियोजना की मांग की जा रही है, मेरी सरकार से निवेदन है कि आप इस लिफ्ट परियोजना के माध्यम से उन लोगों को पानी पिलायें।

मेरी ही विधान सभा की बकानी तहसील की 6-7 पंचायतें हैं, जिसमें लगभग 40 गांव आते हैं, आगरिया पंचायत, कुशलपुरा पंचायत, बरखेड़ा पंचायत, गडरवारा पंचायत, खेरिया पंचायत के 40 गांवों में पीने का पानी नहीं है और ना ही खेती के लिए पानी है। वहां के लोग पानी के अभाव में पलायन कर जाते हैं। वहां उपजाऊ भूमि है। वहां पर छोटे-छोटे खाले, छोटी-छोटी नदियों पर छोटे-छोटे डैम बनाकर पानी रोकने की आवश्यकता है। अगर आप वहां पर छोटे-छोटे डैम बनायेंगे तो निश्चित ही पलायन भी रूकेगा और वहां के लोगों को पेयजल का पानी भी मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, खानपुर विधान सभा में परवन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सिंचाई और पेयजल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना बजट के अभाव में उपेक्षा का शिकार हो रही है। इस परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभाव क्षेत्र के लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। वहां के किसान मुआवजे के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। राजकीय भूमि पर, सिवाय चक पर, वन भूमि में बसे हुए 587 मकानों का मुआवजा बजट के अभाव में अभी अटका हुआ है।

साथ ही उन विस्थापित कॉलोनियों को भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस प्रकार आंशिक रूप से प्रभावित गांवों महुवा खेड़ा, दोलाना, बोरखेड़ी, अकावत कला, अकावत खुर्द, हालोती गांवों को पूर्ण डूब घोषित करने की मांग भी लंबे समय से लंबित है। मेरी आपसे मांग है कि इन सभी गांवों को पूर्ण डूब प्रभावित घोषित कर मुआवजा दिया जाये।

साथ ही परवन वृहत परियोजना से छूटे हुए गांव ग्राम पंचायत करणवास, तारज, मालनवासा, धानोदा, बिसनखेड़ी और हरिगढ़ के सभी गांवों को भी इस परियोजना से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा खानपुर में काली सिंध नदी पर निर्माण, बकानी के मोड़ी में बांध और हरिशचंद्र सागर परियोजना के लिए 33 करोड़ रुपये की राशि का जो बजट सरकार ने दिया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

पेयजल की अगर बात की जाये तो बजट में हर विधान सभा क्षेत्र में, पिछले बजट में 10-10 हैंडपम्प और 5-5 ट्यूव वेल दिये थे। मगर राजनीतिक भेदभाव के चलते मेरी विधान सभा में एक भी हैंडपम्प सरकार ने नहीं दिया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस बजट में जो भी आपने हैंडपम्प और ट्यूबवेल दिये हैं, चाहे किसी भी सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के हों, समान रूप से सभी को दी जाये।

मेरी विधान सभा क्षेत्र खानपुर के 405 गांवों में से केवल 73 गांवों में पूर्ण कार्य हुआ है। इन गांवों में वर्क परियोजना के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की स्वीकृति जारी की गई है। इस पर परवन परियोजना के अंतर्गत 143 गांवों को पेयजल पहुंचाने की स्वीकृति जारी की गई ह। किंतु अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं। मेरी मांग है कि खानपुर के बचे हुए 332 गांवों को जल्दी से जल्दी पेयजल उपलब्ध कराया जाये। साथ ही, मेरी विधान सभा के गाडरवा डूंडी, खानपुर, पीपलाद, जोलपा, सूमर, मोहम्मदपुर, गोल्याजेड़ी, देवपुरा, बावरा, मेंदड़ी, कंवलदा, कंवरपुरा आदि गांवों के लोगों को फ्लोराइड युक्त जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। मेरी मांग है कि हर गांव में आरओ लगाकर उनको पानी दिया जाये।

सभापति महोदय, अनुदान की मांग पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री संजीव कुमार जी।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 41 और मांग संख्या 42 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही है, इस विषय पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह कृषि प्रधान इलाका है। अतः मैं समय का ध्यान रखते हुए मेरे क्षेत्र के किसानों की सिंचाई की मुख्य समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का जब शिलान्यास हुआ तब किसानों के द्वारा इसे एक जीवनदायनी के रूप में देखा गया। लेकिन उस समय के तत्कालीन जन प्रतिनिधि की उदासीनता एवं निष्क्रियता के चलते क्षेत्र के 14 गांवों को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया गया। हालांकि गत कांग्रेस सरकार द्वारा बजट घोषणा में ना केवल 100 करोड़ की थोथी और कागजी घोषणा की गई बल्कि विधान सभा चुनाव से

चंद दिन पहले आचार संहिता लगने के चंद दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्चुअल शिलान्यास करवाकर के क्षेत्र के जन प्रतिनिधि ने ढोल-नगाड़े बजवाकर के जनता की असत्य वाहवाही लेने का प्रयास किया।

माननीय सभापति महोदय, आज भी क्षेत्र का किसान सिंचाई, पानी की आस लगाये बैठा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन सिंचाई से वंचित भादरा एवं नोहर क्षेत्र के गांवों को आईजीएनपी की साहवा लिफ्ट योजना से जोड़कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अमरसिंह सब ब्रांच व सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना का पानी लगता है। इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं की नहरों का कुल डिस्चार्ज 1251 क्यूसेक्स है। इसमें 0.17 एमएएफ यानि लगभग 300 क्यूसेक्स पानी हरियाणा क्षेत्र से नहीं मिल रहा है। वह वाद माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

इसके उपरांत बीबीएमबी की मीटिंग में इन दोनों परियोजनाओं के लिए डैम में पानी की स्थिति के अनुसार शेयर निर्धारित किया जाता है। जब नहरों में रेगुलेशन आता है तो इस शेयर से भी कम पानी हरियाणा हमें देता है। पानी में उतार-चढ़ाव आता है जिससे किसानों की बारी लगातार पिटती है। पानी के लिए बार-बार हरियाणा से निवेदन करना पड़ता है। अतः मैं सरकार से निवेदन करुंगा कि बीबीएमबी की होने वाली मीटिंग में इन सिंचाई परियोजनाओं का शेयर 650 क्यूसेक्स से कम ना किया जाये।

spp/rtm/05.03.2025/19.50/4f

इसके अलावा जो वाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उसमें अच्छे तरीके से पैरवी करके राजस्थान के हिस्से का 0.17 एमएएफ पानी यानी 300 क्यूसेक्स पानी आप दिलवाने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई खालों के द्वारा की जाती है। अमर सिंह सब-ब्रांच और सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग एक लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है तो दोनों परियोजनाओं में खाला निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि वर्षों पुराने खालें होने की वजह से खालें क्षतिग्रस्त हैं, जीर्ण शीर्ण हालत में है, जिसकी वजह से टेल के किसान को पूरा पानी नहीं मिलता और पानी में छीजत होने की वजह से भी पानी की मात्रा कम रहती है। किसान को बड़ी भारी असुविधा होती है, अतः निवेदन है कि इन जर्जर खालों को पुनः बनाए जाने के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ अमर सिंह सब ब्रांच का आर.डी.जीरो से आर.डी.90 तक का रिलाइनिंग का कार्य स्वीकृत है, जिसके टेंडर लग गए हैं। मेरा निवेदन है कि इसके साथ-साथ डीपीएन और एनटीआर सहित विभिन्न वितरिकाओं को भी का भी रिलाइनिंग कार्य स्वीकृत करवाकर उनकी मरम्मत करवाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में जल संसाधन विभाग में काफी समय से तकनीकी कार्मिकों की बहुत कमी है। ड्राफ्टमैन, गेज रीडर, बेलदार, मेट, जिलेदार, पटवारी इत्यादि जो इनके पद हैं, बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं और नहरों के संचालन के लिए इन पदों को भरा जाना अति आवश्यक है, अतः इन पदों पर भर्ती करवाने की सरकार व्यवस्था करें। अमरसिंह सब ब्रांच से निकलने वाली झांसल वितरिका के 9 JSL व 10 JSL के रकबे को सिद्धमुख प्रणाली की रतनपुरा वितरिका के चक आठ आरटीपी एवं पटवा माइनर के चक दो पीटीएम में सम्मिलित किए जाने के बाद रकबा टाइट कमांड हो जाने की वजह से मेरे क्षेत्र के गांव जोगीवाला, लाखनवास, भोलावास, सागड़ा आदि गांव, ये एक तरह से सिंचाई सुविधा से वंचित हो गए हैं। इनके लिए सिद्धमुख नहर के अंतर्गत वर्तमान में सरकार के पास भोलाबास माइनर प्रस्तावित की हुई है। अतः मैं आप के माध्यम से निवेदन करूँगा मंत्री जी से कि ये कृपया भोलाबास माइनर की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की दो परियोजनाएं सिद्धमुख एवं अमर सिंह सिंचाई की सब ब्रांच लगती है। इन सिंचाई परियोजनाओं से हनुमानगढ़ जिले की दो तहसील भादरा एवं नोहर तथा चूरू जिले की सादुलपुर तहसील का एरिया लगता है और दोनों परियोजनाओं का अधिकांश क्षेत्र विधान सभा क्षेत्र भादरा में आता है। पूर्व में पहले यहां अधीक्षण अभियंता कार्यालय भादरा में स्थित था, जिसे नोहर स्थानांतरित कर दिया गया। भादरा में एक कार्यालय के लिए भवन की भी उपलब्धता है और भादरा दोनों तहसीलों के केंद्र में स्थित है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा के भादरा में एस.ई. कार्यालय को पुनः स्थापित किया जाए। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में अमरसिंह सब-ब्रांच एवं सिद्धमुख नहर के रेगुलेशन को हरियाणा की नहरों के रेगुलेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे क्षेत्र को हरियाणा राज्य से सिंचाई पानी, संपर्क बिंदु सीपी फाइव पर दिया जाता है। अमर सिंह सब-ब्रांच में सिद्धमुख फीडर नहर दोनों नहरें समांतर रूप से राजस्थान में हरियाणा से प्रवेश करती है तो हरियाणा क्षेत्र से पानी के उतार-चढ़ाव को सही करने के लिए इन दोनों नहरों का इंटर लिंकिंग चैनल बनाने की आवश्यकता है। इस इंटरलिंकिंग चैनल के निर्माण के उपरांत राजस्थान को हरियाणा के रेगुलेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं पीएचईडी की दो बातें अपनी रखकर और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना में अनेक ढाणी और गांव को, घरों को उससे वंचित कर दिया गया, पाइप लाइन से वंचित कर दिया गया। रिवाइज़ स्कीम में बढ़कर के अभी विभाग के पास विचाराधीन है। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल जीवन मिशन की उन स्कीमों को स्वीकृति प्रदान करने की आप कृपा करें और इसके साथ-साथ जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव की नई सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ दिया

गया तो वो गारन्टी पीरियड में हैं तो ठेकेदारों को पाबंद करें कि उन सड़कों की मरम्मत करवाएं और यदि काम नहीं हुआ है तो उन ठेकेदारों के खिलाफ़ और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ़ भी आप कार्रवाई करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से निवेदन करूंगा कि पीएचईडी डिपार्टमेंट में भी पिछले काफी सालों से जो तकनीकी कार्मिक हैं, लाइनमैन, पम्प ड्राइवर, ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): इस तरह के कार्मिक हैं इनकी भर्ती शीघ्र करने की आवश्यकता है ताकि पीएचईडी में पानी का जो वितरण है, उसके संचालन को सही किया जा सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बात पूरी करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री गणेशराज बंसल।

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 41 एवं 42 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में हमारे जिले को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जीर्ण-शीर्ण खालों के पुनर्निर्माण के लिए हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए 590 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा की है। राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना व भाखड़ा के अंतर्गत नहर प्रणाली में गेहूं व सरसों की फसल पकाव के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। पानी की मांग हेतु किसान आंदोलनरत हैं। फसल के पकाव के लिए एक पानी की आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से एवं जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन है कि किसानों को एक पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी फसल अच्छी पक सके और वो अपना जीवन-यापन अच्छी तरीके से कर सकें।

माननीय सभापति महोदय मैं आप के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ जिले में प्रभावित होने वाली डायवर्शन चैनल सेम नाला में हर समय एक हजार क्यूसेक्स से अधिक पानी चलता है और मानसून मौसम के दौरान सेम नाले में पानी की आवक तीन हजार से लेकर आठ हजार क्यूसेक्स होती है, जो सिंचाई हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है और मानसून के दौरान वर्षा का स्वच्छ जल बिना किसी उपयोग के व्यर्थ में बह जाता है, जबकि स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में ही कृषि योग्य रकबे में उक्त पानी का सिंचाई हेतु उपयोग किया जा सकता है। सेम नाले की 42 आरडी के नीचे साइफन से गुज़रने वाली जीजीआर नहर, जो 250 क्यूसेक्स की है, जो आगे एसएचडब्ल्यू 115 क्यूसेक्स और एचएमएच नहर 70 क्यूसेक्स नहरों से जुड़ती है। उक्त चैनल में सेम नाले

का पानी लिफ्ट करके डाला जा सकता है जिससे एसएसडब्ल्यू नहर का 39 हजार 454 हैक्टेयर के 12 हजार 472 हैक्टेयर में फर्जी नहरों के 5 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे को सिंचाई हेतु अभी अतिरिक्त पानी मिल सकेगा और कपास की खेती वाला रकबा धान की खेती योग्य बन जाएगा। इस योजना से 60 से अधिक राजस्व चकों और हजारों कृषकों को लाभ होगा। उक्त प्रस्तावित लिफ्ट की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये है। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस वर्षा के पानी का सदुपयोग करने के लिए ये लिफ्ट कैनाल की मंजूरी शीघ्र देने का कष्ट करें।

घग्घर सेमनाला गडीसादडी से जीजीआर. एसएडब्ल्यू एच.एम.एच. नहर में पानी लिफ्ट करने हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने से हनुमानगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हनुमानगढ़ टाउन में शहर के बीचों-बीच में से घग्घर नदी गुजर रही है जो कि वर्तमान में कच्ची है। इस घग्घर नदी में पानी आने के पश्चात दोनों शहरों के डूबने का खतरा बना रहता है। वर्ष 1995 में भी बाढ़ में हनुमानगढ़ जंक्शन शहर डूब गया था, जिससे हनुमानगढ़ जंक्शन शहर को काफी क्षति हुई थी। मेरा आप के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि इस घग्घर नदी को रिवर फ्रंट बनाया जाए। गुजरात की अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरह इसको पक्का करके इसे रिवर फ्रंट बनाया जाए ताकि जो शहर को घग्घर नदी आने से खतरा बना रहता है, वो खतरा दूर हो और इस पर आम आदमी घूम सकें और शहर को सुंदर बना सकें।

माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाये जाने का ऐलान किया हुआ है, जो ढाणी-ढाणी नल से जल पहुंचाने का प्रयास केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

jyg/rtm/05.03.25/20.00/4g

लेकिन ढाणियों में तो हम पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं लेकिन कृषि भूमि पर जो कि शहरों में बसे हुए हैं हमारे नागरिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बरसों से, करीब 15 वर्ष से पीएचईडी द्वारा कृषि कॉलोनियों के लिए पॉलिसी बनी हुई है, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया इस तरीके की है कि कबूतर के सिर पर पहले मोम रखो, तो वो मोम पिघलकर उसकी आंखों में पड़ेगी फिर कबूतर को पकड़ेंगे। इस प्रकार की यह जो योजना है वो पीएचईडी की है कि पहले कॉलोनाइजर को प्रशासनिक स्वीकृति लेकर, वित्तीय स्वीकृति लेकर जल के स्रोत का जितना उसमें कंज्यूम होगा, उसका पैसा भरना पड़ेगा जिसमें बरसों लग जाते हैं। इस योजना के तहत कृषि भूमि की कॉलोनी के वासियों को पीएचईडी का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पीएचईडी मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जटिल तरीका है उसको सरल किया जाये, ताकि हमारे शहरों में कृषि भूमि में बसे हुए हमारे नागरिक हैं वो पीएचईडी का

पानी पी सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़ शहर में आरयूआईडीपी के तहत 288 करोड़ की योजना जो कि गत सरकार की वजह से फेल हो गयी, तो मेरा पीएचईडी मंत्री से निवेदन है कि इस 288 करोड़ की योजना को जो कि आर ओ का वाटर हमारे शहर को मिलेगा उस योजना पर भी गौर किया जाये। जलदाय विभाग के जो जल घर हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं। डिग्गियों में पेड़ उगे पड़े हैं, सफाई का अभाव है और जो मजदूर हमारे पानी चलाते हैं, उनका वेतन भी बहुत कम है, मात्र तीन-चार हजार रुपये में वो अपना कार्य कर रहे हैं। मेरा माननीय जलदाय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि उनकी ओर भी ध्यान दिया जाये, ताकि वो अपने परिवारों का जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय श्रीराम।

श्री सभापति: श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों का दु:ख, उनकी तकलीफ और कुछ मांगें रखना चाहता हूं। इर्रिगेशन डिपार्टमेंट हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगानगर जिला इर्रिगेशन डिपार्टमेंट पर ही निर्भर है। गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है जो पूरी तरह नहरी पानी पर निर्भर है। मेरे सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकार के बड़े गुणगान किये, बड़े-बड़े आंकड़े पेश किये, लेकिन आज धरातल पर स्थिति बिलकुल अलग है। पिछले एक साल से गंगानगर जिले में नहरों की स्थिति काफी खराब है। सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिला जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पिछले एक साल से किसान सिंचाई पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब-जब बीजेपी की सरकार आती है, किसानों को सिंचाई पानी के लिए आंदोलन करना पड़ता है। पिछला इतिहास है, चाहे घड़साना आंदोलन हो, चाहे गंगानगर आंदोलन हो, सिसियाड़ आंदोलन हो, किसानों को पानी के लिए आंदोलन ही करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के किसानों की आज फसल पूरी पकी हुई है। उनको सिंचाई के लिए आज पानी नहीं मिल रहा है और बड़े दु:ख की बात है कि पाकिस्तान पानी जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि पंजाब सरकार से बात करें, जो पानी पाकिस्तान छोड़ा जा रहा है वो हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों को दिया जाये, ताकि उनकी पकी हुई फसल को बचाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन आज

जो पानी की स्थिति है, अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे हाथ में सिर्फ कटोरा ही रह जायेगा तो सरकार इस तरफ ध्यान दे। वो किसान आपके हैं, हम गंगानगर वालों को आप लावारिस न समझें, हम आपके ही हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में फिरोजपुर फीडर निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी थी। हमने उसका स्वागत भी किया था। लेकिन आज तक डी पी आर बनकर तैयार नहीं हुई, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में गंग नगर के खाळों के लिए घोषणा की गयी जो मात्र सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र के लिए की गयी है। तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? करणपुर के किसान भी आपके हैं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है माननीय मंत्रीजी, गंग नहर के खाळों के लिए कम से कम आप 100 करोड़ के लिए बजट में घोषणा करें, ताकि वहां के किसानों को राहत मिल सके और उनको भी लगे कि सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, गंग नहर की नहरों की जायका परियोजना के अंतर्गत रिलाइनिंग स्वीकृत करने हेतु मेरे द्वारा माननीय मंत्री महोदय को प्रस्ताव भेजे गये थे उनके रिलाइनिंग कार्य के लिए स्वीकृत किये जायें ताकि किसानों को जो पानी नहीं मिल रहा है, टेल तक पूरा पानी नहीं जा रहा, उसकी कमी पूरी की जा सके। माननीय सभापति महोदय, आज हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के सभी गांवों की कृषि भूमि को नहरी पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है परंतु मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव जीवनदेसर की कृषि भूमि नहरी पानी से वंचित है, इस गांव के पास से नहर गुजरती है फिर भी इस नहरी पानी से वंचित रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, आपसे अनुरोध है कि जीवनदेसर गांव की कृषि भूमि को नहरी पानी देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करायें, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बीबी नहर का हैड ऊँचा होने की वजह से नहर अपनी क्षमता अनुसार पानी नहीं ले पाती, जिससे नहर के सभी मोगे और टेल प्रभावित होते हैं, इसकी जांच करवाकर दुरुस्त किया जाये। माननीय सभापति महोदय, गंग नहर की बीकानेर कैनाल की आरडी संख्या 0 से आरडी संख्या 45 तक नहर की सफाई करवाने का कार्य किया जाये, ताकि एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर उपयोग पाकिस्तान जाने वाले पानी को इसमें प्रवाहित किया जा सके, क्योंकि फिरोजपुर फीडर अपनी क्षमता अनुसार पूरा पानी नहीं ले पा रही जिससे अपने किसानों के हिस्से का पानी पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है। बीकानेर कैनाल की आरडी संख्या 0 से आरडी संख्या 45 तक साफ-सफाई करवाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को इस नहर के माध्यम से लिया जा सकता है और फिरोजपुर फीडर के पुन: निर्माण के समय भी इसके विकल्प के तौर पर पानी लिया जा सकता है जिसका गंग कैनाल के किसानों को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज मैंने प्रश्न काल में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था।

जिससे हम हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले सहित 12 जिले प्रभावित होते हैं। केमिकलयुक्त पानी पंजाब से आ रहा है, बड़ा गंभीर विषय है तो मैं आपके माध्यम से फिर माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि कृपया इस ओर संज्ञान लें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। आज अमृत काल में भी हम स्वच्छ पानी नहीं पी रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार के समय 2023 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षेत्रीय जल योजना 27 एमएल के लिए 9 करोड़ रुपये एवं क्षेत्रीय जल योजना बींजवाला के लिए 6 करोड़ रुपये जीर्णोद्धार के लिए, हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति जारी की गयी थी, लेकिन विधान सभा चुनाव की आचार संहिता के कारण ये कार्य नहीं हो सके। माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध कि क्षेत्रीय जल योजना 27 एमएल बींजवाला की टेंडर प्रक्रिया शुरू करवायें ताकि दोनों क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सके।

माननीय सभापति महोदय, अमृत योजना में वर्ष 2023 में करणपुर शहर के लिए साढ़े छह करोड़ रुपये, केसी सिंघु के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये, पदमपुर के लिए छह करोड़ रुपये, गजसिंहपुर के लिए पांच करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हैं। इनके टेंडर दिसम्बर 2024 में लगे हैं, अतिशीघ्र इनका कार्य करवाया जाये, ताकि आने वाली गर्मियों में पेयजल का लाभ मिल सके। शहरी योजना गजसिंहपुर में पेयजल आपूर्ति की बहुत समस्या रहती है, गजसिंहपुर के लोगों की मांग है कि यहां वार्ड नम्बर पांच में पानी का एक टैंक बनाया जाये, ताकि पेयजल सम्बन्धी समस्या दूर हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

MLS/RTM/05.03.2025/20:10/4h

श्री सभापति: श्री देवेन्द्र जोशी।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 41 और 42 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है, इसके लिए हार्दिक रूप से आपका आभार। मान्यवर, प्रदेश के कर्मशील मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार सरकार राजस्थान की परम्परागत पेयजल की समस्या से निपटने के लिए कटिबद्ध है। मैं इसके लिए भी राजस्थान की सरकार का अभिनन्दन करता हूं, उनके लगातार हो रहे प्रयासों का भी अभिनन्दन करता हूं।

प्रदेश की सरकार ने नदी माता गंगा, यमुना, नर्मदा, पार्वती, कालीसिन्ध और चम्बल से राजस्थान की धरा के अभिषेक से किसानों की समृद्धि और ''हर घर नल से नीर'' की जो योजना प्रारम्भ की है, वह भी वन्दनीय है। निश्चित रूप से नल-नीर का जो गणेश किया है, इससे माननीय भजन लाल जी की सरकार का अभिनन्दन करता हूं। ''कैच द रेन'' का जो अभियान राजस्थान सरकार ने प्रारम्भ किया है, उससे मां धरती को सरस, शस्य श्यामला

बनाने का अभियान भी वन्दनीय है।

प्रदेश सरकार ने अपने 14 माह के कार्यकाल में 11 लाख 36 हजार परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का महती कार्य किया है। जल जीवन मिशन में उल्लेखनीय प्रगति निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व की बात है, जबकि पूर्व सरकार ने तो जल जीवन योजना का नाम ही बदलकर ''जमकर जीमो योजना'' बना दिया। जल जीवन योजना में हर स्तर पर जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उन दिनों तो हर रोज़ अखबारों में सुर्खियां बनती थीं, लेकिन भजन लाल जी की सरकार ने इसको बदला और आज 14 माह के कार्यकाल में निश्चित रूप से जो प्रगति हुई है, वह उल्लेखनीय है। इस भ्रष्टाचार के खेल के कारण आम गरीब व्यक्ति, गांव और ढाणी में रहने वाले उन लोगों तक समय पर जल नहीं पहुंचाया जा सका। इसके कारण से योजना हमको बढ़ानी भी पड़ी।

सरकार पांच सालों में पांच सितारा होटलों से चली। इस कारण से संवेदनशीलता समाप्त हो गयी और संवेदनशीलता समाप्त हुई, उसका सबसे बड़ा फर्क यह पड़ा कि आम गरीब की चिन्ता सरकार को नहीं रही और उसी कारण से जल जीवन जैसे मिशन में भी जो देरी हुई और आम गरीब को जो तकलीफ हुई, वह सरकार तक नहीं पहुंची। इन लोगों ने काण्ड किये और हमारी सरकार काम कर रही है। इन 14 माह में जो बेसिक फर्क देखने को मिला, इन लोगों के काण्ड के सामने हमारी सरकार काम कर रही है और काम करके बता भी रही है, इसलिए मैं इस सरकार का अभिनन्दन करता हूं, विशेष रूप से जलदाय मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी का, जो लगातार दौरे पर दौरे करते हुए हर जिले को टच करते हुए जिस तरह से वे फॉलो-अप कर रहे हैं, मैं समझता हूं, राजस्थान जल्द ही जल के मामले में आत्म निर्भर होगा। एक बार पुनः अभिनन्दन करता हूं।

इस अवसर पर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की अगर बात नहीं रखूं तो लगेगा मैं जोधपुर के साथ न्याय नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, जोधपुर में गर्मी आने से पहले ही पेयजल संकट के हालात बने हुए हैं। इसका मुख्य कारण है, इन्दिरा गांधी नहर की जो मरम्मत का कार्य है, वह पिछली सरकार में समय पर पूरा नहीं हो सका। इस कारण से आज भी सर्दी के दिनों में जोधपुर में पानी की किल्लत बनी हुई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी मरम्मत का कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाये, ताकि आने वाले दिनों में गर्मी के मौसम में जोधपुर में पानी की किल्लत नहीं हो। जोधपुर में पहले से ही आवश्यकता से कम पानी मिल रहा है। उसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए राजस्थान नहर की मरम्मत का कार्य समय पर पूरा होना आवश्यक है।

अभी भी महीने में तीन-चार बार कटौती जारी है। यह कटौती, जब तक रिज़र्वोयर नहीं बढ़ेंगे जोधपुर में, राजस्थान नहर से बराबर पानी की आपूर्ति नहीं होगी, तब तक यह पूरी नहीं होगी। इस उपलब्धता में और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जोधपुर में, वह है अमृत-2.0 योजना के अन्तर्गत सीवरेज के कार्यों में कांग्रेस शासन में दबाकर भ्रष्टाचार हुआ। करीबन-करीबन 50 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार की जांच आज भी जारी

है। इसके कारण से सूरसागर और शहर विधान सभा में कार्य प्रभावित हुए। अब जब कार्य प्रारम्भ हुए तो उसमें यह समस्या हो गयी कि जहां-जहां कार्य प्रारम्भ होते हैं, पानी की पुरानी लाइन टूट जाती है। टूटने के कारण से सप्लाई बाधित हो रही है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि वे अमृत-2.0 योजना के साथ-साथ जहां पुरानी पानी की पाइप लाइन हैं, उनको भी दुरुस्त करें।

मान्यवर, जोधपुर पानी की उपलब्धता के लिए पूरे राजस्थान में नम्बर एक पर है। 24 घण्टे 123 ट्यूबवैल पानी को निकालते हैं। अगर वे निकालना बन्द कर दें तो जोधपुर में ग्राउंड वॉटर लेवल दो से तीन फीट ऊपर आ जाता है। यह जोधपुर की विशेषता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी एक कार्य योजना बनाकर, जिसमें यह पानी क्षेत्र के आसपास जो परम्परागत जल स्रोत हैं, चाहे शहर के अन्दर चान्दबावड़ी है, चाहे शहर के अन्दर काफी बाव़डियां हैं, जालप मोहल्ले की बावड़ी है, इसी तरह से इन बावड़ियों को अगर उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाये तो ये जो परम्परागत वॉटर सोर्सेज हैं, ये रिवाइव भी हो जाएंगे और उसके साथ जो इन क्षेत्रों में हो रहे हैं, जैसे गंगलाव तालाब आज विलुप्त होने पर है, क्योंकि अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया।

अगर उसके पास जो वॉटर रिज़र्व सोर्सेज हैं, ट्यूबवैल आप जो चला रहे हो बकरा मण्डी में, उसका अगर कनेक्शन उससे कर दिया जाये तो एक तो यह अतिक्रमण होने की समस्या से मुक्त होगा और दूसरा ये परम्परागत वॉटर सोर्सेज जीवन्त हो जाएंगे। इनको जीवन्त करने से, जोधपुर अकेला ऐसा शहर है, जो पूरे आसपास के गांवों को भी अपने रिसोर्सेस से पानी दे सकता है, जैसा कि मेरे मारवाड़ से आने वाले कई विधायकों ने उम्मेद सागर को लेकर चिन्ता ज़ाहिर की। मैंने पिछले सत्र में भी उम्मेद सागर को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। उम्मेद सागर एकमात्र ऐसा स्थान है, जो पूरे जोधपुर डिवीज़न में, पानी के मामले में अगर उसको ठीक ढंग से स्टोरेज के लिए तैयार कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कायलाना पर डिपेंडेंसी कम होगी और उम्मेद सागर होने से गांव में जो भी सप्लाई हो रही है, अगर वह उम्मेद सागर के माध्यम से कर दी जाये तो उसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इस बार उस क्षेत्र के लोगों ने एक नहर को ठीक किया। उम्मेद सागर में पांच नहरें आती हैं अलग-अलग क्षेत्रों से।

श्री सभापतिः समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): एक नहर को ठीक करने से 10 फीट पानी उसमें आया। अगर ये पांचों ही नहरें उसकी ठीक हो जाएं तो शायद उम्मेद सागर लबालब भर जायेगा...

श्री सभापतिः श्रीमती गीता बरवड़।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): और एक बार लबालब भर गया तो आसपास के गांवों में उससे सुविधा होगी।

श्री सभापतिः प्लीज समाप्त कीजिये।

श्री देवेन्द्र जोशी (सूरसागर): एक बार पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41, 42 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी विधान सभा की बात करना चाहूंगी। विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पेयजल को वर्तमान की आबादी के हिसाब से बढ़ाये जाने की अति आवश्यकता है। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति 2011 की जनगणना के आधार पर की जा रही है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की आज यह हालत है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वे 2011 की जनगणना के आधार पर बने। आज कहां 2011 और कहां 2025?

वर्तमान में आबादी के हिसाब से पानी नहीं के बराबर है। महोदय, राजस्व ग्राम, नगर, वार्ड अनुमानित आबादी के 15-20 दिन एवं महीने में पेयजल की आपूर्ति सिर्फ एक घण्टे या आधे घण्टे की जाती है और वह भी बीच में अवैध कनेक्शन की वजह से आधे एरिया में पानी आता है, आधे एरिया में पानी नहीं आता। कुछ लोग पानी पी रहे हैं, कुछ लोगों को पानी एक महीने में भी अवेलेबल नहीं हो रहा। मेरी आपसे यह विनती है कि आज की आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से पानी पीछे से बढ़ाया जाये, ताकि जनता को पानी मिल सके और जो पानी की किल्लत हो रही है, वह किल्लत थोड़ी कम हो सके।

सभापति महोदय, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना का तीसरा चरण, 24 नवम्बर 2022 को इसका कार्य शुरू किया गया, जो माननीय गहलोत साहब के समय 1799 करोड़ की लागत से किया गया।

MKD/RTM/05.03.2025/20:20/4j

यह परियोजना 2054 तक की पेयजल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इस का निर्माण कार्य अन्तिम छोर पर है, लेकिन जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक जनता की पानी की आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण किया जाए, मैं इसकी मांग करती हूं। आप जनता और किसानों को कैसे पानी की आपूर्ति करवायेंगे, ये पूर्ति करवाने की मैं मांग करती हूं।

जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, एसआर टंकियों के निर्माण की बहुत आवश्यकता है, लेकिन सरकार के सूखे वादे, सूखे नल। गांवों में पानी की टंकियां, पाइप लाइन टूटी पड़ी हैं।

सभापति महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ग्राम पंचायत जोइंदरा, जालीवाल, विश्नोईया, सेवकी कलां, लेवेरा कलां, लेवेरा खुर्द, गरसानी, राम नगर, साथी की ढाणियां, शिवनाथ नगर के मध्य और रजलाणी के साकेड़ा भाकर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत एसआर पेयजल टंकियों निर्माण किया जाए और वंचित ढाणी, मोहल्ले को पाइप लाइन से जोड़कर, वहां जीएलआर टांके बनाये जाने की मांग करती हूं, ताकि वहां की जनता और किसानों को राहत मिल सके। जो टंकियां पहले से बनी हुई हैं, जिनमें अभी तक पानी भी भरा नहीं गया है। उनमें पानी भरा जाए और आसपास का जो एरिया है, वहां पाइप

लाइनें लगवाकर पानी पहुंचाया जाए।

जल जीवन मिशन के तहत जहां कार्य पूरा हो चुका है, वहां पर नियमित रूप से पानी की सप्लाई के बारे में बात करें। सभापति महोदय, केवल 40 परसेंट ग्राम पंचायतों में काम हुआ, इससे ज्यादा काम नहीं हुआ। इसमें भी जो पाइप लाइनें लगाई गई हैं, उनमें भी पानी सुचारु रूप से चालू नहीं किया। जो पुरानी पाइप लाइनें लगाई हुई थीं, उनको भी हटा दिया। पुराने पाइप लाइनों से जो पानी आ रहा था, वह भी बन्द कर दिया। नई पाइप लाइनों में पानी शुरू नहीं किया गया है।

महोदय, इससे पानी की चारों तरफ त्राहिमाम हो रही है। मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत हो रही है। ऐसी स्थिति रही है, इसकी वजह से पानी की ज्यादा समस्या हो गई। मैं आपसे निवेदन करूंगी, इस समस्या का समाधान कराये। भोपालगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल सप्लाई हेतु अमृत 2 योजना तो स्वीकृत है, लेकिन कार्य प्रगति पर नहीं है।

महोदय, इनका जल्दी ही कार्य शुरू करवाये। ट्यूबवैल और हैंडपम्प की बात करें तो माननीय गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 ट्यूबवैल और 40 हैंडपम्प हर बजट घोषणा में दिये। वर्तमान आबादी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। आप इसके हिसाब से 20 के जगह 40 ट्यूबवैल और 80 हैंडपम्प की घोषणा करते तो सही रहता, लेकिन विधान सभावार आपने 5 ट्यूबवैल और 10 हैंडपम्प की स्वीकृति दी। इसमें भी राजनीति हुई।

मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि जो आपने 5 ट्यूबवैल और 10 हैंडपम्प दिये, वे किसकी अनुशंसा से होंगे, क्योंकि हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि इसके अन्दर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि विधायक की अनुशंसा से ही ये किये जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार पंचायत समितियां पड़ती हैं, लेकिन एक ही पंचायत समिति में ही आपने सारे काम करवा दिये तो तीन पंचायत समितियों में हम क्या करेंगे? वहां की जनता को हम पानी कहां से अवेलेबल करवाये? आप ये करते, आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं। आप करोड़ों का काम लेते तो हम भी कहते कि भोपालगढ़ में आपने विकास की गंगा बहा दी, लेकिन आपने 5 ट्यूबवैल और 10 हैंडपम्प में भी राजनीति की।

सभापति महोदय, आज भारत अमृत महोत्सव मनाने की बात करता है। सभापति महोदय, अमृत महोत्सव तब होगा, जहां पेयजल की आवश्यकता हो, वहां पेयजल उपलब्ध कराये। कई ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन उस ग्राम पंचायत के गरीब लोगों की ढाणी, मोहल्ले को पानी की लाइनों से वंचित रख दिया गया है। उन्हें पाइप लाइनों से जोड़ा जाए। आज भी मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं। वहां हालत यह है कि मीठा पानी तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल पानी भी उनको नहीं मिल रहा है। लोग दिनभर मजदूरी करने के बाद टैंकर से पानी मंगवाते हैं। लवारी में चौकीदारों, बावरियों के मोहल्ले में पचास सालों से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। केलाब, बेरा, कुम्हारों, मालियों व

जाटों की ढाणी, गंगाणी में जल्दी ही मीठे पानी की पाइप लाइनों की व्यवस्था करवाये।

गंगाणी में नवानगरिया एक गांव है, जहां भूमि में ही पानी खारा है। न तो वहां पर ट्यूबवैल करवा सकते हैं, न ही हैंडपम्प करवा सकते हैं। मैंने कई धरने दिये, प्रदर्शन किये, लेकिन आज तक वहां पर पाइप लाइन नहीं डलवाई गई। वे आज भी पानी से वंचित हैं।

सभापति महोदय, जल संसाधन की बात करें तो ग्राम पंचायत गंगाणी में बहुत बड़ा तालाब है, इसको जलापूर्ति के लिए, पेयजल सुदृढ़ीकरण हेतु माणकलाव या सुरपुरा डैम या थबुकडा मुख्य पाइप लाइन से जोड़कर पेयजल हेतु स्टोरेज होज बनाया जाए, ताकि इसकी परिधि में आने वाली ग्राम पंचायतों की ढाणियों के करीब 20 गांवों को पर्याप्त और समयबद्ध पानी की सप्लाई हो सके। यह प्रोजेक्ट करीब 3 करोड़ का है। विभाग ने सरकार को भिजवाया है, मैं स्वीकृत करवाने की मांग करती हूं।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में बांध, तालाब, झीलें ग्रामीण क्षेत्र की जीवनदायिनी संरचना है। इसी प्रकार मेरे भोपालगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सिम्बेशर तालाब है, जो वर्षा ऋतु में बारिश के पानी से पूरी तरह से भर जाता है। यह पानी पूरे भोपालगढ़ काम में लेता है। आपसे निवेदन करती हूं कि इसके रख-रखाव, रिपेयर, रिनोवेशन, सौन्दर्यीकरण एवं एनिकट, जीर्णाद्धार आप कृपया करवाये, ताकि लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा सके।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं उपखण्ड बावड़ी, ग्राम पंचायत आसोप में भी तालाबों के रख-रखाव, रिपेयर, रिनोवेशन, सौन्दर्यीकरण, एनिकट और जीर्णाद्धार निर्माण कार्य करने की मांग करती हूं।

पिछली गर्मी में भी भोपालगढ़ में बहुत पानी की समस्या रही, टैंकर लगवाये गये, लेकिन वे टैंकर गांवों में गये, ढाणियों में नहीं गये, ढाणियों के लोग..

श्री सभापतिः प्लीज समाप्त कीजिये, अंकित नहीं होगा। श्री सुभाष जी मील।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): 000

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।

आज पूरे दिन इसके ऊपर पक्ष और विपक्ष के साथियों ने काफी चर्चा की है, काफी विचार व्यक्त किये हैं और काफी सकारात्मक सुझाव भी इस बीच में आए हैं।

मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का, जिनके प्रयासों से जल जीवन मिशन का समय बढ़ाकर 2028 तक देश के माननीय प्रधान मंत्री मोदी ने किया है। इस सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता की तरफ से हम उनका कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं।

यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, अव्यवस्थाएं हुईं तो हुईं, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर यह समय नहीं बढ़ता तो निश्चित रूप से इसमें सुधार नहीं होता और जो लक्ष्य माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने, हर घर में नल लगाने का, पानी देने का

लिया था, शायद वह लक्ष्य पूरा नहीं होता।

मानानीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पिछले साल में 1 हजार 301 करोड़ रुपये के कार्यादेश और 41 हजार 621 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किये और इस साल में 20 लाख घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य हमारी सरकार ने तय किया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की सुविधाओं के लिए 425 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है।

अमृत-2.0 योजना के तहत 183 शहरों के लिए 5 हजार 123 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया। मैं मेरी तरफ से भी खण्डेला विधान सभा क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे रींगस और खण्डेला नगर पालिका के लिए अमृत-2 योजना में 15 करोड़ रुपये के टेंडर जारी कर दिये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो भूमिगत जल है, वह काफी हद तक समाप्त हो चुका है, ज्यादातर ट्यूबवैल खाली भी जाते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि लगभग 22 करोड़ रुपये के पेयजल के विभिन्न कार्यों के लिए बजट स्वीकृत करने की कृपा करें।

जो सोलर ट्यूबवैल हैं, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में लगभग कम से कम 20 सोलर ट्यूबवैल अगर हम देंगे तो निश्चित रूप लोगों को काफी राहत मिलेगी। मैं अभी चर्चा में सुन रहा था।

माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के एक माननीय सदस्य कह रहे थे, आजादी को 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन क्या किया।

Bhs/Rtm/05.03.25/20.30/4k

राजस्थान में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये तो इसके लिये भी हम दोषी हैं क्या, माननीय जूली साहब? हमें तो बहुत कम समय मिला है, हमें तो बहुत कम समय मिला है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के, इतना बड़ा प्रदेश है विषम परिस्थितियां पानी के लिये हैं हम सब लोग जानते हैं, पूरी जनता भी जानती है विपक्ष के साथी भी जानते हैं, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है यह बात हम सब लोग दिल से स्वीकार करते हैं। विपक्ष के साथी भी मानते हैं और मैं एक छोटी सी बात एक मिनट की कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, एक बार जंगल में आग लग गयी। जब जंगल में आग लगी तो पूरे प्राणी वन्यजीव थे वो चिंतित हो गये। वो एक जगह इकट्ठे हो गये कि क्या किया जाये तो कई लोग जो पुराने थे, जिनकी उम्र ज्यादा थी वो कह रहे थे कि नहीं साहब, यह आग तो नहीं बुझने वाली है, क्या करें तो किसी ने कहा है चलो जंगल को छोड़ कर चल चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं उनमें एक नन्हीं चिड़िया भी थी, जिसको उड़ते हुए बहुत कम समय हुआ था। उसने कहा कि आप लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं प्रयास करूंगी मैं इस आग को बुझाने का प्रयास करूंगी और पास में

जो तालाब है मेरी जो बन पड़ेगी, मैं मेरी चोंच में जितना भी पानी आयेगा उसको बुझाने का प्रयास करूंगी। उन्होंने सब ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो उन्होंने कहा कि आप चाहे बातें करते रहो, लेकिन मुझे अपने काम पर लगना है। यह कह कर जब वो चिड़िया उड़ने लगी तो उन लोगों ने कहा कि अरे तू यह कोशिश मत कर, यह असंभव काम है तो चिड़िया ने जवाब दिया, साथियों, विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, चिड़िया ने जवाब दिया कि जिसकी नीयत अच्छी होती है, ईश्वर भी उसके साथ होता है और ये कह कर कि जब जंगल की आग का इतिहास लिखा जायेगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आयेगा। यह कह कर चिड़िया तालाब से चोंच में पानी भर-भर कर उस आग पर डालने का काम करती है और दोस्तों देखिये थोड़ी देर बाद में आकाश में बादल छाते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है, जंगल की आग बुझ जाती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से इस पानी के अभाव से जूझ रहे प्रदेश के लिये जो इतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करने का काम किया है निश्चित रूप से ईश्वर उनके साथ में है। अगर छोटी-मोटी कोई दिक्कतें भी आ रही हैं, किसी दूसरे प्रदेशों के साथ में थोड़ी बहुत कठिनाई भी आ रही है तो निश्चित रूप से शीघ्र वो कठिनाइयां दूर होंगी और प्रदेश के अंदर इस सूखे प्रदेश में जब पानी लाने का इतिहास लिखा जायेगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा, मैं यह विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा।

साथियों, साथ में एक बात और कहना चाहता हूं। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने देखा है, बजट में चर्चा हुई, अभी अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। माननीय विपक्ष के जो बड़े-बड़े नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेन्स में कहते हैं कि हम सरकार की झाम बांध देंगे वो नजर नहीं आ रहे हैं, खुद की गांठ बंध गयी है और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि आज सरकार पर तथ्यों सहित आरोप लगाने के लिये विपक्ष के पास कुछ भी नहीं, इसलिये यह सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, मैं यह कहना चाहता हूं।

मैं इस माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अगर हम सब लोग मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे, माननीय मंत्री महोदय, मेरा एक सुझाव है कि जितने भी विभिन्न विधान सभाओं में या पूरे क्षेत्र में जो तालाब हैं, जो बांध हैं उनका जो बहाव क्षेत्र है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें ज्यादातर जगहों पर अतिक्रमण हो गये। बांधों में आज एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, उनके पूरे बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाये जिससे बांधों में पानी आये और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा पूरी सरकार को एक लक्ष्य बनाकर कि हमें सालाना एक मीटर, दो मीटर जलस्तर बढ़ाना है, ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक शायद पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गर्मी का समय आ रहा है, हालांकि हमने 142 करोड़ रुपये का प्रोविजन बजट में कन्टिन्जेन्सी प्लान के लिये किया है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में जो चालू ट्यूबवेल्स हैं उनके लिये मोटरों की, पाइपों की, उनकी भी एक बड़े स्तर पर खरीद

करके उनको उपलब्ध कराया जाये। मैं यही कहना चाहता हूं और माननीय सभापति महोदय, अंत में केवल मैं यही कहूंगा कि पानी के स्तर पर हमारे प्रदेश की विषम परिस्थितियां हैं उनके ऊपर सरकार बहुत गंभीरता से कदम उठा रही है यह भी सही है कि अभी एक-सवा साल का कार्यकाल हुआ है और इतनी विषम परिस्थितियों को इतने कम समय में काबू नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री सुभाष मील (खंडेला): हमारे प्रयास सराहनीय हैं इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री चेतन जी पटेल।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को आज जल पर बोलने का समय दिया, जिसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि जल की इतनी बड़ी समस्या है, जिस हिसाब से जो जितनी बड़ी समस्या है, उस हिसाब से सरकार में काम बहुत धीरे हो रहा है और भारत सरकार ने भी जिस तरीके से जल जीवन मिशन में अब पूरे होने का समय जो है 2028 तक बढ़ा दिया इससे ये सब समझ में आता है कि न केवल राजस्थान प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में काम बहुत धीरे चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वर्ष 2024-25 में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिये 70,000 करोड़ रुपये का बजट रखा पर उसमें केवल प्रदेश की सरकार एक तिहाई बजट ही केवल खर्च कर पायी 22,000 करोड़ के आसपास। यह कहते हुए बहुत दु:ख होता है जब हम जनसंपर्क में लोगों के बीच में जाते हैं, अपने विधान सभा क्षेत्र के अंदर तो बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जिनमें श्मशान घाट तक भी नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है फोरेस्ट की जगह है, चरागाह की भूमि है पर वो आवंटित नहीं हो पा रहे हैं। वहां पर पानी की भी व्यवस्था नहीं है तो गांव वाले जब ऐसा बोलते हैं, मुझे शर्मसार महसूस हो रहा है। गांव वाले यह कहते हैं कि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हम जब तक जिंदा हैं, तब तक तो हमारी किस्मत में पानी भी नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड का पानी है और जब हम मर जायेंगे, हम श्मशान घाट में जायेंगे तो हमारी किस्मत में श्मशान घाट भी नहीं है। यह कहते हुए मेरे को बड़ी शर्म महसूस हो रही है तो कम से कम जो इंसान का हक है, अधिकार है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और ये केवल पक्ष और विपक्ष पर आरोप लगाने वाला मुद्दा नहीं है। हम भी सरकार के ही पार्ट हैं कांग्रेस में जरूर हैं, बीजेपी में नहीं हैं, बीजेपी की पार्टी की सरकार है, पर हम सरकार का पार्ट है। दायित्व हमारा बनता है, जिम्मा हमारा बनता है, जवाबदेही हमारी बनती है तो इस मुददे पर मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मौत दुर्घटना के कारण हो भगवान न करे अटैक, कैंसर कुछ भी हो पर अगर पानी की वजह से किडनी फेल हो रही है, कैन्सर हो रहा है, इसकी वजह से

कुछ भी अगर किसी भी प्रकार की हानि हो रही है तो उसकी जवाबदेही हमारी बनती है और मैं समझता हूं हत्या से कम अपराध यह, सिस्टम में चाहे आप हों, हम हों, इसकी जवाबदेही हमारी बनती है हम भी सरकार का पार्ट है। मैं इतना सा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पानी की उपलब्धता हर जगह नहीं है इसलिये दूर से पाइप लाइनों के जरिये पानी लाना होगा जिससे लागत बढ़ेगी। अब मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कुछ गांव ऐसे हैं गांव तो बहुत सारे हैं जहां पानी की समस्या है पर कैसे न कैसे करके वहां पानी की व्यवस्था हो रही है।

कुछ गांव ऐसे हैं जिनके लिये मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी का पी.एच.ई.डी. मंत्री जी का, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं पूर्व में भी उनसे मिल चुका। चार गांव ऐसे हैं जो दूर-दूर तक जिनमें कब पानी पहुंचेगा कोई पता नहीं है चारों तरफ फोरेस्ट है, टंकी का पानी भी भगवान जाने कब पहुंचेगा। ये गांव है, मैं एक बार बता देता हूं ...(व्यवधान)... ये गांव है ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा में ग्राम रूंडिया, ग्राम पंचायत अयाणी का ग्राम श्रीपुरा, ग्राम जोरावर, ग्राम पंचायत जोरावरपुरा का ग्राम वीरोदा और ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, ये चार गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है। और तो और मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि अगर आप इसके लिये बजट नहीं दे सकते फ्लोराइड की बहुत ज्यादा समस्या है तो 70% अगर आप अपने कोष से देते हैं तो हम भी 30% अपने विधायक कोष से इस योजना के लिये मैं अपना खर्च मतलब अपनी ओर से विधायक कोष की ओर से भी लगाने को तैयार हूं पर इन चार गांवों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी पहुंचाना अति आवश्यक है, जिसके लिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। क्योंकि इन लोगों को बचाना हमारा परम कर्तव्य है और अभी ऐसी स्थिति है कि नाम करने के लिये और संख्या बढ़ाने के लिये तो नल लगा दिये और उनमें कोई पानी नहीं आ रहा। गांव में केवल एक शो-पीस बनकर वो नल रह गये हैं। ऐसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत जटवाड़ा है, दो टंकी बनी हुई है ऊपर वाली टंकी में आज दिन तक पानी नहीं पहुंच पाया। बीच में पंक्चर हो जाती है। बहुत ज्यादा पूरे अठारहवां क्षेत्र उधर कहलाया जाता है जिसके सभी गांवों की यही समस्या है।

Kas/rtm/05.03.2025/20.40/4l

माननीय सभापति महोदय, इर्रिगेशन मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ईआरसीपी योजना का नाम आपने भगवान राम के नाम पर रख दिया, बहुत अच्छी बात है। आपको इस योजना के सत्य से अवगत कराना मेरा धर्म है। आपने कहा कि 90 परसेंट फंडिंग भारत सरकार करेगी। हमने पूरा बजट देख लिया, ईआरसीपी के लिये किसी प्रकार के फंड की कोई बात नहीं है। जिस नवनेरा डैम की आप बात कर रहे हो, वो मेरे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में है। बजट में आप बात करते हो कि हमारी सरकार बनी है, वह पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान वह डैम बना, पर जो सत्य आपको पता होना

चाहिये, वो सत्य यह है कि मुख्य मंत्री जी तो केवल उसका निरीक्षण करने आये थे कि कांग्रेस पार्टी के समय जो डैम बना, वो कैसा दिखता है। जब मुख्य मंत्री जी वहां पर पधारे तो उनके साथ आप भी पधारे, मैं खुद आपका स्वागत करने के लिये वहां अपने क्षत्र की जनता के साथ आया। लोकतंत्र में राजा नहीं होता, पर हमने जो आपका स्वागत किया, वो राजा से कम भी नहीं किया। जिस जगह आपका हैलीकॉप्टर लैंड हुआ, पूरी जनता वहां पर मौजूद थी, मैं भी था। वहां पर यह हो रहा है कि जिस जगह पर वो डैम बना, अच्छी बात है कि वहां से लाखों लोगों को पानी जायेगा, पर वहां पर 70 हैक्टेयर भूमि पर आप पम्प हाउस बनाने जा रहे हो, जिसमें 700-800 बीघा के आस-पास लोगों की जमीनें जा रही हैं, उन लोगों का कमाने का जरिया ही केवल किसानी है, खेती है, आप लोग वो ही उनसे छीन लोगे, जिस जगह से आप लाखों लोगों को पानी पहुंचा रहे हो और उस जगह के किसानों को आप वहां से भगा दोगे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। आप कोशिश यह करें कि सरकारी भूमि या वन विभाग की भूमि इसमें अधिग्रहित करें, ताकि किसानों को थोड़ा सा संरक्षण मिल सके। इसी तरीके से आप वहां पर नहरों के लिये फीडर बना रहे हो, जिसमें 100 मीटर चौड़ी नहर बनने जा रही है, जिससे पानी सप्लाई होगा। वहां पर भी किसानों की पूरी की पूरी जमीनें जा रही हैं। इसके लिये भी मैं आपसे निवेदन करता हूं किसानों का बहुत भारी विरोध था। जब डेम की टेस्टिंग चालू हुई तो उस समय हमने धरना दिया, बारिश हुई, लेकिन हम धरने से हटे नहीं, तब जाकर प्रशासन झुका और जब इस डैम की टेस्टिंग हुई तो प्रशासन ने माना कि इस डैम की टेस्टिंग में डैम की वजह से कोई एक भी घर डूब में नहीं आ रहा। हमने भी माना, पर मकानों के किनारों पर पानी आ गया, उनकी नींव कमजोर होगी, मकान गिरने की बहुत ज्यादा आशंका होगी।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसके लिये भी कुछ करें। उन मकानों को डूब में लें, क्योंकि उनकी नींव कमजोर होगी तो वो मकान गिरने ही हैं, उनको मुआवजा प्रदान करवाये। इसके लिये हमने विभाग पर धरना दिया, तो विभाग ने आपको प्रस्ताव भी भेजे हैं।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त कीजिए।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): दो मिनट। जो मकानों की लिस्ट आपको भेजी है, वह बहुत कम है।

श्री सभापति: श्री लादु लाल पितलिया। अंकित नहीं होगा।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): 000

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 41 व 42 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पोटलाव में गंगापुर शहरी पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन व राथलीयास बाँध पर नवीन पम्प हाउस निर्माण कार्य के लिये साढ़े छह करोड़ रुपये दिये, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री

भजन लाल जी, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और हमारे मंत्री महोदय आदरणीय कन्हैयालाल जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना है कि हर घर नल योजना के तहत घर-घर पानी पहुंचाने का है, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, जिला भीलवाडा राजस्थान में जेजेएम (जल जीवन मिशन योजना) के तहत चम्बल-भीलवाडा पेयजल परियोजना के फेज द्वितीय पैकेज चतुर्थ (गंगापुर क्लस्टर) के सहाडा, रायपुर और भीलवाडा तहसील के 261 गांव और लगभग 435 से अधिक ढाणियों के रेटोफिटिंग कार्य की स्वीकृति 25वीं एसएलएसएससी की बैठक दिनांक 02.07.2021 द्वारा राशि 277.00 करोड़ रुपये के टेंडर तो जारी हो गए। वर्तमान निविदा मे दिनांक 30.09.2024 को वित्तीय बिड खोली जाकर विभागीय समिति की 889वीं बैठक दिनांक 05.09.2024 में अनुमोदन के पश्चात श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अपेक्स कमेटी में अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। अनुमोदन की प्रक्रिया में काफी समय लगने से कार्यादेश में बहुत विलम्ब हो रहा है, जबकि पूरे भीलवाडा जिले के कार्यादेश जारी होकर काम भी शुरू हो गए तथा कई जगह कार्य पूर्ण भी हो गए हैं। श्रीमान जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पानी की बहुत समस्या है, परन्तु अब तक मेरा विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जल जीवन मिशन योजना से वंचित है। अगर समय से जल जीवन मिशन योजना के अनुमोदन होकर कार्यादेश जारी हो जाएं, तो योजना को धरातल पर लाने में समय की बचत होगी तथा जनता की पानी जैसी विकट समस्या का समाधान हो पाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में विधान सभा क्षेत्र सहाडा, जिला भीलवाडा राजस्थान में जे जे एम (जल जीवन मिशन योजना) के तहत चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना के फेज द्वितीय पैकेज चतुर्थ (गंगापुर क्लस्टर) के सहाडा, रायपुर और भीलवाडा तहसील के राशि 277 करोड़ के कार्यादेश शीघ्र जारी करने के आदेश प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा में 1500 हैण्डपम्प और 1000 ट्यूबवैल की घोषणा हुई, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की बहुत तकलीफ है। वहां कम से कम 100 हैंडपम्प और 50 ट्यूबवैल की घोषणा हो जाये तो हमारे मंत्री महोदय कन्हैयालाल जी की बहुत मेहरबानी होगी। वैसे तो कन्हैयालाल जी हमारे बहुत बढ़िया मंत्री महोदय हैं। एक महीने पहले हमारे विधान सभा क्षेत्र में पधारे थे, बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है, इसके लिये माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जनता जल योजना सन 1994 में पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत द्वारा चलाई गई थी। जनता जल योजना के कर्मचारी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 30 वर्षों से जल आपूर्ति करके जनता की प्यास बुझा रहे हैं, परंतु उन सहायक पम्प चालकों की विभिन्न लम्बित मांगों के निराकरण नहीं होने से वो आए दिन हड़ताल पर बैठ जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सप्लाई बाधित होती है तथा गर्मियों के दिनों में तो जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके

माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सहायक पम्प चालकों की लम्बित उक्त मांगो पर विचार करें। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की जनता जल योजना के तहत कार्यरत सहायक पम्प चालकों को विभाग में रिक्त स्थायी पदों पर समायोजित करते हुए इन्हें नियमित किया जावे। जब तक नियमित नहीं किया जाता, तब तक समान काम, समान वेतन लागू करने की घोषणा की जावे। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में 70 हजार पद रिक्त हैं, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, अतः तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की जावे। भर्ती में अनुभव के आधार पर जो पिछले बीस-पच्चीस वर्षों से काम कर रहे हैं, उन कार्मिकों को वरीयता दी जानी चाहिए। पिछली हमारी सरकार ने वर्ष 2016-17 में इन कार्मिकों से भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे। वर्ष 2018 में इनके आवेदनों की छटनी करके पात्र कार्मिकों की सूची भी तैयार कर ली गई थी, परंतु हमारी सरकार बदलने से वो भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पुनः अधूरी पड़ी भर्ती को नया विज्ञापन जारी करवा कर रोजगार उपलब्ध करवाया जावे। जनता जल योजना तहत कार्मिकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सामाजिक सुरक्षा बीमा, चिकित्सा सुविधा एवं पेंशन योजना का लाभ दिये जाने की मैं मांग करता हूँ। जनता जल योजना में कार्यरत कार्मिकों को 26 दिन का मासिक मानदेय मिलता है। पिछले 10 वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन कार्मिकों को पूर्ण वेतन दिये जाने की मैं मांग करता हूँ। जनता जल योजना में कार्यरत कार्मिकों को किसी कारणवश सीधा नियमित नहीं किया जाता है, तो संविदा नियम, 2022 में शामिल करवाने की मैं मांग करता हूँ।

Msk/rtm/05.03.25/2050/4m

जनता जल योजना में कार्यरत पम्प चालकों का पदनाम दिनांक 27.03.2023 को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक एमआर 727/एसीएस/पीएचईडी व जीडब्ल्यूडी/21 के द्वारा दिनांक 05.04.2023 को संयुक्त शासन सचिव प्रथम द्वारा सहायक पम्प चालक नाम का आदेश अनुमोदित किया गया, लेकिन आज तक न ही इनके पद स्वीकृत हुए और न ही सेवा नियम बनाये गये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सहायक पंप चालकों के आदेश का अनुमोदन करके सेवा नियम बनाने की मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इन सहायक पंप चालकों की वाजिब मांग रखी है, इनका परीक्षण कराकर लाभ दिलावें, ताकि पंप चालक जनता की सेवा पूर्ण ईमानदारी से कर सकें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाडा में फूकिया बांध ग्राम पंचायत नेगडिया खेडा में बनास बेसिन की चन्द्रभागा नदी पर निर्मित है। बांध की कुल भराव क्षमता 352.04 MCFT है। इस बांध से रेलमगरा, सहाडा एवं कुंवारिया तहसील के कुल 15 गांवों की 3,356 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकती है। बांध के अप-स्ट्रीम में हुए डवलपमेंट के कारण विगत 15 वर्षों में

बांध में जल आवक शून्य रही है, जिसके कारण क्षेत्र का भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है।

श्री सभापति: प्लीज अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): एक मिनट साहब, प्लीज एक मिनट। इस बांध को नदी या नहरों से जोड़कर भरा जाये, ताकि जल स्तर बढ़ने पर किसानों को राहत मिल सके। रायथालियास बांध सहाडा विधान सभा क्षेत्र में बनास बेसिन की चन्द्रभागा नदी पर निर्मित है।

श्री अध्यक्ष: श्री जयकृष्ण पटेल।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): एक मिनट। इस बांध की कुल भराव क्षमता 306.50 MCFT है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जय श्रीराम।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 41 और मांग संख्या 42 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जौहार अर्पित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान विधान सभा के इस सदन के अन्दर पानी जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आज चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे नेता हो, चाहे उद्योगपति हो, पानी की सबको आवश्यकता होती है। आज बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आजादी के 78 साल बाद भी राजस्थान हो, चाहे देश के अन्दर, हम आज पानी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज आम इंसान चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, उसके घर तक हम पानी नहीं पहुंचा पाये हैं।

मैं आज राजस्थान विधान सभा के इस सदन के अन्दर बात करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में और बांसवाड़ा जिले के अन्दर जल जीवन मिशन योजना के नाम से सरकार द्वारा जो योजना चलायी जा रही है, उसके अन्दर मैंने राजस्थान विधान सभा के सदन में प्रश्न के माध्यम से सवाल मांगा, उसका जवाब आया है। यहां पर जल जीवन मिशन योजना के नाम से प्रत्येक गांव के अन्दर घर-घर नल पहुंचाने की योजना तो चलायी है, लेकिन वहां पर आज तक घरों में कनेक्शन नहीं हुआ है और न ही नल द्वारा पानी पहुंच पाया है। सरकार द्वारा गांव में जितने स्वीकृत नल होते हैं, उतने कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। जल जीवन मिशन योजना के अन्दर वे सारे के सारे कार्य पूर्ण बताये गये हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जल जीवन मिशन में यह हालत है कि जिस घर में कनेक्शन नहीं दिया गया है और उस घर में नल द्वारा पानी नहीं जा रहा है, लेकिन उस क्षेत्र में बजट का पूर्ण कार्य बताया जा रहा है। इसके अन्दर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां पर जितने अधिकारी/कर्मचारी होते हैं, यहां पर योजना तो बना देते हैं, लेकिन शहर और ग्रामीण के अन्दर जो योजना बनायी जाती है, उन दोनों में परिवर्तन और योजनात्मक तरीके से अंतर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि गांवों का

जो क्षेत्र होता है, उसके अन्दर कुछ और हालात होते हैं और शहर के अन्दर कुछ और हालात होते हैं।

आज हम देखना चाहेंगे कि जल जीवन मिशन योजना चाहे राज्य के अन्दर हो, चाहे मेरे जिले के अन्दर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इस योजना के माध्यम से हम घर-घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल असंभव जैसा लगता है। मैं आपके माध्यम से जल जीवन मिशन योजना में जगदीश प्रसाद अग्रवाल और जो दो-चार एजेंसियां हैं, फर्मों द्वारा जो कार्य किया गया है, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसके द्वारा एक पृथक कमेटी बनाकर पूरे जिले के अन्दर, जल जीवन योजना में जो कार्य किया गया है, उसकी गुणवत्ता की और कार्य के अन्दर पारदर्शिता, पूर्ण देयता और इसके भुगतान सम्बन्धी की आप समस्त जांच करायें। मैं कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, यह हालात पूरे राज्य के अन्दर होंगे। मैं इस अवसर पर पानी और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि ईआरसीपी योजना के माध्यम से राजस्थान के ईस्ट एरिया के अन्दर हम पानी का सपना गरीब और किसान को दिखाते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, चाहे वह इंदिरा गांधी नहर हो, ईआरसीपी योजना हो या माही डैम के माध्यम से उस क्षेत्र के अन्दर पानी दिया जा रहा हो, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमको सबसे पहले तो उस क्षेत्र के अन्दर पानी किस तरह से पहुंचाना चाहिए। यह पानी आम इंसान, गरीब के खेत के अन्दर कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में पहले देखकर इस योजना का निर्माण करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज हम नये-नये बांध और नये प्रोजेक्ट की योजना तो लाते हैं, लेकिन माही डैम की बात करें तो माही डैम में जिस तरह से पानी का जो संचय है, पानी की जो भराव क्षमता है। माही डैम में हम देखते हैं, चाहे कडाणा डैम में हो, आज यहां ओवरफ्लो अन्दर 69.83 टीएमसी की क्षमता से वहां पर फ्लो के माध्यम से पानी का बहाव हो जाता है। कडाणा होते हुए वह पानी गुजरात से सीधा सौराष्ट्र से अरब सागर की खाड़ी के अन्दर जाकर गिरता है।

मैं कहना चाहूंगा कि आज डूंगरपुर के अन्दर पानी नहीं जा रहा है। प्रतापगढ़ के अन्दर पानी नहीं है, घाटोल का जो इलाका है, उसके आसपास के क्षेत्र के अन्दर पानी की समस्या हो रही है। साथ-साथ माही डैम में जिन-जिन लोगों का विस्थापन हुआ, बांसवाड़ा में छोटी सरवन का जो इलाका है, उस इलाके अन्दर भी हम देखते हैं तो समीप के इलाके में एक-दो किलोमीटर के रेडियस के अन्दर वहां की जनता पानी के लिए तरस रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कहना चाहूंगा चाहूंगा कि इतने ओवरफ्लो से अगर गुजरात तक पानी जा सकता है तो बांसवाड़ा के अन्दर, प्रतापगढ़, घाटोल और मेरे विधान सभा क्षेत्र तक प्रत्येक किसान के खेत के अन्दर पानी दिया जा सकता है। ऐसी योजना बनायें। योजना के माध्यम से पानी

दिया जाना चाहिए। साथ में, यह कहना चाहूंगा कि माही डेम से जो लोग विस्थापित हुए थे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय एक मिनट कहना चाहूंगा। जो लोग विस्थापित हुए थे, उसके अन्दर सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध की तर्ज पर एक निर्णय दिया, वह यह निर्णय दिया गया कि 40 गुना हर्जाना दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि माही-कडाणा में जो लोग विस्थापित हुए थे, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको हर्जाना राशि मिलनी चाहिए। साथ, अपर हाइलेवल कैनाल की जांच की जाए कि वहां वास्तव में क्षेत्र के अन्दर जिन लोगों को आज विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): माननीय एक मिनट। क्या वहां पर किसान द्वारा सहमति ली गयी? नहीं ली गयी। साथ-साथ अगर वहां पर गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है तो उसके बारे में किसान..

श्री सभापतिः श्री मांगेलाल जी मीणा। अंकित नहीं होगा।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): 000

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 और 4, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल संसाधन पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सिंचाई एवं पेयजल समस्या राजस्थान में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अपन सब जानते हैं, जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। इसके लिए सार्थक प्रयास करने चाहिए। केवल ढोल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। बजट के बिन्दु संख्या 101 में ईआरसीपी का नाम 2004 में रखा था, भाजपा सरकार ने ही रखा था। ईआरसीपी का 2004 से 2023 तक यही नाम चलता रहा और 2024 में ईआरसीपी का नाम बदलकर, संशोधन करके पीकेसी रख दिया। बजट 2025 में रामसेतु लिंक परियोजना के नाम से नामकरण कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नाम का भी आपने सहारा लिया है। आप सच्चाई से काम करें और जनता को सत्यता से अवगत करायें, नहीं तो राम भगवान भी आपसे रुष्ट हो जायेंगे, वे भी नहीं बचायेंगे। अभिभाषण के बिंदु संख्या पर एमपीकेसी लिखा हुआ है। मॉडिफाइड पार्वती कालीसिंध चंबल योजना। कितने नाम बदलेंगे? यह नामकरण करने की शैली आपकी अजीब है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब तक जनता के समझ में आता है, कोई योजना के बारे में, उसका नाम बदलकर जनता को भ्रमित करते हैं, क्योंकि जनता आपसे कहीं सवाल खड़े नहीं करे।

mdp/rtm/05.03.25/21:00/4n

बिंदु में बताया हुआ है कि बजट में 9 हजार 416 करोड़ के वर्क आर्डर जारी कर दिए, 12064 करोड़ के टेंडर कर दिए। 12 हजार 807 करोड़ की सेंक्शन निकाल दी, 24 हजार 287 करोड़ की आपने, इस तरह की व्यवस्था बतायी है। 9 हजार 300 करोड़ की बृहद रूप

से घोषणा की गयी है। अगर इन सबकी क्रियान्विति होती हैं तो 33 हजार 587 करोड़ रुपये हो जाते हैं, फिर तो योजना पूरी होने में सालभर ही लगेगा, परंतु मुझे अचरज है कि केवल नवनेरा बांध को बजट भाषण में नींव का पत्थर बताया है। धन्यवाद देता हूं सरकार को कि नवनेरा बांध, ईसरदा बांध की आधारशिला पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, माननीय गहलोत साहब के द्वारा रखी गयी थी और आपने नींव का पत्थर तो उसको कबूल किया। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

नामकरण करने से काम नहीं चलेगा, जनता काम चाहती है। माननीय प्रधान मंत्री जी से शिलान्यास करवाया, उस समय मंच पर देखा था विडियो के माध्यम से कि मटके से मटके में पानी डालने का काम किया जा रहा है। गांव में महिलाएं कह रही हैं कि घर-घर नल की बात करने वाली सरकार स्वयं मटके लेकर घूम रही है। ये क्या पेयजल उपलब्ध कराएंगे। राम जल सेतु लिंक परियोजना, पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण जीवनदायी योजना है। आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार के वित्तीय संसाधनों से इसको पूर्ण करना संभव नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से, या तो आपके कोर्डिनेशन का अभाव है, इसको राष्ट्रीय परियोजना आज तक घोषित नहीं किया, न ही भारत सरकार के बजट भाषण में इसका कहीं उल्लेख किया गया है। इसके लिए बेस्ट कोर्डिनेशन की आवश्यकता है। जैसे यहां माननीय मंत्रियों में, माननीय मुख्य मंत्री का कोर्डिनेशन नजर नहीं आता कि कौन काम करेगा, ऐसा डबल इंजन की सरकार में नजर आता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ई.आर.सी.पी. में राम जल सेतु योजना में अलवर जिले के समस्त रियासतकालीन बांधों को डी.पी.आर. जुड़वाने का मेरा आग्रह है। इससे भूजल भी रिचार्ज होगा, जिससे सिंचाई एवं पेयजल की समस्या स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। तहसील राजगढ़ के बाघोलाव, दमरेड़, ठेकड़ीन, कोठी नारायणपुर, प्रताप बांध, बीघोता, देवती, सुरेड़, खरखड़ा बड़ला और तहसील रेनी के रेनी, डेरा, डगडगा, जामड़ोली, पिलान, टेकड़ा, पाड़ा और डेदावन, तहसील लक्ष्मणगढ़ के झालटाला, बिच गांव, मोजपुर, गोर पहाड़ी, लक्ष्मणगढ़, कनवाड़ा, लिली, दीवली, हरसाना और अंता पाड़ा, इन बांधों को डी.पी.आर. में जुड़वाने के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है।

(समय बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

माननीय जल संसाधन मंत्री जी, आपसे पुन: एक और निवेदन है कि रूपारेल नदी, जो अलवर से निकल कर भरतपुर जाती है। इस पर घाट पिकअप वियर बना हुआ है और घाट पिकअप वियर की ऊँचाई बढ़ाने की जरूरत है। इसकी फीडर नहरों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, जिससे मौजपुर, गोर पहाड़ी, लक्ष्मणगढ़, लिली, आदि बांधों को भरा जा सके, जिससे लक्ष्मणगढ़ की समस्या हल हो सके।

पेयजल समस्या, जल जीवन योजना के मिशन में बजट बिंदु संख्या 5 योजना में 2028

तक बढ़ाने की बात की है। परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सरकार जनता को देरी के कारणों से अवगत क्यों नहीं कराती? 14-15 माह के इंतजार के बाद भी नेशनल जल जीवन मिशन योजना भारत सरकार से आपको, सरकार को कार्यादेश देने की परमिशन नहीं मिली है। इसलिए उन योजनाओं के कार्यादेश आज तक जारी नहीं किये गये हैं। थोथी बातें कर रहे हैं। तहसील लक्ष्मणगढ़ के खोरला, झालताला, मलावली, गोर पहाड़ी, झोलाखेला पहाड़, गोतड़ा, तिलकपुर, खेड़ा मंगलसिंह, रेनी के आधुका, मालूका, मानपुरा, पाटनबास, बहरोर, राजपुर छोटा, मोरेरकलां, बवेली, लपाला, बाड़ बिलेटा, बाड़ घटवाड़ी, बाड़ मकरोटा, इन योजनाओं के टेंडर तो रिसीव कर लिए और पहले की सैंक्शन हैं, 14-15 महीने में हम इनके वर्क आर्डर देने की परमिशन नहीं ले पाए। यह कोर्डिनेशन है भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का। इसी योजना में 15 साल की गारंटी की बात करते हैं। जब ड्राई जोन है तो 15 साल के लिए सोर्स कैसे अवेलेबल होंगे? सोर्स फाइडिंग कमेटी के लिए प्रपोजल भेजे गये हैं। आज तक उनका कोई डिसिजन नहीं हुआ है। इससे बहुत सारी योजनाओं के टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। 15 साल की क्यों गारंटी ले रहे हैं, जब नहर ही ले आएंगे चार साल में तो इसकी गारंटी की जरूरत नहीं है। पांच साल की गारंटी ले लीजिए। इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। जे.जे.एम. में मिस प्लानिंग है। जब कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी पूर्ण प्लानिंग करनी चाहिए। इसका आज तक यह पता नहीं है कि बिजली का बिल कौन जमा कराएगा? बिजली के बिल जमा कराना, पम्प कौन चलाएगा? पैसे कौन देगा? स्कीम कौन रखेगा? इसके बिजली के बिल के लिए पंचायती राज करेगी, मेन पावर कहां से आयेगी? इस योजना में खामी है, इसको भी सुधारने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए। आप विराजिए। श्री कालूराम।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): बजट घोषणा के बिंदु संख्या 178, वर्ष 2021-22 में अलवर जिले के लिए ईसरदा बांध परियोजना से चार शहरों...।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और मांग संख्या 42- जल संसाधन व इंदिरा गांधी नहर विभाग, यह बहत ही महत्वपूर्ण विषय है। पानी के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार रहीम दास जी ने कहा था-

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे, मोती मानस चून।

इसी प्रकार से सपने देखना आसान है, लेकिन इन्हें साकार करने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। हमारी सरकार परिश्रम से काम कर रही है। माननीय सदस्य अभी बता रहे थे, जल जीवन मिशन, मैं थोड़ा-सा आपको जल जीवन मिशन के बारे में बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन, हमारे केन्द्र की सरकार, सम्माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता को राहत पहुंचाने के लिए शुरू किया था। बाकी आपकी सरकार ने जो

काम किया, इस राजस्थान की जनता को बिलकुल पानी नहीं मिले, इस प्रकार से आपने पूरी योजना को तहस-नहस करके रख दिया। जिस प्रकार से 27 हजार करोड़ रुपया आपकी पिछली सरकार को दिया, उस पैसे का आपने दुरुपयोग किया। वह पैसा राजस्थान जल जीवन मिशन में नहीं लगाया और आपने दूसरे कार्यों में इस पैसे को लगाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में पिछले बजट में भवानी मंडी के आसपास के 14 गांवों को राजगढ़ पेयजल परियोजना से जोड़ने के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय, सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ी योजना हमारे धरातल पर उतारी है। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में हमारी पूर्व मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धरा राजे जी ने जो पेयजल परियोजना थी, गागरेन पेयजल परियोजना, माधवी पेयजल परियोजना, भीमली पेयजल परियोजना, पीपलाद पेयजल परियोजना, रेवा पेयजल परियोजना, इसी प्रकार से सभी पेयजल परियोजनाओं पर लाइनें डालकर एक पीएसपी लगाकर पानी देने का काम शुरू किया था। आपकी सरकार से पिछले पांच साल पहले। पूरी विधान सभा में टंकियां बनायी गयी थीं। लाइनें डाली गयी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में, मोहल्लों में पीएसपी लगाकर पानी दिया जा रहा था। जब जल जीवन मिशन आया तो आपने न तो लाइनें बदली, न उन टंकियों को बनाने का काम किया और डायरेक्ट ही आपने कनेक्शन देने का काम शुरू कर दिया। आपने जो कनेक्शन दिए, वह सिर्फ आंकडों, कागजों में कनेक्शन दिए, बाकी वे कनेक्शन घरों पर चालू नहीं हुए। ये आपकी सरकार का काम था। हमारी सरकार ने, सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस योजना को बढ़ाकर हम 2028 तक लागू करेंगे।

Ans/rtm 21.10 4o 05.03.2025

जहां भी घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुई है उसकी जांच की जाएगी और उसका पाई-पाई का हिसाब आपसे लिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन बहुत ही अच्छी योजना है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 100 किलोमीटर दूर गांगरेन डेम से मेरा कुंडला 110 किलोमीटर दूर है वहां से पाइप लाइन डालकर पानी लाया जाता है, उससे 150 गांवों को पानी देते हैं। जबकि नदी के किनारे हमारा गांव बसा हुआ है, चंबल नदी और छोटी कालीसिंध नदी, शिप्रा नदी में यथा पानी भरा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी गंधार नदी में पानी सूख गया है और चार महीने तक हम टेंकरों से सप्लाई करेंगे। 8-8,9-9 दिन नदियां मेरे क्षेत्र में बहकर जा रही हैं। चंबल नदी में इतना पानी है कि मध्यप्रदेश में दो लाख हैक्टेयर भूमि, मेरे अपनी विधान सभा क्षेत्र से नीचे सिंचाई हो रही है, तो दोनों मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार हमारी विधान सभा में 55 लाख का

बांध के लिए छोटी कालीसिंध और चाचुणी नदी पर डीपीआर स्वीकृत हुई थी, जल्दी से जल्द योजना बनाकर उसका बांध बनाया जाए। छोटी कालीसिंध और चंबल नदी पर एक एनिकट बनाकर लिफ्ट सिंचाई परियोजना चालू की जाए। ताकि उस क्षेत्र में हमें पीने के पानी की भी सुविधा मिलेगी और किसानों को भी इससे सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान की जलदायिनी, हमारी बहुत ही बड़ी योजना थी जो हमारी पूर्व मुख्य मंत्री महोदया ने ईस्ट कैनाल के नाम से शुरू किया था, कांग्रेस सरकार ने पांच साल से इस योजना को अटका कर रखा। यह योजना हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। हमारी मैडम ने इसको धरातल पर उतारा था। हमारे भजनलाल जी ने वापस लाकर इस योजना को जोड़ने का काम किया है। इस बजट में किशननगर माइक्रो सिंचाई परियोजना की आपने सौगात दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

मैं पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को याद करना चाहूंगा। उनकी सोच थी कि नदियों से नदियां जुडे, इस सोच को पूरा करते हुए हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने हमारे क्षेत्र में आहू नदी से चवली नदी को जोड़ने का काम किया था। अभी इस सरकार में 01 करोड़ 20 लाख से आहू नदी से पीपलाद नदी को जोड़ा जाएगा, यह सबसे बड़ा काम हमारी सरकार कर रही है। सबसे पहले नदियों को जोड़ने का काम शुरू होगा तो वह झालावाड़ ज़िले से होगा। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नदी से नदी जोड़ने का काम अभी आपने शुरू किया है, इसके लिए 01 करोड़ 20 लाख रूपये की स्वीकृति आपने जारी कर दी है, इसके माध्यम से नदी से नदी अगर जुड़ जाएगी तो हमारे क्षेत्र पानी की किल्लत है उसको दूर सकते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डीपीआर बनाई है इस पर जल्दी से जल्दी से बांध बनाया जाए। मेरे क्षेत्र के कुछ छोटे-मोटे एनिकट हैं, माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह एनिकट भी बनाये जाए। मोगुंदा गांव, जोगा में एनिकट निर्माण कार्य है, ग्राम सेमली गहलोत में एनिकट निर्माण कार्य है, ग्राम पारापीपली में एनिकट निर्माण कार्य है, ग्राम ताईकाखेडा में एनिकट निर्माण कार्य, कोरली में एनिकट निर्माणकार्य, देवगढ़ में एनिकट जीर्णोद्धार, ग्राम पारापीपली एनिकट जीर्णोद्धार, ग्राम पीपल्याकलां में एनिकट और ग्राम उदयपुर में एनिकट, ग्राम दोपड़ा में एनिकट, निर्माण कार्य पीपल्याकलां, बामन, छपरा माइक्रो सिंचाई परियोजना यह परियोजनाएं हैं। अगर आप छोटे-छोटे एनिकट, छोटी-छोटी परियोजना लागू करेंगे तो क्षेत्र में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह योजना आप जल्दी से जल्दी लागू करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति डग मुख्यालय पर एक जलदाय विभाग का उप खण्ड कार्यालय खोला जाए क्योंकि मेरा उप खण्ड कार्यालय करीब 60 किलोमीटर दूर है, ज़िले से 105 किलोमीटर दूर है, इसलिए उप खण्ड कार्यालय खोजा जाए। जो रिक्त पद हैं वे भी भर जाएं। मैं आशा करता

हूं कि बहुत जल्दी ही हमारी चंबल और छोटी कालीसिंध को जोड़ने का काम आप करेंगे।

श्री सभापति: श्री ललित यादव।

श्री कालूराम (डग): इससे इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सकेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 व 42 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका और मेरी पार्टी के नेता का धन्यवाद करता हूं।

कमी तो होनी ही है पानी की राजस्थान में

ना आपकी आँख में बचा, ना आपके जज़बात में बचा

तो यह हालात राजस्थान में पैदा हो रहे हैं।

सभापति महोदय, आज सत्ता पक्ष और विपक्ष, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर राजस्थान की सवा आठ करोड़ जनता को पानी पिलाने का काम करें। अभी गर्मी का सीजन आने वाला है और प्रदेश में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है कि पानी की बड़ी समस्या है।

सभापति महोदय, ईआरसीपी को लेकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने पहले ईआरसीपी, फिर पीकेसी और अब मर्यादा पुरूषोतम भगवान श्री राम का नाम भी इसमें उपयोग में लेने का काम किया है। कुछ गुंजाइश बच गई हो तो आप और भी नाम रख लो भले ही, लेकिन जनता को पानी पिलाने का काम करो। राजस्थान की आठ करोड़ जनता इस सदन से जवाब मांगती है। केवल सत्ता पक्ष की ही नहीं, पूरे सदन की जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता को हम पानी पिलाने का काम करें, सहूलियत देने का काम करें, इसलिए इस विषय पर भी हम लोग गंभीरता से चर्चा करें।

इसमें मध्य प्रदेश की भी भूमिका है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया कि मध्य प्रदेश की जनता को हम पानी पिला पाएंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाएगी उसके बाद हम आपको पानी दे पाएंगे, लेकिन आप लोग सदन में गुमराह करने का काम कर रहे हो। राजस्थान की आठ करोड़ जनता आपसे हिसाब मांग रही है कि पानी नहीं मिल पा रहा है।

पूर्व प्रधान मंत्री जी का सपना था नदी को नदी से जोड़ने की बात पर चर्चा करूंगा। इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि हम सब लोग इस बात पर चर्चा करें कि नदी को नदी से जोड़े, नहर को नहर से जोड़े। राजस्थान की जनता को पानी मिलेगा, किसान को पानी मिलेगा तो किसान आगे बढ़ेगा। राजस्थान में रोजगार तो नहीं मिल पा रहा लेकिन अगर किसान को पानी मिल जाए तो किसान खेती करके, चार फसल लेकर अपने बेटे-बेटियों को, परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। इस विषय पर हम सबको जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि प्रदेश आगे बढ़ सके, किसान आगे बढ़ सके। किसान की आय दुगुनी करने की बात कर रहे है वह हो सके। मेरे इलाक़े में साबी नदी और सोता नाला है, अगर उसमें पानी आ जाए तो पूरे इलाक़े में पानी की किल्लत दूर हो जाए, हमें यह काम करने की आवश्यकता है।

यमुना जल समझौते पर हमने बात कही। शेखावाटी को पानी पिलाने की बात कर रहे हैं। सन् 1994 में जो समझौता हुआ, उसमें 1190 एमसीएम पानी देने की बात पर समझौता हुआ, लेकिन अभी समझौता हुआ, उसमें 577 एमसीएम पानी देने की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे शेखावाटी की प्यास बुझाने का काम करेंगे। मेरा आपके माध्यम से सदन से, मंत्री महोदय से आग्रह है कि सरकार इस पर मजबूत, ठोस निर्णय करें, जिससे राजस्थान की जनता को हम पानी पिलाने का काम कर सके।

अभी हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री खट्टर साहब राजस्थान आये, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप लोग राजस्थान को पानी देने का काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी उसके बाद हम पानी देंगे। पानी की जरूरत तो कहीं पूरी नहीं हो पा रहीं, इसलिए हम लोग बैठकर, इस पर कोई ना कोई बड़ा समाधान करने की चेष्टा करें। पक्ष विपक्ष को और विपक्ष पक्ष को कोसने को बजाय, राजस्थान की जनता के लिए हम लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए सोचने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में 90 परसेंट ईआरसीपी की योजना का पैसा केन्द्र सरकार से आयेगा, लेकिन बजट में मुख्य मंत्री महोदय अपनी कलम व कागज लेकर बैठे रहे, उन्होंने पूरा बजट देखा व सुना, लेकिन एक 'क' भी नहीं लिख पाये, क्योंकि बजट में देश के प्रधान मंत्री ने राजस्थान के लिए कुछ चर्चा नहीं की। पूर्व में मेरे साथी भी कह रहे थे कि कोई कॉर्डिनेशन की कमी है या फिर राजस्थान को उन्होंने छोड़ दिया कि राजस्थान अपने हाल पर रहे। मैं समझता हूं कि आपकी कथनी और करनी में जिस प्रकार फर्क आ रहा है, राजस्थान का भला नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की 15 गांवों की योजना साबी नदी, सोडावास से पानी पिलाने की बात की थी..

VPS-RTM-05.03.2025-21.20-4p

लेकिन कुछ कारणों से उस योजना को बंद कर दिया। मैं पुनः आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि उस योजना को चालू करके, उस डार्क जोन के 15 गांवों को पानी पिलाने का हम लोग काम करें। गर्मी का समय आने वाला है, वहां पर हाहाकार मचेगा, उनको राहत मिल सके, इस पर हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि इस योजना को चालू करवाने का काम किया जाये। नगरपालिका, मुण्डावर क्षेत्र में हमने जे.जे.एम. की योजना, ग्रामीण योजना बनाई थी, लेकिन नगरपालिका होने के बाद में वहां शहरी योजना की जरूरत थी। बजट में कुछ घोषणा तो की है लेकिन उसको जल्द अगर हम चालू करेंगे तो

वहां पानी मिलने का काम हो सकता है अदरवाइज गर्मी के मौसम में बड़ी समस्या आने वाली है। मुण्डावर नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर मुण्डावर बंजारा बस्ती, श्योपुर, तिनकीरूड़ी, गढ़ी, गांधीनगर, मोहम्मदपुर इन सब गांवों को भी पानी उपलब्ध करवाने की हमें आवश्यकता है। नगरपालिका, नीमराना क्षेत्र के अन्दर प्रतापसिंहपुरा गांव में पाइप लाइन खराब होने के चक्कर में गंदा पानी पीने का काम लोगों को हो रहा है। बीमारियां फैल रही हैं। मेरा अनुरोध है मंत्री महोदय से कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शिवपुरी, माधोसिंहपुरा, दौलतसिंहपुरा में नये ट्यूबवैल करने की अभी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, नांगलरानिया, सियाखोह, ऊलाहेड़ी, बृसंगवास गांवों को जे.जे.एम. योजना से नहीं जोड़ा गया तो अभी जो शहरी योजना बनाई है, उसमें इनको जोड़ने का काम किया जाये। जे.जे.एम. के माध्यम से जो योजना आई थी, उसमें ये सड़कें खराब हो गयीं और मैंने यह क्वेश्चन भी पूछा था, लेकिन गलत जवाब दिया है कि सड़कें बिलकुल जैसी थीं, वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। एक भी सड़क को ठीक करने का काम नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, नीमराना क्षेत्र के जे.जे.एम. में कुछ काम बंद पड़े हैं। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो गया, लेकिन जनता की गलती क्या है? सरकार रिस्क एंड कोस्ट के ऊपर दुबारा टेंडर करके जनता को पानी पिलाने का काम करे।

आपने जो हैंडपम्प देने का काम किया है तो हैंडपम्प तो एम.एल.ए. भी दे सकता है लेकिन जो हम बोरिंग की घोषणा कहीं पर कर देते हैं तो उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। न तो पंचायत लेती है और न विभाग लेता है तो इसलिए इसको एक जगह करके उसकी जिम्मेदारी लेने का काम हो सके।

पम्प चालक भी अभी तक नहीं लग पाये हैं उनको भी लगाने का, नियमित करने का काम किया जाये, क्योंकि लम्बे समय से वह प्रक्रियाधीन है और वे पम्प चालक लग नहीं पाये हैं, इसलिए लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ प्रपोजल आये हुए हैं उनको भी आप लोग करवाने का काम करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी। बलवास, प्रतापपुर, चक नम्बर- एक, दो, तीन, बावद, कुल्ला, बटाना, अलीपुर, शहाजहांपुर, सलारपुर, एस.सी. मोहल्ला, जागीवाड़ा, जुड़ाजाकलां एस.सी. मोहल्ला, रजगण, कांकर, कुतीना, रड़वा, सलोरी, मऊ, नगलीओझा, मातोर, बड़ी पेहल, दांतरा शहरी जल योजना मुण्डावर नलकूप, इनको भी आप पूरा करने का काम करोगे तो मैं यह समझता हूं कि हमारे वहां इलाके में पानी की समस्या से राहत मिल पाएगी।

मेरे इलाके में एक बड़ी गांव है, वहां पर बड़ी समस्या थी। मैंने एम.एल.ए. कोटे से पी.एच.ई.डी. को पैसा दे दिया, उसके बाद भी पी.एच.ई.डी. ने बोरिंग नहीं किया। मैंने बीच में यह कहा कि यहां टैंकर लगा दिया जाये, तो कहा कि माननीय मंत्रीजी के यहां से मना कर दिया, टैंकर की व्यवस्था नहीं है। प्यास से कोई मर रहा हो तो अर्जेंट तो कोई व्यवस्था हो सकती होगी? वह काम भी आप लोगों ने नहीं किया। मेरा यह अनुरोध आपसे है कि सरकार इस पर ध्यान दे क्योंकि यह डार्क जोन इलाका है और वहां पर पानी की, एक बूंद भी पानी

जमीन में नहीं है। योजना हमने बनाई है, उसको अभी तक पूरा नहीं किया है तो जिन गांवों में ज्यादा समस्या है उन पर पहले संज्ञान लेकर सरकार काम करने का काम करे।

यह सरकार के सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि हम राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, इधर बैठा विपक्ष भी जिम्मेदार है और केवल सत्ता पक्ष से ही यह सदन नहीं चल सकता, दोनों मिलकर सदन को चला रहे हैं तो इसलिए यह जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग मजबूती के साथ राजस्थान की सवा आठ करोड़ जनता को राहत देने का काम करें।

मेरे इलाके में कुछ छोटी-मोटी घोषणा आपने की है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और जो मैंने सारी चीजें दी हैं, उन सबका भी काम पूरा कर देते तो जनता को राहत मिलने का काम होता, लेकिन जो बड़ी योजनाओं का काम करना था, वह एक भी काम नहीं किया।

पुनः मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं मंत्री महोदय से कि उन सब योजनाओं को पूरा करने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41- पेयजल, मांग संख्या 42- जल संसाधन विभाग की मांग पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में जल, पेयजल के लिए यदि सबसे ज्यादा दंश झेला है तो पश्चिमी राजस्थान ने झेला है और उन्होंने इसकी जो महत्ता है, इसकी पहचान की है तो हम जब छोटे स्टूडेंट थे तब हमें यह पता है कि हम गांव से सिर पर तालाब के अन्दर से घड़ा लेकर, पानी लेकर आते थे और स्नान करने लिए वह खाट बिछाकर, उसके नीचे तगारी लगाकर ऊपर से स्नान करके उस पानी को वापस पशुधन को पिलाने और पेड़-पौधों को पिलाने के लिए काम में लेते थे तो ऐसा दंश पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ ने झेला है। उस समय हमारे तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंहजी के नाम पर महाराज उम्मेदसिंहजी ने तीन बांध बनाये मारवाड़ के अन्दर, जसवंतसागर बांध जो 1899 में बनाया था। जवाई बांध और सरदार समंद बांध, जिसके माध्यम से पूरे मारवाड़ को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा था और वह बांध सारे वर्षा पर ही निर्भर थे तो उनके लिए अब आज की स्थिति पेयजल के लिए यह है जिस पर नूह नारवी ने यह कहा है कि- हम पेयजल का इंतजार करेंगे। हमको इतना ताप नहीं। पिला दो तुम हमें पानी, मंत्री महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): इनका आपके ऊपर ध्यान ही नहीं है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): शैर पर ध्यान नहीं है।

पिला दो तुम हमें पानी। अगर आपके पास जल नहीं है तो हम पेयजल का इंतजार कर रहे हैं। हमको इतनी ताप नहीं, पिला दो तुम हमें पानी। अगर आपके पास जल नहीं है। ...(व्यवधान)... जल है जीवन का अधिकार, पेयजल एक मानव अधिकार, पृथ्वी पर करो

उपकार, पानी को बचाकर बनो महान, आने वाली पीढ़ी पर करो अहसान। ऐसे नारे हमारे कई साथियों ने यहां पर लगाये, अलग-अलग अपनी बात कही है लेकिन मैं अब मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही बात कहूंगा। समय बहुत कम दिया है। हमारी पूर्व की अभूतपूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे ने हमारे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से जोधपुर में जो पानी आ रहा है उसमें माणिक्यलाल दांतीवाड़ा योजना उन्होंने 2008 में स्वीकृत की थी 308 करोड़ की और 119 गांवों और दो नगरपालिकाओं को पानी देने की थी। उस योजना में गत सरकार ने सुरपुरा बांध को सप्लाई दे दी और उसमें से जो जोधपुर का बाहरी क्षेत्र था, उसमें सप्लाई दे दी और उसके साथ ही साथ गत सरकार ने क्योंकि वह पूर्व मुख्य मंत्रीजी का एरिया लग रहा था और उसके बाद हमारे दांतीवाड़ा में जो माणिक्यलाल से सप्लाई हो रही है जिसकी डिजाइन है 2025 तक की, 64 एम.एल.डी. पानी देने की, मंत्री महोदय, आज वहां पर 24 और 28 एम.एल.डी. पानी ही मिल रहा है और उसके बाद भी वहां दांतीवाड़ा से शोधित करने के लिए, तत्कालीन जो सी.एस. थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां भी नौ गांवों के लिए पानी की सप्लाई दे दी, उसमें हमारी जो कटौती की गयी है, 64 एम.एल.डी. की जगह कम से कम हमें 35 और 40 एम.एल.डी. पानी तो दें।

इसके साथ ही साथ, हमारे जल जीवन मिशन पर मैं बात करूंगा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अबकी बार वापस प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से जल जीवन मिशन को जो आपने गत सरकार ने उसका भट्ठा बैठा दिया था उस योजना के, उसमें योजना में वास्तविकता यह थी कि उस योजना के माध्यम से, दिशा निर्देश के अनुसार अपने को ग्राम जल सेवा सर्तकता समिति का निर्माण करना था और उसके माध्यम से वहां की समिति पैसे इकट्ठे करती और उसकी देखरेख करती उस योजना की, उसका ओ.एण्ड एम. करती, लेकिन 2023 के अन्दर तत्कालीन मुख्य मंत्री ने बिना कोई बजट प्रावधान लिये, उन्होंने जो गांव से 2750 रुपये प्रत्येक परिवार से या प्रत्येक कनेक्शन से जो कि वहां पर लेना चाह रहे थे, उन्होंने उस पर रोक लगा दी। उससे अब स्थिति यह बन गयी कि जिन लोगों ने पैसा दिया था, वह पैसा वापस मांग रहे हैं आज की तारीख में। वे कहते हैं कि हमने पैसा दिया है और हमें कनेक्शन नहीं मिला है और जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उनको कनेक्शन दे दिया है तो हमारी क्या गलती थी? तो वे आज पैसा वापस मांग रहे हैं और उसके अलावा ये कुछ योजनाएं, जो जे.जे.एम. को आपने न तो कोई ओ.एण्ड एम. का देखा कि इसके ऊपर कौन इसका संचालन करेगा, इसका संधारण कौन करेगा?

ssy/rtm/05.03.2025/21.30/4q

बिना सोच-समझे इस योजना को ठप कर दिया। आपके पास पहले जो पैसा केन्द्र का अंश आया था, उसकी यूसीसी नहीं देने की वजह से अभी वर्तमान सरकार उससे जूझ रही है कि हम यह पैसा उनको जमा करवाकर कैसे भी वापस करें।

जल जीवन मिशन में मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने

यह राज्य अंश के पैसे का वापस पुनर्भरण कर पूरे राजस्थान में वापस डी सर्वे करवाकर, जो आपने राजनीतिक पक्षपात करके जिन लोगों को कनेक्शन देने थे, उनको नहीं दिया और दूसरे लोगों को देकर आज उस योजना की हालत खराब कर दी है।

मैं इसके साथ मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसी तर्ज पर, 2 मिनट सर, मुख्य मंत्री ग्रामीण जल जीवन मिशन की तरह शहरी योजना की घोषणा की है। इसमें अमृत 2 के तहत, माननीय मंत्री महोदय, मेरी नगर पालिका बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर में 2-2 एसआर और उसकी राइजिंग लाइन, डिस्ट्रीब्युशन लाइन शहर के जो बाहरी भाग हैं, जो अर्बन पोर्शन हैं उसमें तो आपने दे दिया, लेकिन उसके अन्दर दूसरे में नहीं दिया है।

इसके साथ ही माणिकलाव दांतिवाड़ा पेयजल योजना के अंतर्गत देवलिया गांव से जालेली फौजदारां एवं उसके साथ 16 गांवों की डीपीआर बनकर आ गई थी। उसके टेंडर हो गये थे। टेक्निकल बिड खुल गई थी। फाइनेंशियल बिड खुलनी है। कृपया आप उसकी फाइनेंसियल बिड खुलवाकर, उस कार्य के वर्क आउट जारी कर काम चालू करवायें।

इसके अलावा हमारे वहां जो अधिशासी अभियंता कार्यालय है, वह जोधपुर में है। जबकि भोपालगढ़, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर ये उप खंड जोधपुर शहर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उस कार्यालय को उनके कार्यालय के जो क्षेत्राधिकार हैं, वे जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर हैं। कम से कम उसका जो कार्यालय जोधपुर में है, उसको बिलाड़ा में शिफ्ट करवाने की कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पितराम काला।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया इसके लिए आपको और मेरे सदन के नेताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पिलानी के उस क्षेत्र से आता हूं जहां बिट्स जैसी ऐसी संस्थाएं हैं, जहां विदेशों से लड़के पढ़ने के लिए आते हैं। वहां बीपीएस जैसी एक संस्था है, जहां पूरे भारत के लोग पढने के लिए आते हैं। वहां सीरी जैसी संस्था है, सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्युट जहां बहुत अधिक वैज्ञानिकों के उपकरण तैयार किये गये हैं।

पिलानी विधान सभा हरियाणा की सीमा के जरूर टच होता है, लेकिन राजस्थान की 200 विधान सभाओं में आता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जब विधान सभा के अन्दर माननीय राज्यपाल महोदय ने बजट प्रस्तुत किया था तो पिलानी विधान सभा का कहीं कोई जिक्र नहीं आया था। चाहे वह पानी का मुद्दा हो, चाहे जल संसाधन का मुद्दा हो, एक भी रुपया और एक भी कार्य नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, सन 1924 के अन्दर सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। वह पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने उस नगर के अन्दर जब खुदाई की तो यह मालूम पडा कि यह बहुत ही विकसित नगर था। यहां विशाल स्नानागार थे। बड़ी-बड़ी रोड थी, चौड़े-चौड़े बाथरूम थे और हर प्रकार की सुविधाएं थी। लेकिन वह शहर नष्ट हो गया।

वैज्ञानिकों ने सोचा कि किस कारण से नष्ट हुआ, विभिन्न कारण थे, लेकिन उसमें जो मुख्य कारण था वह यह था कि तत्कालीन जो नदी थी, जिस नदी के किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, वह डायवर्ट हो गई। वह खंडहर के रूप में तबदील हो गई। वह सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो गई। आज वही स्थिति मेरे पिलानी की हो रही है। आज जिस प्रकार से पिलानी की उपेक्षा की गई, आने वाले समय में जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई, पिलानी की सभ्यता नष्ट हो जायेगी।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पिछला जो संडे था, मैं घर गया था। पीपली के श्रवण कुमार जी शर्मा मेरे पास आये, आंखों में आंसू थे, दिल उनका भरा हुआ था। मैंने कहा, पंडित जी, क्या बात हुई? उन्होंने कहा, खेत का पानी का कनेक्शन कटवाकर आया हूं। मैंने कहा, बात क्या हुई? उन्होंने कहा, मैंने 19 टयूब वेल खुदवा लिये। एक खुदवाया, यह हुआ कि पानी आ जायेगा, उसमें नहीं आया। दूसरे में नहीं आया। तीसरे में नहीं आया और लास्ट में 19 कनेक्शन करवाकर ट्यूब वेल खुदवाकर यह हालत हो गई कि सारी जमीन बेच दूंगा तो भी मेरा यह पैसा नहीं उतरेगा। आज बिजली विभाग में जाकर ट्युब वेल का कनेक्शन कटवाकर आया हूं। यह स्थिति केवल श्रवण जी शर्मा की नहीं है। यही पितराम काला की स्थिति है और यही दूसरे मेरे हर नागरिक की स्थिति है। वहां पानी की इतनी भयंकर किल्लत है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती।

माननीय सभापति महोदय, जब पिछला बजट पारित हुआ था, उसके अन्दर इसी सदन के अन्दर, इसी मांग के ऊपर माननीय मंत्री महोदय ने यहां यह घोषणा की थी कि आपके जितने ड्राई ट्यूब वेल हैं वे सारे मैं सैंक्शन कर दूंगा। अमृत 2 योजना के अन्दर, पिलानी के अन्दर 10 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दूंगा। 8 करोड़ रुपये चिड़ावा के लिए अमृत 2 की योजना के लिए सैंक्शन कर दूंगा और मार्च, 2027 तक पूरी पिलानी के लिए मैं पानी की व्यवस्था कर दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया। लेकिन 12 महीने व्यतीत होने के बाद में भी उसके अन्दर कोई काम नहीं हुआ। बड़ा खेद है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हर घर के अन्दर हम जल उपलब्ध करवा देंगे। हमारे तो जल तो बहुत दूर की बात है, आप एक महीने के अन्दर एक दिन भी यदि पानी उपलब्ध करवा देंगे तो भी मैं माननीय मंत्री महोदय को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। आज स्थिति इस क़दर पहुंच गई कि चाहे वह मंडेला शहर हो, चाहे चिडावा हो, पिलानी शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र है, केवल पीपली की ही बात नहीं है, यही स्थिति सुजरोला की है, यही दूधवा की है, यही लिखवा की है, यही छापड़ा की है, यही सरदारपुरा की है, यही बेरी की है, यही बनगोठड़ी की है, हर गांव की है। सबके नाम लूंगा तो 125 गांव और 64 ढाणियां हैं, बहुत लंबा समय लग जायेगा। 8 मिनट का, पूरा टाइम उसी के अन्दर हो जायेगा। सबके अन्दर यही स्थिति है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पिलानी विधान सभा को आप राजस्थान की 200 विधान सभाओं के अन्दर ही मानें। यह हरियाणा की सीमा पर जरूर है, लेकिन वहां नहीं है। उसी के

हिसाब से इसके साथ में ट्रीटमेंट करें और इसको अधिक से अधिक आप पानी उपलब्ध करायें।

अभी पिछले दिनों कुंभाराम लिफ्ट योजना थी, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि यह योजना हम सैंक्शन करेंगे। इस बजट के अन्दर कुंभाराम लिफ्ट योजना के लिए एक पैसा नहीं दिया गया। माननीय मंत्री महोदय आप यहां बैठे हैं। सभापति महोदय के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप मांग का जवाब दें तो कृपया इसका खुलासा तो करें कि आप इसके अन्दर दोगे या नहीं दोगे। क्या आपका प्लान है? क्या नहीं है?

ड्राई जो टयूब वेल हैं, उनके अगेंस्ट आपका नये टयूब वेल देने का विचार है या नहीं है? इसी प्रकार से जो टयूब वेल हर गांव और हर ढाणी के अन्दर सूख रहे हैं। आज वहां गहरा करवाते हैं तो मोटर ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है। उसके लिए केबल बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अन्य संसाधनों की आवश्यकता होतीहै। जब इन संसाधनों के लिए वहां के अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं साहब, कंटीनजेंसी के अन्दर आप बता दो, प्रस्ताव करके भिजवा देंगे और वह प्रस्ताव जब स्वीकृत होकर आयेंगे तो आपको उपलब्ध करवा देंगे। जब उन्होंने गत वर्ष के प्रस्ताव ही सैंक्शन नहीं किये तो इस वर्ष के कहां होने हैं?

मैंने पिछली बार भी मेरे भाषण के अन्दर यह कहा था कि आपने जो 5 टयूब वेल दिये थे, वह 5 टयूब वेल भी मेरे तो सैंक्शन नहीं किये। कम से कम वे तो सैंक्शन कर दो। ताकि मैं यह तो कह देता कि यह कार्य तो माननीय मंत्री महोदय ने किया है। लेकिन वह काम भी नहीं हुआ है।

spp/rtm/05.03.2025/21.40/5a

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रीष्मकाल का जो समय आ रहा है, हम सर्दियों में भी बड़े दु:खी हैं और रात दिन यही स्थिति है तो कम से कम गर्मी का जो समय आएगा, जनता के धैर्य की परीक्षा ही होती है, लेकिन जब परीक्षा और धैर्य, दोनों सिर के ऊपर से निकल जाते हैं तो बड़ा आंदोलन जन्म लेता है और जब जनता का बड़ा आंदोलन जन्म लेता है तो उसको रोकने के लिए संसाधन सीमित पड़ जाते हैं और बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं। इस प्रकार के हमारे साथी भी बता रहे थे घड़साना के अंदर हुआ, कितने आदमी मरे। वही स्थिति पिलानी के अंदर होने वाली है। आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि कंटिजेंसी के जो प्लान है वो सैंक्शन करें?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ सारे मंत्री महोदय यहाँ बैठे डीएफटी के अंदर हमने 5 करोड़ जो मिले थे, उसके पानी के प्रस्ताव भिजवाए थे, आज तक वित्त विभाग से नहीं आए हैं। मेरा निवेदन है कि ये भी करें। ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं, नवीन ट्यूब के, ड्राई के

अंगेस्ट के और समर कंटीजेंसी के, ये टेबल करता हूँ। धन्यवाद आपको पहुंचा दूँगा।

श्री सभापति: श्री समाराम जी।

श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इम्पोर्टेन्ट विषय पर जो चर्चाएं हो रही हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में 8 करोड़ की जनता को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बजट दिया था। उस बजट का ये कह रहे हैं कि ये होटलों में मतलब बैठे थे, जबकि वह तो आप ही होटलों में बैठे थो। भगवान भी आपको कम से कम मुँह से कहलवाते हैं कि आप होटलों में एन्जॉय कर रहे थे और ठेकेदार मज़े कर रहे थे। जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में 8 करोड़ जनता का जो पाप लगेगा, आपको पाप तो लग ही चुका है, तब ही उस साइड में बैठे हैं, ये जिस प्रकार से ये जल जीवन मिशन का काम बिल्कुल सब जगह पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है।

मैं, सभापति महोदय, आप के माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे पिंडवाड़ा-आबू विधान सभा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ हैण्डपंपों की आवश्यकता है, क्योंकि हर ढाणी और ग्रामीण एरिये के अंदर पानी पर्याप्त नहीं पहुँच पाता, इसलिए हैण्डपंपों की मैं मांग करता हूँ और जिस प्रकार पूर्व में बत्तीसा बांध बना, उससे भी पिंडवाड़ा और सिरोही जिले में पानी पर्याप्त नहीं हो पायेगा तो मंत्रीजी से यह भी निवेदन है, सभापति महोदय, जो ये फ्लोराइडयुक्त पानी है, यह फ्लोराइड वाला पानी है वो पानी पीते हैं इसलिए बत्तीसा बांध का पानी जो कहीं गांव छूटे हैं तो उनको भी सम्मिलित किया जाए। यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, इर्रिगेशन मंत्री जी भी बैठे हैं, बांधों का काम हमारी पूर्व सरकार में बत्तीसा बांध तैयार हो गया है और अभी वर्तमान में साल गांव बांध का काम बाकी है, वो भी अगर जल्दी, वन विभाग का काम अनापत्ति प्रमाण पत्र एक है, वो मिल जाए और भूमि अवाप्ति का काम बाकी है, बाकी तुरंत प्रभाव से हो जाएगा तो पानी का जल स्तर बढ़ेगा। हमारे विपक्षी सदस्य कह रहे हैं, जल के बारे में चिंता करते हैं। पांच साल कुछ किया नहीं।

एक माननीय सदस्य: आप कर लो।

श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): हम तो कर ही रहे हैं।

यशस्वी पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जलग्रहण योजना चलाई थी, उससे किसानों का कितना भला हुआ था। उससे जलस्तर बहुत बढ़ा था। जल ग्रहण में तो आप लोगों ने पानी के बारे में क्या किया? पानी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। आपने पानी के बारे में अगर सोचा होता तो शायद पाप नहीं लगता आपको। हम पानी पिला देंगे, आपको सबको पिला देंगे, आप चिंता मत करना।

मैं यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी का और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने हमारे स्वरूपगंज भांवरी के अंदर 18 करोड़ 08 लाख की स्वीकृति दी है और पिंडवाड़ा नगर में भी 16 करोड़ का बजट दिया है। मैं बहुत बहुत मंत्री महोदय जी कन्हैयालाल जी का

भी आभार व्यक्त करूँगा और इस प्रकार से उन्होंने बजट दिया है। मैं और अपेक्षा करूँगा और मांग करता हूँ कि हमारे जनजातीय क्षेत्र बाहुल्य है, इसलिए हैण्डपंपों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और छोटे छोटे एनिकेट हैं और पूर्व सरकार में 5 साल तक मैंने बांध के लिए, नहरों के लिए बिल्कुल टूटी फूटी हैं, 5 साल कोई काम हुआ नहीं, रिपेयरिंग के लिए पैसा मांगा था, लेकिन एक पैसा नहीं दिया, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है?

माननीय सभापति महोदय, इनका तो खजाना हमेशा खाली रहता है और मैं तो धन्यवाद देता हूँ यशस्वी मुख्य मंत्री भजनलाल जी का और वित्त मंत्री का, कि कम से कम इनके पास में बजट है। पर्याप्त व्यवस्था के लिए इन्होंने जो भी बजट दिया है और जिस प्रकार से आप तो आपके तो खाली शिला लगी रहती है, बाकी कुछ किया ही नहीं। कम से कम धन्यवाद दो कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है ना तो जनता खुशहाल, किसान खुशहाल, आम व्यक्ति खुशहाल होता है। अंत में बैठे व्यक्ति का मतलब कल्याण करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और कांग्रेस और काल का तो हमेशा जोड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं न, तो पानी, वर्षा भी पर्याप्त होती है, और कांग्रेस और काल, हमेशा कांग्रेस सरकार का जो छाया पड़ती है न तो इंद्र भी नाराज हो जाता है और फिर कहीं पानी नहीं बरसता है। यह है भारतीय जनता पार्टी के चमकते सितारे और भविष्य उज्ज्वल।

माननीय सभापति महोदय, बस आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़ीया।

(समय बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 और 42 के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से जिस विषय के अंतर्गत, मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ मे आदिवासी, गरीब आदिवासी निवास करते हैं। मैं आप के माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर अपर हाई कैनाल का कार्य चल रहा है। मेरे आदिवासी इलाके में गरीब आदिवासी क्षेत्र में अपर हाई कैनाल का काम चल रहा है। इसमें बिना मुआवजा दिये हमारे काश्तकार की जमीन खोदी गई है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं निवेदन करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ए.ईएन. और जे.ईएन. मिलीभगत से हमारे गरीब लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यह महिला माचा की है, इस महिला ने वैशाली मकान बनाया और वो मकान आज तोड़ने की कगार पर आ गया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, डीएलसी की रेट से 10 गुना मेरे आदिवासी क्षेत्र गरीब भाइयों को मिले। इसके बाद में यह जमीन के बदले जमीन उसको दी जाए, तब जाकर इस नहर का काम स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट तो हालांकि उनको डरा-धमकाकर इन्होंने कर दिया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज जो नहर सरकनी-

अंधेश्वर-इटाला होती हुई निकल रही है, उसका पानी, उसकी गहराई 30 मीटर गहराई में नाली जा रही है और 100 मीटर में उसका पानी जायेगा तो मेरे विधान सभा क्षेत्र और जिनकी हमारी जमीन जा रही है, मेरे आदिवासी क्षेत्र गरीब भाइयों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से मेरे नोन-कैचमेंट एरिया है, इस एरिया को वह टोटली टीएसपी क्षेत्र है और इस एरिया में छोटे छोटे बांध बनाकर लिफ्ट द्वारा उनको पानी दिया जाए। यह मैं इस सदन के माध्यम से मांग करती हूँ। जिस तरह से आज पक्ष और विपक्ष की सारी बातें मैंने सुनीं और ये कह रहे थे कि हमारे को 10 ट्यूबवैल दे दिये, 10 हैण्डपम्प दे दिये। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि पिछली बार उन्होंने एक पत्र भेजा था कि जो भी आपके काम हों, उन कामों को डिजायर द्वारा भेजा जाये। मैंने ये भी कहा था कि अगली बार मैं जरूर पूछूंगी।

jyg/rtm/05.03.25/21.50/5b

आपने डिजायर तो जरूर भेजी, लेकिन काम बिलकुल नहीं किया और भेदभाव किया जा रहा है। मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आप भेदभाव कर रहे हो, यह सदन आज सदन के अन्दर आपने जो शपथ ली है, आपने बीजेपी की शपथ नहीं ली, ये 200 विधायक बैठे हैं, उन 200 विधायक की तरफ से और 8 करोड़ जनता की तरफ से आपने शपथ ली है, इस तरह से भेदभाव न करें और मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जरूर मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं का जवाब रिप्लाई में दें कि मेरे लोग गुजरात में पलायन करने जा रहे हैं और बड़े-बड़े हादसे हो रहे हैं। आज रात की दस बजे मैं बैठी हूं, एक वकील के रूप में मेरी जनता ने मुझे भेजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपके माध्यम से यह वकालत मैं कर रही हूं, पर जरूर मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता के लिए आप रिप्लाई में जरूर दें, एक मंत्रीजी नहीं हैं, एक मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि जल जीवन मिशन जो चल रहा है, जो टंकियां बन रही हैं, वो बिलकुल घटिया टंकियां बन रही हैं, गुणवत्ता नहीं है, उसकी जांच की जाये, यह मैं कहना चाहती हूं। बिलकुल पानी नहीं दिया जा रहा है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज ...(व्यवधान)... आप बोलो मत, बार-बार करते हो, यह क्या है? जब देखो तब बोलने का काम करते हो।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य को बोलने दो।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): महिला का अपमान कर रहे हो क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप क्यों खड़े हो गये? ...(व्यवधान)... अपने सदस्य को आप ही डिस्टर्ब कर रहे हो। ...(व्यवधान)... उसके लिए मैं हूं ना।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस तरह से नहीं बोलते हैं, लेकिन आप इधर बोलो न।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह से जल जीवन मिशन

जो लाया जा रहा है और बीजेपी यह कहती है कि हम घर-घर नल से जल पहुंचायेंगे, मेरे घर तक पानी नहीं है, मेरी जनता के घर तक पानी नहीं है। अभी तक उसका कुछ भी नहीं है। आप इसकी जिस तरह से जांच कर रहे हो, अभी जो आप बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूं कि वास्तव में मेरा क्षेत्र बिलकुल सूखा क्षेत्र है। आज टैंकरों से पानी पिलाया जा रहा है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता का और किसान का फोन आया था कि आज टैंकर बिलखुहा में चल रहा है और पानी नहीं मिल रहा है, मैडम, आपको बोलने का अवसर मिले तो जरूर इस मांग को रखना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरह से कहना चाहती हूं कि जिस तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की जनता बिलकुल, इस सदन की तरफ देख रही है, आज टाइम हो गया है, नौ, साढ़े नौ, दस बजने वाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि भेदभाव ना करें और हमारी जनता को न्याय दें, यह मैं कहती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूं, जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री लक्ष्मण राम।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः ऐसा उत्साह यदि सवेरे दिखायी दे भाषणकर्ताओं के लिए तो और अच्छा लगेगा।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): ये तो ढाल बना रहे हैं।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संत-पुरुषों ने कहा है, रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, सभी महापुरुष और संतों ने बताया है पानी के बारे में। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संसदीय कार्य मंत्रीजी आज सुबह से नहीं बोले हैं।

श्री अध्यक्षः अब नहीं बोलेंगे वो। अच्छे आदमी हैं। ...(व्यवधान)... मेरे मित्र हैं।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): देश-प्रदेश में लम्बे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, राज किया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वे आज सुबह से नहीं उठे।

श्री अध्यक्षः उठेंगे तो फिर आपका मार्गदर्शन करेंगे। ...(व्यवधान)... इनकी बातों में मत आना।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): लेकिन प्रकृति से जुड़े पानी पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे आदरणीय मोदीजी ने इस पर ध्यान दिया और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने पानी पर ध्यान दिया। ये बहुत बड़ी चिंता की मोदीजी ने देश की और प्रदेश की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, सभी वक्ताओं ने कहा है कि मारवाड़ क्षेत्र में पानी की बहुत भारी किल्लत हमारे पूर्वजों ने झेली है। आज भी काफी हद तक हम झेल रहे हैं क्योंकि जो पानी नीचे चला गया, खारा हो गया, पीने लायक पानी जमीन में है नहीं,

एक बहुत बड़ी स्कीम हमारे आदरणीय मोदीजी ने जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को दी लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की नीति और नीयत में खोट थी, उस जल जीवन मिशन को जल जीमण मिशन बना दिया और सबके सामने अधिकारी बहुत कुछ शंका के दायरे में जेल भी गये और ऐसी इतनी बड़ी योजना का इन्होंने बंटाढार किया। मैं मेरे नागौर की बात करूंगा तो वहां पर 1100 करोड़ रुपये सरकार ने स्वीकृत किये जल जीवन मिशन में लेकिन नीयत सही नहीं थी पूर्व सरकार की, 300 करोड़ रुपये खर्च कर पाये, सारे पैसे लैप्स हो गये, मैं आदरणीय मोदीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस योजना का टाइम बढ़ाया, 2028 तक किया और पैसे सैंक्शन किये तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि नागौर राजस्थान का भला होगा क्योंकि बहुत बड़ी योजना थी। मारवाड़ क्षेत्र का मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, करीब 70 प्रतिशत जिले नहरी क्षेत्र से जुडे हैं। मेरे नागौर में कोई भी नहर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बरसात के पानी और तालाबों पर निर्भर है। ट्यूबवैल पर निर्भर है, लेकिन ट्यूबवैल में पानी सारा खारा हो गया है तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप जल्दी जल जीवन मिशन के तहत जोड़कर हमें पीने के पानी की समस्या से निजात दिलायें, क्योंकि सिंचाई मंत्री महोदय विराजमान हैं, नागौर की धरती शूरों, वीरों की धरती है, वहां का किसान मजबूत है, जो नागौर और मेड़ता का मूंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, अगर वहां पर सिंचाई का पानी मिले तो निश्चित तौर पर नागौर का वो किसान है जो बहुत कुछ करने को तैयार है, लेकिन पानी की कमी है तो मैं सिंचाई मंत्रीजी विराजमान हैं, आप कहीं से भी नहर की व्यवस्था करें। कम से कम यह निवेदन करूंगा कि ईआरसीपी की योजना अजमेर लेकर आओगे तो मैं निवेदन करूंगा कि पुष्कर होकर आप रियां क्षेत्र में भी लायें तो हमारे किसानों को फायदा मिलेगा। माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं पीएचईडी मंत्री, आप कम से कम ट्यूबवैल नागौर में ज्यादा दीजिये क्योंकि हमारे कोई नहरी क्षेत्र है नहीं, नीचे पानी है नहीं तो जो सबको दिये आपने, हाड़ौती में पानी है, मेवाड़ में पानी है, सब जगह पानी है लेकिन नागौर में पानी है नहीं तो आप ट्यूबवैल आप हमें ज्यादा देने का काम करें, सबको बराबर नहीं क्योंकि हमारा नहरी क्षेत्र है नहीं, इसलिए विशेष निवेदन है कि आप हमारे वहां ट्यूबवैल और हैंडपम्प ज्यादा दें। अन्य को जो दें वो दें लेकिन हमको तो ज्यादा चाहिए। बोलने को बहुत है लेकिन अब टाइम ज्यादा हो गया। इसलिए बोलने को बहुत कुछ ज्यादा है।

सिंचाई मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे मेड़ता क्षेत्र में हम तालाबों पर निर्भर हैं, हमारे बड़े-बड़े तालाब हैं, जब बरसात में भर जायेंगे तो आने वाले एक साल तक उनमें पानी रहता है, तो आप तालाबों पर ध्यान देकर उन तालाबों को डवलप कीजिये, निर्माण कीजिये। ताकि हमारे बांध भी बहुत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करूंगा कि लूणी नदी हमारी जीवन दायिनी है, अभी चली थी, तो मेरा आधा क्षेत्र मालोरिया, अकावा, आदासवास, बड़ायली, रोहिसा, रोहिसी, जड़ावू, झींट्या, जस नगरी सारे गांव जो आसपास थे उनको बड़ा फायदा मिला। आप

लूणी नदी पर भी कुछ पैसे खर्च करके उसको भी डवलप कीजिये जिससे किसानों का भला हो। आज इतना ही बोलूंगा, सरकार ने बहुत कुछ दिया है मेड़ता में और उम्मीद है मंत्रियों से कि और बहुत कुछ दे देंगे। समय को देखते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत। जय मेड़ता।

श्री अध्यक्ष: श्री भगवाना राम सैनी।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): धन्यवाद अध्यक्षजी। मेरे को आपने मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का सबके लास्ट में बोलने का अवसर दिया। ...(व्यवधान)... इस पक्ष से।

माननीय अध्यक्षजी, मैं झुंझुनूं जिले से आता हूं, उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र है और वहां पर पानी की बहुत गम्भीर समस्या है। आप वहां गये इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरे को अच्छा सुकून मिलेगा। झुंझुनूं जिले की पानी की समस्या आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। माननीय हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कुम्भाराम लिफ्ट योजना से मण्डावा में बड़ा कुण्ड बनाया और वहां से फस्ट फेज में झुंझुनूं और खेतड़ी को पानी दिया इसके बाद में उदयपुरवाटी को इससे पहले 8500 करोड़ रुपये स्वीकृत किये, उसमें वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी, टेक्निकल स्वीकृति जारी हो गयी, टेण्डर भी हो गये। आपकी टीम भी गयी थी छह महीने पहले कि चंवरा में एक बड़ा कुण्ड बनेगा। उससे दस गांवों को पानी दिया जायेगा। मणकसास में बड़ा कुण्ड बनेगा, छापोली, मण्डावरा में छापोली में बनेगा, इसके बाद नगर पालिका क्षेत्र में पांच-छह जगह पर कुण्ड बनेंगे। छांवसरी और बड़ा गांव में आपकी टीम छह महीने पहले गयी थी लेकिन अब पता नहीं किस कारण से वो काम रुका हुआ है, केवल वर्क ऑर्डर जारी करना है वो पेंडिंग कैसे है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब तक उदयपुरवाटी हमारा पहाड़ी बेल्ट है और जब तक बाहर का पानी नहीं आयेगा तब तक वहां स्थायी समाधान नहीं हो सकता तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां कब तक पानी आयेगा और इसमें जो वर्क ऑर्डर जारी होगा वो कब तक होगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार जो बजट घोषणा हुई उसमें मात्र 5 ट्यूबवैल और 10 हैंडपम्प दिये गये थे लेकिन मुझे कुछ संतोष इसलिए हुआ कि आपने कहा था कि जो कुएं सूख गये हैं उनको गहरा करवायेंगे और उसके अगेंस्ट दूसरे ट्यूबवैल लगायेंगे।

MLS/RTM/05.03.2025/22:00/5c

मैं खेद के साथ कह रहा हूं कि न तो आज तक वे 5 ट्यूबवैल आये, न 10 हैंडपम्प आये। एक भी ट्यूबवैल गहरा नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य की बात है। बजट घोषणा में नहीं आया। मैं कहना चाह रहा हूं कि आज स्थिति यह है कि मेरे चंवरा में आज पानी का एक

ट्यूबवैल चालू नहीं है। दूसरा, नेओरी में मेरी वही स्थिति है। जोधपुरा में हरिपुरा गांव है, रेवेन्यू विलेज है, वहां एक ट्यूबवैल नहीं है। पापड़ा, वहां पंचायत है, वहां दो ट्यूबवैल हैं। सुरपुरा गांव ऐसा है जहां एक ट्यूबवैल है, उसमें मोटर, पाइप और केबलें बाहर पड़ी हैं। इसी हिसाब से राजीवपुरा रेवेन्यू विलेज है, वहां एक ट्यूबवैल नहीं है। पचलंगी में ढाणियां हैं, मेरे छापोली में बड़ी-बड़ी ढाणियां हैं, उनमें एक ट्यूबवैल नहीं है। यही हमारी नगरपालिका की स्थिति बताऊं आपको। वहां 40 ट्यूबवैल थे, उनमें से आज की तारीख में मात्र 8-10 ट्यूबवैल चालू हैं। बाकी सारे ड्राय हो गये हैं, सूख गये हैं। सात-सात दिनों से आज पानी आ रहा है। गर्मियां तो आगे आएंगी। सात दिन में आज पानी आ रहा है तो आगे क्या स्थिति होगी? इसी प्रकार से मीणा बस्ती इंद्रपुरा और हमारे यहां बासरी एक रेवेन्यू विलेज है, गुड्ढा गोरजी नगरपालिका है, वहां और मीणा बस्ती में, इसी प्रकार से छाऊ और इसी प्रकार केड तो मैं कह रहा हूं कि मेरे गांव के आज की तारीख में ये हालात हैं कि पानी की एक बून्द नहीं मिल रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी ट्यूबवैल बनाये जाएं।

दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा कि सबसे बड़ी गम्भीर समस्या कर्मचारियों की है मेरे यहां। जब आपकी सत्ता आयी थी तब वहां सवा सौ, डेढ़ सौ कर्मचारी थे, आज की तारीख में 35 कर्मचारी हैं और 35 में भी 9 अगले महीने रिटायर होंगे तो 35 गांव, 41 गांव और तीन नगरपालिकाएं। कर्मचारी मात्र 24-25 बचेंगे। यह आप कैसे मैनेज कर पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता। आप उसके लिए ध्यान दें। इसके अलावा अपने जो टीएसएस है, पीएचईडी का एडजॉइन है, वहां टीएसएस के ट्यूबवैल होते हैं, उनको ठीक नहीं किया जाता या उनका बिल नहीं भरा जाता। पिछली गर्मियों में, जब भयंकर गर्मियां थीं, मंडावरा और छाओसरी, वहां बिल के अभाव में कनेक्शन काट दिये गये। मुश्किल से उनके आगे हाथा-जोड़ी करके एक महीना चलाया।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन पंचायतों को आप या तो बजट जारी करें या फिर पीएचईडी को ऑर्डर दें, जिससे कि वे ट्यूबवैल चल सकें। इसके अलावा, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारा जो पहाड़ी बैल्ट है, उसमें यह जो मौसम आता है सर्दियों का, बरसात का तो वहां गायें छोड़ देते हैं, गर्मियां आती हैं तो आदमी तो पानी पी लेता है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उस समय गायें पानी के बिना मरती हैं तो बहुत दुःख होता है। ऐसी स्थिति वहां है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जल्दी से व्यवस्था करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री राजेन्द्र भाम्बू।

श्री राजेन्द्र भाम्बू (झुन्झुनू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन के समक्ष मुझे अनुदान मांग संख्या 41 व 42 अर्थात् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

जल जीवन मिशन ग्रामीण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, जल ही जीवन है, जल

के बिना मानव जीवन की कल्पना असम्भव है। शुद्ध जल प्रकृति की अनमोल देन है और स्वस्थ जीवन का आधार भी। सम्पूर्ण विश्व में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की समस्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है, पानी के बिना कोई भी जीवन असम्भव है, जिसका आशय है, किसी भी जीवित रचना का अस्तित्व जल के बिना सम्भव नहीं है।

शेखावाटी की धरा पर बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों की कमी, कम वर्षा, गिरता भू-जल स्तर, फ्लोराइड, खारेपन और विगत कांग्रेस सरकार ने शुद्ध पेयजल को आम जनता तक पहुंचाने के कार्य को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। राज्य में विगत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आमजन का कल्याण कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। विगत कांग्रेस सरकार की आमजन की मूलभूत आवश्यकताएं यथा- बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उदासीनता व ढुलमुल रवैये के चलते हमारा प्रदेश विकास में अत्यन्त पिछड़ गया। विगत सरकार की गलत नीतियों एवं कुप्रबन्धन के कारण प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के शासन को उखाड़कर डबल इंजन वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर काबिज किया है।

वर्तमान में प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के लिए कृतसंकल्पित है। भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने लाल किले से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। इस मिशन में वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गयी थी, किन्तु राजस्थान में विगत कांग्रेस सरकार ने इस मिशन को घोटाले के अवसर में बदल दिया।

इस बजट में जल जीवन मिशन को मार्च 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। विगत कांग्रेस सरकार के जल जीवन मिशन में घोटाला, गुणवत्ता से सम्बन्धित शिकायतें और क्रियान्वयन में अत्यधिक धीमी गति के कारण प्रदेश का जल जीवन मिशन की कवरेज में सम्पूर्ण देश में 33वां स्थान रहा, जो कि विगत कांग्रेस सरकार की विफलता का परिचय था। मेरे विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में कांग्रेस शासन में शुरू हुए जल जीवन मिशन में बहुत कमजोर प्लानिंग से घटिया स्तर का कार्य किया गया तथा क्रियान्वयन के दौरान टूटी सड़कों की मरम्मत भी नहीं की गयी। अभी तक भी जनता को इस मिशन के तहत पानी नहीं मिला है।

इस योजना के संचालन एवं संधारण की पूर्ववर्ती सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, लिहाजा कुछ पूरी हुई छोटी योजनाएं बन्द पड़ी हैं। नलकूपों के बिजली के बिलों का भुगतान न होने के कारण बिजली कनेक्शन काटे गये हैं। जनता पेयजल से वंचित हो गयी है। हमारी सरकार बनते ही हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा एवं ऊर्जावान एवं कर्मठ जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल जी ने जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान की तथा इन योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ठोस नीति निर्धारण का कार्य करवाना

सराहनीय पहल है। मैं मांग करता हूं कि झुंझुनूं जिले के शेष वंचित क्षेत्र में भी कुम्भाराम नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाये, जिससे पेयजल किल्लत से झुंझुनूं जिले की जनता को राहत मिले।

जल जीवन मिशन शहरी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जल जीवन मिशन का विस्तार करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सभी वैधानिक शहरों में नलों के माध्यम से सभी घरों में स्वच्छ जलापूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। जल जीवन मिशन शहरी एक उल्लेखनीय पहल है, जो पानी की उपलब्धता और प्रबन्धन के नजरिये में एक क्रान्तिकारी बदलाव लायेगी, जो प्रत्येक परिवार के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करेगी। इस पहल का उद्देश्य जल जनित बीमारियों को खत्म करना और घरों को पीने के पानी का स्थायी स्रोत के लिए जल कनेक्शन प्रदान करके जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना है।

अमृत 2.0, प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में शहरी अमृत 2.0 योजना के तहत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति हेतु 5 हजार 123 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये हैं, जिसका उद्देश्य पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्र में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था करना है। अमृत 2.0 की पेयजल स्कीम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कागजों में दबी रह गयी थी, जिसको हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी व ऊर्जावान जलदाय मंत्री जी ने धरातल पर उतारने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए निर्णायक प्रक्रिया तक पहुंचा दिया है।

यमुना जल समझौता, 30 वर्ष पुराना सपना हुआ साकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने यमुना जल को शेखावाटी की धरा पर लाने के लिए एक सपना देखा था। उनका सपना साकार करने के लिए राजस्थान के भागीरथ माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देता हूं। प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि विगत कांग्रेस सरकार ने इस समझौते को लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखायी।

MKD/RTM/05.03.2025/22:10/5d

इतना ही नहीं, हरियाणा विधान सभा के चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में इस समझौते को रद्द करने की बात कही, लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने आगे बढ़कर 14 फरवरी, 2024 को हरियाणा के साथ केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह जी की मौजदूगी में एमओयू किया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री समरजीत सिंह जी।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 और 42 पर आज मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्षः आज के आखरी वक्ता हैं।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): और अन्त में दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन

करना चाहता था कि आज 3 बजे से रात 10 बजे तक इंतजार करते हुए मैंने यह महसूस किया कि हमारी महिलाएं, बहनें जब मटके लेकर कतारों में बैठी रहती हैं, वे क्या महसूस करती होंगी। यह हमारी हकीकत है। यह जिन्दगी की कड़वी सच्चाई है। उसी पर चर्चा करने के लिए हम सब यहां बैठे हैं, इसलिए अफसोस मत करो कि 10 बजे गये, 11 बजे गये। जितनी भी हम जल के बारे में चर्चा करें, अच्छे माहौल में करें, वही हमारे लिए अच्छा है।

श्री अध्यक्ष: अच्छे जो हैं ना, कम समय में गागर में सागर भर देते हैं।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): कर देंगे, साहब। आप निश्चिंत रहिये। मेरी नजर थी आप पर, जब हमारे सचेतक जी कह रहे थे, मैं देखकर ही आपकी भावनाओं को समझ रहा था कि आप जल्दी करना चाहते हैं। मैं इसको कंक्लूड करूंगा और कम समय में करने का प्रयास करूंगा।

राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और साढ़े 10 परसेंट क्षेत्रफल है और आबादी भी साढ़े 5 परसेंट के करीब है। इसमें पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क है, चाहे पीने का पानी हो, चाहे इर्रिशन का पानी हो। इसके लिए आज हम यहां बैठकर कहें कि हमने किया, आपने किया। मैं मानता हूं हरेक ने किया है, यहां तक कि प्रजातंत्र आने से पहले शासकों ने भी इस पर काम किया है। चाहे हम गंगासिंह जी की बात करें, गंगनहर की बात आती है। चाहे हम जोधपुर में, हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, जसवंत सागर की बात और जवाई जैसा बड़ा डैम, महाराजा उम्मेद सिंह जी ने बनाया। इसलिए, किसी एक का ठेका नहीं है। ये पीढ़ियां चलती जाएंगी, आज हम हैं, कल कोई और होगा। हम सबको काम करना पड़ेगा। उसी पर हमारा भविष्य निर्भर करता है।

प्रजातंत्र का जब शासन आया, उस समय भी सब सरकारों ने, शिवचरण जी ने, भैरोंसिंह जी ने, अशोक जी ने, वसुन्धरा जी ने और भजन लाल जी भी करेंगे। अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, सभी को करना भी चाहिए। यही हमारा धर्म है और इसलिए हम चुनकर यहां तक आये हैं।

बातें निकलती हैं और मैंने आज भी बैठे-बैठे अध्यक्ष महोदय यह पढ़ने की कोशिश की कि जालोर जिले में नर्मदा का प्रोजेक्ट किसके कार्यकाल में हुआ। मैंने बैठे-बैठे, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर टाइप किया तो वह भी फेल हो गया। उसने कहा मुझे यह तो पता नहीं है, हुआ जरूर है, यह गुजरात से पानी आया है और राजस्थान में आया है और पानी चल रहा है। इसलिए, आज की स्थिति यह है और हमें देखना पड़ेगा। हमें धन्यवाद देना चाहिए, पूर्व सरकारों को भी। मुझे याद है, मैं 1998 में विधायक चुना गया। उस समय नर्मदा सांचोर का काम चल रहा था। उसके बाद सरकारें बदलीं। 2008 के बाद इसका उद्घाटन हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं, एक दिन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है।

हमें ध्यान देना पड़ेगा, वाटर कंर्जेवेशन की तरफ। हम कितनी भी बातें कर लें। हम यहां पर खड़े होकर सारे विधायक, हम अपने-अपने क्षेत्र की बात करते हैं, हमें टांका चाहिए, हमें

नल चाहिए, हमें पानी चाहिए। पानी होगा ही नहीं तो आयेगा कहां से? उसके लिए हमें अपने पूर्वजों ने जो काम किये, उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बावड़ियां हैं, तालाब हैं, स्थितियां ये हो गई हैं कि उन पर एंक्रोचमेंट हो गया, कैचमेंट एरिये में पानी आने की समस्या है। सरकारों को ध्यान देना चाहिए, उनको सख्ती से खुलवाना चाहिए ताकि वहां पानी भरा जाए।

हम सीख सकते हैं। कनाडा, कनाडा में विश्व का 20 प्रतिशत पानी है पर उसके बावजूद वे लापरवाही नहीं करते हैं। उसको रिसाइकिल करते हैं, उसको रियूज करते हैं। रीयूज करते हैं, उनको आगे की चिन्ता है। हमें इन चीजों को देखना चाहिए। हमें पूर्वजों की बात को समझना पड़ेगा।

छोटूसिंह जी, जैसलमेर से आते हैं। इनकी पीड़ा तो समझ सकते हैं, बेटियां ही नहीं देते थे। यदि बेटी देते थे और अगर वहां शादी करने के बाद वह स्नान करती थी तो कहते थे कि ये जलवाली परी कहां से आ गई। पुष्पेन्द्र सिंह जी के एरिये से जाती थी बच्चियां तो उसको तो रोज नहाने को चाहिए। आज स्थितियां बदली हैं तो हमें पानी के महत्व को समझना चाहिए।

मैं यहां याद करना चाहूंगा हमारे धर्म गुरु शान्तिनाथ जी को। आपके योगी जी भी उनके पांव छूते थे। शान्तिनाथ जी ने जब अन्तिम सांस ली, मैं भावुक हो जाता हूं, जब यह सुनता हूं, जब उनकी डैथ हुई, वे वॉश रूम में गये थे। वे जब बाहर आए कि यह नल से पानी क्यों गिर रहा है, इसको बन्द करो और बाहर आकर उन्होंने अन्तिम सांस ली। हमारी ये भावनाएं होनी चाहिए। ये भावनाएं नहीं होंगी तो हम यहां बैठकर बातें करते रह जाएंगे।

पब्बाराम जी बैठे हैं। मैं विश्नाई समाज के गांवों में जाता हूं। आज भी मुझे खुशी होती है, वे पानी का लौटा भरकर लाते हैं, यह जल बरसात का संग्रह किया हुआ है, टांके से। हम आज बोतलें पीते हैं। आर्टिफिशियल बोतलें, नकली बोतलों का पानी पीते हैं। आप और हम सब समझते हैं। हमें सोचना पड़ेगा, गांवों में आरओ मशीनें लगानी पड़ीं।

मेरा गांव दासवा, जिससे कैयर्न एनर्जी को पानी जाता था। मेरी मदर की डैथ हुई और मुझे पूरा पानी आरओ मशीन से मंगाना पडा। इन स्थितियों में हम पहुंच चुके हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे काम करें, इस चीज के लिए।

राजस्थान की पानी की समस्या को देखते हुए फोरेन नीड्स भी खूब आ रही है। एनजीओज भी काम कर रहे हैं, चुपके-चुपके काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहना चाहूंगा, सरकार को चाहिए कि जो एनजीओ काम कर रहे हैं, उनके साथ जनप्रतिनिधियों को जोड़े, क्योंकि जनप्रतिनिधि दो, ढाई लाख वोटों से जीतकर आता है तो वह ज्यादा उनको गाइड कर सकता है, ज्यादा उन चीजों को सम्भाल सकता है।

चूंकि, अध्यक्ष महोदय का आदेश है, मैं सीधे मांग 41 पर आता हूं। मेरे यहां भीनमाल में ईआर प्रोजेक्ट गहलोत साहब की सरकार में 2013 के बजट में पास हुआ और आज 2025 चल रहा है। आज दो सरकारें बदल गईं। हमें आज तक तो पानी पीने के लिए नहीं मिला।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अभी गर्मियां भी आ रही हैं, वाटर क्लोजर भी आएगा,

वाटर रिजर्वायर तैयार नहीं हुए हैं तो आप कृपया करके उन्हें समय पर तैयार कराये, ताकि 12 साल बाद हम कम से कम उस पानी का स्वाद तो ले सकें। आरओज प्लांट हैं, वे खराब पड़े हैं, उन्हें ठीक करवाये। ट्यूबवैल रिपेयर ठेके पर दे दिये जाते हैं और आम तौर पर ये शिकायतें आती हैं कि ट्यूबवैल की मशीनें बदली नहीं जाती हैं, थोड़े दिन बाद वापस खराब हो जाती है। मेरा निवेदन है कि इस पर भी ध्यान जाए।

एमएलएज को हैंडपम्प दिये गये। इसमें भी ट्यूबवैल आपने दिये हैं, अच्छी बात है। हमारे एरिये में तो हजार-हजार फीट नीचे चले गये हैं, हैंडपम्प काम ही नहीं करेंगे। इस रेशो को भी आप बदलने का प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां बांडी सिणधरा बांध बना है, 2008 से आज तक उससे सिंचाई नहीं हुई। जवाई बांध के बाद सबसे बड़ा डैम है तो कम से कम पीने का पानी ही उससे सप्लाई कर दो तो कम से कम लोगों को फायदा तो मिले।

एक छोटे कांट्रेक्टर जितने भी हैं, आजकल बड़े कांट्रेक्ट दे दिये जाते हैं। मेरी मान्यता है कि अगर छोटे कांट्रेक्टर होंगे, वे टाइम पर, क्योंकि बड़े कांट्रेक्टर भी आखिर छोटे को ही काम देते हैं, सबलैट करते हैं।

मैं मांग संख्या 42 के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माही परियोजना, जो कडाणा डैम के ऊपर है। माही जल एवं खाड़ी समझौता, 1966 में कडाणा डैम का निर्माण हुआ, उसमें 132 गांव राजस्थान के डूब में आए थे। समझौते की शर्त के अनुसार जब गुजरात के खेड़ा जिले में माही की जगह नर्मदा से सिंचित जल कडाणा डैम का एक भाग पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर को दिये जाने का प्रावधान था। आज खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी भी पहुंच गया। सुजलाम, सुफलाम कच्ची नहर भी पहुंच गई, तो कम से कम हमारे उस हक की लड़ाई तो आपको लड़नी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है और गुजरात में आप लोग मेहनत करें तो यह पानी हमें मिल सकता है।

आपके मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा है, सुजलाम, सुफलाम के लिए मुख्य मंत्री जी ने भी पत्र लिखा है जुलाई 2024 में कि यह जो पानी है, सुजलाम सुफलाम जैसी कच्ची नहर साढ़े तीन सौ किलोमीटर बिछाकर गुजरात में, जब कच्ची नहर के मार्फत पानी बिछाया जाएगा तो रिचार्ज भी होगा। पानी नीचे से भी बढ़ेगा, जालोर जिले से तो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। मुख्य मंत्री जी ने खुद ने पत्र में लिखा है कि गुजरात में लगभग 20 किलोमीटर और राजस्थान में लगभग 40 किलोमीटर होगा। इस पानी से साढ़े 12 लाख आबादी को पेयजल का और खेती का लाभ होगा।

आप इन चीजों पर ध्यान दीजिये, मेहनत करिये। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हो गया। आपके मुख्य मंत्री जी तो अभी लैटर लिख रहे हैं। मेरा निवेदन है, इसके अन्दर गहलोत सरकार ने, डब्ल्यूआरसीपी, वैपकॉस से इसका सर्वे भी करवाया है।

Bhs/Rtm/05.03.25/22.20/5e

इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। मेरी यहां बैठे हुए अधिकारियों से...।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): इधर बैठे हुए हैं माही परियोजना के, उधर हाथ मत करो।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): आप सभी को कह रहा हूं मैं तो। एक ही हैं, आप सरकार में सब शामिल नहीं हैं क्या? तो यह वापकोस की रिपोर्ट भी आ गयी मंत्री जी, तो इसके लिये माही की तरफ भी आप ध्यान दीजिये। सुजलाम की बात मैंने आपको कह ही दी। एक बांडी सेंदड़ा की बात जो मैंने अभी कही है आपको। अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहली बार विधायक था, 2003 में इसका शिलान्यास हुआ, 2008 में इसका उद्घाटन भी हो गया और विडम्बना यह है कि आज दिन तक वहां से नहर से पानी नहीं हुआ है, सिंचाई नहीं हुई है। इतने वर्षों बाद, मंत्री जी, इस पर ध्यान दें। नहरें टूटती हैं, रिपेयर होती हैं, जोगेश्वर जी भी जानते हैं, पता कर लें, इस बारे में आज दिन तक नहीं हुआ है और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जिनको पानी देने की स्कीम बनाई गई उनको तो पानी मिल नहीं रहा है और जिस बहाव क्षेत्र के बेरे सूख गये पूरा एरिया ही डैमेज हो गया, तो मेरा तो निवेदन है कि आप उसमें भी नहर का प्रोजेक्ट बनाइये। उनका क्या कसूर है? आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, जोगेश्वर जी भी बैठे हैं, जालोर, आहोर, भीनमाल पूरे जिले की समस्या है, जवाई डैम से भी जो बहाव क्षेत्र का एरिया है, क्या हक नहीं है हमारा उसमें पानी का? पानी रुक गया तो क्या हम भुगतते रहे? हमारे बेरे सूख गये। सुप्रीम कोर्ट तक का डिसिजन है कि 10% पानी उस नदी में छोड़ा जाना चाहिये तो मेरा निवेदन है सरकार से कि इन चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिये और सरकार जितना कोशिश करेगी, प्रयास करेगी क्योंकि सरकारों का काम ही यही है। एक-दूसरे पर आरोप तो लगाते रहेंगे, चलता रहेगा, हम आयेंगे, कल कोई और आयेगा, ये चलती रहेगी दुनिया, ये पल-पल दो पल की कहानी है, आज मैं हूं कल तुम हो, कल कोई और होगा, इसलिये सरकार को पानी जैसे संवेदनशील विषय पर किसी तरह की राजनीति नहीं करते हुए राजस्थान की जनता को जितना लाभ दे सके वह प्रयास करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। अब हमारे दोनों माननीय विद्वान मंत्री हैं वे समय की नजाकत को समझते हुए अपने ओजस्वी उत्तर देंगे। माननीय कन्हैया लाल जी चौधरी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम मांग संख्या 41 - जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी पर चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन में माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं वो हमारे विभाग के लिये नयी इबारत लिखेंगे सब को मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों के कट मोशन प्राप्त हुए हैं उनके जवाब माननीय सदस्यों को दो दिवस में भिजवा दिये जाएंगे।

हमारे शास्त्रों में जल की महिमा बताते हुए कहा गया है कि जल ही जीवन है, जल प्रकृति के आधारभूत पंचतत्वों में एक होने के साथ ही प्रत्येक जीव के लिये भी अत्यंत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आदमी, कोई भी जीव अगर उसको भोजन नहीं मिले तो

महीने दो महीने निकाल सकता है, बाकी पानी नहीं मिले, जल नहीं मिले तो वो 7 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। पुराने लोग जब किसी बाथरूम में कही पर भी अगर बूंद-बूंद टपकती है तो उसको अशुभ मानते हुए तुरंत उसको बंद करते हैं और देखते हैं कि कही हमारा धन जा रहा है यह। लोगों ने एक डर पैदा किया था कि पानी को कैसे बचायें, जल को कैसे बचाया जाये, यह हमारे पुराने लोगों को हम देखते आये हैं बचपन से।

सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश की विषम पेयजल परिस्थिति से वाकिफ हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है और हमारे प्रदेश का 85 प्रतिशत भू-भाग डार्क ज़ोन में है और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहां जो पानी है वह भी फ्लोराइड युक्त पानी है। साथ ही, यहां के जितने भी गांव ढाणियों, मगरों में बसे हुए हैं, यहां पर कोई भी पेयजल की स्कीम बनाते हैं तो उसकी लागत भी दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा आती है। हमारे प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का साढ़े पांच प्रतिशत है और प्रकृति द्वारा प्रदत्त सतही जल भूजल की उपलब्धता देश में उपलब्धता की तुलना में लगभग 1% है। पानी की महिमा, अभी माननीय सदस्य हमीर सिंह जी भायल ने बताया था कि जब पानी की दिक्कत होती थी, पानी नहीं मिलता था तो हमारे पूर्वज उस पानी को बंटवारा करने के लिये पहले तू पी, पहले तू पी, पहले तू पी कह करके जान चली गयी, बाकी पानी का महत्व इतना जबरदस्त महत्व है कि अभी सदस्य ने बताया कि वास्तव में पश्चिमी राजस्थान में पानी कितना इम्पोर्टेन्ट था हमारा।

माननीय सदस्यों ने काफी अलग-अलग विचार दिये। 56 से ज्यादा सदस्यों ने आज अपनी बात रखी। इसमें तारानगर से आने वाले सदस्य ने कहा कि जल जीवन मिशन की मॉनिटरिंग के लिये जिला स्तर पर या विधान सभा स्तरीय कमेटी बने इसके लिये हम हमारे विभाग में चर्चा करते हैं, जिला स्तर पर कमेटी बने, इसके लिए हम चर्चा करेंगे और जिससे इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो क्योंकि जल जीवन मिशन में वास्तव में जो भी दिक्कतें आयी हैं, मैं पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहूंगा, आज मैं मेरी स्पीच में, आप सब लोग यहां हम 200 सदस्य हैं सभी बैठ कर यह करें कि आने वाले समय के अंदर जो भी गलतियां हुई हैं, उनको सुधारते हुए क्योंकि डेढ़ साल वास्तव में हो गया उन गलतियों को सुधारते हुए आने वाले समय में पानी हर व्यक्ति को कैसे मिले, ये प्रॉब्लम कैसे दूर हो, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें जो भी आई हैं, उसको मैं मेरी तरफ से रखूंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, विभाग ने अब तक क्या-क्या काम किया है। ये सारी बातें मैं रखूंगा।

श्रवण जी चौधरी ने भी लायबिलिटी फिक्स करने की बात की। गुरवीर सिंह जी ने काफी अच्छे सजेशन दिये। रामकेश मीणा जी ने बोला कि एस.पी.एम.एल. जो पिछले 2003 से काम कर रही है उस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं वास्तव में उस पर 23 की कार्यवाही भी कर दी बाकी वो कोर्ट से स्टे लेने की वजह से उस पर क्योंकि एक न्यायालय भी एक प्रक्रिया के अंदर कही ना कही दिक्कत आ रही है तो हमने उसकी कार्यवाही कर दी। अमित चाचाण ने भी बोला कि हमारे कुछ जिलों के अंदर अभी तक काम नहीं हुआ उसके लिये भी

हमने वर्क ऑर्डर वगैरह दे दिये हैं और इसी महीने के अंदर सारी सैंक्शन निकल जाएगी। सुरेश जी मोदी, इन्होंने भी कुम्भाराम लिफ्ट के लिये बोला कि कुम्भाराम लिफ्ट का इस बजट के अंदर कोई भी नहीं बोला गया, कहीं उसमें लिखित में नहीं आया जबकि यह पिछले बजट के अंदर कर दी थी, जिसका हमने टेंडर लगा दिया और लगभग 21,000 करोड़ के जो टेंडर लगे, जिसमें 7,500 करोड़ के टेंडर कुम्भाराम लिफ्ट के हैं, जिसके अंदर चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के लिये हैं उसके टेंडर भी हमने लगा दिये हैं और बहुत जल्दी उसके ऊपर सैंक्शन की कार्यवाही करेंगे। ...(व्यवधान)... वो इसलिये करेंगे कि फिर मैं कह रहा हूं कि पीछे मत जाओ कि मार्च, 2024 से पहले-पहले उन लोगों को काम, आप लोगों को काम करना चाहिए था, आप नहीं कर पाये, सालभर से बन्द था। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को जिन्होंने बार-बार निवेदन किया वो पत्र भी, कितने पत्र लिखने के बाद में, क्योंकि सभी राज्य 90% से ज्यादा काम कर चुके थे, यहां 40 परसेंट काम किया था, तो वो जो काम किया था न उसमें मैं कह रहा हूं कि चर्चा मत करो अगर मैं पूर्व में जाऊंगा न तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे आप। मैं सिर्फ और सिर्फ यह कह रहा हूं कि हम कैसे सुधार करें, इस राजस्थान की जनता का भला कैसे करें। हम तार्किक करें क्योंकि मेरे तो पहले ही ये वैसे ही करंट वाले भाई बैठे हैं, पहले ही कह रहे हैं कि बोलो, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा...(व्यवधान)...जो काम होना चाहिए था।

जाकिर जी हुसैन ने कहा अमृत टू का, तो इसके लिये भी हमने टेंडर कर दिया, कोशिश करेंगे कि मार्च के महीने के अंदर इसका आपके मकराना की हम सैंक्शन कर दें और आर.ओ. जो प्लांट हैं इनके भी मेन्टेन्स करते हुए जितने भी आर.ओ. प्लांट हैं, राजस्थान में जहां-जहां हैं वास्तव में उनकी मेन्टेन्स का ओ. एंड एम. का काम खत्म हो गया, उनको ठीक करते हुए हम कोशिश करेंगे कि उनको प्लान बना के किसी स्कूलों में लगा दें क्योंकि हर जगह पर आज जे.जे.एम. के तहत जल जीवन मिशन के तहत सारा शुद्ध पानी आने की जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू किया, उनका कैसे सदुपयोग हो, इसके लिये हम कोशिश करेंगे कि स्कूल में लगायें और उसका एक पॉइंट उस स्कूल से बाहर निकाल दें तो कोई बाहर जिसको जरूरत है वो भी ले ले और स्कूल के बच्चों को शुद्ध पानी मिले। इस पर हम बैठ कर मेरे विभाग से बैठ कर हम चर्चा कर के जो भी इसमें बजट में प्रावधान और करते हैं, उसको हम, जिससे इसका सदुपयोग हो वह वेस्टेज नहीं जाये। हमीर सिंह जी भायल ने बात की कि पोकरण-फलसूंड योजना के काम में बार-बार ट्रिपिंग की वजह से आते हैं, इसके लिये भी हमने बजटीय प्रावधान, इसमें बजट सैंक्शन कर दिया और जिसके स्टैब्लाइजर वोल्टेज बढ़ाने के लिये हमने इसके भी आने वाले समय के अंदर जो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर में जहां पानी बार-बार बिजली की कटौती की वजह से तो ये भी हम काम करने जा रहे हैं। बाकी काफी सदस्यों ने कहा, ऋतु बनावत ने कहा कि हमारे ट्यूबवेल पॉलिसी बनानी है, डांग क्षेत्र में डी.आई. पाइप हैं तो जहां-जहां वास्तव में जहां रोक ऊपर आ गई है, जहां डेफ्थ में नहीं जाते वहां पर डी.आई. पाइप की हम करेंगे कि

डी.आई. पाइप लगाया जाये। डूंगरराम गेदर, रेवतराम डांगा, शिखा मील बराला, चोमू, अरुण चौधरी, बालोतरा ये जो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी हमारी ये बायतू,...

Kas/rtm/05.03.2025/22.30/5f

हमीर सिंह भायल जी के सिवाना, बालोतरा यह राजस्थान कैनाल के टेल पर पड़ता है और नर्मदा के भी टेल पर पड़ता है। पिछले 6 महीने से हम समीक्षा कर रहे थे, हमारे मंत्री महोदय सुरेश जी से भी कहा था कि नर्मदा से जितना कुछ पानी मिल जाये, वहां से एक्स्ट्रा पानी मिल जाये तो हम इन 100-150 गांवों की योजना बना दे। आज माननीय सैक्रेटरी साहब ने भी कहा है कि इसमें कुछ पानी हम आपको दे सकते हैं, जो महाराष्ट्र के हिस्से का था, वो ले नहीं पा रहे। इसकी भी हम डीपीआर बनायेंगे। इस क्षेत्र में हमेशा ही पानी की दिक्कत रहेगी, इसकी डीपीआर बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं और डीपीआर में जितना खर्चा लगेगा, हम करेंगे।

धर्मपाल जी खेतड़ी वालों ने प्राकृतिक जल स्रोतों की मेंटीनेंस, पुनर्जिवित करने का कहा था। अभी हमारे सैनी साहब ने कहा था कि उदयपुरवाटी में जो टेंडर था, वो लगभग 1200 करोड़ का एल एण्ड टी का टेंडर था, हम इसी महीने में कोशिश कर रहे हैं कि उसका वर्क आर्डर देकर उसको जल्दी ही चालू करें, इनकी वास्तव में बहुत बड़ी तकलीफ है। पिलानी, खेतड़ी, उदयपुरवाटी का है, पिलानी के लिये तो कुम्भाराम लिफ्ट से एक्स्ट्रा और आयेगा, पहले यह जो 1200 करोड़ का सालभर से टेंडर अटका हुआ था।

हरलाल सारण, श्रीमती विमला देवी, छोटूसिंह जी, सुरेश जी गुर्जर, संजीव कुमार, गणेशराज जी बंसल, रूपेन्द्र सिंह जी, देवेन्द्र जी जोशी, श्रीमती गीता बरबड़, सुभाष मील, चेतन पटेल, लादु लाल, जयकृष्ण पटेल, मांगीलाल मीणा ने कहा कि मार्च, 2024 को पूरा करना था। यह भी जेजेएम के बारे में कह रहे थे कि आप लोगों ने सही ढंग से इसकी प्लानिंग नहीं की, सही ढंग से इसकी योजना नहीं बनाई। योजना न बनाने का और योजना बिगाड़ने की सबसे बडी गलती की, क्योंकि किस तरह से मेंटीनेंस करेंगे। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त, 2019 को जब पूरे भारत में यह योजना चालू की तो उन्होंने 45-45 परसेंट स्टेट और केन्द्र का राज्यांश रखा और 10 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन जन सहभागिता का रखा, जिससे उस पैसे से उसका मेंटीनेंस हो जाये, उसका बिजली का बिल दे दिया जाये, यह सारी चीज रखी थी। पूरे भारत में सभी राज्यों ने इसी हिसाब से काम किया है। मार्च, 2023 में राजस्थान में इसको माफ करने की घोषणा की, जिनसे पैसे ले लिये, उनको लौटाने का कोई प्रावधान नहीं रखा। शायद सभी सदस्यों को जब जाते थे तो यही कहते थे कि साहब, हमसे पैसे ले लिये, हमें वापस कब देंगे? जिनसे नहीं लिये, उनकी जगह कौनसा बजट देंगे, इसका कोई प्रावधान नहीं रखा। अब हम बैठकर इसकी योजना बना रहे हैं, वह भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे करेंगे।

कालूराम जी, ललित जी ने अभी कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही क्यों नहीं

करते। पदम चन्द जैन और उनके लिये हमने सारी कर दी, उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है, थोड़ी बहुत कोर्ट वाली भी प्रोब्लम आ रही है। पितराम जी काला के अमृत 2 के टेंडर कर दिये, इसी मार्च में वर्क आर्डर दे देंगे। कुम्भाराम लिफ्ट का भी हमने टेंडर लगा दिये हैं। इनके जितने भी ट्यूबवैल, हैंडपम्प खराब हैं, उनकी सारी की डिटेल हमारे पास आ गई है। मैं इनके वहां पर गया था, मैंने मीटिंग भी ली थी, वहां पोजिशन यह थी कि वहां दो जेईएन थे। अभी सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य अनिल जी ने बोला था कि हमें तो पिछली बार 60-60 ट्यूबवैल मिल जाते थे, मिल जाते होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उस ट्यूबवैल में मोटर खराब है, स्टार्टर खराब है या उसकी डीपनिंग करनी है, वो तब 30 लाख रुपये का आता था, वह लगता था 15-20 लाख रुपये में, अफसरों को दुनियाभर का कमीशन मिलता था। उसमें किसी ने मोनेटरिंग नहीं की, जनता का पैसा लगता था, देते थे और सेंक्शन निकल जाती थी, किसी ने मॉनिटरिंग नहीं की। मैंने पिलानी में बैठकर जनता से संवाद किया, उन्होंने कहा कि हमारा ट्यूबवैल है, खूब पीछे पड़े और बार बार यह कहते रहे कि नये ट्यूबवैल लेकर आओ। आम जनता ने सरकारी ट्यूबवैल को 50 हजार रुपये में लगाकर उससे ज्यादा डिस्चार्ज का पानी ले लिया। ट्यूबवैल के जो भी एस्टीमेट बनाकर दे रहे हैं, उसकी एक-एक चीज को अगर हम चैक नहीं करेंगे और वैसे ही सेंक्शन कर देंगे तो जनता का पैसा बरबाद होगा। फिर भी सब जगह से आ गये हैं, इसी महीने में जितने भी खराब ट्यूबवैल हैं, जितने भी आपके पुराने कुएं हैं, हैंडपम्प हैं, चाहे मोटर हो, सबका हमने ले लिया है और उसमें कितना भी पैसा लगे, हमारे मुख्य मंत्री जी ने कह रखा है कि मेंटीनेंस के लिये अभी तो 142 करोड़ है, अगर 1400 करोड़ रुपये भी लगेंगे तो देंगे। मैंने सभी अधिकारियों को कह दिया, कल से ही हम सेंक्शन निकालना चालू कर देंगे, कोई भी चीज नहीं रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सेंक्शन तो पहले खूब निकाल दी, बाकी बिजली के कनेक्शय यह दो-दो साल तक भी नहीं कराते थे। जहां सिंगल फेज ट्यूबवैल में 5 लाख में काम हो सकते थे, वहां थ्री फेज ट्यूबवैल के कनेक्शन 25-25 लाख के लगाते थे, उनको तो केवल बजट करना था। कौन मॉनिटरिंग करे, बिजली विभाग में कौन जाये? मैंने सबको पाबंद कर दिया कि 15 दिन में अगर कनेक्शन नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि इसकी मॉनिटरिंग आप भी देखो, क्योंकि जनता कहीं न कहीं हमको भी दोष देती है और आपको भी दोष देती है। वो कोई नहीं देखता कि बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ, उनको लगता है कि हमारे पानी नहीं आ रहा। हमें इसकी प्रोपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी।

समाराम जी, श्रीमती रमीला खड़ीया जी ने भी कहा, वास्तव में कुशलगढ़ और बांसवाड़ा में जेजेएम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, हमने कमेटी भी बनाई। मैं रमीला जी और इन सबको इतना कहना चाहता हूं ....(व्यवधान).... रमीला जी, घर का कनेक्शन भी करेंगे। कामों की मॉनिटरिंग वास्तव में पहले कभी नहीं हुई। पहले बांसवाड़ा जिले में जाने के लिये

बोलियां लगती थी, मैं कहना नहीं चाहता मेरे मुंह से, बांसवाड़ा और जहां ज्यादा काम है, देखा जाता था कि 6 महीने में सबसे ज्यादा बजट कौनसे डिविजन में आया, उसकी बोलियां लगती थीं। अध्यक्ष महोदय, आज पोजिशन यह हो गई कि हर अधिकारी चाहता है कि मुझे तो फील्ड में मत भेजो, मेरे को तो ऑफिस में ही लगा दो, क्योंकि काम करना पड़ रहा है, ईमानदारी से काम करना पड़ रहा है, यह तकलीफ हो रही है। किसी ने देखा ही नहीं ना कि क्या चीज है।

माननीय सदस्य समरजीत सिंह जी बहुत अच्छे सुझाव देते हैं। आप ठेकेदारों की हिम्मत देखो, मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि ऐसो की तुरंत जांच करके उनके खिलाफ और इंक्वायरी बैठाओ। 40-40 करोड़ की पेनेल्टी लग रही है और कोर्ट में जाकर स्टे ले रहे हैं। उनके खिलाफ जितनी भी जांच करनी पड़े, पाइप उखड़वाना पड़ेगा, तो उखड़वायेंगे, ऐसे जितने भी गंदे ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा समय तो लूंगा, आप मेरे पीछे मत पड़ना, क्योंकि रात-दिन मेहनत की है, हर जिले में जाकर, हर जगह जाकर एक-एक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर, अधिकारियों के साथ बैठकर एक-एक वर्क को, छोटे-छोटे ट्यूबवैल और हैंडपम्पों को देखने की कोशिश की है कि किस तरह से जनता का पैसा बचे और सबको क्वालिटी का समय पर पानी मिले। ....(व्यवधान)....

12 तारीख को यमुना के पानी के बारे में भी आपको कुछ न कुछ मिलेगा, बहुत कुछ काम हो चुका, अभी सुरेश जी बोलेंगे, आप तसल्ली रखो। जो वर्षों से अटकी हुई चीज थी, धीरे-धीरे उस पर बढ रहे हैं, वह भी आयेगी। पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने सोचना तो चालू किया और धरती पर टेंडरों के काम चालू हो गये। राम जल सेतु का तो काम भी चालू हो गया, वो भी आयेगा, माही का भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ब्राह्मणी नदी का भी इस बजट में 6800 करोड़ रुपये दिये हैं। यह सारी बात अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या कर रहे हैं। मुझ से तो केवल पानी वाली बात पूछो। ....(व्यवधान).... देखो बाला जी की कृपा से खूब बारिश हुई है और अभी भी बाला जी चाहेंगे तो होगा। हम बिजली पैदा कर सकते हैं, जल तो बाला जी ही पैदा करेंगे। जिसको आस्था नहीं है, वो नहीं करें, हम तो विश्वास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी योजना देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने, जिस तरह से हर व्यक्ति को घर मिले, बिजली मिले, गैस मिले, किसान सम्मान निधि मिले, सारी योजना का फायदा मिले, उसे खाद्य सुरक्षा में मिले, उसका फ्री इलाज हो, पहली बार उन्होंने सोचा कि हर व्यक्ति को घर में शुद्ध पेयजल मिले, इसलिए 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन योजना लेकर आये। इसके लिये तब 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया। आज 8 लाख करोड़ रुपये मार्च, 2024 तक खर्च करने के बाद भी उस योजना का हम समुचित लाभ नहीं ले पाये।

Msk/rtm/05.03.25/2240/5g

जिन योजनाओं के अन्दर प्रति व्यक्ति पर-घर कनेक्शन के हिसाब से पहले लगभग 60 हजार की लागत आ रही थी। उसके अन्दर 10 परसेंट पैसा कंट्रीब्यूशन का था, 45-45 परसेंट स्टेट और केन्द्र को लगाना था। बाकी हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाये और हम केवल 40 परसेंट काम ही कर पाये। जल जीवन मिशन योजना के तहत..

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): हर विधान सभा में एक हैंडपम्प दे दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह कौनसा तरीका है? नेता प्रतिपक्ष, क्या इनको परमिशन है।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अगर कहीं आपने मेरे विभाग में पत्र दिया हो, कहीं गलती से रह गया हो तो आप मुझे दोबारा दे देना। हम पानी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। पानी के अन्दर 100 परसेंट, किसी कीमत पर भेदभाव नहीं करेंगे, पीने का पानी हर व्यक्ति को चाहिए। मैं और यह कह रहा हूं कि आप लोगों को 10-10 हैंडपम्प एक्स्ट्रा दूंगा, मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अलावा। मैं सबको एक्स्ट्रा दूंगा, पानी में कोई कंजूसाई नहीं है। पानी के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने कह रखा है कि जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा लो, और देंगे सबको। जिसको हैंडपम्प नहीं चाहिए, उतने अमाउंट का ट्यूबवैल ले लेना। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब करेंगे।

श्री अध्यक्ष: सबको पानी पीला देंगे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): डूंगरपुर से आने वाले सदस्य को फोन नहीं मिले थे, यहां तो बीजेपी के राज में आपको ट्यूबवैल मिल रहे हैं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जल जीवन मिशन योजना के तहत हमारे राजस्थान में 42 हजार.. ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द (धरियावद): हैंडपम्प और ट्यूबवैल तो दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य, एक बार ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): समय कम है, भई। जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान में 42,331 गांवों में 92 लाख कनेक्शन करने थे और लगभग 93,427 करोड़ रुपये की लागत की योजना स्वीकृत की गयी थी। 15 दिसंबर, 2023 तक हम केवल 30 हजार करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये। सिर्फ 30 हजार करोड़ रुपये, लगभग 63 हजार करोड़ के काम हमें मार्च, 2024 के बाद करने थे, उसमें जल जीवन मिशन की मियाद खतम हो गयी और वे काम तब से अटके हुए थे। फिर भी आप इनकी प्रगति आप देखें। 15 दिसंबर, 2023 तक जब खूब पैसा मिल रहा था। राज्यांश तो कम था और केन्द्र का पैसा ज्यादा मिल रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि अभी मार्च, 2024 के बाद हमने लगभग 1600 करोड़ रुपये राज्य के ज्यादा दिये, केन्द्र का पैसा कम मिला, क्योंकि स्कीम बंद हो चुकी थी। फिर भी हमारी प्रोग्रेस देखें, आप कहते हैं कि आपने क्या किया? 15 दिसंबर, 2023 तक इन्होंने 36 लाख 28 हजार कनेक्शन किये। इन्होंने पर-डे 2299

कनेक्शन किया। 16 दिसंबर, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक तीन लाख, बीच का यह जब चल रहा था तब हमने 2830 कनेक्शन प्रतिदिन किये, यानी 500 कनेक्शन हमने पर-डे ज्यादा किये। हमने आते ही, क्योंकि तब तक वह चल रहा था। 15 दिसंबर, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक पेयजल हमने 11 लाख 60 हजार किये और 2603 पेयजल कनेक्शन प्रतिदिन किये, जबकि मार्च, 2024 के बाद वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत नहीं होने कारण कनेक्शन का औसत कम होना चाहिए, किन्तु गत सरकार के 2299 प्रतिदिन कनेक्शन के मुकाबले 2603 कनेक्शन प्रतिदिन किये गये। पहले जेजेएम में पूरे देश में हमारे राज्य की रैंक 33 थी। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया, उनके प्रयासों से, उनके आदेश से हम इतने से टाइम में 31वीं रैंक पर आये, जबकि यह प्रगति सरकार की तब है जब जेजेएम की वार्षिक योजना का वर्ष 2024-25 का अनुमोदन ही नहीं हुआ, जब केन्द्र से पैसा..., तो भी हम 31वीं रैंक के ऊपर आये।

जेजेएम योजना का सही क्रियान्वयन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? भ्रष्टाचार अलग चीज है। भ्रष्टाचार में आप यह कर सकते हैं, उसकी डेप्थ कम कर सकते हैं, पाइप की क्वालिटी कम डाल सकते हैं, आप लैंथ खा सकते हैं, आप घटिया सामग्री लगा सकते हैं, बाकी सबसे बड़ी गलती इन्होंने यह की कि जो केन्द्र का पैसा आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी इंडस्ट्री लगती है या कुछ भी होता है, उससे पहले रॉ-मैटेरियल की व्यवस्था की जाती है। जेजेएम में सबसे पहले रॉ-मैटेरियल पानी है। सबसे पहले पानी की व्यवस्था हो, पानी को उठाने का प्रबंध हो, उसको फिल्टर करने का प्रबंध हो और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का प्रबंध, तब जाकर कनेक्शन किया जाता है। तब जाकर वह स्कीम सक्सेस होती है। ...(व्यवधान)... सोर्स तो देखा ही नहीं, क्योंकि बजट को बुक करना था। बजट भी बुक नहीं कर पाये, केवल 30 परसेंट ही बजट बुक पाये, जबकि मार्च, 2024 तक तो 100 परसेंट करना था, वह भी नहीं कर पाये। सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि जिस तरह से जो काम राजनीति के शिकार बनते रहे, राम जल सेतु को राजनीति का शिकार बनाते रहे, वे देंगे 90 परसेंट पैसा देंगे। बाकी कभी किसी ने सोचा नहीं। इन्होंने सिर्फ क्या किया। प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने रॉ-मैटेरियल तो ले लिया। कौनसा लिया? लोकल, जहां पर ऑलरेडी ही पानी नहीं था। अगर पानी होता तो जेजेएम की जरूरत कहां पड़ती? ट्यूबवैल में पानी नहीं था, ट्यूबवैल खोद दिया। किस डेप्थ में जाना है? क्योंकि चलेगा तो तब जब टंकियां बनकर आयेंगी। तब तक तो पैसा ही उठा लेंगे। कोरोना की वजह से जो एसडी रुकती थी, पहले जो कांट्रेक्टर की 10 परसेंट सिक्यूरिटी डिपोजिट रुकती थी, वह रूकी 3 परसेंट। कांट्रेक्टर को डर ही नहीं रहा। 3 परसेंट का क्या डर, 30 परसेंट तो वह एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहा है। ओपनवैल खोदे। ओपनवैल में यह नहीं देखा कि पानी नहीं है और पानी है तो उसमें क्वालिटी क्या है? सबको पता है कि राजस्थान के अन्दर 66 परसेंट एरिया में फ्लोराइड है। फिर आप ओपनवैल क्यों खोद रहे हैं? फिर आप उसमें काम क्यों कर रहे हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ...(व्यवधान)... पानी नहीं आया, कमीशन तो आया है।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): वे जांचें भी हो रही हैं। जांचें तो जांचों की जगह है, पर काम तो करना पड़ेगा ना। जनता तो परेशान हो रही है ना। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अच्छा भाषण चल रहा है, कृपया चलने दें। माननीय सुनिये, आपको बहुत कुछ मिलेगा।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इसकी वजह से आज हमारे लिए जो प्रोब्लम हो रही है। क्योंकि उपभोक्ता के पास जाते हैं, वह कहता है कि टोंटी तो लगा दी, इसमें पानी कब आयेगा? इसका मैंने पहले भी पिछली बार बोला था। इसका दण्ड हमने भुगता, हमारी 11 सीटें खोके। इन लोगों की गलती से, क्योंकि जाते ही वे मांगने तो लग गये, लाओ पानी लाओ। उन्होंने तो टोंटी लगा दी, आप पानी दो। देंगे तो तब, इन्होंने सोर्स तो पैदा ही नहीं किया। वह पैसा वहां खर्च करते तो कम से कम उस आदमी को तसल्ली रहती। मेरे बड़ी लाइनें डल रही हैं, टंकियां बन रही हैं, फिल्टर प्लांट बन रहा है, मेरे यहां पानी आयेगा। बाकी उसको सबसे पहले जाकर लगा दिया। उससे एक वातावरण बन गया कि, साहब, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। हो सकता है कि क्वालिटी खराब हुई है, डेप्थ कम डाली है तो कम से कम दो-चार साल तक पानी मिलता ना। 2053 की स्कीम है तब तक नहीं चलता, वह तो स्टार्ट ही नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जेजेएम में डिले किया। मार्च, 2021 से पहले-पहले जयपुर और अजमेर की जो डिजाइन की थी। स्वर्गीय सांवरलाल जी जाट साहब और पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के समय में, उन लाइनों की लाइफ और उनकी कैपेसिटी, जनसंख्या के अनुसार 2021 में कम्पलीट हो गयी थी। यह काम इनको 2018 से पहले-पहले स्टार्ट करना चाहिए था। चाहे कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करते या उस योजना को बनाते, बाकी इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आज मैं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जयपुर, अजमेर के लिए 2062 करोड़ रुपये का इस बजट में प्रावधान किया। आने वाले दो से तीन साल के अन्दर इस योजना को कम्पलीट करते हुए, जयपुर की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उसको 2053 के हिसाब से हम पानी देने की व्यवस्था करेंगे। अजमेर के लिए 665 करोड़ रुपये की योजना का काम, उसमें भी हमने कुछ के टेण्डर लगा दिये हैं और बाकी के टेण्डर लगाकर इसमें भी हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिले होने का जो कारण था, गत सरकार में 2021 की बीएसआर से दरें लगभग 35 से 40 परसेंट दरें आयी थीं। केन्द्र सरकार के संज्ञान में आया कि यहां पर दूसरी जगह से ज्यादा रेटें क्यों आ रही है? उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया, इसके ऊपर रोक लगायी। दोबारा इसका परीक्षण किया, इन्होंने 15 परसेंट अबोव पर, दो साल पहले इसके वर्क ऑर्डर जारी किये। आज उसी रेट पर, क्योंकि दो साल में लगभग 10 परसेंट से ज्यादा प्राइस वेरिएशन होने के बावजूद भी आज हम 10 से 15 परसेंट अबोव के अन्दर टेण्डर सेंक्शन कर

रहे हैं।

mdp/rtm/05.03.25/22:50/5h

इससे लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपये राजस्थान की जनता का बचा रहे हैं। ये है यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा की सरकार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जे.जे.एम. के अन्दर जो सबसे बड़ी दिक्कत आयी, अभी हमारे माननीय सदस्य, सामने बैठे हुए कह रहे थे कि, साहब, राजनीतिवश नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने उठते ही कह दिया कि हो सकता है कि मेरे अधिकारियों की, क्योंकि कोस्टिंग कम करनी थी, सही एस्टीमेट बनाने थे। दोबारा मैंने टेंडर की जो भी शर्तें थी, उसको हटायी। टेंडर की शर्तें हटाने की वजह से ट्यूबवेल और इनकी कोस्टिंग जहां पर 20 लाख का पड़ता था, आज वह 36 से 37 परसेंट बिलो रेट में आ रहा है। 37 परसेंट बिलो रेट में आता है। उसके लिए सारा परीक्षण किया। कोस्टिंग, जहां पर जो लाइन थी, फेस लाइन 500 मीटर में थी, वह पहले बिजली विभाग वाला 3 किलोमीटर से ला रहा था, उसकी कोस्टिंग हमने कम करायी। एक-एक चीज की मोनिटरींग करने के बाद में जब ये किया, उसकी वजह से थोड़ा समय लग गया। आज हमारे अधिकारियों को हमने कहा कि सिंगल फेज ट्यूबवेल, 10 साल पहले अगर किसी ने नियम बना दिया कि थ्री फेज ही ट्यूबवेल लगेगा, आज हमारे पास नये संसाधन हो गये, नयी टेक्नोलोजी आ गयी। सिंगल फेज की 5 एचपी की मोटर 500 फीट तक पानी आराम से उठाती है और हमारे पास पानी का डिस्चार्ज भी उतना ही है तो हमारी जो कोस्टिंग 5 लाख की आ रही है तो हम 20 लाख क्यों लगाएं?

पहले तो मैं हमारे इन चीफ इंजीनियर्स, अधिकारियों को समझाने में लग गया था कि कानून बनाने वाली ये हमारी विधान सभा है, हम बदलेंगे। बाकी जहां जनता का पैसा बच रहा है तो बचाइए, क्यों नहीं बचा रहे हैं? उसमें हमने काम किया, इसकी वजह से थोड़ी टेंडर्स में डिले हुई। बाकी मैं सारे के सारे जल्दी ही इस महीने के अन्दर लगाते हुए जितनी भी सेंक्शन निकालेंगे, ये ही नहीं इस बजट की भी सेंक्शन हम इसी महीने में निकालते हैं और वर्क ऑर्डर इसी महीने में जारी कर देंगे और अप्रैल महीने के अन्दर आपका काम कर देंगे।

इसके साथ-साथ जे.जे.एम. के अन्दर जो राजनीति की बात हो रही थी, शाहपुरा वाला भी करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, मनीष भाई, बैठ। मैंने देखा है, मैं डीडवाना प्रभारी हूं, नागौर का प्रभारी हूं। वहां जब मैं जाता हूं तो किसी गांव की पापुलेशन है 2000, किसी ढाणी की पापुलेशन है 500, 500 वोट उनके हैं, चाहे वह चार किलोमीटर दूर है, चाहे उसका लेवल नीचा है, वहां पर टंकी बना दी, क्योंकि वे उनके वोट थे। ये देखा है। मैं दूंगा लिखित में। ये राजनीति, ये बैठे हमारे बाबूसिंह जी, जहां पर एस्टीमेट के अन्दर, बाकी मैं इस सदन के अन्दर घोषणा करता हूं कि जे.जे.एम. के अन्दर तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो सेंक्शन थी, वही अमाउंट देंगे। बाकी हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी, जितना भी इसमें डेविएशन होगा हम राज्य सरकार से, कुछ ढाणियां बच गयी हैं, कोई बच गया है,

उसको भी हम पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, दस परसेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से, देखिए इन्होंने सबसे बड़ा पाप क्या किया? इन्होंने, अध्यक्ष महोदय, जो काम 10 परसेंट कंट्रीब्यूशन से हम इसका ओ एंड एम करते, मेंटीनेंस करते बिजली का, अभी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे, साहब, बिजली के बिल का इन्होंने प्रावधान नहीं किया। देश के प्रधान मंत्री मोदी जी जब कोई स्कीम बनाते हैं तो सारे प्रोविजन लेकर चलते हैं कि कैसे चलेगी, कैसे जनता में जागरूकता आयेगी, किस तरह से लोगों की भावना जगेगी, कैसे उसका अंशदान हो तो उसको लगे कि मेरा पैसा लगा है, इसका सदुपयोग कैसे करें। सारी सोच कर करते हैं, सब सोच कर बनाते हैं। बाकी हम उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि हमें वोट लेने हैं। जनता को फ्री करना है, फ्री करना है, फ्री कीजिए बाकी सुविधा तो दीजिए। आज उसकी वजह से पूरा सिस्टम, पूरे जे.जे.एम. को खतम कर दिया। क्या नुकसान हुआ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन स्कीम बनायी। किसी गांव के अन्दर हमें 200 कनेक्शन करने थे, उस परिवार से पूछा, एक परिवार में 5 आदमी रहते थे, 5 परिवार रहते थे, 5 राशन कार्ड थे, क्योंकि आजकल नरेगा में काम करने के लिए अलग-अलग जॉब कार्ड बना लेते हैं और रहते वे एक ही जगह पर हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कंट्रीब्यूशन का तीन हजार, साढ़े तीन हजार लग रहा है, हमें तो एक कनेक्शन दे दीजिए। अधिकारियों ने देखा डिजाइन के हिसाब से 200 कनेक्शन तय कर दिए। जिस दिन मार्च, 2024 को फ्री की घोषणा की, फ्री की घोषणा करते ही, न सरपंच ने देखा, क्योंकि उसको भी वोट चाहिए, नेताओं ने भी देखा कि हमें भी वोट लेना है, अधिकारियों को तो कोई मतलब ही नहीं था कि देखें, उन्होंने 200 कनेक्शन, कोई बाड़े में कर दिया, कोई कहां कर दिया, 400 कनेक्शन कर दिए। जहां 4 एम.एम. की फेरोल से जो पानी आना था, जो प्रेशर मेंटेन होना था, अगर वह डबल से ज्यादा कनेक्शन हो जायेंगे, क्या वहां प्रेशर मेंटेन होगा? क्या वह स्कीम सक्सेस होगी? मतलब इतना बड़ा, ये 36 लाख कनेक्शन के अन्दर सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, पहले तो पानी नहीं है, पानी आयेगा तो भी उसमें प्रेशर कैसे देंगे? अब बताइए, अध्यक्ष महोदय, उस स्कीम को, इस पैसे का कैसे सदुपयोग करें। वह डेप्थ बाद की चीज है, उसको खोद कर अन्दर डालना, ऊपर कम है, यह तो जांच का विषय बाद में है, पूरे सिस्टम में सालभर हो गया कि जाते हैं, देखते हैं उसके बाद में सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि कैसे चलाए? इसमें कोई टेंशन नहीं है इनको कि हमने डाल दिए और इतने कनेक्शन कर दिए। कनेक्शन करना नहीं है, डिलीवरी क्या है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस स्कीम को सक्सेस करने के लिए, हमारे सबसे बड़ा रोडा अटक रहा है कि मार्च, 2023 में एक और कर दिया कि हम 15 हजार लीटर तक के पानी के पैसे नहीं लेंगे शहरों में और जो दस रुपये की पर्ची हॉस्पिटल में जाती है, उसका पैसा नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, दस रुपये की पर्ची कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे साथ में 5 आदमी चले गये। मेरी पर्ची नहीं बन रही तो 5

के 5 ही, साहब, मेरे को भी दवाई दे दो, बाहर आकर फेंक दूंगा मैं। पर्ची बनेगी तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। वह जनता का जो पैसा है, हम इधर तो फ्री कर रहे हैं दस रुपये, बाकी जनता का कितना पैसा बरबाद कर रहे हैं, वह बाहर आकर फेंक देगा। ऐसा ही इसमें किया। आज हम उस जे.जे.एम. के अन्दर 100 रुपये, 50 रुपये लेने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से पैसा लेंगे तो उसको लगेगा कि मेरी जेब से पैसा जा रहा है, मुझे इसको मेंटेन करना है। वह नहीं देगा तो उसका कनेक्शन काटेंगे तो कम से कम रेगूलर तो चले। वह नियम आ गया कि 15 हजार वाला फ्री कर दिया, शहर में। उससे भी बड़ा, माननीय, बैठिए, मैं आपकी ही बात पर आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे थे कि साहब, मेरे 20 हजार का बिल आ गया। इन्होंने दस साल के अन्दर जो किसी से 100 रुपये जो महीने का आता है, वह भी लेने नहीं गये। मैंने चेक कराया है। पूरी जांच करायी है, आपसे आने के बाद में। आज मतलब जहां पर 5 हजार करोड़ रुपये पानी का, बिजली का पैसा आना चाहिए था, केवल 500 करोड़ रुपये आ रहे हैं। सिस्टम को कैसे कोलेप्स कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ राजनीति करनी है। बात करते हैं कि आप पानी में राजनीति मत करो। हम राजनीति नहीं करते हैं। हम सेवा करते हैं। ईमानदारी से सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलते हैं। राजनीति आप लोग करते हैं। राजनीति सारी जनता देख रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे हेमंत जी के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सभी गांवों में, वे मेक्सिमम आदिवासी क्षेत्र के गांव हैं, उन लोगों को जाकर जब हमने देखा, 100 रुपये महीने के कनेक्शन ले रहे हैं और रेगूलर पानी आ रहा है। सबसे बढ़िया सिस्टम चल रहा है। ये गांव हैं प्रतापगढ़, नहीं हो तो आप जाकर देख लीजिए। अगर वास्तव में जनता का भला करना है हमें और आपको इस सिस्टम को चालू करना है। ये पीएचईडी ले लो, वो ले लो, ईमानदारी से किसी चीज का, जब दिन के अन्दर सबको पता है, पूरा राजस्थान भी मेरी बात को सुन रहा है, मेरे को किसी का डर नहीं है, क्योंकि किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग करते हैं। दिन में मोबाइल नहीं हो तो, दिनभर मोबाइल का किस तरह से रिचार्ज कराते रहते हैं, बाहर होटल पर बैठकर कितने चाय के कट पीते हैं, कौनसा खर्चा करते हैं, सुनिए मेरी बात, ये सारा कोई नहीं देखेगा, बाकी 100 रुपये नहीं लगने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आज की तारीख में पूरा होगा।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उस 100 रुपये की वजह से उस आदमी को शुद्ध पानी मिलेगा, क्वालिटी का पानी मिलेगा, जिससे हजारों बीमारियों से दूर होगा। अगर ये सभी लोग चाहे तो इसमें प्रति घर से हम पैसे लेंगे तो 100 परसेंट ये योजना सक्सेस होगी, वरना हम कितना भी कर लें इस योजना पर, आप सब लोगों की सहमति से, क्योंकि कहीं न कहीं जरूरी नहीं है कि 100 लो, हो सकता है कि ज्यादा कनेक्शन हो तो 80 आ जाए, 50 आ जाए, बाकी बगैर कंट्रीब्यूशन के ये योजना सक्सेस नहीं, क्योंकि अरणोद पंचायत समिति के ग्राम कोटड़ी में ग्राम जल जीवन समिति द्वारा प्रतिमाह 100 रुपये की राशि ली जा रही है, जिससे हर घर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से नियमित रूप से

पानी मिल रहा है। जाकर देख लीजिए। प्रतापगढ़ के किसी भी गांव में जाइए।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में जल जीवन मिशन की क्रियान्विति के यही कारण नहीं रहे और भी कारण रहे कि इसकी धीमी गति क्यों रही। विभाग के पास मिशन के इतने बड़े कार्य कराने के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव एवं घरेलू जल संबंधों की संख्या में देश के अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा होने के कारण वांछित, छितराई बसावट के कारण। हमारे यहां छितराई बसावट का कारण भी है।

Ans/rtm 23.00 5j 05.03.2025

इसके अलावा हमारे यहां अंडरग्राउण्ड वाटर कम है। टोटल पानी हमें सतही जल से बाहर से लाने की वजह से, यह भी सबसे बड़ा कारण। प्रति कनेक्शन 1 लाख 74 हजार रूपये आ रही है] पानी की जो कॉस्टिंग जो पहले 60 हजार रूपये आ रही थी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के साथ आज कितनी बड़ी चोट हुई है? जो पहले राजस्थान की जनता का हिस्सा केवल 27 हजार रुपये आ रहा था, आज लगभग 1 लाख 08 हजार प्रति व्यक्ति का कनेक्शन का राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी पानी आयेगा वह सब बाहर से आयेगा। दूर से आयेगा, बड़ी स्कीम का पानी आयेगा। पहले वहां लोकल खोदा या नहीं खोदा और बजट हो गया। अब जो खर्चा आयेगा यह प्रति व्यक्ति कनेक्शन ही आयेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): समाप्त करो, हो गया। बहुत हो गया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अभी तो बहुत है।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अब यह तो टेंडर की पोजीशन है। जब उत्तर दिये थे, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि यह तो पूरे भारत में ही बढ़ी है जे जे एम की तारीख। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने कितनी मेहनत की। मार्च में खतम होने वाली थी उससे पहले ही पत्र लिख दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पत्र दिनांक 15.02.2024 को एवं 16.02.2024 को लिखा। मेरे द्वारा भी 21.06.2024 को व 10.01.2025 को रेगुलर व व्यक्तिगत खुद सी आर पाटिल साहब से हमारे मुख्य मंत्री सम्पर्क करते रहे तब जाकर उन्होंने सोचा कि राजस्थान में वास्तव में दिक्कत है। जब राजस्थान के बढा रहे हैं, जिनके 10 परसेंट काम बचा है तो उनके भी बढ़ा दो, दूसरों को क्यों नाराज करें, तब जाकर जे जे एम बढ़ा। तो यह बढ़ाने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी भजनलाल जी को देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि अमृत-2 योजना में साल भर से काम क्यों नहीं हो रहा, उसके टेंडर क्यों नहीं लगे, लेट क्यों हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व मंत्री धारीवाल जी के विभाग में जबकि यह काम करना था पीएचईडी को ...(व्यवधान)... मेरी बात सुनो।

श्री अध्यक्ष: आपको सुना है, इनको भी सुनो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): क्या था इसमे और उन्होंने क्या कर दिया। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सवा साल हो गया आपको आये ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यही तो सुनना पड़ेगा ना। सुनो सवा साल हो गये ...(व्यवधान)... जब मार्च में हमारे पास आया और हम काम करने के लिए गये, यह कोटा से माननीय सदस्या कल्पना जी बैठी है, यह संजीव जी बैठे है, वहां जाकर हमने पूछा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सुनो तो सही। जितना बीच में बोलेंगे और लंबा चलेगा ।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): टेंडर लगा रहे थे ...(व्यवधान)...पैसे बुक करना नहीं है, उसका सदुपयोग कैसे होगा यह देखना है। ...(व्यवधान)... यही इंजीनियरिंग है।

श्री अध्यक्ष: कर दी व्यवस्था। भोजन हो गया ना?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने वहां लोगों से पूछा, जनता से चर्चा करता हूं कि तो उन्होंने कहा कि एस्टीमेट में 400 करोड़ रूपये किसके लिये, कोटा में जो पानी है, किसके लिए ...(व्यवधान)... कोटा शहर के अन्दर जब मेरे पकड़ में नहीं आये। यहां पहले 10 लाख की पॉपुलेशन थी उस एरिया में, जब ये हॉस्टल वगैरह आये इनसे डबल पॉपुलेशन हो गई, वर्टिकल कोटा बढ़ गया। यह जो लाइनें जिसमें गंदा पानी आ रहा है, यह डिजाइन से पहले छोटी भी थी और यह पूरी टूट गई, यह आप लोगों ने क्यों नहीं लिया। क्योंकि वेवकोस को जिन्होंने दिया वह बैठे-बैठे वहां पर कम्प्यूटर से एस्टीमेट बना दिया। ऑनलाइन देखा गूगल एप से और एस्टीमेट बना दिया, जाकर किसी ने नहीं देखा। तब मैंने तय किया उसके बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद सभी जनप्रतिनिधियों के पास जाओ सभी अधिकारी और विशेषकर जो वहां लाइनमेन है उसको पता है कि पानी की प्रॉब्लम क्या है, उनसे पूछकर दुबारा एस्टीमेट बनाओ और दुबारा एस्टीमेट बनने के बाद सबके टेंडर लगा दिये। इसी मार्च के महीने में सबको फाइनेंशियल बिड ओपन करते हुए इनके बहुत जल्दी वर्क आर्डर जारी कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... वरना वह सारा का सारा 05 हजार करोड़ रूपये बरबादी की तरफ जा रहा था। पैसे भी दिये और उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा था। ...(व्यवधान)... कोटा की नहीं, पूरे राजस्थान की जनता में। सभी जगह यही हुआ है। यह बोलने से नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री जी के जवाब में बीच-बीच में बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जब जाते ना, जनता के बीच संवाद करते ना? ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अनलिमिटेड बोलेंगे, लिमिट तो होगी। कब तक बोलेंगे? ऐसा नहीं होता। बिलकुल ऐसे नहीं होता। आप लोगों का यह तरीका गलत है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। विराजो। सदन में रात को चार-चार बजे तक भी चर्चा हुई है। 12.30 बजे पहले मैंने भी रिप्लाई दिया है। आप लोगों ने आठ घंटे बोला है तो मंत्री जी को भी अपना जवाब देने का पूरा ...(व्यवधान)... आप मुख्य-मुख्य बातें बता दो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा यह रहता है कि जब दो डिपार्टमेंट हों तो आधे-आधे घंटे और एक डिपार्टमेंट रहे तो 45 मिनट। गागर में सागर भरकर और सागर जनता में पहुंचाने की बात है आज तो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): पहले आठ बजे हो जाता था। ...(व्यवधान)... 12-12 बजे तक बैठे हैं, सुबह आकर फिर बैठना है। यह गलत तरीका है।

श्री अध्यक्षः एक मिनट। मंत्री जी, मुख्य-मुख्य बातें बता दो इनको।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है। मैंने आपसे रिक्वैस्ट की कन्क्लूड करें तो नहीं, हमारे तो सब बोलेंगे, अब सब बोलेंगे तो सब सुनो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी मैंने जवाब दे दिया। आप बैठिये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विभाग के पास जितनी भी मशीनें थी, यह स्थिति थी कि जितने भी टयूबवैल के हम टेंडर करते थे, ऐसी शर्तें जोड़ रखी थीं कि अब वह छोटे टेंडर कर दिये, उनके अन्दर शर्तें हटा दी तो कोर्ट में स्टे ले लिया, फिर दुबारा कर दिया। तो ऐसी जगह जहां हमारे विभाग की मशीनें थी उनको ठीक करवा कर, रेगुलर जहां-जहां भी है चाहे डूंगरगढ़ में जो, जोधपुर में हो, हर जगह मशीनें लगाकर गहरा कर रहे हैं, ताकि सरकार का पैसा बचे और काम हो। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, पेयजल की अवैध चोरी। जिस तरह से हमें उसको संचालन करने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास पैसा लेना पड़ेगा और वह खुद ही चलाये। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, इस योजना को फेल करने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अवैध कनेक्शन। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अवैध कनेक्शन पर हम सभी को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर कहीं पर भी पुलिस या किसी को भी कहना पड़ेगा तो कहना पड़ेगा, अगर हम नहीं कहेंगे तो यह सबसे बड़ा कैंसर अवैध कनेक्शन है। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। परसों नागौर ज़िले में फलोद के रोणा को जोड़ने वाली मीठे पानी की पाइप लाइन में लगभग 600 बीघा जमीन में आदमी खेती कर रहा था। रात को 600 बीघा जमीन में। ...(व्यवधान)... चार साल से। उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण था। ...(व्यवधान)... वह चाहे किसी भी पार्टी का हो। ज्यादा करने में तो लंबा हो जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप बार-बार क्यों बोल रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जो भी होगा, किसी भी पार्टी का हो।

...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपको मैं दस बार कह चुका हूं। मेरे पास जब दोनों सचेतक आये थे। एक मिनट मंत्री जी। जब दोनों सचेतक आये थे मैंने कहा नाम कम करो, उन्होंने कहा कि हमारे सब लोग बोलेंगे चाहे रात के दो बजे या चार बजे। दोनों सचेतकों ने मुझे कहा। जवाब सुनिये। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह सब होने के बाद यह तय किया था कि भोजन भी करेंगे लेकिन भोजन कराने से पहले पानी भी पूरा पिलाएंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): रोटी यहीं काडोगा आप? ...(व्यवधान)... ऐसा नहीं है। मंत्री जी अच्छा जवाब दे रहे हैं, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आठ बजे तक मांग पूरी हो जाती थी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः दस, सवा दस तक पूरी हुई है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसे नहीं होता।

श्री अध्यक्षः अभी इनको एक घंटा ही हुआ है। ...(व्यवधान)...क्या बोले यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक-एक पाइप में घुस रहे हैं, टोंटी में घुस रहे हैं ...(व्यवधान)... यह तो मंत्री जी का काम है आप डिपार्टमेंट को आदेश दो, जांच कराओ उसमें कोई एतराज नहीं है। हमें आपके ज्ञान पर कोई संशय नहीं है। हमें पता है, आपका इसी चीज का काम है तो आपको हर चीज की नॉलेज है। आप डायरेक्शन दीजिए, काम कराइये, अच्छा काम कराओ। पर आप पूरी चीज यह कहो कि हमने यहां इसमें टोंटी लगा दी, इतनी पाइप है।

VPS-RTM-05.03.2025-23.10-5k

वहां बोरिंग में टेंडर की क्या शर्ते हैं, यह सारी चीजें तो... (व्यवधान)... आप तो मोटा-मोटा बत्ता दो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, आप कंटीन्यू करो।... (व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ से आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी का उत्तर सुनना होगा। मान लीजिए किसी को देर हो रही है तो यह स्वतंत्र है। ... (व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं है। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः जो सुनना चाहे सुनें, आपने कहा कि दो बजे तक तो अभी तो बारह भी नहीं बजे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, अच्छा जवाब देंगे तो हम सुन रहे हैं। अच्छा जवाब देंगे तो हम सुन रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अच्छा जवाब ही दे रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, हम तो स्वतंत्र ही हैं। कोई रोकने के लिए रोक थोडे ही सकते हैं। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः चलिये, आप बोलिये। आप अपनी प्रमुख-प्रमुख बातें कह दीजिए क्योंकि एक मंत्री और है अभी। ... (व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमुख-प्रमुख बातें ही कह रहा हूं। यह पानी में अगर मैं जो यह बता रहा हूं, इसमें अगर अवैध कनेक्शन पर हमने रोक नहीं लगायी तो यह कैंसर है आपके और हमारे लिए, सबके लिए तो उसमें वह जब तक नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक यह नहीं होगा। हम सब जन-प्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए तब यह होगा। मैं मेरे मालपुरा क्षेत्र की ही बात करता हूं। मैंने लगभग ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप सुनो तो सही, आप सब लोग बीच में बोलोगे तो और लम्बा चलेगा। आप सब बैठ जाओगे, सुनोगे तो फटाफट होगा। ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में पन्द्रह तो एफ.आई.आर. दर्ज करवायी, मेरे ही कार्यकर्ताओं के और लगभग 3 लाख 26 हजार रुपये की पेनल्टी भी अलग-अलग से वसूल की है। कहीं न कहीं डर तो हमें पैदा करना पड़ेगा और डर पैदा नहीं करेंगे तो यह हमारा बहुत बड़ा कैंसर है, यह हमें देखना ही पड़ेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम आपका समर्थन करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब छोटी-छोटी बातें हैं। पेयजल गुणवत्ता के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेयजल स्रोतों का रासायनिक परीक्षण भी किया। विद्यालयों में, आंगनबाड़ियों में, गांवों के पेयजल स्रोत, महिलाओं को जांच हेतु प्रशिक्षित, जल नमूनों की रासायनिक जांच, जल नमूनों की जीवाणु जांच की है। राज्य की सभी 33 प्रयोगशालाओं को रासायनिक पैरामीटर में- एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। जीवाणु जल नमूनों की जांच- एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की जा रही है, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 15 करोड़ के बजट की घोषणा की गयी है।

ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य 121 ब्लॉकों पर प्रगतिरत है।

विभागीय समीक्षा बैठक- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय के अन्दर सभी जन-प्रतिनिधियों की अब और रेगुलर बैठक बढ़ाएंगे, जहां-जहां भी जाना पड़ेगा तो हम सब जगह जाएंगे। जन-प्रतिधिनियों के साथ में बैठ कर अधिकारियों को लेकर जो भी समस्या है, उसका समाधान करेंगे जिससे पानी की दिक्कत नहीं आये। पूरे 200 के 200 विधान सभा क्षेत्रों में जाएंगे।

नियुक्तियां- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि सबसे ज्यादा प्रमोशन, हमारे विभाग में पी.एच.ई.डी. के अन्दर सबसे ज्यादा प्रमोशन हुए हैं। मैं

हमारे सभी अधिकारियों को जिन्होंने किये हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनको मोटिवेट करने के लिए लगभग, इसकी वजह से हमारे नीचे के काफी पद खाली हो गये। ए.ईएन. के 466 पदों की भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 05.08.2024 को विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है।

कनिष्ठ अभियंता के 217 पदों भर्ती हेतु कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 26.11.2024 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है एवं 350 पद जे.ईएन. के और जो अभी प्रमोशन से खाली हुए हैं, इनकी भर्ती हेतु अर्थना शीघ्र ही कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा रही है।

बाकी, यह जीव विज्ञानी के एक पद, यह छोटे-छोटे पद तो काफी हैं जिनमें भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ...(व्यवधान)... उसके लिए भी कर रहे हैं।

समन्वयक एवं डेटा मैनेजमेंट वगैरह और 615 कार्यकारी प्रबंधक, जिससे हमारे जब तक भर्ती हो तब तक हम 615, उसके लिए भी टेंडर भी कर दिये हैं। तकनीकी समन्वयक के लिए यह जो कह रहे हैं, यह लगभग 1381 पद है, इनकी भी हम भर्ती निकाल चुके हैं।

विभागीय कार्यवाही- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जे.जे.एम. के तहत किये गये कार्यों में अनियमितता की कई शिकायतें प्राप्त हुईं, सभी यह कह रहे है कि इसमें क्या कार्यवाही की गयी? 2022 एवं 2023 में किये गये कार्यों की जांच में संवेदकों को किये गये भुगतान की समीक्षा के दौरान कुल राशि रुपये 49.75 करोड़ का भुगतान विभिन्न सम्बन्धित जलदाय खंडों द्वारा सामग्री प्राप्त किये जाने से पूर्व ही किये जाने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंताओं द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। वर्तमान सरकार द्वारा प्रकरण में दोषी अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह सारी चीजें हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले फील्ड में लगने के लिए बहुत बड़ी सिफारिशें आती थीं पर आज ऑफिस में लगने की आ रही है, यह भी एक इसका बिंदु था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रीन एनर्जी के लिए, जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पर यह हमारे राजस्थान का बजट भी था। बिजली कैसे बचे रेगुलर, इसके लिए भी हमने ढाई हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष जो बिजली का बिल आता है, इसके लिए भी हम सोलर पैनल लगा रहे हैं और सबसे पहले मलसीसर पम्प हाउस पर हम तैरता हुआ सोलर पैनल लगाएंगे जिससे वहां का बिजली का बिल नहीं आयेगा। यह प्रयोग चालू कर रहे हैं और आने वाले समय के अन्दर जिससे गांवों के अन्दर या फिर हम यह प्लान बना रहे हैं कि एक जगह सारी बिजली सौर ऊर्जा से ले ले तो सब जगह पर राजस्थान के अन्दर बिजली की जो दिक्कत आती है, रेगुलर जो पैसा दिया जा रहा है, इसकी भी बचत करने का काम कर रहे हैं।

कानून में कठोर प्रावधान- विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं को गति देने के लिए निम्न कदम भी उठाये जाएंगे-

वर्ष 1979 में जारी राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज एक्ट, 1979 (RWSSC Act) में जल के दुरुपयोग को रोकने, अवैध जल संबंधों पर लगाम कसने, बूस्टर नहीं लगाने तथा

विभाग के कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार व मारपीट करने वालों को दंडित करने के प्रावधानों में न केवल स्पष्टता का अभाव था अपितु इस तरह के गैर कानूनी कार्यों की रोकथाम हेतु ठोस प्रावधान नहीं थे। हमने RWSSC Act, 2025 का प्रारूप तैयार कर लिया है जिसमें उपरोक्त कृत्यों पर सख्त कार्यवाही जैसे अधिक आर्थिक पेनल्टी व कड़ी कानूनी कार्यवाही, जेल का प्रावधान भी किया गया है अवैध कनेक्शन में, अब जो ले रहे हैं। जिससे कुछ ही लोगों द्वारा किये जा रहे ऐसे कृत्यों से दूसरे आमजनों को हो रही परेशानी से निजात मिलेगी और नियमों का पालन करने वालों को सही मात्रा व उचित दबाव से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। अवैध कनेक्शन पर यह कर रहे हैं। हमारे जोगेश्वरजी तो हमेशा यह कहते हैं कि कब ला रहे हो कानून? कब ला रहे हो बिल? उसका भी हम कर रहे हैं। विभाग द्वारा ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप टेबल कर दो। टेबल कर दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्यों कर दें? सुनने की क्षमता रखो।

श्री अध्यक्ष: आप भी अपना भाषण सब लोग टेबल कर दिया करो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं को गति देने के लिए निम्न कदम उठाये जाएंगे-

जल जीवन मिशन के तहत जी.आई. मैपिंग वगैरह, जिससे कि हर आदमी ऑनलाइन देख सके कि कहां पर लाइन डली या नहीं डली, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। 43 हजार किलोमीटर पाइप लाइन का पी.एम. गति शक्ति पोर्टल पर अंकन किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60 लाख परिवारों को घरेलू जल कनेक्शन से लाभान्वित किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मनोजजी यह कह रहे हैं कि धीरे, आराम से बोलें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): एक तरफ तो आप जल्दी का कह रहे हो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं-नहीं, जल्दी नहीं, धीरे-धीरे बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपको सुनना पड़ेगा। आप लोग भी बोले हो।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक घंटा सुनेंगे हम, दो घंटे बोलो आप। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप खास-खास बातें बता दो। ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं को गति देने के लिए निम्न कदम भी उठाये जाएंगे-

नये जल कनेक्शन का सरलीकरण।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आराम से, आराम से।

...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपभोक्ताओं को नया जल कनेक्शन लेने की ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लगातार पढ़ रहे हैं जबकि मंत्री पढ़ते नहीं है, खुद जवाब देते हैं। आप टेबल कर दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तीसरी बार बोल रहे हैं। माननीय मंत्रीजी का जवाब होगा तो बोलने का अधिकार नहीं है आपको। आपको सुनना पड़ेगा मंत्री का जवाब। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मंत्री खुद बोलता है। पढ़ता नहीं है। मैं खुद मंत्री रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री का जवाब आपको सुनना पड़ेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है, मंत्री भी कोई भी, यहां पर पढ़कर जवाब नहीं होता है। पढ़ना है तो आप टेबल ही करवा दो। पढ़ना ही है तो टेबल ही करवा दो। ये संसदीय कार्य मंत्री बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता है। ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं जवाब दूंगा न। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप पुराने रिकार्ड निकाल कर देख लो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप पुराने रिकार्ड निकाल कर देख लो। पढ़कर जवाब नहीं दे सकते। यह परंपरा रही है कि पढ़कर जवाब नहीं दे सकते। ...(व्यवधान)...

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बगैर पढ़े दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी। ये सक्षम हैं, आप बैठिये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बगैर पढ़े दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, संजय जी और आप दोनों क्यों बोल रहे हैं? एक-एक घंटा हो गया। 54 मिनट हो गयी। यह कोई मतलब होता है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: होता है, उत्तर होता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इतना नहीं होता है।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बगैर पढ़े बोल लेते हैं, हमारे क्या है?

श्री अध्यक्ष: आप संक्षेप में बतायें। आप अपना कंटीन्यू करें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बगैर पढ़े ही बोलेंगे अब। माननीय

अध्यक्ष महोदय, अब यह पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं तो मैं बोलता हूं। यह इतने कागज लेकर रखे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप जल्दी समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके मुख्य मंत्री ने पिछले साल का ही पढ़ा था, पढ़कर भी बजट दूसरे साल का पढ़ा था मुख्य मंत्री ने। यह तो तथ्य बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप जितना जल्दी हो, वह बतायें।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में जल कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ता परेशान होते थे, कभी जे.डी.ए. की एन.ओ.सी., कभी नगर निगम की एन.ओ.सी., कभी रोड कटिंग वाले से एन.ओ.सी., इसके लिए छह महीने तो उपभोक्ता चक्कर ही लगाते रहते थे। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लालजी का यह डाइरेक्शन था और उनका यह आदेश था कि यह जो जनता परेशान होती है, इसका समाधान करो। एक ही विंडो पर कैसे काम इसके लिए हमारे सारी कैल्कुलेशन करके 8100 रुपये हमने फिक्स कर दिये, यह दे दो। उसमें एन.ओ.सी. भी हमारा विभाग लेगा, नगर निगम, जे.डी.ए. से भी हमारा विभाग लेगा, नगरपालिका से भी हमारा विभाग लेगा और रोड कटिंग का काम भी हमारा विभाग ही करेगा, जिससे आम आदमी को यह जो दिक्कत आती है इसका भी हमने सिंगल विंडो सिस्टम चालू कर दिया हे।

कंज्यूमर कॉल सेंटर, उपभोक्ताओं की शिकायतों को समय पर निस्तारण करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए कंज्यूमर सेंट्रिक एप्रोच के तहत शिकायतकर्ता की शिकायत को दर्ज करने एवं एंड-टू-एंड निस्तारण सुविधायुक्त कंज्यूमर सेल सेंटर स्थापित किये जायेंगे, यह मैं घोषणा करता हूं।

ssy/rtm/05.03.2025/23.20/5l

श्री अध्यक्षः अब घोषणा ही करो।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मार्च में कर ही देंगे डिमांड।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ हमारे माननीय सदस्यों विशेषकर बाबूसिंह जी, शेरगढ़ से आने वाले सदस्य ने कहा कि राजस्थान में जितने भी पुराने कुए, बावड़ी हैं, जिनकी वर्षों से देखरेख नहीं हो रही है, उनमें अच्छा पानी निकल सकता है, लेकिन पिछली बार बालाजी महाराज की कृपा से खूब बारिश हुई जिससे वाटर लेवल बढ़ा। इसका सदुपयोग कैसे हो इसके लिए हम जितने भी कुए, ट्यूबवैल, बावड़ी आदि हैं, अभी हमारे फतेहपुर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि बाव़डिया हैं, वह सब आप हमें लिस्ट दे देना। जितने भी आप देंगे, उन सबका हम जीर्णोद्धार करेंगे। उनकी पूरी साफ-सफाई करेंगे और उनके अन्दर सौर ऊर्जा से मोटर लगाकर, जहां पर मीठा पानी देने का है, वह काम करेंगे। यह सारे काम करेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: हाथी-घोड़ा-पालकी, जय कन्हैया लाल की।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जितने भी पुराने सी डब्ल्यू आर हैं, एस आर हैं, इनकी भी मेंटेनेंस का जहां-जहां भी खराब हो, वह दे दो, पैसे की कोई कमी नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने कह रखा है कि सबका मेंटेनेंस करेंगे। सबका काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब वाइंड-अप करें। अब वाइंड-अप करिये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से डिस्कॉम के अन्दर कोई भी चोरी के लिए पुलिस की अलग यूनिट बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे, हम माननीय मुख्य मंत्री जी और सबसे निवेदन करेंगे कि उसी के साथ पीएचईडी को भी जोड़ दें, एक्स्ट्रा स्टाफ लगा दें तो कम से कम समय पर अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही तो होगी। इस पर भी हम काम करेंगे।

बजट घोषणाएं तो काफी हैं। जितनी बजट घोषणाएं थी, वह तो आप बजट में पढ़ ली। विशेषकर इसमें तो, अब तो समापन कर देते हैं।

हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जल को ईश्वर का रूप कहा गया है, नदियों को देवी माना गया है, सरोवर और कुण्डों को देवालय का दर्जा दिया गया है। जल संरक्षण केवल नीतियों का ही नहीं बल्कि सामाजिकता का भी विषय है। जागरूक जन मानस, जन भागीदारी और जन आंदोलन अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। आपणो राजस्थान सुझाव 'आपका संकल्प हमारा अभियान' के माध्यम से सरकार ने हर गांव, कस्बे, तहसील और जिले पर ध्यान केन्द्रित किया है और आम जन की आकांक्षाओं को एकत्र किया है।

इसके तहत गांवों में पेयजल की कमी दूर करने के लिए भू जल के लिए भू जल स्तर को बढ़ाना, बोरवेलों का पुनरुद्धार और छोटी नदियों का पुनर्जीवन, गौरव और सुरक्षित पेयजल सेवा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के पर्याप्त संसाधन एवं सामुदायिक भागीदारी, एक ऐसे सौगात देनी चाही जिससे हम 2047 में राजस्थान को पेयजल के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य में शामिल कर सकते हैं। जय हिन्द। जय भारत। वंदे मातरम।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग संख्या 41 को पारित करने का निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब मैं दूसरे मंत्री का नाम पुकार रहा हूं। उनसे भी अपेक्षा है कि समय की नजाकत को समझते हुए अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री श्री सुरेश रावत।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 12 बज जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: सब लोग आज के ही दिन अपने घर पहुंचे इसकी चिंता करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर विभाग आय-व्ययक अनुमान 2025-26 पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: घड़ी के बजाना।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे

प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने प्रदेश के लगातार दूसरे बजट में जल संसाधन विभाग को बहुत अधिक बजट दिया और बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने गत जुलाई माह में संशोधित बजट पेश किया, जिसमें जल संसाधन विभाग ने दीर्घकालीन रोड मैप तैयार कर 6 माह की अल्प अवधि के अन्दर काम शुरू किया। इसकी निरंतरता में समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए वित्तीय वर्ष में जल संसाधन विभाग के 8,127.78 करोड़ रुपये एवं इंदिरा गांधी नहर विभाग के 1,872.20 करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल लगभग 10,020 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मांग संख्या 42 में आप सब लोगों ने कटौती प्रस्ताव रखे, सारे कटौती प्रस्तावों के हमने जवाब तैयार कर लिये हैं, जल्दी ही इनको भिजवा देंगे। इसके अलावा भी सदन के अन्दर जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये, हमने सबके जवाब तैयार करवा लिये हैं, वह भी आपको भिजवा देंगे। क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है इसलिए मैं सबका पढ़ना नहीं चाहूंगा, आप सबको भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्षः सवेरे के नाश्ते की भी व्यवस्था करवा दें?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है और इन पंच तत्वों में जल एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह हम सभी जानते हैं। जल के बिना हम जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल ही जीवन है, प्राण है, स्पंदन है, गति है, सृष्टि है। जल जीवन का मूलाधार है। इसके बिना प्राणियों एवं वनस्पतियों के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 'जल बिना जीवन नहीं, जल देता है प्राण, बड़ा ही शक्तिवान जल, करे सृष्टि निर्माण।' हमारी घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं। हमारी घोषणाएं हमारा प्रण है, संकल्प है जिनकी सिद्धि के लिए हम निरंतर संघर्ष करते आये हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा में हम बजट के माध्यम से राज्य में सिंचाई वृहद परियोजनाओं की समयबद्ध क्रियान्विति के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रदेश में मानसून की अनिश्चितता, भूमि में जल की कमी और क्षेत्रीय असंतुलन को देखते हुए हमारी सरकार का पहले से ही प्रयास रहा है कि संपूर्ण राजस्थान में हम वर्ष भर पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए जल दें, प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के साथ ही प्रदेशवासियों की खुशहाली ही हमारा संकल्प है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जल हमारी साझा विरासत और सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत में वैदिक काल से ही वर्षा ऋतु में नदी, नालों में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोककर इनके एनिकट बनाना, जल भंडारण करना और बारिश के जल को स्थाई रूप से संचय करने की हमारी परंपरा रही है। प्राचीन ग्रन्थों में नहर निर्माण, इस एकत्रित जल को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने, कृत्रिम एवं प्राकृतिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, संचित जल के सदुपयोग का हर

जगह उल्लेख मिलता है। पूर्वजों की इन्हीं परंपराओं का समावेश कर हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी, इसी के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बेहतर जल प्रबंधन एवं प्रदेश में जल संकट की चुनौती के स्थाई समाधान हेतु राजस्थान को एक जल सुरक्षित राज्य बनाने के लिए हम युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। 'जिस दिन से चला हूं, मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी आस्था और आचरण में ही जल के संरक्षण का मंत्र छिपा है। हमारी परंपरा में जल और जल के स्रोत, नदी, जलाशयों, कुओं आदि पवित्र, जीवंत और सकारात्मक शक्ति माने गये हैं। भारतीय लोक जीवन में किसी भी सुख और मांगलिक कार्य की शुरूआत जल कलश की पूजा से होती है। लोक आस्था और सामाजिक एकता के प्रतीक जल कुंभी एकादशी एवं कुंभ मेले जैसे पर्वों से जलाशयों, नदियों और जल के महत्व को समझा जा सकता है। जल कुंभी एकादशी पर माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में पहली बार जहां-जहां हमारे तालाब और बांध भरे हैं, वहां पर सब जगह यह कार्यक्रम हुए, हमारी माताएं, बहनों ने नाच गानों के साथ सरोवरों की पूजा की और ईश्वर एवं हमारे इन्द्र देव का धन्यवाद ज्ञापित किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कौटिल्य ने भी अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में शासक को इस बात की भरपूर अनुशंषा की है कि वह कृषि की सुविधा हेतु नदियों आदि से लाये हुए एवं वर्षा के जल को रोककर सेतुबंध का निर्माण करे। विरासत की इसी कड़ी में अकाल और बाढ़ से जूझ रहे प्रदेश की मुश्किलों को दूर किये बिना बहकर समुद्र में जाने वाले जल के समुचित उपयोग की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

spp/rtm/05.03.2025/23.30/5m

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भारत के पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में नदियों को जोड़ने की कल्पना की गई थी और इस बात की सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशंसा की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अपन सभी जानते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि 'घी ढुल्यां म्हारो की नहीं जावे, पानी ढुल्यां म्हारो जीव बले।' इस कहावत से हम सोच सकते हैं कि हमारी क्या परिस्थितियां हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जल के बारे में, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य है, जिसका 10.4% भूमि क्षेत्र है और 5.7% आबादी होने के बावजूद राज्य में सतही जल मात्र 1.16% है, जो बड़ा चिंता का विषय है। भूजल की बात करें तो 1.72% है, ये भी अत्यधिक चिंता का विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम वर्षा की बात करें तो प्रदेश की औसत वर्षा लगभग

541 मिलीमीटर है। अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये मात्र 200 मिलीमीटर पर ही सिमट जाती है। इस वर्ष हमारे प्रदेश में इंद्रदेव की कृपा रही। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी का पगफेरा शुभ रहा और प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 663 मिलीमीटर बारिश हुई। अधिकतर हमारे जो बांध है, तालाब हैं, वो लबालब हो गए। इससे हमारे पशु-पक्षियों को संतोष, फसलों को अमृत, किसान और गृहणियों के चेहरे पर मुस्कान और बाजार को उम्मीद मिली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में कृषि योग्य संचित भूमि 272.11 लाख हैक्टेयर है, जिसमें से वर्तमान में सतही जल परियोजनाओं द्वारा संचित क्षेत्र लगभग 39.36 लाख हैक्टेयर है। राज्य में सतही जल लगभग 25.38 मिलियन क्यूबिक मीटर है तथा राज्य के विभिन्न अंतरराज्यीय समझौते के तहत 17.88 बिलियन क्यूबिक मीटर जल निर्धारित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे देखते हुए जल की बर्बादी को रोकने, नदियों से समुद्र में बहकर जाने वाले पानी, अधिक क्षेत्र में, सूखे क्षेत्र में कैसे पहुंचे, इसके लिए हम माइक्रो पद्धति पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी सरकार ने जल भंडारण हेतु नए बांध बैराज, एनिकट निर्माण के साथ पूर्व निर्मित जल ढांचों की क्षमता बढ़ाने के कार्य भी हाथ में लिए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जल प्रवर्तन, जल की कमी को झेल रहे क्षेत्र के लिए प्रवीण तंत्र के निर्माण, सोलर आधारित स्प्रिंकलर सिंचाई, नए कमांड क्षेत्र के विकास, पुराने कमांड क्षेत्र की पुन:स्थापना, जल परियोजनाओं को जल की उपलब्धता, नहरी तंत्र के निर्माण के साथ मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव कार्य, बाढ़ बचाव कार्य, लुप्त प्राय: नदियों के पुनर्जीवन तथा जलभराव की क्षमता के स्थाई समाधान के प्रयास जारी हैं।

इसी क्रम में हमने बजट में बाढ़ सम्भावित क्षेत्र में, सूखा वाले क्षेत्र में जल के लिए अप्रवर्तन की जल प्रबंध परियोजनाओं को विस्तार दिया है। हमारी सरकार के विशेष प्रयासों से जल, सिंचाई, उद्योगों को जल देने की योजनाएं अब धरातल पर दिखाई देने लगी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय- `
वाकिफ का है ज़माना हमारी उड़ान से है
वाकिफ का है ज़माना हमारी उड़ान से
वो और थे जो हार गए आसमान से।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आज इस बहस में रामसेतु राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी बात कही, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, उन्होंने अपनी बात कही। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने पहले भी कहा कि माननीय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो की परिकल्पना भाजपा सरकार के प्रयासों से ही ईआरसीपी संशोधित PKC के बाद अब राम सेतु जल लिंक परियोजना के रूप में हमारे समक्ष मूर्त रूप ले रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुददे पर पूर्व में भी मैं सदन को अवगत करा चुका हूँ कि इस परियोजना के इतिहास को उठाकर देखें तो विपक्ष की अकर्मण्यता के कारनामों की झलक देखने को मिलती है। माननीय पूर्व प्रधान मंत्री वाजपेयी जी ने वर्ष 1999 से 2004 के शासन में नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की थी। इसके बाद 2017 में माननीय वसुंधराजी के कार्यकाल में हमने इस योजना को आगे बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष महोदय को कहना चाहता हूँ 2004 से 2013 तक केंद्र में आपकी सरकार थी। 2009 से 2013 में आपकी सरकार थी राजस्थान में। 2018 से 2023 तक राजस्थान में आपकी सरकार थी। फिर भी आपने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए कुछ नहीं किया। जन कल्याणकारी योजनाओं का केवल श्रेय लेने में प्रयासरत रहे, श्रेय नहीं मिलने की स्थिति में योजना को रुकावट डालना आपकी आदत में रहा है। 2019 में आपकी सरकार थी, 2019 में आपकी सरकार थी मध्यप्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपकी दल की सरकार थी। आपने इस परियोजना के लिए कुछ भी सार्थक प्रयास नहीं किये, परंतु पलटकर कमलनाथ जी ने पानी कम करने की योजना तैयार करने हेतु पत्र लिखा। वो पत्र भी मेरे पास है। हालांकि इस नूरा कुश्ती का परिणाम यह हुआ कि थोड़े दिन बाद कमलनाथजी चले गए। 2023 में आप चले गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो कमलनाथ जी का पत्र है। ये गहलोतजी का पत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2023 में विधान सभा चुनाव सिर पर था। तब जादूगरों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। जादूगरों के सम्मेलन में ये मंथन हुआ कि हमने तो 5 साल कुछ किया नहीं, अब 2023 में चुनाव में जाना है, कैसे जीते? तो कुछ करने को था ही नहीं, तो किसी के समझ में आया नहीं और बड़े जादूगर आए। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, उसमें ईआरसीपी को फिट करते हैं। उस ईआरसीपी को फिट करके पूर्वी राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पानी और शहर-शहर गए, बड़े बड़े आदमकद के होर्डिंग लगाए, रैलियां कीं और जनता को यह दिखाने की कोशिश की गयी कि साहब ईएआरसी का पानी हम ला रहे हैं, ईआरसीपी पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस झांसे के अंदर नहीं आए और उन्होंने इनको आईना दिखा दिया और इसी का परिणाम है कि आप उधर बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा योजना पर सहमति बनने के प्रयास किए गए, जल शक्ति मंत्रालय की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से मुख्य मीटिंगों में सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहा। इसलिए हम मानते हैं की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ईआरसीपी योजना को लटकाया गया। केवल मात्र राजनीति की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ईआरसीपी के लिए, मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूँ आपके मार्फत कि ईआरसीपी के लिए आपकी सरकार के समय धनराशि इकट्ठा करने के लिए आपने जल संसाधन विभाग की जमीनों को बेचने का काम किया और अरबों रुपए की जमीनों को कौड़ियों में बेचने का काम किया। जब हमारी भजन लाल जी की सरकार आयी

तो उनको निरस्त करके ठीक करने का काम हमने किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्विवादित है कि इस प्रकार की बड़ी अंतर्राज्यीय परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरण संपत्ति संबंधी मुद्दे भी होते हैं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विषय भी होता है, आपसी हितों का टकराव जैसी समस्या भी आती है। परंतु हमारी सरकार ने इसका निराकरण करते हुए निरंतर संवाद कर सहमति बनाने के विशेष प्रयास किये और इस परियोजना में से कृषि जल की उपलब्धता, प्रदेश की आर्थिक समृद्धि वह सामाजिक दायित्व को मजबूत करेगी। इससे महिलाओं और किसानों को वर्षों पुरानी समस्या और चिंता से निजात मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय महत्त्व का मानती है। ये बात हमारे विपक्ष के साथियों को समझ में नहीं आती और इसका दिनांक 5 दिसंबर, 2024 को हस्ताक्षर भी हो गए MOU पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने इस योजना का शिलान्यास भी कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के प्रथम चरण में 1,060 करोड़ की लागत से बने कालीसिंध पर निर्मित नौनेरा बैराज का माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 27 दिसंबर, 2024 को लोकार्पण हो गया है। इसी क्रम में 9,416 करोड़ की लागत से निर्माण कार्यों का शिलान्यास हो चुका है जिसमें नदी पर रामगढ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज और चंबल नदी पर जल सेतु सहित नवनैरा बैराज से बीसलपुर बांध तथा ईसरदा बांध से जल प्रबंधन का तंत्र शामिल हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा की ये 9,416 करोड़ के जो टेंडर हैं, इनके टाइम में लगे। यह ठीक है कि ये टेंडर आपके टाइम में लगे, लेकिन जब आप चुनाव में जाने वाले थे, तब आपने टेंडर लगाए और आपने कोई वित्तीय प्रावधान किया। आप ने टेंडर लगा दिये, आप को अच्छी तरह पता था कि चुनाव सिर पर है, फिर भी आप ने टेंडर लगा दिए, सिर्फ दिखाने के लिए। जब हमारी सरकार आयी, भजन लाल जी की सरकार आयी तो क्योंकि हम जो अच्छी योजना है, उसको अटकाते नहीं हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। माननीय भजन लाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रदेश के हित के लिए उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। हमने टेंडर के वर्क ऑर्डर भी दिए और जल्द ही इसका काम चालू हो जाएगा।

jyg/rtm/05.03.25/23.40/5n

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना के तहत राज्य को कुल ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): राष्ट्रीय परियोजना है न?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): देखिये, मैंने पहले भी कहा है कि अंतर्राज्यीय

नदी जोड़ो परियोजना को भारत सरकार, राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्तर का मानती है और आपको राष्ट्रीय परियोजना से करना क्या है जब 90 परसेंट भारत सरकार दे रही है 10 परसेंट राज्य सरकार दे रही है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं कि 90:10 दे रही है ना?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): हां, बिलकुल शत प्रतिशत दे रही है। आज ही हमारे पास एक पत्र आया है उसका ऑन रिकॉर्ड आपको उल्लेख नहीं कर सकता, अलग से मैं आपको बता दूंगा, 90:10 भारत सरकार देगी। इस परियोजना के तहत राज्य को कुल 4102.60 एमसीएम जल प्राप्त ....(व्यवधान)... सुनो, पेट में दर्द मत करो आप। हम काम कर रहे हैं इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। इसमें आप तो कर नहीं पाये, 522.80 एमसीएम पुन:चक्रीय जल भी सम्मिलित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पीने के पानी की उपलब्धता को प्रधानता दी है। परियोजना में आवंटित जल में से लगभग 44 प्रतिशत का हिस्सा पेयजल हेतु रखा है। हमने ईआरसीपी के प्रस्ताव में सिंचित क्षेत्र 2 लाख 80 हजार को बढ़ाकर संशोधित पीकेसी में 4 लाख 3 हजार हैक्टेयर तक कर दिया है। इसमें 3 वृहद, मध्य तथा अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के साथ कई तालाबों में जल अपवर्धित करने का प्रावधान भी रखा है। इसके लिए 44 हजार 517 करोड़ के कार्यों के लिए स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इसमें से 9 हजार 416 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं और 12 हजार 64 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है जिससे आधारभूत ढांचा तैयार कर परियोजना में पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव सभ्यता की नदियां आधारशिला है। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे फली-फूली हैं, यह हम सभी जानते हैं। नदियां पर्यावरण, जीव-जंतु और वनस्पतियों की रक्षा करने वाली हैं, सर्व कल्याणकारी हैं, सर्व सुखदायिनी होने से नदियों को हम सबने मां का दर्जा दिया है। इस परियोजना में शामिल दस नदियों में से बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, गम्भीरी, सावी जैसी नदियों को जीवनदान मिलेगा। इनके पुनर्जीवित होने से भूमि जल का पुनर्भरण भी होगा। इस प्रकार परियोजना पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक जल की उपलब्धता से राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए वरदान साबित होगा। दोनों राज्यों के लिए नदिया और सहायक नदियों का यह संगम राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ जल की चुनौती के स्थायी समाधान के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी, दोनों ने मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाया, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही राजस्थान से 'रा' और मध्य प्रदेश से 'म', दोनों को संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं तो जल लिंक परियोजना का नाम 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' का नाम दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोगों को 'राम' शब्द से चिढ़

है। यह सर्व विदित है कि कुछ लोगों को राम और सनातन से पुरानी नफरत है, जबकि राम शब्द इतना मनमोहक है, सुन्दर है, हमारे नेता प्रतिपक्ष के नाम के आगे भी 'राम' लगता है। इनके साथ ही हमारे सदन के माननीय 26 सदस्य ऐसे हैं जिनके नाम के आगे 'राम' शब्द आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्राथमिकता संवाद की है। जबकि प्रतिपक्ष की विवाद की है। अच्छे कार्यों में सहयोग के बजाय विरोध करना आपकी कार्यप्रणाली रही है। ...(व्यवधान)... हम व्यवधान नहीं हम समाधान चाहते हैं। काम में रोड़े अटकाने में नहीं, अवरोधों को हटाने में यकीन रखते हैं माननीय।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमने तो कोई विरोध नहीं किया है।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): ...(व्यवधान)...

हम उगते हैं, हम बढ़ते हैं,
हम नभ की चोटी चढ़ते हैं,
कुचले जायें यदि धूलि से,
आंधी से पुनः उड़ते हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यमुना समझौते की भी बता दो। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): ...(व्यवधान)... बता रहा हूं, बता रहा हूं, सब बताऊंगा। सब बताऊंगा, आपमें हिम्मत है तो भले आप चार बजे तक रुको, मेरे पास पूरा पिटारा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने प्रदेश की जनता से असत्य वायदे कर उन्हें गुमराह करने का कार्य किया। जनता से की गयी वादाखिलाफी के कारण आपकी पराजय के बाद राज्य में हमारी सरकार के दुबारा सत्ता में आने पर हमारे पिछले कार्यकाल में प्रारम्भ की गयी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को न केवल पुनः प्रारम्भ किया, बल्कि उसको अधिक विस्तार भी दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि-

रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है,
सर में सौदा हो दीवार में दर बनता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और जालौर में कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने सिक्योरिटी मनी के नाम पर फर्जी एफडीआर लगाकर टेंडर प्राप्त कर लिये, आपकी सरकार में तो जिम्मेदार लोग चुप बैठे थे। माननीय भजन लाल जी की सरकार आयी, तो हमने कड़ी कार्यवाही करते हुए चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता को, अधीक्षण अभियंता को, अधिशाषी अभियंता को तुरंत निलम्बित किया। सम्बन्धित फर्म के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी और उसको ब्लैकलिस्ट किया। बंध बारेठा मध्य सिंचाई परियोजना के अन्दर डिले बरत रहे थे, हमने उनका टेंडर निरस्त किया, इसके अलावा भी हम प्रभावी मॉनिटरिंग करके सभी कार्य समयबद्ध तरीके से हो, उस पर हम काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कुछ सदस्यों ने बीसलपुर बांध में ड्रेजिंग हो रही है उसके बारे में बातकी, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि राज्य के अति महत्वपूर्ण बांध में विगत तीस वर्षों से गाद जमा हो रही है और उसकी लगातार भराव क्षमता कम हो रही है। इसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि बीसलपुर बांध में जमा गाद का अध्ध्यन भारत सरकार की तीन संस्थाओं द्वारा कराया गया था। तीनों संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर बीसलपुर बांध में जमा गाद का आकलन किया गया एवं खुली निविदा प्रक्रिया अपनाकर बीसलपुर बांध की ड्रेजिंग के कार्य आदेश विगत सरकार के समय फरवरी 2023 में दिये थे, लेकिन आपके समय में आप उसमें कोई काम नहीं कर पाये। जब हमारी सरकार आयी तो हमारी सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया, जिससे बीसलपुर बांध में ड्रेजिंग के भराव क्षमता में वृद्धि हुई और जनवरी तक निगम को 28 करोड़ रुपये जीएसटी प्राप्त हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सोम कमला और अन्य बांधों की भी हम ड्रेजिंग कर रहे हैं। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं,

नजर फिरी, फिर नजर न आये,
गिरे जो जमाने की नजर से,
नजर में रहकर नजर मिलाये,
देखकर नजारा मेरी नजर से।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नजर बदलो तो नजारे बदल जायेंगे।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): मैं ब्राह्मणी नदी के बारे में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... चम्बल नदी की सहायक नदी, ब्राह्मणी और राणा प्रताप सागर से कभी 1 हजार एमसीएम कभी 2 हजार एमसीएम और कभी इससे भी ज्यादा पानी बिना उपयोग के बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। नदिया भी यहीं थी, आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, बांध भी यहीं था, बस नहीं थी तो आपकी काम करने की नीयत। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए बरसों तक किसी ने सोचा ही नहीं कि ब्राह्मणी नदी का ग्रेविटी से पानी बीसलपुर में भी आ सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का कि वो स्वयं गये, पूरे रूट को देखा और जल्द ही हम इस योजना पर आगे बढ़ने वाले हैं। ...(व्यवधान)... हमारी सरकार ने पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए ब्राह्मणी नदी को 54.96 भराव क्षमता का बैराज बनाने और ब्राह्मणी नदी और राणा प्रताप सागर में व्यर्थ बहकर जाने वाली पानी को ग्रेविटी से बीसलपुर में प्रयुक्त करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ऊपर वाला पेज पढ़ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश है उस आदेश की पूरी पालना कर रहा हूं, सबका ध्यान रख रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यमुना जल की बात कही, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि शेखावाटी क्षेत्र की जल समस्या के समाधान के लिए

कांग्रेस ने सिर्फ चुनावी घोषणाएं की, न तो उसके लिए प्रयास किये और न ही कुछ काम किया। 30 वर्ष से कांग्रेस के अकर्मण्यता के कारण पानी नहीं आया। ...(व्यवधान)... आप लोग पूछ रहे हैं प्रश्न जबकि प्रश्न पूछने का अधिकार आपको किसने दिया? कोई काम करो तो पूछो, आपका अधिकार है, आपने कुछ किया नहीं, पांच साल तक कमरों में बंद रहे, कभी होटलों में बंद रहे, आप लोगों ने कुछ किया नहीं और आप आरोप सरकार पर लगा रहे हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ यहां बैठकर यमुना जल की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब हरियाणा के अन्दर चुनाव था उस चुनाव के अन्दर आपके दल ने, आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र के अन्दर लिखा, अगर हरियाणा में इनकी सरकार आयेगी तो यमुना समझौते को रद्द कर देगी, उसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता की हाय लगी और आपकी सरकार नहीं आयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी पर राजनीति करना बंद करें। मैं आपको कहना चाहता हूं,

तोड़कर जोड़ लो चाहे, हर चीज दुनिया की,
हर चीज काबिले मरम्मत की, एतबार के सिवाय,
अजब सुकून था, उसके फेर में,
मुझको न था यकीन
मगर फिर भी एतबार किया।

MLS/RTM/05.03.2025/23:50/5o

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... मैं आपके माध्यम से जल संचयन से जल संरक्षण के बारे में बताना चाहता हूं कि राजस्थान में हमारे पूर्वज परम्परागत तकनीकों से वर्षा जल को सहेजने के लिए विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण करते रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक गड्ढों की पालबंदी कर नाड़ी, छतों, आंगनों और जल ग्रहण क्षेत्रों से वर्षा जल एकत्र करने हेतु टांके, स्थानीय जल आपूर्ति के लिए बावड़ी, जल ग्रहण क्षेत्रों से अपवाह को निचली घाटी तल में संग्रहित करना शामिल है। झल्लारे, तालाब और कुण्ड सामाजिक गतिविधियों एवं धार्मिक आस्था के केन्द्र रहे हैं। ये जल संरक्षण कार्य स्थानीय जलापूर्ति और पशु जल के स्रोत थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को। उन्होंने ''कैच द रेन'' अभियान चलाकर, इससे प्रेरित होकर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी को, जिन्होंने कर्म भूमि से मातृ भूमि एक अभियान चलाया और अप्रवासी राजस्थानी जितने भी हैं, उनसे, इसमें कोई सरकार का पैसा नहीं लग रहा, आप भी इसमें सहयोग करिये, आपके भी कोई सम्पर्क में हों तो आप भी जो शाफ्ट से रीचार्ज करने का जो सिस्टम है, उसमें सहयोग करिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके टाइम में

क्या स्थिति थी, हमारे टाइम में क्या स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नवनैरा परियोजना है। 04.10.2018 को 664 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर दिया हमारी सरकार ने। 13.10.2022 को इसको कम्प्लीट करना था। आप पांच सालों में उसको पूरा नहीं कर पाये। अक्टूबर 2024 में जब हमारी सरकार आयी, तब हमने उसको पूरा किया। परवन परियोजना की बात करें तो वर्ष 2017 एवं 2018 में हमने इसके वर्क ऑर्डर दे दिये। 2022 तक पूर्ण होना था। आप पूरा नहीं कर पाये। इस योजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु हम कृत संकल्पित हैं और 2025-26 में 850 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से हम इसको जल्द पूरा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ईसरदा पेयजल परियोजना की बात करें तो 1038.65 करोड़ रुपये का 2017 में हमने इसका वर्क ऑर्डर दे दिया। आप पूरा नहीं कर पाये। अब 2025 में हम पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर लिफ्ट परियोजना की बात करें तो 2017 में हमने इसका वर्क ऑर्डर दिया। 2020 में पूरा करना था। आप पूरा नहीं कर पाये। अब इसको हम जल्द ही पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना एवं पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना की बात करें तो 28.08.2018 को हमने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। यह बड़े खेद की बात है कि जो आदिवासी अंचल की महत्त्वपूर्ण परियोजना थी, आप चार साल तक उसे लेकर बैठे रहे। लास्ट में आपने उसका वर्क ऑर्डर दिया। अब हम जल्दी ही उसको पूरा करेंगे। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना की बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जिनमें इनकी लापरवाही है। अभी समय के लिए आपका आदेश है, इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना और पेयजल व सिंचाई जल आपूर्ति के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कहीं। इसके बारे में मैं सदन को तथ्यात्मक टिप्पणी से अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पोंग बांध में 62 प्रतिशत, रणजीत सागर में 19 प्रतिशत एवं भांखड़ा बांध में 71 प्रतिशत पानी संग्रहित हुआ है। पानी की कमी के बावजूद इस वर्ष रबी की सिंचाई हेतु 3 से 11 एक समूह में पांच बारी पानी दिया। आज की स्थिति में इन्दिरा गांधी नहर हेतु निर्धारित शेयर का उपयोग किया जा चुका है तथा पेयजल हेतु पानी की मात्रा भी इस शेयर के अतिरिक्त ही होगी।

हमने विशेष प्रयास करके बीबीएमबी बोर्ड में अतिरिक्त पानी की मांग रखी, परन्तु बांध में पानी की उपलब्धता के मद्देनजर केवल इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली में 3 हजार क्यूसेक पानी उपलब्ध हो रहा है तथा 10 मार्च के बाद के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पानी की मांग की जायेगी। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इन्दिरा गांधी

नहर विभाग के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस परियोजना के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से सिंचाई सम्बन्धी 16 कार्यों के लिए इस वर्ष के बजट में 1 हजार 595 करोड़ की घोषणाएं की गई हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना-द्वितीय चरण में 10 लाख 71 हजार हैक्टेयर तथा प्रथम चरण में कंवर सेन लिफ्ट के 62 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र की नहरों के निर्माण, रख-रखाव व जल संचालन का कार्य किया जाता है। परियोजना में उपलब्ध पानी के कुशलतम व अधिकतम उपयोग हेतु द्वितीय चरण की लिफ्ट योजनाओं में स्प्रिंकलर (प्रेशर) सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु 27 हजार 449 हैक्टेयर में पायलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत कार्य पूर्व में किये जा चुके हैं। शेष 3 लाख 20 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से लगभग 2 लाख हैक्टेयर में स्प्रिंकलर (प्रेशर) सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने के कार्य करवाये जा रहे हैं। परियोजना के द्वितीय चरण के प्रवाह क्षेत्र की चारणवाला शाखा की नहरें जो विगत कई वर्षों से लगातार जल प्रवाह व समुचित रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो गयी थीं, उनके नवीनीकरण व आधुनिकीकरण हेतु 94.02 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जा रहे हैं।

वर्ष 2025-26 हेतु विभाग को आयोजना मद अन्तर्गत 1106 करोड़ 36 लाख रुपये आवण्टित किये गये हैं, जिससे नहरों के निर्माण, रख-रखाव व जल संचालन के अतिरिक्त नहरों व खाळों के जीर्णोद्धार, प्रेशर सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने, स्काडा प्रणाली इत्यादि के कार्य किये जाएंगे। अगर हम बरसलपुर शाखा नहर प्रणाली क्षेत्र की बात करें तो 72 हजार 246 हैक्टेयर क्षेत्र में रुपये 250 करोड़ की लागत से क्षतिग्रस्त खाळों के जीर्णोद्धार की डीपीआर व निर्माण कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। धोधा वितरिका एवं दांतौर वितरिका शाखा नहर प्रणाली क्षेत्र के 65 हजार 113 हैक्टेयर क्षेत्र में रुपये 230 करोड़ लागत से क्षतिग्रस्त खाळों की डीपीआर व निर्माण कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिन्ता मत करें, आपका जो आदेश है, उसमें मैं खत्म कर दूंगा। 12 बजे का आदेश था, 12 बजाना है न? ...(व्यवधान)... हां, तो 12 बजा देंगे। चिन्ता मत करो। मुख्य नहर की आरडी 961 से 1050 के मध्य से निकलने वाली चारणवाला ब्रांच प्रणाली, गोगड़ियावाला माइनर एवं बीकमपुर माइनर के 44 हजार 250 हैक्टेयर क्षेत्र में रुपये 150 करोड़ लागत से क्षतिग्रस्त खाळों की डीपीआर व जीर्णोद्धार कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर प्रणाली के रिमॉडलिंग का कार्य रुपये 100 करोड़ लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 620 से 1458 तक रुपये 75 करोड़ लागत से नहर के दोनों पटड़ों के सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

बाबा रामदेव ब्रांच की आरडी 35 से 231 के मध्य निकलने वाली नहरों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य रुपये 75 करोड़ की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माफ करना, थोड़ी गाड़ी तेज चल रही है, क्योंकि समय-सीमा आ रही है।

श्री अध्यक्षः वैसे आजकल बुलेट ट्रेन का जमाना है।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बाबा रामदेव ब्रांच की आरडी 0 से 302 के मध्य जीर्णोद्धार का कार्य रुपये 65 करोड़ की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। कोलायत वितरिका नहर का पुनरुद्धार कार्य रुपये 35 करोड़ लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर के शेष रहे क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा विकसित करने का कार्य रुपये 35 करोड़ लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। खिदरत वितरिका नहर का पुनर्निर्माण कार्य रुपये 25 करोड़ लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है।

चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर के आरडी 34.00 से 36.850 के मध्य बैलेंसिंग रिजर्वायर का निर्माण कार्य रुपये 25 करोड़ लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना-द्वितीय चरण में बीकानेर तथा जैसलमेर में मुख्य नहर हेतु बैलेंसिंग-स्टोरेज रिजर्वायर के निर्माण कार्य हेतु रुपये 10 करोड़ लागत से डीपीआर तैयार करवायी जानी प्रस्तावित है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना-द्वितीय चरण की आरडी 620 से 1458 के मध्य कमांड क्षेत्र के विभिन्न चकप्लान, तारबन्दी, खतौनी एवं सरकारी भूमि खातों के डिजिटाइजेशन कार्य की डीपीआर रुपये 15 करोड़ लागत से तैयार करवायी जानी प्रस्तावित है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना-द्वितीय चरण की सभी लिफ्ट नहरों के पम्प हाउस में उपयोग होने वाली बिजली उपयोग कम किये जाने हेतु सोलर पार्क बनाये जाने की डीपीआर रुपये 15 करोड़ लागत से तैयार करवायी जानी प्रस्तावित है। अन्त में, मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों का उल्लेख करना चाहता हूं-

है कौन विघ्न ऐसा जग में,
टिक सके वीर नर के मग में,
मानव जब जोर लगाता है,
पत्थर भी पानी बन जाता है,
पत्थर भी पानी बन जाता है।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अन्त में आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 42 को पारित करवाकर मुझे अनुगृहीत करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MKD/RTM/06.03.2025/00:00/5p

श्री अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): (..व्यवधान..) पानी वाले दोनों पत्थर ही बने रहे,

12 बजवाकर माने खुद की।

श्री अध्यक्षः सुनो, आज मुझे प्रसन्नता है कि अब तक जितनी डिमांड्स यहां पर पारित हुई हैं, उनमें जितने सदस्य अन्त में, पारित करते समय उपस्थित थे, आज सबसे ज्यादा सदस्य उपस्थित हैं।

मैं आप सब का अभिनन्दन करता हूं। मुझे लगता है कि यदि 12 बजे तक चलेगी तो शायद अधिक लोग रहेंगे। ऐसा कई बार मुझे लगता है।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अध्यक्ष जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये दो मंत्री और लोगों से डिफरेंट हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये स्टाफ वाले सारे अधिकारी, कर्मचारी, ड्राइवर, गनमैन, यहां विधान सभा के सब परेशान होते हैं।

मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी का पारण

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,18,66,49,47,000/- (एक सौ अठारह अरब छियासठ करोड़ उनचास लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त 73,82,72,73,000/- (तिहत्तर अरब बयासी करोड़ बहत्तर लाख तिहत्तर हजार) राज्यपाल महोदय को रुपये तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 06 मार्च 2025 के प्रातः (..व्यवधान..), मैं कल नहीं कह रहा हूं, गुरुवार कह रहा हूं, कल तो कहा ही नहीं।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 06 मार्च 2025 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 00.02 बजे गुरुवार, दिनांक 06 मार्च 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-41 मुख्य शीर्षक **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी** के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

1. विधान सभा क्षेत्र महवा में जेजेएम स्कीम से वंचित सभी जगह सोलर सिंगल फेस ट्यूबवैल की स्वीकृतियां जारी कराने तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय खोहरा, मुल्ला में पीएचईडी का नवीन सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

2. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में जल जीवन मिशन में लम्बित कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

3. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

4. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में प्रत्येक गांव एवं ढाणी में स्वीकृत बीसलपुर परियोजना के कार्य लम्बित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डॉ. जसवंत सिंह यादव (वि.सं.61)

5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जेजेएम योजना के अन्तर्गत वर्तमान में बन्द पड़ी योजनाओं को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ड्राई चले गए बोरवेल वाले गांवों को जेजेएम योजनान्तर्गत पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के छह गांव, जिनकी जेजेएम योजना की निविदा होने के उपरान्त अब उन्हें निरस्त कर दिया गया है, को पुनः चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के जिन गांवों में जेजेएम योजना का कार्य अभी तक चालू नहीं किया गया, उन्हें तुरन्त चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के जिन गांवों में पानी उपलब्ध नहीं है, उन गांवों में उचित जगह पर बोरवेल हेतु बजट बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (वि.सं.125)

10. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में 100 हैण्डपम्प एवं 20 सबमर्सिबल बोरिंग स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

11. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेयजल के लिए पोकरण-फलसुण्ड-बायतु-बालोतरा-सिवाना परियोजना का पानी स्टोरेज (वनडे) निर्माण, शोभावास/कालूड़ी या भूकाभगत सिंह में किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की पंचायत समिति-समदड़ी में सहायक अभियन्ता (एईएन) एवं पादरू में कनिष्ठ अभियन्ता (जेईएन), मोबुलसर में कनिष्ठ अभियन्ता (जेईएन), होड़ु में कनिष्ठ अभियन्ता (जेईएन) के कार्यालय पद सहित स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत सभी गांवों में कार्य शुरू करवाने, कनेक्शन से वंचित घरों को जोड़ने के लिए खण्डवार रिवाईज स्कीम स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेयजल की कमी एवं स्वीकृत स्कीम से पानी नहीं आने के कारण नए नलकूप, नए हैण्डपम्प स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में खराब पड़े आर.ओ. प्लान्ट, सौर ऊर्जा चालित नलकूप एवं हैण्डपम्पों को ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)

16. विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में नवीन नलकूप व हैण्डपम्प खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)

17. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में पेयजल आपूर्ति हेतु ड्राई हो चुके 38 ट्यूबवैल के स्थान पर नए ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

18. विधान सभा क्षेत्र भीम में चम्बल परियोजना में अपूर्ण कार्य को पूर्ण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र भीम में जनता जल योजना के अन्तर्गत कार्यों की जांच कर कार्रवाई करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र भीम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हंसराज पटेल (वि.सं.187)

21. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के शहरी क्षेत्र में पुरानी एवं प्रदूषित पाईप लाईन को बदलवाने हेतु राशि रूपये 35 करोड़ स्वीकृत करवाने, नगर परिषद क्षेत्र कोटूपूतली में

15 ग्राम पंचायतों (उप ग्राम) को शहरी जल योजना में जुड़वाने तथा जलदाय विभाग का नया सहायक अभियन्ता कार्यालय-चिमनपुरा में खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

22. किशनगंज तहसील के पिजना व रामगढ़ में नए जीएलआर/एसएलआर बड़ी टंकी बनाकर पेयजल आपूर्ति करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)</u>

23. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों को शीघ्र पूरा कराने तथा योजना से वंचित ढाणी व गांवों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
24. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पेयजल परियोजनाओं के प्रबंधन, संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु खींवसर में जलदाय विभाग का अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय खोलने तथा पांचौड़ी, शंखवास एवं कुचेरा में जलदाय विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
25. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विभिन्न गांवों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए नलकूप एवं हैण्डपम्प स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
26. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विभिन्न गांवों में नाकारा हो चुके नलकूपों के स्थान पर नए नलकूप स्वीकृत करने एवं पानी कम हो चुके नलकूपों की गहराई बढ़ाए जाने तथा विभिन्न गांवों में संचालित पाईप्ड पेयजल योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सामान (मोटर, पम्प, पाईप, पैनल बोर्ड आदि) उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

27. विधान सभा क्षेत्र आहोर के विछावाडी, जोगावा, बांकली, बिठूडा, किशनगढ़ में उच्च जलाशय (एच.आर.) की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
28. विधान सभा क्षेत्र आहोर में नर्मदा के दो प्रोजेक्ट (1) इ.आर. कलस्टर (2) एफ.आर. कलस्टर का कार्य शीघ्र पूरा करके पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
29. विधान सभा क्षेत्र आहोर के भाद्राजुन में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. विधान सभा क्षेत्र आहोर के चांदराई साईबाग, हरजी में लीकेज पाईप लाईन को बदलने, चांदराई एवं आहोर के साईबाग में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

31. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद के देवरी कस्बे को सेहरोल-तलहेटी के तालाब से डबल पाईप लाईन को वित्तीय स्वीकृति देकर हनोतिया, हरियानगर व गाजन को पेयजल के लिए पाईप लाईन से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

32. विधान सभा क्षेत्र महवा के गांवों में जहां-जहां जेजेएम की स्कीमें बन्द हैं, वहां सभी जगह सोलर सिंगल फेस ट्यूबवैल की स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

33. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की प्रत्येक पंचायत में एक हैण्डपम्प मिस्त्री की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)

34. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जल जीवन मिशन में वंचित रहे क्षेत्र को भी उक्त योजना से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जनता जल योजना को जल जीवन मिशन में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत भूवाणा में अमृत जल मिशन में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से स्वीकृत राशि को रिलीज करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश मोदी (वि.सं.183)

37. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में जल जीवन मिशन एवं पानी की सुचारू व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं.88)

38. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में कुम्भाराम लिफ्ट का पानी उपलब्ध कराने, नवीन ट्यूबवैल स्वीकृत कराने, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने, नलकूप गहरा करवाने तथा नवीन नलकूप स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

39. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में ट्यूबवैल बोर की गहराई 300 फीट से बढ़ाकर 400 फीट करने के संबंध में चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में पुरानी जर्जर हो रही पानी की टंकियों के स्थान पर नवीन टंकियों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)

41. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सूखे कुओं एवं ट्यूबवैलों के स्थान पर नवीन ट्यूबवैल खोदने हेतु बजट आवंटन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)

42. विधान सभा क्षेत्र भादरा में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत क्षेत्र की प्रस्तावित रिवाईज स्कीमों को शीघ्र स्वीकृत करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
43. विधान सभा क्षेत्र भादरा के कनाऊ एवं कुंजी ग्राम पंचायत के 8 गांवों के लिए सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की रासलाना वितरिका से पेयजल स्रोत के निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।
44. विधान सभा क्षेत्र भादरा में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
45. प्रदेश में लाइनमैन, पम्प ड्राइवर सहित अनेक पदों को भर्ती के माध्यम से भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
46. विधान सभा क्षेत्र भादरा में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को अभी तक दुरूस्त नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री नाना लाल निनामा (वि.सं.85)</u>

47. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण कराने एवं पानी की सप्लाई नियमित करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शोभा चौहान (वि.सं.165)</u>

48. विधान सभा क्षेत्र सोजत की 10 ग्राम पंचायतों को दातीवाड़ा योजना से पेयजल नहीं मिलने तथा जल जीवन मिशन योजना में संवेदक द्वारा तोड़ी गयी सड़कें ठीक नहीं करवाये जाने एवं कनेक्शन अधूरे छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)</u>

49. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के ग्राम लिखमणसर, बालेटा में उच्च जलाशय पानी की टंकियां नहीं होने से ग्रामवासियों को हो रही पानी की समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।
50. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में जेजेएम योजनान्तर्गत सुजानगढ एवं बीदासर तहसीलों के गांवों में डाली गई पाईप लाईन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं होने से ग्रामवासियों व वाहन चालकों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।
51. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की ग्राम गुड़ावडी में क्षतिग्रस्त पानी की उच्च जलाशय टंकी की जगह नई उच्च जलाशय टंकी स्वीकृत नहीं होने से ग्रामवासियों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिए।
52. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सुजानगढ़ व बीदासर तहसीलों में आपसी योजना के तहत नहर का स्वीकृत पानी तय मात्रा से कम मिलने से क्षेत्र में हो रही पानी की भारी किल्लत के संबंध में चर्चा के लिए।
53. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में जेजेएम योजना में बन रही उच्च जलाशय पानी की टंकियों के पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)

54. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के जनजाति क्षेत्र में जेजेएम के अन्तर्गत वंचित एसटी परिवारों को योजना से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

55. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के उपखण्ड पीपाड़शहर/भोपालगढ़/बिलाड़ा के लिए स्थित अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय जोधपुर से बिलाड़ा मुख्यालय करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. जोधपुर में इन्दिरा गांधी नहर से तृतीय फेज की 2.0 मीटर व्यास की पेयजल पाईप लाईन से जसवंत सागर बांध का पुनर्भरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में माणकलाव-दातीवाड़ा पेयजल योजना अन्तर्गत देवलिया गांव से जालेली फौजदारा एवं 16 गांवों की डीपीआर बनाकर निविदा में वित्तीय बिड खोलकर वर्क आर्डर जारी कर कार्य प्रारम्भ करवाने की चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा अन्तर्गत नगरपालिका, बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर में अमृत 2.0 योजनान्तर्गत 2-2 एस.आर. निर्माण एवं राइजिंग लाईन व डिस्ट्रीब्यूशन लाईन बिछाकर शहरों के बाहरी भाग की छितराई आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन अन्तर्गत वंचित ढाणियों, कुओं पर बसावटें, मजरे, गांवों का पुनः सर्वे करवा कर पेयजल हेतु घरेलू कनेक्शन दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (वि.सं.139)

60. प्रदेश में जनता जल योजना अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

61. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की नगरपालिका श्रीविजयनगर में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल डांगी (वि.सं.21)

62. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में पेयजल के लिए जाखम परियोजना एवं नवीन कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)

63. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना की मौके पर सही क्रियान्विति न होने से योजना का पूरा लाभ न मिलने के कारण अधिकारियों के खिलाफ जांचकर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकियों एवं पाईप लाईन में लीकेज के कारण जनता में उत्पन्न रोष के संबंध में चर्चा के लिए।

65. प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में आखिरी छोर तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संजय कुमार (वि.सं.169)

66. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के सरमथुरा ब्लॉक में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

67. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से वंचित कॉलोनियों को पाईप लाईन से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के पेयजल से वंचित स्थानों पर नये ट्यूबवैल, बोरिंग, हैण्डपम्प सोलर पैनल सहित लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पेयजल पाईप लाईन के दूरूस्तीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्यों का संवेदक फर्मों द्वारा निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में खराब बोरिंग, हैण्डपम्प की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

72. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ में जल सप्लाई भण्डारण झूगली झोहड़ को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के पूर्ण रूप से सप्लाई से वंचित गांवों में पूर्ण पानी की सप्लाई कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं होने एवं गाईड लाईन अनुसार कार्य नहीं करने की शिकायतों की जांच कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के वंचित गांवों में विभाग द्वारा कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

77. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अमृत योजना के कार्य की प्रगति के संबंध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत खोदे नलकूपों के संबंध में चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बन्द पड़े नलकूपों को चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सौर ऊर्जा पम्प की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बजट घोषणा 2024 के हैडपम्प व टयूबवैलों को लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं.96)</u>

82. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना नागाण-पुनियों का तला, भूरटिया-मातासर, काउखेड़ा, जोगसरिया-कवास के विस्तार के कार्य को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बंद/नकारा ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प के स्थान पर नवीन ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर शहर, पंचायत समिति बाड़मेर तथा पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण के गांवों को नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना बिशाला-सेजुओं की ढ़ाणी के विस्तार के कार्य को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं.138)</u>

87. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में जल जीवन मिशन के तहत वंचित ढ़ाणियों को जोड़ने तथा पुराने व परम्परागत जल स्रोतों को खत्म करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)</u>

88. अजमेर शहर में पेयजल लाईनों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु विभाग द्वारा ओ एण्ड एम के लिए निजी कम्पनी से करार/समझौता करने के बावजूद भी नसीराबाद सेवन नम्बर टैंक से आने वाली मुख्य पाईप लाईन के बार-बार टूटने से कार्यरत एजेन्सी की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. अजमेर शहर हेतु स्वीकृत अमृत-2 योजना के कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. अजमेर शहर के लिये बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 186 करोड़ रूपये के कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

91. अजमेर जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध रूप से बनाये जाने हेतु बीसलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के वर्ष 2021 में पूरा होने के पश्चात आगामी तृतीय फेज को अविलम्ब स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. अजमेर जिले को बीसलपुर बांध से 3.7 टीएमसी अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

93. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में अमृत 2 योजनान्तर्गत प्रगति के संबंध में चर्चा के लिए।

94. हर घर जल योजना के समान भीलवाड़ा शहर की समस्त निजी कॉलोनियों में रह रहे लोगों को जल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. भीलवाड़ा जिले के पुराने जल स्रोतों को पुनः चालू कर जलापूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. भीलवाड़ा जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत सभी ब्लॉकों में कार्य पूर्ण होने के बावजूद भीलवाड़ा शहर की जल मांग में कटौती से होने वाली समस्या पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में संसाधनों के अभाव में विभाग द्वारा अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अजय सिंह (वि.सं.02)</u>

98. विधान सभा क्षेत्र डेगाना की ढाणियों में पेयजल पाईप लाईनें डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. डेगाना शहर में पानी की पाईप लाइनें बिछाने के समय क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरूस्त कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्रामों में जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल संकट के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्रामों में संवेदक एलएनटी कम्पनी द्वारा कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम गानेरड़ा, पुन्दलोता, लूनियास, पालड़ी कलां, सिंघलास, सारसण्डा में पेयजल संकट के हल के लिए उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)</u>

103. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में पेयजल आपूर्ति के लिए पाईप लाईन डालने का कार्य शीघ्र कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हंसराज मीना (वि.सं.188)

104. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के डांग क्षेत्र के दूरस्थ गांव/ढाणियों में जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराये जाने, उपखण्ड मुख्यालय सपोटरा में अधिशाषी अभियंता कार्यालय सृजित किये जाने तथा उपखण्ड मुख्यालय मण्डरायल पर सहायक अभियंता कार्यालय सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समरजीत सिंह (वि.सं.174)

105. भीनमाल शहर व ग्रामीण क्षेत्र में नर्मदा नहर से पेयजल आपूर्ति का कार्य लम्बित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कुलदीप (वि.सं.33)

106. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की नगरपालिका क्षेत्र पावटा-प्रागपुरा को ग्रामीण परिसीमन से शहरी परिसीमन में जोड़कर पेयजल सप्लाई के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं.03)

107. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर, सरदारपुरा और सूरसागर में वर्ष 2019 से 2023 तक जारी स्वीकृतियों की नवीनतम अद्यतन कार्य प्रगति और वर्ष 2024 से अब तक जारी स्वीकृतियों और नवीनतम अद्यतन कार्य प्रगति की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर विभागीय योजनाओं के निर्माण, स्वीकृति और कियान्वयन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में सीवरेज लाईन कार्यों के कारण टूटी पेयजल पाईप लाईन को दुरूस्त कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. इन्दिरा गांधी नहर में थर्ड फेज का कार्य तय अवधि मार्च, 2025 तक पूर्ण नहीं होने से पेयजल स्टोरेज की अपर्याप्तता की स्थिति से पेयजल संकट की आसन्न स्थिति के लिए जिम्मेदारी तय करने और कार्य योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. जोधपुर में भू-जल रिसाव से भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या हेतु लाभकारी सबमर्सिबल पम्पयुक्त हैण्डपम्पों की उपयोगिता के मद्देनजर स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में अमृत-2 योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नगर निगम क्षेत्र एवं पेराफेरी क्षेत्र से वंचित नांदड़ी, डिगाड़ी, कुड़ी भगतासनी आदि क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (वि.सं.123)

112. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर स्थित जवाहर नगर कच्ची बस्ती में जगह-जगह से पाईप कटे होने से पानी के रिसाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में आगरा रोड़ पर स्थित बगराना के शेष रहे क्षेत्र में पानी की लाईन डालने, उक्त विधान सभा क्षेत्र में बंद पड़े सभी बोरिंगों को चालू करने एवं जल आपूर्ति का समय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में लगाए गए बोरिंग व पानी की लाइनों में सीवर लाईन का पानी मिक्स हो जाने से उत्पन्न स्थिति एवं पानी की सप्लाई की क्वालिटी को समय-समय पर चैक करने की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रवण कुमार (वि.सं.167)</u>

115. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पेयजल की समस्या का निराकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री नरेन्द्र बुडानिया (वि.सं.84)</u>

116. चूरू जिले में पीने के पानी की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

117. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए स्थानीय जल स्रोतों के विकास और प्रबंधन तथा इन कार्यों से स्थानीय जनता को अधिकतम लाभ दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पेयजल दृष्टि से संकटग्रस्त गांवों में पेयजल संकट का स्थाई समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और परियोजनाओं का लाभ जनता को शीघ्र दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. राजसमंद नगरीय क्षेत्र में पाईप द्वारा 24 घंटे जल आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा चलित पनघट की स्थापना और उनके निरन्तर अनुरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भड़ाणा (वि.सं.22)</u>

122. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के करेड़ा-माण्डल व सुवाणा में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की सप्लाई 17 एमएलडी से 30-35 एमएलडी किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के करेड़ा एवं बागोर में पेयजल पाईप लाईन बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में ग्रामीण जल योजना-सुवाणा में पाईप लाईन बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र माण्डल की ग्राम पंचायत पालड़ी में बड़ी टंकी एवं पाईप लाईन बदले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के करेड़ा कस्बे में पेयजल की लाईन बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं.144)

127. प्रदेश में ट्यूबवैल और हैण्डपम्प की घोषणा के संबंध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में चम्बल से पेयजल आपूर्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत जारी कार्यादेशों पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

130. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पर्याप्त पेयजल हेतु बीसलपुर बांध से पानी की आपूर्ति बढ़ाने, जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पानी के कनेक्शन एवं प्रदेश में पेयजल समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

131. विधान सभा क्षेत्र नोहर में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र नोहर की वंचित ढाणियों में पेयजल कनेक्शन जारी करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र नोहर की तहसील-पल्लु एवं उप तहसील-खुंईया में सहायक अभियन्ता कार्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र नोहर में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पेयजल कनेक्शन से वंचित 30 गांवों में कनेक्शन जारी करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र नोहर के नगरपालिका क्षेत्र नोहर में विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में घर-घर पेयजल कनेक्शन जारी करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

136. विधान सभा क्षेत्र बून्दी में चम्बल कलस्टर पेयजल योजना के अन्तर्गत नियमित रूप से निर्धारित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137. बून्दी शहर में आरयूआईडीपी स्कीम के तहत पेयजल उपलब्ध कराने की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

138. बून्दी जिले में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 64 गांवों में पेयजल हेतु लगाए गए ट्यूबवैलों का नियमित भुगतान नहीं होने से विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

139. प्रदेश के गरडदा बांध पेयजल योजना की क्रियान्विति एवं जल उपलब्ध कराने के लिए 'इनटेक वैल' के निर्माण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

140. प्रदेश में वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष, प्रति विधान सभा क्षेत्र में 10-10 ट्यूबवैल और 20-20 हैण्डपम्प लगाने के आदेश की अभी तक क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री पब्बाराम विश्नोई (वि.सं.87)</u>

141. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के गांधी सागर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च जलाशय निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के ग्राम पंचायत मुख्यालय भींयासर में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

143. विधान सभा क्षेत्र डग में जल जीवन मिशन से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र डग में जल जीवन मिशन योजना का संचालन व अधूरे पड़े कार्यों को समितियों के स्थान पर विभाग के कार्मिकों को दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)</u>

145. रूपवास में चम्बल परियोजना का सहायक अभियन्ता कार्यालय तथा रूदावल में जलदाय विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. प्रदेश में जल जीवन मिशन में संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सुचारू रूप से योजना का संचालन ग्राम पंचायत के स्थान पर जलदाय विभाग द्वारा करने तथा जल मित्रों की भर्ती संविदा पर किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. भरतपुर जिले में अमृत 2.0 योजना में स्वीकृत कार्यों की टेण्डर प्रक्रिया संयुक्त निविदा के स्थान पर पृथक-पृथक जारी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र बयाना की जरमासी ग्राम पंचायत में आकाशीय टंकी बनने के बावजूद अभी तक चंबल परियोजना लाईन से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास उपखण्ड में चम्बल जल परियोजना से शीघ्र ही हर घर को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)</u>

150. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में जल जीवन मिशन के द्वारा शुद्ध जल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

151. अकलेरा शहर में नई बस्ती में ताखा जी पार्क में पानी की टंकी बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

152. चम्बल पेयजल परियोजना के अभी तक पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

153. भरतपुर शहर की गैर अनुमोदित कॉलोनियों में पेयजल की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अवैध कनेक्शनों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हाकम अली खां (वि.सं.197)</u>

155. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में जल जीवन मिशन कार्यों में हो रही अनियमितता एवं वंचित ढाणियों में कनेक्शन देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)</u>

156. जोधपुर शहर के नागरिकों को पेयजल आपूर्ति हेतु नहरी पेयजल का भण्डारण पर्याप्त नहीं होने से अवश्यम्भावी संकट की स्थिति से उबारने के लिए भण्डारण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. प्रदेश में लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों को जानबूझकर लम्बित रखने वाले जांच अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने और जांच प्रकरणों को अभियानपूर्वक निस्तारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. प्रदेश में पेयजल के सेम्पल टेस्टिंग कार्य को तय मानक अनुरूप नहीं करने से दूषित पेयजल सप्लाई होने से जनस्वास्थ्य को हानि की संभावना से बचाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाकर सख्ती से क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पाक विस्थापित नागरिकों की बस्तियों हेतु पेयजल कार्यों की लम्बित तकनीकी स्वीकृति के कारण अटकी निविदा प्रक्रिया को अविलम्ब पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में तिंवरी रोड़ हाईवे धोलकी प्याऊ से सोढ़ों की ढाणी, तापड़िया बेरा से सूरज कुण्ड-व्यास पार्क, पदमसर-व्यास पार्क की पुरानी दूषित पेयजल पाईप लाइनों को बदलने का कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

161. विधान सभा क्षेत्र मकराना के मकराना शहर में पेयजल आपूर्ति आठ से दस दिनों में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की पाईप लाइनों के लीकेज, मैंटिनेंस एवं ठेकेदारों की लापरवाही के कारण हो रहे व्यर्थ पानी के नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र मकराना में आर.ओ.प्लांट का संचालन एवं मैंटिनेंस नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र मकराना के मकराना शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं के बीस हजार रूपए से अधिक के बिल आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं.155)</u>

165. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की ग्राम पंचायत नाल बड़ी को नई पाईप लाईन से जोड़ने एवं पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की ग्राम पंचायत एवं छतरगढ़ तहसील मुख्यालय पर पेयजल समस्या हेतु नई योजना बनाकर समाधान करने की आवश्यकता चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की ग्राम पंचायत भानीपुरा में पेयजल हेतु नोखा दैया से भानीपरा तक नई पाईप लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)</u>

168. प्रदेश में ग्रामीण जल योजनाओं पर तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण संचालन एवं संधारण के कार्यों की स्वीकृति में आ रही कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के गांवों में शेष बची ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामीण जल योजनाओं के वंचित हैडवर्क्स के जीर्णोद्धार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)</u>

171. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ के चकों व ढाणियों में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत ढाणी-ढाणी पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ में एक अतिरिक्त उपखण्ड कार्यालय (सहायक अभियन्ता कार्यालय) की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. सूरतगढ़ उपखण्ड में चार कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों के विरूद्ध तीन कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. सूरतगढ़ उपखण्ड में स्वीकृत तकनीकी कर्मचारियों के पदों के विरूद्ध 85 प्रतिशत रिक्त पदों को भरे जाने या ओ.एण्ड एम. के तहत तकनीकी वर्क फोर्स उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. सूरतगढ़ उपखण्ड में नई जल योजना ठुकराना व 6 डीबीएन बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)

176. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के गोविन्दगढ़ स्थित कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय को कठूमर के स्थान पर अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय, अलवर के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
177. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के रामबास ग्राम में पेयजल सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
178. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के गोविन्दगढ़ में नया सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलकर उसे अलवर एक्सईएन के अधीन रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
179. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के खोरपुरी, डण्ड, बारोली एवं न्याना में जल जीवन मिशन योजना शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
180. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की बडौदामेव तथा नौगांवा नगरपालिका क्षेत्र को अमृत योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)

181. प्रदेश में जनता जल योजना में कार्यरत सहायक पम्प चालकों की विभिन्न मांगों का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
182. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नकारा नलकूपों के स्थान पर नवीन नलकूप स्वीकृत करने, गहरा करने, नए लोरिंग पाईप, कैबल, स्टार्टर इत्यादि की योजनाएं अतिशीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
183. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के आर.डी.134 देवानिया-नाथडाऊ एवं आर.डी.159.5 खुडियाला-आगोलाई-बालेसर जल जीवन मिशन योजना के तहत वंचित राजस्व गांव एवं ढाणियों को जोड़ने हेतु लम्बित पत्रावली की स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
184. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ओपन वैल (खुला कुआ) में हॉरिजेन्टल और वर्टीकल बोरिंग करवाने एवं संधारण हेतु योजनाएं स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
185. Approval of PQ bid for the work "Providing Rising Main Pipeling for Gagadi Dhandhaniya Agolai under District Division Balesar District Jodhpur'' Nit No.41/2023-24 ACE PHED Region-1 Jodhpur (estt.cost Rs.2470.69 Lacs) निविदा की PQ bid की अनुमति प्रदान करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)

186. जयपुर के ग्राम रामपुरा, ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द, पंचायत समिति जोबनेर, जिला-जयपुर के ग्राम रामपुरा की मुख्य आबादी में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पानी की लोहे की पाईप लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री भगवाना राम सैनी (वि.सं.104)</u>

187. जयपुर के ग्राम रामपुरा, ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द, पंचायत समिति जोबनेर, जिला-जयपुर ग्राम रामपुरा की मुख्य आबादी में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पानी की लोहे की पाईप लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)</u>

188. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में पुरानी पाईप लाइनों के स्थान पर नई पाईप लाईन डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में पानी की सप्लाई का समय चक्र निश्चित कर क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानी से बचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में पानी लीकेज को लम्बे समय तक ठेकेदार द्वारा ठीक नहीं करने पर ब्लैक लिस्टेड करने के संबंध में चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के सभी रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर-पश्चिम में हैण्डपम्प के स्थान पर पानी की टंकियां उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)</u>

193. जल योजना 27 एमएल उपखण्ड पदमपुर के टेन्डर जारी कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र करणपुर की ढाणियों में पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. जल योजना बीझवायला के टेन्डर लगा कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के श्रीकरणपुर एवं गजसिंहपुर उपखण्ड में पेयजल की डिग्गियों की सफाई करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)</u>

197. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में सेड़वा पंचायत समिति मुख्यालय पर नवीन सहायक अभियन्ता कार्यालय (जलदाय विभाग) खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा नहर का जल हर गांव एवं घर तक अतिशीघ्र पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में पेयजल की आपूर्ति हेतु प्रमुख जल स्रोत-नलकूप, हैण्डपम्प तथा आर.ओ. प्लान्ट के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में प्रमुख धार्मिक स्थलों (मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं) में नि:शुल्क जल आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं.138)</u>

202. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में पंचायत समिति क्षेत्र अलसीसर एवं मण्डावा के ग्रामीण क्षेत्र में दो वृहद् पेयजल परियोजना के कार्य अधूरे होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में पेयजल परियोजनाओं में हुए घटिया कार्यों एवं पेयजल से वंचित ग्रामों के कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ताराचन्द (वि.सं.73)</u>

204. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में पानी की समस्या से निजात दिलाने हेतु नए नलकूप लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.1)</u>

205. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 10 नलकूपों में से एक भी नलकूप स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थित पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

206. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा एवं सिवाना में नर्मदा नहर के पानी को पीने के लिए उपयोग में लेने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा एवं सिवाना के कई ग्रामों में ओवरहैड टैंक बन जाने के उपरान्त भी कई वर्षों से पानी की सुचारू आपूर्ति नहीं किए जाने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के कोरणा से चांदराई तक, पिण्डारण से उमरलाईल, गोल अथवा खट्टू से चांदेसरा तक, बागुण्डी से आकड़ली एवं पचपदरा तक, कल्याणपुर से अराबा एवं डोली तक, माजीवाला से असाड़ा, बुडीवाडा जागसा, टापरा तक नई पेयजल पाईप लाईन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा एवं सिवाना के अन्तर्गत बजट घोषणा में स्वीकृत पेयजल स्टोरेज हेतु राशि दस करोड़ रूपए से बढ़ाकर लगभग तीस करोड़ रूपए करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम कुडी, सरूपरा, बोको की ढाणी पारलू, रणियादेशीपुरा एवं बालोतरा शहर में सांकरणा तथा नया बस स्टैण्ड एवं खंड रोड़ पर नई ओवरहैड टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अमीन कागजी (वि.सं.9)</u>

211. जयपुर शहर में बंद पड़े नलकूपों को चालू करने एवं नए नलकूपों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

212. जयपुर में अमृत योजना के अन्तर्गत नगर निगम हैरिटेज परकोटे क्षेत्र में सभी चौकड़ियों में पानी की नई लाईन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के तहत जयपुर के नगर निगम हैरिटेज क्षेत्र विशेषकर विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में पानी की नई लाईन डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

214. प्रदेश में जल जीवन मिशन घोटालों के दोषियों को महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

215. प्रदेश में जल जीवन मिशन अनुभव प्रमाण पत्र घोटाले में तीन सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट देने के उपरान्त भी दोषियों के विरूद्ध एसीबी जांच के लिए विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के संबंध में चर्चा के लिए।

216. जयपुर में पानी प्लांट एवं होटलों द्वारा राईजिंग लाईन तोड़कर अवैध कनेक्शन से पानी चोरी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना धाबास, जयपुर में बीसलपुर योजना से कॉलोनी में पेयजल उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

218. जल जीवन मिशन (जेजेएम) के घोटालों के दोषियों के विरूद्ध जांच लम्बित होने के उपरान्त भी पदौन्नति दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)

219. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत अरनोदा में पाईप लाईन बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में जनता जल योजना के अन्तर्गत सतखण्डा, लसडावन, बांगरेडा घाटा एवं मेलाना में क्षतिग्रस्त पाईप लाईन बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के उपखण्ड निम्बाहेड़ा में ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत अरनोदा, जावदा एवं ढोरिया में ग्रीष्म आकस्मिकता 2025 पाईप लाईन बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

222. विधान सभा नगर कॉलोनी, धौलाई, मानसरोवर, जयपुर में बीसलपुर पेयजल योजना के माध्यम से मार्च, 2025 में ही पेयजल सप्लाई प्रारम्भ किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में ग्रीष्म 2025 ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत कनेरा एवं 2025 जनता जल योजना के अन्तर्गत बड़ोली माधोसिंह में ग्रीष्म आकस्मिकता 2025 पाईप लाईन बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)

224. विधान सभा क्षेत्र आमेर के देवी खोल एवं चौमोरिया में बीसलपुर जल प्रदाय योजना से पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. विधान सभा क्षेत्र आमेर में ग्राम उदयपुरिया, आकेड़ा डूंगर, अखैपुरा व नांगल सुसावतान में बीसलपुर जल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226. विधान सभा क्षेत्र आमेर के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता कार्यालय, जालसू में खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम ढ़ाणियों में जल जीवन मिशन के तहत शेष रहे क्षेत्रों में पाईप लाईन व नलकूप टंकियों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायतों में पेयजल आपूर्ति हेतु पाईप लाइनों के विस्तार व पुरानी पाईप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)

229. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम कलरू, डारों की ढ़ाणी (रेण), छापरी व नगरपालिका मेड़तारोड़ में जी.एल.आर. टंकियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

230. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बंद नलकूप एवं हैण्डपम्प को ठीक करवाकर चालू कराने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के जोलपा सहित विभिन्न गांवों में पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के विभिन्न गांवों में फ्लोराईडयुक्त पानी की समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पेयजल आपूर्ति से वंचित गांवों को जल जीवन मिशन अथवा अन्य योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बजट घोषणा की पालना में हैण्डपम्प और ट्यूबवैल स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)

235. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के जयसिंहपुरा खोर में वर्तमान देय 3.5 एमएल पेयजल आपूर्ति के स्थान पर 15 एमएल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के मानपुर सड़वा, केशर की पहाड़ी, संजय कॉलोनी, अफजल विहार, भट्टा बस्ती, शास्त्रीनगर, बदनपुरा में अवैध जल कनेक्शन हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में पेयजल समस्या के समाधान हेतु चित्रगुप्तेश्वर महादेव मंदिर, आयलीवालों की ढ़ाणी, अम्बेडकर पार्क, भौमियाजी का मंदिर, मामलिया की ढाणी, तलाई

रोड़ सागर की कोठी एवं अन्य क्षेत्रों में 15 बोरिंग स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के जयसिंहपुरा खोर में पेयजल की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र हवामहल के जयसिंहपुरा खोर वार्ड नं. 13 के दीपक नगर, सावड़ों की ढ़ाणी में पाईप लाईन डालने के पश्चात मिलान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>

240. भीलवाड़ा के शाहपुरा ग्रामीण में कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में उपखण्ड मुख्यालय फुलिया कलां में (जेइएन) कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के उपखण्ड मुख्यालय फुलिया कलां व प्रसिद्ध तीर्थधाम धानेश्वर में स्रोत व उच्च जलाशय (टंकी) के निर्माण व देवरिया में उच्च जलाशय व कोठिया में (सीडब्ल्यूआर) स्वच्छ जलाशय व पाईप लाईन डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

243. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा ग्रामीण में कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

244. उम्मेद सागर बांध से उपखण्ड मुख्यालय शाहपुरा में पानी की सप्लाई के पुराने पम्प हाऊस का जीर्णोद्वार कर पुनः संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम (वि.सं.175)</u>

245. सिरोही जिले में हैण्डपम्प मिस्त्रियों को रिक्त स्थानों पर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

246. पिण्डवाड़ा एवं आबू क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूर्व में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

247. पिण्डवाड़ा एवं आबू क्षेत्र में हर जगह पानी की पाईप लाईन नहीं पहुंचने के कारण 100 हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए

<u>श्री युनूस खान (वि.सं.121)</u>

248. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में जल जीवन मिशन के तहत वंचित गांवों व ढ़ाणियों को पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

249. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के संचालन एवं मरम्मत के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों के लिये बजट प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना की मांग अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में गांवों व ढ़ाणियों को पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के विभिन्न गांवों में उच्च जलाशय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं.83)</u>

253. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कस्बे गोठड़ा (खेतड़ी नगर) हेतु पेयजल आपूर्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

254. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सूखे बोरवेल एवं हैण्डपम्पों के विरूद्ध नये बोरवेल एवं हैण्डपम्पों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)</u>

255. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में ग्राम झडवासा को बीसलपुर योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

256. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के श्रीनगर पंचायत समिति क्षेत्र के वंचित ग्रामों को जल जीवन मिशन से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम लीरी का बाडिया में पेयजल टंकी में पानी कम पहुंचने से कम पेयजल सप्लाई एवं कम प्रेशर की समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

258. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के विभिन्न गांवों में नये नलकूप व हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम कानपुरा व तिहारी में बीसलपुर योजना का पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मोतीराम (वि.सं.120)</u>

260. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में 'जल जीवन मिशन' के तहत कराये गये कार्यों में व्याप्त उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में 'जल जीवन मिशन' के तहत पेयजल से वंचित गांवों व ढाणियों को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शिमला देवी (वि.सं.163)</u>

262. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में विभाग के अधीन स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं अपूर्ण/लंबित कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

263. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में विभाग के अधीन स्वीकृत ट्यूबवेलों एवं हैण्डपम्पों की स्वीकृति एवं भू-जल की स्थिति पर चर्चा के लिए।

264. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 'हर घर नल' योजनान्तर्गत लाभान्वितों एवं योजना से वंचित परिवारों की स्थिति पर चर्चा के लिए।

265. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत 'हर घर नल' योजनान्तर्गत विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य की स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित यादव (वि.सं.143)</u>

266. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सोडावास (साबी नदी) 15 गांवों की स्वीकृत जे.जे.एम. योजना अंतर्गत पानी दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं.148)</u>

267. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत शेष रहे ग्रामों को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

268. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में हैण्डपम्प व ट्यूबवैल स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)</u>

269. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में ईसरदा बांध परियोजना से तहसील राजगढ़, रैणी एवं लक्ष्मणगढ़ को पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

270. ईसरदा बांध परियोजना से बसवा (दौसा) क्षेत्र की लाईन को 03 किलोमीटर बढ़ाकर राजगढ़ कस्बे (अलवर) को पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुभाष मील (वि.सं.179)</u>

271. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के पूरे क्षेत्र में पेयजल की सुचारू व्यवस्था के लिये विभिन्न जगह ट्यूबवैल, ऊंची पानी की टंकियों व पाईप लाईन के लिये वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

272. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के लिये पेयजल व्यवस्था को दुरूस्त कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)</u>

273. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सहायक अभियन्ता कार्यालय राशमी के लिए नवीन भवन के निर्माण हेतु बजट स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए। `

274. विधान सभा क्षेत्र कपासन के सभी परिवारों को जल जीवन मिशन योजना में नल कनेक्शन दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

275. विधान सभा क्षेत्र कपासन की संचालित पेयजल योजनाओं में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को समय पर भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

276. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में फ्लोराईड की समस्या के समाधान हेतु ग्राम रुण्डया पंचायत लक्ष्मीपुरा हेतु (40 लाख), ग्राम श्रीपुरा पंचायत अयानी हेतु (33 लाख) एवं बीरोदा पंचायत जोरावरपुरा हेतु (22 लाख) रूपये की कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.05)

277. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के गांव पातलीसर छोटा, पातलीसर बड़ा, राणासर बीकान व सोनपालसर के नकारा ट्यूबवैल के स्थान पर नये ट्यूबवैल करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

278. धन्नासर से सरदारशहर तक 1100 एमएम व्यास की पुरानी पाईप लाईन का सुदृढ़ीकरण करवाये जाने अथवा बदलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

279. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के गांव सिकराली व बलरामपुरा में अलग से उच्च जलाशय का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

280. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के गांव भानूदा, बाडा की ढ़ाणी, सिकराली, हामूसर, बरजांगसर, हुडेरा, मेलूसर में एक-एक ट्यूबवैल तथा गांव पाबूसर व बलरामपुरा के नकारा ट्यूबवैलों के स्थान पर नये ट्यूबवैल बनवाये जाने की स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

281. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में जेजेएम योजना के तहत लम्बित योजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी कर कार्य आरम्भ करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

282. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के नगर निकाय, शाहपुरा व मनोहरपुर को मुख्य मंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) में जोड़कर अनुमानित 80 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

283. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में आगामी ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

284. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के ग्राम पंचायत निवाणा, नांगल कोजू, खेजरोली, हाथनोदा, नांगलभरडा, देवथला तिगरिया, कंवरपुरा व अमरपुरा में जल जीवन मिशन के तहत कार्यादेश जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

285. विधान सभा क्षेत्र शिव में स्वीकृत ट्यूबवैल का निर्माण अविलम्ब पूर्ण करवाये जाने के साथ ही विद्युतीकरण से शेष रहे ट्यूबवैलों का अतिशीघ्र विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

286. ईआरसीपी की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान में नवीन डब्ल्यूआरसीपी परियोजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

287. विधान सभा क्षेत्र शिव के विभिन्न सहायक अभियंता कार्यालयों में रिक्त चल रहे तकनीकी एवं गैर तकनीकी संवर्ग के पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

288. विधान सभा क्षेत्र शिव में स्वीकृत किये जाने वाले ट्यूबवैल की गहराई अधिक किये जाने के साथ ही इसके विद्युतीकरण हेतु बजट की स्वीकृति बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

289. विधान सभा क्षेत्र शिव के समस्त सहायक अभियंता कार्यालय को राईजेप खण्ड बाड़मेर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं.81)</u>

290. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में श्रीगणपति ट्यूबवैल कम्पनी से संबंधित ग्रामों के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

291. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जल जीवन मिशन में वंचित ढ़ाणियों को जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

292. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में अमृत 2.0 का कार्य शुरू कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

293. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सूखे नलकूपों के स्थान पर नवीन नलकूप स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

294. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की नवगठित नगरपालिका नारायणपुर को अमृत योजना में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

295. विधान सभा क्षेत्र मकराना के बोरावड़ शहर में पाईप लाइनें आये दिन डेमेज होने एवं बेसरोली से सेवा नोजल की ढ़ाणी से गुजरों की ढ़ाणी तक व चाण्डी से गौशाला तक की पाईप लाइनें 90 एमएम के स्थान पर 50 एमएम डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ताराचंद (वि.सं.73)</u>

296. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रातासर माईनर नहर 9 जीएनपी मुख्य नहर के आरडी 608 से जेजेएम के तहत विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ जिसमें शहर के साथ 108 गांवों को पीने का पानी देने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या- 42 मुख्य शीर्षक **जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना** के अन्तर्गत मांग में से 100 **रुपया** कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

01. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में बांध, नहर, तालाब एवं नवीन एनिकट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

02. प्रदेश के कडिया देह बांध के ओवरफ्लो पानी को जवाजा बांध में लाने के लिए फिडर का एस्टीमेट अनुसार बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. जसवंत सिंह यादव (वि.सं.61)

03. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम गादोज में पुराना खेड़ा मंदिर के पास एनिकट का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
04. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के खुदरोट एनिकट बांध का हरियाणा राज्य की सीमा तक शेष निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
05. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम कायसा नीमराणा में निर्जरा घाटी के पास एनिकट का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
06. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम जखराना में झरने के पास एनिकट का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
07. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम कांकरा बर्डोद में नाहरसिंह मंदिर के पास एनिकट निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खींची (वि.सं.125)

08. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के सभी ग्राम/ढ़ाणियों व तलाबों, बांधों को पीकेसी ईआरसीपी योजना में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

09. नर्मदा परियोजना का पेयजल विधान सभा क्षेत्र सिवाना में देने के लिए सिणधरी मुख्यालय पर मुख्य हेडल केन्द्र बनाकर भविष्य में पीने का पानी उपलब्ध करवाने हेतु डीपीआर बनवाने एवं योजना स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
10. सिवाना क्षेत्र की समदड़ी ब्लॉक के गांवों में नहरी पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने की पूर्व में बनी योजना हेमावास बांध, जवाई बांध-पाली सरहद से लगे गांव खण्डप,

गोलिया, सरवड़ी, रातडी, अर्थण्डी, छीपाली, सेवाली, कुरमावास में नहरी पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. सिवाना क्षेत्र में बरसाती जल संरक्षण को लेकर एनीकट व बांध बनाने तथा बाढ़ बचाव हेतु मवडी, फुलन, देवन्दी, मजल, ढ़ीढ़स, नाल, गुडा-सिणेर, इन्द्राणा, अन्नपूर्णा नगर, भाखरपुरा, धारणा, सेला, धीरा, दन्डाली, कांखी, कुण्डल, मांगी, जिनपुर, तेलवाडा, भागवा में कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. पश्चिमी राजस्थान के लिए भी पूर्वी राजस्थान की भांति ई.आर.सी.पी. योजना की तरह रेगिस्तानी जिले में डब्ल्यू.आर.सी.पी योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के लिए भविष्य में सिंचाई हेतु नहरी पानी की योजना बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)</u>

14. विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में बांधों, नहरों व एनिकटों के निर्माण व जीर्णोद्वार कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखड़ (वि.सं.150)</u>

15. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में गत बजट वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत इन्दिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं.158)</u>

16. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की ग्राम पंचायत फोषलीबोर में स्थित माही भीखाभाई केनाल गांव के मध्य में स्कूल के आस-पास 25 से 30 फीट गहरी नहर में आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उसमें बड़े पाईप डालकर बन्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)</u>

17. विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत नवलीया पग ग्राम पंचायत छापली एवं काछबली में पालीयावास एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं.01)</u>

18. प्रदेश के नहरी क्षेत्र में फील्ड स्टॉफ बेलदार, गेज रीडर, जिलेदार एवं पटवारी के पद रिक्त रहने से नहर प्रणाली निष्फल होने से किसानों में व्याप्त रोष की स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

19. जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना ईआरसीपी में किशनगंज- शाहाबाद को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के रातई-ढिकवानी, खटका मध्यम सिंचाई परियोजना तथा नारायणखेड़ा, सेमली फाटक, उम्मेद सागर, हत्यादह को ई.आर.सी.पी. के रामगढ़ व मेहलपुर बैराज से पेयजल व सिंचाई से जोड़कर क्षेत्र को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)

21. विधान सभा क्षेत्र बगरू के नेवटा बांध के जीर्णोद्धार व मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
22. विधान सभा क्षेत्र बगरू के नेवटा बांध की कच्ची नहरों को पक्की किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)

23. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कोडियात से आगे अमरजोगा नदी में एनीकट बनवाकर बडी का तालाब को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।
24. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में टूटे हुए एनीकट व तालाबों को ठीक करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
25. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में बडली वाला नाके पर एनीकट बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पितराम सिंह काला (वि.सं.88)

26. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में यमुना जल समझौते के अनुसार पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)

27. चित्तौड़गढ़ शहर स्थित खरडेश्वर महादेव के पास एनीकट व घाट का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
28. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की बेडच नदी पर एनिकट निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।
29. विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ के छापरा में नाले पर बांध निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।
30. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के तीन एनिकट कम काजवे का लघु सिंचाई परियोजना में मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (वि.सं.171)

31. प्रदेश में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहरी पटवारी, जिलेदार, गेज रीडर, बेलदार, मेट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित अनेक कार्मिकों की भर्ती किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अमर सिंह सब ब्रांच एवं सिद्धमुख परियोजना क्षेत्र में खाला निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु बजट उपलब्ध करवाकर निर्माण कार्य स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सिंचाई से वंचित चौदह गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र भादरा की सिद्धमुख नहर प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्तावित "भोलावास माईनर" को शीघ्र स्वीकृत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. नोहर में पूर्व में स्थानान्तरित किए गए अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय को पुन: भादरा में स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं.57)</u>

36. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में खारी बांध की कच्ची पाल का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के बदनोर उपखण्ड में भोजपुरा फिडर के अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में खारी बांध, सरेरी बांध व कंटालिया बांध की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में खारी बांध पर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में स्थित रेस्ट हाऊस को तोड़कर आधुनिक सुविधायुक्त नवीन भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री नाना लाल निनामा (वि.सं.85)</u>

40. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ब्लॉक पीपलखूंट क्षेत्र में ऐराव नदी पर सेमलिया से नायन ग्राम पंचायत के बीच एनिकट/एम.एस.टी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रामकेश (वि.सं.133)</u>

41. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के पीकेसी इआरसीपी एवं रामजल सेतु परियोजना से बांधों को भरने एवं सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाशचन्द्र मीणा (वि.सं.37)</u>

42. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पुराने तालाबों के रख-रखाव, जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण तथा क्षेत्र के बड़े तालाबों व नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)</u>

43. विधान सभा क्षेत्र रायसिंगनगर के आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का पूरा पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल डांगी (वि.सं.21)</u>

44. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर स्थित सरजणा बांध, बेड़च नदी, रूण्डेड़ा, मेनार फिडर निर्माण व मुख्य नहरों के सुदृढ़ीकरण कार्य व नवीन कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

45. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के थेगडा मुख्य नहर से छोटी नहर जो बोरखेड़ा होते हुए चन्द्रेसल तक की क्षतिग्रस्त सुरक्षा वॉल को दूरस्तीकरण कर 4 फीट तक सुरक्षा दीवार बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
46. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में चम्बल नहर के पानी से सिंचाई से वंचित गांवों की कार्य योजना बनाकर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
47. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के चम्बल दांई मुख्य नहर से निकली हुई वितरिकाओं (छोटी नहरों) को प्रदूषित होने से रोकने एवं नहरों की दीवार को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
48. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में निर्मित एनिकटों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
49. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में स्थित तालाबों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार की कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

50. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर स्थित सिद्धमुख नहर जर्जर स्थिति में होने के कारण नये सिरे से निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।
51. सिद्धमुख नहर परियोजना में सिद्धमुख तहसील के अधीन गांवों की चकबंदी, मुखाबन्दी करने के संबंध में चर्चा के लिए।
52. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में भिरानी हैड से सिद्धमुख तक पानी चोरी रोकने के पुख्ता इंतजाम करने के संबंध में चर्चा के लिए।
53. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर स्थित सिद्धमुख नहर परियोजना से सिद्धमुख के किसानों को टेल तक पानी पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (वि.सं.50)

54. प्रदेश में गिरते जलस्तर के संबंध में चर्चा के लिए।
55. करौली जिले एवं विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बांधों को ई.आर.सी.पी. योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।
56. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में एनिकट निर्माण एवं एनिकटों के मरम्मतीकरण कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में स्थित बिशन सबंध बांध की नहर की सफाई के संबंध में चर्चा के लिए।

58. करौली जिले में स्थित पांचना बांध की नहरों में पानी छोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

59. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम पंचायत सेमली फाटक एवं औगाड़ के रानीपुरा तालाब व अहिरान तालाब के जीर्णोद्धार के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं.96)</u>

60. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा गांधी नहर से अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पिण्डियों का तलाग्राम पंचायत लंगेरा तथा बालेरा में बरसात के पानी को पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने हेतु बांध/एनिकट का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)</u>

62. प्रदेश के डार्क जोन में भू-जल स्तर को बढ़ाने हेतु एक ठोस कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित खानपुरा तालाब के सौन्दर्यकरण एवं रख-रखाव हेतु आवश्यक बजट उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. प्रदेश में जल संसाधन विभाग के जीर्ण-शीर्ण कार्यालयों, राजकीय आवासों एवं डाक बंगलों को आधुनिक सुविधायुक्त बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. जल संसाधन के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु फार्म पॉण्ड, एनीकट, कूप पुनर्भरण, तालाबों एवं कुओं के पुनरूद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. बीसलपुर बांध को पर्यटन केन्द्र बनाने की दृष्टि से बांध का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

67. भीलवाड़ा जिले को रामसेतु लिंक परियोजना (ईआरसीपी) में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. भीलवाड़ा शहर के मध्य से गुजर रही मेजा नहर में जन व पशुहानि रोकने हेतु सुरक्षा दीवार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. भीलवाड़ा जिले को पूर्व में मिली परियोजना माही जाखम के अधिशेष जल के संबंध में चर्चा के लिए।

70. प्रदेश में पूर्व बजट घोषणानुसार मेजा नहर सहित पुर कनोड़ा, पुर खतोला, नौगांवा डैम और कैनाल के रिनोवेशन कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

71. भीलवाड़ा जिले को मेजा नहर से लक्ष्य अनुसार जलापूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

72. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा स्थित जोधपुर जिले का जसवंत सागर बांध को जवाई नहर से, आईजीएनपी नहर से अथवा यमुना लिंक नहर के पानी से पुर्नभरण करने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित जसवंत सागर/जालीवाड़ा बांध से निकलने वाली नहरों पर निर्मित पुलियाओं की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा स्थित जसवंत सागर बांध पर स्थित निरीक्षण गृह (रेस्ट हाउस) के जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होने के कारण पुर्ननिर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के तालाब भावी, लाम्बा, रावर, ओलवी, रामपुरिया, रामासनी, चांदेलाव, बिसलपुर, फलासनी व लोलावास भटिण्डा की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के जसवंत सागर बांध में आने वाली लूनी नदी में अपस्ट्रीम साईड में केचमेन्ट एवं पेटे में विभिन्न स्थानों पर एनीकट, बांध एवं वाटर बोडी निर्मित होने से जल की आवक बाधित होने पर माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)</u>

77. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की जीर्ण-शीर्ण नहरों को पुर्नजीवित कर क्षेत्र के हर किसान को पानी उपलब्ध कराने एवं नहरों का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अन्तर्गत नहरों का मरम्मत कार्य करने हेतु बजट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हंसराज मीना (वि.सं.188)</u>

79. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में सिंचाई हेतु नहरों का विस्तार एवं नहरों की मरम्मत कराये जाने, मामचारी बांध व कल्याणी एनीकट के रिपेयर एण्ड रिनोवेशन के कार्य कराये जाने, ग्राम चिंगीपुरा, जीरोता, रोधई, औण्ड़ व जाखौदा में एनीकट निर्माण कराये जाने तथा उपखण्ड मुख्यालय मण्डरायल में सहायक अभियन्ता कार्यालय सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समरजीत सिंह (वि.सं.174)</u>

80. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में बाण्डी सिण्धरा बांध, भीनमाल जालोर के बहाव क्षेत्र के गांवों के लिए नहर निर्माण एवं बाण्डी सिण्धरा बांध पर नदी में पानी छोड़ने के लिए फाटक बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के बाण्डी सिण्धरा बांध से निर्मित नहर से सिंचाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कुलदीप (वि.सं.33)

82. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के बांधों/एनिकटों, नालों की मरम्मत एवं निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (वि.सं.123)

83. विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर के कानोता डेम में इसरदा से पानी लाने व ईआरसीपी योजना में राजस्थान के पानी का कोटा कम करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (वि.सं.167)

84. विधान सभा क्षेत्र सुरजगढ़ में इन्दिरा गांधी जल योजना चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के किसानों को सिचांई के लिए पर्याप्त पानी देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र बुडानियां (वि.सं.84)

86. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में नहर निर्माण का कार्य धीमी गति से करने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में 10 हजार हैक्टर जमीन को सिचिंत करने के लिए नहरों में पानी छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)

88. प्रदेश के गोमती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का विकास करने और वर्षा जल का नदी में अबाधित प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

89. राजसमंद झील की नहर प्रणाली के पुर्ननिर्माण एवं डिग्गियां बनाकर पम्प लगाकर और पाइप लाइन से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

90. प्रदेश में बनास नदी पर कुरज, चौकड़ी, मोही, पीपली आचार्यान व जीतावास पर जल संग्रहण संरचना के लिए एनिकट, कॉजवे अथवा सब सरफेस बेरियर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. राजसमंद झील में पर्याप्त जल आवक की स्थाई व्यवस्था के लिए देवास तृतीय एवं चतुर्थ चरण तथा माही घाटी से जल परावर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. राजसमंद झील का राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना में चयन व सौंदर्यकरण कर विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)</u>

93. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के करेड़ा में चोरबावडी बांध को विकसित कर नहरी तन्त्र का सृजन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में अत्यधिक वर्षा होने के कारण मैजा तालाब/मेजा बांध का पानी माण्डल तालाब के कैचमेंट एरिया में छोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र माण्डल स्थित माण्डल तालाब को बांध का दर्जा दिलाने एवं सौन्दर्यकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में करेड़ा तहसील की खाटी नदी में से ऊंटाबोरा बांध या ईसमण्ड नदी से केनाल लाकर क्षेत्र के सभी तालाबों को लिंक करते हुये नहरी तंत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में स्थित मेजा बांध के सौन्दर्यकरण एवं नहरी तंत्र का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)</u>

98. प्रदेश की निर्माणाधीन सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाओं की प्रगति एवं ढूंढ नदी पर एनीकट निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)</u>

99. विधान सभा क्षेत्र नोहर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न माइनरों से बूंद-बूंद सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत डिग्गियों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र नोहर में नोहर फीडर नहर के पुर्ननिर्माण के लिए बजट वर्ष 2023-24 में घोषित 20 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी कर नोहर फीडर नहर का पुर्ननिर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत बंद पड़ी निर्माणाधीन सुई ब्रांच नहर का निर्माण पूर्ण करवाने एवं एटा सिरंगसर नहर का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र नोहर में नोहर फीडर, अमरसिंह ब्रांच एवं सिद्धमुख नहर परियोजना के पुराने व जर्जर खालों के पुर्ननिर्माण के लिए बजट वर्ष 2023-24 में घोषित 58 करोड़ रूपये की जारी वित्तीय स्वीकृति व प्रशासनिक स्वीकृति पर लगी रोक को हटाकर कार्य शुरू करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र नोहर व भादरा के 28 असिंचित गांवों के लिए बजट वर्ष 2023-24 में घोषित 100 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी कर कार्य शुरू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)</u>

104. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत मेज नदी पर बन रहे एनिकट और लाम्बाखेह एनिकट की सही मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

105. बून्दी के गरडदा बांध पूर्ण होने के बाद भी नहरों के निर्माण में बाधा आने के कारण किसान वर्ग को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में बन का खेडा, बम्वोरी, अरणामाता अन्थड़ा हाडो का पीपल्दा, लिलेडा, व्यासान वाजड का कुआं, बडुंन्दा, भवरदा, रामगंज राई का खाल, डोरा, गुवाडी, भैरूपुरा ओझा, आमली के एनिकटों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

107. ईआरसीपी में चम्बल काली सिंध नदी के संगम पर कृत्रिम जलाशय बनाकर चौमहला डग जिला-झालावाड़ क्षेत्र में सिंचाई परियोजना से पानी दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

108. जिला झालावाड़ को मध्यम सिंचाई परियोजना छोटी कालीसिंध व चाचूर्णी नदी हेतु डीपीआर लागत स्वीकृत होने से इसकी क्रियान्विति करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं.24)</u>

109. विधान सभा क्षेत्र बयाना में बंद बारेठा से निकलने वाली नहर का पुन: जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में मिल्समा पंचायत के आस-पास जलभराव की समस्या को देखते हुए बरसाती पानी के लिए चैनल बनाकर पास से गुजर रही गम्भीरी नदी में डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. प्रदेश की गम्भीरी नदी एवं कुन्कुनु नदी के प्रवाह क्षेत्र में आयी मिट्‌टी को हटाने और मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बंध बारेठा बांध में भराव क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जमा मिट्‌टी को हटाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

113. बयाना में पूर्व की भांति खण्ड कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)</u>

114. प्रदेश में कालीखाड़ डेम, मनोहरथाना की नहरों व गुलेण्डी डेम, अकलेरा की नहरों का जीर्णोद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के गोरिया खेड़ा के मध्य व गांव ढाबा के पास परवन नदी पर एनीकट निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

116. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पानी भराव से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए।

117. प्रदेश में यमुना जल समझौते के पूर्ण क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. जिला भरतपुर को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने एवं जल प्रवाह तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. प्रदेश में बाण गंगा नदी एवं गम्भीरी नदी का मिलान कर पांचना बांध से पानी के आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)</u>

120. विधान सभा क्षेत्र मकराना में सीडब्ल्यूटी व पीएसपी पाईंटों पर कनेक्शन नहीं दिये जाने तथा पशुधन से वंचित खेलीयों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्र में 20 एमएलडी के स्थान पर 14 एमएलडी एवं शहरी क्षेत्र में 19 एमएलडी के स्थान पर 12 एमएलडी ही पानी मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र मकराना की वंचित ढ़ाणियों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र मकराना के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र एवं बोरावड़ शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत सी.डी.एस. 02 प्रोजेक्ट के कार्यों में भारी अनियमितताओं के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं.144)</u>

124. प्रदेश के लडकी बांध निरीक्षण गृह की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

125. प्रदेश के राथलियास, फुकिया, लडकी, लाखेला, आटावाड़ा बांध व अन्य बांधों एवं इनकी नहरों की मरम्मत हेतु बजट स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं.155)</u>

126. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की पूगल ब्रान्च नहर के क्षतिग्रस्त खालों का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की आरडी 415 से 620 आरडी के मध्य छतरगढ़ तहसील की समस्त नहरों के क्षतिग्रस्त खालों का पुन: निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुरवीर सिंह (वि.सं.42)

129. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के पक्के खालों को प्री-कास्ट सीमेन्ट कंकरीट से बनवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. बीकानेर कैनाल की टेल आरडी 423 तक सीसी लाइनिंग किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. गंगनहर सिंचाई प्रणाली की सभी वितरिकाओं/माइनरों की रिवाइज कैपेस्टी तैयार कर इसे डिजिटलाईज्ड किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

132. गंग कैनाल हुसेनी वाला से 45 आरडी तक साफ-सफाई व रिलाइनिंग के लिए बजट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में गंगनहर, भाखड़ा नहर व इन्दिरा गांधी परियोजना की पुरानी व जर्जर नहरों व पुलियाओं के पुन: निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में गंगनहर, भाखड़ा नहर व आई.जी.एन.पी. के तहत पुराने व जर्जर खालों के पुन: निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लौह हैड से साधूवाली तक लिंक चैनल की साफ-सफाई एवं रिलाइनिंग के लिए बजट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ 1 जीएनपी सूरतगढ़ ब्रांच की आर.डी.118.00 पर क्रास रेगुलेटर के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखवंत सिंह (वि.सं.65)

137. राम जल सेतु परियोजना में रूपारेल को डीपीआर में शामिल करने तथा इसके बांधों में पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)

138. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में परम्परागत जल स्रोत तालाबों को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ के गोतावर बांध की ऊंचाई सर्वे अनुसार बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन एनीकटों के लम्बित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. प्रदेश में ईआरसीपी की तर्ज पर डब्ल्यूआरसीपी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)

142. प्रदेश में सिंचाई का पानी चोरी करने पर शिकायत करने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

143. गंगनहर की टेल के किसानों को पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

144. गंगनगर क्षेत्र में सिंचाई खालों को पक्का करने के संबंध में चर्चा के लिए।

145. फिरोज फिडर पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रूपिन्द्र सिंह कुन्नर (वि.सं.200)</u>

146. विधान सभा क्षेत्र करणपुर के ग्राम जीवन देसर की कृषि भूमि को अनकमाण्ड से कमाण्ड किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री आदू राम मेघवाल (वि.सं.19)</u>

147. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में किसानों को सिंचाई कार्य हेतु नर्मदा नहर परियोजना का पर्याप्त जल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नगरपालिका, चौहटन के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में निर्मित तालाबों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण तथा जीर्णोद्धार कार्य करने एवं क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सेड़वा तथा चौहटन उपखण्ड मुख्यालयों पर नवीन सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

151. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम डोली, अराना कल्याणपुर, के तालाबों की मरम्मत एवं उनके रख-रखाव हेतु बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा एवं सिवाना के बांधों एवं तालाबों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा में लूणी नदी में साफ-सफाई एवं बालोतरा शहर में तटबन्दी करके घाटनुमा बनाकर नदी के सौन्दर्य को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा एवं सिवाणा में लूणी नदी के प्रवाहित क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सिलोर, जेठन्तरी, कनाना, सराणा, किटनोद, बिढुजा, कुम्पावास आदि स्थानों पर जीरो चेक डेम अथवा रपट बनाकर उक्त नदी के जल स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. जोधपुर से बालोतरा तक जोजरी नदी के बहाव क्षेत्र में गन्दे पानी के बहाव हेतु नाला निर्माण एवं नदी के बहाव क्षेत्र का निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

156. जयपुर के चंदलाई व नेवटा बांध से पानी चोरी पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. जयपुर के कानोता बांध में गंदे पानी की आवक पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

159. प्रदेश में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति को और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

160. जयपुर के रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया से पूरी तरह अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)

161. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के उपखण्ड निम्बाहेड़ा में खण्डीय कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा में मनोहरखेडी, बोरडी एवं मरजीवी लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के 8 प्रमुख एनीकटों {कुन्दीरल, सरसी, जलिया, मनोहर, उंडावेला, बांरेडा, पेचदेवला व मेरिया खेडी (अम्बाजर)} के जीर्णोद्धार के संबंध में चर्चा के लिए।

164. छोटी सादड़ी क्षेत्र के 6 एनिकटों (हुर्राबा गौशाला, धामन दोह, उटंका गोडा, डोका खालगोडा, बेखारा, दाता का खाल) के जीर्णोद्धार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)

165. जल महल के अतिरिक्त पानी के बहाव हेतु नगर निगम हैरिटेज के वार्ड नं. 3 व 4 में होकर जाने वाली पुरानी नहर के पुर्ननिर्माण व पक्की करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण राम (वि.स.141)

166. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में से बहने वाली लूणी नदी पर सब सरफेस बैरियर (एसएसबी) निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम कलरू, लांबा जाटान, रेण, कुरड़ाया, बीटन व पुंदलू के सार्वजनिक तालाब तथा बांध के जीर्णोद्धार के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

168. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में आंशिक डूब प्रभावित गांवों को पूर्ण डूब प्रभावित घोषित कर मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सिंचाई से वंचित गांवों को ईआरसीपी/परवन वृहद सिंचाई के अंतर्गत लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाकर जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में परवन वृहत सिंचाई योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आये राजकीय भूमि पर बने मकानों को मुआवजा देने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी ब्लॉक की ग्राम पंचायतों आगरिया, कुशलपुरा, बरखेडा, गुराडखेडा, गरवाडा व मोडी के 60 गांवों को चेक डेम, छोटे निकट बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)</u>

172. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित विस्थापितों को बकाया मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)</u>

173. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उपखण्ड मुख्यालय बनेडा के जवासियां बांध की रिपेयरिंग व रिनोवेशन तथा मेजा बांध की नहर कमालपुरा (बनेडा) से लिंक नहर निकालकर कोसारिया (बनेडा) तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के किसी भी बांध पर कोई चौकीदार कार्यरत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के अरवड बांध (फुलिया कलां) की एस.एम.सी. एवं आर.एम.सी. नहर के निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

176. उपखण्ड शाहपुरा के भीम सागर ढिकोला तालाब की एस.एम.सी. एवं आर.एम.सी. नहर के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में विभाग के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री युनूस खान (वि.सं.121)</u>

178. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज-II के पेयजल की मांग अनुसार आपूर्ति नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

179. प्रदेश के विभिन्न राज्यों से जल बंटवारे के संबंध में समझौते अनुसार जल की मात्रा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

180. प्रदेश की पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना (एमपीकेसी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के रावी, व्यास, सतलुज नदियों के अधिशेष पानी को लेकर समझौता अनुसार पानी दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं.83)</u>

182. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के सभी एनीकट/बांध इत्यादि के जीर्णोद्धार के संबंध में चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के गाडराटा में नये बांध का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

184. प्रदेश में यमुना जल समझौते के तहत बनने वाली डीपीआर में खेतड़ी के सभी छोटे-बड़े बांधों को जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामस्वरूप लाम्बा (वि.सं.136)</u>

185. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम-चेनपयुरा (राजगढ़) में गुमान/धन्ना के कुंए के पास एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम चेनपुरा के गोपाल सागर तालाब की मरम्मत व जीर्णोद्धार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम नूरियावास के क्षतिग्रस्त एनीकट का जीर्णोद्धार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के तालाबों व एनीकटों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शिमला देवी (वि.सं.163)</u>

189. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत पोंग, भाखडा, रणजीत सागर, हरि के बैराज बांधों की भराव क्षमता एवं मरम्मत कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

190. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के क्षेत्रवासियों को सिंचाई व पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना अंतर्गत हरि के बैराज बांध पर नये गेटों का निर्माण नहीं होने से लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान चले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पोंग बांध विस्थापितों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)</u>

193. अलवर जिले में रूपारेल नदी पर स्थित घाट पिकअप वेयर की ऊंचाई बढ़ाने एवं फीडर नहरों की मरम्मत कर मौजपुर, गोरपहाड़ी, लक्ष्मणगढ़ एवं कनवाड़ा बाधों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुभाष मील (वि.सं.179)</u>

194. नगरपालिका, खण्डेला के बरसाती पानी को एकत्र करने हेतु एक तालाबनुमा जल संग्रहण स्ट्रक्चर बनाने एवं उस पानी को ट्रीटमेंट द्वारा पेयजल के लिये उपयोग में लाने के संबंध में चर्चा के लिए।

195. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के विभिन्न बांधों के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)</u>

196. विधान सभा क्षेत्र कपासन के मात्रीकूण्डिया बांध का 600 एमएलएफटी पानी छोर 2 तालाबों को भरने के लिए लिंक नहर बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.05)</u>

197. सरदारशहर तहसील के 58 गांवों के वंचित रकबों को चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल से जोड़ने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रामबिलास (वि.सं.135)</u>

198. विधान सभा क्षेत्र लालसोट के राहुवास बाहा, सूरतपुरा बांहा एवं खारली बांध को ई.आर.सी.पी. से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं.111)</u>

199. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा एनएच 48 से लेटकाबास रोड़ पर फाफिया नाले का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के बांधों को पीकेसी-एआरसीपी से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं व एनिकटों का जीर्णोद्वार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजस्व ग्राम बिशनगढ में माधोनेवी नदी पर स्थित अरडकी एनिकट के जीर्णोद्वार हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के कार्यालय सहायक अभियंता कार्यालय का जीर्णोद्वार कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

204. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नोनेरा बांध पर पम्प हाउस के निर्माण एवं फीडर कनोल निर्माण हेतु ऐबरा गांव की 73.08 हैक्टर भूमि सरकार द्वारा अवाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम अरूया-ढिढोरा-विजयपुरा-लक्ष्मीपुरा-हरिपुरा में ड्रेनी की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम भेता, अयानी एवं मदाहेडी में तालाबों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं सेफ्टीवॉल निर्माण कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम जलोदा माईनर, करवाड, बोरदा, तलाव, ख्यावदा, अयानी, जटवाडा ककरावदा, गणेशगंज, जोरावरपुरा, गेंता, रजोपा, दुर्जनपुरा, ढीपरी चंबल, किशोरपुरा, बनेढीया, खेरूला, मोरपा, सुल्तानपुर बुढादित, मदनपुरा, झादगांव,

बिसलाई, जाखडोद, कोरडा दीपसिंह ग्रामों के माइनरों को पक्का करने, डेमों की खुदाई व अन्य कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के मांगरोल में लिफ्ट सिंचाई हेतु मोटर बढ़ाने व गणेशपुरा लिफ्ट सिंचाई में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

209. नर्मदा नहर पेयजल परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन के संबंध में चर्चा के लिए।

210. बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना से विधान सभा क्षेत्र शिव की पंचायत समिति क्षेत्र शिव के गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र शिव में जल संचय हेतु बांधों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र शिव में नर्मदा नहर परियोजना से पेयजल के साथ सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

213. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के जैसलमेर जिले के लूणार से विधान सभा क्षेत्र शिव के गडरा रोड तक पूर्व में प्रस्तावित कार्य को पूर्ण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री देवी सिंह शेखावत (वि.सं.81)</u>

214. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बामनवास तालावास के पहाड़ पर एनीकट निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बिलाठ, ज्ञानपुरा व रायपुर में एनीकट निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के हरसोरा बांध में पिचिंग कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ज्ञानपुरा में एनिकट निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बाबरिटा बांध में पिचिंग कार्य कराने एवं भराव क्षमता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।